

DUE DATE SLIP

GOVT COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

अगस्त 1949 को भूटान सरकार ने स्वतंत्र भारत की सरकार से एक नयी सन्धि की। इस सन्धि के अनुसार भूटान और भारत का सम्बन्ध पूर्ववत् रहने का निश्चय किया गया।¹

भूटान के विवास के लिए भारत सरकार सहायता कर रहा है। भूटान के एक महत्वपूर्ण सड़क जो उस राज्य के नगर पारो के साथ भारत का सम्बन्ध स्थापित करती है भारतीय इंजीनियरों की सहायता से बनायी गयी है। एक और सड़क भूटान के उस क्षेत्र में बनायी गयी जिस पर चीन ने दावा किया था। इन दोनों सड़कों के निर्माण में भारत का बड़ा योगदान दिया जा चुका है।

भारत-चीन युद्ध के पश्चात् सिक्किम और भूटान दोनों का महत्त्व बहुत बढ़ गया है। चीन के मानचित्रों में भूटान के तीन सौ वर्गमील का क्षेत्र तिब्बत के भाग के रूप में दिखाया गया था। चीनी सैनिकों का जमाव इन्हीं दो राज्यों की सीमाओं पर है। इस हालत में भारत की राया की सुरक्षा गंभीरता में भूटान और सिक्किम कमजोर पड़ियी हैं। प्रतिरक्षा के प्रयोजन के लिए भूटान और चीन के बीच सीमा की सीमा और सिक्किम तथा चीन के बीच की सीमा की सीमा भारत की उत्तरी सीमा का ही अंग है। इस सीमा की सुरक्षा बनाए रखनी है। भूटान और सिक्किम दोनों की भूमि समुद्र की सतह से एक हजार फीट ऊंची है जो बराबर हिमाच्छादित रहती है। इस हालत में भारत को इस क्षेत्र में विशेष गाम्भीर्य बरतने की आवश्यकता है। उन राज्यों का चीन के सैनिकों द्वारा घेरे होना बरतने की नीति का दावा भी रखा करना भारत का उत्तरदायित्व है।

भारत की स्वतंत्रता के साथ ही भूटान के सामने यह समस्या पैदा हुई कि उसे अपने दो शक्तिशाली पड़ोसियों चीन और भारत के बीच बिना अपना निष्पक्षता वाली स्थिति बनाने के लिए क्योंकि यह छाटा सा पहाड़ी प्रदेश उत्तर में तिब्बत से घिरा हुआ है और दक्षिण में भारत से चीन के प्रति किसी प्रकार की अनावश्यक शत्रुता की अभिव्यक्ति में कटौत हुए भी भूटान के राजा ने यह महसूस किया कि उनके देश का भविष्य भारत के साथ ही जड़ा हुआ है, क्योंकि भारत और भूटान के सम्बन्ध में केवल अंग्रेजी शासनकाल की बजह से कनेक्शन बना हुआ है। इनके अतिरिक्त दोनों देशों की धर्मिकता के पक्ष में भारत की गुरु निरपेक्षता और दूसरे देशों के मामले में अनावश्यक हस्तक्षेप न करने की भी थी।

भारतीय सहयोग—1960 से पहले भूटान अर्ध-दशा के साथ संपर्क स्थापित करने की नीति के पक्ष में नहीं था। मगर तिब्बत में चीन के आधिपत्य के बाद भूटान के शासकों को यह महसूस हुआ कि उनका पुनर्जागरण उत्तर दिशा में नहीं है। अतः भूटान के राजा ने भारत में अनुरोध किया कि भूटान की सैनिक सहायता की जाय। 1960 के बाद इन दोनों देशों के बीच प्रतिरक्षा की नई व्यवस्था का महत्त्व आरम्भ हुआ जिसमें उद्योग विनिर्माण और संचार व्यवस्था सब प्रमुख हैं। 1960 से पहले भूटान में सड़कों की व्यवस्था बहुत ही खराब थी शायद ही कोई ऐसी सड़क थी जिस पर जीप चल सकती हो। एक बरस में दूसरे बरस तक प्रमुख बाह्य सड़क

1. सिक्किम में सन्धि के जरिये अपना वैशेषिक सम्बन्ध और प्रतिरक्षा का भार भारत को सौंप दिया। लेकिन भूटान ने इस संधि के द्वारा केवल विदेश नीति का भार ही भारत को दिया। भारत-चीन युद्ध के बाद उसने प्रतिरक्षा का भार भी भारत को सौंप दिया।

भारत और विश्व-राज

दीनानाथ वर्मा एम ए पीएच डी
रीडर पटना विश्वविद्यालय
पटना



ज्ञानदा प्रकाशन

पटना - ८००००६ • दिल्ली - ११०००६

कमो से अनेक राष्ट्रमण्डलीय देशों का जिनमें भारत भी है राष्ट्रमण्डल की भाषी उपयोगिता के विषय में सन्देह होने लगा है और कुछ देश इससे अलग हो जाने के बारे में भी सोचने लगे हैं। ब्रिटेन के साक्षात् बाजार में शामिल होने के फसले से राष्ट्रमण्डल पर कितना घातक प्रभाव पड़ सकता है उसका पता बहुत कुछ इसी बात से चल जाता है कि भारत में इस विचार को बल मिल रहा है कि ब्रिटिश प्रधान मंत्री विंस्टन चर्चिल राष्ट्रमण्डल के मित्र देशों के साथ घाटा करने जा रहे हैं और ब्रिटेन की परम्परा को भी वह छोड़ रहे हैं। ब्रिटेन की राष्ट्रमण्डलीय दशा का मान पर भीमा मुल्य में रियायत देने की परंपरा रही है। भारत को जानना यह है कि साक्षात् बाजार में शामिल होने के बाद ब्रिटेन की भारतीय मान के आयात पर ब्रूस स कीमती की सिफारिश के अनुसार सीमा तक रोकना हो पड़ेगा।

जनवरी 1969 में जिन में हो रहे राष्ट्रमण्डलीय प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए रवाना होने के पूर्व प्रधान मंत्री एड्रियन गॉर्डी ने यह कहा कि कुछ मिलकर राष्ट्रमण्डल का एक विचार विनिमय मंच से अधिक नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि आवश्यकता पड़ने पर भारत राष्ट्रमण्डल से अलग हो सकता है। लेकिन इस सम्मेलन में उन्होंने एक बात जोड़ दी। श्रीमती गॉर्डी ने कहा कि 1949 में चर्च आ रहे इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विधान की जिम्मेदारी हम नहीं लेना चाहते लेकिन यदि अकस्मिकताओं को यह महसूस होना पड़ेगा कि इसकी उपयोगिता खत्म हो चुकी है तो भारत-सरकार इसमें बने रहना भी नहीं चाहती। इस प्रकार तत्काल के लिए इस समस्या का टाल दिया गया। लेकिन इस समस्या की भयानकता अब धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही है। रोडशिपों जल महत्वपूर्ण मसालों पर यह पुण्यता निरपेक्ष सिद्ध हुआ है। राष्ट्रमण्डलीय प्रधान मंत्रियों के सत्रहवें सम्मेलन (1969) में इस विषय पर चर्चा अवश्य हुई लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। इस सम्मेलन में राष्ट्रमण्डल के महासचिव आर्नोल्ड स्मिथ ने अपने 1966-68 के प्रतिवेदन में लिखा था कि प्रजातीय असहिष्णुता नवपृथ्वीवाद और धनी तथा निधन राष्ट्रों के बीच की बड़ी हुई खाई कुछ ऐसी समस्याएँ हैं जो विश्व की सुख शांति के लिए अभिघात बनी हुई हैं। राष्ट्रमण्डल के सत्रहवें अधिवेशन पर इसी प्रवृत्तियों का प्रभाव रहा और यही बात विश्व के मुख्य विषय रहे। सम्मेलन शुरू होने के पहले ही जर्मन त्रिनोवाद आदि ने यह प्रस्ताव रखा कि सम्मेलन में एक ऐसा विचार ब्यूरो स्थापित किया जाय जो राष्ट्रमण्डल सचिवालय के अग्र के रूप में सदस्य देशों की प्रजातीय और अप्रवासीय समस्याओं का निपटारा करे। आर्थिक सहायता के सम्मेलन में भी बाद विवाद हुए लेकिन सम्मेलन में निर्णायक ढंग से कोई ऐसा निर्णय नहीं किया जो सदस्य राष्ट्रों को काम पहुँचाता।

राष्ट्रमण्डल का सिंगापुर सम्मेलन — जनवरी 1971 में पहली बार राष्ट्रमण्डल के देशों का सम्मेलन ब्रिटेन में बाहर आयोजित किया गया और यह भी एशिया के एक छोटे-से देश सिंगापुर में। 14 जनवरी 1971 को राष्ट्रमण्डलीय प्रधान मंत्रियों का यह अठारहवाँ सम्मेलन शुरू हुआ था और 22 जनवरी को समाप्त हुआ। इस सम्मेलन की विषय सूची में दो मुख्य विषय थे ब्रिटेन द्वारा दक्षिण अफ्रीका के गोरे जातिवादी शासकों को हथियार देने का निरुपेक्ष और हिंद महासागर में डियागो गार्सिया द्वीप में ब्रिटेन और अमेरिका का सैनिक अड्डा बनाने का निरुपेक्ष। अफ्रीका के देश और भारत सरकार सहित के इन दोनों निरुपेक्षों को अफ्रीका तथा हिंद महासागर की शांति के खिगाफ मानते थे इसलिए सिंगापुर में ब्रिटेन तथा अमेरिका के साथ बट कर मुकाबला करने की सैयारी में थे।

प्रकाशक

ज्ञानदा प्रकाशन

पटना—800004

शाखायें —

दिल्ली—24 दरियागज निली-6

मुजफ्फरपुर—बसोक मार्केट मोतावाल

मुजफ्फरपुर

वारा—महादेवा रोड बाग

रांची—एस० एन० गान्गा रा

रांची

नालपुर—डुमरा रो, भागलपुर 2

लेखक

प्रथम संस्करण	जनवरी 1969
द्वितीय संस्करण	जनवरी 1971
तृतीय संस्करण	जुलाई 1973
चतुर्थ संस्करण	नवम्बर, 1975

मूल्य ₹ 15 00 मात्र

मुद्रक

सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस

पटना—8 0004

मूमिका

भारत और विश्व-राजनीति" स्वतन्त्र भारत की विदेश नीति के इतिहास और उसकी समस्याओं की हिता जगत के समान प्रस्तुत करने का संस्कार का विनम्र प्रयास है। भारत की विदेश नीति पर अंगरेजी में कई ग्रन्थ उपलब्ध हैं। लेकिन जहाँ तक ज्ञान का ज्ञान है अभी तक हिता में कोई ऐसा पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है जिसमें इस विषय पर कुछ विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला गया हो। प्रस्तुत पुस्तक इस अभाव को दूर करने में कितना सफल हुई है इसका निर्णय स्वयं हमारे पाठक करेंगे।

पुस्तक के सम्बन्ध में मैं मौलिकता का दावा नहीं कर सकता। इसकी रचना अंगरेजी भाषा में लिखित कुछ प्रसिद्ध पुस्तकों के आधार पर हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय विदेश नीति उस गहन विषय को पाठकों के समक्ष सरल भाषा में रखना है। मुझे पूरी आशा है कि हमारे पाठक पुस्तक की विषय-वस्तु का सरलता से समझेंगे और स्वयं अपना निष्कर्ष निकालेंगे।

पुस्तक के प्रणयन तथा प्रकाशन में मुझे कई व्यक्तियों से बहुमूल्य सहयोग प्राप्त हुआ है। मैं उन सभी मित्रों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मैं उन सभी जेष्ठों के प्रति भी अपना आभार प्रकट करता हूँ जिनकी पुस्तकों से मुझे इस पुस्तक की रचना करने में सहायता मिली है।

पुस्तक के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के सुझावों का मैं सादर स्वागत करूँगा।

—लेखक

विषय सूची

1 स्वतन्त्रता के पूर्व विश्व राजनीति में भारत

1 62

विश्व राजनीति में पराधीन भारत की स्थिति—1 अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में भारत की स्थिति—2 नेपालियन के युद्ध और भारत—3 रूस का आतंक—4 पूर्वी एशिया और भारत—5 अन्तर्राष्ट्रीय समझौते और भारत—6 साम्राज्यवादी प्रसार में भारत का योग—7 भारत के अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व का विकास—8 इम्पीरियल कांफ़ेंस में भारत का प्रवेश—9 इम्पीरियल कांफ़ेंस—10 राउण्ड टैबुल—11 प्रथम विश्व-युद्ध का प्रभाव—12 वेरसि के शांति-सम्मेलन (1919) में भारत—13 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व—14 भारत की सत्ति—15 भारतीय प्रतिनिधि दल—16 राष्ट्रमण्डल में भारत—17 भारतीय सन्तुष्टता के सम्बन्ध में वाद-विवाद—18 राष्ट्रमण्डल में भारत की स्थिति—19 अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व का विकास—20 अन्तर्राष्ट्रीय समझौते—21 भारत में अन्तर्राष्ट्रीय चेतना का विकास—22 अन्तर्राष्ट्रीय चेतना का प्रारम्भ—23 रूस-जापान युद्ध—24 नवीन दृष्टि कोण—25 अशान्ति के प्रवासी भारतीयों की समस्या—26 प्रथम विश्व युद्ध और भारत—27 वेरसि का शांति-सम्मेलन और भारत—28 कांफ़ेंस और शांति-सम्मेलन—29 तिरुपति का पक्ष—30 नवीन की सत्ति और भारत—31 राष्ट्रमण्डल और भारतीय लोकमत—32 तुर्की के साथ शांति-समझौता और भारत—33 एजिप्टाई देहा का सगठन और भारत—34 पाल्मिरा राष्ट्रीय का वसुधैव कुटुम्बकम्—35 एजिप्टाई एकात्मता की भावना का प्रथम विकास—36 यूरोपीय समस्याएँ और द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रति भारतीय दृष्टिकोण—37 भारत और द्वितीय विश्वयुद्ध—38 ।

2 भारतीय विदेश नीति का निर्धारक तत्त्व

63-80

देश की भौगोलिक स्थिति—63 भू-तत्त्व—64 आर्थिक तत्त्व—65 ऐतिहासिक परम्पराएँ—66 वैचारिक तत्त्व—67 राष्ट्रीय चिन्तन—68 व्यक्तित्व तत्त्व—69 राजनीतिक तत्त्व—70 तत्त्वज्ञानी अन्तर्-राष्ट्रीय परिस्थिति—71 विश्व नीति की घोषणा और विद्यमानताएँ—72 ।

3 असंलग्नता की नीति

81-110

भारतीय स्वतन्त्रता के समय अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति—82 अलग-अलगता की नीति का जन्म—83 असंलग्नता की नीति का आविर्भाव—84 दोनो गुटों में मध्यस्थता की कामना—85 आर्थिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता—86 विदेशी सहायता की आवश्यकता—87 भौगोलिक स्थिति—88 नीति निर्धारण में स्वतन्त्रता की रक्षा—89 अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की कामना—90 वैचारिक मूलभूत—91 एजिप्टाई देहा के समान उपहार—92 नैतिक दृष्टिकोण—93 असंलग्नता की नीति की विशेषताएँ—94 असंलग्नता की नीति और तृतीय गुट की

धारणा—91 असह्यता की नीति का प्रयोग—92 1947 स 1950 के कोरिया युद्ध तक—92 1950 स 1957 का काल—93 1951 स 1962 के भारत चीन युद्ध के पूर्व तक—94 भारत चीन युद्ध स लेकर भारत सोवियत संघ तक—95 1965 का भारत-पाकिस्तान युद्ध और असह्यता की नीति—98 गुटबंदियों का जघकारपूर्ण भविष्य और असह्यता की नीति—99 असह्यता की नीति और नष्ट—99, नष्ट की मृत्यु के बाद असह्यता की नीति—100 असह्यता की नीति का भूयावन 101 असह्यता की नीति का जन्म—108 नवीन अन्तराष्ट्रीय स्थिति—108 भारत सोवियत संबंध—109 ।

4 भारत और विश्व शान्ति

111-134

भारत के लिए शान्ति की आवश्यकता—111 नीति-युद्ध क प्रति भारतीय दृष्टिकोण—112 परस्पर विरोधी शक्तियों के मध्य संतुलन का कार्य—112 समन्त शक्तों के साथ मत्रा सम्बन्ध—113 नय संगठनों के प्रति भारतीय दृष्टिकोण—114 नय संगठनों का उत्पत्ति—114 विश्व राजनीति पर नय संगठनों का प्रभाव—115 भारतीय दृष्टिकोण—116 नाटो का विरोध—116 सियाटो का विरोध—116 सेंटो का विरोध—117 भारतीय विरोध के नय कारण—117 निरस्त्रीकरण के प्रश्न पर भारतीय दृष्टिकोण—118 आर्थिक परमाणविक पराजय प्रतिवचन संधि और भारत—119 1968 का परमाणु शक्ति निरोध संधि और भारत—119 भारतीय दृष्टिकोण—120 अंतरिक्ष म चीन का प्रयोग—121 पंचशील—123 पंचशील का उद्भव—123 सिद्धांतों की व्याख्या—125 शान्तिपूर्ण सहजीवन का सिद्धांत—126 शान्तिपूर्ण सहजीवन के सिद्धांत पर भारतीय दृष्टिकोण—126 पंचशील का भूयावन—128 ।

भारत और संयुक्त राष्ट्रसंघ—130 संयुक्त राष्ट्रसंघ म भारत की भास्था—130 भारत की सहायता—131 भारतीय संविधान और संयुक्त राष्ट्रसंघ के आदर्श—131 संघ के महत्त्व का समर्थन—132 संघ की व्यापक रूप से न का भारतीय प्रयास—132 सुरक्षा परिषद् में विशेषाधिकार का प्रश्न और भारत—133 अंतराष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में संघ स सहायता—133 सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र म सहयोग—133 राजनीतिक क्षेत्र में भारत का स्थान—134 ।

5 अफ्रीका एशियाई समस्याएँ और भारत

135-172

एशिया और अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशवाद और भारत—135 भारत द्वारा उपनिवेशवाद के विरोध के कारण—136 उपनिवेशवाद विरोधी नीति का स्वल्प—138 इण्डोनीशिया में दृष्टि सान्नायवाद का विरोध—140 मलाया और हिन्द-चीन—141 अफ्रीका सान्नायवाद का समर्थन—142 संयुक्त राष्ट्रसंघ के सुरक्षित प्रश्न और भारत—143 1957 स उपनिवेशवाद के प्रति भारतीय नीति—143 भारत में फासीवादी तथा पुतंगी उपनिवेशवाद का समर्थन—146 फ्रांसीसी वस्तुता और भारत—147 मोरिशा की समस्या—147 प्रजाताय विभक्त और भारत—148 अफ्रीका अफ्रीका संघ और प्रजाताय विभक्त—149 1919 स 1945 तक के काल में भारतीय समस्या—149 संयुक्त राष्ट्रसंघ में

दक्षिण अफ्रीकी अश्वेतों का प्रश्न—151, भारत और एशिया अफ्रीकी देशों का संगठन—151 अंतर एशियाई सम्मेलन (1947)—151 द्वितीय एशियाई सम्मेलन—152 बाहु ग सम्मेलन—153 संयुक्त राष्ट्र संघ में अफ्रीका एशिया समकक्ष सम्मेलन—157 अफ्रीका एशिया तांत्रिक सम्मेलन—157 वेतन सम्मेलन—158 काहिरा सम्मेलन—159 अजीयस सम्मेलन—160 1966 का तीन सदस्य राष्ट्रों का शिखी सम्मेलन—161 1970 का तुसाका सम्मेलन और भारत—163 जलशक्ति सम्मेलन—163 दारैसलम का तयारी सम्मेलन—165 तुसाका सम्मेलन और भारत—169 गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का चतुर्थ अजीयस सम्मेलन और भारत—170 ।

6 महत्त्वपूर्ण अंतराष्ट्रीय सङ्घर्ष और भारत

173 225

कोरिया-समस्या के समाधान में भारत का योगदान—174 संयुक्त राष्ट्र संघ में कोरिया का मामला—174 युद्ध का प्रारम्भ—175 कोरिया की समस्या पर भारतीय दृष्टिकोण—176 युद्ध का विस्तार—177 युद्ध चीन का समस्या और भारत—180 भारत का दृष्टिकोण—181 चेन्नै सम्मेलन और भारत—182 जनवा समझौता और भारत—184 अंतराष्ट्रीय नियंत्रण आयोग और भारत—184 स्वतंत्रता का संकट और भारत—185 राष्ट्रीयकरण की प्रतिक्रिया—186 राष्ट्रीयकरण पर भारतीय प्रतिक्रिया—186 सम्मेलन सम्मेलन—186 मेनन याजना—187 मुरता परिपद को कारवाई—188 मित्र पर आक्रमण—188 मित्र पर आक्रमण की भारतीय प्रतिक्रिया—189 हंगरी में सोवियत हस्तक्षेप और भारत—191 हंगरी विवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि—191 मुरता परिपद में हंगरी का प्रश्न—192 साधारण सभा में हंगरी का प्रश्न—192 हंगरी में सोवियत हस्तक्षेप और भारतीय प्रतिक्रिया—193 कांगो की समस्या और भारत—196 संयुक्त राष्ट्रसंघ में कांगो विवाद का प्रवेश—196 संघ द्वारा कांगो में हस्तक्षेप—197 भारतीय दृष्टिकोण—198 वियतनाम की समस्या और भारत—199 वियतनाम में अमराका हस्तक्षेप—199 समझौते का प्रयास—201 वियतनाम संकट में भारतीय दृष्टिकोण—201 कम्बोडिया का संकट और भारत—203 भारत और परिवर्तित एशिया का संकट—205 अरब इजरायल सम्बंध—205 तृतीय अरब-इजरायल युद्ध 1967 के कारण—205 तृतीय अरब-इजरायल युद्ध—207 मुरता परिपद और युद्ध विराम—208 अरब-इजरायल संघर्ष में भारतीय दृष्टिकोण—209 भारतीय नीति की आलोचना और उसके आधार—210 भारतीय नीति का समयन—211 भारत और रवात सम्मेलन—215 जवा सम्मेलन और स्थायी इस्लामी सचिवालय पर भारतीय प्रतिक्रिया—220 बगला दंग के प्रति अरब दृष्टिकोण और भारत अरब सम्बंध—221 राष्ट्रपति सजादत द्वारा सचिवालय सहायकारा का मिस्य घोषन की घोषणा—222, अरब आतंकवाद और भारत 223 चतुर्थ अरब-इजरायल युद्ध (1973) और भारत—223 तेल संकट और भारत—225 लाहौर का इस्लामी सम्मेलन और भारत—225 ।

7 भारत और युक्त राज्य अमेरिका

226-230

एतिहासिक पृष्ठभूमि—226 राजनयिक सम्बन्ध की ओर—230
 सन्ध के वातावरण में सम्बन्ध का प्रारम्भ—231 बर्मावर प्रश्न पर
 मतभेद—232 दक्षिण अफ्रीका के प्रवासी भारतीयों की समस्या और
 उपनिवेशवाद पर मतभेद—233 कम्युनिस्ट गान का प्राप्तिभाव और
 भारत-अमेरिका मतभेद—233 ओरिदाद युद्ध और भारत-अमेरिका
 मतभेद—234 जापान का रुढ़ि का समस्या पर मतभेद—234
 हिन्द-चीन के प्रश्न पर मतभेद—235 तिब्बत के प्रश्न पर मत
 भेद—235 सन्ध सौठनों पर भारत-अमेरिका मतभेद—236 पाकि
 स्तान का रुढ़ि सहायता—236 एशिया अफ्रीका में राजनयिक
 गुप्तता का अमरीका सिद्धांत—237 गांधी के सम्बन्ध पर सम्बन्धों में
 विवाद—237 अमेरिका में मतभेद के अर्थ आधार—238
 भारत और अमेरिका के बीच सन्धानुसन्धान—238 भारत को
 अमरीकी आर्थिक सहायता—238 भारत-चीन युद्ध और समुक्त
 राज्य अमेरिका—240 भारतीय प्रधान मंत्री की प्रस्तावित अमेरिका
 यात्रा—241 भारत-पाकिस्तान युद्ध और अमेरिका—242 प्रधान
 मंत्री की अमेरिका यात्रा—243 सम्बन्धों में उत्तार-चढ़ाव—246
 बंगला देश के युद्ध में भारत-अमेरिका सन्ध—248 अमेरिका का
 भारत विरोधा रवैया—248 प्रधान मंत्री की अमेरिका यात्रा—249
 निष्पत्ति का पत्र—250 सामान्यतया पर अमरीका प्रतिक्रिया—250
 युद्ध के विस्फोट पर अमरीकी प्रतिक्रिया—251 अमरीका रवैया पर भार
 ताय प्रतिक्रिया—253 अमेरिका का युद्धपान सन्ध—254 एटोमरात
 भारत-अमेरिका सन्ध—256 पाकिस्तान का पुनः सम्बन्ध
 का निषेध—258 चीन की सन्ध-सन्ध और भारत-अमेरिका सन्ध
 —259 चीन का 480 वीं उमरीता—259 जियांगो सन्धिया के
 सन्ध में मतभेद—260।

8 भारत और सोवियत गण

261-314

एतिहासिक पृष्ठभूमि—261 सन्धियन सन्ध में भारत-सोवियत
 सम्बन्ध—262 सोवियत सन्ध की नया विवेक नति और भारत—264
 हिन्द-चीन की समस्या पंचांग और सन्ध सन्धनों का निनाम—265
 यात्राओं का जन्म जन्म—265 निरन्तरता की गांधी—265
 आर्थिक सन्ध—266 भारत-चीन युद्ध और सोवियत सन्ध—267 सन्ध
 का सन्ध—268 सन्धियन सन्ध का नवीन सन्ध और भारत—269
 भारत-अमेरिका युद्ध और सोवियत नति—269 बर्मावर समस्या का
 सोवियत दृष्टिकोण—270 भारत-अमेरिका युद्ध और सोवियत सन्ध—270
 तात्कालिक सम्बन्ध—273 सोवियत राजनयिक का जादू—274 सोवियत
 राजनयिक की सन्धना के कारण—275 पाकिस्तान की सन्धित सन्ध
 सन्धियता और भारत—277 चेकास्लोवाकिया का सन्ध और भारत—
 सोवियत सम्बन्ध—279 सोवियत हस्तमैत्र—280 चेकास्लोवाकिया
 का सन्ध और भारत—281 सन्धियन चीन विवाद और भारत
 —282 सोवियत विरक्तिय और भारत—282 भारत-सोवियत
 सन्ध की सन्ध—283 भारत-सोवियत सन्ध—283, सन्ध का

स्वल्प—285 यह कोई सनिक गुटवर्गी नहीं है—285 हमारे
के खिलाफ गार टी—285 सोवियत भारत मंत्री का एक नया अध्ययन
—287 अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में नवीनतम प्रवृत्तियों के उभार
की स्वाभाविक प्रतिक्रिया—288 चीन अमेरिका के प्रभावों से तुलना
—290 संधि का उद्देश्य—291 भारतीय विदेश नीति के इतिहास में
एक नया अध्ययन—293 बंगलादेश की राजनीति पर प्रभाव—295
भारत सोवियत प्रभाव की वृद्धि की क्षमता—296 भारत सोवियत
संघ पर अमेरिकी प्रतिक्रिया—298 अशांति का नया दौर—299
भारत पाकिस्तान में और सोवियत संघ—302 भारत सोवियत मंचि
—302 बंगलादेश की समस्या पर भारत सोवियत सम्मेलन—304
युद्ध पर सोवियत प्रतिक्रिया—307 सहयोग का बढ़ता हुआ दायरा—
308 बंगलादेश की भारत यात्रा—310 आर्थिक समझौता—311 एज
मार्स सामूहिक सुरक्षा की सोवियत योजना और भारत—313 सोवियत
आर्थिक सहायता—314।

9 भारत चीन सम्बन्ध

315 349

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि—315 तिब्बत का प्रश्न और भारत चीन
सम्बन्ध—316 तिब्बत की स्थिति—316 तिब्बत और भारत—31
कम्युनिस्ट चीन और तिब्बत—319 तिब्बत का विद्रोह और भारत
—321 भारत चीन सीमा विवाद—322 भूमोहन रेखा—3
लद्दाख—323 सीमा विवाद का आरम्भ—325 गान्धीना वार्ता—324
रगून सम्मेलन—326 भारत चीन युद्ध—327 चीन का त्रिमूर्ती
प्रस्ताव—327 एक-पक्षीय युद्ध विरोध की घोषणा—328 घोषणा के
कारण—329 भारत चीन युद्ध के समय विभिन्न राष्ट्रीय दल—330
पश्चिमोत्तरी गुट की प्रतिक्रिया—330 सोवियत रूस—331 पाकिस्तान
का रूस—332 सहस्र राप्ती का प्रतिक्रिया—33 चीन की दूसरी
धमकी—333 कोम्युनिस्ट सम्मेलन—334 गान्धी प्रस्ताव—334
नासिर प्रस्ताव—335 भारत राक्षस और चीन—336 चीन का
अन्तिमपट्ट—337 चीन की सनिक हस्त—338 संधि का नया और
—338 भारत चीन युद्ध के परिणाम—340 चीन की विदेश नीति में
नई प्रवृत्ति और भारत—342 बंगलादेश के समर्थन और भारत का
के प्राप्त चीन का रूस—345 भारत की प्रतिक्रिया—347 भारत का
प्रति चीन का नवीन दृष्टिकोण—348 कोर्टिस पिटमैन की चीन
यात्रा—349।

10 भारत और पाकिस्तान

350 431

दशौं राप्ती की समस्या—350 आर्थिक तनाव—351 नया
पानी का झगड़ा—352 कश्मीर का विवाद—353 राक्षस का मुकदमा
—353 संयुक्त राष्ट्रसंघ में कश्मीर का प्रश्न—354 संयुक्त राष्ट्र आपेग
के साथ—355 मन्नाटन योजना—356 विधान मन्त्रालय—356 आरम्भ
मिशन—357 प्रधान मन्त्रियों की वार्ता—357 पाकिस्तान अमेरिकी
संघ संधि और कश्मीर समस्या के हल में परिवर्तन—358 युद्ध-वजन
का प्रस्ताव—358 कश्मीर समिती संघ द्वारा राज्य के विलयन का

अनुमोदन—359 जारि मिशन—360 पुन गहम मिशन—361
 आयरलैंड का ब्रिमा विपक्ष प्रस्ताव—361 भारत-चीन युद्ध और
 भारत-पाक सम्बंध—361 स्वयं सिंह मुद्रो वाता—362 पाकिस्तान
 का जम्मूमी पक्ष—362 तवाल घटना और भारत-पाक सम्बंध
 —363 बरनार पुन नुरता परिपक्ष में—363, भारत-पाकिस्तान
 सम्बंध का स्थान में गेह अल्लु के यन—364 ब्रिट का पक्ष
 —364 960 का भारत-पाकिस्तान युद्ध—366 अमर में पक्षि-
 तान की घुसपट— 66 युद्ध का भारत— 67 सुत्त राक्षस में
 भारत का युद्ध का न मन्त्र— 68 भारत-पाक युद्ध—369 नुरता
 परिपक्ष का बहर्ष—369 अन्त का पक्षि जमिपान—371 नुरता
 परिपक्ष का तासरीय—371 प्रस्ताव का समाना—373 युद्ध विराम—
 374 युद्ध का परिणाम—375 युद्ध विराम का नान—377 ताक
 सम्मेलन—377 ताकद समीक्षा का महत्त्व—379 ताकद समीक्षा का
 वाद—380 विमान काहरा का और भारत का सम्बंध—381 पाकि-
 स्तान का युद्ध और भारत—382 पाकिस्तान में निष्पन्न—382
 आवासीय का कक्ष— 83 बगालियों का मुक्ति-यान—384
 पाकिस्तान द्वारा जमन—385 भारत का दृष्टि—387 राजदिक
 तनाव—388 मायता का प्र—389 शत्रु पक्ष का प्रकाश—391
 भारत का विपक्ष सचि—39 राजदिकों का प्रकाश—392 पुन
 मायता का प्रकाश—392 मुक्ति युद्ध का विविध में तनाव—392
 याहा का घाटा—392 सीमाओं पर युद्ध का तनाव—393 इन्डिया
 गांधी द्वारा पाकिस्तान दलों का यात्रा—394 पाकिस्तान में युद्ध दमन
 —394 मुक्ति-हिन्दी का साठन में भारत का योगदान—395 1971
 का भारत-पाकिस्तान युद्ध—396 युद्ध का विवेक— 96 भारत-
 प्रतिक्रिया—397 पाकिस्तान का दावा—397 का भारत का प्रकाश
 पा—397 युद्ध जिन के लिए अंतराष्ट्रीय समुदाय का प्रकाश—398
 वाला दल का मायता—400 पाकिस्तान द्वारा भारत का सम्बंध
 विपक्ष—401 सुत्त राक्षस में भारत-पाक युद्ध का प्रकाश—401 युद्ध
 की निष्पत्ति—401 नुरता परिपक्ष का पहला बहर्ष—401 बगाल का
 प्रतिनिधित्व का प्रकाश—402 नुरता परिपक्ष में भारत-पाक युद्ध—402
 नुरता परिपक्ष का दूसरा बहर्ष—403 सुत्त राक्षस में भारत-
 404 नुरता परिपक्ष की तासरीय बहर्ष—406 बहर्ष और जमिपान का
 प्रकाश—406 सुत्त राक्षस का बहर्ष—407 युद्ध का विवरण
 —407 पाकिस्तान द्वारा भारत का बहर्ष—408 एतरा युद्ध
 विराम—409 युद्ध में पाकिस्तान का हार के कारण—411 अमर
 नति पक्ष—412 नुरता परिपक्ष—413 भारत का हार के कारण
 मो—413 युद्ध का परिणाम—413 भारत का हार के कारण
 प्रकाश—414 दक्षिण अफ्रीका का बहर्ष—414 भारत की
 जारि रचनाति पर प्रकाश—415 पाकिस्तान में युद्ध—416
 युद्धोपरा पाकिस्तान—416 पाकिस्तान में युद्ध—416 बगाल
 का प्रतिनिधित्व—418 भारत का प्रकाश—419 भारत का प्रकाश
 सम्बंध—420 युद्धोपरा भारत पाकिस्तान सम्बंध—421 मण

वार्ता—422 शिमला का शिखर सम्मेलन—422 शिमला समझौते का बाद—426 मानवीय समस्याओं पर समझौता—427 अप्रिल 1974 का समझौता—429 भारत का परमाणविक परीक्षण और पाकिस्तान—430 सितम्बर 1974 का समझौता—431 ।

11 भारत और बंगला देश

432-447

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि—432 बंगला देश की मायता—432 भारत बंगला देश की पहली संधि—433 मुजीब की रिहाई में भारत का योगदान—433 शेख मुजीब का भारत आगमन—433 भारत बंगला देश के बीच दूसरी संधि—434 बंगला देश की मायता—434 मुजीब का बलुक्ता आगमन—435 इन्दिरा गांधी की ढाका यात्रा—435 मित्रता और सहयोग की पचीस वर्षीय संधि—436 संधि का विश्लेषण—437 भारत बंगला देश व्यापार समझौता—439 शिमला समझौता और बंगला देश—441 बंगला देश और समुक्त राष्ट्र संधि—442 भारत बंगला देश सांस्कृतिक समझौता—442 भारत विरोधी वातावरण—442 भारत पाकिस्तान समझौता और बंगला देश—443 पाकिस्तान द्वारा बंगला देश की मायता—444 अप्रिल 1974 की त्रिपक्षीय वार्ता—445 भारत बंगला देश समझौता (मार्च 1974)—445 फरवरी का दिवस—446 ।

12 भारत के छोटे पड़ोसी राज्य

448-489

भारत और अफगानिस्तान—448 अफगानिस्तान के साथ भारत का सम्बन्ध—449 अफगानिस्तान की मांग—449 भारत अफगान सम्बन्ध—450 बदली हुई एशियाई राजनय और भारत अफगान सम्बन्ध—451 रूखा और भारत—451 भारत विरोधी रुखा—452 भारत के प्रति रुखा की नीति में परिवर्तन—453 रुखा में प्रवासी भारतीयों की समस्या—454 नहुष-कोटलवाला समझौता—455 1964 का समझौता—456 बन्धुत्व का प्रश्न—457 रुखा का चुनाव और भारत से सम्बन्ध—459 प्रधान मंत्री की रुखा यात्रा—460 प्रमोदी भट्टार नामक की भारत यात्रा—460 बन्धुत्व पर समझौता—461 भारत और बर्मा—462 बर्मा चीन सीमा विवाद और भारत—463 बर्मा में प्रवासी भारतीयों की समस्या—464 भारत और नेपाल—465 नेपाल की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति—465 स्वतन्त्र भारत और नेपाल—465 नेपाल का गुप्त-मुद्र और भारत—467 नेपाली कांग्रेस और भारत विरोधी अभियान—468 नेपाल की आन्तरिक राजनीति—469 टीका प्रसाद आचार्य के प्रधान मन्त्रित्व काल में भारत-नेपाल-सम्बन्ध—470 के आर्से सिंह का प्रधानमन्त्रित्व काल और भारत—471 बी० पी० कोइराला और भारत—472 1967 के उपरान्त भारत-नेपाल सम्बन्ध—472 1965-1969 के काल में भारत-नेपाल सम्बन्ध—473 भारतीय सैनिक सम्मक दल के सम्बन्ध में नेपाल की मांग—474 1970 की व्यापारिक वाता—476 वार्ता का दूसरा दौर—477 भारत-नेपाल व्यापार संधि—478 शोशी गृहक परिषदना संधि—480 सिक्किम की घटनाएँ और भारत

नेपाल सम्बन्ध—482 भारत के सरलित राज्य सिक्किम और भूटान—
483 सिक्किम—483 अंग्रेजों का प्रवेश—483 1950 की संधि—483
सिक्किम का जन आन्दोलन 1973 और भारत—484 सिक्किम के दो
राजनातिक दल—484 भारत के सह राज्य के रूप में सिक्किम—485
भूटान—486 भारतीय सहयोग—487 ।

13 राष्ट्रमण्डल ब्रिटेन और भारत

4 0 502

राष्ट्रमण्डल का स्वरूप—490 औपनिवेशिक सम्मेलन—490 प्रथम
विश्व-युद्ध के बाद राष्ट्रमण्डल का विकास—491 राष्ट्रमण्डल और द्वितीय
विश्व-युद्ध—492 राष्ट्रमण्डल का वर्तमान स्वरूप—492 राष्ट्रमण्डल
का संगठन—492 राष्ट्रमण्डल में भारत की स्थिति—493 राष्ट्रमण्डल के
साथ भारत का सम्बन्ध—497 राष्ट्रमण्डल का भविष्य—498 राष्ट्रमण्डल
का मिलापूर सम्मेलन—499 राष्ट्रमण्डल का बटावा सम्मेलन—501 ।

स्वतन्त्रता के पूर्व विश्व राजनीति में भारत

(1) विश्व राजनीति में पराधीन भारत की स्थिति

अत्यन्त प्राचीन काल से ही बाह्य जगत् से भारत का सम्बन्ध बना आ रहा है। सम्भवतः भारत ने किसी भी युग में दुनिया से पृथक् रहकर एकांतवासी जीवन व्यतीत नहीं किया।¹ दक्षिण पूर्व एशिया के कतिपय देशों तथा यूनान और रोम के साथ भारत का घनिष्ठ व्यापारिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध था। इनमें से कई देशों के साथ यन्त्रकाल की दृष्टिकोण से राजदूतों के आदान प्रदान भी हुए थे।² वस्तुतः मध्ययुग के आगमन के पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व था। लेकिन मुस्लिम राज्य की स्थापना के पश्चात्पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ भारत का सम्बन्ध पूर्णतया समाप्त हो गया। फिर पश्चिम एशिया में विद्यमान ओटोमन साम्राज्य (Ottoman Empire) की स्थापना के कारण यूरोप के देशों के साथ भी उसका सम्पर्क प्रायः टूट गया। ब्रिटिश राज्य की स्थापना के बाद अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का सम्पूर्ण अस्तित्व सुस्पष्ट हो गया। अब भारत ब्रिटिश साम्राज्य (जो अन्तर्राष्ट्रीय विधि [International Law] के अन्तर्गत एक इकाई माना जाता था) में विलीन होकर उसका अभिन्न अंग बन गया। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसका अपना कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रहा। भारत पर शासन करने तथा भारतीय नीति का निर्धारण करने के लिए 1858 में लन्दन में एक इंडिया ऑफिस (India Office) की स्थापना की गयी और पराधीन भारत की विदेश नीति का निर्धारण वहीं से होने लगा। भारत सरकार ब्रिटिश सरकार की एक अधीनस्थ शाखा (Subordinate Branch) बन गयी और उसपर उसका (ब्रिटिश सरकार का) पूर्ण एवं सर्वोपरि नियंत्रण कायम हो गया। ब्रिटिश सरकार से अलग होकर भारत सरकार किसी समस्या पर स्वतन्त्र रूप से विचार नहीं कर सकती थी। इस सदन में प्रो. वेस्टेक ने ठीक ही लिखा था कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत भारत का कोई स्थान नहीं है। शांति या युद्ध स्वतन्त्रता या अन्तर्राष्ट्रीय वार्ता के लिए वास्तविक अन्तर्राष्ट्रीय

1 India did not lead an isolated life but maintained a close and intimate contact with the great civilization of the West through trade and commerce. This led to cultural and occasionally even Political relations. R. C. Mazumdar & A. D. Pusalkar (Ed) *The History and Culture of the Indian People The Age of Imperial Unity* p 633

2 Ibid Also see A. B. Maitty International Status of India *The Modern Review* April 1954 p 288

इकार युनाइटेड किंगडम (United Kingdom) है जिसका भारतीय साम्राज्य एक अंग माना है।¹

भारतीय देशों रियासतों की स्थिति भी इसका ही प्रतिफल है।² उनके बदलिब सम्बन्धों पर ब्रिटिश क्राउन (British Crown) का पूर्ण नियंत्रण था। ब्रिटिश सरकार के भारत स्थित प्रतिनिधि अंतराष्ट्रीय संधियों को अपना अनुमति देना रियासतों पर लागू कर सकते थे। यदि ब्रिटिश सरकार युद्ध का घोषणा करती अथवा शांति समझौता करती या तटस्थ दृष्टिकोण अपनाती तो देश रियासतों का भी इनमें शामिल होना के लिए वे बाध्य कर सकते थे। यमराजों के ब्रिटिश का इच्छा पर निर्भर करती थी देशों रियासतों के लोगों की इच्छा का इसमें कोई महत्व नहीं था।³ अंतराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत उनकी स्थिति का वर्णन विनियमों के द्वारा न निश्चित किया है। भारत सरकार और देशों रियासतों के पारस्परिक संबंधों में अंतराष्ट्रीय विधि के सिद्धांतों का कार्य महत्व नहीं था। देशों रियासतों ब्रिटिश क्राउन का अधिनियम (Paramountcy of British Crown) के अन्तर्गत और इस कारण उन पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण था।⁴

सं प्रकार यह स्पष्ट है कि ब्रिटिश राज की स्थापना के पश्चात् अंतराष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का अपना कोई पृथक् स्थान नहीं रहा। अंतराष्ट्रीय राजनीति के रणमंच पर भारत की स्थिति एक खिलौने के सदृश हो गयी जो ब्रिटिश क्राउन के इच्छा अनुसार घुमावटें भारत सचिव (Secretary of State for India) के हाथों में रहती रही।

अंतराष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की स्थिति—भारत की इस अवस्था और परावर्तित स्थिति को देखकर यह समझना सरल होगा कि अंतराष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में भारत को महत्व नहीं रहा। वस्तुतः इस स्थिति में रहते हुए भी भारत का अन्तर्गत तथा परोक्ष रूप से अंतराष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख भूमिका का निर्वहन करता रहा।⁵ अन्तर्गत तथा परोक्ष अंतराष्ट्रीय क्षेत्र में ब्रिटिश विदेश नीति के मूल

1 Westlake *Chapters on the Principles of International Law* (1913) p 215

2 ब्रिटिश क्राउन ने भारत दो राजनयिक द्वाइयों में वर्ग किया था ब्रिटिश भारत जिसपर भारत सरकार का प्रत्यक्ष शासन था। अन्तिम देशों रियासतों जिसकी संख्या लगभग 562 थी आर्थात् मामला में स्वायत्तता प्राप्त स्थितिपूर्ण थी। भारत सरकार और देशों रियासतों के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण पहले के संधि समझौते के आधार पर होता था। बदलिब मामला में वे पूर्णतया ब्रिटिश सरकार के अधीन रही थीं।

3 A B Keith *A Concise History of India* pp 19-220

4 William Lee Warner *The Protected Prince of India* p 373

5 The role of India has been that of a pawn playing a part and even a major part in the balance of world forces and world conflict but not of its own choosing or under its own control —R P Dutt *India Today* (1949) p 502

तरका की समझने के लिए हम हमेशा भारत की महत्वपूर्ण एक निर्णायक सामरिक और राजनीतिक स्थिति पर ध्यान रखना पड़ेगा। इन तथ्यों की किसी भी सूच्य पर अति से ओझस नहा दिया जा सकता। उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ से ही भारत ब्रिटिश विद्युत नीति का मूल आधार बन गया। उस काल में ब्रिटन के सामने यूरोपीय शक्ति संतुलन (Balance of Power) को बनाए रखने की समस्या उत्तरी गम्भीर रही या ब्रिताना भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा की समस्या।¹ उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ से तब तक भारत में ब्रिटिश राज्य के अन्त तक इस सम्पूर्ण काल में जो औपनिवेशिक विस्तार युद्ध अथवा शांति सम्झौत कूटनीतिक संघर्ष तथा अंतर्राष्ट्रीय सङ्घर्ष उत्पन्न हुए उन सब के मूल में ब्रिटन की साम्राज्यवादी प्रणाली (Imperial system) के अन्तर्गत भारतीय साम्राज्य की अभ्युत्थिति थी। भारत इस साम्राज्यवादी प्रणाली का केन्द्रविन्दु या आधार-स्तम्भ था।²

नेपोलियन के युद्ध और भारत—भारत को नेपोलियन द्वारा ब्रिटिश विद्युत नीति का निर्धारण उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ से ही शुरू हुआ। उस समय यूरोप के राजनीतिक तन्मण्डल पर नेपोलियन बोनापार्ट का सितारा चमक रहा था। उस महान फ्रांसीसी विजिता की महत्ता का किसी भी व्यक्ति के लिए तब तक कोई स्पष्ट रूप से कहा जा कि ब्रिटन को यूरोप में नज़र हराया जा सकता है क्योंकि वह एक छोटा सा द्वीप ही नहीं बरन् दूर देशों में फैला हुआ एक विशाल साम्राज्य है और

1 No person can understand the foreign policy of England who does not know the relationship which India bears to the British Empire. No person can understand the British foreign policy which has inspired the diplomatic and military activities from the Nepoleonic wars right down to the establishment of the League of Nations unless he interprets diplomatic conflicts, territorial annexations, treaties and alliances and extension of protectorates with the fact of India constantly in mind. For the British Empire is not a European Empire—it is an Asiatic Empire and India is its central pillar.—Agnes Smalley, *India's Role in World Politics* *The Modern Review* May 1925 p. 530

2 British foreign policy during the last two centuries has been greatly influenced by its struggle for determination to control India by secure control of India is necessary for the maintenance of British supremacy in Europe and Asia and with world politics generally. India may in fact be regarded as the centre of power of British Empire in the East and for this reason alone setting aside all other considerations must be found a constant and aggressive. It is not only British supremacy in that country itself which is at stake the uninterrupted intercourse with her eastern colonies themselves would at once be threatened should foreign intervention take place

—Archibald Colquhoun *Russia's Foreign Policy* p. 203

भारत उक्त साम्राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। वह कहा करता था कि ब्रिटन को भारत में पराजित किया जा सकता है। अतः यूरान में ब्रिटेन का पराजित करने के लिए वह भारत विजय की योजना बनाने लगा। सन् 17८8 में एक विशाल सैनिक बल लेकर वह मिस्र की ओर चल पड़ा। उसका विचार था कि पड़ने मिस्र पर आधिपत्य कायम करके उसका एक मुख्य फासीया सैनिक बल बनाया जाय ताकि वहाँ से भारत पर सुगमतापूर्वक आक्रमण किया जा सके। मिस्र पहुँच कर उसने कुछ भारतीय नरेशों के साथ वातालाप भी शुरू कर दी। 1799 में उसने काहिरा से ममूर के नरेश टीपू सुल्तान का एक पत्र लिखा और उनसे साथ सैनिक गठबंधन कायम करने की इच्छा व्यक्त की। नेपालियन की इन सैनिक और राजनयिक गतिविधियों को देखकर ब्रिटिश सरकार सक्रिय हो उठी और तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड वेल्सली ने नेपालियन के सबूत को टालने के लिए वह बल हटाया। उसने उन भारतीय देशी नरेशों को जिनपर उसको जरा भी शक था बुलंदशेर का काम शुरू किया और फिर स्वयं का सफल नेपालियन का मुकाबला करने के लिए भारत से एक सेना भेजने का व्यवस्था की। यह अग्रजों का सोभाव्य था कि नेपालियन कई कठिनाइयाँ साम्राज्य होकर मिस्र से आगे नहीं बढ़ सका। इस लक्ष्य उठाकर अग्रजों ने माल्टा द्वीप पर अधिकार कर लिया। यूरोप से भारत पहुँचने के सामुद्रिक मार्ग में माल्टा का स्थिति अत्यन्त महत्वपूर्ण था और इस द्वीप पर आधिपत्य जमाने से ब्रिटन मुख्यतः इसी तथ्य से प्रेरित हुआ था।

नेपालियन के मिस्र से चले जाने के तुरंत बाद फ्रांस और ब्रिटन के बीच आमिषों का संधि (Peace of Amiens) हो गया और दोनों देशों के बीच युद्ध बंद हो गया। आमिषों की संधि का एक उक्त यह था कि ब्रिटन माल्टा का गणराज्य को लौटा देगा। लेकिन भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा के लिए माल्टा का भी महत्व था उसको ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने उस द्वीप का गैरानुमति से हथियार कर लिया। 1803 में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच पुनः जो युद्ध छिड़ा उसका मुख्य कारण यही था। इस तरह नेपालियन के पक्षों के विस्तार में भारत एक निर्णायक तत्त्व साबित हुआ।¹

1815 में वियना कांग्रेस में ब्रिटन ने केप ऑफ गुड हाउ (Cape of Good Hope) पर दावा किया और कांग्रेस ने नेपालियन की पराजय के उपरान्त जो प्रस्ताव व्यवस्था की उससे अनुसार केप पर ब्रिटेन के अधिकार का मान लिया गया। केप ऑफ गुड हाउ पर अपना अधिकार जमाने के लिए ब्रिटन उन्हीं कारणों से प्रेरित हुआ था जिन कारणों से उसने माल्टा पर अधिकार जमाया था।²

इस का अर्थ—नेपालियन का पराजय के बाद से बीसवीं सताब्दी के प्रथम तर्क तक ब्रिटिश कूटनीति का एक अंग के रूप में रहता रहा। भारत पर अपना आक्रमण की तयारकियत योजना वर्षों तक अग्रजों के लिए सरल बना रही। भारत

1 M Prothero *The Development of the British Empire* p 80

2 Taraknath Das *India in World Politics* p 17

पर आक्रमण करके उसपर आधिपत्य जमाने की आकांक्षा कभी रूस ने पाला हो या नहीं यह बात संभवतः कभी नहीं मानी जा सकेगी। लेकिन सम्पूर्ण उन्नीसवीं शती में अथवा जलौग रूस के आतंक से अत्यधिक भयभीत रहे। उसका ध्यान था कि रूस विगत ओटोमन साम्राज्य को विगलनकर किसी तरह भूमध्यसागर तक पहुँचना चाहता है। जहाँ से उसका दूसरा नदय भारत होगा। इस सम्भावना को ध्यान में रखकर पश्चिम एशिया में ब्रिटिश कूटनीति अत्यन्त सतर्क हो उठी। ओटोमन साम्राज्य जो उस समय यूरोप का मरीज (Sickman of Europe) कहा जाता था जो बचने के लिए ब्रिटेन ने हर सम्भव उपाय का अवलम्बन किया क्योंकि भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा के लिए ओटोमन साम्राज्य का अस्तित्व परम आवश्यक था।¹

इसी बीच भारत के पश्चिमोत्तर सीमात पर स्थित अफगानिस्तान में सन् 1839 में अंग्रेजों के विभाग में कुछ गड़बड़ हो गई। अफगानिस्तान का जमीर रूष के साथ सौंठ गँठ कर रहा है। इस कारण उस युद्ध में रूसी प्रभाव के जमाने की सम्भावना बहुत बढ़ गयी थी। भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अंग्रेज ऐसा होने देना नहीं चाहते थे। 1839-42 का प्रथम अंग्रेज-अफगान युद्ध (First Anglo-Afghan War) इसी नीति का परिणाम था। 1853 के क्रिमिया युद्ध (Crimean War) और उसमें ब्रिटेन की भूमिका का भी हम भारतीय नीति के सन्दर्भ में ही समझ सकते हैं। इस युद्ध में ब्रिटेन एक ही उद्देश्य में शामिल हुआ था। उद्देश्य यह था कि ओटोमन साम्राज्य की प्राणिक अखंडता पुनर्बल प्राप्त हो सके। ब्रिटेन को यह भय सदा बना रहता था कि यदि ओटोमन साम्राज्य पतन हो गया तो यूरोप और भारत के बीच सीधा सम्पर्क स्थापित हो जायगा। यह स्थिति भारत में साम्राज्य की सुरक्षा के लिए अत्यन्त सतर्कता माननी जाती थी। 1878 के बर्लिन सम्मेलन (Berlin Congress) में ब्रिटेन इसी उद्देश्य से शामिल हुआ था। बर्लिन की संधि (Berlin Treaty) द्वारा साइप्रस के द्वीप पर इंग्लैंड का अधिकार कायम हुआ। भूमध्यसागर से भारतीय साम्राज्य तक जाने वाले मार्ग को सुरक्षित रखने के लिए साइप्रस के द्वीप का विशेष महत्व था। इस कारण ब्रिटेन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं मान सकता था जो साइप्रस द्वीप का किसी दूसरी शक्ति (Power) के हाथ में सौंप दे—जो शक्ति जो बाद में चलकर ब्रिटेन का विरोधी हो जाय। विशेषतः 1869 में स्वयं नहर के खुल जाने से यह द्वीप और

1. On the Red Sea at a subervient Turkey was considered preferable to a higher one in Russia and for the next hundred years the British Government became absorbed in wars and intrigues in the Near East. The first had a single purpose to restore the old boundaries of the Turkish Empire so that it should remain in occupation of the road to India.—R. A. Reynolds *India as an International Problem* *The Modernist* May 1930 p. 578

महत्त्वपूर्ण हो गया था। शुरु में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय साझा-ब का मुद्दा को लिए स्वयं नहर के महत्त्व को नहीं समझा था। लेकिन बाद में प्रधान मंत्री डिन्ग्लो ने इसके महत्त्व का समझा जो अब हमें पता चला कि स्वयं-हरे पर ब्रिटन का प्रभाव कोयम कर लिया।

स्वयं नहीं पर प्रमुख वायन रज्जुन के लिए निम्न तथा मूहान का निर्माण किया गया में वायन वायन हा गया जो 1874 के वायन मित्र की राजनीति में ब्रिटन निरंतर हस्तक्षेप करने लगा। 1887 में मित्र न मित्र का लपन लाघाव न के लिए और इसके द्वारा ही मित्रों द्वारा मूहान और मानानिर्देश पर भी उनके अधिकार वायन हा गया। इस समय का वायन कि मित्र पर मित्र का अधिकार अस्वादी है लेकिन इंग्लैंड के मात्रा-मदानी मंत्रालों का इस समय पर स्पष्ट दृष्टि कायम है। दृष्टिकोण यह था कि - हे मित्र न समय और बिना हानत न मित्र ने नह हटना न। भारतीय साम्राज्य का रक्षण के लिए स्वयं नहर पर अधिकार रमना आवश्यक था और स्वयं नहर पर निर्माण अधिकार का वायन रज्जुन के लिए मित्र पर निर्माण प्रमुख भी आवश्यक था।

[illegible]

1 Britain's continual interference in Egyptian politics which followed this event (purchase of Suez Canal's share) may be traced chiefly to the military necessities arising from the Indian Empire. —Ibid.

2 The possible loss of effective control over the Mediterranean and the Suez Canal and the naval base at Singapore which were regarded as vital for the safety of the Indian Empire.

अन्तर्राष्ट्रीय समझौते और भारत—यह दृष्टि ब्रिटन ने दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रों — साथ जो महत्वपूर्ण संधि समझौते किये उनमें भी भारत को हिस्सा नहीं दिया। 1902 का एंग्लो जापानी संधि (Anglo Japanese Treaty) में भारत की चर्चा प्रत्यक्ष रूप से की गयी थी। इसकी दो धाराएँ (1 और 3) मुख्यतः भारत से सम्बन्ध थीं। इनमें कहा गया था कि यदि कम्प्यूटर द्वारा राज्य ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे पूर्वी एशिया और भारत की सुरक्षा पर कोई खतरा पड़ेगा। 1907 की एंग्लो रूसी संधि (Anglo Russian Convention) के साथ भी लगभग ऐसी ही बात थी। तब तक फारस और अफगानिस्तान में रूस अपना साम्राज्यवादी जाल फला रहा था। भारतीय सुरक्षा पर इसका प्रभाव पड़ना अवश्य भावी था। इसलिए ब्रिटन ने रूस की तरफ से निश्चित हानि के लिए 1907 में उससे साथ संधि कर ली।

यह संधि की पृष्ठभूमि में एक दूसरी बात भी थी। 1878 की बर्लिन संधि के बाद ऑटोमन साम्राज्य की प्रति ब्रिटन के प्रति प्रतिवृत्ति बढ़ गई थी। अब वह ऑटोमन साम्राज्य के स्वतन्त्र अस्तित्व को भारतीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं मानता था। अतएव ऑटोमन साम्राज्य में उनकी रुचि निरंतर कम होने लगी। इसी बीच जर्मनी का स्ट्रिटिनोवुन में अपना प्रभाव जमाने का काम शुरू किया और बर्लिन बाग़दाद रेलवे (Berlin Baghdad Railway) की योजना बनायी। इस रेलवे की योजना से भारत की सुरक्षा पर प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न हो गया। ब्रिटन ने इस योजना का बड़ा-बड़ा विरोध किया। फलतः योजना कार्यरत नहीं हो सकी और अन्तिम बग़दाद रेलवे की योजना आगे नहीं बढ़ पायी। फिर भी पूर्व में नवीन जर्मनी के साम्राज्यवाद की शक्ति बढ़ने लगने लगी थी जो उसने हमेशा अपने पुराने दोस्तों — साथ समझौता कर लेना ही उचित समझा। इससे पूर्व 1904 में फ्रांस के साथ उसका समझौता (Anglo French Entente) हो चुका था। लेकिन जर्मनी की महावाकांक्षा को कुचलने के लिए केवल फ्रांस के साथ समझौता पर्याप्त नहीं था। अतएव 1907 में रूप के साथ भी ब्रिटन ने समझौता किया और फ्रांस के साथ तथा ब्रिटन को मिलाकर एक त्रिपुट (Triple Entente) का निर्माण हुआ। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के विस्फोट के पूर्व के यूरोपीय कू नीति इतिहास को भारत में प्रभावित किया। भारत के इतिहास काई विरोधी साम्राज्यवादी शक्ति किताबें भरह आना प्रचुरता न कायम कर सकें इसे रोहन — लिए ब्रिटन।

pire c si the freedom of a number of countries. Protection of India has been an important motive in British aggression in Persia, in Mesopotamia, in Afghanistan, in Tibet, in Burma, even in Egypt and the Mediterranean. In the history of European diplomacy during the last century, India must call attention on every page so far reaching has been her influence.

—P. T. Moon, *India's Role in World History*, p. 311

वस्तुतः एक भारतीय मुनरो निद्वान्त (Indian Monroe Doctrine) का प्रतिपादन किया था जिसका अर्थ था किसी भी मूल्य पर भारत के पड़ोस में किसी भी यूरोपीय देश के साम्राज्यवाद को नहीं पनपने देना।¹

साम्राज्यवादी प्रसार में भारत का योग—ब्रिटिश साम्राज्यवाद और यूरोपीय साम्राज्यवाद के लिए भारत का एक और महत्व था। भारत अनश्वर और अथ नाशनों का अपार भंडार था जिनका प्रयोग दूसरे देशों को पराधीन बनाने के लिए भी किया जाता था। भारत सरकार एक विशाल सना रखती थी। इसके दो प्रमुख काम थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कुचनना और एशिया के अथ भागों में ब्रिटिश साम्राज्य का प्रसार करना। वस्तुतः भारत ब्रिटेन की सैनिक शक्ति का मुख्य केन्द्र बिंदु था। पास-पड़ोस के देशों में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का पनाव भारतीय सना और नाशनों के प्रयोग से ही सम्भव हो गया था। 1839 में चीन के विरुद्ध पहले पहल भारतीय सेना का प्रयोग किया गया। चीन की सरकार ने एक इंडिया कम्पनी के अधिकार के आधार पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन अफीम के व्यापार से अमेज व्यापारी बन् जधिक नान किया करते थे। अतएव उन्होंने तत्कालीन चीन में अफीम पहुँचाता रह किया। जब चीन की सरकार ने एक विरुद्ध कारवाही का तो कइ तरह का बहाना बनाकर अफेजों न चीन के खिलाफ युद्ध उद्घापित कर दिया। अफाम के व्यापार को लेकर कुछ वर्षों बाद चीन के साथ एक दूसरी लड़ाई भी (1857 में) हुई। इन दो युद्धों के फलस्वरूप विदेशियों के लिए चाना तरवाडा जबरन स्वीकृत किया गया और बड़ी सन्ध्या में यूरोपीय लोग उसमें बलान् प्रवेश कर गये। फिर चीनी उखूडा को काटने (Cutting of the Chinese Melon) का युग आया और चीन यूरोप के साम्राज्यवादियों के प्रभाव क्षेत्र (sphere of influence) में विभक्त हो गया।

अफगानिस्तान के साथ भी कुछ ऐसी ही बात हुई। भारत के इन पड़ोसी देश के साथ ब्रिटिश भारतीय सरकार ने तीन युद्ध किए—1839, 1878 तथा 1919 में। इन युद्धों में अपार धन का व्यय हुआ और यह सारा खर्च भारतीय सन्धान से किया गया। अफगानिस्तान के विरुद्ध सैनिक कारवाहियाँ में जिस सना के प्रयोग हुआ वह भारतीय सेना थी। यद्यपि अफगानिस्तान पूरी तरह कभी नहीं जीता जा सका और उसपर प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन नहीं स्थापित हुआ लेकिन इन युद्धों के फलस्वरूप वहाँ के अमीर यूँ ही तह अफेजों के प्रभाव में आ गया। उसकी अपनी शक्ति की

1 The foreign relations of India are regulated by a kind of unwritten Monroe Doctrine. I mean that we maintain over all the countries immediately adjacent the policy of allowing no intervention by other European nations and the predominance of no influence except our own. It is this necessary attitude that gives us incessant occupation abroad in Asia and bringing us into continual contact or collision with European rivals.—Mortimer Durand *Life of Alfred Lyall* p. 398

वैदेशिक नीति पर कोई नियम नहीं रहता। आंतरिक बातों में भी वह अंग्रेजों की मर्जी के बिना सामान्यतः कुछ नहीं कर सकता था।¹

इसी तरह बीसवीं सता की प्रारम्भ में दक्षिण अफ्रीका के बोअर लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध शुरू किया। इस युद्ध में अंग्रेजों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। हताश होकर ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश भारतीय सरकार से सैनिक सहायता माँगी। उस समय भारत का वायसराय लार्ड कर्जन था। उसने तुरंत ही भारत से दक्षिण अफ्रीका के लिए एक विमान सेना भेजने का प्रबंध किया और बोअरों को कुचलने में भारतीय सेना का प्रयोग अत्यंत ही प्रभावकारी रूप से किया गया।²

तिब्बत पर ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित करने के लिए भी भारतीय सेना और साधनों का प्रयोग हुआ। तिब्बत शुरू में एक अलग स्वतंत्र और चीन का संरक्षित राज्य था। भारत और चीन के मध्य में इसकी स्थिति अस्पष्ट महसूस होती थी। अंग्रेजों और ब्रिटिश सरकार ने इस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य कायम करने का निश्चय किया। ब्रिटिश विद्वान मन्नाथ लाल ने यह कहना शुरू किया कि तिब्बत की आरंभ में भारत पर आक्रमण होने का संतरा बहुत बढ़ गया है। अतएव इसकी ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया है। पहले ब्रिटिश सरकार ने अपने एजेंट जामुसो को बोर्ड भेजा तथा उपद्रवों के रूप में तिब्बत भेजकर गुप्त रूप से वहाँ का नक्शा तैयार कराया। फिर तिब्बत का राज्य सीमा का सफाया करा दिया गया और इस बाद विवाद को तय करने के लिए बनस गणहसबंद का निश्चय भेजा गया। लेकिन बनस गणहसबंद ने राजतंत्र के रूप में न जाकर भारतीय सेना की एक टुकड़ी के साथ 1904 में तिब्बत में प्रवेश किया और दलाई लामा का डरा धमकाकर तिब्बत का एक संधि करने के लिए बाध्य किया। गणहसबंद विमान के सैनिक अभियान के तमाम लगभग डेढ़ हजार तिब्बती मारे गए पर उन तिब्बतियों को हटा इसकी प्रतिवर्ति करनी पड़ी। इसका नाम तिब्बत परी तरह ब्रिटिश भारतीय शासन के नियंत्रण में आ गया।

इस तरह के कई अन्य ऐतिहासिक उदाहरण उस तथ्य का सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत किए जा सकते हैं कि ब्रिटिश ने संसार के अन्य भागों में अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए भारतीय जन शक्ति और साधनों का सफल प्रयोग किया और भारत को उसने अपना विश्वव्यापी साम्राज्य का नींव का आधार-स्तंभ बनाया।

1 P T Moon op cit pp 274 9

2 Earl of Ronaldshay *The Life of Lord Curzon* Vol II p 68

3 It is the Indian soldiers who as mere mercenaries fought for the East India Company and other foreign concerns and powers even against their own people. It is a historical fact that through the control of India's trade and power resources and strategic position Great Britain has succeeded during the last three centuries to expand in all Southern Asia.

ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लिए भारत की स्थिति का एक और उपयोग था। पण्डित के बसाव के स्वतन्त्रता संग्राम का कुचलन के लिए भारतीय सना का बसवों का प्रथम भाग से खलकर प्रयोग किया गया। सत्तर के किसी भी भाग में पण्डित ने मन्त्रित पान के लिए किसी स्वातन्त्र्य आन्दोलन के छिड़ने पर भारत से तुरन्त सना भगा जाता था और उसका कुचला जाता था। भारतीय सना हमेशा युद्ध का स्थिति में रखा जाता था और कुछ ही क्षण का सूचना पर वह एशिया और अफ्रीका के किसी काने में भेजा जा सकती थी। इस प्रकार लगभग दो सन्धियों तक भारत नगर में साम्राज्यवाद का प्रभाव बना रहा। इसी कारण एक मित्रा नागरिक ने जल्द से जल्द होकर एक भारतीय से कहा था आप भारतीय कवन अपना ही स्वतन्त्रता नहीं छो बैठे हैं बल्कि आप दूसरा की स्वतन्त्रता के अपहरण में भाग लेने की सहायता करते हैं।

ब्रिटिश साम्राज्यवाद का व्यवस्था में भारत का एक केन्द्रीय स्थिति को देखकर नागरिक न कहा था भारत जिब्राल्टर में शुरू होता और हांगकांग में खत्म होता है (India begins from Gibraltar and ends at Hongkong)। इस विचार को विचार मूल्यांकन पर टिप्पणी कि नागरीय राज्य का प्रभाव महान नहीं कर सकता था। 1904-5 के बचत के अवसर पर इन्डियन इम्पेरियल कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए लॉर्ड बजल न कहा था भारत एक विचार कि नागरिक के समान है ना दो तरफ समुद्रों से आर एक तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है लेकिन इन बाधाओं के बावजूद एक टायुर्जॉ किनारा है हम नहीं चाहते कि इनपर हम अपना अधिकार कायम कर दें। लेकिन हम इस बात को अनुमति भी नहीं दे सकते कि कोई दूसरी शक्ति इनपर कब्जा कर ले। हमला करने वाले सहयोगियों और मित्रों के प्रभाव में अपने को तयार है लेकिन यदि कोई विराघा शक्ति हमसे घुस जाय और यहाँ अपना अंग बना ले तो हम बिना हम्नहो जिय नहीं रह सकते। यदि हम ऐसा नहीं करने और विदेशी शक्तियों का मुँह जमान का अन्तर द देते हैं तो उस अवसर में स्वयं हमारा सुधा खतर में पड़ पायेगा। अरविदा फारस अफगानिस्तान ईरान और म्याम के प्रति ब्रिटिश नाति का यहाँ रहस्य है।¹ इस विचार का बाद में लॉर्ड बजल ने

Africa and Australia India is the key stone of the arch of the British Empire today The great misery of China and the subjugation of various Asiatic peoples even those of Egypt have been brought about by the Indian soldiers and by using Indian resources —T N Das Indian World Politics p 8

1 India is like a fortress with the vast moat of sea on two of her faces and with mountains as her wall on the remainder But beyond these walls which are sometimes of by no means insuperable height and admit of being easily penetrated extends a glaciis of varying breadth and dimensions we do not want to occupy it but we also cannot afford to see it

अपनी एक पुस्तक में और विस्तृत रूप से चर्चा की। बजन ने लिखा कि भातीय साम्राज्य दूसरे के तृतीय महत्वपूर्ण स्थान में है लेकिन उसकी इस महत्वपूर्ण स्थिति का सबसे अधिक और निर्णायक प्रभाव उसके पड़ोसी देशों पर पड़ता है। भातीय निष्कर्ष मध्य देशों का भाग्य भारतीय घुरी पर आश्रित है।¹

इस प्रकार उपभोग दा गताश्रितों तक भारत विश्व राजनानि का एक महत्वपूर्ण तत्व बना रहा। इस काल में अपनी महत्वपूर्ण स्थिति से अपने ब्रिटिश विश्व नानि को निगाह से हटाने में प्रभावित किया। अतर्ही द्वीप देश में ब्रिटन का एक मार्ग भातीय महत्वपूर्ण नानि की स्थिति जिसका निर्धारण भारत पर साम्राज्य की स्थिति में की गया हो। पार्थीन होत हुए भी रत चाहे अनचाहे विश्व राजनानि विश्व पर अपनी पड़ोसी राष्ट्रों में घटनेवाली घटनाओं का प्रभावित करता रहा।

(१) भारत का अंतराष्ट्रीय व्यक्तित्व का विकास

(Development of India's International Personality)

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पहले अर्थात् 15 अगस्त 1947 के पूर्व अन्तराष्ट्रीय राजनानि के क्षेत्र में यद्यपि भारत एक महत्वपूर्ण नामका अंदाज़ में रहा पर अंतराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत उसकी कोई स्थान प्राप्त नहीं था। परन्तु मामलों की तरह के विश्व नानि के क्षेत्र में भी वह पूणतया न स्थित नानि का पक्ष के अश्वीन था और न किसी प्रकार का अंतराष्ट्रीय व्यक्तित्व (International personality) प्राप्त न था। भारत के संबंध में अंतराष्ट्रीय नीति का निर्धारण भारत सरकार नहीं करती थी। यह काम ब्रिटिश सरकार का था। भारत सरकार के बल में भारतीय नीति का निर्धारण अन्तर्निष्ठ व्यापार साम्राज्य के हितों को ध्यान में रखकर करती थी।

occupied by our forces. We are quite content to let it remain in the hands of our allies and friends but if they are unfriendly and if they are a menace to our interests we are compelled to intervene because our interests would otherwise be gravely imperilled. It is a threat to the whole position in Arabia. Persia, Afghanistan, Tibet and as far as India and as Sam

—Quoted in Guy Wint *The First World War* p. 23

1. *The Indian Empire in the strategic sense of the third imperialist position of the globe. But her central and commanding position is no better seen than the political influence which she exercises over the destinies of her labouring races and extent to which their future revolves upon an Indian axis.* —Curzon *Problems of the Far East* pp. 9-10

इम्पीरियल कांफ्रेंस (वामनवेत्य) में भारत का प्रवेश

औपनिवेशिक सम्मेलन—ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन—भारत आने व लक्ष्मण तीन वर्ष बाद ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत भारत का स्थिति में प्राप्त हुआ। कुछ परिवर्तन होने शुरू हुआ। इस परिवर्तन में पहला औपनिवेशिक सम्मेलन (Colonial Conference) और बाद में इम्पीरियल कांफ्रेंस (Imperial Conference) ने प्रमुख भूमिका अदा की। जहाँ औपनिवेशिक सम्मेलन तथा इम्पीरियल कांफ्रेंस के नाम भारत के सम्मेलनों के इतिहास का अध्ययन आवश्यक प्रमाण होता है। इसके द्वारा हम इस तथ्य का समन्वय में सुनिश्चित होगा कि भारत ने किस प्रकार पर ध्यान प्राप्त हुए भाषित काल में एक निर्धारित रूप में अन्तराष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त कर लिया था।

औपनिवेशिक सम्मेलन का प्रारम्भ 1887 में हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य के स्वशासी उपनिवेशों (Self governing Colonies) से सामान्य सम्मेलन पर विचार विमर्श करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने एक संस्था का रूप ग्रहण कर लिया। 1887 में महारानी विक्टोरिया के शासन का स्वयं उत्पत्ता में सम्मिलित होने के लिए स्वशासी उपनिवेशों के प्रधान मंत्रियों ने आम आम हुए थे। इस अवसर पर सामान्य रूप से ब्रिटिश सरकार ने उनके साथ विचार विमर्श करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसका औपनिवेशिक सम्मेलन का नाम दिया गया। बाद में इस औपनिवेशिक सम्मेलन का नाम बदलकर इम्पीरियल कांफ्रेंस रख दिया गया।¹ 1887 के प्रथम औपनिवेशिक सम्मेलन में भारत को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला। 1897 के द्वितीय औपनिवेशिक सम्मेलन और 1902 के तृतीय सम्मेलन में भी भारत का प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया।² इस समय तक भारत में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ था और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (Indian National Congress) का स्थापना के बाद से भारतीय जनता के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई। उन अवस्था में कांग्रेस पर भारी नजरों का प्रभाव था जो ब्रिटिश शासन का प्रतिनिधित्व में अत्यधिक विरोध रखता था। इन कारणों ने बहुत ही जल्दी भारत के औपनिवेशिक सम्मेलन में सम्मिलित करने के लिए। ब्रिटिश ब्रिटिश राजशाही ने भारत को इस भाँति का समन्वय दिया। जिससे मुक्त संसद दूसरी कांग्रेस ने कहा कि औपनिवेशिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्रिटिश भारतीय सरकार का प्रतिनिधित्व होना करने भारतीयों का भी आनंदित किया

1 H D Hall *The Indian Commonwealth of Asia* pp 9-98

2 Notes on the Status and position of India in the British Empire Memorandum presented to the Indian Statutory Commission by the Government of India *Papers of the Indian Statutory Commission* (1930) Vol V p 1333

जाना चाहिए। वह व्यक्ति भारतीय लेजिस्लेटिव कौमिल का गर सरकारी सचिव हो सकता है।¹

इन तर्कों के फलस्वरूप 1907 के औपनिवेशिक सम्मेलन में भारत को अस्थायी रूप से (on ad hoc basis) भाग लेने का मौका मिल गया। भारत सचिव लाइ माले की अनुपस्थिति में इण्डिया ऑफिस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी जम्स मके ने सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। औपनिवेशिक सम्मेलन में भारत की स्थिति स्वशासी उपनिवेशों के मद्देन नहीं थी लेकिन सम्मेलन का प्रमुखता का अवसर उसे अवश्य मिला गया।

इम्पीरियल कांफ्रेंस—1907 के औपनिवेशिक सम्मेलन का चौथा अधिवेशन कांफ्रेंसियों में महत्वपूर्ण था। इसने सम्मेलन को एक स्थायी रूप प्रदान कर उसमें लिए एक विधान तैयार किया। औपनिवेशिक सम्मेलन (Colonial Conference) का नाम बदल कर इम्पीरियल कांफ्रेंस (Imperial Conference) रखा गया तथा स्वशासी उपनिवेशों (Self governing Colonies) के बने कनाडा यूजीलण्ड दक्षिण अफ्रीका यूफाउलंड आदि को डोमिनियन (Dominion) कहने का निर्णय किया गया। यह तय हुआ कि इम्पीरियल कांफ्रेंस में अब से केवल मंत्री स्तर के व्यक्ति ही अपने अपने देशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। लेकिन भविष्य के इम्पीरियल कांफ्रेंस में भारत के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं किया गया। इसका एक कारण था डोमिनियनों के प्रतिनिधि भारत को समान दर्जा देने का तयार नहीं थे। वे भारत की स्थिति को अत्यंत निम्न मानते थे और उसको अपने से कम दर्जा देते थे। उनका कहना था कि भारत एक स्वशासी डोमिनियन नहीं है और इसलिए कांफ्रेंस का द्वार उसके लिए नहीं खोला जा सकता। ब्रिटिश डोमिनियन का राज प्रजातीय भेदभाव का भी समर्थन थे और नहीं चाहते थे कि देशों के संगठन में बाल योग घुस जाय। इन कारणों से प्रेरित होकर इम्पीरियल कांफ्रेंस में भारतीय प्रवेश का उन्होंने बड़ा प्रबल विरोध किया।² इसलिए 1911 के इम्पीरियल कांफ्रेंस में अधिवेशन में भारत को फिर सम्मिलित नहीं किया गया। कुछ समय के लिए भारत सचिव सम्मेलन के अधिवेशन में बैठे अब ये लेकिन ऐसे सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व या सम्मेलन की भारतीय सचिवता नहीं माना जा सकता।

लेकिन 1911 के बाद परिस्थितियाँ धीरे धीरे भारत के पक्ष में होने लगीं। भारत जिस सम्मेलन में प्रतिनिधित्व की माँग कर रहा था वह अब औपनिवेशिक सम्मेलन नहीं रह गया था उसका नाम अब इम्पीरियल कांफ्रेंस हो गया था। इस नाम परिवर्तन का भारतीय दृष्टि से महत्व था। सम्मेलन के साथ इम्पीरियल कांफ्रेंस जुड़ जाने से इसका स्वरूप पहले की ओर अधिक व्यापक हो गया था।

1 158 H C Deb 45 Col 1780

2 S R Mehrotra *India and the Commonwealth* p 91

भारत के बिना इस इम्पारियल काँग्रेस कहना उतना ही श्वेत प्रतीत हो रहा था जितना प्रिंस आफ डेनमार्क के बिना स्मॉल नाटक खेलना । ब्रिटिश साम्राज्य का भारतीय साम्राज्य के कारण हिंस्र इम्पारियल मजस्टी (His Imperial Majesty) का उदात्ति प्राप्त था । इस द्वायत में इम्पारियल काँग्रेस में भारत की अनुपस्थिति सदको खटक रहा थी जमा तक सम्मेलन में ऐसा बरत जो बातों पर बात बिकार हाँका रहा था जिसमें इन्डिया आस्टिस से बिचार किया जाता था । यह इस बात का प्रमाण था कि काँग्रेस में भारत का हित — ना = महत्वपूर्ण — बिना अन्य दामिनिधियों का । ऐसी स्थिति में भारत का उल्लास करना या काँग्रेस में "सक" "का" को राखना नरामर अनुचित माना जाना लगा ।

राउण्ड टबल—इम्पारियल काँग्रेस की संस्था भारत का भिन्न स्वतंत्र समूह बना सम्पन्न इंग्लैंड का एक राउण्ड टबल ग्रुप (Round Table Group) था । यह कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों पत्रकारों और राजनीतिज्ञों का एक मुठ था जो भारतीय समस्या का अध्ययन साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से करता था ।¹ इसके सम्मुख भारत में बनी हुई राष्ट्रीयता के दम को कम करने के लिए ऐसे लोगों को निजाने के लिए पापी और चिंतन किया करते थे जिससे भारतीय प्रभावित होकर ब्रिटिश साम्राज्य के भाग सहयोग करते रहें । इस ग्रुप के सम्मुख समाचार पत्रों में नए निष्कर्ष पुस्तकें प्रकाशित कराके तथा ब्रिटिश संसद में प्रश्न पूछकर २० या रियल काँग्रेस में भाग ले कर प्रश्न का माग का समयन करते रहे और इसके लिए उन्होंने एक मातृका आन्दोलन का स्थापना किया । उनके इस आन्दोलन का बड़ा प्रभाव ११वीं ब्रिटिश राजनीतिज्ञों समाचार पत्रों और संसद के सम्मुख का समयन प्राप्त था । उसके प्रयासों के फलस्वरूप ब्रिटिश संसद में भारत के सम्बंध में नए प्रश्न उठने लगे ।²

प्रथम विश्व-युद्ध का प्रभाव—१९१४ में प्रथम विश्व युद्ध के दिनों में नए आन्दोलन को बड़ा बल मिला । युद्ध दिनों पर भारत न "श्वेत" का पूरा समर्थन किया और हर तरह के भारतियों न इंग्लैंड की पूरी सहायता देने का आवाहन किया । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस न युद्ध पर एक प्रस्ताव पास करके ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति अपना राजसमर्थन का एरोप और भारतीय नरिस्तनत्रिय कोमिल न भा एक प्रस्ताव स्वीकार कर ब्रिटिश सरकार का हर तरह की भारतीय सहायता के बचन दिया । भारतीय सेना युद्ध के कर्मियों पर पेशा युद्ध में उनमें सक्रिय भाग लिया और गज को हराते में महत्वपूर्ण योगदान दिया ।

१ राउण्ड टबल (Round Table) के प्रमुख लोगों में निम्नलिखित व्यक्ति थे—एन एम जेम्स राबर्ट्स, राबर्ट मर्चिन बल्लगान, गिराल्ड रेजिनाल्ड हूबर्ट, सिप्रास कर्जिस, जियाक हावसन फिनिश, वी ए मल्लम, विलियम मरिस, जेम्स मस्टन, थॉमस विल्लेवर तथा ए. ई. रिचमंड आदि ।

युद्ध में भारतीयों की देन उनका यद्ध प्रयास तथा उनकी राजमणि न मम ज राजनीतिज्ञों का बहुत हद तक प्रभावित किया और उनकी ओर से भारत की इम्पीरियलिस्ट का फँस की स स्थिति लाने का प्रयास होने लगा। डोमिनियनों में भी भारत के समर्थकों की संख्या बढ़ने लगी। उनमें से बहुत जो पहले भारत के विरोधी थे अब उमड़े समय के बन गये। परिस्थितियों में 12 गितम्बर 1916 को मुद्रम्भ की मे भारतीय लेजिस्लेटिव कौंसिल में एक प्रस्ताव पेश करने यह माँग की कि भारतियों के युद्ध प्रयास का हान में रक्षित हुए भारत का इम्पीरियलिस्ट का कद की स स्थिति तत्काल दो जाय। मदन मोहन मालवीय ने यह प्रस्ताव का समर्थन किया और यह आश्वासन दिया कि जैसा कि संभव हो सकेगा वह भारत को इम्पीरियलिस्ट का कद की मददस्थिति लाने के लिए हर सम्भव उपायों का प्रयोग करेगा। लेजिस्लेटिव कौंसिल ने इस प्रस्ताव को एक प्रबल बहुमत से स्वीकार कर लिया।

मन्त्र वाद लाड लाडिज ने इस समय मन्त्रिणा अंग्रिस स पर्ष पनाचार विध ओर ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला कि वह भारत को इम्पीरियल का कग के सन्धय ने रूप मे स्वीकार कर ले । उसका उत्तराधिकारी लाड वम्सफोर्ड भी मन्त्रिणा मे चलन करता रहा । उसने इस समय मन्त्रिणा न विधे । ज न मन्त्रिणा अंग्रिस भी निरन्तर इस दिना मे प्रयत्न करती रही । लाड लाडिज ने अपना आ नन और ध्यापक कर दिया । इसी प्र प का एक व्यक्ति फिलिप कर उस समय ब्रि ग प्रान मन्त्री लामड जाज (Lloyd George) का प्राइवेट सेक्रेटरी था । उसने प्रगान मन्त्री को हर तरह से प्रभावित करने सिद्धांत मे इस धान को स्वीकार करा दिया कि भारत को इम्पीरियल का मन्त्र को स सयना मिल जानी चाहिए ।

प्रथम विश्व युद्ध-न सभी पुरानी व्यवस्थाओं को प्रभावित किया। इस युद्ध में भारत तथा अन्य सभी डोमिनियन प्रमुख भाग ले रहे थे और वे हम जान की माँग करने लगें कि ब्रिटिश साम्राज्य का नाति निर्धारक मण्डल में परिवर्तन हो और इस काम में उन्हें भी हिस्सा बंटाने का अवसर मिले। इसी तरह ब्रिटीश विदेश नीति का निर्धारण में डोमिनियन सरकारों से किसी तरह का विचार या परामर्श नहीं किया जाता था। लेकिन उनका कहना था कि ब्रिटीश विदेश नीति से उनका जाजावन प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है और इसलिए इसके निर्धारण में उन्हें भी हाथ बाने का अवसर मिलना चाहिए। डोमिनियन सरकारों की यह माँग अत्यन्त प्रबल हो गयी और अन्त में ब्रिटीश सरकार को मजबूत पड़ा। 19 नवम्बर 1916 को प्रधान मंत्री सायड जाव ने यह घोषित किया कि युद्ध और विदेश नीति पर ब्रिटीश सरकार डोमिनियन सरकारों से विचार विमर्श करने का मिला तयार है और इसका मिला मोझ ही काम उठाया जाएगा। इसके पिले ब्रिटिश सरकार ने इम्पीरियल वॉर कन्वन्ट (Imperial War Cabinet) और इम्पीरियल वॉर कॉर्गेस (Imperi-

1 Proceedings of the Council of the Governor General
1915-16 vol LIV pp 41-43

महाने वाले शान्ति सम्मेलन में भारत को अब यह प्रतिनिधित्व मिलेगा। इनसे दोनों के अधिकारों को रक्षा में उत्तरे में लाना था। इस हालत में यह बात नीय थी कि भारत को भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के निर्माण में बोलने तथा हिस्सा बंटाने का अवसर मिले। नवम्बर 1918 में जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ वैसे ही शान्ति सम्मेलन में डोमिनियन तथा भारत के प्रतिनिधि के का भवान गम्भोर रूप से उठ खड़ा हुआ। 47 अक्टूबर 1918 को जब युद्ध की समाप्ति का सम्भावना दिखने लगी तब लायड आर्जनेट ने इम्पीरियल कॉन्फ्रेंस को बठक बुलायी। ब्रिटिश सरकार शान्ति परिषदों की रूपरेखा के सम्बन्ध में डोमिनियनों और भारत में कार्रवाई के कोण का जानना चाहता थी। इस सम्मेलन में भारत की तरफ से एस. पी. मिह्रा और बोस्चर के सहाराजा सम्मिलित हुए। युद्ध का अन्त करने वाली जो विराम संधि हुई थी उसके सम्बन्ध में डोमिनियनों तथा भारत में कोई विचार विमर्श नहीं किया गया था। अतएव डोमिनियनों को यह आभास था कि शान्ति-सम्मेलन में भी उनका प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा सकता है। लेकिन डोमिनियनों शान्ति सम्मेलन में भाग लेने के लिए बड़ी इच्छा थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री राबर्ट बोर्लैंड ने इस प्रश्न का सम्मेलन में उठाया। लार्ड राज ने आश्वासन दिया कि वह डोमिनियनों की माँगों का सर्वोच्च पद्धति पर विचार के समक्ष रखेगा और यह प्रयास करेगा कि शान्ति सम्मेलन में पृथक् रूप से भाग लेने का अधिकार उसे मिले। भारतीय प्रतिनिधि ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि वे भारत के हितों पर भी ध्यान रखेंगे ताकि शान्ति सम्मेलन में भाग लेने का अवसर भारत को भी मिले।

भारत की रूचि—युद्ध के बाद दुनिया की जो रूपरेखा बननेवाली थी उसमें भारत बहुत पहले से रूचि रखता था। वस्तुतः शान्ति सम्मेलन में भाग लेने की भावना में प्रेरित होकर ही भारत इम्पीरियल कॉन्फ्रेंस की सम्मेलन प्राप्त करने के लिए बल्लब था और इसके लिए इसने निरन्तर प्रयास भी किया था। अक्टूबर 1918 में गवर्नर जनरल लार्ड हाडिन्ग ने भारत सचिव को एक गोपनीय स्मरणपत्र भेजा था जिसमें शान्ति सम्मेलन में प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की बात उठायी गयी थी। इस पत्र में कहा गया था कि पणजा अरेबिया तथा मसोरोमिया में भारतीय हित तथा विश्व राजनीति में भारत की भावी भूमिका को ध्यान में रखते हुए शान्ति-सम्मेलन में उसकी पृथक् प्रतिनिधित्व मिलना आवश्यक है।¹ भारत सचिव के नाम गवर्नर जनरल का यह पत्र इस बात का सबूत है कि युद्ध खत्म होने के बहुत पहले ही भारत सरकार शान्ति सम्मेलन में भाग लेने के लिए बेचन थी और किसी कीमत पर इस अवसर का छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी।

सतिपूर्व के प्रश्न में भी शान्ति-सम्मेलन में भारत की रूचि बढ़ा दी। युद्ध काल में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने यह घोषित किया था कि जर्मनी के विरुद्ध युद्ध जारी

समस्या केवल उसी देश का दावा सकती थी जो सावभौम राज्य (Sovereign State) है। 1919 में किंग्डी भा दृष्टिकोण से भारत एक सावभौम राज्य नहीं था। उसकी स्थिति एक उपनिवेश की थी और प्रत्येक राष्ट्र से वह ब्रिटिश सरकार को अलग था। अन्तिम विचारण में उसका दावा ब्रिटेन और बाह्य नितिया का निर्धारण करने से हाता था। अब जब शांति सम्मेलन में यह प्रस्ताव आया कि भारत को राष्ट्रमण्डल में सम्मिलित किया जाय तो राष्ट्रमण्डल विषयक समिति में इसका भार विराज हुआ। राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन (Woodrow Wilson) का कहना था कि भारत की समस्या का लिए स्वायत्तता का सिद्धांत (Principle of self government) का परिणाम नया किया जा सकता है अर्थात् मध्य की समस्या केवल उदात्तता का मित्रता चाहिए जो स्वतंत्र हो।¹ यदि इस सिद्धांत का अपना करके भारत को राष्ट्रमण्डल की समस्या दे दी जाती है तो दूसरे उपनिवेश भी इसके लिए अपना दावा पेश कर सकते हैं। ब्रिटिश प्रतिनिधि जार्ज रॉबर्ट सेसिल (Robert Cecil) ने इसके जवाब में कहा कि भारत के साथ इस सिद्धांत का अन्वय नहीं किया जा सकता और कई मान में भारत को स्वायत्तता का अधिकार नहीं है। ब्रिटिश सरकार का यह है कि उपनिवेश स्वायत्तता का स्वयं देने का इरादा रखना = 1²

जस यां विचार में दक्षिण अफ्रीका के जनरल स्मूट्स (General Smuts) ने हस्तक्षेप किया और यह बताया कि भारत की राजनीतिक स्थिति जो हो उस राज्य की समस्या अनिवार्य रूप से देनी ही पड़ेगी। भारत का परिणाम के प्रति सम्मेलन में प्रतिनिधित्व मिला है और इस हैमिल्टन में वह वक्ता की सचिवा एक सम्मानित होगा। उस वक्ता की सचिवा की प्रथम छद्म धीमे धाराएँ राष्ट्रमण्डल से सम्बंधित हैं और इस प्रकार भारत अपने आरंभिक राष्ट्रमण्डल के सम्मानित है और इस प्रकार भारत अपने आरंभिक राष्ट्रमण्डल के सम्मानित है। उसको समस्या प्रदान करने का प्रश्न उत्पन्न हो गया है। राष्ट्रमण्डल के विधान (Covenant) में जो स्वायत्तता (fully self governing) का आया है और बहिष्कार के सम्मानों के लिए हैं भारत पर इनको नहीं लागू किया जा सकता = 1³

जनरल स्मूट्स के इस तर्क ने भारत के मनो विरोधियों का मुह बन्द कर दिया और शांति-सम्मेलन ने अपना निर्णय भारत के पक्ष में दे दिया। यह निश्चित हो गया कि भारत राष्ट्रमण्डल का प्रारम्भिक सम्मान होगा। यह भी मान लिया गया कि राष्ट्रमण्डल के सदस्य के रूप में भारत को वे सारे अधिकार प्राप्त रहेंगे जो अन्य पण स्वतंत्र राज्यों का प्राप्त होत। वह राष्ट्रमण्डल की कोमिन और अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय (Permanent Court of International Justice) का

1 S. Baker Woodrow Wilson and World Settlement Vol III p 15

2 D. H. Miller *The Drafts of the Covenant* Vol I pp 164-65

3 Ibid p 166

सदस्य भी बन सकती था। इन सब बातों पर अंतिम निर्णय हो जाने के उपरान्त ही भारत में वसाय की संधि पर हस्ताक्षर किया और वन राष्ट्रमण्डल का सम्बन्ध बना।

राष्ट्रमण्डल में भारत की स्थिति—राष्ट्रमण्डल में भारत की स्थिति अन्तराष्ट्रीय विधिक अन्तर्गत एक विचित्र स्थिति उत्पन्न कर दी। यह बात समझ में आती है कि वह एक देश जिसका स्वयं स्वतंत्र रूप से अपनी आत्मिक नीति का निर्धारण करने का अधिकार नहीं था वरु राष्ट्रमण्डल के सम्बन्ध के रूप में समारंभ के विभिन्न दशा—अन्तराष्ट्रीय व्यवहार और वापसलाप का अब राष्ट्रा के साथ मिलकर नियमित करता। राष्ट्रमण्डल की स्थापना प्राप्त करके अन्तराष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में भारत की स्थिति ही एक उच्च स्थान प्राप्त कर लिया था लेकिन सातहरे सम्मान में वरु पूर्णतः ब्रिटिश सरकार के अधीन था। भारत जनवरी 1919 के भारत सरकार अधिनियम (Government of India Act 1919) के प्रावधानों ने धरो हुआ था जोर इस अधिनियम के अनुसार भारत में व्यवस्थापिका का विधानीति में सम्बन्धित किसी बात पर व समया विचार करने तथा अधिकार नहीं था। यह एक विचित्र स्थिति थी और डेविड हट्टर मित्र ने ठीक कहा कि यह स्थिति में विचित्र (anomaly among the politics) स्थिति कहा था।¹

अन्तराष्ट्रीय सम्बन्ध में हम तरह की विचित्र स्थिति का उत्पन्न करने में ब्रिटिश सरकार के कुछ अपने साथ निहित थे। भारत को राष्ट्रमण्डल की स्थापना प्रदान करने में परिसर का नाति सम्म न म उसका जो प्रयास हुआ उसके पूर्व में एक ही बात थी। ब्रिटिश चाहता था कि राष्ट्रमण्डल के वक्त में स्वयं का मया बड़ जो उनका सम्मान गरह और जो उनके आदगानुसार वही मत द। ब्रिटिश साम्राज्य के डोमिनियन तथा भारत में ही। यहो मत। अब राष्ट्रमण्डल पर अन्तः प्रमुखा वापस करने का मावना से प्रेरित हार ही ब्रिटिश ने भारत को राष्ट्रमण्डल का सम्बन्धता निजाने में मया की थी।²

प्रायः परत की कीथ (A. B. Keith) का कहना है कि राष्ट्रमण्डल की स्थापना ने अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों में भारत का जल स्वतन्त्र्य की स्थिति (Quasi independence in external relations) प्रदान की जिसके परिणामस्वरूप भारत को एक नया अन्तराष्ट्रीय व्यवहार प्राप्त हुआ। इस विषय पर अन्तराष्ट्रीय विधि वेताओं में काफी विवाद हुआ। अन्तराष्ट्रीय व्यवहार प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि राज्य का संधि समझौता करने या युद्ध घोषित करने का पूर्ण अधिकार हो। भारत को इस तरह का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। राष्ट्रमण्डल के प्रति

1. Ibid. p. 13

The British Government was motivated by her selfish interest when it struggled for India's independence for this would secure the material support of India for Britain in her fight for leadership at Geneva.—D. N. Verma, *India's Foreign Policy*, p. 26

3. A. B. Keith, *History of the British Empire*, p. 397

अपनी नाति निवारण करने में भी भारत स्वतंत्र नहीं था। भारत सरकार का अनिवार्यतः भारत मन्त्रिष्वक दावा का पालन करना पड़ता था। प्रारम्भिक सम्मेलन के बाद राष्ट्रमण्डल में भारत की स्थिति अवश्य स्वतंत्र थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार के सम्बन्ध में भारत सरकार एक अशान्तिपूर्ण समस्या थी। इस राष्ट्रमण्डल में वि. व. के उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि राष्ट्रमण्डल की सम्मेलन के बाद भारत एक विगुह अंतराष्ट्रीय व्यक्तित्व का दावा नहीं कर सकता था। डब्ल्यू. ए. हाल (W. E. Hall) ने ठीक ही कहा था कि राष्ट्रमण्डल का सम्मेलन प्राप्त करके स्वशासी डोमिनियन जार भारत ने जव है। अंतराष्ट्रीय व्यक्तित्व प्राप्त कर लिया। लेकिन इस व्यक्तित्व का स्वयं का दावा नहीं करना है।¹ ओपनहैम (Oppenheim) का कथन भी कुत्रणमात्र था। भारत के सम्बन्ध में उन्होंने कहा था कि राष्ट्रमण्डल की सम्मेलन के बाद अंतराष्ट्रीय विधि में उसका एक विशेष स्थान हा गया है। लेकिन इस स्थिति के सम्बन्ध का निवारण बड़ा ही कठिन है। किन्तु भी तरह आधिकारिक रूप में ही सही अंतराष्ट्रीय विधि के सम्मेलनान विचारना न मान लिया कि राष्ट्रमण्डल की सम्मेलन में भारत की अंतराष्ट्रीय स्थिति में मौलिक परिवर्तन आ और अंतराष्ट्रीय व्यक्तित्व का उप एक न। रूप प्राप्त हुआ।

भारत का इस नवान अंतराष्ट्रीय स्थिति को 1921 के वाशिंगटन सम्मेलन (Washington Conference) में मान्यता मिली। इस सम्मेलन ब्रिटिश सरकार ने निम्नप्र किया कि उसने जारा स्वीकार किया गया अंतराष्ट्रीय मंत्रि सम्मेलने डालि नियमा अथवा भारत पर तभी जारु जोगे जव उनके प्रतिनिधि पृथक रूप में उन पर है जार करे और उनकी बातों का वाकार करे। अभी कारण वाशिंगटन सम्मेलन में भारत का पृथक प्रतिनिधि न मिला। भारतीय प्रतिनिधि आनिवाग नादेशा न वाणिग न सुधियों पर भारत का और म हस्ताक्षर किया और जगैह के राजा न पृथक रूप में भारत के लिए इस सत्रि का अनुमान किया।²

अंतराष्ट्रीय व्यक्ति के विकास—राष्ट्रमण्डल का सम्मेलन भारत का वर्ष अथ अंतराष्ट्रीय सम्मेलन का सम्मेलन बन का अवसर मिला। भारत का तत्काल ही अंतराष्ट्रीय सम्मेलन (I. L. O.) अंतराष्ट्रीय सम्मेलन म्यावा जयावाज (Perma-

1 That the self governing Dominions and India have acquired something of an international personality by reason of their membership of the League of Nations seems clear but how much is not so evident — W. E. Hall *Lectures on International Law* (8th Edition 194) p. 35

2 India stood in a special position. By virtue of her membership of the League of Nations India certainly possesses a position in international law. It is not a state and defies classification — Oppenheim *International Law* (4th Edition 1928) p. 195

3 *Council of State Debates* Vol. I 1930 pp. 457-58

neut Court of International Justice) बौद्धिक सहयोग की अन्तर्राष्ट्रीय समिति (International Committee of Intellectual Co-operation) कृषि में सहभाग्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान (International Institute of Agriculture) अफीम और ओपियम की अन्तर्राष्ट्रीय समिति (Advisory Committee on Opium and Drugs) आर्थिक समिति वार्षिक समिति आदि की संस्थापता बन गयी।¹ दो विश्व युद्धों के बीच के काल में जिनने भी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए उनमें भी भारत को पृथक् प्रतिनिधित्व मिलता रहा। भारत ने 1920 का प्रथम विश्व वित्तीय सम्मेलन 1921 की नौ नेताओं सम्मिलित आर्थिक सम्मेलन को प्राप्त में सम्मिलित 1921 के वारमिलोना सम्मेलन 1922 तथा 1927 के जनवा के विश्व आर्थिक सम्मेलन 1931 के हेग के प्रतिष्ठित सम्मेलन और 1932 के विश्व निरक्षरीकरण सम्मेलन तथा इस तरह के कई अन्य अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया।²

इस तरह सीमित अर्थ में जब भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में प्रगति कर लिया तब बाह्य दुनिया के समक्ष हमकी सतर्क प्रस्तुति करना आवश्यक हो गया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सन् 1919 में एक भारतीय उच्चायुक्त (High Commissioner) की नियुक्ति की व्यवस्था की गयी। 1919 में भारत सरकार अधिनियम में इस पद की स्थापना की गयी थी और अधिनियम के लागू होने के पूर्व ही सन् 1919 में भारतीय उच्चायुक्त का नियुक्ति कर दी गयी। इस पद पर काम करने वाले प्रथम व्यक्ति विलियम मेयर (William Meyer) थे जो भारत सरकार में वित्त मन्त्र (Finance Member) के पद पर काम कर चुके थे। 1931 के लुग्नो में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय उच्चायुक्त का राजनयिक दर्जा (Diplomatic status) प्रदान कर दिया।³

राष्ट्रमण्डल का सदस्य बनने के पश्चात् कूटनीति में भी भारत का स्थिति सुदृढ़ होने लगी। पञ्च दनिया के कितने भी भाग में भारत का कोई कूटनीतिक दूत नहीं रहता था और भारतीय हितों की रक्षा ब्रिटिश विदेश मन्त्रालय (British Foreign Office) के जरिये होता था। तब से राष्ट्रमण्डल का सदस्य बनने पर भारत ने अपने कूटनीतिक दूतों का नियुक्त करना शुरु कर लिया। भारत सरकार के राजनीतिक विभाग (Political Department) के पद धारित्री बाबुल तथा बालमोहं के रहने लगे। अफगानिस्तान पर्सिया अरबिया सामार मुगल जहा आदि जगहों में भारत के वाणिज्य दूतों (Consular Agent) का नियुक्ति हुई। 1931 में हमबर्ग

1 International Status of India Memorandum presented to the Indian Statutory Commission Report of the Indian Statutory Commission (1930) vol V p 1637

2 Lanka Sundaram International Status of India Journal of the Royal Institute of International Law vol 18 No 4 1930 pp 451-55

3 S R Mehrotra International Law and the Com p 239

सदस्य उन राशियाँ द्वारा मनोनीत होते जो औद्योगिक महत्व के मुख्य देश (Countries of chief industrial importance) थे। भारत ने दावा किया कि उसको औद्योगिक महत्व का एक मुख्य देश माना जाय और इस आधार पर शासक सभा (Governing Body) का एक प्रतिनिधित्व सीट उसे दिया जाय। इस तरह का दावा कनाडा, पोलैंड और स्विडन ने भी किया।¹ इस प्रश्न पर वास्तविक विवाद उत्पन्न हो गया और सलियन इस समस्या को राष्ट्रसंघ की कौमिसन ऑफ़ इन्वेंस्टिगेशन के लिए मण्डल कर दिया गया। कौमिसन ने काफी बहस के बाद अपना निष्पत्ति भारत के पक्ष में किया। भारत को औद्योगिक महत्व का एक मुख्य देश माना जायता मिल गया। इस फैसले ने 18 अगस्त 1922 को भारत ने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संघ की 'गाररन्टी' सभा में अपना स्थान ग्रहण किया।²

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संघ की दायर सभा की सम्मेलन भारत के लिए बड़े महत्व की बात थी। इसके परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय श्रम में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी। इस सम्मेलन ने भारत को अन्तर्राष्ट्रिय श्रम समस्याओं को हल करने का अवसर प्रदान किया। तब तक सबसे अधिक महत्व की बात यह थी कि हमने भारत के अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहार और स्थिति को अर्थ में सुन्दर किया।³

जब मैं चलाकर भारत की अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति ने उसे संयुक्त राष्ट्रसंघ (U.N.O.) का एक 'गाररन्टी' में सम्मिलित अवसर दिया। संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना के सम्बन्ध में तीसरे विश्व युद्ध के समय से। वास्तव में चलाकर ही और अगस्त 1944 के एम्बटन ओवरम सम्मेलन में इसका शांति का स्वरूप तय हो गया। जून 1945 में संयुक्त राष्ट्रसंघ में इसका प्रथम रूप में स्वीकार कर संयुक्त राष्ट्रसंघ में शामिल हो गया। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत को भी आमन्त्रित किया गया था और संयुक्त राष्ट्रसंघ के शांति पर हस्ताक्षर करनेवाला मैं भी एक 'गाररन्टी' में सम्मिलित था। भारतीय दल जो इस सम्मेलन में भाग लेने गया था, सचिव नेहरू ने रमास्वामी मुनिस्वामीयारन किया था। यह सबविधि है कि 'संयुक्त राष्ट्रसंघ' स्वतंत्रता नहीं था किन्तु 'संयुक्त राष्ट्रसंघ' की बीच के शांति में उभर आनेवाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहार का जो विकास हो रहा था, हमने संयुक्त राष्ट्र की नींव डालने में योगदान करने के लिए उसे अवसर प्रदान किया।

1 International Labour Office *Official Journal* No 6 1920 pp 36-65

2 P. P. Pillai *India and International Labour Organisation* pp 85-93

3 *India's Foreign Policy* by B. B. Chatterjee, p. 158. India not only as a matter of prestige. It also gave India opportunity to wield influence on international labour matters. Above all membership of the Governing Body established and consolidated India's international status — D. N. Verma *India and the World* pp 158-59

15 अगस्त का जब भारत स्वतंत्र हुआ तो वह युवक युवती राष्ट्रियता का स्वरूप बना रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हम संसदीयता के लिए उन बातों का व्यवस्थापन नहीं करना पड़ा।

एक प्रकार 1919 और 1945 के बीच के काल में एक पराजित उपनिवेश हाव नए ना भारत ने एक अनाथा अंतराष्ट्रीय प्रकृति प्राप्त कर लिया। हम विभिन्न वर्तमान के लिए सक्षमपन इत्यादि का नष्ट की संसदीयता से उसकी सहायता मिली। संसदीयता के प्रयोग करने के कारण जब 1919 के परिषद के प्रतिनिधित्व मन्त्र में भाग लेने का अवसर मिला और बनाय भवि का हस्ताक्षर कला हान के नाते वह राज्यसूचक का संसदीय बना। इस संसदीयता ने उस संसदीय राष्ट्रवाद का प्रारम्भिक स्वरूप बनने का अवसर प्रदान किया।

(iii) भारत में अन्तराष्ट्रीय चेतना का विकास

(Growth of International Consciousness in India)

अन्तराष्ट्रीय चेतना का प्रारम्भ—सन्धिों तक एशिया के विविध देश यूरोपीय साम्राज्यवाद के चपुत में पड़े रहे। साम्राज्यवाद का प्रारम्भिक रूप में ही सम्पूर्ण एशिया द्वेष का और उन्मूलन बना एशियाई देश यूरोपीय साम्राज्यवाद का बहा में लगे हुए थे। भारत को बना हिन्दुत्वान मनाया साम्राज्यवाद द्वारा दलों पर निर्माण साम्राज्यवाद और एक साम्राज्यवादियों ने जलना आदिपत्र कायम कर दिया था। इन दोनों के अतिरिक्त चान नाल स्थान परिवर्तन अन्तराष्ट्रीयता का हिस्सा स्वतंत्र राज्य का भी। लेकिन यह स्वतंत्रता केवल नाममात्र का था। यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से हिंसा युद्धों का राज्य का गाने उन्मूलन कायम नहीं हुआ पर प्रत्यक्ष दृष्टिकोण से अन्तर्गत स्थिति भाव परिवर्तन का संकेत हुआ।

एशियाई देशों में राष्ट्रीयता के सिद्धांत का विकास न होने पावे इससे लिए समासूरी इन देशों ने एक-सा नाति का अवलंबन किया। उन्होंने निश्चित रूप से यह व्यवस्था की कि एशिया के परस्पर देशों के बीच हिंसा प्रकार का पारस्परिक संघर्ष कायम नहीं हो और वे जलम में विवाह का आशान बना नहीं कर सकें। इसलिए एशियाई देशों के सम्मान में एक दूसरे के सिद्धांत का स्वीकार किया गया कि एक देश का अति साम्राज्यवादी स्थिति में दूसरे देश का अन्तर्गत नहीं कर सकें। भारत के संसदीय मन्त्र नाति का विचार रूप से सामू किया गया। एशिया साम्राज्य का स्थापना के बाद बाह्य जगत से भारत का सम्बन्ध-नाति एकदम टूट गया क्योंकि एशियाई देशों ने भारत का एक दुनिया में विस्तृत युवक कर दिया था। फलतः विश्व अन्तर्गत के प्रति भारतीय पण्डितों द्वारा उन्मूलन करने लगे। भारत के लोगों में किता उन्मूलन का अन्तराष्ट्रीय भाव नष्ट रह गया।

पर वह स्थिति अधिक दिनों तक टिकनवाला नहीं था। उन्मूलन साम्राज्य के अन्तिम उदात्त कायम साम्राज्य के प्रारम्भिक वर्षों में भारत के उन्मूलन में परिणत हो कर सक्षम प्रकट हुए। पाश्चात्य देशों के विकास और आधुनिक आवागमन एवं यातायात के साधनों में वृद्धि के कारण भारतीय अर्थिकान में धार-धार

परिवर्तन होने लगा। विश्व का घटनाओं से भारतीयों को घृणित रखने की साम्राज्यवादी नीति अग्रिम दिनों तक बाधित नहीं रह सकी और दोनों ही की प्रारम्भ से भारतीय अग्रिम दिनों की राजनीतिक गतिविधियाँ अवगत होने लगी। यह समय राधाकृष्ण और राधाकृष्ण आन्दोलनों का था और इनसे सम्बन्धित विभिन्न घटनाओं का अध्ययन भारत के नागरिकों के लिये। इटली में मजदूरी और गरीबी की स्थिति को देखते हुए उनका ध्यान गया। 1896 में इटली और अमीनीनिया के मध्य जो युद्ध हुआ था उसमें इटली एक आफकी दंग से पराजित हुआ। भारत में इस घटना के महत्व की विवेक का समझा गया। बोअर युद्ध में ब्रिटेन ने पनामन में भारतवासी एक नदी आगा का संचार हुआ। ब्रिटिश साम्राज्यवाद पर किसी भी आधार को भारतीय जनता मुक्ति के दृष्टिकोण से देखने लगे।

एशिया दशा को एक दूसरे से घृणित रख की साम्राज्यवादी नीति का बहुत दिनों तक नुकसान हुआ। भारतीय दृष्टिकोण से यह दोषार उन्नीसवाँ शताब्दी के अन्तिम वर्षों में ही दृष्टि में लगे। विभिन्न घटनाओं में बढ़ती हुई दृष्टि ने भारतीयों को विभिन्न भ्रमण की ओर प्रेरित किया। ओर इस काल में कई प्रमुख भारतीयों ने विदेशों की ओर प्रेरित किया। न भारतवासी में स्वामी विवेकानन्द की प्रेरणा का नाम पढ़ा जाता है। इन लोगों ने पश्चिमी देशों का भ्रमण किया वहाँ की लोगों का सम्पन्न स्थापित किया और स्वदेश लौटने पर अपने देशवासियों को इन देशों के सम्बन्ध में जानकारी दी। न तरह की यात्राएँ कई कारणों से की जाती थी लेकिन उनका राजनीति में महत्व था और कभी कभी राजनीति में वही सर्वांगीर हो जाता था।¹ 1893 में विवेकानन्द ने जापान का भ्रमण किया था। वहाँ जापान की उन्नति और आधुनिकीकरण से बहुत प्रभावित हुए थे। प्रगतिशील जापान की उन्नति से अपने देश की पिछड़ेपन का तुलना करने पर उन्होंने बौद्ध धर्म का अनुभव किया था और विभिन्न होकर अपने देश में अपना मन व्यक्त किया था। अन्तिम शब्द में भारतीयों का विचार उनका सामूहिक निराशावादी भावों की उन्नति के घटु आलोचना की थी और भारतीय विचारियों का इस कारण फटकारा था कि वे किराने बनने में आगे की - व मूर्खतापूर्ण नहीं रखने। उन्होंने भारतीय विचारों का इस मनोवृत्ति का बोझ आलोचना की जा निरन्तर केवल इसी प्रकार विवेकानन्द से यह कहना कि अज्ञान क्या है समुद्र पार आना प्रेम विवेक है या नहीं या उम्मा हुआ भोजन पाना चाहिए अथवा नहीं। विवेकानन्द ने अपने देशवासियों को सताराना और पता दिव जापान जाय वहाँ जो बाने हो रही हैं उनका दम समझ और

1 Such travels were undertaken for various reasons but they never lacked political significance and eventually the political motive became the most frequent and permanent
—Warner Lewis *The Indians* 1912 P 19

उन्का अनुकरण करे। भारत का बह्यांग यही म है।¹

हम ज्ञान युद्ध—इस प्रकार साम्राज्यता की प्रारम्भ में विनिष्ट भारत की शिक्षण प्रणाली में भारतीयता में अंतराष्ट्रीय चेतना का विकास पात लगा। अभी समय पूर्ण एशिया में एक और सम्बन्धन घटना घटी जिसने भारतीयों का जीवन स्थानों में घटाया या कम और ज्ञान के समय 1904-5 का वर्ष। हम युद्ध में एशिया के एक छोटे में हम ज्ञान न यूरोप के एक में निश्चितगाना हम हम का तरी तरह पराजित कर दिया। यह एक छाया या मूर्तत्व घटना था। यह स्वतन्त्रता के बोध (Whiteman's Burden) का दाय था।² एशिया के लोगों में यह विश्वास बना कि उनका पराधीनता का बोध की वजह से यूरोप के सम्बन्ध में और विश्व में हम पराजित बना दिया जा सकता है। निष्कर्ष का विषय न हम अग्रविश्व का सम्बन्ध दिया और एशिया में यूरोप में अग्रविश्व का मानसिक नींव (Psychological foundation of western imperialism) बुरी तरह हिन रहा। समय एशिया में जापान की शक्ति का रूप का साथ स्वातन्त्र्य दिया गया। एशिया की पराजित

1 अपने एक सभास मित्र को जापान में विमान में जा रहा दिया था उसका एक सारांग इस प्रकार है— I cannot write what I have in my mind about the Japanese in one short letter. Only I want that numbers of our youngmen must pay a visit to Japan every year.

And you what are you? Talking to iddle all your lives. You are talkers. Come see those people and go and hide your face in shame. A race of dotras you lose your caste if you come out. Sitting down in the e thousand years with an ever increasing load of crystallized superstition on your hands for a thousand years spending all your energy upon discussing the touchableness or untouchableness of this food or that repeating undigested trays bits of European brain work and bent upon getting a thirty rupee clerkship or at best becoming a lawyer.

Come be men come out of your narrow holes and have a look abroad. See how nations are on their march. Do you love your country? Then come look back but forward. —Quoted in *The Indian Press* vol VI No 1 January 1900 p 3

यह बह्यांग विपत्ति (Rudyard Kipling) द्वारा प्रतिपादित मित्र मित्र था। हमने हमें बताया कि युद्ध के विभिन्न माता न हमें युद्ध अग्रविश्व अग्रविश्व नदी अधिकमिन् लागा के बोध के युद्ध सम्बन्ध तब सम्बन्ध का प्रवर्धन उन्का उद्देश्य करना लक्ष्य के था ज्ञान यूरोपीय जागा का बन रहा है। विपत्ति न यह तक अग्रविश्व विपत्ति का प्रवर्धन का समय बना। गार जागा का महान् उद्देश्य है। अग्रविश्व अग्रविश्व समय गाँव के विपत्ति का बोध है। —मिथ P T Moon *Imperialism and World Politics* p 73

जापानियों में एक नयी भावना का संचार हुआ और वे अनुभव करने लगी कि जापान के तरीकों को अपनाकर यूरोपीय साम्राज्यवाद के चंगुल से मुक्त हुआ जा सकता है।¹

भारतीय राजनीति पर हम जापान युद्ध के परिणामों का प्रभाव विचार करने पड़ा। जापान की विजय पर सम्पूर्ण देश में हर्ष-यवन किया गया और कश्मीर से कन्या कुमारी तक इसका उपलब्ध में खुशी मनायी गयी। भारतीय समाचारपत्रों ने इस पर अग्रज्य छाप और सताप प्रकट किया।² गोपानकृष्ण गोखले ने कहा कि भविष्य में भारत की विजय के लिए जापान के रास्ते को ही अपनाना होगा।³

1. 147 कन्या कुमारी के एशियाई सम्मेलन में कई प्रतिनिधियों ने इस बात को स्वीकार किया कि 1905 में जापान की विजय ने एशिया के इतिहास को एक नया मोड़ दिया। रविचन्द्र Nicholas Mansergh 'The Commonwealth in Asia' पृष्ठ 155-156 (1950) पृष्ठ 9

During the Russo Japanese War the sympathy of India was wholly with the small island people. Her victory set the hearts of subject peoples in the East a throbbing with joy and pride. It fired the ambition and hope for national freedom. Indians came to regard Japan as the leader of the awakened Asia as the shield and bulwark of Asiatic freedom. Since these days Japan became a place of pilgrimage of Asiatic patriots an asylum to exiles from the many lands of Asia.

2. इस जापान युद्ध में जापान की विजय पर विपणनी बरत दिए इंडियन रिस्त्रिब्यूट (Indian Press) के सम्पादक ने लिखा था

The fall of Port Arthur opens a new chapter in the history of the brilliant career of this wonderful and marvellous country which within a single generation has risen from a backward to a most forward place in the scale of the civilized nations of the world. We have witnessed indeed the birth of a nation in a day.

Almost for the first time in the history of the world Asia's power hitherto somewhat despised and not taken into account has humbled a huge European Power by no means a mean representative of all that is haughty and arrogant among the nations of the West. A race of dwarfs has been able to demonstrate to the astonished world that she can as well the latest death dealing devices of the white man. Japan has compelled to capitulate the very power which once distained to recognize her entity.

Indian Press Vol. VI No. 1 January 1905 p. 1

3. There can be no surer road to a final success than that which Japan has trodden.

—Gopal Krishna Gokhale 'Self Government for India' p. 243

मिस्र और आयरलैंड के लोगों के सघर्ष में भारतीयों की सहाय्यप्रति सहाय्य के पक्ष में थी। 1905 की हूमा ज़ाति 1908 की युवा तुर्क ज़ाति और 1911 की चीनी क्रांति ने भारतीयों के दिल में अगार से साहू का गन्धार किया। म. ग. म. भारत का राष्ट्रीय अ. आसन इन घटनाओं से बहुत प्रभावित हुआ और चीनी ज़ाति के नेता डॉ. सन्यात मेन बहुत ज़िनों तक भारत के राष्ट्रपति या के हूय मन्नाट बन रहे। चीन की ज़ाति के सम्बन्ध में खबर भारतीय समाचार पत्रों में महत्व के साथ छपी और भारतीयों ने हमने सबक लेने का मौका प्राप्त किया।

इस परिवर्तन से भारतीय मुसलमान भी अप्रभूत नहारे 1857 की ज़ाति की फलता के बाद से भारतीय मुसलमानों ने अपने प्रायः का भारतीय राजनीति में बिल्कुल पृथक् कर रखा था और दोगो विपत्ती घटनाओं के प्रति व. पूण या उ. भीन हो गये थे। लेकिन इस्लामी जगत की घटनाओं में उनका ध्यान भी त्रि. व. ज्ञानाति की ओर आकृष्ट किया और उनमें भी एक नयी अन्तः प्रीय चेतना का उदय हुआ। 1878 में बर्लिन सम्मेलन के बाद आटोमन साम्राज्य के प्रति इंग्लैंड का नाति में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। इसके फलस्वरूप इटली और तुर्की का सम्बन्ध विगलन लगा। भारतीय मुसलमान इस बात से बहुत चिन्तित थे। ओ. मेन साम्राज्य का शत्रुता मुसलमानों का घम गुरु माना जाता था और जब ब्रिटिश सरकार ने उसका विरोध करना शुरू किया तो भारतीय मुसलमान ब्रिटिश नीति से बर्लन गगलिन हो उठे। वस्तुतः भारतीय मुसलमानों में इस बात पर बहुत विचार होने लगा कि यदि ब्रिटिश और तुर्की में युद्ध छिड़ गया तो व. जिसको अपना समर्थन देगे। मुसलमानों में एक ग. था जो कहता था कि इस युद्ध की स्थिति में भारतीयों का तुर्की के मुसलमानों का समर्थन करना चाहिए क्योंकि वह मुस्लिम जगत का गन्धोका था।¹

अंग्लैंड की तुर्की विरोधी नीति भारतीय मुसलमानों को लगातार परेशान करती रही। 1907 के अंग्लो रूसी सम्मेलन (Anglo Russian Convention) का उ. ने गलतकर विरोध किया क्योंकि उसने इन वि. व. म. पर ग. रा. आधान था कि रूस तुर्की का शत्रु और इंग्लैंड उसका मित्र है। 1911 में ज़िन्को को लेकर जब इटली ने तुर्की के खिलाफ युद्ध घोषित किया और अंग्लैंड ने इस घ. ना. के सम्बन्ध में तटस्थ नीति का अवलम्बन किया तब भारत का मुस्लिम साहमन अरु. न. परेशान हो गया। भारतीय मुसलमानों का कहना था कि उनकी घाबिर् भावनाओं का ध्यान में रखकर ब्रिटिश का इ. व. व. विरुद्ध तुर्की का समर्थन करना चाहिए था। 1912 के का. इन युद्ध ने भारतीय मुसलमानों की ओर भा. मयभीन कर दिया। मोरक्को पर फ्रांसीसी आक्रामक (1905) बाल्कन हाइड्रोग्राफिना पर आ. या. का आधिपत्य व. गैरवा. शा. स्वत. बना की घोषणा और ज़िन्को पर इ. व. आ. म. ने उनके इस वि. शा. को दृढ़ कर दिया कि पश्चिमी राष्ट्रों ने तुर्की साम्राज्य को संहित करके उस आपत में बाँट लेने का कोई गुप्त सम्मेलन कर लिया है। भारतीय मुसलमानों ने बाल्कन युद्ध की इस्लाम और ईसाई मजहबों के बीच युद्ध

कम्यून प्रवृत्ति किया। जागतिक मुसलमानों ने तुर्की के पक्ष में भारत में जावमत लाना करना शुरू किया। तुर्की के लिए वह एक बड़ा सफलता प्राप्त किया गया और मस्जिदों में तुर्की की विजय के लिए नमाज़ें पढ़ाई गईं। नवंबर 1912 में एम. ए. एंसारी (M. A. Ansari) के नेतृत्व में एक चिकित्सा मिशन (Medical mission) तुर्की भेजा गया। भारतीय मुसलमानों ने अजुमाती गुदामी कावा नामक एक संस्था की स्थापना की जिसके नेतृत्व में तुर्की की रक्षा के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का फैसला था। जीवनभर ही इस समस्या के संबंध में चर्चा चल रही थी।

जिन यह प्रयास किया कि इस में तुर्की का सहयोग के लिए भारतीय मुसलमानों ने एक स्वयंसेवक दल बनाया जाय।¹ यह पक्ष इस तरह के कार्य में मगलित नहीं हो सका। लेकिन इस रास्ता पर एक प्रबल प्रभाव पड़ा कि इस विचारणा के माध्यम से एक गहरा जनजातीय अन्धकार का विकास हो रहा था।² अंत में राष्ट्रीय रूप में नवजागरण के स्तर पर यह।

दक्षिण अफ्रीका के प्रवासी भारतीयों का समझना — न केवल में अग्रिम प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व भारत एक अंतराष्ट्रीय घटना में अत्यंत ही महत्वपूर्ण था। विश्व अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों का गौरव बढ़ाई का सरकार प्रशासन के नाम पर बना भ्रमभाव कर रहा था। जिसमें उनका लगा निरंतर गौरव होता जा रहा हो। इस समय अफ्रीका का पता लगा और उसमें भूमिगतों पर यूरोपीय लोगों ने अपना आधिपत्य जमाया उस समय में अफ्रीका के जंगलों का माफ करने और उसका विकास करने का काम निष्ठा मुलामों में किया जाता था। लेकिन जब 1848 में मुलामा प्रथा का अन्त्य घोषित कर दिया गया तब अफ्रीका में मजदूरी करने वालों का बड़ा बूमो हुआ। इन हालात में यूरोपीय साम्राज्यवादीयों का ध्यान एशिया विभाग पर भारत और चीन की विभाजन जनसंख्या की आर आधुनिक युवा। भर्ती करने भारतीयों मजदूरों का अफ्रीका में जान के लिए भारत के अन्तर्गत स्थानों में मजदूरी करना। न मजदूरों के प्रतिनिधि भारत के दौरे में घूम घूम कर गौरव भारतीयों का तरफदारों के प्रभावों के लिए अफ्रीका जान के लिए प्रेरित करने थे। भारतीय मजदूरों और एशियाई के बीच एक प्रकार का इकरारनामा होता था जिसके अनुसार मजदूरों का काम स्थान का बांटा दिया जाता था और भारतीय अफ्रीका जान की बात पर राज हो गई। अन्त और निधन भारतीयों दहाती के इकरारनामा का कनो कनो कोन। जन जातीय किन्तु अन्तर्गत आर्थिक स्थिति अन्तर्गत गौरव हुआ गया था कि वह किसी भी भाग पर अपना अन्तर्गत के लिए किया कि किसी भी भाग में जान का ठगार हुआ जाय। इन भारतीयों का जानवरी का तरह अन्तर्गत पर जा के अन्तर्गत पड़ना किता जाता था। अन्तर्गत माय माय इनके परिवार के अन्तर्गत माय माय जगह पर चल रहा। इनके अन्तर्गत एक बड़ा संस्था में बुद्धिजीवी भारतीयों का दान अफ्रीका में। बुद्धि हा

1 Lal Bahadur The Muslim League 1954 p 89

2 R. Palme Dutt *It is To a* p 501

यहों में दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की मजदूरी हजारों हजार में बढ़ गई।
कालान्तर में वे वहीं बस गये।¹

यूरोपीय साम्राज्यवादीयों का भारतीय मजदूरों की सेवा की आवश्यकता थी व उनकी मुक्त मुविधा या मजदूरी के लिए विभिन्न नहीं थे। प्रवासी भारतीय मजदूरों का गणना करने से अपमान करने का निम्न भाव्यता करने लगे। इससे अतिरिक्त प्रजातीय भेदभाव (racial discrimination) के कारण भारतीयों के साथ यूरोपीयों का बड़ा ही अमानुषिक व्यवहार हुआ था। प्रवासी भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका में गणना न मानकर अधिकार भी प्राप्त नहीं थे। उन्हें यूरोपीयों के लिए निम्न मजदूरी देने शुरू किया गया था जिसके उपयोग का अधिकार नहीं था। भारतीयों की स्थिति यूरोपीयों से बहुत ही नीची थी। वे रात का खाने पाने से बाहर नहीं निकल सकते थे और बिना सरकारी आमा प्राप्त किए एक गृह में दूसरे गृह में नहीं जा सकते थे। इस तरह के कई अन्य प्रतिबंध गणितवादीयों पर लगे हुए थे जिनसे उनका जीवन अत्यन्त कष्टमय हो गया था।² उन्नामनी प्रजातीय के अन्तिम वर्षों में जब भारतीयों का जीवन अत्यन्त ही गंवा तो उन्होंने इससे निवारण आवश्यकताओं को बताया। इसका नेतृत्व मोहन दास करमचन्द गांधी (महात्मा गांधी) ने किया जो उस समय अपनी वकालत करने के निमित्त दक्षिण अफ्रीका पहुँचे थे। दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों की अपनी स्थिति ठीक करने के लिए वर्षों तक समय करना पड़ा। 1911 में भारतीयों और दक्षिण अफ्रीकी सरकार के बीच एक समझौता (Gandhi Smuts Agreement) हुआ जिसने कठोरता प्रवासी भारतीयों की स्थिति में कुछ सुधार हुआ।

भारतीय दक्षिण अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका की इन घटनाओं का बड़ा महत्व है। दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों का जीवन समय खराब रहा। भारत में इसके प्रति बड़ा बेचैनी रही। यह पहली अन्तर्राष्ट्रीय घटना थी जिसने भारतीयों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रवासी भारतीयों के समय में रुचि लेना आरम्भ किया और 1894 के बाद से कांग्रेस का प्रत्यक्ष अधिकार में दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों की समस्या से सम्बन्धित प्रस्ताव पारित किये गये जिनमें दक्षिण अफ्रीकी सरकार की भारत विरोधी नीति की तीव्र निन्दा की गयी।³ मुस्लिम लीग ने भी प्रवासी भारतीयों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करके उनका समर्थन किया। दक्षिण अफ्रीकी भारतीयों के समय का आदेश में लाने के लिए भारत में कई दस्तावेज किये गये। इंग्लैंड में भारतीयों के मोक्ष के लिए मोक्ष तथा मदन मोहन मालवीय के भ्रमण हुए। इन लोगों ने भारत सरकार से आग्रह किया कि वह दक्षिण अफ्रीका की सरकार पर भारत विरोधी नीति

1 C Jondapi *Indians Oversea* pp 5-7

2 R C Majumdar *British Paramountcy and India Renaissance* v II pp 670-72

3 Ibid pp 623-24

के परिहारा के लिए दबाव डाले।¹ भारतीय लोकमत व समस्त भारत सरकार का झुटना पना और राजकीय स्तर पर उत्तरे प्रवासो भारतीयों का गुवान नित्त अफिका की सरकार तथा ब्रिटिश सरकार व समस्त उठाया। 1897 न नित्तय औप निर्विक मम्मलन (Colonial Conference) में ब्रिटिश आफिन व एक अनित्तिय न इम सुवान का उठाया। औपनिवेगिक मामनों के मन्त्रा नोमुफ चम्बरनन न स्वचासी ब्रिटिश उपनिवेशा विनेपकर दक्षिण अफिका के प्रधानमन्त्रा स बाग्रह किया कि व किसा वसा नाति का अवनम्बन नहीं करें जिसका भारतीयों की भावना पर प्रतिकूल प्रभाव पडे।²

प्रथम विश्व युद्ध और भारत—28 जून 1909 क लॉन टाउन्स म भारत में ब्रिटन क भविष्य (Britain's Future in India) नापक क अतगत नावाट फ्रमर (Loat Fraser) का एक लेख प्रकाशित हुआ था। इस लेख का मुख्य निष्कर्ष यह था कि यूरोपीय संघों म ब्रिटन के फसन ही सम्पूर्ण भारत में विद्राह हा जायगा। इसी तरफ के विचार कुछ अय अग्र ज न्त्राओं न भी उस समय यवन किये।³ जमनी का सम्भवन यह विश्वास हा गया था कि नित्त छात्र ब्रिटन यूरोपीय युद्ध में फंसगा उसी गण भारत में विरोह की आग फन जायगी। नकिन 1914 म जब यूरोप म प्रथम विश्व युद्ध छिटा तो भारत में इस तरह का कां बात नहीं हूँ। अग्रोजा राय का विराध करन क बावतून भारत के राष्ट्रवाग यने की ब्रिटिश सम्राट क प्रति वफादार बहन में गौरव का अनुभव करत य और किसी भा अनराष्ट्राय संकट म ब्रिटन का हर तरह की मन्त्र दन को तयार य।⁴ यूरोप में युद्ध क छित्त ही एम्पौरियन लजिम्बटिव कौसिन न 8 सितम्बर 1914 का युद्ध

1 Gopal Krishna Gokhale *Speeches* p 51

2 India and Imperial Conference *Pound Table* December 1915 p 96

Also see Lanka Sundaram India and Imperial Conference *The Indian Review* vol XXVI No 86 1930 pp 370 71

3 William Archer *India and the Future* (1917) p 17

4 इस समय कुछ ऐसे क्रांतिकारी भारतीय अवश्य य जा ब्रिटन क गत्र औ स भिन्नकर और उनसे सहायता प्राप्त करक भारत का स्वतंत्र करान क पन म य। नासा हरदत्तन बरकतुल्ला आदि इस कुछ निवाग्नि भारतवासि न युद्ध छित्त ही जमन सरकारस सम्पन्न (आशित) विद्या और बलिन म एक भारत समिति (India Committee) का स्थापना क। जमन सरकार और भारतसमितिक बीच एक संधि हुई जिसक अनुसार यह तय हुआ कि युद्ध में भारतीय जमनी को मन्त्र करेंगे और युद्धोपरानविजय प्राप्त करक जमनी भारत का स्वतंत्र करान में सहायता दगा। भारत समिति व एकाधिकारिया की जमन सरकार न राजनयिक स्तर प्रशन किया और राजदूतों की तरह उन्हें विषय रुचिआ प्राप्त थी। नकिन अनराष्ट्राय राजनीति पर भारत समिति का काइ विषय प्रभाव नहीं पडा और युद्ध क छान हात हा समिति का नामानिधान मिट गया। देखिये Jawaharlal Nehru, *An Autobiography* p 152

से सम्बन्धित एक प्रस्ताव पास किया। इसमें ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति भारतीयों का वफादारी की भावना को व्यक्त किया गया था और हर तरह से ब्रिटिश सरकार को मजदूरी देने का आश्वासन दिया गया था।¹ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दृष्टिकोण भी अत्यन्त सहयोगात्मक था। 11 दिसम्बर 1914 में काँग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ। उस अधिवेशन में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस प्रस्ताव में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादारी की बात कहा गया थी और हर हालत में ब्रिटिश के युद्ध प्रयासों में मजदूरी देने का आश्वासन दिया गया था। काँग्रेस ने युद्ध के पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय सेना भेजे जाने के निर्णय का स्वागत किया तथा बापूराय को इस दान के लिए धन्यवाद दिया कि उन्होंने भारतीयों का साम्राज्य की सेवा करने का अनूय अवसर दिया है।²

भारतीय नेताओं के इस सहानुभूतिपूर्ण रवये से ब्रिटिश सरकार का युद्ध में बड़ी भूमिका मिली। युद्ध के पहले भारत सरकार ने यह सोच रखा था कि युद्ध के दिवसे ही भारतीयों पर नियंत्रण रखने के लिए इंग्लैंड में अतिरिक्त सैन्य भर्तियाँ पड़ेगी। लेकिन ऐसी नीबूत नहीं आयी और भारतीयों का सहयोग-नमयन के आश्वासन पर विश्वास करके बापूराय लाहौर हाइज ने भारतीय सेना की एक महत्वपूर्ण कोर्बिचमी मान पर उनके लिए पुराना भेज दिया। पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के युद्ध-स्थल पर भी भारतीय सैनिक बहुत बड़ा योगदान भरे। कुल मिलाकर दस लाख के लगभग भारतीय सैनिक युद्ध में भाग लिया। 146 लाख पौंड की अविश्वसनीयता भी भारत ने दी। इसके अतिरिक्त भारतीय सैन्य ने भी घन घन से सरकार की सहायता की।³

सरदार के समय पण्डितजी ने कहा है कि एशियाई दृष्टिकोण में प्रथम

1 *Proceedings of the Congress, Governor General of India* 1914-15 vol. LIII pp. 16-17

2 कांग्रेस का यह प्रस्ताव इस तरह था

The Congress congratulates His Majesty the Emperor and the people of England its profound devotion to the Throne its unswerving allegiance to the British connection and its firm resolve to stand by the Empire at all hazards and at all costs. It notes with gratitude and satisfaction the dispatch of Indian troops to the Western front and offers to the Viceroy its most heartfelt thanks for affording to the people of India an opportunity of showing that as equal subjects of His Majesty they are prepared to follow the lead of the British people in the cause of the Empire — *Report of the Congress of India to the Congress* 1914 p. 1

3 S. R. Mehrotra *India and the Commonwealth* p. 65

विश्व-युद्ध यूरोपीय राज्यों के परिवार में एक बड़ा युद्ध था। उस युद्ध ने पहली बार यूरोप के साम्राज्यवादी सामंती का एकता को छिन्न भिन्न कर दिया। युद्ध काल में यूरोपीय देशों ने अपने-अपने-अपने के निवासियों से सहायता के लिए अपील की थी। यह एक नयी बात थी। इसने एशिया के देशों में एक नया मनोबल पैदा किया। उन्होंने अनुभव किया कि उनके यूरोपीय आसक्तों का भी उनकी सहायता का जरूरत पड़ सकता है। वस्तुतः युद्ध ने समय और संभव था यूरोपीय राष्ट्रों एशियाई राज्यों को निगाह में इतना गिरा दी जितना पहले कभी नहीं गिरी थीं। उनकी सारी प्रतिष्ठा धूल में मिल गयी। जर्मनी युद्ध ने गारों के साथ अपने-अपने उन लोगों ने देख लिया कि यूरोपीय लोग बीरता में उनसे घबड़ा होने का भाव नहीं कर सकते। भारत के लिए विश्व-युद्ध विशेष रूप से महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। उस का राजनीतिक महत्त्व को नया जीवन मिला। घन और जन में भारत का मान्यता दन और विश्व अधिकारियों गता इसके लिए कृतज्ञता प्रकट न भारतीयों का ध्यान देना का महत्व के सम्बन्ध में जागृत बना दिया। वे अनुभव करने लगे कि विश्व राजनीति में भारत एक मुख्य भूमिका भूमिका कर सकता है। युद्ध के समय निम्नराज्यों के नेताओं ने कहा था कि उनका युद्ध उद्देश्य सुधार का प्रकाशन के लिए सुरक्षित बनाना है। राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने राज्यों के लिए आत्म निर्णय के सिद्धांत (Principle of self-determination) का नारा दिया। उन गारों ने भारतीयों में एक नवीन उत्साह का सुचारु किया और वे इन सिद्धांतों की घोषणा से अत्यधिक प्रभावित हुए। यही कारण था कि निम्नराज्यों के युद्ध प्रयास में भारतीयों ने जी जान से प्रयास किया। गणेशजी शहास ही में अपना बलिदान से लोग ये गुजरात के गांवों में घूम घूम कर किसानों का विश्वास में नती हान को बह रहे थे। साकनाथ बाग गणेश तिलक और विरिच चंद्रपान उस उद्देश्य नता था कि के युद्ध प्रयासों में सहयोग करने के लिए जन दलियों से अपील कर रहे थे।

यूरोपीय साम्राज्यवाद का नींव को हिलान में 1917 के रूस का दार्शनिक क्रान्ति का भी भूमिका था। क्रान्तिकारी बल्शेविकों ने साम्राज्यवाद का उद्धार करने की कोशिश की। उन्होंने स्वयं रूस के अक्षय्य पराजय क्रान्तियों का मुकाबला कर दिया और अपने पराजय देशों के आत्मसुधार में मदद देने का वादा किया। एशियाई देशों के राष्ट्रवादियों का मनोबल बहुत बढ़ा। देशवादिक क्रान्ति से भारत विद्रोह रूप में प्रभावित हुआ। युद्ध के पूर्व भारत में किसानों या मजदूरों का कोई संगठन नहीं था। लेकिन युद्ध के बाद इनका मतलब में एक-एक अलग बढि हु। अपने-आप संगठित नहीं कि इस परिवर्तन का मुह प्रयोग करने का प्रारंभ था।

युद्धकालीन परिस्थितियों से उत्पन्न इन सारा बातों ने भारतीय विचारधारा को गहरा रूप में प्रभावित किया और भारतीय दृष्टिकोण में क्रान्ति। अतः व सारा दृष्टिकोण हान में। अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण से भारत में अन्तर्गत था

रण हुआ। युद्ध के समय ही भारतीयों ने पहल पहल अनुभव किया कि भारत का बाहर भी एक विशाल दुनिया है जिसका अनेकानेक समस्याएँ हैं जिनके साथ हमारा प्रत्यक्ष सम्बन्ध है तथा हमारे ऊपर उनका प्रभाव अनिवार्य रूप से पड़ता है। युद्ध के पहले भारतीय नेताओं ने यह कभी नहीं सोचा कि अंतर्राष्ट्रीय जगत् में भारत का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व हो सकता है। देश की विदेश नीति पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया था। प्रशासन के इस अंग में उन्होंने कभी भी हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं महसूस की और इसको अंग्रेज शासकों के ऊपर ही छोड़ते रहे। लेकिन युद्ध के बाद नयी परिस्थिति में अब विश्व नीति और अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध के विषय में सोचने लगे। उन्होंने पहले पहल अनुभव किया कि अंतर्राष्ट्रीय क्षमता में भारत का अपना अलग और स्वतंत्र अस्तित्व हो सकता है। प्रशासन के नए अंग को वे अब छूटना नहीं छोड़ सकते थे। इस अनुभव के उपरान्त वे ब्रिटिश भारतीय सरकार की विदेश नीति की आलोचना करने लगे। उन्होंने यह भी कदम उठाया कि ब्रिटिश सरकार को भारत के अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के निर्धारण का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के अंत होते ही भारत में एक अमूल्य अंतर्राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ।

पेरिस का शान्ति-सम्मेलन और भारत—यह तरह के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुकामों का लेकर प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय राजनीति में बड़ी सरगर्मी और बेचबनी थी। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तुर्की का था। युद्ध में तुर्की हार गया था और ऐसा विश्वास किया जाने लगा था कि उस पर एक ऐसी संधि आरोपित की जायेगी जिससे तुर्की खटित हो जायेगा। इस कारण भारतीय लोकमन अत्यंत क्षुब्ध था। इसके अनिश्चित युद्ध के समय मित्रराज्यों ने आत्मनिर्णय के सिद्धांत (Principle of self-determination) को दुनिया में लागू करने का वादा किया था। लेकिन जैसे जैसे युद्ध का अंत निकट आता गया भारत में ब्रिटिश सरकार की नीति को देखकर यह स्पष्ट प्रतीत होने लगा कि भारत पर इस सिद्धांत को लागू करने का उसका इरादा नहीं है। रणघोषणाओं के बावजूद यूरोप के साम्राज्यवादी राज्य पराधीन राष्ट्रों को कुचलने की अपनी पुरानी नीति का ही अनुसरण करते रहे।

काँग्रेस और शान्ति सम्मेलन—यह हालत से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने निष्पत्ति बढाने की नीति का परिणाम कर देना ही अचरकर समझा। वे चाहते थे कि युद्धोपशान्त शान्ति संधियों द्वारा जिस नवीन विश्व का निर्माण हो उस कार्य में भाग लेने का अधिकार उन्हें भी मिले। युद्ध प्रशंसकों में भारत की दून भारतीय नेताओं द्वारा युद्ध में ब्रिटेन का समयन आदि बातों की वृद्धभूमि में भारत का राष्ट्रीय काँग्रेस के नेता चाहते थे कि पेरिस के शान्ति सम्मेलन में भारत को उचित प्रतिनिधित्व मिले। 1919 के शान्ति सम्मेलन में भारत को प्रतिनिधित्व था कि मिला लेकिन भारतीय इसके पक्ष में असंतुष्ट थे। यह प्रतिनिधित्व भारत सरकार को प्राप्त हुआ जो किसी भी दृष्टिकोण से भारतीय लोकमन से प्रभावित

होनवाला नह। था। अन्तराष्ट्रीय समस्याओं पर भारत का अपना दृष्टिकोण था और यह दृष्टिकोण ब्रिटिश भारतीय सरकार के दृष्टिकोण से विपरीत था। इस हानन में भारत के राष्ट्रीय नेताओं के लिए यह आवश्यक हो गया कि वे प्रत्यक्ष अन्तराष्ट्रीय मंच पर भारतीय दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण करें।

इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पेरिस के शांति सम्मेलन में शामिल होने का निश्चय किया। दिसम्बर 1918 में लिस्बन कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। पेरिस में होनेवाले शांति सम्मेलन के सम्बन्ध में अपने यह प्रस्ताव किया कि उसमें भारत को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और भारतीय प्रतिनिधि दल में जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति का नामित किया जाना चाहिए।¹ इसके अतिरिक्त कांग्रेस ने बाल गंगाधर तिलक मोहनदास करमचंद गांधी और हमन इमाम जैसे बरिष्ठ नेताओं को शांति सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से शामिल होने के लिए बुलाया। यह निश्चय हुआ कि ये तीनों व्यक्ति पेरिस के शांति-सम्मेलन में राष्ट्रवादी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उस समय तिलक इंग्लैंड में थे। अतः कांग्रेस ने उन्हें वहीं से पेरिस जान का आग्रह किया। तिलक ने पार्लियामेंट के लिए अवकाश लिया और ब्रिटिश प्रधानमन्त्री को लिखा कि शांति सम्मेलन में भाग लेने के लिए एक भारतीय प्रतिनिधि दल गठित हो जिसमें भारत की विविध समस्याओं द्वारा निर्वाचित व्यक्ति रहे जाय। ब्रिटिश सरकार को यह प्रस्ताव मान्य नहीं हुआ और उसने तिलक का पेरिस जान की अनुमति देने से इंकार कर दिया।

तिलक का पत्र—जब उपरोक्त तिलक ने शांति-सम्मेलन के अध्यक्ष के पास एक पत्र भेजने का निश्चय किया। सम्मेलन के एक नियम के अनुसार यह व्यवस्था की गयी थी कि कोई व्यक्ति या मुस्यौल जिसको सम्मेलन में प्रतिनिधित्व नहीं मिला हो इस तरह का आपन सम्मेलन के विचार से प्रस्तुत कर सकता है। अपने पत्र में तिलक ने शांति सम्मेलन का ध्यान भारतीय समस्या की ओर आकृष्ट किया और कहा कि भविष्य की शांति के लिए भारतीय समस्या का समाधान परम आवश्यक है। उन्होंने लिखा कि सभी राष्ट्रों से भारत एक माघन युक्त और स्वायत्त सम्बा देता है और समार के बिना देश की भूमि पर उसका काबू नहीं है।

1 Report of the Joint Anglo-Indian National Congress, 1918 Appendix A p. VII परामर्श शांति सम्मेलन भारतीय प्रतिनिधि-समिति के संवर्धन में 6 फरवरी 1919 का भारतीय एजिटिव बोर्डिल में एक सम्मेलन के 10 चरणों में सरकार को ध्यान देने योग्य भारतीय समस्याओं के प्रस्तावों के द्वारा आकृष्ट किया। दिनमें यह ध्यान की गयी थी कि सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सरकारी (non-official) प्रतिनिधि दल जाना चाहिए। चण महोदय यह जानना चाहते थे कि भारत सरकार का इन प्रस्तावों के प्रति क्या दृष्टिकोण है। इसके जवाब में बांगराय कोलिन के स. स. सर विलियम विन्सेंट ने कहा कि सरकार का इन प्रस्तावों को मानने का कोई प्रयास नहीं है और शांति सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व एक सरकारी प्रतिनिधि नहीं करेगा। दक्षिण —Proceedings of the Indian Legislative Council vol. LVII 1919 p. 447

अपने विशाल सम्राज्य अपरिमित साम्रज्य और अपार जनसंख्या के आधार पर भारत विश्व की एक महान शक्ति बनने की आकांक्षा रखता है। इस परिस्थिति में पूर्वी गोलार्द्ध में शक्ति बनाये रखने के काम में यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। प्रस्तावित राष्ट्रमण्डल का भारत प्रबल समर्थक हो सकता है।¹ लेकिन जबतक भारत पराधीन है तबतक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यह अपनी भूमिका अदा नहीं कर सकता। भारत पर ब्रिटिश शासन का कायम रहना विश्व शान्ति के लिए प्रयत्नजनक है। शान्ति के भारतीय साम्राज्य को स्वरूप यूरोप का साम्राज्य की शक्तियों में पहले भी मनमुटाव था और इसका लेकर अब उनकी प्रतिस्पर्धिता में और अधिक वृद्धि का सम्भावना हो गयी है। अतएव साम्राज्य में शान्ति बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि भारत को अविनश्य स्वतंत्र कर दिया जाय।

इस पत्र में निलक ने विश्व राजनीति में सम्बंधित कई अन्य प्रश्न भी उठाये। एशिया में यूरोपीय साम्राज्यवाद की स्थिति उसकी कायपद्धति एशियाई देशों के गोपण के तरीकों आदि पर उन्होंने घोर आपत्ति का और यह माना कि पृथ्वी के इस भाग में आत्मनिर्णय का सिद्धान्त तत्काल लागू होना चाहिए। निलक ने भारतीय शासन व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह अत्यन्त अमानवीय जनक है। उन्होंने अंग्रेजों के इस कथन पर कि भारतीय स्वाशासन के माध्यमों से आपत्ति की ओर कहा कि सभ्यता की दृष्टि से भारतीय विज्ञान में कम नहीं है। अतः निलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों के रूप में शान्ति सम्मेलन में अंग्रेजों का कि वह इस बात की मांगता है कि स्वाशासन के लिए भारतीय गवर्णा बोर्ड है और भारत के साथ आत्मनिर्णय का सिद्धान्त तुरन्त लागू किया जाय।²

पेरिस शान्ति सम्मेलन के अध्यक्ष विनमो (Clemenceau) के नाम निलक का यह पत्र कई दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। भारतीय स्वतंत्रता के प्रश्न की एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठान का यह प्रथम प्रयत्न था। युद्ध के बाद भारतीयों में जिस अभ्यन्तर अंतर्राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ उसका यह प्रथम विद्वत्ता। विश्व राजनीति के सम्बंध में भारतीय कांग्रेस की यह पहली घोषणा थी।

1 India's self contained harbours no design upon the integrity of other states and has no ambition outside India. With her vast area, enormous resources and prodigious population she may aspire to be a leading power in Asia and in the world. She could therefore easily be a powerful steward of the League of Nations in the East for the maintenance of peace of the world against all aggressors or disturbers of peace whether in Asia or elsewhere. —Quoted in Andrews and Mukherjee *The Indian National Congress 1885-1947*, p. 271

निलक के इस पत्र के पूरा अंग्रेजी में लिए दलित *Indian National Review* part II 1900 pp. 181-90

जिसने भारतीय और ब्रिटिश दृष्टिकोणों के मौलिक अंतर को स्पष्ट कर दिया। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विशेष नीति का गिला-यास किया और बाद में इसी नींव के आधार पर कांग्रेस की विदेश नीति विकसित हुई।

वर्साय की संधि और भारत—तत्काल का पत्र शांति सम्मेलन के निष्कर्षों को कियी तरह प्रभावित नहीं कर सका। भारतीयों के आत्मनिर्णय के सिद्धांत की भाव की सुवर्णा उपेक्षा की गयी। सरकार द्वारा भेजे गये भारतीय प्रतिनिधि दल ने सम्मेलन द्वारा तयार किये गये वसाय-संधि के मुद्दों पर हस्ताक्षर कर लिया। ऐसा करते समय उसने भारतीय लोकमत पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध किया। वसाय-संधि का विरोध संयुक्त राज्य अमेरिका का सान्ता में भी हो रहा था। वहाँ के रहनेवाले कुछ भारतीयों ने वर्साय-संधि के विरुद्ध प्रचार करना शुरू किया। उन्होंने अमरीकी जनता से आग्रह किया कि वे वर्साय की संधि का स्वीकार नहो करें क्योंकि इस संधि ने राष्ट्रपति विल्सन के आत्मनिर्णय के सिद्धांत को भारत के सम्बन्ध में लागू नहीं दी है।¹ इसी बीच भारतीय कांग्रेस ने अमरीकी सीनेट में प्रस्तुत करने के लिए एक पान पत्र तयार किया। अगस्त 29 1919 का अमरीका सीनेट के एक सदस्य डड्ले फ़िल्ड मेलोन (Dudley Field Malone) ने सीनेट की वदेशिक मामलों की समिति (Foreign Relations Committee) के समय इस पत्र पढ़ा। भारत की वकालत करते हुए उन्होंने कहा कि जबतक शांति संधियाँ द्वारा भारत के साथ गाय नहीं होता उस आत्मनिर्णय या स्वायत्तता का अधिकार नहीं दिया जाता। तबतक संयुक्त राज्य अमेरिका को इन संधियों का अनुमोदन नहीं करना चाहिए। सीनेटर ने कहा कि भारतीयों ने इसी आवासन पर विचार करके युद्ध प्रयास में मित्रराष्ट्रों की मार की थी। यदि उनके साथ इन दिव गये बच्चों का पालन नहीं किया जाता है तो उनका दिल टूट जायगा।² उन्होंने कहा कि सान्ता शांति संधियों में समाधान कर बिस्व के द्वारा यह आवश्यक हो जाय कि इस पर हस्ताक्षर करनेवाले सभी राष्ट्रों का सरकारों का स्वरूप पूर्ण प्रजातांत्रिक हो। सीनेटर मेलोन ने भारत का तत्काल स्वतंत्र करने की माँग की और विश्व शांति के लिए इस परम आवश्यक बताया। अन्त में उन्होंने कहा कि जबतक शांति-संधियों के अन्तर्गत भारतीय समस्या का समाधान नहो हो जाता तबतक संयुक्त राज्य अमेरिका का यह माँग नहो होना चाहिए।

संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट के वदेशिक मामलों की समिति में कांग्रेस के प्रयास में भारतीय प्रश्न का उठाया जाना इस तथ्य की ओर संकेत कर रहा था कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध के क्षेत्र में भारतीयों ने एक नया दृष्टिकोण अपनाया है। युद्ध के पहले भारतीयों ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया था। पर अब स्थिति बिगुल बन गया। ब्रिटिश भारतीय सरकार को अब एक नये क्षेत्र में भारतीयों के विरोध का मुकाबला करना पड़ा।

1 *The Indian Annual Persister* 1920 pt II pp 262-63

2 B Prasad *The Origins of Indian Foreign Policy* pp 63-64

राष्ट्रसंघ और भारतीय लोकमत—हम कह आये हैं कि परिसंघाति-सम्मेलन में शामिल होने और वार्षिक संधि पर हस्ताक्षर करने के फलस्वरूप भारत राष्ट्रसंघ (League of Nations) का प्रारम्भिक सदस्य (Original member) बन गया था। जिस समय राष्ट्रसंघ की स्थापना की बात चली उसी समय भारतीयों ने इसके प्रति अपना उत्साह प्रकट किया था। प्रबुद्ध भारतीय चाहते थे कि राष्ट्रसंघ की स्थापना अवश्य हो और भारत को भी उसका सन्स्थता मिले। तिलक ने विनमो को जो पत्र लिखा था उसमें हम बात की चर्चा की गयी थी और यह आश्वासन दिया गया था कि पूर्व में भारत राष्ट्रसंघ का प्रबल समर्थक बनने का इरादा रखता है। पेरिस के शांति सम्मेलन के निष्पत्ति के अनुसार भारत राष्ट्रसंघ का सन्स्थ अवश्य बना लिया गया लेकिन यह सन्स्थता उस भारत को नहीं मिली जिसकी कल्पना भारतीय नेताओं ने की थी। भारतीय नेताओं का ख्याल था कि यद्योपरांत भारत को स्वशासन का अधिकार मिलेगा और एक स्वशासी भारत राष्ट्रसंघ का सदस्य बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत पर ब्रिटेन का शासन कायम रहा और इसलिए राष्ट्रसंघ में भारतीयों के प्रतिनिधित्व का अधिकार ब्रिटिश भारतीय सरकार को प्राप्त हुआ जो वह न स्थित ब्रिटिश सरकार के आदेशानुसार काम करती थी। इस कारण राष्ट्रसंघ के प्रति भारतीयों का उत्साह तुरंत ही भंग पड़ गया। एक पराधीन राष्ट्र होने के कारण राष्ट्रसंघ में भारत अन्य सदस्य राष्ट्रों के सम्बंध में समानता का दावा नहीं कर सकता था। वह राष्ट्रसंघ की असेम्बली का सन्स्थ अवश्य बना लिया गया लेकिन जब उसने कॉमिशन का सन्स्थ बनने का प्रयास किया तो किंगी ने उसको समर्थन नहीं दिया। विदेशी राष्ट्र राष्ट्रसंघ का भारतीय सदस्यता का गणना को निगाह से देखते थे और असेम्बली में अपने वोटों की सहायता बढ़ाने के लिए इसे ब्रिटेन की चाल समझते थे।¹ अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय (Permanent Court of International Justice) के लिए भारतीय न्यायाधीश बनने के समय भी भारत को पुनः ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा था। इसके लिए दो बार भारतीय उम्मीदवार खड़े हुए (1921 में जमशेदजी टाटा तथा 1938 में सुभाष चंद्र बोस) लेकिन दोनों बार उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा।² इनको लेकर भारत की राष्ट्रसंघीय सदस्यता के वास्तविक स्वरूप का पता लग गया। यद्यपि राष्ट्रसंघ के विधान (Covenant) के अनुसार भारत को सभी सदस्य राष्ट्रों के साथ समान अधिकार था लेकिन उसकी राजनीतिक स्थिति अर्थात् उसकी पराधीनता ने व्यवस्थित रूप से उसे इन अधिकारों का उपयोग नहीं किया।

एक अन्य कारण से भी भारतीय असंतुष्ट थे। राष्ट्रसंघ की असेम्बली का अधिवेशन प्रतिवर्ष जेनेवा में होता था और इसमें भाग लेने के लिए भारत सरकार की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल जाया करता था। इस प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों और उनके नेता की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार किया करती थी। इसमें प्रायः एक ही लोगों

1 D N Verma *India and the League of Nations* pp 65-5

2 Ibid pp 90-91

का नियंत्रण जाता था जो सरकार के पिछे होत थे और जो भारतीय लोकमत से कभी प्रभावित होनेवाले नहीं थे। प्रतिनिधि दल का नृत्तन बसल अंग्रेज करत थे और उन पर किसी भारतीय को नियुक्ति नहीं की जाती थी। सरकार को इस नति से भारतीय लोकमत अत्यंत शत्रु था। इस समय सुक देव का शासन 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत चल रहा था। इस अधिनियम ने भारत के लिए एक केन्द्रिय व्यवस्थापिका (Central Legislature) का स्थापना की था। यद्यपि यह व्यवस्थापिका का सम्पूर्ण व्यवस्थापक अधिकार के आधार पर नहीं हुआ था किन्तु तत्कालीन परिस्थिति में यह माना जाता था कि यह भारतीय लोकमत का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए केन्द्रिय व्यवस्थापिका के दोनों सभा में भारतीय सम्प्रदाय ने जो दार यह प्रश्न उठाया कि राष्ट्रमण्डली के लिए भारतीय प्रतिनिधि दल का संगठित करने का अधिकार केन्द्रिय व्यवस्थापिका को दिया जाय। सरकार के समय यह मांग रखा गया कि व्यवस्थापिका का नामा की एक सूची तैयार करने का अधिकार मिले और इस सूची से सरकार आवश्यकता अनुसार व्यक्तियों का चुन ले। उन सम्प्रदाय में व्यवस्थापिका के दोनों सभाओं में कई बार प्रस्ताव लाये गये थे किन्तु भारत सरकार पर इन प्रस्तावों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनका कहना था कि राष्ट्रमण्डल में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि दल के सदस्यों का चुनने का अधिकार बसल सरकार को है और उसमें व्यवस्थापिका का हस्तक्षेप अनुचित है। सरकार इस मांग को पूरा करने में अस्मर्थ है।

भारतीय प्रतिनिधि दल के नृत्तन को लेकर भी केन्द्रिय व्यवस्थापिका में बड़ा हुगामा आया। प्रतिनिधि दल में राष्ट्रमण्डल के विधान के अनुसार तीन सम्प्रदाय होते थे। 1929 तक भारतीय प्रतिनिधि दल का संगठन इस प्रकार होता रहा एक बरिष्ठ अंग्रेज राजनीतिज्ञ दल का नेता होता था दूसरा सभा में भारतीय विद्वानों का एक नरंग होता था तथा तान्त्रिक व्यक्ति ब्रिटिश भारत का कां प्रमुख व्यक्ति होता था। प्रतिनिधि दल के संगठन के इस तरीके पर भारतीयों ने भार आपत्ति का। उनका कहना था कि एक अंग्रेज को प्रतिनिधि दल का नेता नियुक्त करना गणतन्त्र अयोग्य है जबकि भारत में उच्च न्यायिक राजनीतिज्ञ उपलब्ध है और वायसराय की कार्यकारिणी समिति में भी भारतीय सम्मिलित किया जा रहा है। भारतीयों के लिए यह बड़ा अपमानजनक स्थिति थी कि वे भी उन्हीं के प्रतिनिधि होंगे जो पर दृष्टिहीन किया करते थे। अतएव केन्द्रिय व्यवस्थापिका के सम्प्रदाय ने भारत प्रतिनिधि दल के पूर्ण भारतीयकरण की मांग की और 1922 से 1928 तक लगातार इस प्रश्न पर कई प्रस्ताव रखे गये। कौन्सिल ऑफ स्टेट के सम्प्रदाय भी अपना न इस प्रश्न पर बड़ा हुगामा दिया। मुद्रा में सरकार टानमटान का नाति में काम करती रंग किन्तु अन्त में उस चुनना पड़ा और 1929 में पहली पहल एक

एक प्रस्तावों और उ पर बहुमत के लिए *Journal of the Debates* (1922) vol II pt II pp 1132-42 and *Legislative Assembly Debates* (1922) vol II pt III pp 3626-53

भारतीयकी प्रतिनिधि दलका नेतृत्व करने का मौका मिला। उस वष वायसराय की कायकारिणी समिति के एक सन्स्थ मुहम्मद हबीबुल्ला प्रतिनिधि दल के नेता बनावे गये और उसके बाद हर वष इस पद पर भारतीयों की ही नियुक्ति होती रही।¹

भारतीय प्रतिनिधि दल व साथ और भी कई तरह की सीमाएं थीं जिससे वे भलीभांति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं कर पाते थे। तबप्रथम उनकी नियुक्ति भारत सचिव व द्वारा होती थी और वही उनको आदेश देता था। भारतीय प्रतिनिधि दल को १९०५ आदेश के बंधनों में रहकर राष्ट्रसंघ के समस्त उपस्थित समस्याओं पर अपना दृष्टिकोण निर्धारित करना पड़ता था। इसी आदेशों के अनुसार अमम्बली या उसकी समितियों में व भाषण देने थे प्रस्ताव पेश करते थे और मतदान करते थे। इस अवसर पर वे भारतीय लोकमत या भारत के हित अहित पर जरा भी ध्यान नहीं रखते थे उनकी आवाज भारतीय आवाज होती थी जिनके विचार पूर्णतया विनाशकारी होते थे। इस स्थिति को भारत के राजनीतिज्ञ वगैरे ही अपमानजनक मानते थे। जजिस्ट्रिय असेम्बली में बोलते हुए भगवान दास ने ठीक ही कहा था कि भारत को राष्ट्रसंघ का एक स्वतंत्र सदस्य माना जाता है लेकिन यह निम्न कोटि की है। यह सभी जानते हैं कि भारत की ओर से राष्ट्रसंघ में जो आवाज निकलती है वह भारत की आवाज नहीं बरन इंग्लैंड की आवाज है।² भारतीय हितों की रक्षा कर ब्रिटन के साम्राज्यवादी हितों का रक्षा करना भारतीय प्रतिनिधि दल की निश्चित नीति हो गयी थी। निरस्त्रीकरण के प्रश्न पर भारत ने इसी भावना से प्रतिक्रिया होकर अपनी नीति का निर्धारण किया। राष्ट्रसंघ के विधान के अंतर्गत राष्ट्रों के बीच हथियारबन्दी की हार्ड को कम करने के लिए जेनवा में एक ही साथ कई प्रयास हो रहे थे। उस समय भारत की जो स्थिति थी उसका ध्यान में रखते हुए हम होड को सोमित करने में ही भारत का हित था। सेना और हथियार पर भारत जसा गरीब देश भी अपार खर्च कर रहा था। यदि इस धन का उपयोग उद्योग धंधों की उत्पत्ति पर किया जाता तो देश की आर्थिक अवस्था में पर्याप्त सुधार हो सकता था। इस दृष्टिकोण से निरस्त्रीकरण का कार्यक्रम भारत के लिए बड़ा लाभदायक था और उसे जेनवा में ऐसे ही प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए था। जकिन भारत ने ऐसा नहीं किया क्योंकि यहाँ ब्रिटन व विदेशवादी साम्राज्यवादी हितों के प्रतिष्ठन पड़ता था। अतएव भारतीय प्रतिनिधि दल ने हमेशा भारतीय हित और भारतीय लोकमत की उपयोग करते हुए निरस्त्रीकरण व प्रश्न पर विशिष्ट नीति का समर्थन किया। इस कारण भारतीय नेता बहुत असुखी थे।³

1 D N Verma *India and the League of Nations* pp 83 89

2 The ostentatious pretence is that India is an independent member of the League but everyone knows that this is only brazen diplomacy. The representatives of India on the League have always been the nominated tools and mouthpieces megaphone and microphone of the British Government — *Legislative Assembly Debates* (1937) vol III p 2597

3 D N Verma *India and the League of Nations* pp 98 105

कुछ अर्थ अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर भी भारतीय प्रतिनिधि दल का दृष्टिकोण इसी तरह रहा। 1931 में जापान ने चीन पर आक्रमण किया और चान ने इस बात की शिकायत राष्ट्रसंघ में की। उस समय चानो और भारतीय जनता में बड़ा ही मधुर सम्बन्ध था। चीन जापान युद्ध में भारतीयों की सहानुभूति चान के साथ थी और इसलिए भारतीय नेताओं का विचार था कि राष्ट्रसंघ में भारत चीन का समर्थन करे। लेकिन ब्रिटिश सरकार की नीति ठीक इसके विपरीत थी। वह ऊपर से तो चीन का समर्थन कर रही थी लेकिन उसकी वास्तविक सहानुभूति जापान के साथ थी। अतएव राष्ट्रसंघ में जब चीन जापान विचार आया तो भारतीय प्रतिनिधि दल ने भारतीय जनता का इच्छा की अवहर्तना करत हुए ब्रिटिश सरकार के आदेशानुसार हा अपना दृष्टिकोण निश्चित किया।¹ 1935 में इटली ने अवीसीनिया पर आक्रमण कर दिया। उस अवसर पर भी भारतीय प्रतिनिधि दल का रवैया बड़ा ही निष्पक्ष रहा। भारतीय जनता का सहानुभूति अवीसीनिया के साथ थी लेकिन ब्रिटिश सरकारों के आदेशों पर चलत हुए भारतीय प्रतिनिधि दल ने इटली का ही समर्थन किया।²

यस प्रकार यह स्पष्ट है कि राष्ट्रसंघ की सन्धयता ने भारतीय दृष्टिकोण और सरकारी दृष्टिकोण के बीच के मौलिक अंतर को सामने ला दिया। यह जाहिर हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर दोनों एक दूसरे के विरोधा विचार धारा के पापक हैं। राष्ट्रसंघ के प्रति भारतीय दृष्टिकोण ने यह भी सिद्ध कर दिया कि भारत में अपूर्व अंतर्राष्ट्रीय चेतना का विकास हो गया है।

तुर्की के साथ गान्ति समझौता और भारत—तुर्की का सु-जान मुस्लिम जगत का खलीफा होता था और भारतीय मुसलमान उसको अपना धर्म गुरु मानत थे। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने ब्रिटन के खिलाफ जर्मनी के साथ किया था। अतएव तुर्की के सम्बन्ध में भारतीय मुसलमान गुप्त से ही सक्रिय थे। उनका ख्याल था कि जर्मनी ने तुर्की को घाखा देकर अपने पक्ष में कर लिया है। युद्ध प्रयास में भारतीय मुसलमानों ने इस तमोद पर अग्रजों की सहायता करने का निश्चय किया कि यदि युद्ध में तुर्की हार भा गया तो उनकी भावना का आदर करत हुए इंग्लैंड तुर्की के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनायेगा। जनवरी 1918 में सायड नाज ने एक भाषण में यह संकेत भी दिया कि युद्धोपरांत तुर्की के साथ किसी तरह का दु-प्रवहार नहीं किया जायेगा और न उसके भू-भाग की हस्तगत किया जायेगा। इस आश्वासन के उपरांत भारतीय मुसलमानों ने भी जान से युद्ध में अग्रजों की मर्त्य का।

लेकिन जब युद्ध का अन्त निकट आया तो यह अकवाह्य जारों से फरा कि मित्रराज्यों के बीच तुर्की साम्राज्य के वटवार के लिए गुप्त समझौता किया है और तुर्की के साथ जो समझौता होगा उसका एक बहुत बड़ा भू-भाग छीन लिया जायेगा। एशिया माइनर और अरब का छीना जाना बिनाकुल अव्यय्यभावी प्रतीत हो रहा था। यह भा बात सुनने में आयी कि तुर्की का राष्ट्रपति

1 Ibid pp 106 7

2 Ibid p 107

नोपुल पर भी मित्रराज्य अधिकार कर सेंगे या उसका अन्तर्राष्ट्रीयकरण कर दिया जायगा। कन्स्टांटीनोपुल पिछले चार सौ वर्षों से इस्लाम का केन्द्र स्थल था। यह सारा नगर मुसलमानों की धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ था। इसमें कई ऐतिहासिक मस्जिदें थी और ये इस्लामी सभ्यता के मुख्य केन्द्र मानी जाती थी। ऐसी हालत में तुर्की के साथ होनेवाले व्यवहार के सम्बन्ध में अफवाहें सुनकर मुगलमान बहुत चिन्तित हुए। उनका यह खोम बिबुल स्वाभाविक था।¹

युद्धोपरांत पराजित तुर्की के साथ अच्छा व्यवहार हो और उस पर कोई कड़ी संधि नहीं थोपी जाय इसके लिए भारतीय मुसलमानों ने आन्दोलन शुरू किया और भारतीय लोकमत को तुर्की के पक्ष में बनाने का निश्चय किया। महात्मा गांधी ने मुसलमानों की मांग का समर्थन किया। तुरंत ही एक खिलाफत कांफ्रेंस (Khilafat Conference) की स्थापना हुई जिसका उद्देश्य ब्रिटिश भारतीय सरकार पर दबाव डालना था ताकि तुर्की के साथ संधि हो सके। नवम्बर 1919 में खिलाफत कांफ्रेंस का अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। सभी जागरूक भारतीयों ने तुर्की का समर्थन किया और ब्रिटिश सरकार को यह चेतावनी दी कि यदि तुर्की के साथ अत्याचार किया गया तो इसका परिणाम बड़ा बुरा होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक प्रस्ताव स्वीकार कर सरकार से आग्रह किया कि वह तुर्की की समस्या का समाधान भारतीय मुसलमानों की भावना को ध्यान में रखते हुए करे। एक खिलाफत डिपुटेशन (Khilafat Deputation) को गठित किया गया और उसे यूरोप भेजने का निश्चय किया गया। महात्मा गांधी ने खिलाफत के पक्ष में अत्युत्तम आन्दोलन चलाते हुए निश्चय किया।²

इस प्रकार तुर्की के साथ होनेवाली शांति सन्धि ने भारतीय राजनीति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया और देश का राजनीतिक वातावरण अत्यन्त उष्ण हो गया। सरकार के लिए यह चिन्ता का विषय था। अतएव भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना शुरू किया कि वह भारतीय मुसलमानों की भावना को ध्यान में रखते हुए ही तुर्की के सम्बन्ध में नीति का निर्धारण करे। वायसराय ने अपने कई भाषणों में तुर्की की चर्चा की और भारतीयों को आश्वासन दिया कि उनकी सरकार इस दिशा में यथेष्ट रूप से सक्रिय है और तुर्की के साथ कोई अत्याचार नहीं होने दिया जायगा।

अपने द्वारा दिये गये आश्वासनों को पूरा करने के उद्देश्य से वायसराय ने भी पेरिस शांति सम्मेलन में एक खिलाफत डिपुटेशन भेजने का निश्चय किया। आगा खान, आफताब अहमद तथा मुसूफ खान को सरकार ने पेरिस भेजा। पेरिस शांति सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि दल के साथ मिलकर इस डिपुटेशन ने तुर्की के पक्ष में बकायत की। 17 मई 1919 को सर्वोच्च शांति परिषद् के अध्यक्ष वायसराय लार्ड बोररो वि सन क्लेमण्टो तथा आरलैंडों के समक्ष यह डिपुटेशन उपस्थित

1 S R Mehrotra *India and the Common wealth* p 192

2 B Prasad *The Origins of Indian Foreign Policy* pp 53 56

हुआ।¹ सर्वप्रथम भारत सचिव इ. एस. माट्यू का एक सन्निहत भाषण था जिसमें उन्होंने भारत सरकार व दक्षिण का समझाया। उसके बाद जागा खी बोले। फिर आफ्नाब अहमद युसूफ जना बाकानर के महारान और नाड एस पी सिंहा ने अपने विचार कहे किये।² समा. क. भाषण का एक ही नम्य था— तुर्की व साथ अत्याचार नहीं किया जाय उसका साथ नरमी का बनाव था उस पर कोई ऐसा शांति संधि आरोपित नहीं की जाय जिससे तुर्की की क्षति न हो उसका अपना विशाल साम्राज्य बचाना पड़े।

सम्भवतः शांति-सम्मेलन के उद्घाटक पर भारतीय विद्यमान के उस प्रयास का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और तुर्की व साथ एक अत्यंत कठोर संधि की रूपरेखा तैयार की गया। यह संधि की संधि (Treaty of Sevres) थी। 14 मई 1920 को सेव्रे की प्रस्तावित संधि का प्रारूप प्रकाशित कर दिया गया। भारत में इसके विरुद्ध बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। एक स्वयं से भारतीयों ने उसका विरोध किया। 22 जून 1920 का भारत के प्रमुख नेताओं ने वायसरॉय को पत्र लिखा। इसमें संधि की संधि की आलोचना का गया थी और उस बात पर लाभ प्रकट किया गया था कि तुर्की के विनाश में ब्रिटिश सरकार अपने सभी आवासनों से मुक्त कर दिया जायों का साथ दे रही है। अंत में वायसरॉय से अपील की गयी थी कि वह भारतीय मुसलमानों की भावना पर ध्यान रखते हुए ब्रिटिश सरकार पर संधि में सगा घन के लिए दबाव डालें। यदि भारत सरकार ऐसा नहीं करता तो भारतीयों के समस्त अक्षयभाग आदाना चलाने के अतिरिक्त कोई अन्य चारा नहीं रखा जायगा।

भारत सरकार परिस्थिति की सम्भारता का समझती थी और इसलिए गोपनीय रूप से उसने इन्दिया आफिस पर दबाव डालना शुरू किया। भारत सचिव माट्यू का रुख भी सहानुभूतिपूर्ण था। लेकिन संधि का संधि का संशोधन करना सरल नहीं था। तत्काल क्रुद्ध हान वाला नहीं था। अतएव तुर्की के प्रश्न का उत्तर 1 अगस्त 1920 का भारत में खिलाफत आन्दोलन प्रारम्भ हो गया।

तुर्की के प्रश्न और खिलाफत आन्दोलन के सम्बन्ध में भारतीय काँग्रेस व्यवस्थापिका में व. व. वार प्रश्न उठे और उन पर काफी बहस विवाद हुआ। लेकिन सबसे लूकाना बहस कॉमिल आउट स्टैंड में 21 फरवरी 1921 का हुआ। एक सम्मेलन खिलाफत आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति पर विचार करने के लिए सम्मेलन में काय स्वयं प्रस्ताव (adjournment motion) रखा। बहस के दौरान ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार पर काफी आपत्तियाँ किय गयीं उन पर बचन विमुखता व आरोप लगाय गये और पुनः इस बात की मांग की गयी कि संधि की संधि में आवश्यक संशोधन हो।

तुर्की और खिलाफत के प्रश्न भारत सरकार और इन्दिया आफिस के लिए

1 *Papers Relating to the Foreign Relations of the United States*
Paris Peace Conference 1919 Vol V p 690

2 *Ibid* pp 690-701

लगभग तीन वर्षों तक भयंकर संरक्ष के विषय बने रहे। इसी प्रश्न पर ब्रिटिश विदेश सचिव नाइ कज़न और भारत सचिव मां ग्लू के मध्य घोर विवाद हुआ जिसके फलस्वरूप मांग्लू को पदत्याग करना पड़ा।¹ राजनयिक अन्याय म इसको ठकर महीनों तक बनातनी बनी रही। अंत में सेव्र की संधि को ख म करना पना और उसकी जगह तुर्की के साथ जुलाई 1923 में एक नयी संधि—लूसान का संधि (Treaty of Lausanne) की गयी। तुपान की संधि ने तुर्की के साथ किये गये कई अय यो का अंत कर दिया।

भारत में अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण और चेना व विकास में युद्धापरात तुर्की के साथ गाति संधि की समस्या को एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया जा सकता है। इस मामले पर भारतीय जनमत का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से प्रत्यक्ष सामना आ और पहले-पहल भारत ने विश्व के कूटनीतिक इतिहास को प्रभावित किया। मत्र की संधि में सगाधन और उसकी जगह पर लूसान की संधि को भारतीय लोकमत ने निर्णायक रूप से प्रभावित किया था।²

तुर्की के प्रश्न पर भारतीय र्वि का एक और परिणाम निकला। इसके क रण सत्तार की अय समस्याओं म भी भारतीयों की र्वि बढ़ी और प्र येक अ न र्राष्ट्रीय घटना पर अब व अपना विचार व्यक्त करने लगे। भारत की सहानुभूति निश्चिन्त रूप से पराधीन राष्ट्रों के साथ थी। अब भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस न पराधीन जातियों के मुक्ति आन्दोलन के प्रति सहानुभूति यक्त क ना गुरु किया और इस सन्दर्भ में कई प्रस्ताव स्वीकार किये गये। 1923 के काँग्रेस अधिवेशन ने आयरलैंड के सम्बन्ध म प्रस्ताव स्वीकार करके आयरिश सहोदा के प्रति अपनी श्रद्धाजलि अर्पित की और आयरलैंड के स्वातंत्र्य संग्राम का समर्थन किया।³ तुर्की में मुस्तफा कमान पागा ने कतिपय यूरोपीय राष्ट्रों के खिलाफ युद्ध जारी कर रखा था। इस युद्ध म भारत की सहानुभूति निःसंदेह तुर्की के पग म थी। अतएव युद्ध में जब मुस्तफा कमान विजयी रहा तो भारत ने इसे यूरोपीय साम्राजवाद के विरुद्ध एगियार् राष्ट्रीयता की विजय के रूप म स्वीकार किया। काँग्रेस ने 1923 में तुर्की से सम्बन्ध एक प्रस्ताव स्वीकार किया तुक लोगो को विजय के लिए बधाई दी और तुर्की की विजय को एगियार् राष्ट्रीयता की विजय की गिना में प्रथम क म म ना।

खिलाफत के प्रश्न म र्वि लेने के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति म काँग्रेस की र्वि इतनी बढ गयी कि 1921 म उसने विदेश नीति पर एक बड़ा प्रस्ताव स्वीकार किया। इस प्रस्ताव ने काँग्रेस की विदेश नीति व मूल मिट्टा का प्रतिपादन करते हुए भारत की भावी विदेश नीति का गिनायास किया। इस प्रस्ताव के द्वारा काँग्रेस ने विदेशी राष्ट्रों विपक्षर भारत क पड़ोसी राष्ट्रों को

1 *Indian Annual Register* vol 2 1922 pp 138-1

2 S R Mehrotra *India and the Commonwealth* p 195

3 *Report of the Twenty Fifth Indian National Congress* 1920

यह आवासन लिया कि भारत को संसार के किसी देश से समुदा नहीं है और किसी भी दक्षिणीय से भारत सरकार भारतीय जनमत का प्रतिनिधित्व नहीं करती। प्रस्ताव में स्पष्ट कर लिया गया कि भारत अपने पन्नेसा राष्ट्रों से स्थायी मंत्री कायम करना चाहता। भारत-मरहमद इन राष्ट्रों पर जा संधिया आरापित की है उनको भारतीय जनमत का समर्थन किसी तरह प्राप्त नहीं है। यह भारत और उसके पहासियों के बीच स्थायी खाइ पना करने की साम्राज्यवाणी चाल है और भारत की जनता इस पुणतया अस्वीकार करती है।¹

(iv) एशियाई देशों का संगठन और भारत

इस प्रकार 1919 1921 के काल में विश्व राजनीति के क्षेत्र में कांश्रिप की रुचि अत्यधिक बढ़ गयी और वह साम्राज्यवाद का विरोध तथा पराधीन राष्ट्रों के राष्ट्रीय आन्दोलन का समर्थन करने लगी। इसका फलस्वरूप भारतीयों में पञ्चनित तथा गोपित राष्ट्रों के साथ बंधुत्व का नयी भावना जगी। इसका एक और परिणाम हुआ। भारत के राजनीतिज्ञ यूरोपीय साम्राज्यवाद के विरुद्ध एशियाई देशों को संगठित करने का प्रयास करने लगे।

एशिया की राजनीति में भारत द्वारा रचि लिया जाना भौगोलिक और राजनीतिक दोनों दक्षिणों से आवश्यक और वांछनीय था। भौगोलिक दक्षिणीय से भारत एशिया के मध्य में स्थित है अतएव एशियाई धनशास्त्रों का भारत पर प्रभाव पड़ना आवश्यक था। राजनीतिक दक्षिण से भी एशिया का राजनीति में भारत का बड़ा महत्व था। भारत एशिया में यूरोपीय साम्राज्यवाद का मुख्य स्तम्भ था। भारत पर ब्रिटिश आधिपत्य को कायम रखने के लिए ही एशिया के कई देशों को पराधीन बनाया गया था। पराधीन एशियाई देशों के राष्ट्रिय आन्दोलनों का कुचलन के लिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने भारत का अपना मुख्य सैनिक आधार (military base) बना रखा था। पास पड़ोस के स्वातंत्र्य संग्राम को कुचलने के लिए भारत से ही सैनिक भेजे जाते थे। इस प्रकार भारत सम्पूर्ण एशिया की दासता का प्रतीक बन गया था। ऐसा हालत में यदि भारत आन का साम्राज्यवाणी गुलामी से मुक्त कर लता तो सम्पूर्ण एशिया की मुक्ति का दरवाजा खुल जाता। जसा कि गांधीजी ने कहा था एशियाई और गर-यूरोपीय लोगों के दोषण का मूल आधार भारत है। भारत को स्वाधीन कराके मैं उन सभी पञ्चनित राष्ट्रों का मुक्ति दिलाता चाहता हूँ जो यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा दोषित हो रहे हैं।²

1 Ibid pp 75-76

2 India is the key to the exploitation of the Asiatic and other non European races of the Earth. Through the deliverance of India I seek to deliver the so-called weaker races of the earth from the crushing heels of western exploitation —Quoted by U R Rao, Gandhi and Asia United Asia I (1948) p 59

सुर्को के प्रश्न को लेकर भारतीय राजनीति में जो हलचल मच गई उसका फलस्वरूप भारतीय नेताओं की एशियाई देशों को संगठित करने की गतिशीलता को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला और अपने राजनीतिक भाषणा में वे बराबर इस बात की चर्चा करने लगे। 1922 में खिताफन कांफ्रेंस के गया अधिवेशन में अध्यक्ष पद से भाषण करने हुए एम. ए. जवाहर ने एक एशियाई संघ (Asian Federation) बनाने का प्रस्ताव रखा। 1922 में कांफ्रेंस के अध्यक्ष सी. आर. दास ने एशियाई देशों को पश्चिम के विरुद्ध संगठित करने की आवश्यकता पर बल दिया। 1923 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कांफ्रेंस अध्यक्ष की हैसियत से बोले हुए कहा

पराधान और गोपिन एशियाई देशों की समस्याओं के साथ भारतीय समस्या का तालमेल अत्यंत आवश्यक है। भारत को तत्काल मिस्र, सीरिया, फिलिस्तीन, मारबो आदि के राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करनी चाहिए।¹ 1926 में एक अन्य भारतीय नेता एम. श्रीनिवास आयर ने पुनः इस तथ्य पर जोर देते हुए कहा कि अब वह समय आ गया है जब भारत सभी एशियाई देशों के कल्याण के लिए एक एशियाई संगठन कायम करने की बात साचे।²

एशियाई देशों को संगठित करके एक एशियाई संघ के निर्माण की बात भारतीय राजनीति में इस प्रकार घुस गयी कि कांफ्रेंस ने इस काल में एशियाई देशों के राष्ट्रीय आंदोलनों के समर्थन में कई प्रस्ताव पास किये। कांफ्रेंस के नेताओं में यह विचार जन्म गया कि एशिया की राजनीति से अलग करके भारत की समस्या को नहीं देखा जा सकता है। उनके साथ एकता कायम करके ही भारत को मुक्त किया जा सकता है तथा यूरोपीय राष्ट्रों के साथ समानता प्राप्त की जा सकती है। एशियाई राजनीति में भारतीयों की रुचि इतनी बढ़ गयी कि रवीन्द्रनाथ ठाकुर तथा कई अन्य भारतीय नेताओं ने पड़ोसी देशों का भ्रमण शुरू किया। इन यात्राओं का मुख्य उद्देश्य एशियाई देशों के साथ घनिष्ठतम सम्पर्क कायम करना था।³ एशियाई देशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध कायम करने के लिए भारत में

1 *Indian Annual Register* 1923 II, p 193

2 *Indian Quarterly Register* 1926 II 305-6

3 एशियाई देशों के साथ भारत का घनिष्ठतम सम्बन्ध स्थापित कराने में रवीन्द्रनाथ ठाकुर की दल अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। 1920 में रवीन्द्रनाथ ने शांति निवेदन में एक एशियाई शोध-संस्थान स्थापित करने की योजना बनायी और 1921 में विश्व भारती में भारत-चीन अध्ययन विभाग (Department of Sino Indian Studies) खोला गया। 1923 में चीन के गणराज्य के निमंत्रण पर रवीन्द्रनाथ अपने कुछ साथियों के साथ चीन गये। 3 अक्टूबर 1924 को अपने अंक में किंचित यन साइंस मॉनिटर (Christian Science Monitor) ने इस यात्रा का महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा था कि भारत और चीन के सम्बन्धों में यह भावना-यात्रा एक नया अध्याय खोलिगी।

कवि रवीन्द्र की यात्रा के उपरान्त भारत-चीन अध्ययन विभाग के प्राध्यापक डा. प्रबोध चन्द्र वाग्वीरिंग वि विद्यालय में अल्पकाल के लिए शिक्षक (Visiting Professor) हुआ करते गये।

वई सस्याए कायम की गयीं। एशिया दशों की राजनीतिक सस्यावा के नेताओं को कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों में प्रेषण के रूप में आमंत्रित किया जाना लगा।¹

एशियाई देशों को संगठित करने के इस सद्भावितक दान विधान का एशियाई देशों के सम्मेलनों में भाग लेकर भारतीय नेताओं ने एक आवश्यक रूप लिया। ऐसे सभी सम्मेलनों में स बात का मायता मिली कि एशिया की मुक्ति में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका का निवाह करना है। 1920 में एशियाई देशों का एक सम्मेलन का आयोजन सोवियत संघ ने बाकु (Baku) में किया था जिसमें भारत सहित बीस एशियाई देशों के राष्ट्रीय जागृतेन के नेता शामिल हुए थे। यह पहला अवसर था जब एक सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए एशिया के कुछ देश एक मंच पर उपस्थित हुए थे। बाकु सम्मेलन के बाद एशियाई देशों का दूसरा सम्मेलन 1926 में नागासाका में हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में एशियाई देशों के प्रवेश को निषिद्ध कर दिया था और ब्रिटिश डामिनियन के राज्यों में भी प्रसार विधायक बनाने का बात सोच रहे थे। इस विधायक का विरोध करने में जापान ने अग्रणी का काम किया। सप्रसिद्ध जापानी नेता काउन्ट ओकुमा (Count Okuma) एशिया एशियावालों के लिए (Asia for Asiatics) के जागृतेन का मुख्य प्रवर्तक था। उसी ने इस कानून के विरुद्ध नागासाका में एक एशियाई सम्मेलन का आयोजन किया और उस एक सस्या का रूप देने का प्रयास किया। इस सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन 1927 में गंधार में हुआ और भारत की ओर से प्रताप सिंह ने इसमें प्रमुख भाग लिया।

पश्चित्त राज्यों का दूसरा सम्मेलन—एक सम्मेलनों में साम्राज्यवाद पश्चिमा एशिया के देशों के साथ भी रबीन्द्रनाथ ने मधुर संबंध कायम करने में सफल हुए। अपनी यूरोपीय यात्रा के समय जब वे यूरोप जा रहे थे तो कुछ दिनों के लिए मिस्र में ठहर और मिस्र के राजा फौद न—हैं विश्व भारती के फलानी विभाग के लिए कुछ अरबी पाण्डुलिपियाँ भेंट कीं। मिस्र के महान कवि बूस्तानी (Bustani) कवि रबीन्द्र के निमंत्रण पर शांति निकेतन आये और कुछ संस्कृत महाकाव्यों का अनुवाद उन्होंने अरबी में किया। 1923 में कवि रबीन्द्र का इरान के शाह रेजाशाह पहलवी का व्यक्तिगत निमंत्रण प्राप्त हुआ। उस वर्ष इरान में शाह की धूमनाम से कवि का जन्म दिन मनाया गया था। इस उपरान्त इरान के कवि फोर दाऊद (Fouze Daoud) शांति निकेतन आये। इरान की गान्धी पुस्तकालय से साये हुए कुछ अमूल्य पाण्डुलिपियों को उन्होंने विश्व भारती के पुस्तकालय का भेंट किया।

अपने जीवन के अन्तिम दिनों में जब कवि बामारय इस समय जब का भारतीय एशियाई देशों के भ्रमण पर जान के पहले कवि से भेंट करने जाता था वे भावुकता से गद गद हो जाते। जवाहरलाल नेहरू की चीन यात्रा के समय कवि ने आशुतोष के साथ उन्हें बिना किया था। इस सम्बंध में विस्तृत बतान के लिए देखिये—Tagore Pioneer in Asian Relations *Modern Review* February 1966 pp 109-112

1 D N Verma *India and Asian Solidarity Journal of the Bihar Research Society* vol XLIX 1963 p 322

विरोधी सघ (League Against Imperialism) के संस्थापकान में हुए 1927 का पदलित राष्ट्रों का ब्रसेल्स सम्मेलन (Brussels Congress of Oppressed Nationalities) सबसे महत्वपूर्ण था। इस सम्मेलन का आयोजन बर्लिन के लोगो ने किया था। सबसे प्रथम इसमें ब्रिटेन के उपरवासी मजदूर नेताओं का प्रमुख हाथ था जिन्होंने मजदूर दल (Labour party) की नीति से अमान्य होकर अपना अलग स्वतन्त्र मजदूर दल कायम कर लिया था। ये लोग साम्राज्यवाद के बहुत विरोधी थे। इसका कलना था कि इंग्लैंड के मजदूरों की हानत तब तक नहीं सुधर सकती है जब तक ब्रिटेन के विगत साम्राज्यवाद अन्त नही हो जाय। उपनिवेशों में सस्ती दर पर मजदूर मिनते थे। इस कारण अधिक लाभ कमाने की दृष्टि से ब्रिटेन के पजीपति अपनी अतिरिक्त पूजा (surplus capital) को उपनिवेशों में ही लगाने (invest) लगे थे। इसके फलस्वरूप अनेक मजदूरों की स्थिति दिनोदिन खराब होती जा रही थी। अतएव इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी (Independent Labour Party) वाला ने एक साम्राज्यवाद विरोधी मोर्चा कायम किया जिसका उद्देश्य साम्राज्यवादी दशा में उपनिवेशवाद के विनाश का आयोजन करना था। प्रथम सम्मेलन के आयोजन में इनका प्रमुख हाथ था।¹

साम्राज्यवाद विरोधी मोर्चा की जमनी की सरकार का भी समयन मिला। वर्षों की संधि द्वारा जमनी के सारे उपनिवेश छीन लिये गये थे। अतएव जमनी अब उपनिवेशवाद के रास्ते नहीं चला सका था। वह चाहता था कि यूरोप के अन्य राष्ट्रों के उपनिवेश समाप्त हो जायें और हमारे लिए वह साम्राज्यवाद के विरोधियों को हर तरह की सहायता देने को प्रस्तुत करता था।² इस समय बर्लिन में चीन की कोमिन्तांग पार्टी के प्रतिनिधि बड़े सक्रिय थे। चीन के मुक्ति आन्दोलन को व्यापक रूप देने के लिए वे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे थे और जब इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के लोगो ने उनके समक्ष अपने इस मतलब का प्रस्ताव रखा तब उन्होंने उसका हृदय से साथ इतना स्वागत किया और सम्मेलन को सगठित करने का प्रबल प्रयास किया। वस्तुतः कोमिन्तांग का ही एक प्रतिनिधि जबान्गवान नेम्ह से मिला और उससे अपने सम्मेलन में भाग लेने का आग्रह किया।³

अन्तिम अमेरिका के देशों ने साम्राज्यवाद विरोधी मोर्चे का स्वागत किया। दक्षिण अमेरिका में समुदाय राष्ट्रों के साम्राज्यवादी प्रभार से अधिकतर देशों का भी विगत था। अतः प्रथम सम्मेलन के विचार को उठाने अपना

1 विस्तृत विवरण के लिए देखिये—

(i) Roger Baldwin The Brussels Congress 1927

The Nation (New York) vol 174 No 3273 p 317

(ii) R P Dutt Crisis of Britain and the British Empire p 59

(iii) R L Schuyler The Rise of Anti Imperialism in England Political Science Quarterly XXX VII pp 44 71

2 Jawaharlal Nehru An Autobiography p 161

3 Ibid pp 161 62

जबरन समथन किया।¹ इसी तरह एशिया और अफ्रीका के देशों ने भी इस विचार का स्वागत बड़े उत्साह से किया।

इनके अतिरिक्त सावित्र सुध और पश्चिम घूराप का कम्पुनि-पात्रियों न सम्मत्तन को सफल बनान तथा साम्राज्यवा विराधी माचा का मुद्र कान में ज्वना बमूल योगदान दिया । सावित्र सुध न सरकारा तौर पर सम्मत्तन का समर्थन किया ।

1926 में सम्मेलन के आयोजकों ने फरवरी 1927 में ब्रूमस में पत्रालित राज्यों का एक सम्मेलन बुलाने का निश्चय किया। उस समय जवाहरलाल नेहरू अपनी पत्नी के साथ के तिलसिन के घ्राण में थे। वहाँ कुछ राज्यों ने उनसे मुलाक़ात की और ब्रूमस सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शामिल होने की दान व।। नेहरू ने उस विचार का स्वागत किया और कांग्रेस ने अनुराण किया कि इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए वह एक प्रतिनिधि भेजें।³ कांग्रेस ने अपना गौहा अधिवेशन मध्य प्रस्ताव पर विचार करके नेहरू का आदेश दिया कि वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से ब्रूमस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करें ताकि हमारा राष्ट्रीय आन्दोलन साम्राज्यवाद के विरोध में हा रहे विवन्धाया आन्दोलन के साथ जुट जाय।⁴ — उस प्रकार ब्रूमस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार जवाहरलाल नेहरू को प्राप्त हुआ।⁵

को कुचलने के लिए बाहर भेजा गया है। न बातों से यह सिद्ध होता है कि सम्मेलन ने भारतीय स्थिति को विशेष महत्व दिया था।

जवाहरलाल नेहरू के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने का यह पहला अवसर था। भारत की स्वतन्त्रता की समस्या को विश्व लोकमत के समक्ष रखना तथा एशिया के पड़ोसी देशों के साथ सम्पर्क स्थापित करना इन्हीं दो उद्देश्यों को सामने रखकर उन्होंने सम्मेलन में काम किया। सम्मेलन के शुरू होने के एक दिन पूर्व समाचारपत्रों के प्रतिनिधियों ने बातचीत करते हुए उन्होंने भारतीय समस्या और विश्व पर उसके प्रभाव का उल्लेख किया और बतलाया कि पराधीन जातियों की मुक्ति के लिए भारत की स्वतन्त्रता परम आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत की समस्या को राष्ट्रीय समस्या नहीं है यह एक विशुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है क्योंकि भारतीय स्वतन्त्रता के साथ कई पराधीन देशों का भाग्य जुड़ा हुआ है। संसार के जापानों का मुक्ति के लिए भारत की स्वतन्त्रता जरूरी है।

दूसरे दिन सम्मेलन में भाषण करने हुए उन्होंने इन बातों को दुहराया। इस अवसर पर उन्होंने भारतीय सेना को बाहर भेजे जाने की बात का भी उल्लेख किया और बतलाया कि किस प्रकार दूसरे देशों का राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए भारत के साधनों का प्रयोग किया जाता है। उन्होंने कहा हमारे लिए भारत की स्वातंत्रता आवश्यक है लेकिन हमारी स्वतन्त्रता आपके लिए भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। हमारी पराधीनता आपकी स्वातंत्रता के लिए सबसे बड़ा बाधा है अतः अब हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारी मदद कीजिये। इसमें आपका भी योगदान है।¹

अब से सम्मेलन में चीन के प्रतिनिधित्व ने नेहरू को बड़ा प्रभावित किया। सम्मेलन के सम्बन्ध में उन्होंने कांग्रेस को जो प्रतिवेदन² पेश किया उसमें चीनियों के उत्साह उनकी शक्तिशाली प्रवृत्ति आदि की बड़ी प्रशंसा की गयी थी। इसमें नेहरू ने लिखा था कि इस क्षण में भारत को चीनियों का अनुकरण करना चाहिये। भारत और चीन के प्राचीन सम्बन्ध नये तौर पर पुनः स्थापित करने के लिए चीन के प्रतिनिधियों के साथ उन्होंने घनिष्ठतम सम्पर्क स्थापित किया। 9 फरवरी के अपने सभापतिता सम्मेलन में ही उन्होंने चीन के प्रश्न को उठाया और कहा कि भारत चीनियों के संघर्ष के साथ पूर्ण मेलानुभूति रखता है। उन्होंने यह आगाह्यवन की कि चीन में राष्ट्रवादी या की विजय से एशिया के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू होगा। नेहरू ने कहा हमारे लिए ये बड़े ही अपमान और शर्म की बात है कि भारतीय सेना का प्रयोग चीन के राष्ट्रवादीयों को कुचलने के लिए किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका घोर विरोध किया है और भारतीय सज्जित स्नेहि अनेकवली में भी यह प्रश्न कई बार उठाया गया। भारतीय जनपत्रिकाओं में भी इस विषय का आवाज उठाया है। लेकिन ब्रिटिश भारतीय सरकार पर इसका

1 *Indian Annual Register* vol I (1927) pp 205-7

2 प्रतिवेदन (Report) के पूरा अर्थ के लिए देखिये B Prasad *The Origins of Indian Foreign Policy* pp 262-80

का बनर नहीं पड़ा है। फिर भी हम भारतीय मन्त्रालय मन्त्र मन्त्र का इस निश्चिन्ता नाति से बना हान का घोषणा करते हैं भारत का जय पान्ति का नाम है—केवल इसलिए नहीं कि नाम का साथ हमारी सम्पत्ति के साथ ना अनुभव करते हैं कि चीन के राष्ट्रवादी का विद्रोह में साम्राज्यवाद का नष्ट करने में हमें पर्याप्त सहायता मिलेगी।

इस समय सम्मेलन में भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रति स्वयं को समझने पर पर्याप्त बात विचार आता। सम्मेलन में यह स्वाभाविक कि प्रत्यक्ष राष्ट्रीय का मुक्ति के लिए भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का विशेष भूमिका होना चाहिए। भारत के सम्मेलन में सम्मेलन में एक प्रत्यक्ष स्वीकार किया। अतः हमें भारत की स्वातंत्र्य मुक्ति के समर्थन किया गया मान के राष्ट्रवादी का क्या गया कि वे अन्तर्गत के किसान द्वारा मजदूरों का स्थिति पर विशेष ध्यान दें और दूसरे का नामों में कहा गया कि वे का अपना बाय नहीं करें जिससे भारत का स्वतंत्रता के आन्दोलन में बाधा पड़ेगा।

सम्मेलन के अंत में भारत द्वारा चाक प्रतिनिधियों का एक संयुक्त विनिर्दिष्ट प्रस्तावित यह प्रस्ताव सम्मेलन में एक प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किया। इस विनिर्दिष्ट में जाना गये—प्रधान मन्त्रियों का अंतर्गत या जोर हमें बहुत पर बल दिया गया था कि हमें सुझाव का प्रति सम्मेलन करना जरूरी है। हमें क्या गया था कि दोनों पक्षों में भारतीय मन्त्रालय के प्रधान का प्रति करते हैं और चाहते हैं कि दोनों पक्षों में स्वतंत्रता के लिए नवम्बर के अन्तर्गत मित्रों के जो निश्चिन्ता में सम्मेलन के अन्तर्गत जाना गया था कि वे निम्न निम्न साम्राज्यवाद का एक ही मार्ग या मोर्चा पर लड़ना पड़े।

1 *Indian Annual Register* vol 1 (1927) p 211

2 भारत के सम्मेलन में चाक मन्त्रालय के प्रस्ताव के प्रकार था—

The Congress (Brunei Congress) accords its warm support to the Indian National Movement for complete freedom of India and is of the opinion that liberation of India from foreign domination and all kinds of exploitation is an essential step in full emancipation of the people of the world. This Congress trusts that peoples and workers of other countries will fully co-operate in this task and will specially take effective steps to prevent the dispatch of foreign troops to India and the retention of an army of occupation in that country. This Congress further trusts that the Indian National Movement will base its programme of the full emancipation of peasants and workers of India without which there can be no real freedom and will co-operate with movements for emancipation in other parts of the world —*Indian Annual Register* vol 1 (1927) p 217

3 बा में इंग्लैंड के प्रतिनिधि ने भी इस विनिर्दिष्ट प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि वे इंग्लैंड में निम्न साम्राज्यवाद का अन्तर्गत नाति का अन्त करने के लिए आन्दोलन शुरू करें जिससे भारत और चीन दोनों के राष्ट्रीय आन्दोलनों का सहारा मिले।

सम्मेलन में नेहरू द्वारा चीन का पण समयन उनकी कुशल राजनीतिज्ञता और दूरदर्शिता का परिचायक था। तत्कालीन विश्व राजनीति के विश्लेषण के उपरान्त नेहरू को इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ा कि भारत द्वारा चीन का पण समयन भारत के हित में आवश्यक है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद और चीनी राष्ट्रवाद का संघर्ष बड़ा भयंकर रूप धारण करता जा रहा था और दोनों के मध्य एक भीषण संघर्ष की सम्भावना बहुत बढ़ गयी थी। इस युद्ध का प्रभाव भारत पर अनिवार्य रूप से पड़ता क्योंकि इसका सारा भार भारत को वहन करना पड़ता। इस युद्ध में केवल भारतीय घन और जन की बर्बादी होनी जिसके फलस्वरूप भारतीय जनता की आर्थिक परेशानी और बढ़ जाती। अतः भारत का क्याण इसी में था कि वह ऐसे युद्ध को छिड़ने से रोके। यह तभी सम्भव था जब भारत में चीन के पक्ष और ब्रिटेन के विपक्ष में एक सबल आंदोलन चलाया जाय और ब्रिटिश सरकार का दाव्य कर लिया जाय कि चीनी जनता को दबाने के लिए वह भारतीय साधना का प्रयोग नहीं करे। व मेम सम्मेलन के अपने प्रतिवेदन में नेहरू ने इस तथ्य को सामने रखा था और कायस को परामर्श दिया था कि वह बड़े पमाने पर एक आंदोलन प्रारम्भ करे और चीन में भारतीय साधनों के प्रयोग को असम्भव बना दे।

व मेम सम्मेलन के उपरान्त नेहरू को स्वदेश लौटने पर काँग्रेस द्वारा चीन के सम्बन्ध में कई प्रस्ताव स्वीकार किये गये। 1927 में काँग्रेस ने चीन के प्रति सहानुभूति का प्रस्ताव पास किया और चीन से भारतीय मना की वापसी की माँग की। वहाँ बिक्रितस्त्री का एक जया भी भेजने का निश्चय किया गया, लेकिन भारत सरकार ने हमके लिए आवश्यक अनुमति नहीं दी। उसी वष अपने वार्षिक अधिवेशन में काँग्रेस ने चीन से सम्बद्ध एक दूसरा प्रस्ताव पास किया। इसमें चीन के मामले में ब्रिटिश हस्त उप की निंदा की गयी थी। इस प्रस्ताव के द्वारा पुनः चीन में भेजे गये भारतीय सेना की वापसी की माँग की गयी। इस प्रस्ताव ने भारतीयों को परामर्श दिया कि वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद का एक टुकड़ा चीनी जनता के दमन के लिए चीन न जाय क्योंकि चीनी और भारतीय साम्राज्यवाद के विरुद्ध हो रहे संघर्ष में साथी एवं सहयोगी हैं। इस प्रकार चीन के प्रति भारत की स्वतंत्र नीति की नींव व मेम सम्मेलन के बाँट डाली गयी।

व मेम सम्मेलन ने नेहरू और उनके जरिये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस की विचारधारा को अत्यन्त निष्ठापूर्ण रूप में प्रभावित करके राष्ट्रवादी भारत की विदेश नीति को एक नया मोड़ दिया। नेहरू ने कांग्रेस का चेतावनी देते हुए कहा कि भारतीयों को केवल अपनी ही दुनिया में सीमित नहो रहना चाहिए। बाह्य जगत् की शक्ति और अधिक शक्ति संचयन करने में ही भारत का हित है। नेहरू के इस विचार का अनुमोदन काँग्रेस ने एक प्रस्ताव स्वीकार करके किया। प्रस्ताव में कहा गया था कि भारतीय जनता का राष्ट्रीय संघर्ष ससार के सभी छोड़ित राष्ट्रों के मुक्ति संघर्ष का एक अंग है और इसलिए भारत को ऐसे सभी राष्ट्रों के साथ अपना सम्पर्क कायम करना चाहिए। इस समय काँग्रेस के अन्दर

एक विदेश विभाग (Foreign Department) खोलने का निणय किया गया । उससे उभरात काँग्रेस ने अपने वार्षिक अधिवेशनों में प्रत्येक वर्ष सम्मिलित होने के लिए विश्वास प्रतिनिधि दल को नियमित रूप से आमंत्रित करना शुरू किया । इस तरह के प्रतिनिधि दल अब निरंतर आने लगे ।

ऐस प्रकार सभार के अन्तः पराधीन राष्ट्रों के साथ भारत का सम्पर्क बढ़ने लगा और उनकी राजनीति में काँग्रेस भी धीरे धीरे रुचि लेने लगा । 1928 के काँग्रेस अधिवेशन ने बड़े पैमाने पर अनेकानेक प्रस्ताव स्वीकार किये । इन प्रस्तावों द्वारा मित्र सीरिया पर कब्जे के खिलाफ अन्तराष्ट्रीय मुक्ति संग्राम का समर्थन किया गया और उनके प्रति भारतीय जनता का सहानुभूति का आवाहन किया गया । काँग्रेस ने एशियाई संघ (Asian Federation) के निर्माण की सम्भावनाओं पर विचार किया । इस संयुक्त ने इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें कहा गया कि सम्पूर्ण एशिया के संघ निर्माण के हेतु काँग्रेस विचार करे और 1930 में मुम्बई प्रथम अधिवेशन दिल्ली में बुलावे । काँग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और अपनी कार्यकारिणा समिति का आह्वान किया कि वह ऐसे एशियाई संघ के संगठन के लिए सर्वश्रेष्ठ कदम उठावे ।

काँग्रेस के प्रस्ताव और प्रयास के बावजूद एशियाई संघ का कोई अधिवेशन भारत में नहीं हो सका । इस समय तक काँग्रेस देश का आन्तरिक राजनीति में बुरा तरह डूब चुका था और असहयोग आन्दोलन का सवारी में पड़ चुका था । तबले ब्रिटेन सम्मेलन में भाग लेने के फलस्वरूप भारत अन्तराष्ट्रीय सम्मेलनों के प्रति जागरूक हो गया । इसमें उसकी रुचि इतनी बढ़ गयी कि उसने नियमित रूप से ऐसे प्रत्येक सम्मेलन में भाग लेना शुरू किया । साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलन (League Against Imperialism) की विविध समितियों के अतिरिक्त इस समय भारत ने जिन जिन अन्तराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया उनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं—1929 के लाहौर और 1930 के टाकियो के अखिल एशियाई सम्मेलन (Pan Asiatic Conference) 1928 का हार्ने का विश्व युवक शान्ति सम्मेलन (World Youth Peace Conference) 1928 का ब्रिस्बेन का श्रम और समाज अन्तराष्ट्रीय सम्मेलन 1934 का कानम्बा का अखिल एशियाई श्रम सम्मेलन (Pan Asiatic Labour Conference) । इन सम्मेलनों में शामिल होकर भारत ने निश्चय ही एशियाई देशों का संगठित करके आन्दोलन का आग बल्ले में सूर्योदय कर दिया ।

भारतीय एशियाई सम्मेलन का एक और अभिप्रायक परिणाम निकला । सम्मेलन में भाग लेने के लिए कई पराधीन राष्ट्रों के नेता आये थे । उनमें से कुछ का अखिल भारतीय सम्पर्क स्थापित हुआ । यह सम्पर्क बाद में वर्षों तक बना रहा और इससे भारत का और दूसरे एशियाई देशों को नाम हुआ । 22 अगस्त 1946 का इंडिया काउंसिल ऑफ वॉर एफेयर्स (India Council of World Affairs) की सम्बन्ध-शाला के समस्त भाषण करते हुए नेहरू ने कहा था आपकी यह जानकारी खुशी होगी कि हमारे कुछ मित्र जिनसे हमारी मित्रता आज से बीस

चप पूव व से-स मे हुई इण्डोनिशिया म आज सरकार चला रहे हैं। इस मित्रता से आज भी हमे लाभ पहुँच रहा है क्योंकि उनके साथ व्यक्तिगत सम्बन्ध ने मुने उनकी समस्याओं मे व्यक्तिगत चिन्ता करा दी है और वे लोग भी भारत की समस्याओं में रुचि ले रहे हैं। अभी हाल म (जब भारत म खाद्यान्ना की कमी थी) उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा मे हमारे यहाँ चावल भेजा है। यह युद्ध अर्थों मे उस व्यक्तिगत सम्पर्क का परिणाम था जिसको बीस वर्ष पूव हमने व स से म कायम किया था।¹

एशियाई एकता की भावना का चरम विकास—यूरोपीय साम्राज्यवाद का विरोध करने के लिए एशियाई देशों को एक सूत्र में संगठित करने का उत्साह भारत म कभी मद नहीं पड़ा। तबिन 1931 में मधुरिया को लेकर जापान ने जब चीन पर आक्रमण कर दिया तो भारतीय नेताओं को इससे बड़ा सदमा पहुँचा। उन्होंने इस प्रगतिशील एशियाई एकता आंदोलन पर प्रशंसा आक्रमण माना। 1905 से ही भारत जापान के प्रति बड़ा उत्साह प्रदर्शित करता आ रहा था। उसका विश्वास था कि एशिया के मुक्ति आंदोलन मे जापान सहायक होगा और वह एशियाई देशों का नेतृत्व करेगा। भारत की समस्या मे भी जापान बहुत दिनों से अत्यंत सहानुभूति पूर्ण रुचि लेता आ रहा था। जापानी नेताओं ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का केवल समर्थन ही नहीं किया था वरन् इसमे सहायता देने का अवसर भी दिया था।² इस कारण भारत में जापान के प्रति बड़ी उदासी थी लेकिन जब उसने चीन पर आक्रमण कर उसके भू-भागों को हस्तगत करना शुरू किया तो भारत का सारा उत्साह समाप्त हो गया। चीन जापान युद्ध मे भारत की पूरी सहानुभूति चीन के साथ थी। भारतीयों की इस भावना की झलक हमें रवी द्रनाथ ठाकुर के उपन्यास में मिलती है जिसे उन्होंने एक प्रसिद्ध जापानी कवि का लिखा था और जिसमें जापान के वास्तविक उद्देश्य का रहस्योद्घाटन किया था।³

भारतीय लोकमत चाहता था कि ब्रिटिश सरकार चीन का पक्ष लेकर जापान

1 It might interest you to know that some of the friends I made twenty years ago at the Conference [Brussels] are running the Indonesian republic today and those contacts have stood us well now because apart from knowing each other distantly personal relationship made me personally more interested in Indonesia and to some extent made them interested in India.

Recently some months back they offered to send a great deal of rice here. That too was partly due to certain personal contact that began nearly twenty years ago.

—Jawaharlal Nehru *India As an Relations Indian Quarterly* October-December 1946 p. 2

2 John Grotte *Japan Fights For Asia* p. 261

3 G. S. Pohekar *Tagore and Asia United Asia* I 1948

क विरुद्ध सैनिक कार्रवाही करे। लेकिन उस समय भारतीय लोकमत का महत्व हो क्या था? फिर भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने कतब का पानन किया। उसने चीन के सम्बन्ध में पुनः क' प्रस्ताव पास किया। एक प्रस्ताव के द्वारा भारतवासियों को कहा गया कि विरोध जताने के लिये सब जापानी मालों का बहिष्कार करें। सम्पूर्ण देश में एक एक बार चीन दिवस (China Day) मनाया गया।

चीन और जापान का यह संघर्ष वनों तक लगातार चलता रहा और बाद में चलकर यह द्वितीय विश्व-युद्ध का भाग बन गया। लेकिन इस संघर्ष के बीच भारत ने लगातार चीन का समर्थन किया। दिसम्बर 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अध्यक्ष को चीनी नेता चू तै-का एक पत्र भिजा। उस पत्र में उन्होंने भारत का सहानुभूति के लिए धन्यवाद दिया था और अपने पत्र के विरुद्ध संघर्ष में भारत की सहायता माँगी थी। इस पत्र का पाठ ही कांग्रेस अध्यक्ष ने दण्डीसियों में अपनी बातों का कि वह 9 जनवरी 1938 का पुनः चीन दिवस मनाकर चीन के प्रति अपना सहानुभूति प्रदर्शित करें। उस दिन सम्पूर्ण देश में जमाए हुए और चीन की मदद के लिए चला इकट्ठा किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि उस संघर्ष की घड़ी में चीन की सहायता करना हर स्वतंत्रता प्रेमी का परम पुनात कर्तव्य है।¹ इसके तुरंत बाद कांग्रेस ने डा. एम. अन्तर्गत नृत्त्व में पाँच डॉक्टरों का एक मेडिकल मिशन संगठित किया और 1938 में उस चीन भेजा। मुमापचन्द्र बास के नेतृत्व में यह चीन के प्रति भारत की अपार सहानुभूति का प्रतीक था। चीन का उल्लास और सरकार ने इस मेडिकल मिशन का अत्यन्त स्वागत किया। मिशन का उस सैनिक जहाज के साथ संगठन किया गया जिसका नेता माओत्से तुंग था। माओ ने भारतीय मेडिकल मिशन के कार्यों का प्रशंसा करते हुए नेहरू का एक पत्र लिखा और इसके लिए भारतीय जनता को धन्यवाद दिया।²

चीन के प्रति भारत की प्रगाढ़ सहानुभूति प्रकट करने के लिए 1939 में स्वयं जवाहरलाल ने चीन का यात्रा का और वहाँ जनसंग पट्टे त्यों तक टहरा। इस यात्रा के महत्व का वर्णन करते हुए अपना आत्मकथा में उन्होंने लिखा है— चीन की मेरी यह अल्पकालीन यात्रा हमारे लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण थी। मैं और भारत चीन के भावी सम्बन्धों के दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्वपूर्ण रहा। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि चीन के नेता हमारे इस विचार से कि भारत और चीन के बीच अनिच्छित सम्बन्ध स्थापित हो चुका है, सहमत थे। उनसे साथ मैं चीन और भारत के भविष्य पर बातें करता था। भारत चीन पर मैं चीन और चीनी जनता का प्यार की वरण और अधिक प्रभावित बन गया। यात्रा में इस बात का कहना भी नहीं कर सकता हूँ कि मैंने प्राचीन राष्ट्रों का भगवान और उनकी निराला कला देखी।³

1 *Indian Annual Register* vol I 1938 p 291

2 B Prasad *The Origins of Indian Foreign Policy* p 127

3 Jawaharlal Nehru *An Autobiography*, p 603

इसी वर्ष नेहरू ने मिस्र और लका की भी यात्रा की। काहिरा में वक्तापार्टी के नेताओं से उनकी मुलाकात हुई जहाँ उनके साथ उ होने पारस्परिक हिता की समस्याओं पर विचार विमर्श किया। लका में उन्होंने प्रवासी भारतीयों की समस्याओं के समाधान का प्रयत्न किया। इन यात्राओं ने नेहरू के एंग्लो-संघ और एकता की भावना को सुदृढ़ किया। बाद में उन्होंने लिखा कि भविष्य के बारे में मरी बलवान है कि चीन भारत बर्मा लका और कुछ अव देशों को मिलाकर एक संघ कायम हो।

इस प्रकार एंग्लो-संघ की एकता और उनके संगठन की बात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और नेहरू के कार्यक्रम में हमेशा बनी रही। द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में ही इस क्षय करके इस भावना पर जबरदस्त कुठाराघात किया। लेकिन युद्ध के समाप्त होने ही यह भावना पुनः भारतीय राजनीति में प्रविष्ट हुई। जवाहरलाल नेहरू के परामर्श पर इंडिया कौंसिल ऑफ वल्ड एक्जम 1946 में एक एंग्लो-सम्मेलन बुलाने का फैसला किया और भारत की स्वतन्त्रता के पूर्व ही माघ अग्रिन 1947 में इस सम्मेलन की बैठक नयी दिल्ली में हुई।

(v) यूरोपीय समस्याओं और द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रातः भारतीय दृष्टिकोण

1931 से यूरोप का राजनीतिक और राजनयिक वातावरण अमान्य होने लगा और धीरे-धीरे नवी विश्व युद्ध की तयारी होने लगी। 1933 में हिटलर ने जर्मनी के शासन पर कब्जा करके अपना अधिनायकत्व कायम किया। इससे पूर्व इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में फासिस्ट प्रणाली का शासन तत्त्व स्थापित हो चुका था लेकिन 1930-1935 की यूरोपीय घटनाओं पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विशेष ध्यान नहीं दिया। उस समय भारत की आंतरिक राजनीति यही हावाबोला थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आन्दोलन चल रहा था और समझौता हुआ और सन्तान में गोलमज सम्मेलन की धूम रही। भारतीय नेता इन्हीं घटनाओं में व्यस्त रहे लेकिन 1935 से जब यूरोप में फासिस्टवाद और नारसवाद का जन्म नृत्य होने लगा तो कांग्रेस के लिए यूरोपीय घटनाओं के प्रति उदासीन रहना अगम्य हो गया। कांग्रेस ने फासिस्टवाद का घोर विरोध किया। उसकी पवित्र विरोधी नीति का प्रवक्तृ जवाहरलाल थे। फासिस्टवाद से उनका घृणा इतनी तीव्र थी कि जब मुसोलिनी ने उन्हीं इटली आने के लिए आमंत्रित किया तो नेहरू ने इसे तत्काल अस्वीकार कर दिया।¹

1935 में इटली ने अबीसीनिया पर हमला कर दिया। अबीसीनिया में राष्ट्रमण्डल का अंगत्व की अपील की लेकिन महान राष्ट्रों की दुरंगी नीति का कारण राष्ट्रसंघ ने उसकी कोई सहायता नहीं की। कांग्रेस के संघन ऊर्ध्व विवेचन (अप्रैल 1936) में नेहरू ने अपने अध्यक्षीय भाषण में इंग्लैंड की आक्रमण की तीव्र भाषना की और कांग्रेस ने अबीसीनिया से सम्बंधित एक प्रस्ताव स्वीकार किया। इसमें अबीसीनिया के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गयी थी और कहा गया था कि अबीसी

पर यदि युद्ध का उद्देश्य जनतांत्रिक आधार पर सत्कार में नयी व्यवस्था कायम करना है तो कांग्रेस का इन युद्धों में बड़ी रुचि होगी। अतएव कांग्रेस ने न यह माँग की कि यदि मित्रराष्ट्र सत्कार में जनतन्त्र की व्यवस्था चाहते हैं तो आवश्यक है कि सर्वप्रथम वे अपने उपनिवेशों को स्वतन्त्र कर अपना अङ्गीकार कर लें। कांग्रेस का कहना था कि यदि सरकार युद्ध में भारतीय जनता का समर्थन और सहयोग चाहता है तो वह भारत का तरास स्वतन्त्र कर दे। स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में ही भारत नए युद्ध में सम्मिलित हो सकता है।

भारत सरकार या ब्रिटिश सरकार पर कांग्रेस की इस योजना का काइ प्रभाव नहीं पड़ा और वे कान में तल डालकर शांत बैठ रहे। भारतीय राजनीति में एक तरह का गतिराज्य पदा हो गया।

1942 में युद्ध का स्थिति अत्यन्त नाजुक हो गयी। संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें प्रवृत्त कर गया और सोवियत संघ पर जर्मन आक्रमण से युद्ध के रूप में भारी परिवर्तन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के निरन्तर गिठन से अमेरिका राष्ट्रपति रूजवेल्ट और चीना नेता च्यांग-काइ-शेक ब्रिटिश सरकार पर भारतीय समस्या के समाधान के लिए दबाव डालने लगे। प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिल ने नए स्फूर्ति द्रव्य को भारतीय गतिरोध का मुन्धान के लिए भेजा लेकिन जिस का मिशन सफल नहीं हो सका। उनके उपरांत अगस्त 1942 में कांग्रेस ने माँग पत्रान पर सरकार के खिलाफ संधप शुरू कर दिया। सरकार ने इस भारत छोड़ो आन्दोलन को शांति ही कुचल दिया। भारतीय नेता कद कर लिये गए। युद्ध प्रयास में भारतीय साधनों का प्रयोग होता रहा और इसका विरोध करनेवाला ना नहीं रह गया। कांग्रेस के सभी नेता जेल में बन्दे। युद्ध में भारत का अपार धन और हानि उठाना पड़ी पर भारतीय अर्थिकी से युद्ध से भारत का कुछ लाभ भी हुआ। युद्ध के समय चालू अरान और दशा से भारत का सम्पर्क बना। नया नयी संकेत बनी। 1942 में त्याग से एक सम्भावना मिशन भारत जाया। फरवरी 1942 में च्यांग काइ-शेक ने भारत की यात्रा की। उस भारत और चीन के सम्बन्ध में दृष्टा आया। सर जफर जहाँ चीन में भारत के एजेंट बनने नियुक्त हुए। राष्ट्रपति रूजवेल्ट के विशेष राजदूत बने बार भारत आए। संयुक्त भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के सम्बन्ध में एक नया अध्याय शुरू हुआ। संयुक्त राष्ट्रसंघ (U N O) की स्थापना के लिए जो बातें चर्चा में आये, उसमें भारतीय प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक गतिविधि में भारत ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के पहले ही एक प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया। विविध अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर अपना प्रतिक्रिया व्यक्त कर तथा अपने अर्थिकी के सम्बन्ध में प्राप्ति करते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतन्त्र भारत की विदेश-नीति का पृष्ठाधार स्याद कर दिया।

भारतीय विदेश-नीति के निर्धारक तत्व

(Determining Factors of Indian Foreign Policy)

आज के युग में विदेश-नीति प्रत्येक देश के प्रशासन का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग बन गया है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की जटिलता उतनी बढ़ गयी है और उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है कि हर देश को इस पहलू पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। यह अनिवार्य है। राजनीति जीवन का मूल बन चकी है और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रभाव से कोई मुक्त नहीं है। यह हमारे जीवन को तिन प्रतिनिधि और प्रशयन रूप से प्रभावित करती है। इसलिए अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखत हुए प्रत्येक देश को अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं के प्रति दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है। इस स्थिति में जब किसी राष्ट्र की नीति की अविवक्षित होती है उसको विदेश की नीति कहते हैं। इसके निर्धारण का काम कभी कभी बड़ा कठिन और दविधाजनक स्थिति में डालनेवाला होता है।

15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत सरकार के समस्त विदेश नीति के निर्धारण की कोई समस्या नहीं थी। ब्रिटिश शासन काल में भारत द्वारा जो विदेश-नीति अपनायी जाती थी उसे हम शुद्ध रूप में भारतीय विदेश नीति कहा सकते क्योंकि हमसे सम्बन्धित सभी नियमों और प्रोटोकॉल को सरकार द्वारा लिये जाते थे और उन नियमों को भारत सचिव भारत सरकार तक पहुँचा देता था। लेकिन 15 अगस्त 1947 की स्थिति एकदम बदल गयी और भारत सरकार को अपनी विदेश नीति के निर्धारण का पूरा अधिकार मिल गया। यह अत्यन्त बर्तन उत्तरदायि व था। विदेश नीति का निर्धारण बस ही कठिन होता है लेकिन सचिव और आर्थिक दृष्टि से कमजोर नवाहित राष्ट्र के लिए तो यह कठिनाई कई गुना बढ़ जाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत को ऐसा ही स्थिति का सामना करते हुए अपनी विदेश नीति का निर्धारण करना पड़ा। स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत ने जिस विदेश नीति का निर्धारण किया उसने मुख्य निर्धारक तत्व निम्न लिखित थे

(1) देश की भौगोलिक स्थिति—जिसो भी राष्ट्र की विदेश-नीति में कोई भौगोलिकता नहीं होती। बहुत अर्थों में इसका निर्धारण देश की भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है। के एम पणिकर (K. M. Panikkar) ने लिखा है

जिसो देश की नीति उसकी भौगोलिक परिस्थितियों से निर्दिष्ट होती है जब नीतियों का सत्य प्रादुर्गिक सुरक्षा होता है तो उनका निर्धारण मुख्य रूप से भौगो

कायम रखनी है। असलमनता की नीति के मूल में यह एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। किसी एक गुट में शामिल होकर भारत अपनी एक दिशा की ओर झुक कर नहीं चाहता। इस तथ्य का विश्लेषण करते हुए ज. सी. कुन्ड्रा ने लिखा है भारत की भौगोलिक स्थिति से जो महत्वपूर्ण तथ्य निकलता है वह यह है कि पश्चिमी गुट के मुख्य सामान्यों की अपेक्षा वह साम्यवादी सत्ता अथवा उसके मुख्य साधनदारों (रूस और चीन) के अधिक निकट है। परिणामस्वरूप अपने पड़ोसियों के साथ रहने के ठाक तरीके की खोज करना उसके लिए उनकी अपेक्षा अधिक आवश्यक है जो उससे दूरी पर स्थित हैं। यह बात अवश्य दूसरी है कि उसे यह विश्वास हो जाय कि उसके पड़ोसी उसपर आक्रमण करने की चेष्टा रखते हैं। दूसरी तरफ भारत इस तथ्य का भी अवहेलना नहीं कर सकता कि पश्चिमी गुट का नीति-मोह महासागर एवं सत्ता के अधिकांश समुहों पर हावी है। यदि भारत दोनों गुटों के बीच तटस्थता की नीति का अनुमरण करना चाहेता है तो ऐसा करने में उसकी इच्छा सम्भवतः यह है कि विस्फोटकारी सम्भावना के क्षेत्रों को यथा सम्भव अपने सीमा-क्षेत्रों से दूर रखा जाय। स्पष्टतः ऐसी नीति उसके राष्ट्रीय हितों स्वाधीनता और सम्प्रभुता से सब ही मेल खा सकती है जब उसे यह विश्वास हो कि दोनों गुटों में से उसे किसी से भी खतरा नहीं है।¹

भारतीय विदेश नीति के निर्धारण में भौगोलिक पक्ष इतना प्रबल है कि 1947 में गार्डिन्स (Guy Wint) ने लिखा था कि ब्रिटिश सत्ता के समाप्त होने पर भी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भारतीय विदेश नीति में कोई मौलिक अंतर नहीं आयगा। भौगोलिक परिस्थितियों की अपेक्षा बने रहने के कारण भारत के वास्तविक हित वैसे ही बने रहेंगे जैसे वे ब्रिटिश काल में थे। ये हित मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं—(i) भारत पर जिन समीपवर्ती अथवा अन्य देशों से आक्रमण हो सकता है उन सबके साथ तटस्थता या मित्रता। ये देश ईरान, इराक, अफगानिस्तान, लका, मलाया, हिन्दो, चीन, थायलैंड, इंडोनेशिया हैं। (ii) मध्यपूर्व, बर्मा तथा इंडोनेशिया से तेल की प्राप्ति। (iii) भारत के समीपवर्ती राज्यों में बसेनाओं भारतीयों का कल्याण और भारतीय व्यापार की वृद्धि। (iv) हिन्द महासागर में भारत की सुरक्षा और व्यापार के आधारभूत समुद्री तथा हवाई मार्गों की सुरक्षा। (v) बाह्य जगत में और सर्वोच्च सत्तासम्पन्न राष्ट्रों के मामले में अपने अतीत के इतिहास और संस्कृति के अनुरूप महत्वपूर्ण भाग लेने की आकांक्षा।²

इस प्रकार भारतीय विदेश नीति के निर्धारण में देश की भौगोलिक स्थिति पर सदा ध्यान देना है। स्वतंत्र भारत की विदेश नीति का निर्माण जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं इस तथ्य का महत्व स्वीकार करते हुए कहा था कि हम एशिया के महत्वपूर्ण भाग में स्थित हैं। विदेश नीति के निर्धारण में यह हमें याद होनी चाहिए कि इस तथ्य की उपेक्षा नहीं कर सकते।

1 J. C. Kundra *Indian Foreign Policy* pp. 11-1

2 Cited in Karunakar Gupta *Indian Foreign Policy* p. 70

(11) सैनिक तत्त्व—किसी भी देश की विदेश-नीति का मुख्य लक्ष्य वास्तविकता से दृढ़ता से रखा करना होता है। इसके लिए सैनिक दृष्टि से देश का सम्पूर्ण करना आवश्यक होता है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत के समक्ष यह एक विकट प्रश्न था। भारत के दोनों छोरों पर पाकिस्तान स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच वर्षों निरन्तर खींचातानी के बाद पाकिस्तान की स्थापना हुई थी। इस कारण भारत और पाकिस्तान का सम्बन्ध सन्तोषजनक नहीं था। देश के बंटवारे के पन्ध्रवर्ष साम्प्रदायिक दंगों का जो विस्फोट हुआ उसको उबर दानों देशों का सम्बन्ध और भी खराब हो गया। दानों देश एक दूसरे से संशयित थे। इसके अनिर्विकृत भारत दक्षिण-पूर्व और दक्षिण-पश्चिम में समुद्रों से घिरा हुआ है। इतने लम्बे समुद्र तट का रक्षा के लिए एक विमान नौ सेना का आवश्यकता थी जिसका स्वयं अभाव था। इस दृष्टि से हम पूर्ण रूप से अशक्ति पर आश्रित थे। भारतीय सेना का संगठन भी पाश्चात्य देशों पर हुआ था। देश का समूचा सैनिक प्रशिक्षण ब्रिटिश पद्धति पर आधारित था। अब अपना समर्थता का बनावे रखने के लिए भारत को विदेशी नीति की ब्रिटिश सहायता पर निर्भर रहना पड़ता था।

राष्ट्रीय सुरक्षा के साधनों के लिए भारत पूर्णतया विदेशी सहायता विशेष तया पश्चिमी राष्ट्रों की मदद पर आश्रित था। सैनिक दृष्टि से भारत की स्थिति एकदम नगण्य थी। जिस समय देश स्वतन्त्र हुआ उस समय किसी तरह की युद्धाभ्यासों सामग्री भारत में तयार नहीं हाता था। जीप टैंक वायुयान, सुदृढीकृत ब्रह्मनाभियों के लिए हम पूर्णतया दूसरों पर आश्रित थे। उनकी प्राप्ति के लिए हमें पश्चिमी देशों और साम्यवादी राष्ट्रों का मुंह ताकना पड़ता था। आणविक आगुओं के सत्तर का सामना करने में तो हम विलुप्त असमर्थ थे। हमारा शाण और हथक सैनिक स्थिति हमें इस बात के लिए बाध्य करती थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हम विश्व की सभी महत्वपूर्ण शक्तियों के साथ गम्भीरपूरा सम्बन्ध बनाने लें।

सुरक्षा की दृष्टि से भारत के समक्ष एक और समस्या थी। यद्यपि उग्र जी दासता से भारत मुक्त हो चुका था लेकिन देश के अन्दर भी बड़े विद्रोहावस्थाएँ थीं। पांडिचेरा, गाजा आदि जगहों पर अब भी फ्रांस का प्रभुत्व के अधिनस्थता कायम थी। इन विदेशी उपनिवेशों का त्याग करना भारत का स्वतन्त्रता के लिए बड़े खतर की बात थी।

(12) आर्थिक तत्त्व—आर्थिक दृष्टि से भारत एक अत्यन्त गरीब और पिछड़ा हुआ राष्ट्र था। सदियों के विदेशी आक्रमण ने भारत का आर्थिक रोग हाड़ की ओर सम्पूर्ण देश में गहरी एक वामाण का अन्धकार रोग छाया डाला था। दीर्घ काल से चली आ रही इस आर्थिक स्थिति की तत्कालीन आंतरिक परिस्थिति ने और भी खराब किया। देश के विभाजन के बाद साम्प्रदायिक दंगों के कारण देश की हालत अत्यन्त गौरीनीय हो गयी थी। बंटवारे के पन्ध्रवर्ष आर्थिक दृष्टि से भारत एक इकाई नहीं रहा था। साम्प्रदायिक दंगों के फलस्वरूप देशों का सहयोग में शरणार्थी पाकिस्तान से भागकर भारत चले आये थे। भारत सरकार के समक्ष उन

पुनर्वास की समस्या थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ ही दिनों बाद भारत को कभी भी को लेकर युद्ध में फँस जाना पड़ा। देश की आर्थिक स्थिति पर द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव अपना रंग जमाने लगा था। वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि तथा बेरोजगारी की समस्या भयंकर रूप से सामने आ रही थी। साधारणों की भारी कमी हो रही थी। इन सब बातों से देश का आर्थिक जीवन पूरी तरह से छिन्न भिन्न और सहस्र-नहस हो गया था। मजदूरों में घोर असंतोष पावने लगा। हड़तालों मामूली बात हो गयी थी।

स्वतंत्र भारत को इस विकराल आर्थिक समस्या की ओर तत्काल ध्यान देना था। इस समस्या के समाधान के लिए साधारणों के उत्पादन में अभिवृद्धि और औद्योगिक उन्नति करना परम आवश्यक था। स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद हम साधारणों का अपार मात्रा में आयात करना पड़ा। यह आयात मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ। अतः हमारी विदेश नीति उससे साथ अनुकूल सम्बन्ध बनाये रखने की थी। यह आवश्यक था कि हमारी विदेश नीति में अमेरिका के प्रति प्रश्रय और प्रत्यक्ष सहानुभूति हो। 1940 के कारियाई युद्ध में उत्तर कारिया के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की जानेवाली कायवाणी के विषय में भारत ने अमरीकी प्रस्ताव का समर्थन अमेरिका में खाद्यान्न संकट दूर करने के लिए मिलनेवाली सहायता से प्रभावित होकर किया था।

आर्थिक दृष्टि से भारत का अधिकांश व्यापार पश्चात्त्य देशों के साथ विनियमन ब्रिटन और राष्ट्रमण्डल के देशों के साथ होता आ रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भी उसका व्यापारिक सम्बन्ध बना। इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का 98% व्यापार पश्चिमी देशों के साथ होने लगा तथा भारत को उद्योगों में ब्रिटिश पूँजी अधिक लगी होने से हमारी विदेश नीति का ब्रिटन का अनुकूल बने रहना आवश्यक था। बाजार में वित्तीय और प्राविधिक सहायता के लिए हम अनिवार्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका पर निर्भर करना पड़ा। उस समय सोवियत संघ में कोई सहायता मिलने की आशा नहीं थी। स्टालिन के नेतृत्व में सोवियत संघ ने द्वितीय विश्व युद्ध के नीति का अवलम्बन कर रहा था और पिछड़े हुए राष्ट्रों की सहायता करनी उसकी नीति नहीं थी। अतएव संयुक्त राज्य के साथ मधुर सम्बन्ध कायम रखना अत्यावश्यक था। स्टालिन युग के अंत के पश्चात् जब सोवियत नीति में परिवर्तन हुआ तब भारत ने सोवियत संघ से भी सहायता प्राप्त करना प्रारम्भ किया। भारत ने सोवियत संघ द्वारा आविष्कृत नियोजित आर्थिक विकास के कार्यक्रम को लागू किया और समाजवादी ढंग के समाज स्थापित करने का निश्चय किया। फलस्वरूप समाजवादी धर्म के साथ भी हमारे आर्थिक सम्बन्धों में सुधार हुआ। औद्योगिक विकास के लिए भारत दोनो गुँटों ने आर्थिक और प्राविधिक सहायता प्राप्त करने लगा। अतः हम बिल्कुल स्वाभाविक हैं कि भारत गुटनीतियों की नीति से अलग रहकर अगल-गलती की नीति का अवलम्बन करे।

दश के आर्थिक विकास के लिए भारत विश्व शांति को परम आवश्यक मानता था। गरीब और पिछड़े हुए देशों के लिए युद्ध बड़ा ही महंगा पड़ता है।

मामूली अरब राजरायन युद्ध के फलस्वरूप स्वेज नहर के बंद हो जाने से भारत को अपार आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा है। स्वयं भारत को तीन युद्धों में फंसा पड़ा। चीन और पाकिस्तान से भारत की जा लड़ाई हुई उसका फलस्वरूप दश की अर्थ-व्यवस्था एकदम चौपट हो गयी। इन बातों को दक्षिण रखत हुए भारत के लिए यह अत्यावश्यक है कि उसका विदेश नीति नीति की भावना से ओत प्रोत हो। 1947 में यह बात उतना ही सत्य था जितना आज है। भारत के लिए नीति के महत्त्व का स्वाकार करत हुए श्रीमती विजय लक्ष्मी पटित ने ठाक हा कहा था कि हम यह अनुभव करत हैं कि युद्ध हमारे लिए साम्यवाद की अपेक्षा अधिक बड़ा सबोट है। इस तरह स्पष्ट है कि भारत आज जो असलगतता और शांतिप्रियता की विदेश नीति अपनाये हुए है उसके मूल में आर्थिक तत्त्वों ने एक विशेष भूमिका अदा की है।

(iv) ऐतिहासिक परम्पराएँ — विदेश नीति के निर्धारण में देश की ऐतिहासिक परम्पराएँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तत्त्व होती हैं और भारतीय विदेश नीति इस तथ्य से भी प्रभावित हुई है। हमारा विदेश नीति के निर्धारण में इतिहास का महत्त्व कितना अधिक है इसका उदाहरण ब्रिटेन और भारत के घनिष्ठ सम्बन्धों में मिली प्रकार स्पष्ट होता है। पिछले दो शताब्दियों से ब्रिटेन का भारत से सम्बन्ध रहा है। मिले ही यह सम्बन्ध ग्रासक और शांति का था फिर भी भारत पर ब्रिटेन का गहरा प्रभाव पड़ा है। ब्रिटेन के साथ हम अपने सम्बन्ध की सरलता से विच्छेद नहीं कर सकते हैं। यद्यपि अंग्रेज हम सत्ता सौंप कर हमें जग से चैन गये किन्तु उनकी शलाघी हुई मसीही प्रणाली उत्तरवाद अंग्रेजी भाषा का प्रयोग प्रशासनिक ढाँचा कानून शिक्षा और बिक्रिता पद्धतियाँ अर्थ-व्यवस्था सैनिक एवं राजनयिक समस्याएँ यथापूर्व विद्यमान हैं। ब्रिटेन के साथ रहे हमारे ऐतिहासिक सम्बन्धों का ही यह परिणाम है कि स्वतन्त्रता के बाद भी हमने राष्ट्रमण्डल में बने रहना स्वीकार किया। स्वतन्त्रता-युग में के दौरान दश के नतीजा बड़ा करते थे कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत किसी भी हात में इस समस्या के साथ सम्पर्क नहीं रखता। लेकिन राष्ट्र की सभी व्यवस्थाओं पर अंग्रेजीयत का रंग इस तरह चढ़ा हुआ था कि उस सम्बन्ध का विच्छेद सरल नहीं था। आज भी देश के कई हस्तों से राष्ट्रमण्डल से सम्बन्ध विच्छेद करने की मांग होती रहनी है लेकिन ऐतिहासिक परम्परा को दृष्टि में रखकर भारत सरकार के लिए सम्बन्ध विच्छेद का निणय अत्यन्त कठिन हो जाता है।

प्रारम्भिक वर्षों में चीन के प्रति भारतीय नीति का विशेषण भी हम ऐतिहासिक परम्परा के आधार पर ही कर सकते हैं। 1962 के भारत-चीन युद्ध के कुछ वर्षों पूर्व तक इन दोनों देशों के सम्बन्ध में भारत-चीनी भाई भाई का बोल बाला था। दा पड़ोसी देशों के मध्य इस मधुर सम्बन्ध की नौवें स्वतन्त्रता सप्ताह के समय ही ढाली गयी थी। उस काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और विशेषकर जवाहरलाल नेहरू ने चीन के प्रति अपार सहानुभूति का प्रदर्शन किया था। महट्ट के दिना में भारत ने चीन की बड़ा सहायता की थी। चीन के प्रति नेहरू का प्रगाढ़ प्रेम था। उन्हें बहुत विश्वास था कि एशिया की सुविन और कल्याण के लिए

भारत और चीन में घनिष्ठतम सम्बन्ध का होना परम आवश्यक है। स्वतन्त्र भारत के प्रधानमंत्री होने के उपरान्त नेहरू इसी विश्वास के आधार पर चीन के प्रति अपना नीति को निर्धारित करते रहे। नेहरू की इस भावना को सुदृढ़ करने के लिए पकिंग स्थित भारतीय राजदूत सरदार के एम. पणिक्कर में बड़ी मदद मिली। इतिहास के महान विद्वान व नाते भारत और चीन के सम्बन्ध पर पणिक्कर का कुछ अपनी धारणाएँ थीं। इस सम्बन्ध में उन्होंने लिखा था भारत और चीन के हजारों वर्षों का सम्पर्क एशिया के इतिहास के प्रमुख दृश्य में एक है। गर इस्लामी एशिया को आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक एकता भारत और चीन व इसा पुराने सम्पर्क द्वारा प्राप्त हुई थी। तबमग एक हजार वर्ष तक किसी भी प्रकार के सम्बन्धों के न होने के बावजूद भी वह एशिया के इतिहास का एक मुख्य तत्व है। यह इतिहास की विडम्बना है कि इधर हाल के वर्षों में भारत और चीन के सम्बन्ध अत्यंत बिगड़ गये हैं लेकिन चीन के प्रति प्रारम्भिक भारतीय नीति का मुख्य स्रोत स्वतन्त्रता संग्राम के समय चीन के प्रति हमारा दृष्टिकोण था।

पाकिस्तान के साथ भारत के गततापूर्ण सम्बन्ध का भा एक ऐतिहासिक पृष्ठाधार है। स्वतन्त्रता संग्राम के समय मुस्लिम लीग सम्प्रदायिकता के आधार पर देश के विभाजन की मांग करती थी और भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ने इसका विरोध किया था। फलतः दोनों के सम्बन्ध अत्यंत कटु बने रहे। दशक विभाजन के उपरान्त दोनों डोमिनियनों का शासन प्रबन्ध अर्द्धोपाधियों के हाथ में आया। उनकी पुरानी गतता जारी रहा। जिन परिस्थितियों के बीच देश का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण हुआ था उसकी भुनाया नहा जा सकता था। पाकिस्तान के प्रति भारतीय नीति के निर्धारण में इस तथ्य ने प्रमुख भूमिका अदा की।

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के जमाने में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का प्रबल विरोध किया। वस्तुतः काँग्रेस की मुख्य लड़ाई इसी के विरुद्ध थी। काँग्रेस ने कई बार प्रस्ताव स्वीकार करके यूरोपीय साम्राज्यवाद का विरोध किया था। अब जब वह स्वतन्त्र हुआ तो उपनिवेशवाद का विरोध उसकी विदेश नीति का एक मुख्य तत्व बन गया। भारत ने इण्डोनीशिया अल्तीरिया मोरक्को ट्यूनिशिया लीबिया माइप्रम आदि पराधीन उपनिवेशों की स्वतन्त्रता का प्रश्न समझा किया। उपनिवेशवाद का यह विरोध ऐतिहासिक परिस्थितियों की उपज है।

साम्राज्यवाद के उन्मूलन के लिए भारत ने एशियाई देशों को संगठित करने का भी प्रयास किया था। इसी उद्देश्य से वह गोपित एवं पराधीन जातियों के कई सम्मेलनों में सम्मिलित हुआ था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त भारत ने इस आन्दोलन को संगठित करने का बड़ा प्रबल प्रयास किया। 1947 के प्रारम्भ में अन्तर एशियाई सम्मेलन का आयोजन कर उसमें इस आन्दोलन में एक नयी जागृकता और नए परम्परा को जीवित रखने के लिए बड़ी हमला मन्त्रि रहा। एशियाई एकता को स्पष्ट करने का भारतीय नीति की अन्तर्गत भी हम अपने इतिहास में ही खोज सकते हैं।

शुरू से ही भारत की नीति शान्तिवादी रही है। भारत के अतीतकालीन इतिहास का अध्ययन करने से इस बात का मन्वी प्रकार पता लग जाता है कि

भारत ने किता भा देश को पराजित करने और उस पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न किया। रूसी व चीनी गतिविधियाँ महात्मा ने विद्रोह में उसका प्रभाव विवादित रह है। भारत का महत्त्व और परंपरा मजबूत हो गति की समर्थक रहा है। स्वतंत्र्य सुझाव के बिना में भी यह परंपरा कायम रही। उन राशियों को अस्मिकता कायदाहिया का मना किया गया। 1938 में चान पर जापान का आक्रमण 1935 में अंग्रेजों द्वारा परंपरा के आक्रमण तथा 1938 में बल्लोन्तावाकिया पर अंग्रेजों का अक्रमण का निम्न कारणों में था। 1935 में लाला लजपत राय का विद्रोह प्रभाव स्वीकार करने था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विश्व गति का नाम का अपना प्रवेश समर्थन किया। 'महात्मा' ने उस समय का भी समर्थन किया यद्यपि राष्ट्रपति के गठन या समर्थन का पदवि में वह बहुत अलग था। कांग्रेस का निश्चय था कि सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत विश्व में गति बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए स्वतंत्र भारत ने गति का विश्व युद्ध के बाद स्थापित मुक्त राष्ट्र संघ का जोरदार समर्थन किया और उसका मनबुझा के लिए भरपूर योगदान दिया। मुक्त राष्ट्र संघ के प्रति भारतीय गतिविधियों का समर्थन के लिए हम उस देश का धर्म से आसक्त नहीं कर सकते।

पन्नेस देशों के साथ भारत का सम्बन्ध व के निष्कर्ष में हमें ज्ञान गति का प्रमाण मिली है। इसका सारांश इस प्रकार है कि भारतीय गति का विश्व गति के विकास के लिए हमारे आधुनिक और आधुनिक गतिविधियों में है। अतः हमें अपने देश का भारत के हित में अपार समर्थन और सहायता देनी चाहिए।

(५) वैचारिक तत्व—भारतीय गति-नाति का एक बड़ा आधार तत्व प्रमाण का विचारधारा है। प्रायः यह कहा जाता है कि भारतीय गति का विश्व गति में भारत के परंपरागत गति का प्रभाव मान्य होता था होता है। भारत का प्रमाण भारत और गति विवाद का नाति का मन आधार भारत का परंपरागत महिम्ना और भारत की गति विवाद का बुद्ध और महात्मा गांधी की अस्मिता का प्रमाण बुद्ध ने स्मरण महात्मा गांधी का गति का प्रमाण का भारतीय गति न अतिथि (Exile) में सं बचकर महान माता का अवलम्बन कान का प्रमाण है। इस गति का अनुसरण भारत ने आज के विश्व के गति अतिथि में अन्तर्गत गतिविधियों की नीति का अवलम्बन किया। महिम्ना का प्राधान परंपरा के कारण भारत का कहना था कि साम्प्रदायिक और परम्परागत नियंत्रण गतिविधियों में है। गतिविधियों ने न तो का एक बुरा है और न का प्रमाण है। गतिविधियों का प्रमाण का अनुमान बनाने का बल नहीं करना चाहिए। महामहिम का सिद्धांत का आधार है हो गतिविधियों के सम्बन्ध का निमित्त दिया जा सकता है। इस गतिविधियों के अनुसरण का अनुसरण भारत ने अपना गति-नाति का निष्कर्ष दिया। पंचशात और गतिविधियों महिम्ना का दाव का इस प्रकार में समझा जा सकता है।¹

भारतीय विदेश नीति पर गांधीवादी दंगन का प्रभाव एक बड़ा ही विवादास्पद विषय बन गया है। यहाँ कहा जाता है कि भारत की विदेश नीति पर महात्मा गांधी के अहिंसा और शांतिवाद के दंगन का बड़ा प्रभाव है जमा कि जो एक हडसन (G F Hudson) ने लिखा है — गांधी के शांतिवाद ने देश को यह विश्वास दिलाया कि विश्व में शांति समझौतों द्वारा ही स्थापित हो सकती है न कि मजबूत सशस्त्र सेनाओं से। भारत ने इसे अपना कर्तव्य माना कि वह दो विरोधी गुटों से अलग रहे और न में मध्यस्थता का कार्य करे।

गांधीजी ने यहाँ भी कहा था कि किसी कार्य को सम्पन्न करने के लिए हम साधनों (means) पर भी खयाल रखना होगा। यदि आप कोई बड़ा या अच्छा काम करना चाहते हैं तो उसके लिए नैतिक और श्रद्धा साधनों को ही आनाना चाहिए। दूसरे शब्दों में गांधीजी के दंगन ने साधनों को भी उतना ही महत्व दिया जितना साधनों को। अतएव कहा जाता है कि स्वतंत्र भारत ने अपनी विदेश नीति के निर्धारण में इस बात का समावेश कराया। हमारे नीति निर्धारकों ने अखिलेश्वर को प्राप्त करने के लिए अखिल साधन अपनाने की बात को स्वीकार कर दिया। उन्होंने अपना काम यह कि वास के आधार पर किया कि विश्व शांति के लक्ष्य को हिंस्रमय साधनों द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता है। 20 नवम्बर 1955 को बुन गानिन तथा एन डेव के सम्मान में दी गयी राजकीय दावत के अवसर पर बोले हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। हम इस बात में विश्वास करते हैं कि जो लक्ष्य प्राप्त किया जाय वह अच्छा होना चाहिए। साथ ही इस बात में भी विश्वास करा है कि साधन भी अच्छे ही अपनाने जाये चाहिए। ऐसा न किये जाने पर नयी नयी समस्याएँ उठ खड़ी होती हैं तथा स्वयं मतलब भी बन जाता है। एक दूसरे अवसर पर उन्होंने कहा था कि हमें बुराई का विरोध करना चाहिए किन्तु किसी बड़ी बुराई द्वारा नहीं। हिंसा और धृष्टता का अधिकारिता और धृष्टता द्वारा दमन नहीं किया जा सकता। आने वाली श्रद्धा के आधार पर भारत ने अपनी विदेश नीति में निम्न साधनों को अपनाया। अन्तर्राष्ट्रीय विवादा को दूर करने में सान्त्वना, पक्ष पक्षों के बीच मध्यस्थता का प्रयोग करना शक्ति के प्रयोग अथवा प्रयाग की धमकी से दूर रहना आदि।

इस आधार पर अनेकानेक लेखकों ने कहा है कि भारत की विदेश नीति बहुत अर्थों में गांधीवादी दंगन से प्रभावित है। परन्तु यदि गहराई में उत्तरकर देखा जाय तो यह पता चलेगा कि भारतीय विदेश नीति के मध्यम में गांधीवादी प्रभाव को बहुत बड़ा पड़ाकर बनाया जाता है। स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने इस तथ्य को स्वीकार किया था। 22 जून 1950 को रंगून में बोले हुए उन्होंने कहा था गांधी का सिद्धांत बनना में बहुत पसंद करता लेकिन ऐसा मैं नहीं हूँ। साथ ही अहिंसा के मर्म को न समझनेवाले मानवीय साधनों के जरिये काम करने वाले राजनेता को कभी कभी समझौता करना पड़ता है।¹ इस प्रकार भारतीय विदेश नीति के मुख्य निमोना

1. I wish I were a disciple of Gandhi but I am not Statesmen who have to work through human agencies which have not a perfect preception of truth and non violence must always compromise —Nehru The New Chronical June 23 1950

जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं कहा था कि भारत की विदेश-नीति और गांधीवादी दृष्टान्त के बीच कोई मूढ़ातिवत् लगाव नहीं है। इस सम्बन्ध में कहनाकर गुप्त ने निम्ना है। यह बात सन्तुष्ट है कि सत्य और अहिंसा के गांधीवादी सिद्धान्तों का भारत की गृह व्यवस्था विदेश-नीति पर किसी बड़ी सीमा तक प्रभाव पड़ा है। गांधी हिन की भाँति मनु के बात पूरी तरह सम्मानित हुए किन्तु उनका कोई ऐसा गिण्य नहीं था जो उनके सिद्धान्तों की क्रिया रूप में परिणित करता। उनकी मृत्यु के तुरन्त बाद नवीन भारत ने साम्यवादी और सम्प्रदायवादी विरोध का दमन करने के लिए सवाधिवार्तावादी उपायों का प्रयोग किया। काश्मीर और हैदराबाद में सन्तुष्ट हिंसा का प्रयोग किया गया ता नवान्त के आंतरिक संघर्ष में भी हिंसा-नाति का अवलम्बन हुआ। वज्र के यह स्वरूप जिसमें कि मुनिक-यय के लिए पचास प्रतिशत में अधिक की पदार्था की गयी है यह प्रकट करता है कि भारत का प्रजा-पुजाय नाति में पुनिस उपयोगों पर बन गया जाता है। इन परिस्थितियों में यह बात विश्वसनाय नहीं कि भारत की विदेश नीति पर गांधीवादी अहिंसा के सिद्धान्त का का निगायक प्रभाव पड़ा है।¹

भारतीय विदेश-नाति के निधारण में वचारिक तत्त्व (ideological factors) को हम जम्बिक महत्त्व नुता सकते। वचन प्रचार की शक्ति में यह महत्त्वपूर्ण हा जाता है नाति निधारण के वास्तविक क्रम की आरम्भ पर विरोध ध्यान नहीं दिया जाता। यह बात केवल भारत के साथ ही नहीं बरन सभी देशों के साथ समान रूप से लागू होनी है। विदेश नाति के निधारक सभी तत्त्वों में सर्वोपरि स्थान तो राष्ट्रीय हिन (national interest) का हाता है।

(vi) राष्ट्रीय हिन—मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन का भाँति राष्ट्रीय जीवन में भी व्यवहार के दो पक्ष हाता है। पक्ष स्वायत्त पक्ष और दूसरा परमाय पक्ष। पहन पक्ष के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र के प्रत्येक काय का प्रनुवन्त्य उसके स्वयं के स्वायत्तों की पूर्ति करना हाता है। दूसरा पक्ष एक राष्ट्र का न ता का स्वायत्तों मित्र हाता है और न कोई स्वायत्त दशमन्। वचन स्वायत्त स्वायत्त हाता है। अयत्त यदि उस राष्ट्र के इस स्वायत्तों की पूर्ति में एक सहायता का काय करेंगे तो अवश्य हा गहर मित्र बन जायेंगे किन्तु यह मित्रता केवल तमा तक स्थिर रहगी जब तक उसका आधार स्वायत्त पूर्ति कायम करना रहता है। इस आधार के समाप्त नात हा मित्रता का महत्त्व भी घरागायी हो जायगा। यह भा सम्भव है कि व देश परस्पर दशन हा दशन बन जायेंगे जितना कि पहन के मित्र य। विश्व का इतिहास एक अन्तराष्ट्रीय घटनाओं का क्रम है वचन की पुष्टि के लिए इतना प्रमाण दे सता है कि यह वचन आजकल स्वयं सिद्ध सत्य मा बनता जा रहा है। वस्तुतः राष्ट्रीय हिन हा विदेश नीति की सबसे आधारगिता होती है। विदेश-नीति का निधारण सिद्धान्तों के आधार पर होता उतना आवश्यक नहीं है जितना कि राष्ट्रीय हिनों के आधार पर। राष्ट्रीय हिनों को ध्यान में रखकर कई बार सिद्धान्तों की तिलाञ्जलि देनी पड़ता

है। विदेश नीतियों का निर्माण सूत्रम सिद्धान्तों के आधार पर नहीं होना किन्तु यह राष्ट्रीय हितों के क्रियात्मक विचारों का परिणाम होता है। भारतीय विदेश नीति के सम्बन्ध में भी यह सिद्धान्त पूर्ण रूप से लागू होता है। स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने इस बात का स्वीकार करते हुए कहा था कि किसी भी देश की विदेश नीति की आधारगिरी उसके राष्ट्रीय हित की सुरक्षा होती है और भारत की विदेश नीति का भी ध्येय यही है।

राष्ट्रीय हित के स्वरूप को निर्धारित करना बड़ा कठिन काम होता है। यह कोई स्थिर या गतिवत वस्तु नहीं है यह तो एक परिवर्तनशील तत्त्व है जिस गतिमय (dynamic) कहा गया है। असल में राष्ट्रीय हित गिरगिट की तरह रंग बगन रहता है क्योंकि परिस्थितियों एवं समय की आवश्यकताएं उसे जसा चाहती है मोड़ देती है। स्थान और काल के परिवर्तन के साथ यह अपना स्वरूप बदलता रहता है। एक राष्ट्र के एक ही समय में अनेक हित हो सकते हैं। इन हितों में बीच परस्पर विरोधाभास भी रह सकता है। भारत की विदेश नीति भी ऐसी ही स्थिति में है।

भारत की विदेश नीति में राष्ट्रीय हित के तत्त्व का चिन्ता में त्वपूर्ण स्थान है इसको दो तीन उदाहरणों को प्रस्तुत करके समझा जा सकता है। भारत प्रारम्भ से ही उपनिवेशवाद का विरोध करता आ रहा है। 18 माघ 1946 का सिंगापुर में भाषण दत्त हुए नेहरू ने कहा था। भारत केवल अपने लिए ही स्वतन्त्रता नहीं चाहता। आप आधी दुनिया को स्वतन्त्र और आधी का परतन्त्र नहीं रख सकते। भारत स्वतन्त्र जगत् में स्वाधीनता चाहता है। जब वह स्वतन्त्र होगा तो उसका सारी शक्ति सभी पराधीन देशों की स्वतन्त्रता के लिए लगायी जायेगी। यह बात इण्डोनीशिया मलाया तथा सभी देशों के लिए समान रूप से लागू होनी है। सात वर्ष बाद अर्थात् 1953 में मलाया की जनता ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध अपना यापक मण्डप शुरू किया। इस मण्डप को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने नेपाली गुरखों की भर्ती करना शुरू किया और इन नेपालियों को भारत सरकार ने मलाया पहुँचाने के लिए भारत के भू भाग से होकर जाने का मार्ग रखा। उपनिवेशवाद का विरोध के उचित आदस का गला घोटने का इसमें अत्यन्त उदाहरण दूसरा नहीं मिल सकता है। लेकिन इस महान सिद्धान्त के साथ भारत ने समझौता क्या किया? इसका एक ही उत्तर है। भारत ने ब्रिटिश सरकार के दबाव से नहीं प्रसृत राष्ट्रीय हित की दृष्टि से प्रतिक्रिया कर एसा किया और साम्राज्यवाद से विरोध के उचित आदस पर डटे रहने की अपना वास्तविक राजनीति का टोस परिस्थितियों को देखते हुए ब्रिटिश मना को अपना भू भाग से गुजरान दिया। नेपाल भारत की उत्तरी सीमा से लगा हुआ एक सीमांत राज्य है जिसकी अवस्था का मुख्य आधार इसकी जनता का सेना में भर्ती होना है। यहाँ इसमें बाधा डाली जाय तो नेपाल की पूरी अवस्था दिग्न भिन्न हो सकती है वही व्यापक असंतोष और विद्रोह उत्पन्न हो सकता है। इसमें भारत की सुरक्षा घनरे में पड़ सकती है। अतएव आमरक्षा के राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर भारत ने ऐसा किया।

स्वतंत्रता के बाद भारत द्वारा राष्ट्रमण्डल का सम्मेलन करने के रहने का निश्चय भी बहुत जल्दी में राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर हो किया गया था। स्मरणीय है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस और विशेषकर नेहरू ने स्पष्ट कह दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत राष्ट्रमण्डल में किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रहेगा। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ तब राष्ट्रीय हित का ध्यान मर खड़ा। उसे राष्ट्रमण्डल का सम्मेलन करने रहने का समझना करना पड़ा। सामुद्रिक सीमा का सुरक्षा के लिए भारत पूरी तरह ब्रिटिश नौ-सेना पर आश्रित था। भारत के सांख्यिकीय जीवन में ब्रिटिश विनियोग मुद्रा समुदाय वामा जहाजरानी आदि बड़े शक्तिशाली तत्त्व थे। इन बातों का विचार भी हालत में उपेक्षा नहीं की जा सकती थी।

इसी तरह की बात निरस्त्रीकरण के सम्बन्ध में भारत के बहुत दृष्टि-कोण में देखी जा सकती है। नाग्न धूम से ही निरस्त्रीकरण का बहुत बड़ा समर्थक रहा है तथा विश्व शांति के लिए निरस्त्रीकरण का परम आवश्यक मानता आ रहा है। इनोलिए अपने अगस्त 1963 का आणित परमाणविक पराजना संधि का स्वागत किया और भारत उत्साह के साथ संधि पर हस्ताक्षर करके समझा अनुमोदन किया। चान न संधि में सम्मिलित होने से अब इन्कार किया जा भारत में इसका तात्पर्य नमना हुआ।

उनके तत्काल विपरीत 1968 में जब परमाणु शक्ति प्रसार निगम सम्बंधी संधि (nuclear non proliferation treaty) का मानन की बात आयी तो भारत ने इसके प्रति ठोसासनना ही नहीं प्रदर्शित किया बल्कि इसका विरोध भी किया। निरस्त्रीकरण के सारे सिद्धांत सफाई हो गए। भारत का अपनी नातियों पर पुनर्विचार करने की मजबूरी मूलतः चीन का परमाणविक नाति के कारण हुई। 1962 के अपने कटु अनुभव के बाद भारत चीन से कुछ अतिरिक्त सतकता बरत कर अपने का इस स्थिति में नहीं पड़ा था कि वह उपराजित संधि आम मूद कर मान ले। यह बात में चान बहुत अधिक परमाणु शक्ति सम्पन्न बन गया था और चान का परमाणविक शक्ति के रूप में दखतर भारत का भयभात होना स्वान विक था। यह भी आवश्यक था कि भारत स्वयं परमाणविक शक्ति बनने की चष्टा करे। निरस्त्रीकरण के तथ में भारतीय शक्ति का परिवर्तन के मूल में राष्ट्रीय हित के अतिरिक्त और दूसरा कोर तत्त्व नहीं था।

आपक शक्ति का स भारत के राष्ट्रीय हित का परिभाषित करना या उसका निर्धारण करना एक बड़ा हा कठिन काम है। फिर भी देश का राजनीतिक और आर्थिक स्थिति तथा अंतराष्ट्रीय परिस्थिति के विनयन करने के उपरान्त यह कहा जा सकता है कि निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखकर भारतीय विश्व नीति का निर्धारण होना चाहिए। भारत की भौगोलिक स्थिति उसका स्पष्टीकरण सीमा का चान और आश्रित मध्य से लगा होना विस्तृत समुद्र की रक्षा सामुद्रिक व्यापार का सुरक्षा के लिए ब्रिटिश पर निर्भरता आर्थिक विकास और

घोषों की दृष्टि से विछड़ा होना सनिक नियसता दग मे घाघान की कमी विदगी पू जी की आकृषकता ग्रिटेन ओर अमेरिका के साथ सुद्ध आर्थिक सम्ब द गति की आव दछता और एगिया क राटों में अपने सामर्थ्य के अनसार मन्वपूण स्थान पाने की आकांक्षा । भारतीय विदेश नीति के समय इन तत्वों की किसी भी मूल्य पर आलो स ओगन नहीं किया जा सकता ।

(vii) व्यक्तिगत तत्व—विदेश नीति के स्वयं निर्धारण में व्यक्तिगत तत्वों की भी अस्वीकार नहा किया जा सकता । स्वतन्त्र भारत की विदेश नीति के प्रमुख निर्माता 1917 से 1964 तक अपनी मस्तुपय त भारत के विदेश एव प्रधानम भी जवाहरलाल नेहरू थे । उनके जीवन गगन विचारधारा ओ दृष्टिकोण स हमारी विदेश नीति को नेहरू नीति भी कहा जाता था ।

राजनीतिक क्षत्र में नेहरू पर ब्रिटिश विचारक हेरोल्ड सास्की के दगन का प्रभाव था । सास्की की विचारधारा वा चार्य दारवाद और मावगवाद के सम वध वा पर आधारित थी । अगननता की नीति का उद्भव और विकास सास्की की इस विचारधारा से प्रभावित हुआ था ।¹

नेहरू पर वा चार्य साकनत्रवाद अथवा समाजवाद का अ य किसी भी विचारधारा का कुछ भी प्रभाव रहा हो लेकिन यह तो मानना ही पड गा कि भारत की विदेश नीति की आधारगिता रखने म और उसको विकसित करने म उनका सबसे निर्णायक हाथ रहा था । सतह वषों तक लगातार व भारत के विदेश मन्त्री रहे । इसके पूव लगभग पचीस वषों तक वे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस का विदेशी मामल म प्रमुख वक्ता भी रह चुके थ । 1927 के वा विदेशी मामलो म सम्बधित काँग्रेस का कोई ऐसा प्रस्ताव नो है जिसकी समार करने मे नेहरू का हाथ न रहा हा । इसा वान म वि क राजनीति के सम्ब ध मे उनकी सभी धारणाए वनी । सत्रप्रथम क अ नर्णयोजना और अखिल एगियावाद के समयक थे । भारत क राष्ट्रीय आ दोनन को उहोने कभी भी पृथक रूप से नगा देखा । उनकी दृ ट म भारत का राष्ट्रिय आ दोलन गमार की समस्त पददलित जातियो क सघष का एक अण था । त्रितीयत के साम्राज्यवाद उपनिवेगवा और फासिस्टवाद क कट्टर विरोधी थे । उनका अग्न विश्वास था कि जबतक इस तरह की शक्तियाँ समार म कायम रहगी मानव मात्र का कल्याण नही होगा । तीसरे सभी अंतर्राष्ट्रीय विवाे की सातिपूण तरीको स सुनाने के के समयक थे कि तु साम्राज्यवाे आक्रमण के प्रतिरोध क लिए वे शक्ति क प्रयोग को अनुचित नहा समजते थे । चीन सोवियत सघ और चीन क प्रति उनकी विनेय सहानुभूति थी । सोवियत सघ क सम्बन्ध म उाका वि वात था कि उसके नेता फासिडी नहीं है और साम्राज्यवाद क प्रबल शत्र है । चीन क प्रति उनका अनुराग बहुत हा बड़ गया था । 1927 के बाद स ही क

चीन की राजनयिक में रुचि नत आ रहे थे। प्रस्तुत गठों के द्रुमस्त नमेलन न लौटने के उपरान्त उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चीन के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने को कहा और नेहरू के निश्चय पर कांग्रेस ने चीन की मजदूरी के लिए यथामुम्भव प्रयास किये। भारत की सेवा और उसके प्रति दायित्व के बावजूद यदि नेहरू ने किसी बात पर उस समय ध्यान दिया तो वह चीन के प्रति उनकी अनुराग था। इस तथ्य को महात्मा गाँधी ने भी स्वीकार किया था।¹ पाचवें जवाहरलाल महात्माविनयों के अध्याय में भारत के लिए असम्मानिता का नानि का सर्वोत्तम सनवत थे। ज्ञान नहीं विचारों के अनुरूप उन्होंने भारत की विश्व-नाति का टाना और आज भारत का विश्व-नीति का जामा रूप हमारे सामने है वह नेहरू के उपरोक्त विचारों का ही प्रतिरूप है।

भारत की प्रारम्भिक द्विदेश नातिक निर्धारण में स्वतन्त्रता की प्रभाव के रूप में नेहरू जात है। जिन इच्छाओं में बहुत बड़ा हिस्सा है कि वे उनके सर्वोत्तम थे। उनमें भारत के लिए मजदूरी के कुछ अन्य व्यक्त भी जात है जिनके अभाव का कम नहीं किया जा सकता। सरदार बल्लभ भाइ पटेल गांधी के अग्रणी और बाद में भी वे कृष्णमनन के साथ मजिस्ट्रेट के एक मुख्य यजमान नाति निर्धारण में प्रमुख भाग लिया था। पाकिस्तान के प्रति भारतीय नानि के निर्धारण में इन व्यक्तियों का काफी अंतर बताया जाता है। मनमोहन लाल के विश्वस्त मित्र थे। अतः कारिया मित्र और चीन के सम्बन्ध में नेहरू का नाति को प्रभावित करते रहे। कृष्णमनन ने सुषुप्त राष्ट्र में भी और विश्व के प्रमुख देशों में भारत की विश्व नाति का एक प्रभावशाली राजदूत के रूप में सराजनीय कार्य किया। केन्द्रीय मजिस्ट्रेट के अग्रणी बालिक मामलों में अग्रणी स्थिति का विश्व-नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका रहा है।

भारतीय विश्व मन्त्रालय के विशिष्ट अधिकारी और भारतीय राज्यों ने भी हमारी विश्व नीति का रूप निर्धारित करने में कम हाथ नहीं बंधा है। विश्व मन्त्रालय का कार्य दोनों की तरह यही था विश्व-नीति का निश्चय करने में वे एक महत्वपूर्ण भाग होता है इनके दृष्टि अधिकारी सामान्यतः हम नाति का संचालन करते हैं। भारतीय राज्यों में सर्वप्रथम राधाकृष्णन तथा सरदार के लाल पाणिक्कर के नाम विशेष रूप में उल्लेखनीय हैं। राधाकृष्णन का स्वयं का श्रम है कि सावित्र नथ में भारतीय राजदूत के रूप में उन्होंने स्पष्टित का प्रभावित कर भारत और हम के सम्बन्धों में एक नया अध्याय खोला। भारतीय विदेश नीति के निर्धारण पर पाणिक्कर के प्रभाव का स्वर पयाप्त बात बिना है। चीन के प्रति भारत का प्रारम्भिक नाति का उन्होंने बहुत ही नक

1. Jai aharlal has conceived a love for China only excelled if at all by his love of his own country —Mahatma Gandhi quoted in Warner Levi *Free India in Asia* p. 20

प्रभावित किया था। भारत का स्वतंत्र होने के समय और चीन में जवादी गणराज्य की स्थापना के समय तथा उसके बाद के वर्षों में वह पिक्किंग में भारतीय राजदूत था। चीन का प्रति भारतीय नीति का निर्धारण उन्हीं के द्वारा भजी गयी रिपोर्टों के आधार पर हुआ था। अनेक विदेशी और भारतीय प्रेस का कहना है कि पाणिक्कर भारतीय राजदूत के रूप में चीन के इरादों का भरोसा प्रति समझन में पूर्णतया असफल रहे और चीन के बारे में भ्रांतिपूर्ण सूचना देकर भारत सरकार का गुमराह करने लगे। फलतः जाग चले और चीन के प्रति भारतीय नीति विकृत असफल हो गयी। जसा कि जाज के पेटसन ने लिखा है इसमें कोई सन्देह नहीं कि पाणिक्कर व्यक्ति के रूप में चीन की भ्रांति के प्रति सन्तुष्टि रखता था। लेकिन वह भारत के नेता का प्रतिनिधित्व करने वाला राजदूत था और इसलिये यह उसका अभ्युपेक्षा था कि वह पिक्किंग सरकार द्वारा कभी जानबूझी बातों का औपचारिक मन्तर स्वीकार करता चला गया। हम जानते हैं भारत को इस समय तथा उसके बाद अत्यधिक हानि पहुँचायी।¹

(viii) राजनीतिक तत्त्व—भारत की विदेश नीति का निर्धारण में भारतीय समझ की भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण रहा है। सवा मुख्य कारण यह है कि समझ में एक ही दल का विशाल बहुमत अभी तक रहा है। जवाहरलाल नेहरू इस दल का सर्वोच्च नेता थे और उनका व्यक्तिगत की सुती सम्पूर्ण दल पर हमेशा छाया रहती थी। विदेश नीति के सम्बन्ध में वे जो भी कहते थे समझ उस पर अपनी स्वीकृति की मन्तर लगा देती थी। लोकसभा का अतिसमर्थक विदेशी विषयों की परामर्श समिति अवश्य गठित हुई है। और उसमें सभी राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व होता है। पर विदेश नीति के निर्धारण में इसका वह महत्व नहीं है जो अमेरिकी मोनरो के विदेशी सम्बन्ध समिति का प्राप्त है। फिर भी विदेश नीति में समझ ने पर्याप्त रुचि लिया है और विदेशी मामलों पर उसमें कई उच्चनीय व्यक्तियों का नीतिनिर्धारण पर कोई प्रभाव पड़ा है या नहीं यह कहना कठिन है लेकिन जनमत तयार करने में हमें बड़ी सहूलियत मिली है। चीन के विरुद्ध देश में उमात्पन्न करान में इन बहनों का प्रमुख हाथ रहा है।

विदेश नीति का निर्धारण में भारतीय जनता का भाग नगण्य रहा है लेकिन भारतीय समाचारपत्रों तथा पत्र पत्रिकाओं ने इसमें प्रमुख भाग लिया है। लेकिन समाचारपत्रों की भूमिका कभी ही पर्याप्तपूर्ण रही है। भारत का विदेशी समाचार पत्रों की एजेंसियाँ मुख्यतया पश्चिमी देशों की हैं। रॉयटर्स (Reuters) या एसोसिएटेड प्रेस (Associate Press) आदि सवा समाचार पत्र प्राप्त किए जाते हैं उनमें पश्चिमी जगत् का स्वभाव प्रधानता मिलती है। भारतीय समाचार एजेंसी जम—प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (Press Trust of India) का स्थापना भी भारतीय जनता माना जा सकता है। एनी समाचार एजेंसियाँ द्वारा दी गयी खबरों का आधार पर

नेशा का समान एक अनिर्विकल्प समस्या उत्पन्न हो गयी थी। तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ में भारत का समान यह मांग व्यक्त था कि या तो यह नीति विरोधी गुणा में से किसी एक गुण में शामिल होकर अन्तर्राष्ट्रीय नीति को सम्भावना का जोर कम कर दे। शक्ति मन्तुलन का धिक् पिछे मिडान्त का आंतर पर अपना विश्व नीति का निर्धारण कर एशिया में भी इस विपावन मिडान्त का प्रचार कर और शम्प्रास्त्रा तथा सन्निक गुन्त्रातिया का प्रोत्साहन दे अथवा गुणा में जलग रहने हुए प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या का गुण अवगुणा का सम्पादन कर स्वतन्त्र रूप में और बिना किसी बाह्यी हस्त रूप के अपना विशेष नीति का निर्धारण करे। अतः इस प्रकार की स्वतन्त्र विशेष नीति का अनुसरण के लिए यह परम आवश्यक था कि नैतिक राजनीतिक औद्योगिक तथा खाद्य उत्पादन की दृष्टि में आत्मनिर्भरता का पुरी ता का न जयवा जगिन पुरी ता का अवसर उपस्थित होना पर धन में किसी भी कमजोरी के कारण राष्ट्र का अपनी विदेश नीति में परिवर्तन करने के लिए बाध्य नही जाना पड़े। दूसरे शब्दों में तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ के पक्षधारा में विशेष नीति का एक मुद्दा जागर भी प्रदान करना था। 1947 में भारतीय विशेष नीति का जो निर्धारण हुआ और इस जो आधार प्रदान किया गया उसमें मध्यम मूल्यपूर्ण और निर्णायक तत्व सत्तार का दो खमा में बट जाना और उनका मध्य शीत युद्ध का प्रारम्भ था।

भारत की विदेश नीति का उपरागत निर्धारक तत्वों पर विचार करने के उपरान्त निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि इस नीति का निश्चित करने में अवगत तान नहर् का मन्त्रवर्ण हायरता है। अतः भौगोलिक यति एतितमिक परम्परा जायिक और सैनिक आवश्यकताएँ तथा सर्वम ऊपर राष्ट्रीय हित ने नम नीति का एक निश्चित निशा प्रदान की है। इस सम्बन्ध में हम एशिया का जागरण और विश्व की महाशक्तियों की शक्ति-कूटनीति की उपरा भी नहीं कर सन।¹ इन मध्य नहर् ने पथर पथर रूप में और कभी कभी भिन्न जुनकर भारत की विश्व नीति का निर्धारण का प्रभावित किया है। इस सम्बन्ध में नहर् का यह कथन मध्या उपरुवन प्रदान होता है कि भारत की विदेश नीति का मरी व्यक्तिगत नीति का ना मवधा ध्यातिपुन है। यह यनिए मन्त है कि मैंने कवन उम नीति का मन्त्रा मन्त्रिपान किया है जाविधार नही किया है यह नीति मध्यत हमारी परिस्थितियाँ की उपज है। व्यक्तिगत रूप से मरा विश्वास है कि भारत का वदेति मामन् की बाग डार यति किसी अन्य व्यक्ति या दल के हाथ में हानी ना भी हमारी निम्न नीति वत्तमान नीति में भिन्न नहर् हानी।

1 Indian foreign policy like all policy is a mirror of competing purposes and pressures generated in a semi colonial economy with a class as well as a caste hierarchy at the same time conditioned by the fixed facts of geography as well as the fluid facts of power relationship in the changing context of the world balance of power —Karunakar Gupta *Indian Foreign Policy* p 11

विश्व नीति की घोषणा और विनोदताएँ

जब भारत स्वतंत्र हुआ और अपना विश्व-नीति का निष्पत्ति करने का उन अधिकार प्राप्त हुए तो उसमें उपराष्ट्र सभा तथा का मन्त्रालय जनिवाय रूप में जाना था। जतन्मि सरकार का स्थापना के तुरन्त बाद 7 मितम्बर 1946 का जतन्मि नरुह न प्रस मम्मलन म भारत की भावा विश्व नीति का एक स्पष्ट प्रस्तुत का। सरकार और पर भारत का विश्व-नीति म सम्बन्धित यह पत्रा महत्पूर्ण घोषणा था। नरुह न कहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र म भारत एक स्वतन्त्र नानि का अवलम्बन करण और विनी भा मुह म शामिल नगी जात। मुह का उचिताना म 1947 रहकर प्रसार के समस्त पराधान राज का जातिनीय न अधिकार मान करण तथा प्रजाताप भूत भाव का नीति का दृष्टापूर्वक समन करना समका निश्चित नीति हात। भाव हा यह समार के अन्तर्गत प्रमा जात नीतिप्रि राजा के साथ मितकर अन्तर्राष्ट्रीय मद्राज और मद्रावना के प्रसार के लिए निरन्तर प्रयत्नान करण। नरुह न भारत राज मयक्त राष्ट्रमध न पूरा मद्राज करन का आश्वासन दिया और अपना नीति तथा हमियत के अनु नार विश्व नीति के लिए मन्त्रि रूप म काय करन के लिए भारत का स्वाएअर्पित की। नरुहने भारत के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध वधान पर भा वन दिया और कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मान प्राप्त करे न के बाद यह आवश्यक हो गया है कि भारत मसार के समा राज के साथ कूटनातिक सम्बन्ध स्थापित कर।

स्वतन्त्र भारत का विश्व नीति का यह स्वरुप वस्तुतः एक सन्निवतम् और स्पष्टतम् व्यास था। समा आधार पर भारत का विश्व नीति विकसित रह। सन् 1947 म अभा नन का भारतीय विश्व नीति के इतिहास का अधिन विदा जात तो उनका निम्नलिखित विषयताए पायी जा सकता है

(i) दुर्बलता म अन्त रहकर विश्व राजनानि में प्रम रणता का नीति का अवलम्बन करना।

(ii) शान्तिपूर्ण महजीवन के मिद्वान्त में विश्वास करत हुए तथा समस्त राजा म मित्रता का सम्बन्ध कायम करत हुए विश्व नीति का स्थापना में यथा सम्भव सहयोग देना।

(iii) परस्पर विरोधा गतिवता में अनुबन्ध का काम करना ताकि राजों का आपना राजा विस्फाट रूप न धारण करे।

(iv) अनिष्टावाज और प्रजाताप विभक्त का विराध करत हुए पराधान राजों का स्वतन्त्रता प्राप्ति के प्रयास म सहान्ता देना।

(v) पारम्परिक आर्थिक तथा जन जिन के रणाय एणिगत अन्ति राजों का मगति करना। तथा

(vi) मनुन राष्ट्रमध तथा सम सम्बद्ध समका अन्त सम्भारा का समन करत हुए नन साथ मद्राज करना।

आ के पक्षों म हम नही विपताआ का वधान करत नरुहने मन्त्रित करन का प्रयास करे।

असलग्नता की नीति

(Policy of Non alignment)

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद के काल की विश्व राजनीति में असलग्नता या गुटनिरपन्ना (non alignment) का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया था। इस शक्ति का प्रयोग प्रायः उन राज्यों की विदेश नीति की माहिरा करने के लिए प्रयत्न किया जाता रहा जो कि साम्यवादी और पश्चिमी गुट के साथ किसी सैनिक संधि में बद्ध नहीं थे। यद्वात्तर काल में इस सिद्धांत का प्रतिपादन भारत न किया बस इस सिद्धांत का अस्तित्व भारत द्वारा इस अपनाये जाने के पहले भी था एवं इसमें संवध में पर्याप्त साक्ष्य की रचना हो चुकी थी। स्वतंत्रता के बाद भारत न अपनी विदेश नीति का मुख्य आधार असलग्नता की विचारधारा का बनाया। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को इस नीति का जनक माना जाता है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इसका अपनाया उसे स्पष्ट किया इसकी मद्दातिन विवेचना का कार्य किया तथा नवोन्मिता राष्ट्रों में इसका प्रचार किया।

नेहरू द्वारा असलग्नता की नीति की अपनाये जाने का एक ऐतिहासिक पृष्ठ था। हमारा राष्ट्रीय आन्दोलन के नेताओं ने स्वतंत्रता से बहुत पहले ही अन्तराष्ट्रीय राजनीति में रुचि लेना प्रारम्भ कर लिया और इसमें परिणामस्वरूप ही बाद की हमारी विदेश नीति का रूप निर्धारित हुआ। दो विश्व युद्धों के बीच के काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विश्व राजनीति के सम्बन्ध में समय समय पर प्रस्ताव स्वीकार किये। इनमें एक ने इस बात पर बल दिया था कि भारत का अन्तराष्ट्रीय द्वारा की जानेवाली गुटबन्दी या झगडा में अपने आपको सम्मिलित नहीं करना चाहिए।¹ हमारा स्वतंत्रता मस्य कवन स्वतंत्र राष्ट्रीय स्थिति प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं था वह क्रमशः गिरेन तथा अन्तराष्ट्रीय शक्तियों के साथ भावी सम्बन्ध विषयक सिद्धान्त भी निर्धारित कर रहा था और हम प्रक्रिया में वह न कवन गिरेन से दूर जा रहा था अस्तित्व उन देशों में भी दूर जा रहा था जिनके उद्देश्य तथा सिद्धान्त भिन्न थे। प्रत्येक दृष्टि में यह एक स्वतंत्र या असलग्न नीति की प्रारम्भिक अवस्था थी जो कतिपय ऐसी हिता और आशों पर आधारित थी जिनमें भारत परदे रहना चाहता था। स्वतंत्र भारत की विदेश नीति में असलग्नता का सिद्धान्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इस स्वतंत्र नीति का स्वाभाविक विकास है।

1. The nationalist movement instilled a yearning for a decisive voice in world affairs. At the same time however there also grew a desire to save India from involvement in the power politics of Great Power —B Prasad *The origins of Indian Foreign Policy* p 253

इन आराग और प्रत्याराग म युद्धोत्तर विश्व की सारी समस्याएँ मन्त्रहीन हो गयीं और हमके साथ साथ तीसरे मन्त्रासमर की तयारी चल रही। एक म एक मया नन शस्त्रास्त्र बनने लग। भविष्य मगठना का निमाण शरू हुआ। कुछ ही मिनटों में ऐसा प्रतीत होना लगा कि ज्ञाना गुण के मध्य अंतिम पमना के लिए युद्ध का हो जाना अनिवार्य है।

1947 के आने आने गीन गुट का क्षत्र बढकर बहुल यापक हो गया । यूरोप और एशिया के अधिकांश देश नन गुटवाल्या के जात म फम गय और के गुट तीर पर एन नसरे का समथन करन लग । इनम से प्रथम गुट नयात्रि स्वतंत्र राष्ठा को अपन एत म भिजान के निग उमरु था । के अपने समथका की मर्या बढाना चाहने थे । बिश्व राजनीति की नय दिवट परिस्थिति मे ही स्वतंत्र राष्ठा के रूप म भारत का जन्म हुआ था ।

असहजता की नीति का जन्म—स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मन्त्रमंभ भारतीय विदेश नीति के मूल सिद्धान्त का निर्धारण एक बड़ा ही कठिन प्रश्न बन गया। गुट प्रणाली की विस्तृत स्थिति में भारत क्या करे? क्या समार के जय देशा नी तरफ़ का भी किसी एक गुट में शामिल हो जाय? तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों—भारत के समस्त दो विदेश स्वतंत्र विदेश या ताब शक्तिमत्तवत्त के घिसटित सिद्धान्त के आधार पर दो विराट्टी गटा में से किसी एक गुट में शामिल होकर अपनी विदेश नीति का मन्त्रान कर एशिया में भी हस्त विधान सिद्धान्त का प्रचार करे और सम्प्रदाय की ओर एक गतिर गत प्रणाली का प्रामाण्य दे अथवा ग। में जाय रहने पर प्रदेक अंतर्राष्ट्रीय समस्या के गणवगणा का मू यकिन कर स्वतंत्र रूप में और बिना किसी बाधों के हस्त ले के अपनी निरक्ष विदेश नीति का निर्धारण करे। दूसरा विचार ग। में मन्त्र नी या क्यारि स्वतंत्र विदेश नीति के अनुकरण के लिए परम आवश्यक था कि एक राजनीतिक जातिव शीघ्रागि और प्रायः सम्प्रदाय की विरुद्ध जातिभर। जाति परीत के अन्तर उभरि होन पर स्वतंत्र में किसी भी कमजोरी के कारण राष्ट्र का अपनी विदेश नीति में परिवर्तन करने के लिए बाध्य नहीं होना पार। पर्याप्त बिना विमर्श के बाद एक निश्चय किया गया कि सभी रक्षिता या के बादजून भारत के राष्ट्रीय नित (national interest) में विदेशी साय या अस्मन् ही नितर है। दैव के तित और विश्व के वृत्तर तित में भारतीय निताना का यो नित निताना हुआ कि पवित्र गन्तवत्त के सिद्धांत का निताचन कर के यो में जाय रहने पर सम्प्रदाय विदेश नीति का अनुकरण किया जाय और विराट्टी ग। के मन्त्र एक सम्प्रदाय के अनुस्थापित करने का वाणिश की जाय तारि विर। अपय और वमन्त्र अति सम्प्रदाय हो और विदेश नित भग। न के सम्प्रदाय के उन्तर। है। नन्तर प्रारम्भ में श्री भारत के नीति निर्धारण करने पर कि व समार के किसी गुट में सम्मिलित न। ग। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सभी प्रश्नों पर तत्कालीन नीति का सम्प्रदाय करे और नन्तर वास्तविकता पर ध्यान रखते हुए स्वतंत्र रूप में सभी प्रश्नों के दृष्टिकोण अन्तर्कर एक अपना निणय करेग।

असंगनना की नीति का औचित्य (Justification of Non alignment)

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति से विवेक हाकर और अन्तर्राष्ट्रीय हित का ध्यान में रख कर भारत ने यह निश्चय तो कर लिया कि नयी नीति के अवलम्बन में अनेक कठिनाइयाँ थी। ज्ञात युद्ध के महारथियों का यह दाव समझ में नहीं आया कि काँ पछिछा हुआ नवजाति राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में कम और क्या स्वतन्त्र नाति का अवलम्बन कर सकता है ? तब जय ज्ञानयुद्ध तथा गुला का आपसा में भग्न गहरा होता गया वन वन उनक (विपक्षक अमेरिका गन) का यह प्रयत्न होता कि किमाँ भी तरह समार के न देना का जो अन्त का तन्मय मानने के अन्त में शामिल कर लिया जाय। इस उद्यम का प्राप्ति के लिए सभी तरह के उपायों का अवलम्बन किया जाना पड़ा। एशिया और यूरोप के नवजाति राष्ट्र पश्चिमा गट के देशों के उपनिवेश से आगे अन्तर्गत प्राप्ति के दावों में भी शामिल थे। सदियों के आपस के कारण आर्थिक दृष्टि में एकत्र पड़ने वाले देशों के नवनिर्माण के लिए विनाशकारीता का ज्ञान था। म समझ समार में नईकन राज्य अमेरिका ही एक ऐसा देश था जो दावा विनाश या प्राप्ति धित महायता दे सकता था। अतएव हमी स्थिति में तब उदाकर अमेरिका गट ने कूटनातिक धमकियाँ कर आर्थिक मजबूती के सम्बन्ध में अमानता का प्रयत्न कर तथा अन्य तर्कों में दावों को नष्ट किया ताकि विवेक हाकर हम राष्ट्र में गट में शामिल हो जाय। माविष्य सुष का कारण म तरह का दावों को नष्ट ता तब जाता गया कि तन्मय राष्ट्रों के सम्बन्ध में नया विचार भी उन्ना बढ़े न था। 4 दिसम्बर 1947 का भारतीय मन्त्रिपरिषद् ने जवाहरलाल नेहरू ने कहा हमारा नतीजा म म किमाँ भी गट में शामिल न कर विनाशकारीता में अन्त रटन का निश्चय किया है। किन्तु इसका परिणाम अज्ञात नया है। ज्ञान में म काँ भी गट अन्तर्गत के प्रति मनुष्यता नहीं रखता।¹ फिर भी तब न हमी उद्यम के दौरान मय मय कर लिया कि हमका परिणाम चाँ तो भी भारत अपना तन्मय और स्वतन्त्र नाति का परिणाम नष्ट करणा क्या कि हमी नाति का अवलम्बन करने में भारत का जित और क्या मिति के अन्तर्गत नये नये अवलम्बन का निषेध मात्र धार्मिक आत्म या आत्मवादिता का परिणाम न था य एक सम्भार चिन्तन का परिणाम था जिसके मूल में निम्नलिखित बातें थी

दोनों गटों से मन्त्रीपूण सम्बन्धों की कामना—स्वतन्त्रता के समय जब नर भारत का जय हुआ तब दावा भी गट के देशों ने मनुष्यता प्रतीति का ज्ञान भारत ने मन्त्रीपूण सम्बन्ध रखने का दावा कर का। भारत का मुख्य विरोध ब्रिटिश कर काँ के प्रति था। उसका ज्ञान म काँ विरोध भी समाप्त हो गया और सभी ने

भारत की सद्भावना का प्राप्त करन की चेष्टा की। इस पृष्ठभूमि में यदि हम एक गुट में सम्मिलित हो जाते तो यह एक भयंकर भ्रम होती। हम बिना कारण एक का मित्र बनाकर दूसरे की दुश्मनी माँगते। अतएव अमरगता की नीति अपना दोना गटा की मित्रता कायम रखना थी। जब दोना ही हमारी मित्रता चाहते थे तो हम एक का मित्र और एक को शत्रु क्या बनाते

इस सम्बन्ध में एक बात और है। अमरगता की नीति का निर्धारण में यूरोप और एशिया के राजनयिक इतिहास ने निर्णायक भूमिका अदा की है। यूरोप में राष्ट्रा के बीच बढ़ता और मजबूत की एक दमनी परबरा है। नया इतिहास ही गठबंधन का इतिहास है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों के पक्ष यूरोप में हमेशा दो या दो से अधिक गठ रहे। अतएव एशिया के देशों के साथ ऐसी कार्यवाही नहीं थी। एशिया का अपना राजनयिक जीवन एक स्वच्छ स्तर पर प्रारम्भ करना था। स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जब भारत का प्राप्ति हुआ तब तो उस समय एशिया के किसी भी देश के साथ उसका शत्रुता नहीं थी और न समार के किसी भाग में उसका अशान्तिपूर्ण स्वाधिन ही निर्मित था। इस पृष्ठभूमि में वह समार के प्रत्येक देश का मित्र बन सकता था और विश्व शांति की मजबूत तब पृथक् में सबके साथ सम्बन्ध कर सकता था। यह अमरगता की नीति का अनुसरण करके ही सम्भव था।

आर्थिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता — वर्षों के साम्राज्यवादी शोषण के उपरांत भारत अभी अभी स्वतंत्र हुआ था और उसके समक्ष सत्रय महत्वपूर्ण प्रश्न देश के आर्थिक पुनर्निर्माण का था। म काय के लिए समार में शांति का कायम रहना परम आवश्यक था। गला में शांति हो जाने से अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में और बढ़ि जाती और यह की सम्भावना प्रती जाती जो निश्चय ही भारत के राष्ट्रीय निर्माण के लिए अतिक्रम होती। भारत में अभी का ता था कि स्वयं उनकी सीमाओं में शांति एक बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय शांति के लिए अधिक उम्मीद था क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय शांति के अभाव में आर्थिक विकास और प्रगति के उमरे सभी सपने अधरे हो जाते। अतः आवश्यक था कि वह न केवल तटस्थ और स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करे बल्कि सभी मजबूत और रचनात्मक अन्तर्राष्ट्रीय विचारधारा का मूलन और विकास करन में सहयोग दे जिसके विरोधी विचारधारा का गला शक्तिशाली गटा के मध्य बढ़ता हुआ तनाव और कमनस्य कम हो। हमने अतिरिक्त यह भारत किसी शक्ति गट में शामिल हो जाता तो इसका मतलब था कि वह विरोधी गट द्वारा शत्रुता की श्रेणी में मान लिया जाता शांति गट हमारी सीमाओं में प्रविष्ट कर जाता और मजबूत साधन गला का उपयोग आर्थिक विकास के कार्यों के लिए न होकर मजबूत शक्ति का निर्माण करन के लिए होना। विश्व मजबूत सहायता और आर्थिक सहायता पर निर्भर होने के कारण देश की अर्थ व्यवस्था का स्वाभाविक विकास भी नहीं होता और विकासोन्मुख और आम निर्भर बनाने के बजाय वह मजबूत व्यवस्था कुत्रिम आर्थिक समृद्धि और मजबूत स्थिति के भार में चरमरा कर टूट जाता। भारत का क्याण इसी में था कि वह गला में

भोति निर्धारण में स्वतंत्रता की इच्छा—स्वतंत्र रूप में नीति निर्धारित करने की कामना ने भारत का असलगनता की नीति की आधार प्रगति किया था। 'याय' की भी यह याद है कि हम अपना नियम स्वयं लें। भारतीय राष्ट्रीयता का गारव और प्रत्येक क्षण पूर्ण स्वतंत्र रहने का उत्कट अभिप्राय तटस्थ और स्वतंत्र विश्व नीति के अवतम्बन में दूसरा प्रकट हो रहा था। वपों के प्रयास और महत्वाकांक्षी प्रमियों के विनियान के बाद भारत स्वतंत्र हुआ था। एसी स्थिति में भारतीयों के लिए स्वतंत्रता से बटकर मर्यादा का दूसरी वस्तु नहीं था। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किसी गुट में सम्मिलित होने का जब इस मर्यादा के स्वतंत्रता का छोड़ देना था। भारत यह अनुभव करता था कि विश्व राजनीति में घिरे हुए स्वतंत्र रूप में भाग लेना उस पूर्ण अधिकार है। अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत अपना कार्य नियम स्थापित नहीं कर सकता कि यह गलत अथवा सही गलत ठहराया जायेगा कि उसका नियम का आधार की होगा जिसको वह ठीक समझता है और जो उसके गारव के लिए है। गटबन्ध में शामिल होने का अर्थ होता था कि पक्ष से हाँ कुछ मायताओं के आधार पर नियम बना। गटबन्ध की राजनीति में नियम गलत की नीति का आधार पर होता था किन्तु राष्ट्रों के नहीं। यदि भारत किसी गट में शामिल हो जाता तो उसकी सारी स्वतंत्रता खत्म हो जाती। भारतीय मसल में जब किसी सम्मेलन में मुझसे पेश किया कि भारत को अपना असलगनता की नीति का प्रतिपादन कर देना चाहिए तो मेरे मन में तब दृढ़ता से कहा कि किसी गट में सम्मिलित होने का अर्थ क्या है? इसका जवाब एक ही था—किसी एक पक्ष में शामिल होकर अपने विचार का परिचायक कर दें और दूसरे का खुश करने तथा उसकी सन्तुष्टि प्राप्त करना के लिए उसके विचारों को मान लें। भारत के लिए एसी स्थिति असह्य थी। वह अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्र रहना चाहता था और किसी गट में शामिल होकर इस स्वतंत्रता को बायम नहीं रखा जा सकता था। राष्ट्रीय स्वाभिमान का तकावा था कि भारत जहाँ प्राचीन एवं सम्माननीय देश किसी भी गट विचार के साथ अपने को न बाँधकर स्वतंत्र रहे। कुछ समय में भारत ने नैतिक विचार और भौतिक प्रगति में समार के शक्तिशाली देशों की जगह में पहुँचने की सम्भावना थी। अतएव यह गारवी था कि वह किसी के साथ जुटकर अपने अधिकारों को समाप्त कर दे। एवं अवसर पर मेरे मन में ठीक ही कहा था।

किसी गट के साथ मजिद संधियों में बंधन के कारण मर्यादा उसके द्वारे पर नाचना पड़ता है और साथ ही अपनी स्वतंत्रता खो देता है। अतः कुछ भी हो जाय हम किसी देश के साथ मजिद संधि नहीं करेगा। जहाँ हम असलगनता का विचार छाँट रहे हैं हम अपना गारव छोड़कर नहीं लगते हैं। किसी देश से बंधना आपस में मानना है यह बहुत ही निम्न की विन्यास है।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की कामना—अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रतिष्ठा पान की कामना ने भी भारत का असलगनता की नीति का अंगान के लिए बाध्य किया। जवाहरलाल नेहरू का विश्वास था कि यदि भारत स्वतंत्र विश्व नीति का अवतम्बन करने हुए सभी अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर नियम रूप में अपना नियम लगा तो दोना

गट-नक विचारों का आंतर करेग और अन्तराष्ट्रीय तनाव में क्या हाथी नया भारत का अन्तराष्ट्रीय प्रतिष्ठा घटगी। समार क दो गुटा म दट जान क कारण बिब ताज नाति म यता-कता गतिराधा उत्पन्न हात रहत थ। एस गतिराधा का दूर करन क लिए कुछ एस राष्ट्रा का भा जावश्यकता थी जा का बाच का सन्ता निवानकर दोनों पक्षा क बीच समझौता करा नकें। गुटा म शामिल राष्ट्र इस तरह का प्रिम्स द्वारा नगें जा सकत थ क्याकि उनका नाफ स का उचित प्रस्ताव भा जाना ता विराधा गट उनका शक का निगाहा न दखता उसका प्रतिष्ठा का प्रान बनाकर नामकर कर जाता। अन्तराष्ट्रीय गतिराधा का मिगान नया हम तज शामिल का सुरक्षित करन क उद्देश्य म हा भारत न अन्तराष्ट्रीय का नीति का अपनाना चित समझना। बाट का अन्तराष्ट्रीय घटनाजा न हम अनुमान का वन धामें टीक नावित किया। दूसर बात म भारत क प्रथम न क अन्तराष्ट्रीय गतिराध मुधाव गय। यदि भारत किना गट म शामिल हा गया रहता ता हम य गाव नगें प्राप्त हाता।

व्यवहारिक मतभेद—व्यवहारिक मतभेद का कारण चाहक भा भागन किना एक गति क साथ टुट नया मकना था। पश्चिमा टुट म जा राष्ट्र सम्मिलित थे व सब के म साम्राज्यवादी रह चुके थ जो अभी ना जनक कद प्रतिष्ठा कायम थ जा व पराधीन जातियों क स्वातंत्र्य सशम का बुखान में यन्त थ। थ तद्विषय गोपण का नाति वस्तुतः थ और गभट का नाति क समझक थ। य एन टाप थ निम्न भागन का अधिक घृणा था और उन टाप क पादकों का भागन म का सम्बन्ध नहा ग मकता था। हम प्रकार साम्यवादी टाप के साथ सम्मिलित जाना भी भारत क लिए अमंजब था। थ साम्राज्यवादी विचारधारा और राभट की नाति के विरोधी थ परन्तु उनका राष्ट्रीय राजन्याय म अतिरिक्त राजन्याय स्वतंत्रता क लिए का यान नगें था। स्वतंत्रता क सम भारत का गमन निन ताग क हाथ म था व राजन्यायिक व्यवस्था पर टुट जार नेत य नया इन पान आवरण मानत थे। अतएव नाविन टुट का जार भा भागन का युक्त नगें हा माना था। हम स्पिति म जसमानता का नाति क अतिरिक्त भारत क समझ बाट दूसर विषय नगें था।

एशिया देशों क समझ उद्धारण—यदि भारत पश्चिमा टुट म शामिल हा जाना ता मध्य एशिया पर सका वन कुछ प्रभाव पड़ता। एशिया क नवास्ति राज्य पश्चिम का शक का दृष्टि म रखत थ और य जाग रहत थ कि साम्राज्य बाट क विरुद्ध भावा तपाय करन म भारत आपा का काम पड़ता। उदाहरणतः म नवी देश-देश सम्माने था क्याकि स्वतंत्रता सामन क निना न न्होंने भारत का स्वातंत्र्य का प्रान का एशिया क प्रान म पदक बाँट तीरता था। म यगा धार म यदि व भारत का किना गट म सम्मिलित करा रहता था टुट गवर्ण या पश्चिमा साम्राज्यवादी का टट्टू क मकत थ। जाना गों म स्वतंत्र रखकर हों

भारत का मिर ऊँचा किया और अपने विरोधियों को भयाना करने का जयमराजी निया।¹

नतिक दृष्टिकोण—नतिक दृष्टिकोण में भी यह मानना पड़गा कि नतीजा। युद्ध में से किसी का पक्ष पूर्ण प्रयत्न नहीं था या कोई पूर्णतया निर्दोष नहीं था। एक शताब्दी है और दूसरा शताब्दी यह प्रचार निरूप्य करना अत्यंत कठिन था क्योंकि यह स्वतंत्र और अश्वेत का रणभूम नहीं था। दाना ही गन्ध और असत्य का मिश्रण था। मध्य युग में ईसाइयों के दो दवा—प्रायश्चित्त और कथारिका—में मध्य युग कथारिका प्रचलन अपने आपका मध्य का ठीकदार मानना था किन्तु अंत में नतीजा का ही सन्निधता और मध्य अस्तित्व का पाठ पढ़ना पड़ा। नतीजा का नया समसामयिक राजनीति में मध्यमाली के नायकों का करना पड़ा किन्तु नतीजा में मध्यमाली नतीजा। जयमराजी की विचारधारा नतीजा स्थिति उत्पन्न करने में सहायक। इस धारणा में भी भारत का अमलगनता की नीति का अपना ही प्रतिनिधित्व निया।

अमलगनता की नीति की विनियमताएँ—अमलगनता की नीति का विवेचन करने पर प्राथमिक पीछे नतीजा है। नीति युद्ध में अथवा मध्यमाली का अमलगनता तथा सोवियत मध्य द्वारा प्रेरित बड़ी शक्तियों के साथ। के मध्य युद्ध की राजनीति का राजनयिक प्रतिनिधित्व में किसी भी पक्ष का समर्थन करना। मध्यमाली का विचार अन्तर्निहित है। भारत का मध्यमाली अमलगनता का अभिप्राय यह था कि भारत विश्व का नीति का नतीजा पढ़ा में से किसी एक में भाग्यविनिर्णय के लिए तयार नहीं था अतः उनका पक्ष रहने का भी उनका मध्यमाली कायम रखने और उनकी सहायता से अपनी उन्नति करने का इच्छुर था। भारत को विश्वास था कि अन्तराष्ट्रीय शांति की सुरक्षा में उनका मध्यमाली कायमान तभी हो सकता है जबकि वह अपने विचार की स्वतंत्रता नहीं छोड़े किन्तु यदि वह किसी एक विचार के साथ बंध जाय अथवा उसका साथ स्थायी मध्यमाली कायम कर ले तो वह ऐसा नहीं कर सकता था।

मध्यमाली में अमलगनता की मध्यमाली का भारतीय नानि अन्तराष्ट्रीय राजनीति से एक अत्यंत विवादास्पद विषय बन गया। इसका एक मुख्य कारण यह था कि किसी भी स्थिति में निर्धारण भी इसकी व्याख्या स्पष्ट नहीं की नहीं कर पाते थे। नतीजा नीति का विविध नाम में पुनरावृत्ति जाना गया जस—नतीजा विविध

1 If Nehru becomes a formal ally of the west in cold war he would be going against the whole grain of Asian anti colonial sentiment. He would be under constant and effective attack as a stooge of western imperialism. By his independence of either bloc he is able to draw on all the pride of Indian nationalism and to charge convincingly that it is the Asian communists who are the foreign stooge. —Chester Bowles *Ambassador's Report* P. 141

एसी बात क' लिए आमसमवष जिस व' गत समझने थे । त्तीय यह किमी अंतर्राष्टीय विषय पर अन्तावक विचार व्यक्त करन म जानासानी भी नही करता था । तृताय भारतीय नेताओं न एसी किमी भी स्थिति म जिस व' सी समझन थ' अपने आपका आग्रह करन म जानासानी नही की और न उम पर आश्रित किमी भी अन्तर्राष्टीय को वान करन म कभी टानमटान की । त' तानीन अंतर्राष्टीय राज नीति क' सम्म म भारतीया न सन्व यह सम्मूम किया कि व' अन्तर्राष्टीय उत्तर दायित्व का वान करने से बतरा नही मक्त ।

असंलग्नता की नीति और तृतीय गुट की धारणा
(Non alignment and Concept of Third Bloc)

[illegible]

यह निश्चयिता कि सिद्धांत कि इस विस्तार को दृष्टिगत अंगवर्तना की भारतीय नीति कि मध्य धर्म पश्चिमा दशा की एक सामान्य धारणा यह है कि यह एक नवय की भय है कि नेहरू को समान विचारवादी तटस्थता कि गट का निर्माण करने का प्रयत्न करती थी। उनकी अंगवर्तना का उद्देश्य अपने पारंग और अपने नरुत्त म छात्र राष्ट्रा का एक गट खड़ा कर देना था जिसमें शक्ति समुत्तन वायम रखा जा सक और एक द्वारा समान शक्तिवादी गटा पर हारी हुआ जा सक। पश्चिमा आवाचना द्वारा बराबर यह बात कही जाती थी कि भारत किसी गट में इसदिप सम्मिलित नही जाना चाहता कि वह अपने नरुत्त म एक तीसरा गट बनाना चाहता था। भारतीय नही इस बात को मानने से इंकार करते रह। यह सम्बंध में नेहरू ने कहा कि इस दश या उस दश के नरुत्त म तीसरे गट का निर्माण हमारा अभीष्ट नहीं है हमारा उद्देश्य तो दोना गटा को मिलाकर एक सहकारी विश्व का निर्माण करना है।

वस्तुतः असमर्थता का नाति कि जगति नृत्ताय तु क निर्माण या आकाश भारत न कभा नहा पाया । एक जनिताता नृत्ताय तु का निर्माण नृत्त य आकाश का सनिक शक्ति क आधार पर हा किया जा सकता था और मध्य ता यत् कि समस्त एशिया गण्टा का मित्राकर भा एक एम जनिताता नृत्ताय तु का निर्माण समभव नहा था । जसा कि नृत्त न कया था । पृथक्-पृथक् रूप न या मयून रूप म एशिया दगा क पास जा सनिक शक्ति न वह नागर है । चूकि या दगा शनिता के मुकाबल म बढा म-बना शक्ति छाया ह जत अपराहितकमद्धार गण्टा हा नामग शक्ति अमरिका या मावियनसध का सनिक शक्ति हा मुकाबल कम क मज्जा पा । तटाय राय नया चाहत थ कि विश्व का और अधिक गुणों म विभाजन या और इस नृत्तय का पूर्ति किता नय गट का निर्माण करक नयों का जा सकता था । नृत्त न एक तटाय तीमरा शक्ति क विचार का हवा वात क क खनि शिवा या और आन्तर गता म हम वात का चयन किया था कि भारत अपना गता प्रविष्टा नृत्तय या किता जय कारण न विश्व का अर अधिक गुण म विभाजित करन का परिकल्पना करता ह । यदि असा एशिया नयों म असमर्थता का निचाधारा का प्रसार नया ता इसका एकमात्र कारण यह था कि न नवाहित गता नया नाति का अनुसरण करन म अपना कता मानत थ ।

असमर्थता की नीति का प्रयोग

असमर्थता का भारतीय नाति क नम सन्निष्ठ विचारण क उद्धान अर हम यत् नखता न कि भारत न हम नीति का प्रयोग कतकत और कम-कम किया है । इस नाति क स्निहान का मुद्रन चार भागों में बाटा जा सकता है

- (i) 1947 न 1950 क कारिया युद्ध तक
- (ii) कारिया युद्ध न 1957 क त्रितीय भारतिय त्राम चुनाव तक
- (iii) 1957 न 1962 क भारत-चात युद्ध क पूर्व तक
- (iv) 1962 न भारत-मावियन सध तक ।

(i) 1947 स 1950 क कोरिया युद्ध तक—स्वतंत्रता क मुक्त दात असमर्थता का नाति वस्तु ह नृत्त जम्पय था आ क कारण म विगुड न था । न त्रिा भारत का नाति अमराता या पश्चिमा गुट का नरक थाया था न या जयान अनराष्ट्राय मामलों में न पश्चिमा गुट का असाक्तन अकि रूप नया था नृत्त क कारण थ सवप्रथम मुग्धा क मामल म नम पश्चिमा गुटों पर पूरवया जाशित थ । भारतिय नया का सगता द्वितीय पद्धति क आधार पर दृष्टा या ना इनलिए हम त्रिन क नाथ नम मामल म बुग तरक मन्द थ । नम अनिनि भारत क समन्वयताय नामा का रणा क रिण भा हम त्रिन न या जाशित थ । त्रितीय भारत क स्थित वग पर पश्चिमा गुटों का अवस्थि भाव था । नमागे शिवा-पद्धति पश्चिमा गुट पर नाया गया था और नम पद्धति में स्थित नामा की महानुक्ति स्वभावत त्रिन और पश्चिमा गुट क नाथ था । त्रििन मध्य प्रमथ

कारण अधिक था। पहले से ही हमारा व्यापारिक सम्बन्ध केवल पश्चिमी राष्ट्रों से था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हम अधिक दृष्टि में पश्चिमी गट पर और अधिक जाति हुए गये। अधिक पुनर्निर्माण के लिए भारत का विदेशी सहायता की आवश्यकता थी। यह सहायता मध्यम ग्रेने और मध्य रात अमेरिका से प्राप्त हो सकती थी। उस समय सावियन सच जायिक और गतिक दृष्टिकोण में स्वयं एक शक्तिहीन राष्ट्र था। अतएव इन परिस्थितियों में भारत की अमरग्नता की नीति निम्न प्रकार से सका और पश्चिमी गट की ओर उसका अधिक झुकाव रहा। सब जन्म उदाहरण दिए जा सका है।

भारतीय अमरग्नता की नीति निम्न नहीं था यह पूर्वी जमनी के प्रति भारतीय नीति में स्पष्ट हो जाता है। विभाजित जमनी में एक का (पश्चिमी जमनी) का पश्चिमी गुट में सम्बद्ध था उसका राजनयिक सायता प्राप्त करना और दूसरे (पूर्वी जमनी) का न। मानना तकमगत नही प्रतीत होता। पूर्वी जमनी का यह कट्टर भारत में सायता नही ले कि ऐसा करना जमनी के विभाजन का मानना होगा जिन भारत का ऐसा स्वरूप नही था।

कारिया युद्ध के प्रारम्भ में भारत का रुझाव कुछ जमी तरफ पतानरण रहा। उत्तरण के लिए मयक्त राष्ट्र अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों की तरफ भारत ने भी उत्तरी कारिया को आश्रय घोषित किया था यद्यपि पश्चिमी देश न आज तक अपने बंधन के समर्थन में विश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए हैं। यह बहुत सम्भव है कि जिन कारिया न ही उत्तर कारिया पर आश्रय दिया। जमा कि कम्पास ग न लिखत है— भारत का निम्नय श्री का डापी की रिपोर्ट पर आधारित था ज र य रिपोर्ट "सब व्यक्तिगत विचारों में अधिक प्रभावित थी। इस तरफ की अन्य कई अन्तर्जातीय घटनाओं में भी भारत पश्चिमी राष्ट्रों के साथ सम्बद्ध रहा।

(ii) 1950 से 1957 का काल—ज काल में सावियन सच के प्रति भारतीय रुझाव कुछ परिवर्तन हुआ। इसके कई कारण थे। 1953 में स्टालिन की मृत्यु के बाद सावियन व्यवस्था में कुछ उत्तरावस्था का समावेश हुआ। इसके साथ सामरिक दृष्टिकोण में भी सावियन सच कुछ शक्तिशाली हुआ। इस समय तक अणु बम का आविष्कार सावियन सच में हो चुका था। स्टालिन के मरणोपरांत सावियन नीति में परिवर्तन का नम मन्वदन उत्तरण युगास्तविया के प्रति सावियन दृष्टिकोण में

1. The Indian Cabinet decision on the matter was made after the receipt of a report from Mr. Kondap, the Indian delegate to the United Nations Commission on Korea. The conduct of the Indian members in the U N Commission on Korea should be a matter of public scrutiny as there is ample evidence to indicate that they were guided more by personal prejudices than facts. In sending advice about the origin of the Korean war on June 25, 1953.

—Karunakar Gupta *Indian Foreign Policy* p 11

म भारत ने हम मामूले में सोवियत संघ का समर्थन किया था किन्तु राष्ट्रम भारत सोवियत संघ का विरोध करने लगा। हमारे अतिरिक्त पश्चिमी देशों का साथ देने बढ़ावा का एक और परिणाम यह हुआ कि उपनिवेशवाद का विरोध में भारत का उत्साह भट्ठ पड़ने लगा। इसलिए पश्चिमी एशिया और पूर्वी एशिया में पश्चिमी साम्राज्यवाद का विरोध जब भारत बहुत ही बढ़े हुए जमाने में करने लगा। रियल नाम संकट का समय था में भारत की प्रारम्भिक अस्पष्ट एवं दबमुन नाति * । परिस्थितियाँ का परिणाम था।

(iv) भारत चीन युद्ध से लेकर भारत सोवियत संबंध तक—नवम्बर 1962 का भारत चीन युद्ध से लेकर आज तक का वात असाह्यता की नीति का निष्पत्ति में ईद दृष्टि का सन्तुष्टपूर्ण है। हम हम नीति की अग्नि परीक्षा का राजा में संकट * । भारत चीन युद्ध का समय और हमारे राष्ट्र जनक विपत्ति और राज नीति का न असह्यता की नीति का वात आवाचना की और कई क्षत्रा में सन्तुष्ट की माग की गयी कि चरित्र नीति पूर्णतया असफल रही है इसलिए यथाशीघ्र हमारा परिष्कार कर देना चाहिए। सन्तुष्ट की माग जनसंघ स्वतंत्रता पार्थी और नीति की तरह विचार रखना वात प्रतिगामा त्रा में नीति हुई वस्तु में निष्पत्ति और निष्कर्ष नगरिका न भा की। उनका कहना था कि निष्पत्ति नीति का एक दम का निष्पत्ति का सुरक्षा करने और बढ़ाना होता * । राष्ट्र की अखण्डता सन्तुष्ट यही बात है। सन्तुष्ट हमारी नाति विपत्ति मिद्ध हुई * । चीन न हमारे मित्रा न श पर अधिकार कर लिया * । भारी सन्तुष्ट सहायता में ही उभर जाता जा सकता * ।

1 Nehru projected the policy of non alignment not merely because he believed that international peace could best be preserved by keeping India out of any military intanglement with either bloc because he was drawn both to the political principles of Western democracy and to the economic principles of Soviet socialism but also because he wanted a free hand in furthering the escape of captive peoples from the custody of any great power. Gradually however as India became more absorbed by her own vast economic problems and with mounting anxiety sought substantial aid from the West the Nehru Government grew less concerned about colonial liberation and not without a measure of self importance concentrated its efforts upon securing international peace by attempting to mediate in the quarrels of the Great Powers. —Ronald Segal *Crisis in India* P 267

Since 1957 India has tended to be content with a rather quieter role in international matters than hitherto by contrast with either Egypt or Yugoslavia to be more moderate less stridently radical and revisionist even on anti colonial issues. —Peter Lyons *Neutrality* p 127

अपना गया कि तब पश्चिमा गणों के साथ सैनिक गृहयुद्धों में सम्मिलित न होकर भारत न भाग भूत की है। ए. डी. गार्गुलाना न मा का कि भारत का पश्चिम के साथ सैनिक सम्बन्ध सुदृढ़ करने में नहीं चिन्तना चाहिए। अतः पार्थी के चरित्रों राजाशासकाचार न कहा कि भारत का पश्चिमा गणों के साथ जटिल घनिष्ठता का सम्बन्ध कायम करना चाहिए। उन्होंने क्या था कि जो गण सैनिक सन्धियों के जग पश्चिमा गणों के साथ थे उन पर चान आक्रमण करने का मात्स न। करता। हाग-काग और मकासा चान के प्रयोग ह पर उनके स्वामा विरुद्ध आर पुनर्गत नाग के सम्बन्ध है। उन गण उन पर हमला नहीं करता। गार्गुलाना चान का आशा था सधन रात्र अमेरिका का नौसैनिक बल उनका आक्रमण था। परन्तु चान उन गण हमला करने का विध्वन नहीं कर सका। यदि भारत पश्चिमा गणों के साथ निकट विना सन्ध साज्ज में समित न गण करता तो विना भा गण न चान उन गण हमला करने का मात्स नहीं करता। और यदि वह हमला करने का क्षमता गता तो गार्गुलाना में मुमकिन न हो कि कारण भारत का अमान जनक पणाय न स्थिति का सामना नहीं करना गता।

यस सम्बन्ध में आचार्य ने दो कृतानता न अपन एक गण में एक बल आ तत्पण सन्ध आता। चान के विचाराना आर आकस्मिक आक्रमण का मुग बला क्या कि तब भारत सरकार न पश्चिमा गणों के सैनिक सन्धिता का अज्ञान था। अमेरिका जो विरुद्ध न तत्काल भारत का सैनिक सहायता उन का निश्च विद्या आर बल बल मात्रा में उन गणों न आचार्य भारत पणाय था। असुरतता का नाति पर आगत करने के लिए आगताना न उन स्थिति में ताम आत गण विना नि सुमार आत न विगधा गण में बल आ और भारत गणों गणयिता के मात्स में असुरतता का नाति का अवलोकन कर गता। अब स्थिति यह कि भारत आ गता में न एक आगत साम्यवादी गण के प्रमत्त सन्ध चान के साथ दृढ़ का स्थिति में आर सका सहायता करने के लिए समक विगधा अमाना गण न सैनिक सहायता गता। उन गण में हनाउ नाति का कम अवलोकन बला आ सता है अब सम्य आ गता है कि भारत अपना नाति पर पुनर्विचार करे। चान के आक्रमण में भारत परिस्थिति में न ता बल असुरतता का नाति का आगत न सता है न असुरता सन्धिता स्वागत करने के बाद युवा गवा की का सता है।¹ इस न ह भारत चान दृढ़ के सम असुरतता का नाति पर आर आक्रमण गता है।

चान के आचरण में स्वर पणित गण का बल धक्का गता। 25 अक्टूबर 1962 का स्थिति क्या कि अभी तक अमान बलता आत में विरुद्ध आ गता सम आक्रमण में हन सम्बन्धित अज्ञान में आता है। अतः उन अज्ञान के बाद यह सन्ध गता गता कि प्रदान सन्ध न असुरतता का नाति का सामना आ आर

संकेत दिया है और शायद भारत नहीं परिस्थिति में इस नीति का परित्याग कर दे। घाता और समुक्त अरब गणराज्य आदि तटस्थ राधा में यह उम्मीद की जा रही थी कि इस विचार में वे समान विचार धार असह्यता भारत का एक और समयन करेंगे अतः इन माघी दशा ने मध्यस्थ रूप में कार्य करना ही उचित समझा। उनसे दृष्टिगत है भारतीय जनता और सरकार का क्या सम्मता पहुँचा। एसा प्रतीत हुआ कि असह्यता की नीति सिद्ध हो गयी है और इससे दशा में हिन सघनता की है।

अतः जवाहरलाल नेहरू का अपने दशन और अपनी नीति में अट विश्वास था। असह्यता विश्वास में प्रती नही दिख और उगावर कृत रूप कि असह्यता की नीति ही एक ही मगर्तम है और व मरा अनुमरण करा गया। एक अमेरिकी पत्र फोरिन एफेयर्स (*Foreign Affairs*) में असह्यता की नीति की प्रामाणिक ध्याता करत हुए उक्त सम्मता अवस्थित समझन दिया। नरुन दिया कि चीन का मतापना करत ने तिन भारत न ही पश्चिमी दशा में मनिन सहायता प्राप्त की है अतः इस में तयता व माघ तिमो प्रकार की सान्नीति जन न। थी। तिमो सहायता का जा रिता जन प्राप्त की जाय असह्यता का नीति में दूर हटा नया क्या जा सकता है।¹

भारत चीन युद्ध ने मन्त्र में असह्यता की नीति की आ जागेरना शुरू मरा करने का जात्रता का यह भी समझना चाहिए कि इस नीति का परि धाग तर जिम गट में भारत का शामिल कराना चाहत थे उन दिना मरिन डीन रस्क (Dean Rusk) ने स्वयं कहा था कि तत्काल परि स्थिति में भारत के लिए असह्यता की नीति ही उचितकर था। ब्रिटिश प्रधान मंत्री मरलिनन ने भी म बात की पुष्टि की थी। दूसरी बात यह है कि असह्यता की नीति का फातर अमरिका गट में शामिल हो जान व फलस्वरूप भारत को भीमा सघनता में युद्ध का एक अणु हो जाना और तब भारत चीन विचार कभी भा हन न। जाता। अमरिका गट में शामिल हो जान में यदि भारत अपने धाय हुए भू भाग का प्राप्त करेगा तो इन पविनया का व्यव भी इन नीति का समर्थन करने का तयार हो जाना था। अतः युद्धावर बात का अतर्हीय स्तिता में उताना है कि अमरिका व सम्पन के सबजू न तः काग्रेस और तयली का स्वीकरण हो सता आन पाकिस्तान का कश्मीर मिन मरा जो न जनता जात का जन ही न सता। इस पृष्ठाधार में भारत चीन भीमा सघनता का अतः युद्ध का अतः बात न म भारत का क्या नाम ला ? अमरिका दः जाणा करत निरा मूयता होनी रि यदि भारत पाकिस्तान गला व स या माध्या में म म मिन गया तो ना बात नरा अधिपत उमर म भाग धाय मिन गय होन। इस सभी परि स्थिति का म जात करत न न न स्ति कर दिया था कि भारत अपनी स्ति व तिन सभी

¹ *Foreign Affairs* April 1963 pp 456-57

की अंतिम रूप में निश्चित कर दिया। यही कारण है कि पाकिस्तान में भी कुछ समय के लिए कहा नहीं जा सका कि असमनता की नीति को अपना लेने की बात सच पड़ी। पाकिस्तान के शासन भी समझने लग गये कि शांति के लिए शांति की नीति राष्ट्रीय नीति का ही हिस्सा है।¹ इस हानत में भारत के लिए इस नीति का परिणाम राजनयिक आत्महत्या के अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा।

गटबन्धियों का अधिकारपूर्ण भविष्य और असमनता की नीति—इस बात में (1963-69) असमनता की नीति का बनावे रखने के पक्ष में एक नए तर्क और सामन आया है। बयूटा के संकट (1962) के बाद चीन युद्ध की गर्मी बहुत शांत हो गयी। एडवर्ड क्रैकशॉ (Edward Cranekshaw) के शब्दों में यह उच्च स्थिति का प्रतिकूल शोषण (dumping down) था। 1963 के मध्य में यह भी स्पष्ट हो गया कि संसार के दाना गटों के अन्दर अनेक घोर मतभेद उत्पन्न हो गये हैं और गटबन्धियों में तनाव उत्पन्न हो गया है। भारत के राष्ट्रपति चाणूद गान के रविवार के कारण अद्वैतिक गट का भविष्य अधस्तार में आ गया।² गान ने नावजनिक तौर पर सबसे बड़ा राज्य अमेरिका पर यह आरोप लगाया था कि वह अद्वैतिक गट का एकमात्र भू-विकास करने चाहता है जिससे नाटो राष्ट्रों की स्वतंत्रता पर खतरा उत्पन्न हो गया है। जब फ्रांस तथा अन्य यूरोपीय राष्ट्रों के साथ अमेरिका का यह व्यवहार था तो भारत के साथ उसका क्या व्यवहार होगा यह साबित की बात थी। साम्यवादी गट की हानत भी इसी तरह डाकड़ाना हो गयी क्योंकि वह भी घोर मतभेद उत्पन्न हो गया। इसी हानत में गटबन्धियों का भविष्य ही खतरों में पड़ गया। कुछ ही वर्षों में इस मतभेद ने अपना उच्च रूप धारण कर लिया कि यह सम्भावना व्याप्त की जाने लगी कि उनका अंत हो जायेगा। जब गटों का ही भविष्य अधस्तार में आ गया तो असमनता की नीति का आगमन कर किसी गट में शामिल होने का क्या औचित्य हो सकता था।

असमनता की नीति और महत्त्व—असमनता की नीति के जन्मदाता और

1. यह युद्ध के कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान के शासक ने भारत के शासन द्वारा प्रतिपादित असमनता की नीति का पक्ष में राजनयिक वाक्यांशों में एक पद्धति विधि माना जाता था। किन्तु भारत-पाकिस्तान युद्ध के उपरान्त गटबन्धियों में शामिल होने की नीति पर पाकिस्तान में भी उच्च हानत पड़ी। कुछ राजनीतिज्ञ यह कहने लगे कि पाकिस्तान का अमेरिकी सहायता का परिणाम एक स्विटजरलैंड सरीखी तटस्थता की नीति का अनुसरण करना चाहिए जो अमेरिकी सटस्थतावादी से भिन्न है। कि पाकिस्तानी राजनीतिज्ञ ने कहा था कि पाकिस्तान के देश के लिए पूर्व और पश्चिम का संबंध सम्पूर्ण पश्चिमी राष्ट्रों के देशों के बीच दो प्रकार की पश्चिमी विचारधाराओं के रूप में गठित है। यह निश्चय ही एक सद्भावना विरोध का रूप धारण कर लिया है कि मूलतः यह विश्व के भाग जमान के लिए दो शक्ति समूहों के मध्य संबंध है। पूर्व के देशों को दोनो ही आक्रामक प्रतीत होते हैं।

अमलग्नता की नीति सर्वोत्तम है और व 'उसी नीति के आधार पर अपनी विदेश नीति का निर्धारण करना रहेगा। वाट की घटनाओं ने सिद्ध कर दिया कि शांसी का यह निश्चय पर दृष्टिधान में उचित था। यही कारण है कि 'राजगुरु शास्त्री की मृत्यु (जनवरी 1966) के बाद जय श्रीमती ने राजगुरु भारत की प्रधान मंत्री बनी तो उन्होंने भी यह घोषणा की कि भारत हमें भारत में अमलग्नता की नीति का अनुसरण करेगा। उनके स्पष्ट कर दिया कि अमलग्नता की नीति के परिणाम के रूप में और स्पष्ट रूप से अभी स्पष्ट नहीं हुए है।

सका एक और भी कारण था। अमलग्नता एक ऐसा नीति था जिसका भारत के प्रायः सभी राजनीतिक नेता ने स्वाकार कर लिया था। दश में पश्चिमी गठबंधन में भी थे और विरोधी भी। सभी प्रकार साम्यवादी गठबंधन में समर्थन और विरोधी भी थे। वे सब भारत की विदेश नीति की आलोचना करने में 'वि-माफ साध' नहीं थे। वे सब दूसरा विकल्प नहीं बताते थे। हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि अमलग्नता में भारत का शामिल हो जाना चाहिए। वह नतीजा अमलग्नता की नीति का न चाहते हुए भी हमारा नतीजा बनने था। अतिरिक्त अधिकतर नेता विरोध इसी बात पर करते थे कि अमुक नतीजा या संकट के सम्बंध में अमलग्नता की नीति का भारत उचित रूप में नहीं हुआ।

म स्थिति में यदि अमलग्नता की नीति का परिणाम कर लिया जाता तो दश में राजनीतिक मतभेद था। जानना चाहना पड़ता है कि 'हमारे समय में ही देश की राष्ट्रीय एकता का क्षीण करने वाली अन्तर्जातीय समस्याएँ हैं। अमलग्नता की नीति हमें इन समस्याओं में एक और ही वृद्धि हो जाती है। हमें यह भी कमजोरी बतानी और साथ ही अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में हमारे सम्मान का धनना पड़ता है। किन्तु भी हमें यह नीति के प्रति अन्तराष्ट्रीय जगत में तब सम्मान प्राप्त जाता है जब हमारा सम्मान 'महान की परीक्षा करता करती है। वस्तुतः दश की विदेश नीति की सफलता 'सर्व गीय' में है। दश की जनता का जितना अतिरिक्त समर्थन प्राप्त होता है उतनी ही प्रतिपादित यह नीति होगी। हमें दृष्टि में भारत की अमलग्नता की विदेश नीति राष्ट्रीय माना जाती रही। इस समय हमका परिणाम करने में राष्ट्र 'मजबूत' हो जाता है। गठबंधन में सम्मिलित होने में हमारी विदेश नीति राष्ट्रीय न रहकर 'अलग्न' बन जाती है। एक समय में जब भारतीय राजनीति में विचारधाराओं का ध्रुवीकरण (polarisation) हो रहा था अमलग्नता की नीति का परिणाम करना एक अत्यंत 'स्थिति' का उत्पन्न करना होता था राष्ट्र का कमजोर बनाने के सिवा कुछ और नहीं कर सकता था।

अमलग्नता की नीति का मंथन

भारतीय विदेश नीति का मुख्य विचार अमलग्नता या गैरनिर्भरता की नीति प्रारम्भ में ही प्रथम और निष्ठा राना का पात्र रही है। इसके प्रारम्भ का कहना था कि सैनिक और आर्थिक रूप से कमजोर होने हुए भी अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में

भारत न तो स्याति प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त किया वह भी निरूप्य नाति का सफलता का प्रबल प्रमाण है। जमा कि पण्डित नर न एक बार कहा था यद्यपि यह एक आत्म प्रशंसा है किन्तु तो भी मैं यह कहूँ कि 'मार्ग' विज्ञानानि समार न भारत का सम्मान दाना म प्रमख तत्व है। हमें विपरीत आवाजों का मत था कि भारत का विज्ञानानि अविवक्षणीय अमर जौर छात्रों की है तथा अन्य देशों भारत न तो स्याति और प्रतिष्ठा अभिन का है वह वास्तविकता निम्न कुछ तथा है। प्रसिद्ध कथनित नता 'जनापाम न्त' अग्रित 19:9 में भारत का विज्ञान गति का निर्माण उदात्तता नर का एशिया का नया च्याता का कहा था। हमें विपरीत ब्रिटिश तथा अमेरिका पक्ष न भारतनाय नाति का समझना करने न का कारण-दम वाका न्या रही। अपन 5 फरवरी का एक म मंचन गार्गियन न नर का कारिया सम्प्रदा नाति का आवाजना करत हुए उह नान विवक्षता कहा था। टासिना न अपना पतक म लिखा कि भारत का नातिदान कारण था है। हमरा क अंतराष्ट्रीय विद्वान म गानिपण समझान की साक्ष नवाता भारत अरन पञ्जा पाकिस्तान क नाथ भा म पन सम्प्रदा स्थापित न। पर मेरा। एक पश्चिमा पत्रकार न मनताकर कहा था कि भारत का विज्ञान नाति रहस्य क आवरण म पगड मानन भादना है जो पन का एक विपता है। स्वयं देश न भारत का एक नर विज्ञान का विषय था। गा म जना रन का नाति का आवाजना करत हुए यह कहा जाना था कि हम कब एक मृगमराचिका का और दो र हैं जिनका अन्तिम परिणाम राष्ट्रीय न्ति म कमा अच्छा नहा पागा। उनका कना था कि चान और पाकिस्तान म मध्य का न्दारा मरक्कातान घनिया न य प्रमाणित कर दिया कि अमरगुना का नाति क वापन हम न का पक्का मित्र बना सक और न अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान क रख म सफल हा सक। उनका कना था कि विज्ञान नाति क विचारण क समय ममा आवश्यक परिस्थितिया और सम्भावनाओं का ध्यान म न रखा गया और अक सम्भावित न्या का अपना का रही। 1954 तक चान का विज्ञानानि का मुल प्रवृत्तिय स्पष्ट हा गया था फिर भी हमन निवन पर उनका प्रभुमत्ता स्थापन कर ता। यदि कुछ परिस्थितिया क नवाव क कारण हम क करना न्या ना न्मा मनय हम अपन देश क हजारों मोन नम्ब सामान का भा स्पष्ट रूप म निशानित कर ता चाहिए था। वन जिना तक हम चान म जास्या रनत हुए उनका नाति का मानन पर कि चान क नवा म जो भारतीय नू भाग लिखायन्य थव कामिता क नवा पर आधारित थे और चान का नया मरका नम नर हा गणाधन कर गगा। मारा वाता की पता कर हम कवन पञ्जात का प्रापणा मात्र म न मनुष्य न यय और चान क नगर्णों का पना करत हुए जिना चाने भा म भा का मारा नवान र। हम तर हम पूर समय तक मृगमराचिका क पाछ नोजव न जिसन न्दारा विज्ञान नाति क छात्रपन का मिद्ध कर दिया। वन आवाजना का कना कि भारत का विज्ञान नाति जगतीकर तथा का सामना करने का अस्वाहृति म अधिष्ठ कुछ नही है।

भारतीय विदेश नीति का आलोचना का एक और दृष्टिकोण यह था कि अपनी नीति का पालन करता था। यह दृष्टिकोण नीति के मनुष्य सिद्धांत का समर्थन करता था। किन्तु वह कहता था कि भारतीय कूटनीति में परिपक्वता का अभाव है कि सद्दान्तिक रूप में विदेश नीति ठीक पालन पर भी वह असफल हो जाती है। उनका विचार भारतीय विदेश नीति में व्यापक और व्यावहारिकता की कमी बनी थी। अमरगता की नीति का वह प्रश्नमा अवश्य करते थे कि वह हमारे कार्यालय के तरीके की आलोचना करते थे। उनका अनुसार भारतीय अमरगता का नीति का तत्वात्मक पालन का पालन था जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारे देश की प्रतिष्ठा का जन्म देती थी।

हमारे कार्यकर्ता ने कि उपयोग के आलोचनाएँ अत्यधिक अतिरिक्त और एकतरफा थी। प्रत्येक देश या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में कभी कभी अत्यंत विचारजनक विचारों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति का सामना एक प्रकार की स्थिति में होता था। भारतीय स्थिति में समय अत्यंत कम हो जाती है। जो किसी उद्देश्य के प्रश्न पर साधारण तर्क से विचार किया जाता है। अपना विचार या नीति पालना है। जहाँ दाना मसाला भी सीना जाता है। भारत की विदेश नीति का मूल ध्येय बन गया है। हमें तब तक नहीं जानना पड़ता कि सफल हो सके। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कुछ हमारे विचारों और विचारों के अन्तर्गत आय के अन्तर्गत हमारे भारतीय विदेश नीति निष्पादन में विचलित होगी। किन्तु अस्पष्टता और संशय का कारण हमारे नीति के अन्तर्गत हमारे देश पर आ गयी। प्रत्येक देश की विदेश नीति का मूल ध्येय अपनी सुरक्षा, समृद्धि और स्थिरता की रक्षा करना, दूसरे देशों की अभिवृद्धि करना होता है और सन्तुष्टि कुछ अन्तर्गत पर राजनीति का आश्रय लेते हुए कतिपय ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जिसमें नागरिक मूल्य भ्रम हो जाता है कि विदेश नीति अपनी जिम्मेदारी ले रही है। कुछ अवसरों पर भारतीय विदेश नीति हमारे प्रकार के भ्रम का गिरावट बनी है। फिर भी राष्ट्रीय स्थिति का ध्यान में रखकर यदि हमारे कार्य सामयिक जिम्मेदारी परिवर्तन हुआ जाता है तब तक उसी आधार पर अपने विदेश नीति का आश्रय लेनी पड़ेगी। यदि आलोचना भारत की विदेश नीति पर यह आरोप लगाते हैं कि वह अस्पष्टता और विचारों का पालन करती थी तो उन्हें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अक्टूबर 1946 में स्वयं सफट के समय भारत ने अमरगता के अन्तर्गत विदेश नीति का जन्म देता है। 1958 में अमरगता और अमरगता में अमरगता तथा अमरगता की नीति का उद्देश्य विचार किया था।

भारतीय विदेश नीति का कुछ आलोचना का यह कहना था कि यदि भारत पश्चिमोन्मुखी नीति का साथ सैनिक सन्धि में आसक्त रहता तो 1962 में चीन का आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ता। किन्तु हम प्रश्न की आलोचना करते हैं कि हमें तब तक समझ पड़े कि सैनिक सन्धि में शामिल हो जायेंगे हमारी स्वायत्तता का ही विनाश हो सकता था। यह विचार का साथ सैनिक दृष्टि से सम्बद्ध हो

समयाने जाया कि भारत के पश्चिम गतिक गुट के साथ आवश्यक ज्ञान का व्यापारिक परिणाम यह होता कि सावित्त रुम और चीन का दूगरे के अधिार निरन्तर जान की आवश्यकता मागूग करने क्योंकि तब गतिन मनुवन उाके विपरीत हो जाना । चीन और रुम की मनुवत ज्ञानित तथा गतिन शक्ति गयवा राग्य अमरिका के लिए एक मयावा स्थिति पदा कर लेती । अतः अमरिका का तित इसी मयावा रि हन होता राग । म मतभन्न विद्यमान रहे और फुट उरती रहे तथा भारत अपनी तत्स्थता की नीति ब्याय रघ । नीतिगत अमरीकी राजदूत गगनर घन वया था फीजी ग गया दकर हम भारत की पश्चिमी गुट ग शामिल कराना । जा त और ने हम भारत का तत्स्थ नीति को ब्यावा व ही समथक है । अरिका भारत की तत्स्थ नीति का स्वागत करता है ।

विश्व नीति की मपनता असतन्त्रता का जीवन का एक तरीका यह भी है कि हम यह रघ कि भारत के विनन नय मिथ बा । प्रक्षता का रघ था कि भारत के ग र मित्र ती थ । कश्मीर का क्षमता घात र साथ सामा रिता बर्मा म भारतीय सम्पति का परत रुका म प्रक्षता भारतीय का प्रश्न पश्चिमी शक्तिनयो म रभा तमी मामताय शक्ति जाय घरा म फिरकर भारत रिदि ग नीति अपन माग के मयध म रघा त नीति द्यामी दती थी और लभता था कि नय प्रश्ना के समाधा । उरता मित्रतापण सहयोग की स नी मिलन वाला है । य रघा ताता था कि भारत ग दानो घटा ग अगम रुकर तथा दानो के साथ मित्रता बढ़ाने के प्रयास म जाता के रिता म ग रघ की स्थापना का । रघ ग रघ के कारण सामन्या ती गुट भारत का छिपा रजोपति दण करता था और पश्चिम गुट हत अध्याम्यवाली कती थ । रिगी समस्या पर रगकी नीति त र रगण रिघति कभी कभी गुट राजर हो जानी थी । रघा ताता था कि भारत का समा वा भी मित्र ती है किमपर रि वर गवटपाल म भरागा कर गत । यत हो गतना था कि एक मन्तागित भारत के समथक के लिए जा जाय किन्तु एगा य रघ्य अपनी सुविधा या स्वाथ के कारण करता रिगी प्रम अथवा मित्रता के कारण न । रघ घात के विपरीत यह व । जा गवता था कि विश्व राजनीति म दता के स्वायी मित्र या भयु ती होते । केवन स्वायी स्वाथ हात है ।

अ तर्कीय राजनीति के क्षत्र म असतन्त्रता की नीति भारतीय वि श नीति की एक अरथ त मत्स्यपूर्ण दन थी । दगम कार्ग म नही रि रघ नीति का पया त मपनता मित्री थी और ये लोग भी रगक प्रक्षमक बत गव ता कभी रगके बट्टर रिरो जी थ । दतना ती रघा हमारी असतन्त्रता की नीति घडापर वाग का विश्व राजनीति का एक मुख्य तत्त्व (factor) बन गयी किमको तत्स्थतावा (the status quo) की रघा ता जाती थी । एजिया और अफिका के अधिारण नतीन रा त जो जान म ही स्वतन्त्र हुए । रघ नीति का अनुगरण कर र थ । अतः विचारका का व ना था कि बर्मा के ऊनू तथा मनुषी अरथ गणराग्य के राष्ट्रपति तामिर ने तत्स्थता एक असतन्त्रता का पाठ नथी लिखी म पढ़ा था । दगम कार्ग गलेन रगी रि भारत असतन्त्रता केा का माग रगक रघा । दगवा हम भारतीय राजनय की उत यही मपनता मान गवा है ।

नए गाय घनिष्ठ स योग कायम करना तथा विश्व शांति कायम रखने में सक्रिय योग देना था। ये तथ्य हमें कान में भी उठाने की मन्त्रपण्य थी जिनसे आठ मंथन हुए थे। दूसरी हुई परिस्थिति में भी हमारा मन्त्र तिसी तरह कम नहीं हुआ था। यद्यपि पश्चिमो एशिया और दक्षिण पश्चिम एशिया की स्थिति अत्यन्त नाजुक था जिसका प्रभाव भारत पर भी अनिवाद्य रूप में पड़ा फिर भी भारत ने इन क्षणों में स्थायी शांति का स्थापना या न समझाया था कि राजनीतिक समझौता के लिए नार्थ सक्रिय कर्म नहीं उठाया। गुट निरपेक्ष राष्ट्रा में वनस्पति सम्मेलन (1961) में प्रतिष्ठित न हो सका था। विश्व में जय कोर्स मन्त्र पड़ा है जिसके कारण शांति रखने में पड़ा जाय उग समय कबन यही स्थिति कि मंगु निरपेक्ष है हम सक्रिय। इनका प्रेरित करगी। यहाँ स्थिति ही हम बाध्य करगी कि हम शांति का रास्ता बना सकना है क्योंकि यह छिड़ जान पर उनके प्रभाव में हम बच नहीं सकते।

भारत की विदेश नीति में इस तरह परिवर्तन की स्थिति आने का एक कारण था। हमें पुरुष में ही रहना और तब का जमाना रहा और यह विश्व पर एक ध्वनि के जाल में और विचारों में अधिष्ठित प्रभावित थी। पश्चिम में वास्तविकता की जपना भी गयी। अमरगन्ता तथा उपनिवेशवाद का विरोध करना भारतीय विदेश नीति का प्रमुख मौखिक तत्व था और यह तब का विचार था कि विविध घटनाओं के सम्बन्ध में विविध स्तर पर लागू किया जाता था। भारतीय विदेश नीति की यह एक प्रवृत्ति बनी किन्तु यही और एक प्रवृत्ति न थी कि विदेश नीति के प्रति सतर्क रहना पड़ा था।

किन्तु भी विदेश नीति का सफलता अंतिम विश्लेषण में उस दशक आधिन और मनिक स्थिति पर निर्भर करता है।¹ हम तथ्य का स्वयं पहिले नज़र से स्वीकार किया था। यद्यपि आधिन और मनिक दृष्टि में कमजोर हानि हुए भी भारत ने पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रीय स्वाभिमान हासिल की अति विश्व राजनीति का निर्माण रूप में प्रभावित करने और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य तत्व बनाने के लिए आधिन और मनिक दृष्टि में शक्तिशाली हाना आवश्यक है। भारत की नीति निर्धारण एक तथ्य में अपनी अर्थ नहीं चुका सकने थे। यह तथ्य था अन्न और आर्थिक मामलों में अन्न की असमर्थता। जब तक यह असमर्थता बनी रही तब तक तिसी की अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर हम अपने उन ताताओं की बात चाहकर या अनचाह मानना ही पड़ी जा जय-तब मात्र भिन्न पात्र में थोड़ा बहुत दान और पैसे डालते रहने थे।

1. Ultimately foreign policy is the outcome of economic policy and until India has properly evolved her economic policy her foreign policy will be rather vague incoherent and will be groping. It is well for us to say that we stand for peace and freedom and yet that does not convey much to anybody except a pious hope —Nehru in Constituent Assembly (Dec 4 1947)
Quoted in Ronald Segal *The Crisis of India* p 272

असंलग्नता की नीति का अन्त

(End of Non alignment)

नवीन अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति—जब से भारत स्वतंत्र हुआ तब से नवरा विमानावृत्ति का मूल आधार गुट निरपेक्षता या असंलग्नता का सिद्धांत था। भारत पर कभी तरह के दबाव समय-समय पर पड़े ताकि वह इस नीति का पालन करे लेकिन अत्यंत मुश्किल का घंटा में भी भारत ने इस नीति का पालन नहीं किया। देश के अन्दर बंटन निम्न से यह भाग्य रहा था कि जनता काय राजनीति में भाग ले सकना पड़ता जा रहा है और इस अक्षयन का शूर करने के लिए असंलग्नता की नीति का परित्याग होना चाहिए। यह भी भाग्य रहा कि समनामयिक अन्तराष्ट्रीय असंलग्नता में असंलग्नता की नीति का औचित्य नहीं रहे गया है। असंलग्नता की निष्पत्ति वसुधैव कुटुम्बकम् का प्रचारित सिद्धान्त का गुण मिला था कि 1960 के बाद के युद्धों में विभाजन रखा मित्रों गया है और समार के प्रमुख रूप से मित्र के गुट में सम्मिलित हैं। ऐसा स्थिति में 1946-47 में निर्धारित का गया नीति का अन्तिम माना चाहिए। लेकिन इन भाग्य का अनकानक राजनयिक पालना—दाखू भारत सरकार अपने सिद्धांत पर दृढ़ रही और असंलग्नता की नीति का नहीं छोड़ा।

लेकिन 1965 के बाद से अन्तराष्ट्रीय राजनीति में जम जम पुनरा पुनर्विचार का महत्त्व घटता गया वन-वन से दलीलें प्रस्तुत परिस्थिति में असंलग्नता की नीति का कायम अन्त के आचरण पर आगे बढ़ता था। 1971 के मध्य में ही अत्यंत ही महत्त्वपूर्ण घटनाएं घरीं। चीन के साथ मानसिक सम्बंध कायम करने के लिए राष्ट्रपति निकसन का चीन-यात्रा का धारणा था। उस समय पूर्वी पाकिस्तान में बंगलादेश का स्थापना का उदर स्वतंत्र देश हुआ था। उस देश के राजा न भारत के विदेश-नीति का बहुत अधिक प्रभावित था। अन्तरगत निम्न से भारत की स्थिति चीन का समझा अन्तराष्ट्रीय स्थिति पर प्रभावित था। अतः चीन समझा के सिद्धांत से चीन की स्थिति बहुत गहन का सम्भावना हो गया। इसलिए भारत की अपनी नीति का पुनर्विचार करना था। ऐसा पांच पूर्व पाकिस्तान में गृहयुद्ध छिड़ा और स्वतंत्र बंगलादेश का स्थापना हो। भारत की महानुभूति बाना के साथ थी। लेकिन पाकिस्तान में नया न बाना देश के निवासियों पर छार अत्याचार कि और देश समझ के न्यायवादी हो। नाबो-बाह्य विस्थापित भाँवर भाँव जाय। भारत ने प्रमाण निम्न निम्न समार के अन्त में का पक्ष उदर पश्चिम पाकिस्तान में बाना देश का दबाव डालकर बंगला देश का समस्या के समाधान में भाग ले रहे। लेकिन निम्न सत्र में भारत की महत्वा नहीं मिला। अन्त पाकिस्तान ने अपना भाँव कि वह भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ रहा। पाकिस्तान की चीन तथा अमेरिका के समर्थन का आग्रहमन भी था।

भारत सोवियत संधि—एसी शान्त में एसी स्थिति पर
एक दूसरा भारत पाकिस्तान पर तब तक बांधी प्रतीत होना चगा। ३
का मित्र हीन और अनेक मध्यम शक्ति। यह अत्यंत का दूर करने तथा
गुरुता के लिए भारत ने अपनी विशेष नीति मध्यम शक्ति पर विचार करने का।
जिसे १९ जून १९७१ का सोवियत संधि के साथ भारत की एक प्रमुख शक्ति में
शान्ति और सुरक्षा संधि संपन्न हुई। भारत और सोवियत संधि की समझौते अमन्यता
की नीति का अंग बन गया। शान्ति और संधि में संधि का दफना दिया। किन्तु भारत सरकार
का यह प्रवृत्ति का अमन्यता का नीति में अत्यंत अधिक मात्रा का कि यह संधि
यह समझौते का एक भाग भी वह यह कि यह समझौता अत्यंत है कि भारत ने
गुरु निरपेक्षता की नीति का परित्याग कर दिया है। जून १९७१ का शान्ति में
एक विशेष जनसमूह की शक्ति में भाग लेने वाले प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा
गान्धी ने कहा कि आज शान्ति का यह संधि का संधि है उसका वाक्य भारत
अपना गुरु निरपेक्षता की नीति पर कायम रखा। हमने सोवियत संधि के सामने
स्पष्ट कर दिया कि भारत गुरुता की नीति में अत्यंत रचना चाहता है और हमारी
बात उमा माननी है।

किन्तु प्रधान मंत्री की यह नीति और धारणा में काफी तब नीति का।
समझौते में नीति कि भारत की गुरु निरपेक्षता की नीति का यह संधि न अंग बन दिया
है। गुरु निरपेक्षता की नीति का मतलब महाशक्तियों की धोखे संधि एक तनाव में
अपने का दूर रहना होता है। किन्तु एक महाशक्ति के साथ संधि करने भारत अंग
अपने का यह संधि तथा तनाव में दूर नीति रख सकता है। भारत के लिए यह
गुरु निरपेक्षता की अत्यंत स्वातंत्र्य का यह है। अंतराष्ट्रीय परिस्थितियों
और वातावरण के घटने में अमन्यता की नीति बन गया। दूसरी थी। भारतीय
निष्ठा मंत्रालय का अंग बनने उनकी शक्ति का यह है। १९ जून १९७१ का
प्रामाण्य का भारत सामान्यतः अंग बनने का मांग प्राप्त कर दिया और ६
जून १९७१ का अंग ही अंग बनने का संधि कर दिया। भारत सरकार का
प्रवृत्ति का यह संधि का यह संधि का स्वातंत्र्य का यह चाहिए।
आखिर गुरु निरपेक्षता का एक मात्र धर्म यह है। दान के लिए यह अंग
कि नीति में अत्यंत कर अंग है और करना चाहिए।

1. There is no doubt that in entering a
secular arrangement with one of the world's two super powers
India has abandoned non-alignment and will in the eyes of
many third countries be regarded as having aligned itself with
the Soviet bloc. *The Hindustan Times* 10 August 1971

भारत-आविर्गत मुद्रि के बाह्य अधिकांग मावजनिक बाह्य विचार तथा प्रान्त पर कद्रित आ गया । क्या यह मुद्रि भारत का गुटनिरपेक्षता का नाति स नन खाता है ? क्या स्वक द्वारा उस नाति पर अतिक्रमण तथा है ? स्वका एक कारण यह था कि गुटनिरपेक्षता के सम्बन्ध में हमारा यह धारणा आ गया था कि यह एक नाति नहीं बरन एक मिटान है । ऐसा स्थिति में भारतीय अधिकांगिनी — तिए नन स्थिति का कद्रन करना कठिन आ गया । व उस बात का मानन के निग नयाग नहीं थ कि मुद्रि स इस नाति पर किता नरुज का ज्ञातात पचा है । इसनिण न निरनर दन गा जनापत रह कि मुद्रि अस नगनता का नाति के विचारों में एक सम्बन्धन बना ह । अतिन सत्य ना यह है कि भारत-आविर्गत मुद्रि न पहर-पहन ऐसा स्थिति पचा कर ती जिसमें भारत यह नहीं के सकता कि वह महा-विश्वों के आवर्षेच न क्षात ह । वस्तुतः उस अब उस आवर्षेच में सक्रिय भाग लेना है ।

भारत और विश्व-शांति

(India and World Peace)

भारत के लिए शांति की आवश्यकता—स्वतंत्र होने के बाद भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता विश्व शांति की थी। इसका एक महत्वपूर्ण कारण था। सदियों के साम्राज्यवादी शोषण के परिणामस्वरूप भारत की आर्थिक दशा अत्यंत खराब हो चुकी थी। सम्पूर्ण देश में गरीबी भुखमरी और बीमारी का राज्य था। इस अवस्था को दूर करने के लिए कुछ समाने पर भारत को राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का कार्य करना था। 15 अगस्त 1947 को भारत केवल राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र हुआ था। आर्थिक दृष्टिकोण से स्वतंत्रता प्राप्ति का महान कार्य अब उसके सामने आया था। फिर आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता भी व्यर्थ थी। विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए भी देश को आर्थिक दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर बनाना था। यह सारा उद्देश्य आर्थिक विघटन का अंत तथा देश के आर्थिक पुनर्निर्माण का कार्य करके ही पूरा हो सकता था।

भारत के आर्थिक पुनर्निर्माण का कार्य शांति के वातावरण में ही संभव था। किसी भी विघटन के लिए विश्व में शांति का वायम रहना आवश्यक है। अतएव विश्व शांति के माग से सभी विघटनवाधियों को हटाना भारतीय विदेश नीति का एक मुख्य लक्ष्य हो गया। विश्व शांति भारत के लिए न केवल अपेक्षित आया था बल्कि एक गम्भीर आवश्यकता भी थी। के. एम. पाणिशेर ने टीका की है कि यदि समय मिले तो भारत के लिए स्वयमेव अपने ढंग से विश्व शांति बनाना भी पूरा अवसर है। भारत को इस बात की बड़ी चिंता है कि उसकी प्रगति को तथा सामान्य रूप से मानव जाति की उन्नति को सड़क में शानने घाना को युद्ध न हो।

गरीबी और विकासशील राष्ट्र पर युद्ध का बितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इसका अनुभव भारत को कई अवसरों पर हुआ। 1956 के स्वेज नहर का नजर आ युद्ध हुआ वह अफ़सोसनीय हो था लेकिन उम्मे भारत की पञ्चवर्षीय योजना पर गहरा असर डाला। 1962 के भारत-चीन और 1965 के भारत-पाकिस्तान संघर्षों ने भारतीय आर्थिक व्यवस्था को भूखण्डित किया। फिर 1967 के अरब-इजरायल युद्ध के कारण स्वेज नहर बन्द हो जाना से एक बार फिर भारतीय आर्थिक व्यवस्था पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इन सारी बातों ने स्पष्ट कर दिया कि युद्ध के परिणामों से चाहे वह युद्ध कहीं हुआ हो चाहे देश में ही स्वयं। अतएव भारत के लिए केवल यही आवश्यक नहीं था कि वह स्वयं युद्ध से बचने का

यथासम्भव प्रयास करें समझो ऐसी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के सृजन में भी योगदान देना था ताकि विश्व के किसी कोने में युद्ध की नींव नहीं आये। इन सारी बातों पर खयाल करते हुए 12 जून 1945 को जी अवाइलान नेटवर्क ने कहा था हमारी पन्नी नीति तो यह होनी चाहिए कि हम ऐसी भीषण आपत्ति (तृतीय महायुद्ध जैसी) का घटित होना रोके। हमारी नीति इसमें बचन की होनी चाहिए और तीसरी नीति ऐसी स्थिति बनाने की होनी चाहिए कि यदि युद्ध छिड़ जाय तो हम इस रोकने में समर्थ हो सकें। मैं यह चाहता हूँ कि एशिया में ऐसे देशों का क्षेत्र अधिक विस्तृत हो जाय। निम्नलिखित के कि चाह कुछ भाग जाय व युद्ध में सम्मिलित नहीं होंगे। मैं चाहता हूँ कि ये देश कुछ भी घटित होना पर गारंटी रखें रणक्षेत्र में प्रवेश न करें। अथवा प्रदक्षिणा में हाथ-बाज बद्ध कक्षत्र को सीमित करें अतः प्रयोग की रक्षा करें और दूसरा कक्षत्र का सुरक्षित बनाने का, भाषान करें।

ऐसी स्थिति में स्वतंत्रता के बाद विश्व शांति की स्थापना के लिए सन्तुष्ट रहना और इस महान कार्य में योगदान करना भारतीय विदेश नीति का एक मान लिये हो गया। अतः विश्व नीति का निर्धारण भारत ने इस तरह करना शुरू किया ताकि विश्व की शांति भंग न हो। इसलिए भारतीय विदेश नीति का कभी कभी शांति की नीति भी कहा गया है।

ग्रेट युद्ध के प्रति भारतीय दृष्टिकोण :—तृतीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद और भारतीय स्वतंत्रता के पहले मसाले दो परस्पर विरोधी गठों में विभक्त हो चुका था तथा अमेरिकी गुट एवं सोवियत गट के मध्य ग्रेट युद्ध हो चुका था। अतः गुट एक-दूसरे की शान के प्यास हो गये थे। ऐसा प्रतीत होने लगा था कि इतना बड़ा किसी नाशक युद्ध छिड़ सकता है। दोनों गट अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए हर सम्भव उपाय का अवलम्बन कर रहे थे। उनका ध्यान विशेषकर एशिया के नवजात राज्यों पर था जिनको अपने गठ में मिलाने के लिए वे तरह-तरह से दबाव डाल रहे थे। यह समस्या भारत के समक्ष भी उत्पन्न हुई। तब भी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में भारत क्या करे यह एक गम्भीर प्रश्न था। लेकिन विश्व शांति को ध्यान में रखते हुए भारत ने अपना गैर-हस्तक्षेप निश्चित किया। वह इस प्रकार था—यदि भारत किसी गट में शामिल होकर शांति-युद्ध में सम्मिलित हो जाता है तो इसका परिणाम एशिया की स्थिति का विपरीत और तृतीय विश्व युद्ध की सम्भवन की ओर मजबूत करना होगा। अतः एक भारत ने गटों में अलग रहने की नीति का अवलम्बन करने का निश्चय किया। उसका विचार था कि भारत गुटों से अलग रहकर शांति-युद्ध में भाग लेने को नामित करेगा और ऐसी स्थिति का सृजन करेगा जो शांति के लिए अनुकूल हो। गटों में पृथक् रहने की असमर्थता के भारतीय नीति मुख्य रूप से शांति की सुरक्षा रखने के उद्देश्य से अपनाया गया था। भारत के राष्ट्रीय हित में यह उचित था।

परस्पर विरोधी शक्तियाँ — मध्य सेतुबन्ध का कार्य — कलकत्ता सम्मेलन का पृथक् रहने की नीति में ही शांति सुरक्षित नहीं रह सकती है। भारत ने युद्ध के

महत्त्वपूर्ण भूमिका भी अनायी। वस्तुतः भारत की विदेश-नीति ने विश्व में परस्पर विरोधी गुटों के मध्य सेतुबन्ध का काम (Maintenance of balance between power blocs) किया है। अरुणस्यता की नीति और शांतिपूर्ण तथा मन्त्री का लक्ष्य होने के कारण भारत को इस कार्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता रहा है। सनिक ओष अपिह दृष्टि से भारत विश्व का एक बमबोरे राष्ट्र है। फिर भी वर्तमान विश्व की परिस्थितियों में दोनों गुटों की शक्ति का लगभग समुतन होने के कारण विविध अन्तराष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थता का काम करने की दृष्टि से भारत की स्थिति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रही है। कोरिया हि दक्षीन आदि की समस्याओं को सुलझाने में भारत ने शांति-दूत का काम जिस सफलता के साथ किया उसकी प्रशंसा दोनों ही गुटों द्वारा की गयी है। भारत ने समुक्त राष्ट्र संघ में और उसके बाहर से व अपनी विवेक बुद्धि के आधार पर एक स्वतन्त्र नीति का अनुसरण किया है। इसीलिए जहाँ भारत ने पान्थात्म्य राष्ट्रा की नीतियों का उचित होने पर समर्थन प्रदान किया है वहाँ अनचित्ता हान पर उनका विरोध भी किया। उसका यही दृष्टिकोण साम्यवादी राष्ट्रों के प्रति भी रहा है। जहाँ स्वेज पर क्रिनेन प्रांत और इजरायल का आक्रमण भारत की निंदा का विषय रहा है वहाँ हंगरी में सोवियत रुस के हस्तक्षेप की भी भारत ने अनचित्ता बताया है। कोरिया में आक्रमण की स्थिति पदा होने पर भारत ने उसकी निंदा की थी लेकिन साथ ही यह भी ध्यान रखी दोषी सि दक्षिण कोरिया की सहायता करनेवाली समुक्त राष्ट्र रुषीय फौजों को 38 अक्षांश रेखा के उत्तर में नहीं रुकना चाहिए। कोरिया के मामले में भारत की स्वतन्त्र नीति ने जान मपाई जैसे मन्त्रिमण्डल के सदस्यों को भी धक्का देकर मान दिया था क्योंकि इसमें भारत ने पहले उत्तर कोरिया के विरुद्ध कायवाही में समुक्त राष्ट्र अमेरिका का साथ दिया बाद में चीन को आक्रमण घोषित करने के प्रस्ताव पर अमेरिका का समर्थन नहीं किया और मई 1951 में चीन को सामरिक सामग्री भेजने पर प्रतिबन्ध लगा देनेवाले प्रस्ताव पर भारत तटस्थ रहा।

समस्त देशों के साथ मन्त्री का सम्बन्ध—विश्व में शान्ति को सुरक्षित रखने के लिए भारत इस बात की आवश्यक समझता है कि दुष्टार के सभी देशों के बीच मैत्री भाव रहे। यदि सभी देशों में मैत्री का भावना से आवद्ध रहने लगे तो युद्ध की स्थिति आने की सम्भावना नहीं रहेगी। इसी भावना से प्रेरित होकर भारत ने अपिह से अधिक देशों के साथ मित्रता की स्थापना की है। इनमें से कुछ उल्लेखनीय संधियाँ निम्नलिखित हैं 14 अगस्त 1948 को भारत स्वित्जरलैंड मैत्री संधि 4 जनवरी 1950 को भारत अफगानिस्तान शांति-संधि 31 जुलाई 1950 को भारत नेपाल मैत्री संधि 5 दिसम्बर 1950 को भारत तिब्बत मैत्री संधि 3 मार्च 1951 को भारत इटाली मैत्री-संधि 3 मार्च 1951 को भारत बर्मा मित्रता संधि, 14 दिसम्बर 1951 को भारत-तुर्की मित्रता संधि 9 जून 1952 को भारत-जापान

शान्ति-सन्धि 11 जुलाई 1952 की भारत-चीनी गणतन्त्र मित्रता सन्धि 10 नवम्बर, 1952 की भारत-राष्ट्रीय मित्रता सन्धि 15 मार्च 1953 की भारत-मल्लय मित्रता सन्धि तथा 6 अप्रैल 1955 की भारत-मिस्र मित्रता सन्धि। इस सम्बन्ध में जवाहर लाल नेहरू ने एक बार टीक हा कहा था। मरा यह विचार है कि इस विज्ञान विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जिसके साथ हमारे सम्बन्ध शत्रुतापूर्ण हों। हम ज्ञान आदि के साथ व्यापारिक सम्बन्धों के कारण कुछ देशों की धार विज्ञान रूप से व्यवस्था आकृष्ट हैं लेकिन भौतिक रूप से हम सबके मित्र हैं। अस्तुतः पाकिस्तान, नेपाली चाल, तुर्कान और दक्षिण अफ्रीका का ध्यान कर भारत का विश्व के सभी देशों के साथ अत्यन्त मित्रतापूर्ण सम्बन्ध रहा है।

सैन्य संगठनों के प्रति भारतीय दृष्टिकोण

सैन्य संगठनों की उत्पत्ति—प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब संयुक्त राष्ट्र के चांटर बना तो उसका 52वाँ धारा में प्रांतीय सैन्य-संघों (Regional military alliances) की मायता दी गयी। उसमें कहा गया कि अंतराष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा को स्थापित रखने के लिए ऐसे प्रांतीय सैन्य-संघों की स्थापना का स्वागत है जो चांटर में उल्लिखित उद्देश्य एवं सिद्धांतों से भन खाते हों।

चान्टर की यह व्यवस्था किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं प्रतीत होती। कुछ इस कारण से। एक तो यह प्रांतीय-संघ के परिणाम से धार फिर इस तरह से सन्धियों को प्रभावित करके अंतराष्ट्रीय शांति का बनाया था। सबसे धन्य था तो यह भी कि उसने संयुक्त राष्ट्रसंघ के महत्त्व का ही कम कर दिया था। उनके बाद चान्टर ने अनेक रूप से मानव-सन्धियों का आश्रित कर दिया था और अनेक ऐसी बातें सन्धियों पर धिम्मे ने दिया जा कि मूलतः संयुक्त राष्ट्रसंघ का सर्वोपरि था। विश्व शान्ति कायम रखने के लिए 1919 में ही शान्ति-सन्धुतन के सिद्धान्त को प्रतिष्ठित किया गया था लेकिन इन सैन्य-संगठनों ने उचित-सन्धुतन के उल्टे पुराने और असफल सिद्धान्त को फिर से एक नया आवरण प्रदान कर दिया।

द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद सैन्य संगठनों की स्थापना के आशयन का सूत्रात करने का ध्येय ब्रिटिश राजनीतिविद सिल्वन सेन्टिन का दिया जाता है। 1946 में अमेरिका के पुल्सन नामक नगर में इस बयानबद्ध राजनीति का एक ऐतिहासिक भाषण हुआ जिसमें उसने सोवियत आवरण (Iron curtain) को सामित करने तथा कम्युनि-म को प्रसार को रोकने के लिए हर सम्भव उपायों का अवलोकन करने का आग्रह किया। अमेरिका में शान्ति-संघ के महारथियों ने इस दृष्टिकोण का स्वीकार कर दिया। 11 जून 1948 को अमेरिका के सानटो ने ब्रिडनबन का एक प्रस्ताव चोमठ के विरुद्ध धार मता से स्वीकार कर दिया जिसमें कहा गया था कि संयुक्त राष्ट्र निम्नतर एवं प्रभावपूर्ण आभिनयता एवं प्राथमिक सहयोग के आधार पर व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक आभारों के लिए प्राथमिक और सार्वजनिक सन्धियों का क्रमिक रूप से विकसित करने का प्रयास करे। फलस्वरूप जिसने सभी में इस प्रकार के सन्धियों और समन्वय का शब्द धा गयी है। सर्वप्रथम 4 अप्रैल 1949 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा और

पश्चिमी यूरोप के दस राज्यों (बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, नॉर्मनवेय, हांनैड, पोलैंड, ग्रैटब्रिटेन और नार्वे) ने एक दोसरे वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर करके उत्तर एटलांटिक संधि संगठन (North Atlantic Treaty Organisation NATO) का जन्म दिया। (फरवरी 1952 में यूनान और तुर्की और मई 1955 में पश्चिमी जर्मनी भी इस संगठन में शामिल हो गई) इस संगठन का उद्देश्य पश्चिम यूरोप में सोवियत संधि के तत्कालीन विस्तार को रोकना है और इस क्रम में सार्वजनिक-कारवाई करने की भी व्यवस्था है। 1 सितम्बर 1951 को आस्ट्रिया, यजोलैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका को मिलाकर एक दूसरी सुरक्षा संधि कायम हुई जिसको आज़स पक्ट (Auzus Pact) कहते हैं। नाटो का विरोध में पूर्वी यूरोप के कम्युनिस्ट देशों को मिलाकर सोवियत संधि ने जो संगठन कायम किया उसको वारसा पक्ट (Warsaw Pact) या पूर्वी यूरोपीय संधि संगठन कहते हैं। 1953 में चीन ने कम्युनिस्ट चीन के विपक्ष दक्षिण पूर्व एशिया के लिए नाटो जैसा एक संगठन का प्रस्ताव रखा। हिंद-चीन को नष्ट के अन्तर्गत 1954 के जेनेवा सम्मेलन के उपरान्त संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस क्षेत्र के लिए भी एक संगठन का निर्माण कर डाला जिसको मनीला पक्ट या दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन (South East Asia Treaty Organisation EATO) कहा गया। इस संगठन में आस्ट्रिया, फ्रांस, ग्रीस, यजोलैंड, पाकिस्तान, फिलिपाइन, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हुए। नतीजतन अमेरिका और ग्रीस की प्रेरणा और निरंतर संधि पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को मिलाकर 1955 में बगदाद संधि की स्थापना की गयी। 1958 में बगदाद संधि के अन्तर्गत सन्तक शक्ति के कारण इस संधि की अवधि समाप्त हो गयी। अतएव बाद में उसकी जगह पर 1959 में सेंट्रल संधि संगठन (Central Treaty Organisation CENTO) की स्थापना हुई।

विश्व राजनीति पर संधि संगठनों का प्रभाव—संसार के प्रकार-प्रकार के संगठनों का जन्म हो रहा है। आश्चर्य तो यह है कि सारा संसार ही संधि संगठनों के नाम पर चला रहा है। इनके अस्तित्व को स्थापित करने के लिए हमारा चार्टर की 51वीं और 52वीं धारा का हवाला दिया जाता है। लेकिन वास्तव में यह चार्टर के सिद्धान्तों के विपरीत है और असंशुद्धि सम्मेलन के प्राधान्य और व्यर्थ सिद्धान्त का इन एक नया जीवन मिला है। चार्टर ने सांख्यिकीय सुरक्षा का ऊपर दायित्व सुरक्षा परिषद् पर छोड़ा था और सुरक्षा परिषद् कायम है। फिर उ के ऊपर दर्जनों सुरक्षा परिषद् का निर्माण करने की क्या आवश्यकता है? इन संगठनों का अस्तित्व संयुक्त राष्ट्रसंघ की शक्ति को छीन कर रहा है। ये शक्ति का सौदा करने वाले नहीं बरन संघ की निमंत्रण देनेवाले होते हैं। इस समय संयुक्त राष्ट्रसंघ के विराम की समस्या सम्भावनाओं को नष्ट कर दिया है।

इससे अनिश्चित सन्तक मुद्दों की अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान नहीं है। उनकी उपस्थिति ही संघ के दूषित वातावरण को तयार करती और समस्याओं को

चुनौती रहती है। एक गुट के दूसरे गुट से सगठनों का बल सैन पर तब गुप्त कगार का निति समझता है। प्रत्येक राष्ट्र का अपने गुट का नमि पर विश्वास बना रहता पता है जो उस राष्ट्र का स्वतंत्रता के लिए बड़ा हा खतरनाक साबित हो सकता है। किन्तु इससे बड़ा खतरा तो यह है कि इसके कारण अंतरराष्ट्रीय तनाव हमेशा बना रहता है और शांत-युद्ध में तब तक समा नहीं हो सकता जब तक इन सगठनों का अस्तित्व बना रहे।

भारतीय दृष्टिकोण—उत्तर में युद्ध का सम्भावनाओं का कम करना और शान्ति का वातावरण बनाये रखना भारतीय विश्व निति का एक मुख्य उद्देश्य था। इस हानि में यह अवस्थितिमावा था कि भारत इन सगठनों का विरोध करे। भारत के विरोध में दो मूल बातें थीं—प्रथम इसके कारण विश्व में तनाव कम होने का स्थान पर बढ़ता है और विशाल क्षेत्र का भा खतरा बढ़ जाता है। अवाहरलाल नेहरू ने ठीक ही कहा था कि इसके कारण सुरक्षा का भावना में कोई बढ़ि नहीं होती बल्कि शीत-युद्ध और मध्य में बढ़ि होता है। द्वितीयतः सिजाटो और सेंटो जैसे सगठन एगिप्ताइयन का ऐसे क्षेत्रों में जकड़ रहे थे कि एगिप्ताइयन मामलों में पश्चिमी हस्तक्षेप की सम्भावना बढ़ गया थी।

नाटो का विरोध—यहाँ तक नाटो का सम्भव है भारत ने इस पर अधिक आपत्ति इसलिए नहीं की कि यह एक युद्ध मूलाधार मामला था और इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्रसंघ के उद्देश्यों से मेल खाता था। किन्तु बात में जब इसके क्षेत्र में अमरीकन विस्तार क्षेत्र तथा तब भारतीय नेताओं के मन में यह चका उठी कि यह भा अविश्वसनीय की रक्षा के लिए एक सगठन हो गया। गांधी के प्रश्न पर नाटो गणों ने खुलझाम तर्काल का समर्थन किया। भारत का गुला उस समय बार बढ़ गया जब अंतरराष्ट्रीय न्यायिक प्रस्ताव रखा कि कोई ऐसा तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए जिसमें कि नाटो का उद्देश्य संधि और सिजाटो संधि पर एक साथ जुड़ जाय।

सिजाटो का विरोध—भारत ने सिजाटो का सबसे दृढ़ विरोध किया। इसमें बाल सम्भव है जिसमें जवने तीन गुट—पश्चिमी पाकिस्तान और फिलिपाइन—एगिप्ताइ हैं। ये पाँच महा-एगिप्ताइ राष्ट्र हैं। इसमें से बाहर निया और यूजानेड का एडम पक्ष के अतिरिक्त अमरीका से सम्बंध है। इस सिजाटो में इसलिए शामिल था कि यह उसके द्वारा दिये जाने में अपना प्रत्येक कार्य में सहता चाहता था। किन्तु वह हिन्दु मुस्लिम मनाया सिजापुर और हाकाग में कतिथ था। संयुक्त राष्ट्र अमरीका बलत साम्यवाद को रोकने के लिए विवर्तित था। मध्य में सम्मिलित हानवाले देशों में एगिप्ताइयनों का बल पता प्रसिद्ध प्रतिनिधित्व था।

भारत ने इस सगठन का प्रश्न विरोध किया। अवाहरलाल नेहरू एगिप्ताइ देशों की प्रभुता का अल्पन करने के लिए पश्चिमी देशों का एक पापपूर्ण प्रयास मानता था। उनका यह कहना था कि यह अस्तित्व प्रश्न बढ़ति का नवान सम्करण है जिसका उद्देश्य उसका उद्देश्य के विरुद्ध किसी क्षेत्र विश्व को रक्षा करना है, यह

एक ऐसी शाल है जो किसी न किसी रूप में बड़ी शक्तियों का प्रभावक्षेत्र की पुरानी विचारधारा के निकट है। जो कि कृष्णमनन के मगानसार यह सुरक्षा का शीघ्र माग्न नही है बरन ऐसे विदेशी लोग का संगठन है जिन्हें इस क्षेत्र में अपने हितों की सुरक्षा करनी है। जवाहरलाल ने इसे एक प्रकार का मुनरो सिद्धान्त (Munroe Doctrine) माना जिसको दक्षिण-पूर्वी देशों पर जबरन स्वीकार किया गया है। भारतीय दृष्टि में यह पुराने अनिवार्यता का आधुनिक संस्करण है।

सिआटा संधि के प्रति भारत के विरोधी रुख का एक कारण यह भी है कि मार्च 1956 में कराँची में आयोजित सिआटा परिषद की बैठक में पाकिस्तान की प्रेरणा से परिषद् ने अपनी विज्ञप्ति में कश्मीर समस्या का उल्लेख करते हुए उसके शीघ्र निवटारे की आकांक्षा प्रकट की थी। यह भारत और उसकी कश्मीर-नीति की निन्दा थी। भारत ने इस बात की कड़ी आलोचना की। इस सम्बंध में आपत्तिजनक बात यह थी कि सिआटा ने एक गर सदस्य देश के भगड़े का बारे में उल्लेख किया है और वह भी ऐसे समय में जब दूसरे पक्ष की समस्या पर अपना दृष्टि बिंदु रखने का मौका नहीं दिया गया था।

संघों का विरोध—सिआटा की तरह भारत ने संघों की भी विरोध किया। इस विरोध के भी कई कारण थे। सर्वप्रथम इससे अरब राष्ट्रों की एकता पर आघात पहुँचता था। दूसरे यह पश्चिम एशिया के मध्यकालीन सामंतवादी राष्ट्रों के संगठनों का मजबूत बना रहा था लेकिन भारतीय दृष्टिकोण से इस संगठन का सबसे बड़ा विरोध इसलिए हुआ कि इसने पश्चिम एशिया के लिए अवांछनीय स्थिति पैदा कर दी जिसका भारत पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता था। संघों या बग़दाद संधि में शामिल होनेवाले राष्ट्रों का उद्देश्य एक नहीं था। इसका तीन सदस्य ब्रिटेन तुर्की और सयुक्त राज्य अमेरिका इसे साक्ष्यित आक्रमण के विरुद्ध एक आधार मानते थे। इसके दो अन्य सदस्य इराक और पाकिस्तान इजरायल और भारत के विरुद्ध अपनी मनाशमना की पूर्ति का साधन मानते थे। भारतीय नेताओं का कहना था कि पाकिस्तान संघों में साक्ष्यित संधि का विरोध करने के लिए नहीं शामिल हुआ। वह कश्मीर के प्रश्न पर सबन आधार पर भारत का साथ बातचीत करने का उद्देश्य से ही इसमें शामिल हुआ है। भारतीय दृष्टिकोण से पाकिस्तान का सिआटा या संघों में शामिल होना भारत के लिए उतनी ही विज्ञा का विषय था जितना कि स्वायत्तता का बरखा संधि में सम्मिलित होना अमेरिका के लिए हो सकता था।

भारतीय विरोध के अन्य कारण—संघ संगठनों को भारतीय नेता एशिया की पूर्ण मुक्ति की दिशा में एक मुख्य बाधा मानते रहे। इससे एशियाई देशों को संगठित करने का प्रयास का धक्का लगा। उनका कहना था कि संघ संगठना का सदस्य होने के नाते सहायता प्राप्त करनेवाले राष्ट्रों में हीन भावना और सहायता देने वाले राष्ट्रों में अहंमयता तथा अधिकार की भावना पैदा होती है। व्यावहारिक दृष्टिकोण से भारतीयों का विश्वास था कि अतकाल राष्ट्रों और उनके संप्रदाय विध्वंसियों का

बीच सैनिक गठबन्धन का बाढ़ अप नहीं है। किसी भी हानत में यह समानता क सिद्धांत पर आधारित नहीं हो सकता।¹ लेकिन भारत द्वारा सत्य सत्ताओं का विरोध का सर्वांगीण कारण यह था कि वह उन्हें विश्व शान्ति के लिए खतरनाक मानता था। शान्ति की आवश्यकता न भारत का इन सत्ताओं का विरोध करने के लिए बाध्य किया।

निरस्त्रीकरण के प्रश्न पर भारतीय दृष्टिकोण

राष्ट्रा के बीच हथियारदानी का होना विश्व शांति के लिए बड़ा खतरनाक होता है। दो विश्व युद्धों का यह मुख्य कारण था। अतएव द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हथियारदानी (Armament race) का रोकना या सीमित करने का निश्चय किया गया। द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद यह समस्या पहल की अपेक्षा अधिक गम्भीर बन गयी थी। इस युद्ध के पूर्व हथियारदानी का समस्या परम्परागत सस्त्रास्त्रों (Conventional weapons) तक ही सीमित थी लेकिन युद्ध के बाद राष्ट्रों के सस्त्रागार में एक नये भयानक अस्त्र का प्रादुर्भाव हुआ। परमाणु बम का आविष्कार न समस्या का अत्यन्त जटिल बना दिया। अतएव निरस्त्रीकरण की समस्या पर तत्काल ध्यान देना आवश्यक था। युद्ध के बाद यह काम समुचित राष्ट्रसंघ के जिम्मे सौंपा गया और निरस्त्रीकरण के लिए बहुमुखी प्रयास किए जाने लगे।

विश्व शान्ति की दृष्टि से भारत निरस्त्रीकरण को परम आवश्यक मानता था। अतएव निरस्त्रीकरण के लिए किए जानेवाले प्रयासों में उसने अपना सक्रिय योगदान देने का निश्चय किया। संयुक्त राष्ट्रसंघ निरस्त्रीकरण के प्रश्न पर भारत ने समय समय पर महत्वपूर्ण सुझाव रखे। 1958 की साधारण सभा के तत्काल अधिवेशन में भारत ने दो प्रस्तावों पर वोट दिया (1) समझौता हान की अवधि तक परमाणुबम आधुनिकों के परीक्षण तुरत बन्द किये जाय और (2) आकस्मिक आक्रमणों को बन्द करने की सम्भावना के प्रश्न पर विचार किया जाय। भारत के निरस्त्रीकरण के सम्बन्ध में समझौता हान तक परमाणुबम विस्फोट बन्द रखने का सुझाव साधारण सभा द्वारा भारी बहुमत से स्वीकार किया गया और अमेरिका, सोवियत संघ तथा ब्रिटन द्वारा काफी समय तक इसका पालन आ किया गया। 1961 में अन्तर्राष्ट्रियों का एक

1 इस बात का स्पष्ट करत हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा। मान सचित्र कि किसी एक देश का किसी दूसरे देश के साथ सैनिक गठबन्धन है तो वह उस सीमा तक आदर होता है कि यदि उससे भी हो तो उसे तथाकथित सामान्य हितों के कारण बरिष्ठ भागीदार की नीति का अनुसरण करना पड़ता है। मन्वन् से न केवल भारतीय स्वतन्त्रता नियन्त्रित हो जायगी वरन् ऐसा परिस्थितियाँ भी उत्पन्न हो सकती हैं जिनमें भारतीय हितों की रक्षा की जान नयेगी। भारतीयों का यह विचार है कि किसी गुट में सम्मिलित होने का यह अर्थ है कि किसी गुट की नीति पर चलना न कि किसी मुक्त या स्वतन्त्र देश की नीति पर। भारतीयों के अनुसार मन्वन् को जिन में कमजोर राष्ट्र का कहना पड़ता कि मरना भिन्न हो सब कुछ है चाह वही हो या गलत।

निरस्त्रीकरण आयोग (Disarmament Commission) की स्थापना हुई। भारत को भी इसका एक सचिव बनाया गया। जनेवा में होनेवाले इस आयोग के सम्मेलनों में आज भी भारत प्रमुख रूप से भाग ले रहा है।

आंशिक परमाणुबिखेरी परीक्षण प्रतिबन्ध संधि और भारत—1963 में परमाणुबिखेरी निरस्त्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण घटना घटी जब 25 जुलाई को ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने इस सम्बंध पर एक समझौता कर लिया। आंशिक परमाणुबिखेरी परीक्षण प्रतिबन्ध संधि (Partial Nuclear Test Ban Treaty) के द्वारा बाह्य आकाश वायुमण्डल तथा जल के भीतर अब परमाणुबिखेरी परीक्षण बंद करने का निर्देश दिया गया। भू-गर्भ परीक्षण पर रोक लगाने के दृष्टि में समझौता नहीं हो सका। यद्यपि भारत स्वयं एक परमाणुबिखेरी शक्ति नहीं था लेकिन नाटिकी दृष्टिकोण से उसने इस संधि का स्वागत किया तथा इसका प्रति अंगार उद्घाटन का प्रार्थन करते हुए इस पर हस्ताक्षर कर दिया। चीन और फ्रांस ने इस संधि पर हस्ताक्षर करार छेदना कर दिया तो भारतीय नेताओं ने उनकी बड़ी आलोचना की।

1968 का परमाणु शक्ति निरोध संधि और भारत—शुल्क में केवल अमेरिका को ही परमाणुबिखेरी आधे पर ध्वजधार था। बा में ब्रिटेन और सोवियत संघ ने भी इन आधे को समार कर दिया। फिर फ्रांस की चारो आधे और 1964 में चीन ने भी अपने प्रथम अणवम का विस्फोट किया। इस प्रकार 1964 के अंत होते होते परमाणुबिखेरी शक्ति के सार्वभौमिकी रुढ़ि हो गयी। अतएव परमाणुबिखेरी आधे का प्रसार पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए साधारण सभा में विचार हुआ और जब संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ में इस बात पर समझौता हो गया तो एक परमाणुबिखेरी आधे प्रसार प्रतिबन्ध संधि (Nuclear Non-Proliferation Treaty) का एक मसविदा समार हुआ। 1968 ई. में कई देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए।

इसमें कोई संदेह नहीं कि निरस्त्रीकरण की दिशा में यह परमाणुबिखेरी आधे प्रसार प्रतिबन्ध संधि के दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्वपूर्ण था। अगस्त 1963 के परमाणुबिखेरी प्रतिबन्ध विषयक संधि के बाद निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में यह एक दूसरा ऐतिहासिक घटना थी जिसके पक्षस्थान निरस्त्रीकरण के अर्थ में बहुतों का समर्थन की सम्भावना बढ़ गयी थी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दृष्टिकोण से भी इन संधि का महत्व कम नहीं था। यह संधि इसलिए महत्व हो सकी कि इसका लिए साक्ष्य संयुक्त संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों ने मिल जुमकर योगदान दिया। यह बात से सम्यक् की दृष्टि होती थी कि यदि दो महाशक्तियों में मिल जुमकर काम कर तो विश्व की सारी कठिन समस्याएँ सुलझायी जा सकती हैं। यद्युक्त चीन ही देशों का यह मनी भीति समझा जाना था कि परमाणु शक्ति सम्पन्न देशों की रुढ़ि जिनकी अधिक होती जायगी परमाणु अस्त्रों द्वारा समार की बिना के बाजार तक पहुँचाने

की संभावना उसनी ही बढ़ती जायगी। इस स्थिति में परमाणु अस्त्रों का प्रसार की रोकना आवश्यक माना जाना लगा। 1945 में अमरिका का महान परमाणु शक्ति से अपने बचाव का बचन एक रास्ता सोवियत संघ को दिखाया गया था। वह रास्ता था स्वयं परमाणु शक्ति-सम्पन्न हो जाना का। अब स्थिति यह थी कि वह अमरिका का साथ बंदम से बंदम मिलाकर तुनिया के दूसरे परमाणु शक्ति-सम्पन्न अथवा परमाणु शक्ति विहीन देशों को घेर घेर कर परमाणु-शक्ति संवधा एक संधि पर दस्तखत कर देने की बात कर रहा था। इसका कारण था कि अब स्थिति बिल्कुल चुकी थी। परमाणु अस्त्रों का आगार केवल अमरिका और सोवियत संघ के पास नही रह गया था। दूसरे देश भी इस शक्ति से घनी हो उठे थे। यहाँ बजह थी कि सोवियत संघ और अमरिका दोनों परमाणु अस्त्रों का उत्पादन और प्रसार पर प्रतिबंध लगाने का प्रयत्न समायक हो गये।

फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि वह संधि श्रुतिहित था। इस संधि में तो एक ओर यह प्रतिबंध लगाया गया कि जो राष्ट्र अबतक परमाणु बम नहीं बना पाये थे वे भविष्य में भी बमों नहीं बनायेंगे और दूसरी ओर अणु आयुध के आश्रमण से उन्हें बचाने का निष्पत्ती आश्वासन दिया गया वह यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से आन्तर्गत देशों को अणु-आयुध से सहायता की जायगा और इसका नियंत्रण सुरक्षा-परिषद् करेगी। संयुक्त राष्ट्रसंघ ने आश्रमण शक्ति की जायदाद नही बना है जिससे यह भ्रम बना रहगा कि सुरक्षा परिषद् जिस हालत में किसी आश्रमणकारी समझगी। दूसरी बात यह थी कि यदि सुरक्षा परिषद् में किसी स्थायी सदस्य ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर किसी आन्तर्गत देश की सुरक्षा के आश्वासन से वंचित कर दिया तो फिर आश्वासन का क्या महत्त्व रह जायगा? इस प्रकार संधि में और भी कई बातें हैं जो श्रुतिपूर्ण थीं।

संधि पर सबसे जागरूक आपत्ति पश्चिम जर्मनी, इटली और भारत की थी। पश्चिम जर्मनी और इटली यह महसूस करते थे कि परमाणु-अस्त्र-सम्पन्न सोवियत संघ फ्रांस और ब्रिटेन के सामने वे यूरोप में नग्न होकर रह जायेंगे। भारत का परमाणु अस्त्र-सम्पन्न चीन से जबरदस्त खतरा था और संधि उस खतरा को दूर नहीं कर सकती थी।

भारत का दृष्टिकोण—1962 के अपने बड़े अनुभव के बाद भारत चीन से कुछ अतिरिक्त सहकता धरतत हुए अपने का हम स्थिति में नहीं पा रहा था कि वह इस संधि पर आंख मूंदकर हस्ताक्षर कर दे क्योंकि उसी दौरान चीन ने अधिक परमाणु शक्ति सम्पन्न बन चुका था और कोई तात्पर्य नहीं कि अपने कुछ वर्षों के भीतर उसका पास अमरिका और सोवियत संघ की सम्मिलित परमाणु शक्ति का मुकाबला करना जायक शक्ति हो जाय। अतएव जब जन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में समन्वय का प्रस्ताव रखा गया तो भारत ने बहुत जोरदार ढंग में कहा कि जो भी प्रस्ताव पास किया जाय उनके अंदर निश्चित रूप से निम्न बातें का व्यवस्था होनी चाहिए

(1) जो राष्ट्र परमाणु अस्त्रों से सम्पन्न हैं वे उसके निर्माण का नहीं बकाव (2) जिन राष्ट्रों के पास परमाणु अस्त्र नहीं है या जिनमें क्षमता नहीं है वे हैं किसी भी तरह का भय परमाणु-सम्पन्न देशों से नहीं होना चाहे और (3) परमाणु शक्ति से सम्पन्न बड़ी शक्तियों को यह घोषणा करनी चाहिए कि वे इस तरह का अस्त्रों को एकत्र न करके उसे बम करेंगे। अब कि इन प्रस्तावों को सोवियत संघ और अमेरिकी प्रतिनिधियों ने सम्मिलित रूप से प्रस्तुत किया था इसलिए दोनों का भारत का खयाल बड़ा बुरा लगा और इसके लिए उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की लेकिन भारत अपने निश्चय पर डटा रहा। जेनेवा सम्मेलन में भी उसने ऐसा ही तब रखा था और अमेरिका तथा सोवियत संघ दोनों से अलग अलग गारंटी चाही थी कि यदि चीन भारत पर परमाणु आक्रमण करे तो वे देश उनकी रक्षा करने को प्रस्तुत हो जायेंगे। कहा गया कि संधिपत्र पर दस्तखत करने के लिए भारत की यह एक अनिवार्य शर्त है। बाद में जेनेवा से लौटने पर भारतीय विदेश मंत्री ने और शर्तें जोड़ दीं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए भारतीय विदेश मंत्री एन. सी. छागला ने कहा कि यदि सोवियत संघ और अमेरिका भारत पर चीन के आक्रमण का विरुद्ध गारंटी दे भी देंगे तो भी भारत संधि-पत्र पर दस्तखत तब तक नहीं करेगा जब तक परमाणु ऊर्जा के गान्तिपूर्ण उपयोगों के बारे में कोई निष्पत्ति नहीं होगी और परमाणु निरस्त्रीकरण के मसले पर कोई फैसला नहीं हो जायगा।

भारत को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने की मजबूरी मूलतः चीन की परमाणुशक्ति मोर्चा के कारण हुई। चीन की परमाणुशक्ति गति का प्रसार और विश्वास से भयभीत होकर वह परमाणु छतरी (Nuclear umbrella) चाहता था। इसलिए जब उभय बल संधि का मसला 1 जुन 1968 में साधारण सभा में पेश हुआ तो भारत ने इससे सम्बन्धित मतदान में भाग नहीं लिया। उसने इस संधि का विरोध इसके प्रतिपक्ष होने के कारण किया लेकिन निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में भारत की बगली हुई नीति के मूल में एक दूसरी बात भी थी जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। चीन की परमाणुशक्ति शक्ति के रूप में देखकर भारत का भयभीत होना स्वाभाविक था।

अंतरिक्ष में चीन का प्रवेश - 24 अप्रैल 1970 को चीन ने अपना प्रथम भू उपग्रह अन्तरिक्ष में छोड़ा। इस घटना ने निरस्त्रीकरण पर भारतीय दृष्टिकोण को निर्णायक रूप से प्रभावित किया। चीन द्वारा उपग्रह छोड़े जाने से पतल प्रसारण तथा परमाणु विकास में एक बड़ी और जुड़ गयी और यह चीन की एक महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धि बतायी गयी। अंतरिक्ष में वह मरकर चीन ने बहुत उन चार देशों (अमेरिका सोवियत संघ फ्रांस और जापान) की पवित्र में पहुँच गया जो कि उसके पूरे भू उपग्रह छोड़ चुके थे यदि उसने विश्व की शक्ति सततता को भी प्रभावित किया। चीन ने इस राष्ट्र की मजबूती से भू उपग्रह छोड़ा था जो बाकी शक्तियों को था। चीन की इस शक्तता से भारत का सम्बन्धित होना स्वाभाविक था। निरस्त्रीकरण का सम्बन्ध में अपना दृष्टिकोण निर्धारित करते समय भारत के लिए इन सभी तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक था।

भारत का परमाण्विक परीक्षण—18 मई 1974 को पश्चिमी राजस्थान में एक पूर्व नियंत्रित स्थान पर परमाणु ऊर्जा आयोग के वैज्ञानिकों का दख रथ में पहला नाभिकीय विस्फोट करके भारत विश्व के उन दस गिन राष्ट्रों की पंक्ति में शामिल हो गया जिन्हें इस अत्याधुनिक और महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत के क्षेत्र में विकास और अनुसंधान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। भूमि के अन्दर एक छोटे मात्रा में किया गया यह पूर्व नियंत्रित विस्फोट अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना थी क्योंकि किसी भी नाभिकीय देश ने अभी तक पहला परमाणु विस्फोट भूमि के अन्दर नहीं किया था। अमेरिका सोवियत संघ ब्रिटेन फ्रांस और चीन सभी ने पहले विस्फोट पृथ्वी के ऊपर वायु में किए। भूगर्भ विस्फोट करने में इन देशों को काफी समय लगा। इसलिए तकनीकी दृष्टि से अब भारत का एक बड़ा उत्साह मानी जाया। वायु या समुद्र में पहला विस्फोट करने की सुविधा भारत की नहीं थी क्योंकि 1964 में भारत ने परमाणु परीक्षण प्रतिवन्द्य समझौते को स्वीकार कर लिया था।

छठे परमाणु शक्ति सम्पन्न देश के रूप में भारत के राष्ट्रभावा का विश्वासी प्रतिनिधता होना स्वाभाविक था। भारत के परमाणु विस्फोट पर सबसे तात्की प्रतिक्रिया अमेरिकी हलका में हुई। अमेरिका ने न केवल अपना अप्रसन्नता व्यक्त की बल्कि यह भी कहा कि भारत के परमाणु विस्फोट से विश्व में स्थायित्व को घटका पहुँचाया गया कि विश्व के शक्ति-संतुलन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस विस्फोट और बाद के विस्फोटों के फलस्वरूप भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर सकता है। सम्भवतः यह स्थिति समुक्त राज्य अमेरिका को पसन्द नहीं है। अब अमेरिकी हलकों में भारतीय परमाण्विक विस्फोट का अत्यन्त सज्जनक बताया गया। यूनाइटेड नेशन्स पर टिप्पणी करते हुए एडिडा था— एक बार तो भारत खाद्य और जनसंख्या जैसी विकट समस्या का कोई समाधान नहीं ढूँढ सकता है और दूसरी बार परमाणु परीक्षण में लगा है। चाहें जो भाँहा भारत के करोड़ों नागरिकों की आर्थिक समस्याओं को एक तरफ रखकर भारत ने अपने माधनों का उपयोग परमाणु शक्ति-सम्पन्न होने में किया है जो उसकी बड़ी शक्ति बनने की आकांक्षा का प्रतीक है। परमाणु शक्ति-सम्पन्न देशों में छठे नम्बर पर आने वाला भारत अपनी छह वर्ष तक अपनी खाद्य समस्या तथा अन्य आर्थिक समस्याओं पर बाध पाने के लिए दूसरे देशों से सहायता का इच्छुक था लेकिन आज भारत के वैज्ञानिक परमाणु परीक्षण के लिए अपनी प्रतिभा का उपयोग कर रहे हैं और खाद्य तथा जनसंख्या की समस्या की ओर से आँखें बंद कर दिया है। अभाव की संकटपूर्ण स्थिति में भारत का परमाणु परीक्षण के लिए जनन वैज्ञानिक माधनों का उपयोग किसी भी हानि में सराहनीय नहीं कहा जा सकता।

अमेरिका की चिन्ता का एक और भा कारण है कि जब तक कुछ मित्र देश उस पर यह दबाव डाल सकते हैं कि वह उन्हें भी परमाणु अस्त्र के लिए सहायता दे।

पाकिस्तान के प्रधान मंत्री बुट्टो ने परमाणु बम बनाने के लिए जो उत्सुकता दिखायी है और अमेरिका तथा संयुक्त राष्ट्र सभ से हवाई छत्रों प्राप्त करने का जो संकेत दिया है उसे देखते हुए यदि पाकिस्तान को परमाणु विस्फोट करने के लिए अमेरिका से सहायता मिले तो वह कोई अप्रत्याशित घटना नहीं होगी। इस तरह ऐसा प्रतीत होता है भारत के सफल परमाणुबिक विस्फोट से एक नया सिनसिवा शुरू हो गया है जो निरस्त्रोकरण आन्दोलन में लिए बना घातक सिद्ध हो सकता है।

अमेरिका में अनावाजित अथवा देशों ने भारत से परमाणु विस्फोट का मुखर विरोध किया वे थे—जनाब जापान चीन और पाकिस्तान। भारत के इस आश्वासन का उसने परमाणु शक्ति के शांतिमय प्रयोग के लिए यह परीक्षण किया है किसी ने विश्वास नहीं किया। इस कथन पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता था क्योंकि परीक्षण के शारिरिक महत्त्व की अपेक्षा किसी भी हानत में नुक़ा की जा सकती थी। इसकी क्या गारंटी है कि सैनिक कार्य के लिए परमाणु शक्ति का उपयोग नहीं होगा। परमाणु परीक्षण परमाणु अस्त्र बनाने की गंगा में ही एक बंदम होता है। भारतीय नेता भने ही शांतिपूर्ण उपयोगों के लिए प्रतिबद्ध हो मगर क्योंकि परमाणु बम बनाने का रास्ता ज्ञात आता है इसलिए भारत का परमाणुबिक परीक्षण अथवा देशों को भी ऐसा ही करने के लिए उत्तजित कर सकता है।

पञ्चशील

पञ्चशील का उद्भव—पञ्चशील के पाँच सिद्धान्तों का प्रतिपादन भी भारत की शांतिप्रियता का स्रोत है। 1954 से कुछ वर्षों तक भारत की विदेश नीति को पञ्चशील के सिद्धान्तों ने एक नयी दिशा प्रदान की थी। इस काल में यह भारतीय विदेश नीति का एक मुख्य आधार स्तम्भ रहा।

पञ्चशील को नया सार नहीं है। "संशान्ति" का प्रयोग पहले-पहल महात्मा बुद्ध ने किया था। यह बौद्ध धर्म का एक पारिभाषिक शब्द था। बौद्ध धर्म स्वीकार करके जो व्यक्ति भिक्षु बनता था उसको पाँच व्रतों को धारण करना पड़ता था जिन पञ्चशील कहा जाता था। इसके अंतर्गत निम्नलिखित पाँच सिद्धान्त आते थे—अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, सत्य भाषण और मद्यपान निषेध। यह बौद्ध धर्म के आचरण के पाँच सिद्धान्त थे। आधुनिक युग में भारतीय विदेश नीति के सम्बंध में इसका प्रयोग दूसरे अर्थ में किया गया। जहाँ बौद्ध पञ्चशील धार्मिक आचरण के नियमों का सिद्धान्त था वहीं भारतीय पञ्चशील अन्तराष्ट्रीय सम्बंधों में समुदाय युक्त राज्यों के आचरण से सम्बंधित नियमों की श्रृंखला बनी। भारत के पञ्चशील में जिन पाँच सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया वह इस प्रकार हैं।

(1) सभी राष्ट्र एक दूसरे की प्रादेशिक अखण्डता और संप्रभुता का सम्मान करें।

(2) कोई राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण नहीं करे और दूसरा भी राष्ट्रीय सीमाओं का अतिक्रमण न करे। किसी राज्य की सीमा को कोई दूसरा राज्य नहीं करे।

की भावना (3) सभी प्रजातियों तथा छोटे बड़े राष्ट्रों की समानता (4) दूसरे देशों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना (5) समुक्त राष्ट्रमण्डल के चाटर के अनुसार प्रत्येक देश का आत्मरक्षा करने का अधिकार (6) किन्हीं महाशक्तियों द्वारा विघटन उद्देश्य को पूरा करने के प्रयोजन से बनायी गयी व्यवस्थाओं से अलग रहना तथा दूसरे देशों पर दबाव डालने से बचना (7) आक्रमण व कार्यों को न करना तथा हमले की धमकियाँ न देना (8) सभी अन्तर्राष्ट्रीय भगड़ोश का शान्तिपूर्ण उपाय—सन्धिवाता—समझौता मध्यस्थता आदि से निबटारा करना (9) पारस्परिक सहयोग और हिंसा की वृद्धि करना तथा (10) साथ-एक अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व के प्रति सम्मान रखना ।

दो वर्षों के अन्तर पञ्चशील के सिद्धान्त का तुनिया के कई देशों ने स्वीकार कर लिया । इसके सिद्धान्त को भारत का यात्रा करनेवाले विदेशों के अनेक प्रधान मंत्रियों और शासनाध्यक्षों ने अपन वक्तव्यों में स्वीकार किया । फिर जब भारत के प्रधान मंत्री विदेश भ्रमण पर गये तो वहाँ भी कई देशों के साथ पञ्चशील के सिद्धान्त के आधार पर समुक्त वक्तव्य प्रकाशित किये गये । इसके उपरान्त, 14 सितम्बर 1959 को समुक्त राष्ट्रमण्डल की साधारण सभा ने भी भारत द्वारा प्रस्तुत पञ्चशील के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया । इस तरह पञ्चशील के सिद्धान्त को विश्व में मान्यता मिलने लगी । यद्यपि अमरीका और ब्रिटेन आदि नाटो के देशों ने इसे पूर्णतः स्वीकार नहीं किया फिर भी उन्होंने इसका खुला विरोध भी नहीं किया । भारत में एक अमरीकी राजदूत जी चर्मन कपर ने अपने एक भाषण में कहा था कि अमरीका पञ्चशील के सिद्धान्तों से पूर्णतया सहमत है ।

सिद्धान्त की व्याख्या—पञ्चशील के सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय सम्बंध व क्षत्र में अत्यन्त महत्वपूर्ण मान जाते हैं । अतएव इनका कुछ और अधिक विवचन आवश्यक है । इसका पहला सिद्धान्त यह आदेश देता था कि सशस्त्र सभी राष्ट्रों का एक दूसरे की प्रादेशिक अखण्डता और सम्प्रभुता का सम्मान करना चाहिए । इस तरह यह साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद को जड़ पर कुठाराघात करता था । इसके द्वारा यह अर्थ स्पष्ट होता था कि किसी भी राज्य का अपने स कम सन्निवासी राज्यों पर राजनीतिक या सैनिक गत नहीं लाजनी चाहिए तथा प्रादेशिक और आर्थिक साम्राज्यवाद के सिद्धान्तों का परित्याग कर देना चाहिए । इस सिद्धान्त के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि दूसरे देशों में विघटन आर्थिक अधिकार और सुविधाएँ प्राप्त करना विरोधात्मक नीतियों को प्रोत्साहन देना दुबल कठमनी सरकारों की स्थापना करना तथा किसी भी राज्य में किसी दल विघटन को आर्थिक सहायता देना—यह सारे कार्य राज्यों की सम्प्रभुता तथा हस्तक्षेप के सिद्धान्तों का उल्लंघन हैं । इसलिए यदि सभी देशों के सर्वोच्च सत्ता के पूर्ण सम्मान रखने के लिए साम्राज्यवाद का स्वयमेव अन्त हो जायगा । अनाक्रमण और दूसरे देश के मामले में हस्तक्षेप की नीति के अनुसार में संघर्ष व क्षत्र को सीमित करनेवाले हैं । पञ्चशील के चौथे सिद्धान्त के द्वारा समानता और पारस्परिक लाभ पर बल दिया गया था । यदि इस सिद्धान्त का

जनकरण किया गया तो काइ भी राज्य चाह छोटा हो या बड़ा एक दूसरे के साथ सम्मानता के सिद्धान्त के आधार पर जन सम्बंधों का निर्माण कर सकता है और एक दूसरे के हित को जागे बना सकता था। यदि सभी राष्ट्र एक-दूसरे के साथ सहयोग करें तो पिछड़े हुए देशों की गरिबी और सब प्रकार के अभावों का दूर किया जा सकता था।

शांतिपूर्ण सहजीवन का सिद्धान्त—पंचगान का सबसे महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त या तथ्या स जीवन (Peaceful co existence) का था। अतएव इसका विषय विवेचन बाध्यता है। आज संसार में तरह-तरह का राजनीतिक आर्थिक वार समाप्ति पद्धतियाँ काममें हैं जिनमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण समाजवाद और पूँजीवाद है। इनके नेत्र समाज विराघो गुंठा में बँट गया था और अंतरराष्ट्रीय तनावनी जलना बढ़ गयी थी कि आपसिक बातुओं के इस युग में तृतीय विश्व युद्ध की सम्भावना प्रतीत हो रही थी। पूँजीवादी देश समाजवाद को जन्म-मृत से टपट पेंकना चाहत थे और समाजवादी देश पूँजीवाद को दम करन पर उतारत थे। ऐसा स्थिति में सार्वभौम युद्ध से बचान या एकमात्र राय शांतिपूर्ण सहजीवन के सिद्धान्त में विश्वास करना था। यदि यह मान लिया जाय कि पूँजीवाद और समाजवाद दाता विरोधी किसी रूप में रहा तो अन्त-सी समाजातों का हन ह जायगा। यदि हम ऐसा नहीं मानते तो यह वास्तविकता से मुह माड़ना होगा। पूँजीवादी देश साम्यवादी देशों — इस अन्कार का मानें कि उन्हें अपने देश में किसी तरह रदन का अधिकार है। जो लोग का बात समाजवाद नाग भी मान लें। यदि समाजवादी और पूँजीवादी गुंठा की प्रगतियों विचारधारालों तथा आर्थिक राजनीतिक एवं सामाजिक गणनों से जमीन आसमान का भेद हो तो भी ये विश्व शान्ति के द्ति में परस्पर मिलकर शांति पूर्वक रह सकते हैं। यदि ऐसा हो गया तो संसार में किसी प्रकार का संघर्ष नहीं रहना और सब लोग अचानुसार अपने देश में शांतिपूर्वक रहने शांतिपूर्वक सहजीवन का यही तत्पर था। पंचशील का पाँचवाँ बिंदु इस बात पर बल देता था कि विभिन्न देशों के सामना से नीतिक न हान पर भी एक-दूसरे के उन्मूलन का प्रयत्न नहीं करना चाहिए किन्तु एक-दूसरे के साथ शांतिपूर्ण रहने का नीति ग्रहण करना चाहिए।

शांतिपूर्ण सहजीवन के सिद्धान्त पर भारतीय दृष्टिकोण—पश्चिम के कतिपय उपग्रहियों का यह मत था कि साम्यवादी गुंठ के साथ सहजीवन अनम्भव है, क्योंकि लोग का विचारधारालों में अमान आममान का अन्तर है और दोनों में सख्य अनिवाय है। उनका कहना था—मक्का और मक्का का सह-अस्तित्व सम्भव हो सकता है। गुंठ तथा अरिया एक घाट पर पानी पा सकते हैं किन्तु यह नहीं हो सकता कि साम्यवादी और पूँजीवाद एक-दूसरे के बगन में शांतिपूर्वक रह सकें। उनका कहना था कि मार्क्सवाद-लेनिनवाद के दर्शन में पूँजीवाद तथा साम्यवाद के बीच सह-अस्तित्व का बात बभी नहीं स्वाकार की गया है। उनके मत में कम्युनिस्ट शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व

का मारा सभी दते हैं जब उनकी मीति से यह भेज जाती है। अपने मत के समर्थन में वे युद्ध-युद्ध के मास्सीवाट और पांचा य लोकतन्त्र के बीच तल्ल तल्ल घुसने की बात दोहराते थे जो युद्ध में प्रतिष्ठित हुआ और जिसका परिणाम एक पक्ष के उत्थ और दूसरे पक्ष के जीवन्त म निरुत्थ। साम्यवा और पू जीवा के अनिवार्य मध्य के विद्वान के समर्थन में वे 1919 में लेनिन द्वारा किये गये उद्योग भाषण का हवाला देते थे जिसमें उसने कहा था हम केवल राय में ही नहीं रह रहे हैं अगिनु राय की एक प्रणाली में रह रहे हैं और सोवियत गणराज्य के साथ साम्राज्यवादी रायों की व न साम्राज्य के लिए साथ साथ अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। अग्न म किसी एक की विषय अनिवार्य है। इनके पहले कि अग्न आते सोवियत गणराज्य और पू जीवादी राज्यों के बीच बहुत से सपनों का होगा अन्तर्मन्त्राधी है।

इस सत्र में भारतीय दृष्टिकोण यह था कि वर्तमान परिस्थिति का ता में में यह छासनी बात हो गयी है जिसका स्वयं साम्यवादी नेताओं ने प्रतिवाद किया है। बाद में स्वयं लेनिन ने कहा था कि सभी राष्ट्र समाजवा तक पहुँचेंगे क्योंकि यह अपरिहार्य है किन्तु सभी राष्ट्र समाजवा तक एक ही रास्ता से नहीं पहुँचेंगे। इसी प्रकार लेनिन ने कहा था कि यदि पू जीवा अपने उत्थान की अनकम्पनीयत कर सकें अर्थात् अधिकतम लाभ में लेकर उठे मजदूरों के लाभ के लिए वितरित करें तो कोई रुकट सहा नहीं होगा। 1952 में उसने पुनः कहा था। मैं अब भी यह विश्वास करता हूँ कि समुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच युद्ध अवश्यम्भायी नहीं माना जा सकता है और ये दोनों बेग भविष्य में एक-दूसरे के साथ सान्तिपूर्वक रह सकते हैं। एडवो ने हथ भावना को और अधिक बल प्रदान किया। सान्तिपूर्ण सहजीवन के सिद्धांत पर बोले हुए उगन हुआ था। हमारे लिए इसका अर्थ केवल सान्तिपूर्वक दूसरे के साथ रहना मात्र नहीं है किन्तु उगन विचारों के प्रति सहिष्णु रहना है और उन्हें अंगीकार भी करना है यदि वे अधिक यत्नयुक्त हों। ऐम लोग भी देख गये हैं जो प्रम तो नहीं करते किन्तु विचार मूल में उद्योग जान के बाद प्रम पूरा नहीं तो पारस्परिक रूप से समाधानकारक अन्दा जीवन व्यतीत करते हैं।

भारतीय नेताओं ने साम्यवादी नेताओं की इन उक्तियों का समर्थन करते हुए कहा कि दोनों विचारधाराओं में सह अस्तित्व सम्भव है। अन्तर्गत भारतीय आत्मसन्तान के इस विचार से सहमत थे कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वर्तमान तनाव मुख्यतः वैचारिक कठिनायों के कारण नहीं है। यह ऐसे मामलों का सचय नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सके। वस्तुस्थिति यह है कि इतिहास की पुनरावृत्ति हो रही है। जो सचय किसी समय यूरोप और गर यान्त्रिक के बीच घनानिया और गर यान्त्रिकों के बीच हुआ था और गर इंग्लैंड के बीच तथा प्रोटेस्टैंट और कैथोलिकों के बीच चल रहा था आज एक बार पुनः साम्यवादी और गर साम्यवादी शक्तियों के बीच पट पड़ा है। इसी चीज में बीजते हुए जवाहरमान नेट्स न एक बार

कहा था। हमारी अधिकांश विचारधाराएँ साम्यवाद और साम्यवादी विचारों द्वारा विकृत हैं। यदि सच साम्यवादी गतिविधि हुए बिना एक महान गतिविधि होता जसा कि वह आजकल है तो भावही सघन और भी गहनता के साथ विद्यमान रहता। नहरे के उस दिष्टार का समर्थन हैरत लाक न भी किया था। आश्चर्यजनक न कहा था मैं इस सम्बन्ध में विस्तृत विश्वसूचक कह सकता हूँ कि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही पूँजीवादी या साम्यवादी या समाजवादी देश हों, तो उनकी प्रतिस्पर्धा परस्पर विरोधाभासी तब विद्यमान हो तनाव में प्रतिफलित हो तो कि आजकल दोनों देशों के बीच विद्यमान हैं।

भारतीयों की ओर से यह भी तर्क दिया जाता है कि यदि पश्चिमा देशों और सोवियत संघ के बीच सघन में पश्चिमा देश विजयी भी हो जाय तो इस बात की क्या गारंटी है कि मानव समुदाय उसी दिग्गमार्थ में पुनः अरन-आका नहीं पाएगा। व प्रोफेसर एच. बरन्हाल्ड के उस विचार का अनुमोदन करते हैं अब उन्होंने कहा था हम यह भी कह सकते हैं कि यदि सम्पूर्ण सोवियत संघ और उस सम्पूर्ण मित्रराज्य उसी क्षण समुद्र में डबा दिया जाय तो भावसा ही अनुभव कर स हमारे साथ फिर होगा।

इन सारा बातों का ध्यान में रखकर भारतीय विश्व नीति में गतिधूर्त सह जावन के सिद्धान्त पर अत्यधिक बल दिया गया था।

पञ्चशील का मूल्यांकन

सबसे कोई सन्देह नहीं कि पञ्चशील के सिद्धान्त का ही प्रमाणन आया है। जिस प्रकार राष्ट्रीयता न समग्रदृष्टि के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के अन्तिम में उत्पन्न हुआ उसी प्रकार नहरे के पञ्चशील के रूप में गतिधूर्त का उत्पन्न उत्पन्न हुआ। यह एक द्वितीय विश्व युद्ध का विचार था जो उत्पन्न गतिधूर्त के लिए भारतीय साम्यवाद का प्रस्ताव करते हुए व्यक्त किया था। फिर भा. इसका सिद्धान्तों पर अनेक आलोचनों की गयीं। इसकी प्रेरणा जैव आलोचनों का आरोप लगाया मात्र कहा गया और इसका तुलना 1815 में पवित्र संघ (Holy Alliance) तथा 1927 के ब्रिग्स ब्रिग्स पक्क (Kellogg Briand Pact) से की गया। कहा जाता था कि पञ्चशील एक ऐसा पापपा है जिसका पानन करान के लिए न तो कोई सत्ता है बार न का व्यवस्था। अतएव इसकी शक्ति का उपस्थिति नहीं है। फिर पञ्चशील का अर्थ भा माना जाता रहा क्योंकि इसके सार सिद्धान्त समुच्चर राष्ट्रपक्ष के चारों में सन्निहित है और अन्तिम पक्ष रूप से अन्तर्गत पुनरावृत्ति निरस्त था। पञ्चशील का कोई भा ए। सिद्धान्त नहीं था जो बाहर में न था। इसके अतिरिक्त पञ्चशील के सिद्धान्त पर और भा बड़े आपत्तियों की गयीं उन-उत्पन्न प्रस्ताव अन्तिमों के द्वारा भी यह दयास्थिति का पोषक था आति। इन आपत्तियों का जवाब वृत्त ए जवाब के तौर पर 9 दिसम्बर 1954 का पत्रिका नहरे के भारतीय राष्ट्रपति में कहा था। लोगों ने पञ्चशील का विरोध किया है, किन्तु आधार पर? व कहते हैं आप यह

कैसे विश्वास करते हैं कि इन सिद्धांतों का पालन भी किया जायगा ? निस्संदेह यदि आप किसी बात पर विश्वास नहीं करते तो इसकी खर्चा करने और उसकी बारी में निखने से कोई लाभ नहीं है और फिर आप के लिए कोई दूसरी बात गप नहीं रह जाती सिवाय इसके कि आप अकेले रह और नडकर एक दूसरे पक्ष को परास्त कर—इसके अतिरिक्त अन्य कोई भाग नहीं है। यह हमारे पक्ष के वचन पर विश्वास करने का प्रश्न नहीं है किन्तु ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करने का प्रश्न है जिसमें दूसरा पक्ष अपने वचन को भंग न कर सकें। यह सम्भव है कि वह अपने को अधिक विषम परिस्थितियों में पावें। यदि विश्व के विभिन्न देश पारस्परिक सम्बन्धों के लिए इन पाँच सिद्धांतों को बार बार दुहराते हैं तो इसके लिए एक वातावरण उत्पन्न करत है।

भारतीय राजनीतिज्ञ इस बात को भलीभाँति महसूस करते हैं कि पञ्चशील काई ताड़ की छड़ी नहीं है जिसके अन्तर्गत मात्र से अन्तर्राष्ट्रीय तनाव का लोप हो जायगा परन्तु यदि इन पर अमन किया जाय तो अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में निश्चय ही कमी होगी और संघर्ष के कारणों का उन्मूलन किया जा सकता है। जवाहरलाल ने एक बार कहा था कि यदि सोमाय से सारे सारे देश सह-अस्तित्व के इन पाँच सिद्धांतों का स्वीकार कर लें तो भी सम्पूर्ण विश्व शांत नहीं हो सकेगा। उनसे अधिक से अधिक जो आगाही जा सकती है वह यह है कि उनके प्रभाव और कार्य के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष का प्रभाव प्रमत्त मूख जायगा। नहर्न के गे में ऐसे करारों से ऐसा विषम तयार करने में असमर्थ मिला है जो प्रमत्त दुष्ट गतिधर्मों को भी प्रभावित करता है और उसके लिए दुःखद्वार करमा शक्ति बना देता है। वस्तुतः वह किसी विविष्ट विचारधारा को जन प्रदान करने के साधन नहीं है क्योंकि उम्मा किसी विचारधारा से कोई सम्बन्ध नहीं है। उम्मा जमीन पर तन के काम करने के लिए तथा प्रतिस्पर्धा गुटों के बीच अन्तर् सम्बन्ध स्थापित करने के लिए प्रमत्त मार्ग प्रगस्त करने के लिए किया जा सकता था।

जहाँ तक सिद्धांत के रूप में पञ्चशील का प्रश्न है इस पर कोई विषय उत्पन्न नहीं हो सकती किन्तु व्यावहारिक राजनीति की दृष्टि से और विशेषकर भारत चीन सम्बन्ध की पृष्ठभूमि में पञ्चशील एक अत्यन्त असफल सिद्धांत साबित हुआ। उसके आलोचकों की एक प्रमुख आपत्ति यह भी थी कि एक सिद्धांत का जन्म ही अत्यन्त वातावरण में नहीं हुआ था। यह एक अपवित्र माता की पवित्र सन्तान (Holy daughter of an unholy mother) है क्योंकि सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन भारत और चीन के तिब्बत के सम्बन्ध में हुए सम्मेलन के सम्मेलन हुआ था। उसके द्वारा भारत ने तिब्बत में चीन की हस्तक्षेप रद्दता का स्वाकार करने के लिये का स्वायत्तता के अपहरण में चीन का समर्थन किया था। इस कारण भारत में पञ्चशील का स्वायत्तता के अपहरण में चीन का समर्थन किया था। इस कारण भारत में पञ्चशील से हाँबुछ नागों के द्वारा इसकी बट आलोचना होती रही। अतः पञ्चशील के जन्म के समय आचार्य कृपलानी ने कहा था—यह पञ्चशील सिद्धांत पापपूर्ण परिस्थितियों की उत्पत्ति है क्योंकि यह साम्यात्मक और सामुदायिक रूप से हमारे ना विरा—9

साथ सम्बद्ध एक प्राचीन राष्ट्र के विनाश पर हमारा स्वाइति पान के लिए प्रतिपादित किया गया था।¹ आचार्य कृतान्ती की यह उक्ति 'आयद सय न हा' क्योंकि विश्व के प्रति भारत का यह नीति अनचित नहीं था लेकिन 1962 के अक्टूबर में भारत-चीन युद्ध के समय चीन ने इस प्रकार का व्यवहार किया उसने परिणामस्वरूप पश्चीन का नामानिष्ठान मिट गया। उसका उद्गार सिद्धांतों का उल्लंघन उसका अर्थ प्रदान एक राष्ट्र के द्वारा दुआ और उस कारण पश्चीन में लोगों की आस्था नहीं रह गयी। यह भारतीय विदेश नीति का एक बलवही असफलता माना जायगी।

भारत और संयुक्त राष्ट्रसंघ (India and U N O)

संयुक्त राष्ट्रसंघ में भारत की आस्था — द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद संसार को भावा विश्व युद्ध का विभाषिका से दवान तथा संसार में शान्ति के प्रहरी के रूप में काम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गया थी। भारत जिसने विश्व शांति का अपना विशेष नीति का मूलमंत्र बना लिया था के लिए यह विश्व स्थापनादिक था कि वह इस विश्व संस्था को अपना पूरा समर्थन दे। अतएव भारतीय नेताओं ने प्रारम्भ से ही संघ के प्रति अटूट धृष्टा तथा भक्ति का प्रमाण दिया और इसको दुश्मनी एवं सतप्त मानवता के परिचाय का एकमात्र साधन बनाया। यद्यपि शास्त्र में कहा गया था भारत सरासरी देश संयुक्त राष्ट्रसंघ की किसी भी क्षेत्र में योगदान मिलने की उम्मीद नहीं थी क्योंकि किसी भी क्षेत्र में उसका उचित महान न था। फिर भी भारत ने अपना जिम्मेदारियों से मुह नहीं माना तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की सक्षमता के लिए जो भा-उत्सव सम्मनवा मुका किया। जवाहरलाल नेहरू ने इस समस्या के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए कहा था। संयुक्त राष्ट्रसंघ आज हमारे जीवन में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुका है कि उससे रहित विश्व की हमारा बलना भी नहीं कर सकत। समुद्र के जावन-दल संघ के प्रदान समर्थक रहे। सुरक्षा परिषद में मलेशिया के चुन जाने मात्र से ही अमानागिया न संघ का छोटा हिस्सा और कश्मीर के प्रश्न पर पाकिस्तान ने भी एक बार संघ छान्न का धमका दी लेकिन संयुक्त राष्ट्रसंघ में जवाहरलाल का कितना अधिक निष्ठा थी यह उस बात से भना प्रकार प्रमाणित है कि कश्मीर और गांधी के मामल में संघ से निराग हान के बावजूद उन्होंने संयुक्त राष्ट्रसंघ में अपना निष्ठा नहीं छोड़ा और अपने दवायियों को निरंतर समझाते रहे कि समस्त श्रुतियों और साम्राज्य के बावजूद संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव जाति की सबसे बड़ा आग है। अपने जीवनपत्र उन्होंने इस विश्व संस्था के

1 The great doctrine was born in sin because it was enunciated to put the seal of our approval upon the destruction of an ancient nation which was associated with us spiritually and culturally

प्रति अपनी अगाध निष्ठा कायम रखा तथा असहमता की नीति का दृढ़तापूर्वक अवनमन करते हुए उद्दान मध्य राष्ट्रमण्डल की सक्रियता की ओर सञ्चन बनाने के लिए प्रयास में भरमनाश योगदान प्रदान किया।

मध्यकाल राष्ट्रमण्डल में भारत का अग्र विचार है और उसकी यह नीति है कि निया के अन्तर्राष्ट्रीय विचारों को सुलभता में इस विश्व-मण्डल का अधिकाधिक प्रयोग किया जाय। मध्यकाल राष्ट्रमण्डल के प्रति भारत के अग्र विचार का प्रबल प्रमाण भारत पाकिस्तान युद्ध के समय सुरक्षा परिषद के युद्ध विराम प्रस्तावों का भारत द्वारा तत्काल स्वीकृति है। इस बात में एक महीने के अन्दर सुरक्षा परिषद की तीन बैठक हुई और प्रस्ताव पास हुए। भारत ने इन सभी प्रस्तावों का तुरन्त मान लिया। जहाँ पाकिस्तान ने इन प्रस्तावों को मानने में आनाकानी की वहीं भारत युद्ध में बिजली हाते हुए भी सुरक्षा परिषद के आदेशों को सहर्ष स्वीकार करने में जरा भी सबाध का प्रदान नहीं किया।

भारत की सदस्यता :—स्मरणीय है कि कई परिस्थितियों के संयोग से भारत पराधीन होते हुए भी मध्यकाल राष्ट्रमण्डल की पूर्ववर्ती संस्था राष्ट्रमण्डल (League of Nations) का सदस्य था और कई सीमाओं के अन्दर रहते हुए भी उसमें उस पुरानी विश्वसत्या में महत्वपूर्ण योग दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उस राष्ट्रमण्डल का विघटन कर दिया गया और संयुक्त राष्ट्रमण्डल की स्थापना के लिए जून 1945 में गार्मिन्सको में सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत का भी आमन्त्रित किया गया तथा संयुक्त राष्ट्रमण्डल के चार्टर पर हस्ताक्षर करनेवालों में वह भी एक प्रारम्भिक सदस्य था। भारतीय दल का इस सम्मेलन में भाग लेने गया था उसका नेतृत्व रामास्वामी मुन्नियार ने किया। जिस समय भारत संयुक्त राष्ट्रमण्डल का सदस्य हुआ उस समय वह स्वतन्त्र नहीं हुआ था। लेकिन अपने तत्कालीन प्राप्ति के द्वारा उसने उसके पूर्व निश्चय के अनुसार संधि राष्ट्रमण्डल से अपना सम्बन्ध स्थापित रखा और पूर्ववर्ती संस्था का सदस्य बना रहा और उसकी कार्यवाहियों में सक्रिय रूप से भाग एवं रुचि लेता रहा।

मान्य सचिवालय और संयुक्त राष्ट्रमण्डल के आदेश :—संयुक्त राष्ट्रमण्डल में भारत की आगामी निरन्तर बढ़ती गयी। ब्रिटिश दासता से मुक्त होने के कारण स्वतन्त्र भारत के लिए क्या सचिवालय बनाया गया और उसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया कि भारत अपने राष्ट्रों के मध्य सद्भाव बढ़ाने तथा अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं गरिमा की स्थापना के लिए भरपूर प्रयत्नशील रहेगा। सभी राष्ट्रों के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार और मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम रहेगा तथा अन्तर्राष्ट्रीय संधियाँ और अन्तर्राष्ट्रीय शांति के लिए सद्भाव कायम रहेगा। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि संयुक्त राष्ट्रमण्डल के चार्टर की यही सबसे प्रमुख बात है और उसका प्रत्येक सदस्य राष्ट्र में स्वतन्त्रता के अन्तर्गत आचरण करने की आशा की जाती है।

संघ के महत्व का समर्थन — भारत ने उन सारे प्रयासों का निरन्तर विरोध किया है जिनका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्रसंघ के महत्व को कम करना था। प्राथमिक संयुक्त राष्ट्रसंघ का विरोध उसने सभी आधार पर किया है। चाटर का धारा 52 में प्राथमिक संस्थानों की स्थापना का प्रावधान है। उस धारा की आरंभ में जा प्राथमिक संयुक्त राष्ट्रसंघ बन भारत ने उसका सख्त विरोध किया। भारत का क्या है कि इन संस्थानों ने संयुक्त राष्ट्रसंघ के महत्व को कम किया है। 9 सितम्बर 1954 को वाटरगैट नहर न सिआटी अधिकाधिक करत हुए कहा था कि यह संयुक्त राष्ट्रसंघ का भावना का प्रतिबिम्ब है। संयुक्त राष्ट्रसंघ का सफल बनाने का उद्देश्य है। भारत इन संस्थानों में शामिल नहीं होगा और असंगतता की नीति का अवलम्बन करता रहा। यदि वास्तव में ऐसा नाय तो भारत की अस्मिता का नीति धार में निहित भावना का पूरा पूरा धार करती है और वह उसके सख्त अन्तर्गत है।

संघ की स्थापना रूप देने का प्रयास — भारत का दृष्टिकोण है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ वास्तविक रूप से एक सीमित और सङ्कुचित माया न रहकर व्यापक और विस्तृत हो सभी विश्व का कल्याण होगा और चाटर में निहित बातों का परिपालन हो सकेगा। इसलिए उसने संयुक्त राष्ट्रसंघ का एक विश्व व्यापक समस्या बनाने में भी महत्वपूर्ण योग दिया है। कोरिया युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्रसंघ में नये राष्ट्रों का संयुक्तता प्रदान करने के उद्देश्य पर निर्धारण हुआ गया था। अविश्व और अमेरिकी गुट दोनों नये संस्था बनाने का विरोध कर रहे थे। इस कारण संयुक्त राष्ट्रसंघ में नये राष्ट्रों का प्रवेश अस्मभव हो गया था। भारत ने इस प्रतिरोध का दूर करने का यत्न किया। नवम्बर 1953 में जब मासोन बुगानिन और सचिव भारत आयता पत्रित नहर न सार संघ समया पर बातचात की और अन्त में यह तय हुआ कि अमेरिका अविश्व संघ द्वारा समर्थित देशों का विरोध न करे और इस प्रकार अविश्व संघ का पक्षमा गुट द्वारा समर्थित देशों का विरोध नहीं करे। कोरिया और वियतनाम के संघ का संस्था का प्रश्न अभी छोड़ दिया गया। इस समझौते के अनुसार 8 सितम्बर 1955 का संघ की एक साधारण सभा ने प्रस्ताव पास करके अठारह नये देशों को संघ का संस्था बनाने की सिफारिश का पर यह प्रश्न सुरक्षा परिषद में जाया तो राष्ट्रवादी चीन ने वीग का प्रयोग करके सार समझौते का हार कर दिया। दूसरे बार अविश्व संघ न माओ का प्रयोग शुरू किया। फिर एक बर्तन परिस्थिति उत्पन्न हो गया। इसके समाधान में भारतीय प्रतिनिधि श्री कृष्ण मदन ने बराबर प्रयास किए और उनके परिश्रम के फलस्वरूप नये राष्ट्रों की संस्था का प्रश्न बहुत कुछ हल हो गया। सितम्बर 1955 में साठ नये राष्ट्र संयुक्त राष्ट्रसंघ के एक ही साथ संयोजन। इस प्रकार भारत ने इस विश्व अंतराष्ट्रीय समस्या का हल करने में अपना महयोग दिया।

सुरक्षा परिषद के सङ्गठन के बारे में भारत ने यह दृष्टिकोण अपनाया है कि इसमें एशिया और अफ्रीका के देशों की जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व मिलना

चाहिए। इसलिए जब 1960 में वार्डर का संगठन के सुरक्षा परिषद् के सन्धियों की सन्ध्या बढ़ायी गयी तो भारत ने उसका स्वागत किया। उसने कई बार अपने इस मांग को भी दुहराया है कि चीन के अनायास भी किसी एक देश का मुद्दा परिषद् में स्थायी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

सरक्षा परिषद् में बिगबाधिकार का प्रश्न और भारत।—सुरक्षा परिषद् की मनगन प्रणाली अर्थात् वोटों की व्यवस्था से भारत संतुष्ट नहीं है तथापि उसने कई कारणों से इसका समर्थन किया है। भारत हमें बात की मनी भाँति समझता है कि सुरक्षा परिषद् के स्थायी सन्धियों के विशेषाधिकार न कभी इसी मयुक्त राष्ट्र सब का एकत्र पदु बना लिया है। लेकिन कबन भी आधार पर वही एक के अनायास समर्थक नहीं है। उसका कहना है कि अमन पर दूषण का साक्षर अन्तराष्ट्रीय समस्याओं का समाधान न। किया जा सकता है। बोटों का प्रावधान अपने आप में बुरा नहीं है। इनका दुहायाग तो तीन युद्ध के कारण होता है। इसलिए य अन्तराष्ट्रीय सन्धियों का दोटन बन गया है। यदि इस सन्धियों को दूर कर लिया जाय तो विशेषाधिकार के दुहायाग की समस्या अपने आप विनीत हो जायगी।¹

अन्तराष्ट्रीय सरक्षा के क्षेत्र में सन्धियों सहयोग —मनिक और ओद्योगिक दृष्टिकोण से द्वाण होने पर भी भारत न प्रारम्भ से ही अन्तराष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में और मयुक्त राष्ट्रसंघ के कार्यों में प्रागनीय भूमिका का निर्वाह किया है। अनेक अवसरों पर भारत ने मध्य के मध्य पर से पूर्व और पश्चिम के मध्यमों को बोटों काई को कम करने का उद्देशनीय प्रयास किया है। दो तीन अवसरों पर ही उसने निश्चित रूप से अपनी रचनात्मक भूमिका द्वारा तृतीय मयुक्त के दावानत को प्रवर्तित होने से रोका है। वि. व. की प्रमुख राजनीतिक समस्याओं का समाधान तथा शांति स्थापना के हेतु भारत द्वारा मयुक्त राष्ट्रसंघ में किये गये कार्यों का वर्णन हम इस प्रकरण के छठे अध्याय में करेंगे।

सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में सहयोग —भारत ने कबल शांतिस्थापना के कार्य में ही मयुक्त राष्ट्रसंघ के साथ सहयोग न। किया है बल्कि आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में भी उसने प्रागनीय कर्म चलाया है। विद्युत वर्षों में भारत के प्रतिनिधियों ने मयुक्त राष्ट्रसंघ की विभिन्न शाखाओं उसकी सम्बद्ध समस्याओं तथा विविध आयोगों और समितियों में उत्साहपूर्वक भाग लेकर अक्षी द्याति प्राप्त की है। अन्तराष्ट्रीय श्रम संघ (I L O) मयुक्त राष्ट्र आर्थिक वज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (U N E S C O) के कार्यों में उसकी विशेष रुचि रही है। यूनिफा एक

1 One of the aspects of India's foreign policy which is puzzled many foreigners is India's refusal to support attempts made to restrict the area of veto. As was often stated by India's spokesman, the constant exercise of the power of veto by the Soviet Union was only a symptom of the tension in the international field. Its abolition therefore will not cure the basic disease. The Indian Government considered the voting privilege enjoyed by the permanent members of the Security Council to be the reflection of the power situation in the world.—K. P. Karunakaran *India in World Affairs* (1950-1953) pp. 147-48

ए ओ० और डब्ल्यू एच० ओ के प्रादेशिक कार्यालय भारत में स्थित हैं। एक मनावा समुक्त राष्ट्र सघीय टक्कन सहायता बोड विश्वकाय सूचना सवा अन्तर्राष्ट्रीय थम रुध यूनेस्को और विश्व बैंक के कार्यालय भी भारत म खुले हुए हैं। 1954 और 1964 के बीच भारत को समुक्त राष्ट्र सघाय टक्कन सहायता काय क्रम के अंतगत 1567 टक्कन विशेषता की सवाए प्राप्त हुई तथा 1464 भारतीय टक्कन विश्व प्रविष्टा के लिए विदेशी को भेज गये। 1963 तक भारत का मुन मिलाकर 109 करोड रुपये की समुक्त राष्ट्र सघीय सहायता प्राप्त हुई।

राजनीतिक सत्र म भारत का स्थान 1-समुक्त राष्ट्रसघ के राजनीतिक शाखाओं में भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। 1950 51 में वह पहली बार सुरक्षा परिषद का सन्स्य चुना गया था। 1966 में वह दुबारा सुरक्षा परिषद का सन्स्य चुना गया। 1946 1949 1951 1953 1955 1962 64 में वह आधिक और समाजिक परिषद का भा सन्स्य रह चुका है। भारत उस विनिष्ठ समिति का सन्स्य है जिसका स्थापना साधारण सभा द्वारा समुक्त राष्ट्र सघ की शांति रक्षा रुवधी कायबाधियों के अध्ययन के लिए का गयी। वह समुक्त राष्ट्र सघीय ठठारह रुदरसाय निरन्तरकरण आयोग का भा सन्स्य है। वनक भारताय समुक्त राष्ट्र सघ में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन रह चुके हैं। इनमें विजया लम्भा पान्त (साधारण सभा का अध्यक्ष) रामास्वामा मुदालियर का बार सन, डा होमा मादा ज भाभा डा पी एस लोचनायन के नाम विग्य उल्लेखनीय हैं। श्री बी एन राव अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाचार्य और डा० राधाकृष्णन यू० ए० सचिवालय पर आसीन रह चुके हैं। लगभग एक सौ पन्ह भारतीय सघ के सचिवालय के विभिन्न भागों में काय करत हैं तथा उसकी विविष्ट एजिसिया में लगभग तीन सौ भारतीय विद्यमान हैं।

भारत प्रति वष एक बहुत बड़ी रकम सघ के वार्षिक खर्च के लिए देता है। 1964 में यह वनराशि ठठसो लाख रुपये की थी। इसका मनावा समुक्त राष्ट्र सहायता कायक्रमा का भारत ने 1965 में 1 02 करोड रुपया दन का वचन दिया। उनी वष सघ की द्वितीय रुवट का मुकदला करन के लिए बयानीस लाख रुपया दिया।

समुक्त राष्ट्र सघ में भारत की आस्था पर कोई विवा नही उठ सकता। विश्व की राजनीति में वह इसकी अत्यधिक महत्व प्रदान करता है। इसलिए समुक्त राष्ट्र सघ के अधिवक्ताओं में भारत अपन ठठ वोटि के राजनतावा की अपना प्रतिनिधि वनाकर नता है जो उसका बाद दिवशी में प्रमुख भाग नत है। पछित नह के जीवनकाल में साधारण सभा का साय हा का अधिवक्ता आ हो जिसमें भारत न कोई प्रताव ही पस किया। समुक्त राष्ट्रसघ द्वारा आमाजित कई अठ राष्ट्रीय सम्मेलन भा भारत में हो चुके हैं। अब भा समुक्त राष्ट्र सघ का आन्ति स्थापना के काय के लिए सभा की आवश्यकता पठा है भारत न उसमें उवा मदद करक अपने उत्तरदायित्व का निवाह किया है। शांति के रक्षा सघ के आन्ति पर भारतीय सचिवालय का कारिया माना मित्र कागा और साह्य आन्ति दलों में नत्र कये थ।

अफ्रो-एशियाई समस्याएँ और भारत

(Afro Asian Problems & India)

एशिया और अफ्रीका की समस्या में गहरी रूचि रखना भारत के लिए विनमूलक स्वाभाविक है। इन दो महाद्वीपों पर उसका भविष्य भी निर्भर करता है और उनकी राजनीति का प्रभाव उस पर (भारत पर) पड़ना अनिवार्य और अवश्यभावी है। अतएव स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने अफ्रीका और एशिया की विविध समस्याओं में गहरी रूचि लेना शुरू किया। उस समय उन महाद्वीपों के समस्त दो प्रमुख समस्याएँ थीं : उपनिवेशवाद का उन्मूलन तथा रंग भेद की नीति पर आधारित प्रजातिवाद का विरोध। इसके अतिरिक्त एशियाई देशों के गैरजागरण के फलस्वरूप एक एशियाई भावना का विकास हो रहा था। इस भावना ने एक एशियाई सम्बन्ध (Asian Solidarity) का जन्म दे दिया। भारत का इस आंदोलन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना था।

एशिया और अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशवाद और भारत

(Attitude Towards Colonialism)

इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में हम यूरोपीय साम्राज्यवादी प्रणाली में भारत के विनिष्ट स्थान और उसके महत्व की चर्चा कर चुके हैं। वहाँ हमने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि एशिया और बहुत जगहों में अफ्रीका में यूरोपीय साम्राज्यवाद का मुख्य आधार भारत था। भारतीय साम्राज्य की रक्षा के लिए ब्रिटेन ने कई देशों की स्वाधीनता पर अतिशय ध्यान देकर उनपर अपना अधिपत्य जमाया था। पुनः यदि इन देशों में कभी स्वातंत्र्य सपना छिन्ता तो उनका कुचनन के लिए भारतीय साधनों का प्रयोग किया जाता था। निटन सासन काल में भारत यूरोपीय साम्राज्यवाद का मुख्य आधार बन गया (Keystone of the arch of imperialism) था। 15 अगस्त 1947 का जब भारत स्वतंत्र हुआ तो आधारगिता के हट जाने से साम्राज्यवाद के सम्पूर्ण भवन का धरागायी हो जाना अब सम्भाव्य हो गया। अतः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया के देशों में जो राष्ट्रवाद का प्रचलन हुआ उसका भारत की स्वतंत्रता से बड़ी प्रेरणा मिली और महाद्वीप के देश एक-एक करके स्वतंत्र होने लगे। अतः इस लूफान की रोकने का प्रयास हुआ वहाँ एशियाई राष्ट्रवाद और यूरोपीय उपनिवेशवाद का प्रतिरोध में भीषण संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में भारत की सहानुभूति निश्चय रूप से एशियाई राष्ट्रवाद के प्रति थी जिसका उसने अनेक पक्ष समर्थन दिया। 18 मार्च 1946 को सिंगापुर में भाषण देते हुए इंदिरा ने कहा था भारत केवल अपने लिए ही स्वतंत्रता नहीं चाहता। आप सभी दुनिया के स्वतंत्र

और आजा का परतंत्र नहीं रख सके। भारत स्वतंत्र होने में स्वाधीनता चाहता था। अब वह स्वतंत्र होगा तो उसका सारा धर्मित सभी पक्षों में वांछनीय था। किये लगाये जायें।

भारत द्वारा उपनिवेशवाद के विरोध के कारण :- एशिया और अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशवाद का विरोध करना भारत का विशेष अधिकार था। एक प्रमुख विरोधक रहा है। भारत की विश्व गति में इस तरह का समर्थन के कारण से व्यवस्था की थी। स्वतंत्र भारत स्वयं यूरोपीय साम्राज्यवाद का विरोध करता रहा है। भारत का यह दावा नहीं मूल संकेत था कि किस प्रकार सत्ता सत्ता पार से अलग है। कुछ अलग अन्य परदेवरों और घटहास विनिर्माण के द्वारा यह तथ्या नैतिक-नैतिक मुद्दों का प्रमाण कर हमारे देश पर अधिकार जमाया। यह तथ्या से स्पष्ट है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का एक ही आधारित है यह था। प्रत्यक्ष दृष्टि से पराजित भारत का ध्यान करना। देश का उद्धार के लिए हमें यह कर ब्रिटिश सरकार से भारत के धन की टाँहर का कारण का खाना भरना शुरू किया। भारत में लोगों के चम्पा और विकास में उसका कोई रूचि नहीं थी। एतद्वा जिनमें में जहाँ कभी था और दूसरे का नया बन्ता मावही राधा बाना और मधुमयी का साम्राज्य था। हर दिना में देश का विकास के लिए और भारत दुनिया के अन्तर्गत पर एक अलग महत्त्वपूर्ण देश बनकर रहेगा। इस प्रकार का भी क्यों तक साम्राज्यवादी प्रणाली का विकास हान के कारण भारत उपनिवेशवाद की पीड़ा का जवाब और बहुत अनुभव प्राप्त कर चुका था। इस हानत में निम्नी नीतियों के उद्देश्यवाद का विरोध करना उनके लिए स्वाभाविक था। एशिया के अलग देशों का भारत की तरह ही गति हा रहे थे उनका प्रति भारत की सहानुभूति देश प्रबल थी। इन देशों के मुक्ति-युद्ध (Liberation struggle) का समर्थन करना भारत का एक बल था।

द्वितीय एशिया में यूरोपीय उपनिवेशवाद का विरोध करने के लिए भारत व्यवस्था था। भारत का स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सत्ता क्षेत्र और सभी तरह के उपनिवेशवाद का विरोध किया था। अन्तर्गत अपने भारतीय राज्यों का अन्तर्गत एशियाई राज्यों का एक अलग माना था और इस सम्बन्ध में अन्तर्गत प्रणाली स्वाधीनता थी। प्रायः अन्तर्गत अन्तर्गत में अन्तर्गत ने प्रस्ताव स्वीकार करके उपनिवेशवाद का विरोध किया था और यह संकेत दिया था कि एशिया से यूरोपीय साम्राज्यवाद के अनुत्पन्न का भारत जाना तब तक माना है। इसलिए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दुनिया के अलग भागों में ही रहे उपनिवेशवाद विरोध अन्तर्गत का उत्तम समर्थन दिया था। अन्तर्गत एशिया में के अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत के अन्तर्गत में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के अन्तर्गत के अन्तर्गत का विरोध किया था और यह स्पष्ट कर दिया था कि भारत की अन्तर्गत अन्तर्गत विरोध अन्तर्गत की अन्तर्गत से अन्तर्गत अन्तर्गत है। अन्तर्गत विश्व-युद्ध के अन्तर्गत राष्ट्रसंघ (League of Nations) के अन्तर्गत का अन्तर्गत अन्तर्गत (Mandate system) अन्तर्गत की

थी उसको भारतीय नेताओं ने साम्राज्यवाद का परिवर्तित रूप माना था। वस्तुतः राष्ट्रमण्डल के समूचे ढाँचे को उलटाने एवं साम्राज्यवादी यंत्रकला में देखा और इससे ही उषा विरोध किया। नतीजा यह सामान्य न कहा जा सकता। इस राष्ट्रमण्डल कहना जब कि यह यूरोप का एक संगठन है साथ ही मना होता है।¹ इस प्रकार अपने साम्राज्यवादी स्वभाव के कारण राष्ट्रमण्डल भारत में कभी लोकप्रिय नहीं हो सका।

दो विश्व युद्ध के बीच में पराधीन राज्यों के वर्ग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए जिनका उद्देश्य विश्व व्यापी युरोपीय साम्राज्यवाद का विरोध करना तथा गोपित जातियों को संगठित करना था। भारत ऐसे प्रत्येक सम्मेलन में भाग लेता रहा और इन सम्मेलनों के मंच से भारतीय प्रतिनिधियाँ न केवल बतलाती कि वे बेवकूफ भारत में ही नहीं बरन सम्पूर्ण विश्व में उपनिवेशवाद का विरोध करते हैं और उनका उद्देश्य न केवल भा. तरह का बताने करने का समार है। अतएव जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसको अपने नेताओं की न चापलायन का आन्दोलन करना था और इसके अन्तर्गत विदेश नीति का निर्धारण करना था। भारतीय विदेश नीति में उपनिवेशवाद के विरोध का तब ऐतिहासिक परम्परा का परिणाम था।

तृतीय समस्तानीय विश्व राजनीति के म. म. में उपनिवेशवाद का विरोध करना भारत के लिए परम आवश्यक था। विश्वने अध्याय में हम कह आये हैं कि स्वतंत्र भारत ने अपनी विदेश नीति में विश्व शांति का सर्वोपरि स्थान दिया। क्योंकि राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए वह बड़ा आवश्यक मानता था। लेकिन उपनिवेशवाद के अस्तित्व मात्र से विश्व शांति पर हमला सतारा बना रहता है। इसके कारण अत. राष्ट्रिय तनाव और संघर्ष की संभावना बहुत बढ़ जाती है। जब 1948 में हानेड ने इण्डोनीशिया पर अपना उपनिवेश कायम रखे रहने का प्रयास किया तो यह विश्व शांति और विश्व-युद्ध का प्रश्न बन गया। कम-से-कम राष्ट्रों के मध्य घोर मनमुटाव हो इसने पदा कर ही लिया। इसी तरह स्व. न. पर अपना नियंत्रण कायम रखने के लिए 1956 में इराक और फ्रांस ने मध्य पर आक्रमण कर दिया। यह आक्रमण उनके औपनिवेशिक मनोवृत्ति का परिणाम था और इसका नेत्र तृतीय विश्व-युद्ध की सम्भावना बढ़ गयी। उपनिवेशवाद की वजह से तीसरे युद्ध में भी उषा आयी। सोवियत संघ ने पश्चिमी राष्ट्रों की उपनिवेशवादों को न पर कह कर आग्रह किया और पश्चिम ने भी उनका जवाब उसी तरह दिया। इस तरह उपनिवेशवाद अत. राष्ट्रिय तनाव का एक मुख्य कारण बन गया जो निश्चय ही शांति की सुरक्षा के लिए खतरनाक थी। अतएव विश्व शांति के स्थापन भारत उपनिवेशवाद के सम्पूर्ण को आवश्यक मानता था और इससे लिए वह सतत प्रयत्नशील रहने का इरादा रखता था।

चौथे हम यह भी कह आये हैं कि विश्व शांति की सुरक्षा की दृष्टि से भारत समुक्त राष्ट्रमण्डल को एक प्रभावशाली संस्था बनाना चाहता था। इसके लिए हमने

एक व्यापक संघटन का रूप देना जरूरी था। भारत का कहना था कि संघ का सदस्यता सभी राष्ट्रों को प्राप्त होना चाहिए, न कि केवल उन राष्ट्रों का जो राष्ट्रों का स्वतंत्रता और उनका सावधानीपूर्वक आवश्यक था। इसके अभाव में किसी राष्ट्र का संघ का सदस्यता नहीं मिल सकती थी। उपनिवेशवाद स्वायत्त राष्ट्रों का पतन के मार्ग में बन्त था। बाधक था। इस कारण भारत उपनिवेशवाद के समाप्ति का समर्थन कर रहा था।

इस अवधि के उपनिवेशों में निवास करने वाले लोगों का राजनीतिक आकांक्षा के दमन से भाव के मौलिक अधिकार का भाव उत्पन्न हो रहा था। संयुक्त राष्ट्रसंघ के निर्माण पर जो मानव के मौलिक अधिकार (Fundamental Human Rights) की घोषणा हुई उसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि शांति के पक्ष में स्वस्थ वातावरण बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सभी मानवों के मूलभूत राजनीतिक अधिकारों का मान्यता मिले। इसमें आत्मनिर्णय का सिद्धांत स्वाभाविक रूप से सम्मिलित था। इस दृष्टिकोण से भाव उपनिवेशवाद का विरोध करना जरूरी था। अप्रैल 1947 में दिनांक के एशियाई सम्मेलन में भारत ने जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। एशिया के दश चिरकाल तक पश्चिम देशों के दरबारों में प्रायः और भिन्न बने रह रहे हैं। यह अतीत को क्या हो जानो चाहिए। हम चाहते हैं कि हम अपने पर पर छत्र हा जा हमारे साथ सहयोग करें हम उनके साथ सहयोग करने का तयार हैं। हम दूसरे के हाथों का खिलौना नहीं बनना चाहते यह हमारा मौलिक अधिकार है।

पाँचवें आठ के युग में प्रत्येक देश यह चाहता है कि उसके सिद्धान्तों और विचारों का अधिकतम अधिक बतकरण दूसरे देश करें। यह आकांक्षा भारत की भी थी। भारत चाहता था कि एशिया के स्वतंत्र राष्ट्रों में लोकतंत्र के सिद्धान्तों के आधार पर आर्थिक व्यवस्था कायम हो न कि उपनिवेशवाद इस तरह के राजनीतिक और आर्थिक विचारों के पतन में बाधक सिद्ध हो न लगे। पुराने पराधीन उपनिवेशों में उपनिवेशवादियों की ऐसी भाव के टट्टी मिल गयी जो प्रतिस्पर्धा तथा सामन्तवादी व्यवस्था का कायम रखने में अपने मानवों के साथ सहयोग करने के लिए तयार थे। साम्राज्यवादी देश अपने स्वयं साधन के लिए तथा पराधीन रूप से आर्थिक गुलामी करने के लिए ऐसी तरीकों का पूरा समर्थन करते रहे। स्वयं देशों में एशिया के विकास के लिए यह बन्त बड़ा बाधा थी और इस कारण भी भारत उपनिवेशवाद का विरोध करने को बाध्य हुआ।¹

उपनिवेशवाद विरोधी नीति का स्वरूप :—भारत मुख्यतः पश्चिमी यूरोप के देशों के उपनिवेशवाद का विरोधी रहा है। उसने ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड, पुर्तगाल, बेल्जियम तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राजनीतिक और आर्थिक साम्राज्यवाद का विरोध किया है। इसके लिए भारतीय नीति पर पत्राचार का भारी बोझा पड़ा।

1 M S Rajan *India in World Affairs* 1954 56 P 42.

2. जहाँ तक ब्रिटेन के उपनिवेशवाद का प्रश्न है, वह कारणों से भारतीय देशों की नृत्ता में परभाव का पावन है जिसका विवरण हम आगे करेंगे।

है। पश्चिम तथा भारत के कुछ विद्वान और राजनीतिज्ञ यह कहते हैं कि भारत केवल पश्चिमी साम्राज्यवाद का ही विरोध करता है तथा साम्यवाद-उपनिवेशवाद पर मोन रुकता है। तीसरे विश्व-युद्ध जब खतम हो रहा था तब साम्यवाद ने पूर्वी यूरॉप के देशों (हंगरी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, पूर्वी जर्मनी, अल्बानिया और रूमानिया) का नात्सी (Nazi) दासता से मुक्त किया और उन देशों की कम्युनिस्ट पार्टियाँ का समर्थन करके उन्हें वहाँ साम्यवादी व्यवस्था कायम करने में मदद की। अपनी सुरक्षा के लिए उसने कई उपाय किये। इन बातों को देखकर यह कहा जाने लगा कि पूर्वी यूरॉप के कम्युनिस्ट देश स्वतंत्र नहीं बल्कि सोवियत संघ के उपनिवेश बन गये हैं। इस आधार पर सोवियत संघ को भी साम्राज्यवादी देश कहा जाने लगा। आलोचकों का कहना था कि एक तरफ तो भारत पश्चिमी साम्राज्यवाद का जो पार विरोध करता है लेकिन सोवियत संघ के इन नवान साम्राज्यवाद के संघर्ष में वह कुछ भी नहीं जोड़ता लेकिन इस प्रश्न पर भारत को अपनी प्रतिश्रुति व्यक्त करने का कोई औचित्य नहीं था क्योंकि पूर्वी यूरॉप के राज्यों को उसने सभी सोवियत उपनिवेश नहीं माना। सोवियत संघ का इन देशों के साथ बसा सम्बन्ध नहीं था जो पश्चिम के साम्राज्यवादी देश और उनके उपनिवेशों में पाये जाते हैं। साम्राज्यवादी देश अपने नाम के लिए उपनिवेशों का शोषण करते हैं। उपनिवेशों से वे अच्छा माल ले जाते हैं और अपने बन हुए सामानों को उनके बाजारों में बेचते हैं लेकिन सोवियत संघ ने पूर्वी यूरॉप के देशों के साथ इस तरह का कोई व्यवहार नहीं किया। 1945 के पूर्व इनमें भ्रष्ट जमींदारों और पूँजीपतियों का शासन कायम था। सोवियत संघ ने इस पुरातन व्यवस्था के उन्मूलन में उन राज्यों का सहामाँदा करके उनके आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया। इसको मानने से इनकार नहीं किया जा सकता कि साम्यवादी व्यवस्था कायम होने के बाद से पूर्वी यूरॉप के देशों की जनता के रहने-सूने का स्तर मजबूत रूप में ऊँचा उठा है। पूर्वी यूरॉप में साम्यवाद उपनिवेशवाद की बात शीत युद्ध की भाषा में उभरकर थी लेकिन भारत की नीति शीत-युद्ध के पक्ष में पड़ने की नहीं थी। अतएव उसने तथाकथित सोवियत उपनिवेशवाद का सभी विरोध नहीं किया। फिर भी लगभग यूगोस्लाविया पर जब भी साम्यवाद संघ ने किसी प्रकार का दबाव डाला भारत ने उसका विरोध किया और मांगें टीको का समर्थन किया। इसी तरह भारत ने हंगरी में साम्यवाद का विरोध भी किया।

शीत युद्ध के शुरू होने पर पश्चिमी देशों ने यह कहना शुरू किया कि उपनिवेशवाद का अन्तिम व्यवस्था हो गया है और यद्यपि विश्व के समस्त मुख्य समस्याएँ साम्यवाद का हैं लेकिन भारतीय जनता और सरकार इस विचारधारा का समर्थन करने का तैयार नहीं हुईं। 26 अगस्त 1954 को भारतीय संसद में जोरदार एक पत्रित नेहरू ने कहा कि एशिया के लोगों के समस्त मुख्य शत्रु उपनिवेशवाद का है। स्वतंत्रता के नाम पर बोलनेवाले शीत-युद्ध के महारथियों की निन्दा करते

एए उल्लेख कि व एशियावासी की भावना का खान्तरा करन की तयार नहीं है। एक दूसरे अवसर पर बोलते एए उल्लेख पन इस बात का दुहराया और कहा। यह सच है कि उन्निवेशवाद का युग अब समाप्त हो चुका है लेकिन आज भी मसाले के कई भागों में किसी न किमा रूप में वह अपना सर उठान का प्रयास कर रहा है। पश्चिमी देशों के नेताओं ने यह भावना कि साम्यवाद उन्निवेशवाद से अधिक खतरनाक है और इसलिए कुछ समय के लिए उसकी उभार की जा सकती है ताकि साम्यवाद को खत्म किया जा सके। भारत इस विचारधारा में भी सहमत नहीं था। उनका कहना था कि उन्निवेशवाद साम्यवाद के प्रसार का एक कारण हो सकता है। पराधीन राष्ट्र अपनी मुक्ति के लिए साम्यवाद का सहारा लेने लगते हैं। अतएव यदि पश्चिमी राष्ट्र साम्यवाद का विनाश चाहते हैं तो उन्हें सबसे प्रथम उन्निवेशवाद का उन्मूलन करना चाहिए।¹

इण्डोनेशिया में डच साम्राज्यवाद का विरोध — भारत ने भी पश्चिमी उन्निवेशवाद का विरोध किया है। भारत की उन्निवेशवाद विरोधी नीति का एक बड़ा प्रमाण यह है कि 1946 में लाड माउण्टबटन का अध्यक्षता में बनाया गया 'ब्रह्ममन्त्र' नोट की अन्तिम सरकार का एक पहलू था कि उनमें ब्रिटिश अधिकारिता द्वारा नियंत्रित एशिया के प्रांतीयों और उन्निवेशों में अन्तर्गत आनेवाले दवान के लिए बनायी भारतीय फीजों की वापस वला दिया। यह निम्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उन्निवेशवादों के अनुरोध पर ब्रिटिश समय समय पर उन्निवेश किया था।

उन्निवेशवाद के विरुद्ध सक्रिय काम उठान का पहलू अवसर भारत की पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त होने के पहले ही मिला। 17 अगस्त 1945 को जापान के काम सन्तुष्टि के दो दिन बाद डा. मुक्त ने 'इण्डोनेशिया की स्वतन्त्रता की घोषणा कर दो और इण्डोनेशिया गणराज्य' के नाम से नये स्वाधीन 'इण्डोनेशिया गणराज्य' का स्थापना का। यह नाम उन्निवेशों के इण्डोनेशिया में पुनः प्रवेश करने के पहले ही सम्पन्न हो गया। हालांकि (जिसका इण्डोनेशिया उन्निवेश था) उस स्थिति की मानने के लिए तयार नहीं हुआ। उसने 'इण्डोनेशिया गणराज्य' के विरुद्ध उन्निवेश कार्यवाही शुरू कर दी। 20-21 जुलाई 1947 को उन्निवेश सेनाओं ने इण्डोनेशिया पर पुनः अधिकार स्थापित करने के लिए जावा और सुमात्रा पर हमला कर दिया।

1. B. H. D. ... bad and are not ... a way ... colonialism is not abolished soon it might encourage Communism among the colonial people. Colonialism represents the biggest threat to Asia and Africa and leads to Communism and both of them were of European origin. Both represent physical and intellectual aggression of the West against Asia and Africa. —Nehru quoted in Roeslan Abdulganis *The Asian African Conference in Retrospect Foreign Affairs Report* Vol 4 (1955) p 98

2. Karunakar Gupta *Indian Foreign Policy* p 75

भारत में डच्चा की इन कारवाही की तीव्र प्रतिक्रिया हुई। 28 जुलाई का अंतरिम सरकार के प्रधान मंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र सच से इंडोनीशिया के मामले में अविनम्य हस्तक्षेप करने की अपील की। आस्ट्रेलिया और भारत ने मिलकर सुरक्षा परिषद में इस प्रश्न का उठाया और परिषद को सलाह दी कि कार्यवाही करने पर प्रेरित किया। भारत ने हावर्ड का सरकार के विश्व बहुपक्षीयता का भी संयोजन किया। उसने उनके विमानों का उस समय भारतीय भूमि पर उतरने की सुविधा प्रदान करने से इनकार कर दिया जबकि वे त्रांजिट का दमन करने के लिए इंडोनीशिया की ओर अप्रसर थे। उपनिवेशवाद के विश्व युद्ध भारत का एक प्रबल प्रयास था।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बीच बचाव से हावर्ड और इंडोनीशिया गणराज्य में कुछ दिनों के लिए युद्ध ब्रेक हुआ और इन बीच बार्ता के जर्मिये समस्या का समाधान का यत्न किया गया लेकिन 19 दिसम्बर 1948 की युद्ध बिराम संधि पुनः भंग कर दी गयी और दोनों पक्षों में युद्ध छिड़ गया। भारत ने तत्काल इस प्रश्न को सुरक्षा परिषद में उठाया। इसी बीच 20 जनवरी से 23 जनवरी 1949 तक नयी दिल्ली में इंडोनीशिया की समस्या पर विचार करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन हुआ। यह भारत की प्रेरणा पर हुआ था जिसमें एशिया के पाँच राष्ट्र तथा आस्ट्रेलिया और मजीनेई शामिल हुए थे। सम्मेलन ने इंडोनीशिया में डच कार्यवाही की जोरदार निन्दा की और एक ऐसा लोकमत का निर्माण किया कि इंडोनीशिया में डच साम्राज्यवाद की पुनर्स्थापना असम्भव हो गयी। सचमुच इंडोनीशिया की स्वतंत्रता के लिए भारत के प्रयास बड़े ही सुरुज थे। इसलिए इंडोनीशियावास जवाहरलाल नेहरू को बड़ा मुकूर्त था कि अपनी स्वतंत्रता का दूसरा जनक मानते थे।

मलाया और हिन्दोचिन : स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के प्रारम्भिक वर्षों में मलाया और हिन्दोचिन में भी राष्ट्रवादी आन्दोलनों ने बड़ा उग्र रूप धारण कर लिया। मलाया जो कि ब्रिटिश उपनिवेश था मराठवाड़ी आन्दोलन का नेतृत्व वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी कर रही थी जिसने पूरे जार गोर से पुना और छापामार युद्ध शुरू कर दिया। मलाया के इस साम्यवादी आन्दोलन को ब्रिटिश सरकार कुचनती रही। भारत ने मलाया के राष्ट्रवादी आन्दोलन का समर्थन किया। उसका मत था कि मलाया को साम्यवाद के प्रभाव से बचाने के लिए उसका तत्काल स्वतंत्र कर देना आवश्यक है। ब्रिटिश सरकार ने भी परिस्थिति का आभय किया और मलाया को प्रथम स्वतंत्र करने की नीति को अपनाया और 1957 में मलाया की स्वायत्तता मान ली गयी।

दक्षिण पूर्व एशिया में स्पिन प्रांत के उपनिवेश हिन्दोचिन में भी इसी तरह का राष्ट्रीय संघर्ष वहाँ के कम्युनिस्ट के नेतृत्व में शुरू हुआ। प्रांत इस संघर्ष को कुचनने के लिए दृढ़ सफल था। भारत ने पुना इस संघर्ष का समर्थन किया। इसी तरह

पश्चिम, एरियन (West Indian) के प्रश्न पर भी भारत ने अंगानोशिया का समर्थन किया।¹ पश्चिम एरियन को इंडोनेशिया को वापस मिलाने के लिए भारत संयुक्त राष्ट्रसंघ में निरंतर प्रयास करता रहा।

अफ्रीकी राष्ट्रवाद का समर्थन — पश्चिम विश्व-युद्ध के बाद अफ्रीका में राष्ट्रीयता का अनूर्व जागरण था और सारा महात्मा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उठावता हा उठा। भारत ने लीनिया टयूनिस्विया मारक्का अल्जीरिया गान् कोल् (घाना) साइप्रस आदि देशों के स्वातंत्र्य संग्राम का पूरा-पूरा समर्थन दिया। मोरक्का टयूनिस्विया तथा साइप्रस के मामलों को संयुक्त राष्ट्रसंघ में उठाने में भारत ने प्रमुख भाग लिया।

अफ्रीका देशों के स्वातंत्र्य संग्राम में भारत ने अल्जीरिया के प्रश्न पर गहरी रुचि का प्रदर्शन किया क्योंकि वहाँ दोनों ओर से (राष्ट्रवादी अल्जीरियावादी तथा फ्रांसीसी साम्राज्यवादी शासकों) बहुत बड़ा पमान पर हिंसात्मक कार्य हो रहे थे और हजारों-हजार की संख्या में अल्जीरियाई लोग काह-मकाह की तरह प्रतिदिन मारे जा रहे थे। भारत सरकार ने सावजनिक रूप से इस प्रश्न पर अपना विमता व्यक्त की और फ्रांस का सरकार पर जवाब देना कि वह अल्जीरिया की समस्या का शाश्वत समाधान करे। 19०5 में एशिया और अफ्रीका के तरह राष्ट्रों के साथ मिलकर भारत ने संयुक्त राष्ट्रसंघ में अल्जीरिया के प्रश्न का उठाया। अगस्त वर्ष (19०6) में भी संघ में इस प्रश्न का उठाने में भारत बग रहा। उसी वर्ष अल्जीरिया के राष्ट्रवादी नेता का एक प्रतिनिधि दल भारत आया। उस दल ने भारत के सत्रिय सहयोग के लिए अनुरोध किया। इस पृष्ठभूमि में 22 मई 19०5 का अल्जीरियाई समस्या के समाधान के लिए जवाहरलाल नेहरू ने एक पाँच-सूत्री प्रस्ताव रखा। अल्जीरिया के राष्ट्रवादीों ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया लेकिन फ्रांस की सरकार इससे सहमत नहीं हुई। 1962 में अल्जीरिया पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ। उस अवधि में सामान्य रूप से भारत सरकार अल्जीरिया संघर्ष का समर्थन करती रही।

मिश्र के राष्ट्रीय आन्दोलन तथा उन्निवृद्धा विरोधी संघर्ष को भी भारत का समर्थन मिलता रहा। पश्चिम विश्व-युद्ध के समय अंग्रेजों ने 1936 के अंग्रेज-इंग्लिशियन संधि (Anglo-Egyptian Treaty) के अन्तर्गत स्वयं नहर क्षेत्र और मित्र के बीच भू-भाग में द्वितीय सन्धि रख दिया। युद्धांश मित्र की सरकार ने उन मामलों का वापस मुनान का माग था। जब द्विज ने ऐसा करने में अनाकाना हा ता

1. हंगड ने ता इंडोनेशिया को स्वतंत्र कर दिया लेकिन पश्चिम एरियन पर उसने अपना आधिपत्य कायम रखा। यह स्थानाधिकार कि इंडोनेशिया स्वतंत्रिवाद के इस व्यवस्था का अपना समर्थन मित्रों का प्रयास करे। इस भू-भाग को पान के लिए इंडोनेशिया का वर्गें तक प्रयास करना पड़ा और 1964 में इका उ इस वापस लिया।

मिस्र के राष्ट्रवादी सत्त्व सक्रिय हो उठ और अंगरेजी सेना व सिवाप छिन्नपट बिोह हाने लग। मिस्र में ब्रिटिश विरोधी भावना यो उग्र हो गया। इस समय सचर्य के दौरान भारत ने मिस्र का समर्थन किया और कटनीतिक सूत्रों के जरिये ब्रिटेन पर दबाव डाला कि वह मिस्र से अपनी सेना हटा ले। 1954 में ब्रिटेन और मिस्र में एक समझौता हुआ और मिस्र के भू भाग से ब्रिटिश सेना हटा ली गयी।

पुन 1956 में स्वेज नहर राष्ट्रीयकरण के बाद ब्रिटिश और फ्रांसीसी सरकारों ने मिस्र पर हमला कर दिया। भारत ने इसका प्रबल विरोध किया। भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में इस साम्राज्यवाद का मजबूतकरण कहा गया। इस अवसर पर मिस्र को भारत से वसी सहायता मिली जसी सहायता किसी अन्य देशों से नहीं मिली।

साहस्रसंयम सम्बंध में भारत ने तुर्की तथा यूनानियों में विभाजन का विरोध करते हुए इसका शासन द्वीपवासियों को सौंपने पर बल दिया। भारत ने कयद्या पर अधिकार जमान के अमरीकी प्रयास का भी विरोध किया। इस प्रकार ब्रिटेनी सत्ता से मुक्ति पान के लिए विश्व में जहाँ कहीं भी राष्ट्रवादी आन्दोलन हुआ भारत ने उसका समर्थन किया।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के संरक्षित प्रदेश और भारत :—भारत ने शुरू से ही संयुक्त राष्ट्रसंघ के ट्रस्ट (Trust) में रहे हुए संरक्षित प्रदेशों का भविष्य में रुचि ली है। निम्नलिखित एक ऐसा ही प्रदेश था जिसको पूर्ण स्वतंत्रता दिलाने में भारत का प्रयत्न बढ़ा ही स्तुत्य रहा है। भारत ने संरक्षित प्रदेशों (Trust territories) का प्रशासन के संबंध में संयुक्त राष्ट्रसंघ के पूरे नियंत्रण और निरीक्षण का समर्थन किया है। इस बात पर भी बल दिया है कि स्वायत्त न करनेवाले प्रदेशों (Non self governing Territories) का शासन चाटर के सिद्धांतों के अनुसार किया जाना चाहिए इस पर शासन करनेवाली साम्राज्यवादी शक्तियाँ को संध के प्रति उगी प्रकार उत्तरदायी होना चाहिए जैसे संरक्षित प्रदेशवाली शक्तियाँ अपने संरक्षित प्रदेशों के लिए हैं। भारत अखंडस्वासी प्रदेशों का सम्बंध में सूचना प्राप्त करनेवाली संयुक्त राष्ट्रसंघ की समिति (U N Committee on Information from Non self Governing Territories) का 1958 से 1961 तक का लिए अध्यक्ष चुना गया। 1958 में भारत का पश्चिमी समोजा भेज जानवाने निरीक्षक मण्डल का प्रधान तथा पश्चिमी अफ्रीका जानवाने निरीक्षक मण्डल का सदस्य चुना गया।

1957 से उपनिवेशवाद का प्रति भारतीय नीति :—समय का सदेश रहा कि भारत की प्रारम्भिक नीति उग्र रूप से उपनिवेशवाद विरोधी थी। कुछ संशय का विचार है कि 1957 के बाद से भारत का उपनिवेशवाद विरोधा जोग बहुत बड़ा पड़ गया। प्रोफेसर नॉर्मन पामर ने इस mellowing of Indian attitude कहा

है¹ और 'एनिक्वायल' की धाराधना वह प्रयत्न थी जवान स करने गया। इस तथ्य से समझने में कई उगहरण प्रस्तुत किये गये हैं। मनाया में बर्मा का जनता के स्वातंत्र्य प्राप्ति का बुचन के लिए जब ब्रिटिश सरकार ने मनाय से फौज मगाया तो भारत सरकार ने उन फौजों का खनन का से गुजरने दिया। वही भारत सरकार का इंग्लैन्डिया का राणा का जन का बुचन के लिए तावासे जहां का जन से से बायुमाय नहा दिया था। यह वस्तुतः भारत का 'एनिक्वायल' विरोधा नाति में एक स्पष्ट विरोधाभास था। भारत के समुनिपय का बड़ा कभी धाराधना का और सामान्य रूप से उसका उचित टागना बना करि था। मनाया के स्वाधानता सुप में कम्युनिस्ट अंगा से और इस कारण भा सम्भवतः भारत सरकार ने ऐसा निणय किया हा। राष्ट्रमन्त्र के जवान्नीय सत्यता ने भा सम्भवतः भारत का ऐसा करने का विवय किया हा। यह हमारे समय का एक बन्त बड़ा विरोधाभास है कि मनाया में ब्रिटिश द्वा का भारत से निष्पता राज लृष्टा जतना क्रिन् का अमीजी सुनिक् गुग से सम्मिन्ति हान से भा नहीं मित।

एक दूसरा उदाहरण अंग्नीगिया है। जिस समय अंग्नीगिया के राजवाणी फ्रांसिसा साम्राज्यका के विनाफ अपना राणाय मुक्ति सुषय बना रहे थे उस समय उन्होंने एक उत्तम अंग्नीगिया सरकार का स्थापना कर ला था। इस सरकार ने अंग्नीगिया के लोगों से मायता प्राप्त करने को सटा व्यक्त गा। इस तरह का अनुपेय टागेन भारत सरकार के समर्थ भा रहा। उन्ने विवाम था कि यदि भारत सरकार इस अंग्नीगिया सरकार का मायता प्राप्त कर ता तो उनक राणाय मुक्ति सुषय का और अधिक बन मिता तकिन भारत सरकार ने इस सरकार का अपनी मायता नहीं दा। (चोन मित प्राप्ति का न तरवान सम सरकार का अपनी मायता दा था से) भारत सरकार कई कारणा मुक्रम की मुद का नाराज करा नहीं खान्दा था और इस कारण वह अंग्नीगिया के लोगों का पूरा समर्थन करने में विविर रहा था। भारत के हक में इसका परिणाम जटा नहीं गुता। अफ्रिका के लोगों से इसका लोकप्रियता बन्त बट गया और खान ने इस स्थिति से पूरा जान स ला।

1961 से भारत का 'एनिक्वायल' विरोधा भाग और भी टाग पढ गया। पहन भारत 'एनिक्वायल' का विश्व की सभा सम्प्राका का ड मानता था और

1 On the one hand extreme doctrine anti colonialism continues to shape the attitude of the Indian Government and the Indian people and on the other hand India had to support a policy of gradualism blatantly and shown a case of sober responsibility on the question of colonialism —Norman D. Palmer Indian Attitude to Colonialism *Orbis* Vol I 1957 pp 234-35

2 Roland Senal *Crisis of India* pp 267-68

किसी भी मूल्य पर इसके साथ समझौता करना जो तयार नहीं था। जब भी मोका आया उसने दृढ़तापूर्वक 'उपनिवेशवाद' का विरोध किया। अक्टूबर 1961 में भारतीय विमानों ने इस उद्घाटन का परिष्कार कर दिया। इसका सफ़र सितम्बर 1961 में हुए सटस्थ रायों के संयोजित सम्मेलन में मिला। सम्मेलन में बोले हुए चीन के समर्थक 'इण्डोनीशियाई' राष्ट्रपति सुन्दर ने कहा कि चीन का वर्तमान जनमत हमसे यह अपेक्षा करता है कि हम यह विश्वास करें कि अंतर्राष्ट्रीय सन्तुलन और सन्तुलन का वास्तविक स्तर महानिर्णयों का प्रतिफल है। मैं इसे यथार्थ मानता हूँ। वर्तमान में यदि कोई सन्तुलन है तो वह स्वतन्त्रता और 'पाप' की तथोक्त सन्तुलन तथा उपनिवेश का भी पुराना गतिमत है।

स्पष्ट है कि डॉ. सुबुष ने 'पाप' और 'सन्तुलन' का उद्गम सद्दान्तिन मतभेद या सीत युद्ध को न मानकर उपनिवेशवाद को माना। इस विषय पर उसी सम्मेलन में पण्डित नेहरू ने उपनिवेशवाद के विरोध को प्राथमिकता न देकर 'पाप' की समस्या को महत्व दिया। उन्होंने कहा कि साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद प्रजातीय विभेदवाद और अन्तर्गत की सभी अन्य बातें अंतर्राष्ट्रीय सन्तुलन के समक्ष नगण्य हैं क्योंकि यदि छिन्न जाता है तो ये सब व्यर्थ हो जाते हैं। अन्तिम में प्रतिनिधियों और उसी जनता को सम्मिलित नहूँ के विचार पर नहूँ आये हों। क्योंकि पराधीन व्यवस्था के लिए तो पूर्ण सुखमय स्तर का कोई महत्व नहीं है। अतः लिए स्वतन्त्रता का प्रश्न ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है।

इस विमर्शण से यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत ने उपनिवेशवाद का विरोध करना छोड़ दिया है गंगा होगी। विदेश के रूप में उपनिवेशवाद का विरोध भारतीय विदेश नीति का महत्वपूर्ण बना हुआ है यद्यपि हम पर गढ़ने की ओर आगे बढ़ने का अवसर कम हुआ है।

उपनिवेशवाद के प्रति भारतीय नीति में इस परिवर्तन के कई कारण बताये गये हैं। एक बात यह भी जाती है कि विद्यमान दशक में साम्राज्यवादी राज्यों की दृष्टि यादृच्छिक मूल्य कम हो गई है। एतत्तः उपनिवेश स्वतन्त्र हो गये हैं और जो सन्तुलन है वह भी सन्तुलन करने के लिए काम लगाये जा रहा है। साम्राज्यवादी दशक अन्तिम में यह माना जा रहा है कि उदात्त विचारों को आत्मनिर्णय का अधिकार मिलना चाहिए। द्वितीयतः भारत किसी भी समस्या को दानि

1 Imperialism colonialism racialism and the rest—things which are vitally important—a somewhat overshadowed by the crisis. For if war comes all else for the moment goes.

—Jawahar Nehru *India in the World* September 4 1961

2 Even if the alleged mellowing of the Indian attitude (towards colonialism) is true could it not be largely a reaction to the mellowing of the once adamant attitude of the colonial powers towards demands for self-determination

—M. S. Rajan *Indian World Affairs* 1951-56 p. 43

पूर्ण ग सं सुवर्णान का समर्थक है और वह चाहता है कि उपनिवेशवाद की समस्या का समाधान भी इसी तरह हो। एक समस्या का किसी तरह और किसी उपाय से समाधान करने भारत और सम्मार्ण उप न करना नही चाहता। जसा कि नहरे न कहा था। अपने तरीके से हम समस्या (उपनिवेशवाद) का उन्मूलन करना चाहते हैं, लेकिन उस प्रक्रिया को उग्र तराको से पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए हमनाम आज क उपनिवेशवाद क बिबिध पहनथा की आलोचना नहीं करते चते ताकि दुनिया म मनमुटाव तनाव और संघर्ष में बढि हो" में समझता ह कि यह सही तरीका है। हमनोर्गो की अन्तराष्ट्रीय समस्याओं क "यापक रूप को समझना हागा और ऐसे काम से बचना होगा जिस एक समस्या के समाधान के बाद उस आघ दजन से भी अधिक समस्याए प्रकट हो जाय।¹

भारत मे फ्रांसीसी तथा पुर्तगाली उपनिवेशों की समस्या

गतिपूण दग से उपनिवेशवाद की समस्या के समाधान क सिद्धांत में भारत का विश्वास इतना प्रबल था कि उमका अपनी भूमि पर से उपनिवेशवाद के अवधार्यों का मिटान में लगभग चौंह वर्ष का समय लग गया। अगस्त 1947 म भारत स्वतंत्र हुआ और अजरज हमारे देश से चन गये। लेकिन भारत का भू भाग पर उसक बाद भी कुछ फ्रांसीसी और पुर्तगाली उपनिवेश रह गये थे। फ्रांस क अधीन पाण्डिचरी, कारीकल च इनगर मंगम और माही तथा ततान के अधीन गोआ, डायन और डगू के क्षेत्र बच रहे थे। भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन मुख्यतः ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति के लिए चलाया गया था किं भा य, उम्मी की जाता थी कि जब अजरज भारत न चले जायेंगे तो फ्रांसीसी और पुर्तगाली भी उनका अन्तर्करण करते हुए उपरोक्त वस्तियों पर से अपना आधिपत्य समाप्त कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और तब भारत इह मुक्त करने का बात साचन गया। ऐतिहासिक भौगोलिक आर सांस्कृतिक सभी दृष्टिया से ये प्रदे भारत क अग य और यह विविध लग रहा था कि भारत का मुख्य भाग उपनिवेशवाद म मुक्त हो जाय और कुछ भाग पर विदगी गसन बना रह। सामरिक दृष्टिकोण से भा इन प्रग्ता का भारत के लिए महत्व था। फ्रांस और

1 In our own way we are trying to put an end to it (colonialism) But we realise that this process will not be helped by adventurist tactics. We do not therefore go about merely condemning this or that aspect of present day colonialism and thereby increasing the ill will and conflicts of the world. ... I am sure that this was the right approach. We have to take a larger view of international problems and not try to solve one problem at the expense of creating half a dozen more difficult ones.

—Jawaharlal Nehru *Congress Bulletin* Quoted in M S Rajan op cit

तैंगान इन जगहों में अपना अपना सैनिक अड्डा बना रहे थे जो भारत की सु दाय के लिए खतरा पड़ा कर सकत थे। पुन ये बस्तियाँ तस्ली (Smuggling) का अड्डा बन गया थी जिनका प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा था। इन परिस्थितियों में भारत के लिए इन बस्तियों का मुक्त करने का बात साबना विद्वुन स्वाभाविक था।

फ्रांसीसी बस्तियाँ और भारत—भारत सरकार ने प्राप्त आर तगान की सरकारों स न्न बस्तियों के सम्बन्ध में वार्ताएँ करने का आग्र किया। पुतगाल ने किसी तरह की वार्ता प्रारम्भ करने से नकार कर दिया लेकिन प्राप्त ने घाटा समय और समझौतारी से काम लिया। चन्नगर में 1949 ई में जनमत संग्रह हुआ और उसके परिणामों के आधार पर जून 1952 ई में यह क्षेत्र पूरा तरह भारतीय मध्य में मिला लिया गया। नवम्बर 1954 ई में पाण्डिचेरी बारीकन भाड़ी तथा यनाम की भी प्राप्त की सरकार ने भारत को सुत कर दिया। इन तरह भारत में फ्रांसीसी बस्तियों की समस्या का समाधान सतोपजनक तौर पर हुआ गया।

गोआ की समस्या।—लेकिन पुतगाली बस्तियों के साथ ऐसी बात नहीं हुई और इनके लिए भारत को चौद वर्षों तक मध्य के साथ नृत्तजार करना पड़ा।

सोनेहवी गताया में ही गोआ डामन और डयू पर पुतगाल ने अधिकार कायम कर लिया था। जब भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन में न्न बस्तियों की जनता में प्रभावित होने लगे और उहने भी अपनी मुक्ति के लिए सघन युद्ध किया तो पुतगाली गायन ने उसका बड़ा कर रता से दमन घुट किया। 1949 ई में भारत सरकार ने निम्न में अपना दूतावास खोला और 1950 ई में अपने गोआ आर् के हस्त तरण की वार्ता पुतगाली अधिकारियों से चनायी लेकिन सानाजार के दामन ने गाना की स्वतन्त्रता और भारत के साथ समता की आधार मानकर वार्ता करने से इकार कर दिया। अतएव धन्य होकर जुलाई 1953 ई में भारत ने पुतगाल के साथ आना कटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद कर लिया। 1955 के लगभग गोआ और भारत का जनमत संग्रह हो उठा। गोआ के साथ भारत की एकता की भावना ने देश के जनमत को इतना उल्लिख पहले भी नहीं किया था। इसके पन्स्वरूप 1955 में भारत का सभी राजनीतिक पार्षा न एक सभाग्रह आ गेन का आयोजन किया जा रहा था स्वयसेवका ने गोआ में गान्तिपूण प्रवण करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी लेकिन पुतगाली अधिकारियों ने घणित तरीका से इस सभाग्रह के विरुद्ध अपना दमनात्मक कारबाया शुरू कर दी। इस सभाग्रह में धनीय भारतीयों के प्राण गये सो से भी अधिक घायन हुए और हजारों लोग गिरफ्तार कर पुतगाली जेलों में ठ स दिये गये। पुतगाल द्वारा इस तरह की उत्तजनात्मक कारबाया की जा रही थी और भारत सरकार का विरोधा काम नहीं उठा रही थी। न्न कारण उसकी नीति की निना होने लगी। स्वतन्त्र भारत में गोआ जमे बिन्नी अ की अस्थिति न केवल देश की साबभौम सता का भयकरतम अमान था बरन इससे देश की सुरता के लिए भी गम्भार खतरा उत्पन्न हो रहा था। यह भी क

अफ्रीका एवं दक्षिण-पश्चिम एशिया में प्रवासी विभेद अरब सीमा पर पहुँचा हुआ है। यहाँ की गरीब सरकारें अपने चमड़ेवाले व्यापारियों और प्रवासी भारतीयों पर प्रजाति एवं रंगभेद के नाम पर भी अत्याचार करती रही हैं। भारत ने इस नीति का जोरदार विरोध किया। यह विरोध केवल मानवता के सिद्धांत पर ही आधारित नहीं है। भारत का कहना है कि रंगभेद की नीति से अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ना है और यह अंतर्राष्ट्रीय न्याय का एक मूल सतित्व है।

दक्षिण अफ्रीकी संघ और प्रवासी विभेद — इस क्षेत्र में भारत की राजीव विद्रोहप्रिया दक्षिण अफ्रीका में हजारों हजारों की संख्या में भारतीय निवास करते हैं और उनका मातृ प्रजातीय विभेद का आधार पर घोर अत्याचार होता है। दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों की समस्या बहुत पुरानी है। इस समस्या की उत्पत्ति का वजन हम इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में कर चुके हैं। प्रवासी भारतीयों ने महात्मा गाँधी के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका सरकार के विरुद्ध एक अवरदस्त आन्दोलन चलाया था जिसका अंत 1911 के गाँधी स्मूट्स समझौता (Gandhi Smuts Agreement) से हुआ था। इस समझौते में इस समय का एक अध्याय समाप्त हुआ।

1919 से 1945 तक के काल में भारतीय समस्या—प्रथम विश्व-युद्ध के काल में दक्षिण अफ्रीका के प्रवासी भारतीयों की समस्या से सम्बन्धित ऐसा कोई विशाल घटना नहीं थी जिसका उल्लेख यहाँ किया जाय। लेकिन युद्ध के समय होते ही दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने पुराने प्रवासी भारतीय विरासी नीति का अवनमन शुरू किया और कई ऐसे कानून बन जिसके कारण भारतीयों का जीवन कष्टमय हो गया। जीवन के हर क्षेत्र में रंगभेद और पृथक्करण (Apartheid) के सिद्धान्त को लागू किया गया।

स्मरणीय है कि इन समय भारत राष्ट्रसंघ के एक संस्थापक बन चुका था। राष्ट्रसंघ अस्तित्व की द्वितीय अधिवेशन में भारतीय प्रतिनिधि जेनिब में गाँधी ने इस प्रश्न को उठाया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सरकारी तौर पर दक्षिण अफ्रीका का प्रश्न उठाने का यह पहला मौका था। इसका बालू लगातार कई वर्षों तक यह प्रश्न उठता रहा और भारतीय प्रतिनिधि न अस्तित्व की मंच पर दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध भारतीयों पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाता रहा।

इसी तरह यह प्रश्न समय समय पर होवाने लगे लेकिन कार्यक्रम में भी उठने लगे। दक्षिण अफ्रीकी सरकार की नीति से भारतीय लोग नाराज हो रहे थे और इस कारण ब्रिटिश भारतीय सरकार बहुत चिन्तित थी। अतएव इंग्लैंड में भारतीयों के प्रतिनिधियों का यह कहा जाता था कि वे प्रवासी भारतीयों का समर्थन को सम्मेलन में विशेष रूप से उठाव। भारत सरकार ने स्वयं दक्षिण अफ्रीका सरकार पर दबाव डालना शुरू किया। अन्त में समस्या के समाधान के लिए दक्षिण अफ्रीका

संयुक्त राष्ट्रमण्डल में दक्षिण अफ्रिकी अल्पसंख्यकों का प्रश्न — दक्षिण अफ्रिका की रणभेद नीति की भारत में बड़ी ताज़ा प्रतिप्रिया हुई। भारत ने अपने गाँधी स्मृतिसममोता तथा कण्टाग्न सममोता दोनों का उल्लंघन माना और दक्षिण अफ्रिकी सरकार से इस नीति का परित्याग करने को कहा। लेकिन दक्षिण अफ्रिका ने इस पर ध्यान नहीं दिया और अपनी पूर्ववत् नीति पर चरता रहा। फलतः 1946 के प्रारम्भ में भारत ने उसके साथ अपने सारे यातायात सम्बन्ध विच्छेद कर दिये तथा भारतीय उच्चायुक्त (High Commissioner) को वापस बुला लिया। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्रमण्डल के दो सम्मेलन राज्यों के बीच संधि की स्थिति उत्पन्न हो गयी। अतएव संयुक्त राष्ट्रमण्डल के चार्टर की 10वाँ तथा 14वो धाराओंके अंतर्गत 22 जन 1946 को भारत ने इस सम्मूह विवाद को संधि के साधारण सभा में पेश कर दिया। इस प्रकार दक्षिण अफ्रिका के प्रवासी भारतीयों की समस्या में एक नया अध्याय शुरू हुआ।

1946 का साधारण सभा के अधिवेशन में भारत ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें कहा था कि दक्षिण अफ्रिकी सरकार की रणभेद की नीति मानव के मौलिक अधिकारों का न्यूनन है और इसलिए यह चार्टर का भी उल्लंघन करता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय संधि की सम्भावना भी है। अतएव दक्षिण अफ्रिका की सरकार इस नीति का परित्याग करके चार्टर की भावनाओं का आदर करे। दक्षिण अफ्रिका के प्रतिनिधियों ने इस प्रस्ताव का घोर विरोध किया। उसका कहना था कि दक्षिण अफ्रिका में प्रवासी भारतीयों की समस्या या रणभेद की नीति उसका आंतरिक मामला है जिसमें संयुक्त राष्ट्रमण्डल को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। बू कि दक्षिण अफ्रिका को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ब्रिटेन का समर्थन प्राप्त था इसलिए यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं हो सका।

1957 तक संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा के सभा अधिवेशनों में दक्षिण अफ्रिका से सम्बन्धित प्रस्ताव भारत और अन्य अफ्रो एशियाई देशों के समर्थन से पेश किया जाता रहा लेकिन उनका कोई नतीजा नहीं निकला। दक्षिण अफ्रिकी सरकार ने इस विषय पर घातक बर्तन से साफ-साफ इन्कार कर दिया। 1956 में दक्षिण अफ्रिकी सरकार के प्रतिनिधि ने यह कह दिया कि अगले वर्ष से वह संयुक्त राष्ट्रमण्डल के साथ किसी क्षेत्र में सहयोग नहीं करेगा। भारत ने दक्षिण अफ्रिकी सरकार से अपना राजनयिक सम्बन्ध तोड़ दिया और दक्षिण अफ्रिका ने संयुक्त राष्ट्रमण्डल को छोड़ दिया। इसके उपरान्त यह सारा प्रश्न सट्टाई में डाल दिया गया। किन्तु भारत में दक्षिण अफ्रिका उसकी रणभेद तथा प्रजातीय भेदभाव की नीति का कोई खर्चा नहीं होती। यह भारतीय विदेश नीति की एक घोर असफलता मानी जायेगी।

भारत और एशिया अफ्रिकी देशों का संगठन

(India and Afro Asian Solidarity)

अन्तर एशियाई सम्मेलन (1947)।—एशियाई देशों को संगठित करने में भारत की इच्छा बहुत पुरानी है। स्वतन्त्रता उपान्त के समय से ही जसा कि हम इस

दिया कि एणिया व दोनों पर यूरोपीय उन्निवेशवाद की सादे रहना अब असम्भव है।

बाइ ग सम्मेलन — इण्डोनीगिया की समस्या पर विचार करनेवाला सम्मेलन का एणियाई सम्मेलन एणिया व द्वितीय में एक वतन बिन्दु माना जा सकता है। इसकी सफलता न इस बात की सिद्ध करे कि यदि एणिया व राज्य एक सूत्रे व साथ सम्मेलन करते रहें तो उनकी अधिगत समस्याओं का समाधान हो सकता है। अतएव उसी समय से एक दूसरे सम्मेलन की आवश्यकता में गूँस की जाने लगी। इसी समय जनवरी 1954 में नवा व प्रधान मंत्री सर जान कोटेलवाला भारत आये और उनका सुभाव पर बर्मा नवा भारत इण्डोनीगिया तथा पाकिस्तान व प्रधान मंत्रियों का एक सम्मेलन 28 अप्रिल 1954 को कोलम्बो में था। यहाँ पर अनेक प्रस्तावों पर विचार हुआ और यहाँ पर निर्णय लिया गया कि एणिया और अफ्रीका के देशों का एक वल्लु सम्मेलन चलाने का आयोजन किया जाय। इस सम्मेलन के स्वयं पर विचार करने के लिए इस पीछे गये व प्रधान मंत्रियों का एक और सम्मेलन 28 दिसम्बर 1954 को बोरो में हुआ। यहाँ एणिया और अफ्रीका के महाद्वीपों के राष्ट्रों में सभावना और सयोग विकसित करने के लिए और पारस्परिक जाविक सामाजिक और सांस्कृतिक सम्बन्धों एवं विद्युत्ताति और सहयोग में अपना योगदान पर विचार करने के लिए एणियाई और अफ्रीका राष्ट्रों का एक सम्मेलन आयोजित करने का निश्चय किया गया।

इस निश्चय के अनुसार 1955 में 18 अप्रिल से 24 अप्रिल तक इण्डोनीगिया के नगर बोरो में एणिया और अफ्रीका के उत्तरीय राष्ट्रों के प्रतिनिधि एक सम्मेलन में शामिल हुए। ये राष्ट्र थे—भारत पाकिस्तान बर्मा नवा इण्डोनीगिया मलय मूडान गोडकोस्ट सारंगिया इराक लिविया फारस सीरिया तबनान जार्डन मध्य अफ्रीका सघ मरुदी अरब यमन ओ नवान। फाइनल और फिनीशइस ने निमन्त्रण स्वीकार नहीं किया था।

सम्मेलन का उद्घाटन इण्डोनीगिया व राष्ट्रपति सुवर्ण ने किया। अनेक स्वागत भाषण में इनने कहा कि सम्मेलन में य सम्मेलन मानव समाज का माग निर्माण करेगा। मुझे आशा है कि ये इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करेगा कि एणिया और अफ्रीका का प्रारम्भ हो गया है।

सम्मेलन का वास्तविक उत्तरीय प्रयास सबसे अच्छा तथा विस्तारपूर्वक उत्तरीय अंतिम दिन प्रमाणित एवं विकसित किया गया। इन वक्ताओं का मत एक राष्ट्रवर्षीय फंड (U N Fund) की स्थापना तथा बहुपक्षीय व्यापार के आदान प्रदान एवं वित्तमित्र प्रसार के निषाज द्वारा विद्युत् व एणिया एवं अफ्रीका क्षेत्र के जाविक विकास की आवश्यकता पर जोर दिया। नवा एणिया और अफ्रीका के देशों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व से एक अंतराष्ट्रीय अणुशक्ति संस्था (International Atomic Energy Agency) की स्थापना की माग का प्रमाणित भी था तथा उन्निवेशवाद के प्रत्येक स्वरूप—विशेषकर उत्तरी तथा दक्षिण अफ्रीका के

प्रशस्ति प्रदान—का उल्लेख मानवीय सम्मान के विषय कहकर किया जा चुका है।
 ज्ञान में अरब नौकों के अंतरों का समन्वय किया। विश्वज्ञान मन्त्रालय का
 गान्धेपूजा हस्त तथा राष्ट्रमधीय प्रस्ताव का निर्देश करने का जीवन का वात
 परन्तु यह इंडोनायिया राष्ट्र का समन्वय किया। राष्ट्रमधीय सम्मेलन में बद्ध
 तथा प्रक्रिया एवं एशिया का अधिक प्रतिनिधित्व करने का भी निराश्रयता
 प्रभावगता अन्तराष्ट्रीय नियंत्रण में अर्थिक शक्तों के निर्माण तथा ऐश्वर्यश्रुतियों
 के अभावों का दूर करने का प्रकार का तथा गान्धि स्वतंत्रता नागरिक
 अधिकारों के प्रति अन्तःप्रमाण द्वारा सुनिश्चितता सुना गया। एक नया समन्वय
 प्रत्येक राज्य और जाति का समन्वय। बहुमुखी नृपति राष्ट्रमधीय चरण के
 अन्तर्गत व्यक्तिगत तथा सामूहिक गुणों के अधिकार शक्ति प्राप्त होती एवं अन्तः
 मात्राया प्रयत्नों से अन्तर्गत और अन्तर्गत शक्ति प्राप्त होने का समन्वय किया।

27 अक्टूबर 1950 का अवसर सम्मेलन खाने तथा समन्वय कार्य का
 यो निर्देश है। यथा कि एशिया का अर्थिक एक नया अन्तर्गत और
 नया चरण का साधन बन रहा है। यह अन्तर्गत और विश्व अन्तर्गत शक्ति तथा
 गान्धि मुक्तता नहीं बल्कि गान्धि मन्त्रालय तथा गान्धि सहजित्व का
 था। इस नया अन्तर्गत और नया नया चरण का बुद्धि बर्तनवालों में प्रमुख यो भारत के
 अन्तर्गतता नही बल्कि चान के चान्दन्-नन्द इंडोनायिया के गान्धि निन्तर्गतता तथा
 निन्तर्गत के कनन नागरिक।

बाङ्गला सम्मेलन में नया अन्तर्गत एशिया और अर्थिक राष्ट्रों के जीवन में
 एक नया अन्तर्गत और अन्तर्गत का उद्देश्य था। एक नया अन्तर्गत एशिया के पूर्वी
 और मध्य अर्थिक तथा विश्व मन्त्रालय में गूँज रहा। यह अन्तर्गत यह था कि
 एशियावादी और अर्थिक के बाह्य-भारतों गान्धि चान्दन्-नन्द पराधीन नहीं रहेंगे। वे
 अन्तर्गत तथा अन्तर्गत अन्तर्गत का विगम करेंगे। उनका बहुधाया अन्तर्गत अन्तर्गत नहीं वा
 चान्दन्। उन्होंने यह ना नया प्रकार समन्वय किया कि स्वतंत्रता और गान्धि परन्तु
 अन्तर्गत हैं और अन्तर्गत के किसी ना भाग में पराधीनता का अन्तर्गत गान्धि अन्तर्गत
 एक चरण है। ठीक उसी प्रकार अन्तर्गत गान्धि के अन्तर्गत में अन्तर्गत के हर कान में स्वतंत्रता
 के विकास में बाधए पड़ती हैं। इस चरण का अन्तर्गत में अन्तर्गत समन्वय न निन्तर्गत
 करण। अन्तर्गत अन्तर्गतों का पूर्ण बहुधाया और अन्तर्गतों के अन्तर्गत नियंत्रण
 का पूर्ण समन्वय किया और अन्तर्गत राष्ट्रमधीय का विश्व में गान्धि अन्तर्गत रखने के
 एक नया प्रभावगता अन्तर्गत के रूप में मान्यता दी। सम्मेलन ने इस बात पर अन्तर्गत
 प्रकाश दिया कि अन्तर्गत राष्ट्रमधीय और अन्तर्गत एशिया में एशियावादी राष्ट्रों का प्रति
 निन्तर्गत अन्तर्गत है। सम्मेलन में अन्तर्गत राष्ट्र अन्तर्गत रखने के अधिकार का

राष्ट्र रूप से स्वीकार किया गया और यह भी माना कि उद्घमनिगता और सामंजस्य रूप से आगमण के विपरीत अपनी रक्षा करने का समय राष्‍ट्रमय के चार्टर के अनुसार था। अधिकार है पर तु इनके साथ ही यह भी माननी भी दी गयी कि इन प्रकार का सामंजस्य सुरक्षा प्रणाली का बड़े राष्ट्रों के स्वार्थ साधन के उद्देश्यों के रूप में परिणत होने दिया जाये।¹

बाह्य सम्मेलन के परिणामस्वरूप साम्यवादी चीन को एशिया के देशों के मध्य अपनी स्थिति को स्पष्ट करने का मौका मिला। अभी तक चीन के मध्य में तत्काल में बर्फ़ तरह की भाँति भाँति से लिखा बाह्य सम्मेलन में चीन के प्रधान मंत्री चाऊ एन लाई ने एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया जिसने एक वक्ता चीन की गयी सरकार एशियाई देशों में लोकप्रियता हासिल कर ली। चाऊ एन-लाई ने सम्मेलन में लाये गये प्रस्तावों का जोरदार समर्थन किया और बारम्बार कहा कि हम एशियावासी एक ही प्रकार के अस्वाभाविक परिणित रहें हैं और हमारा लक्ष्य भी एक है। हम एशिया और अफिरायासी लक्ष्य ही एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और हमारे रसते रहें हैं। एशिया और अफिरा के हमयोग उपनिवेशवाद की लूट और अस्वाभावों के निवारण हुए हैं और इन प्रकार गरीबी और निष्पक्षता की स्थिति में रहने का लिए मजबूर किये गये हैं। हमारी आवाज जगत दर्जा में है। हमारी महावाक्ताओं का कुछना गया है और हमारा माध्य दस्ता का दया पर निर्भर रहा है। अतएव इन दासता को विरुद्ध विरोध करने का अति गत हमारे पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं है।

चीन के प्रधान मंत्री ने एशिया और अफिरा के राष्ट्रीय आलोचकों का जोरदार समर्थन किया। एशियाई तथा अफिराई देशों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए उन्होंने कोई बखर नहीं उठा रसते जोर दस्तमें उन्हें पर्याप्त उपलब्ध मित्री। चीन का अभी तक अत्यंत देश का एशियाई देशों की भव्ती में प्रवेश पा गया यद्यपि यह भी ताकर यह प्रकट हो गया कि चाऊ एन लाई ने इन तम और अत्यधिक विनम्रताएँ एवं सहयोगात्मक दस्त की पीछे वास्तविक रहस्य कहा था। था के चीन की भाँति। तो स्पष्ट कर दिया कि उसने बाह्य सम्मेलन के प्लेटफार्म को केवल प्रचार के लिए प्रयोग किया था।

बाह्य सम्मेलन प्रारम्भ हो। ने पूर्व पश्चिमी देशों को उसने उद्घमा और लक्ष्यों के लक्ष्य में बहुत सँ दे था। उद्घम था कि पश्चिम के विरोधी तत्त्व सम्मेलन का उपयोग एशिया और अफिरा में पश्चिम विरोधी भाषना को और अधिक उग्र बनाये और सम्भवतः पश्चिमी देशों की बहुत आलोचना करने के लिए करेगे पर तु सम्भवतः की कार्यवाही जित्त जग पर हुई और जित्त समय पूर्व विवेक और निर्णय का परिणाम था। एशियाई देशों के ताओ सम्मेलन के मध्य पर दिया उद्घम था

देशों के मध्य का निराकरण ही नहीं कर दिया बल्कि उनमें यह विश्वास भी पैदा कर दिया कि एशिया के देश उनमें सम्मिलित और रचनात्मक सहयोग करने के लिए तैयार हैं और पुरानी दुश्मनी और बमनय पूर कर विश्व शांति और समृद्धि के द्वार में मजबूत सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं।

समुक्त राष्ट्रसंघ में यह एशियाई राष्ट्रों का सम्मिलित होने का आकांक्षित नज़रना मिला गया था कि वह देशों का विश्व भारत का विकास माना है। जर्मनी-एशियाई-एशियाई से इस सम्मिलन का एक और महत्वपूर्ण परिणाम यह निकला कि समुक्त राष्ट्रसंघ में एशियाई प्रतिष्ठा का एक पूरा नया रूप था जिसके कारण संघ के स्वयं में ही परिवर्तन हो गया। पाँच वर्षों के अन्तर अर्थात् 1960 तक समुक्त राष्ट्रसंघ का साधारण सभा में अफ्रीका तथा एशिया के राष्ट्रों की संख्या पैदा हो गई। इस हानत में संघ का साधारण सभा में एक का भागित्व इस रूप की उम्मीद करने नहीं किया जा सकता था। विश्व के दो विद्वान् वस्तुतः सपास हानवान् प्रस्ताव के लिए एक रास्ता का समर्थन प्रदान किया गया। बाद में सम्मिलन के बाद पाँच वर्षों तक और कई कारणों से भारत इस रास्ता का अग्रणी रहा। भौगोलिक दृष्टि से एशिया में भारत की केन्द्रीय स्थिति है और तत्परता तथा सामर्थ्य का नतीजा के कारण वह एशिया का एक महान् राष्ट्र है। स्वतंत्र होने के बाद उसने आन्तरिक शांतिव्यवस्था का धार विरोध किया। अब एशियाई राष्ट्रों के सामने बलों के सम्मिलन की आवश्यकता है। भारत ने एशियाई राष्ट्रों का अपना स्वयं समर्थन दिया और सामर्थ्यवान् पश्चिम का विरोध किया। 1953 का प्रस्ताव का नीति के विरुद्ध आवाज उठाना पहला देश भी भारत ही था।

ऐसी स्थिति में एशिया की राजनीति में भारत की वही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो गया है। इस कारण भारत पर बिरोध का जवाब देना पर यह आरोप लगाया जाता रहा है कि उनका प्रस्ताव अक्षिण पूर्व एशिया के नष्ट करने का है। नेहरू ने हमेशा इसी महत्वाकांक्षा रखने का खतन किया। फिर भी उसी जि सुप्रसिद्ध ब्रिटिश पत्र द टाइम्स (The Times) ने 2 जन 1953 का एशियाई परिस्थितियों के सामान्य निरीक्षण से यह स्पष्ट हो गया कि भारत का नारायण इस नष्ट को न चाहें किन्तु अन्तराष्ट्रीय दिनों में उन्हें यह नष्ट स्वीकार करना पड़ेगा। समुक्त राष्ट्रसंघ में नका बर्मा इस भौगोलिक और कई कारणों के कारण निषिद्धों के साथ घनिष्ठ सम्पर्क रखते हैं भारत के विचारों का विरोध करने का अनिच्छा रखते हैं। भारत की यह प्रवृत्ति बन गई है कि वह अपने अन्तर्गत का नष्ट किन्तु समूचे एशियाई समुदाय की ओर से दोषी है। इसमें सन्देह नहीं कि कुछ अन्तर्गत में एशियाई दृष्टिकोण का प्रवृत्ति होने में भारत का प्रभाव का एक कारण यह है कि उसने पश्चिमी राष्ट्रों के सामर्थ्य का विरुद्ध एशियाई राष्ट्रों के राष्ट्रीय आन्दोलनों का प्रवृत्ति समर्थन दिया है किन्तु यह स्पष्ट भी महत्वपूर्ण है कि उसने साथ घनिष्ठ सम्पर्क रखने वाले देशों एशियाई देश हैं किन्तु नष्ट और समुदाय का मन

स्रोत भारतवर्ष है। इसी कारण भारत बाहुल्य सम्मेलन के वातावरण में अफ्रो एशियाई देशों के साथ सम्मेलनों में प्रमुख भाग लेता रहा है।

अफ्रिका एशिया समन्वय सम्मेलन

अफ्रिका एशिया समन्वय सम्मेलन (Afro-Asian Solidarity Conference) का अधिवेशन अराजकीय स्तर पर काहिरा (मिस्र) में 19 7 के 26 दिसम्बर से 19 8 की 1 जनवरी तक हुआ। सम्मेलन में दोना महादेशों के अनेक देश एवं औद्योगिक देशों से पाँच सौ प्रतिनिधि आये थे। कुछ राज्यों ने इसका स्वतन्त्र साम्यवादी सम्मेलन इसमें अपना प्रतिनिधि भेजना अस्वाकार कर दिया। ये राज्य थे सायेरिया पाकिस्तान फिलीपाइन दक्षिण वियतनाम मोरक्का मलाया कम्बोडिया और लाओस। सोवियत संघ से यहाँ स्तार्लिन द्वायतया का एक प्रतिनिधि मण्डल आया था। इस सम्मेलन में कई प्रस्ताव विद्ये गये। साम्राज्यवाद उन्निषेध और प्रजाति भ भाव आदि की निन्दा की गयी। इन सभी प्रस्तावों में भारत का मुख्य हाथ था। कतिया कमला युगाण्डा मैडागास्कर सोमालीलैंड आदि देशों की स्वतन्त्रता एवं सार्वभौमिक आत्मनिर्णय की मांग की गयी। उत्तर दक्षिण अफ्रिका एवं उत्तर और दक्षिण वियतनाम मिला देने का समर्थन किया गया। अंग्रेजों और आइरलैंड के सिद्धांत को अरब राज्यों की स्वतन्त्रता का माधक तथा अराजकता का साधक माना जा रहा था। एक अहंता बहा गया एवं संयुक्त राष्ट्रसंघ में साम्यवादी चीन और मंगोलिया का सम्मिलन करना पर जोर दिया गया। काहिरा में संसद के एक स्थायी सत्र का आयोजन करने का भी विषय हुआ। इस सम्मेलन का द्वितीय अधिवेशन अगस्त 1960 में कोमागरी में हुआ।

अफ्रिका एशिया आर्थिक सम्मेलन

यह सम्मेलन 19 8 के 8 से 11 दिसम्बर तक काहिरा (मिस्र) में हुआ जिनमें अफ्रिका और एशिया के बीस देशों से व्यवसाय मण्डल के प्रतिनिधि आये थे। भारत भी इसमें सम्मिलित था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता मिस्र के मन्त्रि रशीद न की। सम्मेलन में दोना महादेशों के आर्थिक सहयोग के लिए एक संस्था—अफ्रिका एशिया आर्थिक सहयोग गण्डन (Afro Asian Economic Co-operation Organisation) की स्थापना की जिसका तात्कालिक कार्यालय काहिरा में रखा गया। गण्डन की परामर्श समिति बनायी गयी जिसमें चीन इण्डोनेशिया थाईलैंड मंगोलिया भारत इराक ग्रीस निजिया पाकिस्तान सूडान और संयुक्त अरब गणराज्य के प्रतिनिधि रहे गये। गण्डन की रूपरेखा तैयार करने का भारत की समिति पर छोड़ा गया। सम्मेलन में दोनों महादेशों के उद्योग धर्मों और वाणिज्य-व्यवसाय की उन्नति के सम्बन्ध में कई दूसरे प्रस्ताव भी पास किये गये। इस सम्मेलन का तृतीय अधिवेशन 30 अगस्त 1960 का काहिरा में हुआ।

वेलफ्रेट सम्मेलन

एशियाई और अफ्रीका महाद्वीपों के तत्सम राज्यों का पहला सम्मेलन सितम्बर 1961 में यूगोस्लाविया के राजधानी बेलग्रेड में हुआ। इसका तत्सम राज्यों का सम्मेलन कहना अधिक उचित है क्योंकि इसमें एशिया अफ्रीका महाद्वीपों के बसने वाले तत्सम देशों शामिल हुए थे। बेलग्रेड सम्मेलन के पहले राष्ट्रपति मुख्तार अब्बाखान ने इस सम्मेलन को बुलान का प्रस्ताव रखा। कम्युनिस्ट चान ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और इस कारण विनाय शाह ने सम्मेलन का आयोजन नहीं हो सका क्योंकि यूगोस्लाविया संयुक्त अरब गणराज्य तथा भारत दोनों चान के विरोधी देश थे। इसी बीच अप्रैल 1961 में राष्ट्रपति शाह संयुक्त अरब गणराज्य के साथ वहीं बेलग्रेड सम्मेलन का निषेध किया गया। 26 अप्रैल 1961 का राष्ट्रपति शाह और शाहीन अब्बाखान तत्सम राज्यों का एक भोज और उन्हें एक सम्मेलन में शामिल होने के लिए निमन्त्रित किया। सम्मेलन की तयारी करने के लिए पहले काहिरा में तत्सम राज्यों के विश्व मंत्रिणा का एक सम्मेलन हुआ (12 जन) तत्पश्चात् 1 सितम्बर 1961 का बेलग्रेड में अब्बाखान तत्सम राज्यों के आमना-समाका सम्मेलन हुआ। सम्मेलन का बुलान के निम्नलिखित उद्देश्य थे —

सबसे पहले जर्मनी की समस्या का लक्ष्य गीत-सुद्ध बनाया गया था और अन्तराष्ट्रीय सम्बन्ध निरन्तर खराब हो रहा था। मुद्दा का गति के लिए देश ही खतरनाक वातावरण उत्पन्न हो गया था। सम्मेलन ने संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ से अनुरोध किया कि वे शात-सुद्ध का वातावरण कम करें और जर्मनी की समस्या का समाधान ढूँढ़ निकालें। हथियारबंदी का ह्रास अमेरिका और सोवियत संघ दोनों को करना जरूरी समझा जा रहा था। सम्मेलन ने इस बारे में सम्बद्ध देशों का ध्यान आकृष्ट किया। लेकिन सम्मेलन का यह उद्देश्य था कि जिस दिन सशस्त्री कायदाहा शुरू हो उसी दिन सोवियत संघ न पुनः परमाण्विक परीक्षण करेगा। फिर भी सम्मेलन ने निश्चय किया कि तत्सम राज्यों का आरंभ एक प्रतिनिधिमंडल संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ नशा जाय और राष्ट्रपति बनने तथा प्रधान मंत्री सूचक से अनुरोध किया जाय कि प्रत्यक्ष बातचीत करे और निरस्त्राकरण प्रारंभ तथा शात-सुद्ध का समाधान करें। सम्मेलन ने इस उद्देश्य पर विचार और निष्कर्ष निकाला कि विश्व शात-सुद्ध का मुख्य विषय रहा। सम्मेलन ने यह विचार व्यक्त किया कि यह तरह का अनिश्चितता तथा प्रस्ताव विनियोजन संयुक्त राष्ट्र के अन्तर्गत के सिद्धांतों का उल्लंघन है और मुद्दा के समाधान दोनों का मूल ही मुक्त किया जाय।

बेलग्रेड सम्मेलन में एशियाई देशों के केवल भारत भाग लेता था। यूनानिया का राष्ट्रपति मुख्तार अब्बाखान का समझौता विचार भी मुनी सुराहिया का जह बताया। उनका कहना था कि विश्व का एकाग्र समस्या अनिश्चितता है और मुद्दा के तत्सम राज्यों का अनिश्चितता के अन्तर्गत के लिए प्रयास करना चाहिए। इसके

विपरीत भारत के प्रधान मंत्री पंडित नेहरू ने विश्व शांति की स्थापना को मुख्य स्थान दिया और इस बात पर उन्हें राष्ट्रपति टीटो तथा कर्नल नासिर का पूरा समर्थन प्राप्त हुआ। इस प्रकार सम्मेलन में दो दृष्टिकोणों में परस्पर टक्कर हो गयी और सम्मेलन विफल होते होते बचा। अंत में निश्चय हुआ कि सम्मेलन के प्रस्ताव को लेकर राष्ट्रपति मुकण तथा टीटो अमेरिका जाय और वहाँ राष्ट्रपति कर्नल से मिलकर उन्हें सम्मेलन के निणयो से अवगत करायें। इस तरह का दायित्व पंडित नेहरू और इनप्रमा को दिया गया जो स्व श्रेय से मित्र मानस्यो गये। बागिंग्टन और मास्सा में शांति के इन दूतों का यथोचित सम्कार हुआ लेकिन वास्तविक राजनीति पर उनका कोई प्रभाव भी पड़ा यह एक सविम्व बात थी।

पश्चिमी राष्ट्र बेनब्रह सम्मेलन से बहुत घाराज थे क्योंकि उनके द्वारा सोवियत संघ की नीति पर सतना औरदार प्रहार नहीं किया गया था जितना अमरीकी गुट की नीति पर। सम्मेलन के महत्त्व को ससार के हर देश में समझा गया और ऐसा प्रतीत हुआ कि दुनिया में एक नयी शक्ति का आविर्भाव हो रहा है। लेकिन सम्मेलन की कार्यवाही ने एगियाई देशों के आपसी मतभेद और फट को भी स्पष्ट कर दिया। उसी समय यह स्पष्ट हो गया कि एगियाई अफ्रीकी देशों को एक शक्तिशाली गुट में संगठित करने का प्रयास अनेक कठिनाइयाँ से भरा पड़ा है और उनके बीच जो दरार है उसको भरा नहीं जा सकता है। कम्युनिस्ट चीन की नीति ने इस मतभेदों का और भी गहरा कर दिया। यद्यपि चीन को इस सम्मेलन में प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हुआ था (क्योंकि वह तत्स्य राय नहीं था) फिर भी इण्डोनीशिया के जरिये चीन का प्रभाव सम्मेलन में काम कर रहा। चीन की विश्वव्यापी महत्वाकांक्षा ने एगियाई अफ्रीकी संगठन और एकता की आगा पर पानी फेर दिया।

काहिरा सम्मेलन

तत्स्य राष्ट्रों का दूसरा सम्मेलन और एगियाई अफ्रीकी राष्ट्रों का पाँचवाँ सम्मेलन 5 अक्टूबर 1964 को काहिरा में शुरू हुआ और 11 अक्टूबर को यह खत्म हुआ। इस सम्मेलन का उद्देश्य तटस्थतावादी शक्ति को विलुप्त करना तथा इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय तनाव खत्म करना था। इस सम्मेलन में भी पुनः नव विचारधाराओं के बीच सघर्ष खपन हो गया और सम्मेलन विफल होते होते बचा। सम्मेलन के अंत में एक बिलम्बित प्रकाशित हुआ जिनमें उपनिवेशवाद के पूर्ण अंत की बात कही गयी। बिलम्बित में हर तरह के उपनिवेशवाद की निन्दा की गयी। यह कहा गया कि स्वाधीन होना 'येक राष्ट्र का अधिकार है और पराधीन देश अपनी स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए उपनिवेशवाद कायदा के खिलाफ सशस्त्र प्रयोग कर सकते हैं। सम्मेलन ने ससार की मुख्य-मुख्य समस्याओं के सम्बन्ध में निम्न निश्चित सिफारिश की

1. राष्ट्रों को अपने आपसी भगड़ू गाँवतूपा दंग से तय करना चाहिए और उन्म शांतिपूर्ण सद् अस्तित्व के सिद्धांत में पूरी आस्था रखनी चाहिए।

कर दिया जाय। साथ ही यह भी निश्चय किया गया कि सम्मेलन होने की पूर्व स्थिति पर विचार करने के लिए 18 अक्टूबर का विन्ग मंत्रियों का एक सम्मेलन हो। इस निश्चय के अनुसार अ-जोयस म विन्ग मंत्रियों का 9वां सम्मेलन शुरू हुआ और अ-जोरिया की समाधारण स्थिति को ध्यान में रखते हुए 1 नवम्बर 1965 को यह निश्चय किया गया कि अफ्रीकी एगियाई देशों का सम्मेलन फ्लिहान अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाय।

अ-जोयस में विन्ग मंत्रियों के सम्मेलन के अस निष्पत्ति से एगियाई-अफ्रीकी संगठन की भावना को गहरी रूप पहुँची। इस निश्चय के बाद अब इस बात पर भी सन्देह होने लगा कि एगियाई-अफ्रीकी संगठन की भावना नामक कोई चीज है भी या नहीं। सम्मेलन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देने से यह निश्चयपरक नहीं कहा जा सकता कि अब एगियाई-अफ्रीकी देशों का कोई सम्मेलन कभी होगा। इसकी सारी जिम्मेवारी चीन पर है। शुरू में जब जन 1955 में पहली सम्मेलन शुरू होनेवाला था तो अ-जोरिया के विरोध से सन् 9 परिस्थिति के कारण इसे स्थगित करना आवश्यक था तो चीन ने इस बात का जो-तो-प्रयास किया कि सम्मेलन पूर्व निश्चित योजना के अनुसार अवश्य हो लेकिन अब नवम्बर में सम्मेलन शुरू करने की बात आयी तो उसने इसका बड़ा बड़ा विरोध किया और यह धमकी दी कि यह सम्मेलन का बहिष्कार करेगा। इस बार निश्चित था कि सम्मेलन में चीन की नाति का भण्डाफाँट होता और एगियाई-अफ्रीकी देशों के बीच बड़ा बड़ा नाम होता। इस अतिरिक्त चीन के मूट में इस समय गति नहीं थी। भारत के साथ युद्ध में हारकर पाकिस्तान पना हुआ था। अण्डोनीगिया में आंतरिक उग्रता हो रहे थे। चीन को अपने इन से दो सहयोगी राशिया के सहयोग मिलने की कोई आशा नहीं थी। अतएव उसने सम्मेलन को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित करने की नीति का अवलम्बन किया और इसमें उसको मफलता भी प्राप्त हुई। एगियाई-अफ्रीकी गुट में पट पैदा करनेवाली चीन की नाति मफल हो गयी और इस प्रकार वास्तविकी भावना का अंत हो गया। इनका भावना पनप सकेगी यह एक सविशेष विषय है।

1966 का तान तटस्थ राष्ट्रा का दिल्ली सम्मेलन

चीन की हारकता से अ-जोयस सम्मेलन की असफलता के बाद एगियाई देशों के संगठन का आगमन को उद्देश्य धरना लगा। अतएव एगियाई देशों को संगठित करने की आवश्यकता फिर से महसूस की जान लगी। भारत ने 9वां अ-जोयस म सम्मेलन उठाया और तीन तटस्थ देशों—भारत, सटुवा, अरब गणराज्य तथा युगास्लाविया के आगनाध्यत का एक सम्मेलन नया किया गया। आयोजित किया। 21 अक्टूबर 1966 का प्रधान मंत्री श्री रा. गांधी राष्ट्रपति नामि और राष्ट्रपति टोटा का सम्मेलन प्रारम्भ हुआ। दोस्तों के घाते में बंधन-मन दोनों देशों के आगनाध्यतों का सम्मेलन इसके पूर्व 1961 में हुआ था। सम्मेलन में यह विचार आया कि रा—11

वियतनाम से बाहरी सेनाओं का हटना बिनबुझ जफरी हो गया है। प्रसिडेंट नासिर ने स्पष्ट किया कि बाहरी शक्ति से उनका मतलब अफ्रीकी गना मे है क्योंकि यहाँ लोगता कि दक्षिण वियतनाम में उनर वियतनाम की सेनाएँ हैं। जहाँ तक वियतनाम का ताल्लुक है वह दक्षिण वियतनाम का ही एक टुकड़ा है और दक्षिण वियतनाम का गृहयुद्ध बुनियादी तौर पर मुद्र है जिसमें दखन देने का कोई अधिकार अफ्रीका को न है।

सम्मेलन में तटस्थता की अनुरोधों का स्वागत भी हुआ। यह बात जोर देकर कही गयी कि दक्षिण अफ्रीका की परिस्थिति में भी तटस्थता का मूल्य खोया नहीं है। मुख्य प्रश्न यह है कि उसे किस तरह अधिक मजबूत और प्रासंगिक बनाया जाय। चीना नज़रों का मत था कि छह वर्षों में तटस्थता में यकीन रखने वाले देशों की संख्या घटी नहीं बड़ी ही है। चीनी नेताओं ने यह भी स्वीकार किया कि जाति के प्रयत्न में भी वृद्धि हुई है। यह सही है कि तटस्थ देशों को अपने हितों बढ़ाये हैं मगर इसका बावजूद तटस्थता आज भी अपनी आज्ञा की सुरक्षा रखने का एकमात्र तरीका है। इसके अलावा इन चीना देशों के आपसी हितों की समस्याओं पर भी चर्चा हुई और यह पाया गया कि जहाँ तक अधिक चीना का ताल्लुक है चीना में और अधिक सहयोग होना चाहिए। चीनी नेताओं ने मुझ को दिया है कि इन देशों के अर्थ मजबूती का एक सम्मेलन हो जो इस बात पर विचार कर कि अपने आर्थिक स्रोतों का किस तरह विकास किया जाय जिससे परनिर्भरता का सबट कम हो। इस सम्मेलन का अर्थ-व्यवस्था सम्बन्धी नहीं है छोटे देशों के लिए मांग पैदा साबित हुए। अबतक साम्राज्यवाद से बेचन राजनीतिक स्तर पर लगाई सही जा रही है लेकिन अब उसके विपक्ष आर्थिक माया खाने की जो इच्छा तीन देशों ने जाहिर की वह साम्राज्यवाद का सन्ध कर्षा में कम हो और नियम बनानेवाली हो।

सितम्बर 1970 में एगिप्ताई अफ्रीकी देशों के मगठन आन्दोलन और तटस्थतावादी को एक जोर धक्का लगा जब संयुक्त अरब एमिराज का राष्ट्रपति अहमद नासिर की एकाग्र मृत्यु हो गयी। राष्ट्रपति नासिर तटस्थता की प्रतिबद्धता का प्रयास करते रहे थे। कहना पड़ेगा कि उनके निधन से पश्चिम के बाद तटस्थता का एक और मगठन हुआ गया।

1970 का लुसाना सम्मेलन और भारत

वेगल ट सम्मेलन—गुट निरपेक्षता का विद्यमान सम्मेलन 1974 में हुआ। तबतक संसार की राजनीतिक मंडी में निरपेक्षता का पाँचवाँ साल पची हुई थी लेकिन तबतक संसार पाँच-छह वर्षों के भीतर अनेक गुट निरपेक्षता की राजनीतिक और सामरिक पराभव हुआ और य आनी भीतरी समस्याओं में उलझ गये। अनेक छोट छोटे देशों ने अपने पड़ोसी देशों में समर और सन्नता में स्थिति को जिस तरह उनका दिया उससे विपरीत और सेने की भविष्य सम्पत्तियों से

मुक्त रहने का वक्त अब नहीं रह गया। गुट निरपन्न राष्ट्रों विरुद्ध यह स सुरक्षा दिया और समुक्त अरब गणराज्य की इस बात बराबर यह इच्छा रहा कि तत्पक्षता को फिर से एक नियामक शक्ति के रूप में मान्यता दिया जाय। गुट निरपन्नता किस हद तक विश्व राजनीति का आज भी नियामक हा सत्ता है इस पर विचार करने के लिए जुलाई 1909 में बना ड में तत्पक्ष राष्ट्रों का एक सम्मेलन जिसमें पचास निरपन्न राष्ट्रों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य बचपन में बना था। निरपन्न राष्ट्रों के राष्ट्रता और प्रतिनिधियों के इस सम्मेलन में मुख्य रूप से विश्व स्थिति तथा निरपन्न राष्ट्रों में उनका असर और निरपन्न राष्ट्रों के बीच सहयोग और विचार विमर्श को सम्भावना पर विचार किया गया। विस्तारवाद और पश्चिम एशिया निरपन्न राष्ट्रों का चिन्ता बना के रह रहे हैं। यद्यपि 1909 की स्थिति में पहले से कुछ सुधार आये हैं लेकिन अब भी इन समस्याओं का कोई हल नहीं हो सका है। विस्तारवाद और पश्चिम एशिया तथा बाइबेल के सहित अधिकतर निरपन्न राष्ट्रों ने इस अवसर दिया था क्योंकि दो ही के दिमाग में उनका विश्वास नहीं है अशांति अनुभव की सम्भावनाएँ लगातार बढ़ती जा रही हैं। स्त्री सन्ध में निरपन्न राष्ट्रों की परिभाषा का वर्णन का भी प्रयोग किया गया लेकिन निरपन्नता के बतियाएँ विज्ञान में भी ना परिवर्तन नहीं आये हैं जिससे कि निरपन्नता का स्वप्न ही बन गया जाय। भारत ने निरपन्नता की प्रशंसा के लिए भी आवश्यक सिद्धान्त सम्मेलन का भाग

1 निरपन्न राष्ट्रों की विशेष शक्ति स्वतन्त्र होना चाहिए और उस सह-अस्तित्व के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। उस विभिन्न राष्ट्र-व्यवस्थाओं के प्रति सहिष्णुता बरतना चाहिए और निरपन्नता का आरंभ प्रवृत्ति होना चाहिए।

2 निरपन्न राष्ट्रों का राष्ट्रीय स्वायत्तता के अधिकारों का निरंतर अभ्यस्त करना चाहिए।

3 निरपन्न राष्ट्रों का किन्हीं सैनिक सशस्त्रों का सम्मेलन नहीं होना चाहिए।

4 अगर कोई देश किन्हीं बड़ा सत्ता के साथ सम्बन्धित निरपन्न राष्ट्रों का किन्हीं क्षेत्रों सैनिक सशस्त्रों का सम्मेलन है तो यह सशस्त्र राष्ट्रों के सत्ता उद्देश्यों के सम्मेलन में नहीं होना चाहिए।

5 और कोई भी किन्हीं निरपन्न सत्ता का सशस्त्र सम्मेलन का सम्मेलन नहीं होना चाहिए।

भारत द्वारा निर्धारित इन सिद्धांतों के आधार पर पाकिस्तान अतः निरपन्न राष्ट्रों के सम्मेलन का सम्मेलन प्राप्त करने का दावा नहीं है। पाकिस्तान को और भी अधिक चाहिए कि उस निरपन्न सम्मेलन में भाग लेने का अधिकार हो जाय लेकिन पाकिस्तान अतः किन्हीं अन्य देशों के सैनिक सशस्त्रों का सम्मेलन है इसलिए, उसे अब तक सम्मेलन में नहीं आया है। अब पाकिस्तान ने निरपन्न सम्मेलन में हिस्सा लेने का इच्छा व्यक्त की है अब यह

संकट कर दिया गया था कि अगर वह सम्मेलन में शामिल होना चाहता है तो अपना स्वागत है लेकिन इसके पहले उसे मित्रों और एंटी सनिक संधियों से अनन्य होना पड़ेगा। पाकिस्तान की ओर से यह कहा गया कि सनिक संधि में अपनी उपस्थिति मूल्य प्रतीकात्मक है। अगर सचमुच ही ऐसा है तो पाकिस्तान को दिए इन समझौतों से अनन्य होना और भी आसान होना चाहिए जिन आधारों पर पाकिस्तान का अब शामिल नहीं किया गया है उन्हीं आधारों पर सोवियत संघ और चीन को भी निरपेक्ष राष्ट्र नहीं माना गया।

सम्मेलन में कुछ राष्ट्र चेकोस्लोवाकिया का मामला भी उठाने का इच्छा रखते थे। अपनी ओर से युगोस्लाविया का इस पर कोई आपत्ति नहीं होने की घोषणा कर स इसलिए कि चेकोस्लोवाकिया में सोवियत हस्तक्षेप पर सबसे पहले युगोस्लाविया ने प्रतिनिधियों को भी सनिक युगोस्लाविया निरपेक्ष सम्मेलन की मजबूती कर रहा था और वह चेकोस्लोवाकिया पर बल को प्रोत्साहन देकर कुछ अन्य निरपेक्ष राष्ट्रों को जिनका कि सोवियत संघ से अलग सम्बन्ध था उत्पन्न नहीं होना चाहता था।

सम्मेलन में पारित प्रस्तावों का भारत अल्जीरिया युगोस्लाविया नाइजीरिया जाइया केन्या और समूह अरब गणराज्य ने बहुत ध्यानपूर्वक जाँच पड़ताल के बाद प्रस्तावनात्मक भर्त्ता किया। प्रस्ताव में इबराहिम दणिश अफ्रीका एतहाल और रोडोपा की कारवायों की निंदा की गयी और उनके साथ ही साथ वियतनाम की जनता का समर्थन भी किया गया। एंगोला महाद्वीप में खन रहे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विवादों में बड़ी गतिविधियों का कार्य की भी दृष्टि में भर्त्ता किया गया। वियतनाम के मामले में सोवियत संघ और समूह राष्ट्र अमेरिका के हस्तक्षेप को सम्मेलन ने बरी मजूर से देखा। अधिग्रहण से या को इन बातों का एहसास हुआ गया कि बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं की ओर तटस्थ राष्ट्रों की अपनी समस्याएँ ही इतनी जटिल हैं कि सभी का ध्यान पहले उन्हें ही ओर जाना चाहिए। भारतीय प्रतिनिधियों की ओर के प्रस्ताव हम सभी दूसरे प्रतिनिधियों के साथ बैठ कर विचार की वर्तमान स्थिति पर विचार विमर्श करने कायदा किन्तु हम मान्य हुआ है कि विश्व की ओर से तटस्थ राष्ट्रों का वर्तमान स्थिति और उनके भविष्य की ओर अधिग्रहण देने की आवश्यकता है।

बारेस्वनाम की तयारी सम्मेलन—मूल निरपेक्ष राष्ट्रों का एक दूसरा सम्मेलन अप्रिल 1970 में रेस्वनाम में हुआ जिसका उद्देश्य एक बहु-पक्षीय निरपेक्ष सम्मेलन की तयारी करना था। इसमें बावन राष्ट्र सम्मिलित हुए।

सम्मेलन शुरू होने के बहुत पहले से ही यह स्पष्ट था कि कम्बोडिया के प्रतिनिधिमण्डल के सयान की ओर गतिरोध उत्पन्न होगा क्योंकि कम्बोडिया के दो प्रतिनिधिमंडल इस सम्मेलन में भाग लेंगे किन्तु पक्षों के बीच। इससे तो राजकुमार निहलन के अध्यक्ष सम्मेलन में न केवल उत्पन्न हो और उपर कम्बोडिया की नयी सरकार का प्रतिनिधिमण्डल उस स्थान पर आधिरस्य चाहते थे। आखिर दोनों में

स कोई भी यह स्थान न ले सका। इस प्रकार सम्मेलन का गुटबिरोध से हा हुआ। बाद सम्मेलन की वापवाहा से लग रहा था कि भाग लेनेवाले सभी देश पूर्ण रूप से उद्देश्य और गति का भावना को पकड़ नहीं कर पा रहे हैं। कम स्थान को भारत ने तटस्थता के अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन किया और गुट निरपेक्षता का आज का स्थिति के सम्मेलन में उचित ठहरान की भी वांछित की। लेकिन उपस्थित प्रतिनिधि इस बार गुट निरपेक्षता देना के सिद्धर सम्मेलन के लिए अधिक उदात्त दिखायी नहीं पड़े। भारत गायक बननी इस सफलता पर खुशी का एहसास कर सकता था कि गुट निरपेक्षता में स्थान पान के पाकिस्तान के प्रयत्न को उत्तम अंश देकर दिया। इन प्रयत्न का असफल होना कुछ इसलिये स्वाभाविक भी था कि जो लोग पाकिस्तान को प्रवेश कराने का मामला बहुत बड़े तरह सम्मेलन के सामने पेश नहीं कर सका। ताजानिया और युगोस्लाविया दोनों ने भारत का ही पक्ष लिया। वैसे पाकिस्तान गुट निरपेक्षता को कोई शत भी पूरी नहीं करता था। इस प्रश्न पर भारत की गुट निरपेक्षता में से प्रमुख का समर्थन मिलना अपने आप में एक बड़ा सफलता थी।

सम्मेलन में एक बार तो कुछ प्रश्नों पर ऐसा गतिरोध दिखाया गया माना सम्मेलन असफलता की ओर बढ़ रहा हो परन्तु किसी न किसी तरह गतिरोध का दूर कर सम्मेलन ने अपना रास्ता साफ कर लिया और आखिर 1970 में ही गुट निरपेक्ष देशों के सिद्धर सम्मेलन के आयोजन की घोषणा कर इस सम्मेलन ने अपना साफल्य सिद्ध कर दी। अंतिम दिन के विचार विमर्श में फिर मतभेद पदा हुआ और भारत संयुक्त अरब गणराज्य और युगोस्लाविया जस देशों के लिए मध्यस्थता करने का काम भी बहुत कठिन दिखायी पड़ा। जब संयुक्त विनष्टि का मसविदा तैयार हो गया तो पश्चिमी एशिया संकट में निहित कई पक्षों प्रश्नों पर मतभेद का छाया पड़ रही था।

पश्चिमी एशिया की स्थिति पर विचार व्यक्त करने के साथ साथ दक्षिण-पूर्व एशिया में विदेशी हस्तक्षेप की निन्दा की गयी। सम्मेलन में एक सप्ताह की बैठक सुनने के बाद स्थापित एक निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि गुट निरपेक्ष देशों के अपने मतों में—ना तो ओर उद्देश्यों के बारे में—काफी गहरे थे। अधिकांशता के विचार मन्त्री के भाषण में यह बात स्पष्ट नजर आ रही थी। उन्होंने स्वयं यह स्वीकार किया कि सैनिक गठबंधनों का विरोध करने के लिए गुट निरपेक्ष देशों के पास कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिस पर वे स्वयं सहमत हों। 1961 और 1964 के सम्मेलनों में इन देशों के जो मतभेद सामने आये थे वे अभी बराबर बने हुए थे। ताजानिया के राष्ट्रपति ने अपने भाषण में गुट निरपेक्ष देशों का और विकसित देशों का मात्र प्रवक्तृ बनाने अथवा इस सम्मेलन का इन देशों के एक संगठित आन्दोलन का रूप देने का जायज कहा उसे भी बहुत अधिक समयन प्राप्त नहीं हो सका। आधिक्य प्रश्नों पर विचार के समय भी राजनीति ही सम्मेलन पर छाया रही और गुट निरपेक्षता में

उद्देश्य की जा एकरा स्थापित होनी चाहिए जो वह नहीं हो सकी। गैर राजनीतिक प्रस्ताव पर विचार विमर्श का सिनसिना कुछ आग बढ़ता ही था कि कोई न कोई राजनीतिक प्रश्न उस सिनसिना में बाधक बन जाता था। स्पष्ट है कि गुट निरपेक्ष देश अपनी तटस्थता को कायम रखने के साथ साथ अन्य विकसित देशों को लिए कार्य करने की जा मूमिका निभा सकते थे वह भी वे नहीं निभा पा रहे थे।

अनक पेचाइ प्रस्ताव पर विचार विमर्श के बाद मुख्य गतिरोध उस समय उत्पन्न हुआ जब गुट निरपेक्ष देशों के गिस्तर सम्मेलन के लिए जाबिया का राजधानी लसाका को चुना गया। गिस्तर सम्मेलन के स्थान के बारे में इसपर तो अजीरिया और उरर जाबिया का निमन्त्रण अफ्रीकी राष्ट्रों और काले अफ्रीका के बीच प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया। इस प्रश्न पर विचार विनिमय के दौरान वातावरण में कुछ तनाव भी दिखायी पड़ा लेकिन अंत में अपना गिस्तर सम्मेलन लसाका में होना का निश्चय हुआ। ऐसा स्थान था जिसका अफ्रीका के विरुद्ध निरपेक्ष होने के कारण लसाका सम्मेलन ससार का ध्यान दक्षिण अफ्रीका जैसे औपनिवेशिक देशों और उनकी दक्षिणपूर्वी नीतियों पर दिना सवंगा और यह गुट निरपेक्ष देशों के अनेक उद्देश्यों में से एक था।

लुआका सम्मेलन—संयुक्त राष्ट्रों का तीसरा गिस्तर सम्मेलन अफ्रीका का जोबया की राजधानी लसाका में 8 सितम्बर 1960 का प्रारम्भ हुआ। इस सम्मेलन में 63 राष्ट्रों ने भाग लिया। सम्मेलन के आरम्भ होने के पूर्व कई तरह की आगवाहें ध्वस्त की गयी थी। कुछ प्रश्नों का कहना था कि 1970 का अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में विश्व तटस्थ राष्ट्रों के इस सम्मेलन की ओर अधिक ध्यान नहीं देगा और न सम्मेलन के निर्णयों का अधिक समय तक ध्यान रखा जायगा। इस तीसरी दुनिया का आज इतना प्रभाव नहीं है जितना पहले था। तटस्थता आन्दोलन की प्रतिष्ठा को सबसे अधिक धक्का तो इस बात से लगा है कि वैसे राष्ट्रों के आपसी सम्बन्ध बनाने लगे हैं और तीसरी दुनिया पर प्रभाव जमाने की बजाय अपने क्षेत्र में बाहर की अनेक शक्तों पर वे एक दूसरे से सहयोग करने लगे हैं। ऐसी स्थिति में तटस्थता की भावना का अर कोई महत्त्व नहीं रहा।

इस आगवाहों के बावजूद लसाका सम्मेलन हुआ और कई दृष्टियों में यह सफल भी रहा। 63 राष्ट्रों के इस सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये और पिछले दो सम्मेलनों (बन्दर 1961 तथा का हरा 1962) की अगला इस बार का विचार विमर्श और वास्तव्य अधिक स्पष्ट था।

तटस्थ राष्ट्रों की साथ सम्बन्ध रखना सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पश्चिम दुनिया का था जिस पर सम्मेलन ने स्पष्ट और निश्चित निर्णय लिया। पश्चिम एशिया के बारे में प्रस्ताव में कबल अरबों के पक्ष का समर्थन ही नहीं हमरावर इजरायल का आवश्यकता पड़ने पर बाधना करने तथा नाटोव दो सह करने की बात थी। इजरायल से उन देशों से तुरत अपनी फौज हटा लेने का आग्रह किया गया

जिस पर उसने 1967 के युद्ध के दौरान कब्जा किया था। पश्चिम एशिया में शान्ति प्रयत्न का स्वागत करते हुए सम्मेलन ने प्रयत्नों को जारी रखने का अनुरोध किया और साथ ही हिमालय क्षेत्र में भी ऐसे ही प्रयत्न करने की सिफारिश की। भले ही संधि और विवादों में उसे हुए राष्ट्र सम्मेलन का सिफारिशों पर ध्यान न दें पर विचार विमर्श और इन प्रश्नों पर तटस्थ राष्ट्रों की अतिश्रम की अनदेखी नहीं की जा सकती।

इसी प्रकार वियतनाम के बारे में हुआ सम्मेलन एक कदम पहले से अग्रिम बढ़ा। वियतनाम से अमेरिकी फौजों तथा अन्य सभी देशों की फौजें हटाने की मांग की गयी। इस मामले पर हुई बहस में यह स्पष्ट हो गया कि गुट निरपेक्ष देशों में आम राय यह है कि अमेरिकी फौजों ने वहाँ जाकर स्थिति बिगाड़ दी है। अस्थायी आतंकवादी सरकार की परराष्ट्र मंत्री श्रीमती बिन्ह को सम्मेलन में प्रवेश बनाकर यह भी सिद्ध कर दिया गया कि गुट निरपेक्ष देश राष्ट्रीय स्वातंत्र्य मार्ग के साथ हैं।

कम्बोडिया के बारे में सम्मेलन में भारी वामत राजकुमार सिंहनुक का पक्ष मिला। फिर भी आवश्यकता को ध्यान में रख कर राजकुमार की सरकार और लोन लोन की सरकार में से किसी को भी सम्मेलन में शामिल नहीं किया गया। वक्ताओं ने यह साफ कह दिया था कि जनरल लोन की सरकार न राजकुमार सिंहनुक को अपदस्थ करके बिन्ही हस्तक्षेप के लिए भाग खोलेगी।

उपनिवेशवाद और आर्थिक प्रगति पर तटस्थ राष्ट्रों के परस्पर सहयोग का प्रश्न पर अधिकाधिक सहमति थी और ये दोनों बातें सम्मेलन की सफलता का आधार बनीं। उपनिवेशवाद के सन्दर्भ में दक्षिण अफ्रिका की चर्चा स्वाभाविक थी और इस सम्बन्ध में सम्मेलन ने सभ्य देशों से स्पष्ट गुच्छों में अनुरोध किया कि दक्षिण अफ्रिका की हवाई कम्पनियों के विमानों का वह अपन ऊपर से होकर जान की अनुमति न दें। यह अफ्रिका में स्वाधीनता के लिए संधि करनेवाली जनता को एक प्रकार का नैतिक समर्थन देने के समान है। निरस्पर्ध तटस्थ राष्ट्रों द्वारा इस तरह की कार्रवाई से दक्षिण अफ्रिका पर दबाव जबर पड़ा। परन्तु यह कार्रवाई कहीं तक कारगर होगी यह तो अन्य बहुत सी बातों पर निर्भर करेगा परन्तु औपनिवेशिक दासता में जकड़ अफ्रिकी लोगों के लिए मात्र नैतिक समर्थन देना ही काफी नहीं था। सम्मेलन ने अफ्रिकी जनता के स्वाधीनता संधि के लिए धनराशि एकत्र कराने का प्रस्ताव भी रखा परन्तु इसका कोई निश्चित व्यवस्था नहीं की गयी जिससे कि इस तरह की कार्रवाई का लाभ सीधे संप्रत्यक्ष अफ्रिकी जनता को पँच सके।

तटस्थ राष्ट्रों की एक सूची में रखेवाले आर्थिक सहयोग का प्रश्न पर भारत ने हमला से ही जोर दिया है। इस बार भी आर्थिक सहयोग पर भारत की जोर से ही जोर दिया गया। विकास तथा आर्थिक उन्नति के कार्यों में सभ्य देशों द्वारा आर्थिक सहयोग की बात अफ्रीका के तृतीय सम्मेलन से भी बहुत पहले निश्चित की

गयी थी। इस समय व मे अश्वियो की बठक मे कुछ निणय लिय गये जिन पर अमन करते रहने का अनुरोध जमाका सम्मेलन में भी किया गया।

गुट निरपक्ष देग गुटव ी के सिताफ चने थे और या व स्वय ही अपना संगठन बना न तो वह भी एव गुट का रूप लेगा। इसीलिए जसाना में स्थायी संगठन बनाने और उसका कार्यालय स्थापित करने का स्थाय की अवबोधार किया गया। इस मामले में कुछ अफ्रीकी न आगे थे और व चाहते थे कि जुसाका मे ही संगठन का स्थायी कार्यालय खोन दिया जाय। भारत ने बडा विरोध किया और संगठन नहीं बन पाया।

सम्मेलन की समाप्ति पर प्रतिनिधि दल अपने अपने देशों को लौटते समय उपलब्धि का एहसास हो रहा था और सभी की म धारणा थी कि तीसरा सम्मेलन सम्मेलन केवल सफल ही नो रहा बकि उसका संचालन भी पिछले सभी सम्मेलनों की अपेक्षा कुशल और निर्बाध था। सबसे बडा बात तो सम्मेलन में भाग लेनेवाले प्रतिनिधियों का यह वि बात था कि तटस्थता आज भी उनके लिए सार्थक है और आज की बाकी दुनिया के लिए भी तटस्थता न अपना अध लीया नहीं है। भारतीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का विचार था कि इस सम्मेलन में सहयोग की जो भावना देखी गयी उसका पूरा पूरा लाभ उठाया जाना चाहिए। प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और युगोस्लाविया व राट्रगति टीटो दानों ने ही सम्मेलन को सफल माना है और उसकी उन्नति यों पर हर्ष व्यक्त किया। स्वयं रवाना होने से पहले श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारतीय सवादाताओं से बातचीत करते हुए सम्मेलन की सफलता पर सतोष व्यक्त किया पर उनका कहना था कि सम्मेलन के बाद की गतिविधियां पर बहुत कुछ निर्भर करता है। दूतगान और दक्षिण अफ्रीका से उनकी औपनिवेशिक नीतियों के कारण सम्मेलन के सत्य देगो न राजनतिक सम्बंध बिच्छे करने का जो फसना किया व एक ठोस निर्णय था।

जुसाका सम्मेलन और भारत :—भारत सरकार गुरु से ही गुट निरपक्ष देगो के इस शिखर सम्मेलन बुलाने व सिताफ रही था। पहले तो भारत ने ब सान तक टाउनमेटोव की फिर जब देखा कि अधिकांश गुट निरपक्ष देग यह चाहत है कि सम्मेलन हो ता भारत भी जनमने मन स राखी हुआ। जब अधिकांश देगों ने इस बात पर जार दिया कि तीसरा शिखर सम्मेलन सिनो में हो ता भारत न इत्कार कर दिया। असल गुट निरपक्षता के स्तम्भ तीन देग रहे हैं : भारत युगोस्लाविया और संयुक्त अरब गणराज्य। व ना शिखर सम्मेलन युगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था दूसरा संयुक्त अरब गणराज्य की राजधानी काहिरा में। इसविष तीसरा शिखर सम्मेलन भारत की राजधानी दिल्ली में होना चाहिए था और इस बात पर अनेक देग की ओर से जोर भी दिया गया था लेकिन भारत की ओर स यह बात नहीं मानी गयी। इसका कारण यह नहीं था कि दिल्ली में ऐस ब बतर्लान् सम्मेलन की सुविधा नहीं है बकि इसलिए कि भारत सम्मेलन का ही टाउन था ता था। फिर भारत को यह भी भय था कि वही पाकिस्तान इस में भाग लेने के लिए न आ टपक। पाकिस्तान को

सम्बन्धी की स्थापना के स' में में गूट निरपेक्षता की नये गुट निरपेक्ष देगों को अब नये सिरे से निश्चिन करना चाहिए और अमेरिका जमे ब' देगा व प्रभाव तथा में छोड़े बिना उन सहयोग किया जाय। अजीयमें सम्मेलन में य' सबान 'ट भी। नीविया ने सम्मेलन की राजनीतिक समिति में यह प्रस्ताव रखा कि की नयी परिचाया की आय आर गूट निरपेक्ष राष्ट्रों व लिए एक बड़ा विधान किया जाय। सम्मेलन व लिए एक स्वायत्त सचिवालय की स्थापना के लिए भी प्रस्ताव आया और अफ्रीका मुक्ति आन्दोलन का सहयोग विये जान की बात भी सम्मेलन में कई बार उठायी गयी।

गूट निरपेक्ष देगा व इस अल्जायस सम्मेलन में भारत ने इन महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। सम्मेलन व सबसे प्रमुख राजनीतिक समिति का संचालन भारत ने किया और कई प्रस्ताव भारत की इच्छानुसार पास हो गये। समा और से यह माना गया कि सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्रीमती श्रीमती गांधी व स्वतंत्रता की याक जम गयी थी और गायन ही कुछ ऐसा हुआ हो जो भारतीय प्रधानमंत्री की इच्छानुसार बन न हुआ हो। भारत की सफलता की इस प्रकट रंगिना जा सकता है

1 अंतिम घोषणा पत्र में सिफारिश की गयी है कि अगला देग का राष्ट्र संध का सन्ध बनाया जाय। भारत के यान से कुछ अरब देगों का यह यान सफल नहीं हो सका कि घोषणा पत्र में यह बान न लिखी जाय।

2 घोषणा पत्र में लिखा गया कि हान क भ रत पाकिस्तान समझौते से इस उर महाद्वीप में स्थायी शांति का मार्ग प्रगस्त हो गया है।

3 भारत और युगास्लाविया का यह आप्रहृ स्वीकार कर लिया गया कि गुट निरपेक्ष देगों का स्थायी चार्पितय अभी स्थापित न किया जाय।

4 भारत के आप्रहृ पर सम्मेलन ने प्रस्ताव पास करके निश्चय किया है कि पाँचवाँ गूट निरपेक्ष निश्चर सम्मेलन 1976 में होना चाहिये। भा व की म' बात समा और से स्वीकार की गयी कि अगला निश्चर सम्मेलन एगिया में हो क्योंकि पहला सम्मेलन मराय (रमरह) में दूसरा सोसरा और चौथा अफ्रीका में हुआ था।

5 हालांकि भारत आर्थिक समिति का अध्यक्ष नहीं था। फिर भी यह स्पष्ट है कि जो आर्थिक प्रस्ताव सम्मेलन में पास किया उसका समर्थन तयार करने में भारत की सक्षम बड़ा हाथ था। आर्थिक क्षेत्र में गूट निरपेक्ष देगों का अन्तही सहयोग विये। वरतियो जादि का राष्ट्रीयकरण सदा आर्थिक आजा। पर जोर देने का बात भारत लगातार कहता रहा और चौथे निश्चर सम्मेलन में पाँच सभापन व साथ भारत का ही मनवि। स्वीकार किया।

6 अरब इजरायला विवाद और फि चान के देगों के चार में भारत ने मध्यस्थता करके प्रस्ताव नरम बनवा विये और इनलि ए सदस्यसमिति से उद्घ पास करने में कठिनाई नहीं हो।

7 सम्मेलन इस व सार श्रीमती गांधी विभिन्न देगा व नेताओं से मिली। इनमें कई साम हुण-जसे युगाडा व राष्ट्रपति जनरल अमान से मोधा बातचीत करने से यह साम हुण कि व युगाडा से निहाने गये भारताधी की हर्षिता देने की

राजा हो गये। यह निश्चय किया गया कि उसके लिए एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल बनाया जाएगा और विस्तार से बातचीत करेगा। थामनी गाँधी न अजीरिया के राष्ट्रपति बूमोएन को भी 1971 व भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में बताकर उनकी भावित्या को दूर करने का प्रयत्न किया।

इस प्रकार गुट निरपेक्ष अंगत में भारत ने इन चीजों का स्थान प्राप्त कर लिया। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि भारत चीन युद्ध के समय अंतराष्ट्रीय रणमंच पर भारत ने जो छोपा था वह फिर प्राप्त कर लिया।

इस प्रकार भारत ने एशिया और अफ्रिका के देशों को संगठित करने और उनमें सहयोग की भावना उत्पन्न करने का प्रयत्न प्रयास किया है। यह उसकी विदेश नीति का एक मुख्य उद्देश्य रहा है। लेकिन यह आश्वासन अब तुष्ट मा होता जा रहा है और इसको जीवित रखने के लिए भारतीय कूटनीति फिरहास बिल्कुल निष्प्रिय है। एशिया और अफ्रिका के देशों के संगठन की मुख्य आधार पश्चिमी साम्राज्यवाद का विरोध था और जम-जमे उपनिवेशवाद का अन्त होता गया है वैसे-वैसे संगठन की भावना भी कमजोर होती गयी है। एशिया और अफ्रिका के विविध देशों का अपने अलग-अलग हित और स्वार्थ हैं और इन हितों के बीच परस्पर संघर्ष का हा जाना स्वाभाविक है। एशिया के महान देश भारत और चीन अपना सामुरा बनग अलग बना रह रहे हैं। इसके कारण इस आन्दोलन को गहरा धक्का लगा है। इसके अतिरिक्त एशियाई अफ्रिकी देशों के संगठन की भावना बिल्कुल निष्प्रिय और स्पष्ट नहीं थी। अंतराष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में यह एक स्यामा और क्षणभंगुर आन्दोलन था जिसका प्रयाग युद्ध अंग में संनिवेशवाद के विरोध में किया गया। एशियाई एकता और संगठन के आन्दोलन को इससे अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता है।

फिर भी इसी सीमित दायरे में एशियाई देशों को संगठित करने में भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। भारत का मत है कि औद्योगिक क्षेत्र एवं जनसंख्या की दृष्टि से एशिया और अफ्रिका का पर्याप्त महत्व होना चाहिए और उनका आवाज को प्रभावपूर्ण माना जाना चाहिए। भारत ने इन महाशक्तियों के देशों की मंत्री अंतर्गत करने के लिए उनके आर्थिक विकास में परामर्शमय सहयोग दिया है और उनके हित एवं प्रभाव का बढ़ाने के प्रयत्न अवसर का लाभ उठाया है। जब तक भी एशिया के लोगों के हितों को ठम पड़ेवायी जाती रही है अथवा उनका आवाज को दबाया गया है तो भारत ने अपनी पूरी शक्ति से उसका विरोध किया है। यह भारत के लिए स्वाभाविक है क्योंकि भारत एशिया में है और यहाँ के निवासी दूसरों की अपना एशिया के क्षेत्र में हैं। अतीत काल में भी भारतीय संस्कृति ने इन देशों का प्रभावित किया और स्वयं भी कई क्षेत्रों में इनमें प्रभावित हुआ था।

भारत एशिया महाद्वीप के देशों को उनका उपोचित सम्मान एवं महत्व जिलान में सन्व प्रयत्नशील रहा है, लेकिन उसने कभी भी इस महाद्वीप को अथवा महाद्वीप के लोगों से पूरी तरह अलग रखना चाहा और न दूसरा का तुलना में अनावश्यक सबों उच्चता प्रदान करने का पक्ष पोषण किया है। भारत एशिया के लोगों को दूसरे महाद्वीपों के लोगों के समान बड़े महत्व एवं गौरव जिलाना चाहता था जिससे कि अवायव्यता तरीके से वे एक नव्य समय से संबंधित रखे गए।

महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सङ्घटन और भारत

(Important International Crs I and India)

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पहले अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत का कोई महत्त्व नहीं था। वह एक गुलाम देश था और दुनिया के किसी कोने में उसका आवाज नहीं सुनी जाती थी। दो विश्व युद्धों के बीच के काल में अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बड़ी-बड़ी घटनाएँ घटीं लेकिन भारत अपने राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से इनमें से किसी भी घटना को निष्पक्ष रूप से प्रभावित नहीं कर सका। ऐसे ब्रिटिश भारतीय सरकार ब्रिटेन के विश्व व्यापी साम्राज्यवादी नीति का ध्यान में रखकर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की स्थिति का प्रयोग करती रही और भारत चाहे अनचाहे अपनी स्थिति के अनुरूप विश्व राजनीति में अपनी भूमिका निभाता रहा लेकिन भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण से इसका कोई महत्त्व नहीं था।

अगरत 1947 में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत की इस स्थिति में एकाएक परिवर्तन आया और वह उन सारी महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं में प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लेने लगा। दुनिया की प्रत्येक घटनाओं पर भारत के अपने दृष्टिकोण का विकास होने लगा। यह आवश्यक और धार्मिक था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में घटनाएँ द्रुत गति से घटने लगीं। गुटों के प्राथमिक और द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारम्भ से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति विषम हो गयी और यह युद्ध तथा गति का प्रश्न बन गयी। ऐसी गम्भीर परिस्थिति में भारत चुपचाप नहीं बैठ सकता था क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय घात की आवश्यकता उसके लिए सर्वोपरि थी। सारे राष्ट्र का भविष्य इसी पर निर्भर करता था। अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं के प्रति किसी भी हानि में भारत उपस्थित नहीं रह सकता था उनमें अपनी सक्रिय भूमिका निभाना व अपना अधिकार और कर्तव्य दोनों मानना था। अतएव सन्धि और औद्योगिक दृष्टि से क्षीण होने पर भी वह प्रारम्भ से ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय एवं प्रभावशाली भूमिका का निर्वाह करने लगा। इस रूप में भारत के कार्यों ने इस बात का प्रमाणित किया कि दो प्रबल गतिशील गुटों में विभाजित आधुनिक सत्ता की स्थिति में एक स्वतन्त्र किन्तु रचनात्मक असहमति का नीति महत्त्वपूर्ण एवं प्रभावशाली सिद्ध हो सकती है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद का भारतीय विदेश नीति का इतिहास बताता है कि अनेक सङ्घटपूर्ण अवसरों पर भारत ने पूर्व और पश्चिम के मध्य में की चोड़ा छान्नी को कम करने का उच्चेष्टनीय प्रयास किया है। दो-तान अवसरों पर ही उन आने रचनात्मक भूमिका द्वारा तृतीय महायुद्ध के दावानज को प्रभावित हान से रोका है और दोनों पक्षों के मध्य गति के दूत का काम किया है। युद्धांतर काल का कुछ

निर्वादा किया गया कि कोरिया में स्वतंत्र निर्वाचन द्वारा एक स्वतंत्र सरकार की स्थापना का काम में योगदान करें।

संयुक्त राष्ट्रमंडल के कोरिया पर अस्थायी आयोग (U N Temporary Commission on Korea) को दक्षिण कोरिया में आतंक पर जांच पहचान करने की सभी सुविधाएँ सुनिश्चित की गयीं। भारत भी इस आयोग का एक सदस्य था। आयोग को सोवियत अधिकृत उत्तरी कोरिया में प्रवेश नहीं करने दिया गया। अतः इसने विचार होकर अपनी देख रेख में दक्षिण कोरिया में 10 मई 1948 को चुनाव करा दिये जिसके फलस्वरूप 25 अगस्त 1948 को दक्षिण कोरिया में एक गणतान्त्रिक सरकार की स्थापना हो गयी। सिंगमनरी (Syngman Rhee) को इस गणराज्य का शासक चुना गया। सत्रह दिनों के बाद अमेरिका ने गणराज्य का अधिकार दक्षिण कोरिया की सरकार को सौंप दिया। इसी मध्य उत्तर में किम इल सङ की अध्यक्षता में आम चुनाव के बाद मोरतत्रीय गणराज्य की स्थापना हो गयी।

12 फरवरी 1948 को साधारण सभा ने सिंगमनरी की सरकार को ही पूरा कोरिया को एक मात्र वैध सरकार घोषित किया तथा उत्तरी कोरिया का लोकतन्त्रीय जनगणराज्य को उद्घोषित कर दिया गया। इसके उपरान्त साधारण सभा ने अपने एक प्रस्ताव के द्वारा अमेरिका और सोवियत मध्य से यह निवारण की कि वे अपनी सत्ता को कोरिया से वापस बुला लें। साथ ही संयुक्त राष्ट्रमंडल द्वारा कोरिया के एकीकरण हेतु सात सदस्यों का एक आयोग बनाया गया (भारत इस आयोग का अध्यक्ष था) जिसके कार्य में साम्यवादी और सिंगमनरी दोनों ही अड़नेवाला लगाने लगे। सोवियत संघ ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि साधारण सभा कोरिया के शासक में कोई पग नहीं उठा सकती क्योंकि यह प्रान्त मास्को समझौते के अधीन और उस पर विचार सम्बन्धित मित्र राष्ट्रों द्वारा किया जाना चाहिए। 25 दिसम्बर 1948 काँग्रेस ने उत्तरी कोरिया में अपनी सेनाओं की वापसी की घोषणा की। दक्षिण में अमेरिकी सैनिकों को 29 जून 1949 को वापस बुला दिया गया जिसकी श्रुति गणराज्य कोरियाई आयोग द्वारा की गयी। इस समय तक दक्षिणी कोरिया की सरकार को अमेरिका के सभी विद्युतगुप्त दैर्घ और उत्तर कोरिया को सभी माध्यमों से दूरियों की भाषणा मिल गयी। इस हानत में एकीकरण का कार्य बड़ा कठिन हो गया। कोरिया गीत युद्ध का अखाड़ा बन गया और दोनों पक्षों के बीच सघर्ष अनिवार्य प्रतीत होने लगा। सीमाओं पर दोनों पक्षों के बीच निरन्तर प्रतिनिधित्व गठभड़ होती रही। ऐसी स्थिति में कोरिया की स्थिति अत्यन्त खराब बनती गयी।

युद्ध का प्रारम्भ :— 25 जून 1950 को कोरिया में लड़ाई शुरू हुई। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर युद्ध प्रारम्भ करने का घोषणा किया और दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया को आक्रामक बतलाया। संयुक्त राष्ट्रमंडल का आयोग जो इस समय कोरिया में उपस्थित था और जिसकी अध्यक्षता भारत के ने की एक मन्त्री (H. P. S. Menon) कर रहे थे यह स्थिति लिया कि यह आक्रमण उत्तर कोरिया द्वारा पूर्ण आयाजित सम्पूर्ण तयारी के साथ हुआ है।

कारिया के संयुक्त राष्ट्र आयोग को इस सूचना पर सुरक्षा परिषद् का आवश्यक बैठक बुलायो गयी। परिषद् के दोनों पक्षों को तुरंत युद्ध बन्द करने तथा सन्ताना का 38 अन्तर्गत रखा तब चीन जान का कहा। लेकिन दोनों पक्षों ने सुरक्षा परिषद् के इस कथन को सबधा अवहेलना का। अतः अमेरिका के निर्देश पर सुरक्षा परिषद् ने कोरियाई युद्ध में उत्तर कारिया के विरुद्ध सैनिक कारवाही करने का निर्णय किया। उन दिनों सोवियत रूस सघ गारा कम्युनिस्ट-चीन का मायता न दन के प्रतिवात्स्वरूप सघ की सभा बैठकों का बहिष्कार कर रहा था। अतः सुरक्षा परिषद् में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का कारिया में सैनिक कारवाही का प्रस्ताव 27 जून 1950 का वही सुगमता से पास हो गया। सुरक्षा परिषद् में इस पक्ष में नौ बार आर यूगास्लाविया ने वार्ड नहीं दिया रूस अनुपस्थित था। रूस प्रस्ताव में उत्तर कारिया का सना के कार्यों का शांति बना करनेवाला घोषित करते हुए तत्पश्चात् वार्ड कर दन को उत्तर कारिया की फौजों को 38 अन्तर्गत रखा के उत्तर में चीन जान का तदा संयुक्त राष्ट्र सघ के सन्स्था की स प्रस्ताव के क्रियावित्त करने में सहायता दन का कहा गया था। एक दूसरे प्रस्ताव में यह सिफारिश की गया था कि 'संयुक्त राष्ट्रसघ के सन्स्था कारिया के गणराज्य को ऐसा आवश्यक सहायता दे जा सगन्त्र आक्रमण का प्रतिरोध कर सक तथा उस क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाये रख सक। यह प्रस्ताव सात बार्डों से पास आर यूगास्लाविया तत्स्थ रहा मित्र और भारत ने वार्ड में भाग नहीं लिया सोवियत सघ अनुपस्थित था। 7 जून 1950 के एक तीसरे प्रस्ताव में युद्ध का संयुक्त बमान बनात हुए अमेरिका का इसका सनापति निश्चित करने का कहा।

कोरिया की समस्या पर भारतीय दृष्टिकोण — कारिया की समस्या में भारत प्रारम्भ से ही रुचि रखता आ रहा था। इसलिए जब रूस समस्या के समाधान हेतु सघ की साधारण सभा ने एक अस्थाया कारियाई आयोग का स्थापना की ता भारत को ना रसवा सन्स्था बनाया गया। अयोग के भारतीय सन्स्था के पा एम् मनन ने समायाम रचना अधिक रुचि का प्रत्यन किया कि उन्हें गान्न ही इसको प्रधान बना दिया गया। मेनन ने कारिया के एकाकरण पर बर्तन जारी किया। उन्होंने आरम्भ से ही उस बात पर बर्तन किया कि कारिया का समस्या पर विचार सम्पूर्ण केरिया को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिये। फरवरी 1948 में भारत के साधारण सभा में कारिया के चुनाव करनेवाले प्रस्ताव का कार्यावित्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्रसघ का अन्तर्गमि समिति का यह प्रस्ताव मान लिया कि आयोग का किया के जिन हिस्सा में सम्भव हो वहाँ चुनाव कराये। यह बात मान लवपूर्ण किया गया। कोरिया की अपनी सारी समस्याओं का मूलपात इसा प्रस्ताव ने कराया गया कि रूसी कारण कोरिया उत्तर और दक्षिण के दो परस्पर विरोधी हिस्सा में विभक्त हो गया। कारिया के विभाजन का उक्त विरोधा होते हुए भी भारत ने रूस प्रस्ताव का इसलिए

निया कि इस समय तक भारत सरकार का दृष्ट पूर्णतया कम्युनिस्ट विरोधी हो गया था।¹

अभी बीच जून 1950 में कोरिया में युद्ध शुरू हो गया। युद्ध छिने पर भारत ने निर्दिष्ट रुद्र से पर्चा बमों गट का समर्थन किया। भारत ने इस बात को मान लिया कि उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण किया है। यह इसलिए जाना गया था कि भारत स्वयं उन समुक्त राष्ट्रीय आयोग का सत्य था जिसने इस बात की सूचना दी थी कि उत्तर कोरिया ने ही दक्षिण कोरिया पर आक्रमण किया है। कर्माकर गुप्त का कहना है कि आयोग के दो भारतीय प्रतिनिधि सी को डराव और डा. अनूप सिंह निराश नहीं थे। वे कम्युनिस्ट विरोधी थे और इसलिए उन्होंने भारत सरकार को शक्ति सूचना दी और इस सूचना के आधार पर भारत सरकार ने अपना दृष्टिकोण निर्दिष्ट किया। 7 जून को न्यायपालिका नेहरू ने कहा कि जब उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के विरुद्ध आक्रमण किया तो बिना किसी विरोध के यह स्पष्ट था कि यह एक अर्ध-तरह का अपराध और बड़े पैमाने पर किया गया आक्रमण था। इस अवस्था में भारत सरकार की स्वाभाविक नीति इस आक्रमण को रोकनेवाले सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का समर्थन करने की थी। इसलिए भारत ने सुरक्षा परिषद के प्रथम प्रस्ताव का पूरा-पूरा समर्थन किया। दूसरे प्रस्ताव पर सुरक्षा परिषद में भारतीय प्रतिनिधि ने अनैतिकी के अभाव (lack of instruction) में मतदान नहीं किया लेकिन बाद में भारत सरकार ने सूचित किया कि वह दूसरे प्रस्ताव से भी सहमत है।

एक बार समुक्त राष्ट्रसंघ के सैनिक कायबाहा का समर्थन करने के बाद भारत ने इस युद्ध को सीमित और बंधन करने का पूरा यत्न किया। उन इस युद्ध में समुक्त राष्ट्रसंघ की सहायता के लिए एक भी सैनिक दस्ता नहीं भेजा क्योंकि वह इन युद्ध के शांति के भंग करने की सामग्री देने में सहायता नहीं करना चाहता था। इस भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि द्वारा समर्थन पत्रिका में भारतीय राजदूत पणिकर की प्रेरणा से इस युद्ध को रोकने के लिए मा को और वाणिज्य में स्थान और अस्त्रों को लिखे गए पत्र थे। यदि वाणिज्य नष्ट के शान्ति प्रस्तावों का उत्तर ही उसी से स्वगत करता जितने उसी से माहता न किया था तो कोरिया युद्ध बहुत जल्द समाप्त हो जाता।

युद्ध का विस्तार :— दस दिन के भीतर सुरक्षा परिषद ने अमरिका के निर्देश पर तीन प्रस्ताव स्वीकार कर लिए थे। रोकथाम संधि इसका विरोध किया और पारपत्र का कायबाही में भाग लेने के लिए उसका प्रतिनिधि न वापस आ गया।

इसी बीच समुक्त राष्ट्र की सभा में सोलह राष्ट्र सम्मिलित हो गये। इसका प्रधान सभापति जनरल मकार्यर बनाया गया। युद्ध अभी तक संधि सभा पर

1 Karunakar Gupta *Indian Foreign Policy* p 10

2 Ibid pp 11 12

प्रस्ताव पाम हो गया। इसका बाण राष्ट्रपति ट्रुमन ने कारिया में अणुबम प्रयोग करने की धमकी दी। इससे अंतर्राष्ट्रीय तनाव बहुत बढ़ा। 5 दिसम्बर 1950 को भारत ने अरब एशियाई राष्ट्र के बख्तराबाद के मायमिनकर गति के लिए अंगीत की। फिर जून 1950 में भारत ने युद्ध बंद करने तथा संधि करन का एक प्रस्ताव रखा। पर यह भी स्वीकार नहीं हुआ।¹ इस प्रकार यद्यपि भारत का कूटनीति को कोई आगामीत सफलता नहीं मिली फिर भी इसमें काफी सफलता नई कि हमने कारिया का युद्ध विरुद्ध युद्ध का एक कारण करने में सफल हो गया।

जब दोनों पक्ष युद्ध संधि आ गये तो पानमुन जान में विरासत में आया कि एक संधि बननी चाहिए लेकिन पानमुन जोन की संधि वाता न एक विकट रूप धारण कर लिया। 575 बटरी का बा विराम संधि हो गयी लेकिन वास्तविक मध्यम समाप्त न हुआ। इसमें युद्धकर्मियों के प्रत्यावर्तन का प्रश्न सबसे बटित था। संयुक्त राष्ट्र संधि द्वारा युद्ध में बंदी बनाये गये कुछ मानव चीन और उत्तर कोरिया वापस जाना चाहते थे लेकिन रूस और चीन इन्हें वापस गोटान पर तब तक नहीं देते थे। इस प्रश्न को हल करने के लिए भारत ने कई प्रस्ताव रखे किन्तु इन्हें सोवियत मध्य ने स्वीकार नहीं किया। अंत में मार्च 1953 में दोनों पक्षों ने एक प्रस्ताव स्वीकार किया जो भारतीय प्रस्ताव से बहुत भिन्नता जुता था।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार स्वयं वापस लौटने के लिए अंगीत संधि कर्मियों को सम्मया हल करने के लिए पाँच तटस्थ राष्ट्रों—भारत स्विट्जरलैंड स्वेडन पोलैंड चेकोस्लोवाकिया—का एक आयोग (Neutral Nations Repatriation Commission) नियुक्त किया गया। भारत इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त हुआ। जेनरल धिमैया की अध्यक्षता में भारतीय सैनिकों ने संधि को स्वयं गोटान का काम बड़ी ही सावधानी के साथ किया। इस काम को पूरा करने में भारतीय सैनिकों ने अपूर्व सफलता का परिचय दिया। छुट्टाई के काम में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। इन बटितानियों के वापस आयोग जनवरी 1954 में संयुक्त राष्ट्रमध्य की बमान की उत्तर कोरिया के वार्षिक हजार युद्धकर्मियों को चीन या उत्तर कोरिया वापस जाना नहीं चाहते थे।

कोरिया के सम्पूर्ण सङ्घर्ष में भारतीय नीति अत्यंत सराहनीय रही और दोनों पक्षों ने इसकी प्रशंसा की। इस सम्बन्ध में चेस्टर बार्न्स ने लिखा है— नयी दिल्ली 38वीं अक्षांश रेखा पर युद्ध बंद करने के लिए बन गया। इस संधिबन्दी की परवाह न करते हुए हम उत्तर में बढ़े। चीन की सैन्य सेना न ताकान मालूम नहीं पार की। तीन वर्ष बाद अंत में हमने उसी 38वीं अक्षांश रेखा विराम संधि करना स्वीकार किया। गौ बाध नहीं हुआ। सभी अंग्रेजों और पक्षा नहीं। अतः चीन और कोरियाई मारे गये तथा घायल हुए। कोरिया में गति स्थापना के कार्य में भारत द्वारा लिये गये योगदान की सराहना और भी अनेक स्थानों पर विभिन्न देशों में की

1 Ibid p 136

2 Karunakar Gupta In *Foreign Policy* pp 114 115

गया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति आर्नेस्ट हेवरन कोरिया में भारतीय संरक्षक सेना का कार्य की सराहना करते हुए कहा था। विगत २० वर्षों में किसी अन्य सेना न कोरिया में भारतीय सेना का असाधारण अधिक नाजुक और कठिन कार्य नहीं किया है। इन अफसरों तथा सैनिकों का कार्य भारतीय सेना की उच्चतम श्रेष्ठि के बराबर मान्य था। वे उच्चतम प्रशंसा के पात्र हैं। जनवरी 19५0 में स्टालिन ने भी नहर की शान्ति स्थापना के कार्य की प्रशंसा की थी।

हिंद चीन की समस्या और भारत

दक्षिण-पूर्व एशिया के हिंद चान पर फ्रांस का आधिपत्य 1884 में कायम आया। अतः इस उपनिवेश का प्राप्ति न केवल जापानों में जा रहा था। कोचान चान पर इसका प्रत्यक्ष शासन था। लेकिन आन्तर्गत टायवान, कम्बोडिया तथा त्राओस फ्रांस के सुरक्षित राज्य थे। 1940 में जापान के द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश करने पर दक्षिण-पूर्व एशिया के सभी देशों के समान हिंद चीन का भी जापान के आधिपत्य में जाना पड़ा। युद्ध के अन्त में ही यहाँ की स्थिति पूर्णतया बदल गया। त्राओस एक सर्वोच्च सत्ता सम्पन्न राष्ट्र बन गया। सम्राट सिमाधाग के शासन के अन्तर्गत 11 मई 1947 को यहाँ तक संवैधानिक राजतन्त्र का स्थापना हुआ। जनवरी 1949 का जापान फ्रांसीसी संघ के अन्तर्गत कानूनान्तरित स्वतंत्र देश बन गया। 15 मार्च 1945 का कम्बोडिया के प्रधान मंत्री ने अपने देश की स्वतंत्रता का घोषणा कर दी। 1947 में यहाँ एक राष्ट्रीय संविधान बनाया गया और 8 नवम्बर 1949 का यहाँ की असेम्बली प्रोच यूनिटन के अन्तर्गत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्वीकार कर लिया।

युद्धागस्त 3 विद्यमान का इतिहास त्राओस और कम्बोडिया से संबंधित रहता। जापान के शासनकाल में ही विद्यमान में राष्ट्रवाजियों का जोर बढ़ने लगा था और जापान का हटते समय इन राष्ट्रवाजियों का शासन और युद्ध-सामग्री इत्यादि प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो गया कि दोषकाल तक छापामार युद्ध करना मकें। अतएव जापान की सेनाओं के हटते ही राष्ट्रवाजियों ने मिलकर विद्रोह 'रीग' (स्वतंत्रता रीग) नाम के एक आतंककारी गण का संगठित कर लिया। इसका नृत्य साम्यवाद। छापामार नेता हो-ची मिन्ह कर रहे थे। अगस्त 1945 में विद्रोह रीग ने जापान द्वारा लाय गये शासक बाओ इ का 'वा पक्ष' के नाम का शासक था हटने के लिए बाध्य कर लिया। युद्ध के बाद जब यह क्षेत्र पुनः कानूनन शासक का प्राप्त हुआ तो उसने यहाँ की परिस्थिति का मानन से इकार कर लिया। राष्ट्रवाजियों से किसी प्रकार का समझौता करने के बजाय उसने उसका दमन करने का निष्पत्ति कर लिया। उपर साम्यवादी नेता हो-ची मिन्ह का साम्यवादी चान से पूर्ण सहायता मिलने लगा। 1945 से लेकर 19५4 तक सम्पूर्ण विद्यमान में फ्रांस का सेनाओं और हाओ मिन्ह की सेनाओं के मध्य अनेक लड़ने लड़ाई हुई जिनमें फ्रांस को अपरिचित क्षति उठाना पड़ी।

लाओस मे भी प्रात को सी तरह प विरोध का सामना करना पड़ा । 1949 में लाओस प्रासी ती र प व अतर्गत स्वतंत्र देा बना या सेकिन यहाँ क साम्यवादी यों ने इस वयस्या को मानने से इंकार कर दिया और उनके विरुद्ध ताघट लाया या लाओ मुमि नामक आ लेनन संगठित किया और उत्तरी विपतनाम साम्यवादियों क साथ मिलकर कार्यवाही करने लगा । उनकी सेनाओं ने 1953 और 1954 के आरम्भ में अनेक सगरत्र आक्रमण किये ।

विपतनाम म साम्यवादी या और प्रासीसियों के बीच लगातार भीषण सघर्ष चलता रहा और इनमें साम्यवादिया का पनड़ा दिनो दिन भारी पड़ता गया । अंत में मई 1954 म दोन दिन प मे प्रांस की सबसे बड़ी और िर्णायक पराजय न प्रांस की कमर तोड़ दी । प्रांस का साम्यवादियों के साथ सम्झौता करने के लिए बाध्य होना पड़ा । यह बात समुत्त राय अमेरिका को मूल्य नहीं थी । यह प्रांस पर क्याय करने लगा कि प्रांस अमेरिका से मु मंणी अनिक सहायता प्रा त करके युद्ध को जारी रने । जब प्रांस उनके लिए राजी नहीं हुआ तो यह स्वयं हि चीन के युद्ध म प्ररक्षण कद पन्न का प्रयास करने लगा । अमेरिका प इन निदक्षय न हि दम्भोन को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक विशदतम प्र न बना िया । इसके कारण तृतीय विश्व युद्ध की सम्भावना बहुत बढ़ गयी क्योंकि युद्ध में अमेरिकी हस्तक्षेप की स्वाभाविक प्रतिक्रिया स्वयं चीन विपतनामा के कम्युनिस्टों की मदद करता और हग चीन सधि स अनार साविषय सघ चीन का साथ देता ।

भारत का स्थिती — हि चीन के सघर्ष म भारत की िनचरणी कि कुन स्वाभाविक थी । इसका एक कारण था कि भारत यहाँ होनेवाले मदर्ग की राट्याय मदों के हन म लेखता था । यह यरोर के अनिवेगवाद से एक एगिमाई दग को मुक्ति िलाने का प्रयत्न प्रयास था । द्वितीय भारत नी चाहता था कि उसका पाग पकोस में युद्ध की म भयानक स्थिति बनी रहे ि तम तृतीय विश्व युद्ध की सम्भावना थी । यदि किसी दुषंटनायन इसन एक व्यापक युद्ध का रू प्रहण कर लिषा तो भारत इसके प्रभाव से अछूता नहीं रह सकता था । यह सतर तय और बढ़ गया जब 20 मा । 1954 की प्रांस के प्रधान म यात्रिकारीपान एली (Paul Eliy) ने अमेरिका की यह सूचिन किया कि यह उगे सुरत भारी मात्रा म सगमता प्रा त करे कम्पया से कम्युनिस्टा से सधि करने के लिए विषय होना पड़गा । 5 अप्रिल को अमेरिकी विदेश सविष पास्टर डनेस ने मिनट क वदेगिक मामला की समिति की बहा कि अमेरिका हि चीन की कम्युनिस्टों के हाथ में नहीं पडन रगा । इसका अय अमेरिका द्वारा युद्ध में बचना था ।

इस सफटूर्ण स्थिति म भारत न इस रीति तया िनोंदशी में समझता बगान का घन किया । 22 फरवरी 1954 को उहो हि चीन म द नों पक्षों मे युद्ध बर करने की अरीन थी । नहक ने कहा था कि यह दई हो र म की बात है कि दोनों पक्ष समझौता कर सेने का इरादा रखते हैं । फिर भी यह सनी युद्ध चलता जा रहा है ।

प्राम की सरकार ने इस अधीन पर विचार किया और यद्यपि इस प्रस्ताव का कोई महत्वपूर्ण नतीजा नहीं निकला लेकिन शान्ति के वातावरण को प्रश्रुत करने में इसकी सहायता मिली। अप्रिल के प्रारम्भ में पश्चिमी क्षत्रों से जब यह धमकी आई कि यदि हिन्दु चीन में चीन न खुद रूप से हस्तक्षेप किया तो उसके विरुद्ध परमाणुबम का प्रयोग किया जाएगा तो नहरे न तुरत अपना प्रतिप्रिया यत्न करते हुए कहा कि शान्ति स्थापित करने का यह कोई तरीका नहीं है। धमकी का सहारा लेकर हम शान्ति नहीं स्थापित कर सकते। बाद में जब भारतीय रुख में यह सवाल पूछा गया कि क्या भारत अरब क्षत्र से प्राम की मध्य के लिए अमेरिका वायुयानों का गुजरने दगा? हरे का उत्तर स्पष्टतया नकारात्मक था।

युद्ध में स्थिति निर्दिष्ट दिग्गजों के कारण प्राम की सरकार ने समझौता कर लेना ही उचित समझा और काफी विचार विमर्श के उपरान्त हिन्दु चीन की समस्या पर विचार करने के लिए सभी पक्ष एक सम्मेलन के लिए राजी हो गए। 26 अप्रिल से 21 जून 1954 तक यह सम्मेलन जेनेवा में हुआ। यद्यपि इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत का आमन्त्रित नहीं किया गया था लेकिन 24 अप्रिल 1954 का प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हिन्दु चीन की समस्या के शान्तिपूर्ण समाधान के लिए जेनेवा सम्मेलन के विचारार्थ छद्म प्रस्ताव रखा। पहले प्रस्ताव में शान्ति और संधिवाता का वातावरण बनाने के लिए सब सम्बद्ध देशों से यह कहा गया था कि वे धमकियाँ न दें और योद्धा दशा का युद्ध में उजो न लाने की सलाह दी गई थी। दूसरे प्रस्ताव में युद्ध विग्रह के प्रश्न पर सबसे पहले ध्यान दिया जाना चाहिए था। तीसरे प्रस्ताव में सम्मेलन का कहा गया था कि सद्यः समाप्त करने के लिए यह नितांत आवश्यक है कि हिन्दु चीन की पूर्ण स्वाधीनता प्राप्ति की सरकार द्वारा स्वीकार कर ली जाय। चौथे प्रस्ताव में दोनों पक्षों का फ्रांस और हिन्दु चीन द्वारा इस प्रश्न पर सीधा वातावरण करके इस हल करने को कहा गया था। पाँचवें प्रस्ताव में संयुक्त राज्य अमेरिका सोवियत संघ ब्रिटन और चीन का एक ऐसा पवित्र समझौता करने का कहा गया था जिसके अनुसार वे अपने आप आपसी पक्षों का प्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार सहायता न दें। छठे प्रस्ताव में इस सम्मेलन का प्रगति संयुक्त राष्ट्रसंघ का उद्देश्य करने का तथा समझौता करने के लिए उसका सहायता लेने की बात कहा गया था। इन प्रस्तावों का जेनेवा सम्मेलन पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा।

जेनेवा सम्मेलन और भारत :—हिन्दु-चीन युद्ध विग्रह के लिए का गयी नहरे का अधीन का संयुक्त राज्य अमेरिका का छात्र संसार के लगभग सभी देशों ने स्वागत किया। नहरे ऐसी अधीन करनेवाले पहले राजनीतिज्ञ थे। यद्यपि भारत का हिन्दु चीन के शान्ति सम्मेलन में बुलाने के प्रयत्न सफल नहीं हुए किन्तु उसने इस युद्ध को बंद करवाने के प्रयत्नों में कोई कमी नहीं की। उसके अनुरोध से कोन्फो में मई 1954 में होने वाले दक्षिण पूर्व एशिया के प्रधान मंत्रियों के

सम्मेलन ने इस प्रश्न पर विचार रूप से विचार किया। वस्तुतः इस सम्मेलन के अङ्ग पर जो समुक्त विनम्र निष्कर्ष उसमें नेहरू के छ सूत्री प्रस्ताव की ही दुहराया गया था। ब्रिटेन ने इस समय दक्षिण पश्चिम एशिया में गति स्थापित करने के प्रयत्नों में भारत से बड़ी सहायता ली। वा. के. कृष्णमनन जेनेवा सम्मेलन के समय वहाँ उपस्थित रहे ब्रिटिश प्रधानमंत्री ईडन ने नेहरू का लिख एक पत्र में मनन के शर्तित कार्य की विधि रूप से सराहना की।¹

हिंदी चीन के सम्बंध में भारत द्वारा किये गये प्रयत्नों का मर्मोक्त करते हुए चेम्बरलैन ने लिखा है। भारत ने हिंदी चीन में फ्रांस के जीवननिर्वाहक साम्राज्य का समर्थन करने की निष्पत्ति के सम्बंध में हमें बार बार चेतावनी दी थी। जनवरी 1954 में नेहरू ने विराम स्थापित करने पर न दिया तो उत्तरदायी अपराधियों ने उन पर साम्यवादी की भाँति सद्भावभूति का दोषारोपण करते हुए यह कहा कि वह दोषी है। चीन को उसकी निकट भविष्य में होनेवाली हार से बचना चाहता है। तीन महीने बाद दा विन प का पतन हुआ और फ्रांसीसी सेना की गलती का दस्ता में भाषण सैनिक पराजय का सामना करना पड़ा।

जेनेवा सम्मेलन की सफल बनान में भारत की देन को सबों ने एक स्वर से स्वीकार किया है। यद्यपि आधिकारिक रूप से भारत को इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था लेकिन हिंदी चीन का समस्या में भारत की रुचि इतनी अधिक थी कि जवाहरलाल नेहरू ने वा. के. कृष्णमनन का सम्मेलन का गतिविधि पर नजर रखने लिए जनवा भ्रम। सम्मेलन में नपस्य का कटनीति (Behind the scene diplomacy) का बालवाला या और इस कटनीति में मनन ने समझौता कराने का अत्यंत प्रयास किया। इसी कारण जनवा में मनन की उपस्थिति का स्वागत सभी पक्षों ने किया है और मनन के मशरूपण हस्तक्षेप से कई ऐसी बातों पर समझौता सम्भव हो सका जिस पर वार्ता के दूर जान की परा सम्भावना हो। यो था। सम्मेलन के अङ्ग पर विविध दलों के प्रतिनिधि दोनों न मनन के सराहनीय कार्य के लिए भारत का बधा दी। फ्रांस के प्रधान मंत्री ने फ्रांसीसी सशस्त्र में बोलते हुए जनवा सम्मेलन में भारत का सराहनीय भूमिका का निर्वह पर बधाई दी और चीन के प्रधान मंत्री ने कहा कि जनवा में भारतीय कूटनीति का उपस्थिति से इन (दो) हा समझौता का मार्ग प्रशस्त हुआ था।

1 Krishna Menon's mission had been that of a true envoy bringing with him hopes of a great absent powers India determined to smooth out the physiological difficulties which have prevented and to a considerable extent still prevent discussions from developing real negotiations on the substance of the question

—Survey International Affairs 1954 p 47

2 M S Rajan *India in World Affairs* (1954-56) p 129

जनवा समन्वयता और भारत-जनवा सम्मेलन न 21 जून 1954 का मुद्दे बन्द करने का समझौता किया। सुदूरत का गुर्तो क अनुसार आश्रम और कम्प्लेक्स का उत्पन्न घोषित कर दिया गया। यह निश्चित था कि विश्व सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। जाओस क सम्मेलन में यह घोषणा का गया कि 1954 के विवाचन पर निर्मित हानिमान गणाय सरकार में पाठ्य भाषा के प्रतिनिधित्व को भी शामिल कर दिया जायेगा। विद्यतनाम के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्थाएँ का गयीं :—

(1) विद्यतनाम का भाषा में बदल गया। उनका विश्व नाम और रीति विद्यतनाम। 17वीं जनता रक्षा के तहत में हानि नहीं मारता। भाषा भाषा उनगे विद्यतनाम सम्मेलनियों का बिना बार उस दिना में य क्षता विद्यतनाम रणगात्र की स्थापना पर।

(11) गतों भाषा के बीच एक वरत सत्र का भाषा भाषा का गया।

(111) प्राभासी स्थापना पर भाषा विद्यतनाम का। क न का निम्न भाषा।

(111) समस्त भाषा के निम्न का निम्न करने के लिए बन्ना की गया कि जून 1956 में निर्मित नीति मन्त्र जनता द्वारा गतों भाषा का एकाकरण किया जायेगा।

(11) गतों भाषा मन्त्र की गतों का पानत करने के लिए निर्मित भाषा अन्तराष्ट्रीय विद्यतनाम आयोग का भाषा का गया। स्वर सम्मेलन-भारत जनता और पानत बनाय गये आयोग का भाषा भारत का भाषा गया।

अन्तराष्ट्रीय विद्यतनाम आयोग और भारत भारत अन्तराष्ट्रीय विद्यतनाम आयोग की सम्मेलन स्वीकार के गया नहीं। सम्मेलन में कूटनीतिक सत्र भाषा उत्तम पुष्पभाषा की गया। भारत न सम्मेलन की वरत करने के लिए कुछ गतों रक्षों और उच्च उनकी गतों मन्त्र का भाषा का गया। ता वह इस महान् उत्तराधिकार (नष्ट) का स्वीकार करने का तयार हो गया। भारत के कूट नीति सम्मेलन का आवाचना भाषा दिना न सम्मेलन में सम्मेलन प्रान्त सम्मेलन किया। उनका कहना था कि भारत सम्मेलन विद्यतनाम का वरत करने को तयार नहीं होता तो सारा जेवा समझौता भाषा हो जा। और सम्मेलन का राजनीतिक सम्मेलन असम्भव हो जाता। सम्मेलन स्वीकार होता न। मुद्दे का प्राप्ति और सम्मेलन भारत का अन्तिम होता।

कम्प्लेक्स और नाजोस के सम्बन्धित जनवा सम्मेलन बिना विश्व विषय सम्मेलन के भाषा हो गया। सम्मेलन सम्मेलनों में सम्मेलन करने की भाषा उद्देश्य की दिना सम्मेलन विषय सम्मेलन नहीं दिना दिना अन्तराष्ट्रीय विद्यतनाम आयोग का विद्यतनाम में वरत भाषा सम्मेलनों का भाषा करना पडा। जनवा सम्मेलन के उत्तराधिकारी विद्यतनाम की राजधानी भाषा में निर्मित (Lgo Dixx Die) न सम्मेलन सत्र सम्मेलन। वह सम्मेलन का तय गतों विद्यतनामों के

एकीकरण के लिए कराये जाने वाले चुनावों का प्रबल विरोधी था। जब अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग सगोन पहुँचा तो अमेरिका के निष्कर्ष पर उसने इसका साथ सहयोग करने से साफ़ साफ़ इन्कार कर दिया। जनवादी समझौते के प्रथम वर्षगांठ पर दक्षिणी वियतनाम ने लोक दिवस मनाया और वियेन द्वारा दक्षिण वियतनामी गण्डो ने अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के संस्था को उनके हॉटल में घेरकर उनके समक्ष प्रस्ताव किया और अपनाका का व्यवहार किया। भारतीय संस्था के विरुद्ध उनका आश्रित बिरोध रूप से तीव्र था। फिर भी इन्हीं परिस्थितियों में भारत अपने एक महान अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व का निर्वाह करता रहा। 1964 में जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने वियतनाम में खुली आक्रामक कारवाही शुरू कर दी तब अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग बंद हो गया।

स्वेज का संकट और भारत

स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण :—स्वेज नहर का निर्माण 1869 में हुआ था और इसकी छह रेल तथा संचालन एक स्वेज नहर कम्पनी करायी जिनका शेयर ब्रिटेन और फ्रांस का था। इसकी रक्षा के लिए 1936 की संधि के अनुसार ब्रिटिश सरकार एक सेना रखती थी। तिसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेनाएँ इसी के अनुसार इस प्रदेश का रक्षा करती रहीं। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने पर मित्र में राष्ट्रीयता का आन्दोलन प्रबल हो उठा। मित्र के लोग ब्रिटिश सेना की उपस्थिति को देश के आत्मगौरव से भी च सता तथा प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझने लगे। अतएव मित्र ने यह हटाने की माग की लेकिन ब्रिटेन इन मागों को अस्वीकार करता रहा। बड़ी जल्दी समझौता वार्ता के बाद 27 जुलाई 1954 की हुई संधि के अनुसार 20 जन 1956 तक ब्रिटेन ने स्वेज नहर के क्षेत्र से अपने आठ हजार सैनिक हटाकर इस प्रदेश को खाली करना स्वीकार कर लिया। समझौते के द्वारा यह भी तय हुआ कि यदि मित्र पर तुर्की या किसी अन्य राज्य का आक्रमण हो तो ब्रिटिश सेनाएँ इस क्षेत्र में पुनः आ सकती थी। स्वेज नहर को मित्र का अविभाज्य अंग तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का भाग स्वीकार किया गया और दोनों देशों ने 1888 के समझौते के अनुसार नहर में नौचालन की स्वतंत्रता की गारंटी के पूर्ण पालन का दृढ़ निश्चय प्रकट किया।

इस समय मित्र में कमल नासिर का शासन था। वह पश्चिमी साम्राज्यवाद और प्रभुता का कट्टर विरोधी था। वह अंग्रेजों की दरिता की दूर करने के लिए नील नदी पर आस्वान में बाड़ा बांध बनाना चाहता था। इसके लिए अपेक्षित विनाश घनराशि उसे पश्चिम से प्राप्त हो सकती थी किन्तु जब उसके पश्चिम विरोधी तथा रूस पक्षपाती रुख के कारण पश्चिमी देशों ने उसे यह राशि देने से इन्कार किया तो उसने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण करके पश्चिम के विकास के लिए यह राशि प्राप्त करने का निश्चय किया। नासिर के बयानानुसार स्वेज

नहर का एक अरब डॉलर का मुनाफ़ा प्रतिवर्ष कमाना के सिवा फ़ाय और यूरॉप के हिस्समारी का चला जाता था। इस विधान धन प्रवाह का मित्रवासियों के कल्याण में अज्ञान के उदर्यों से नासिर ने 26 जनवरी 1956 का स्वयं नहर के गणना करण का घोषणा का तथा मिस्र में स्वयं नहर कम्पनी को संगठित को जन्म कर दिया।

राष्ट्रीयकरण का प्रतिक्रिया।—स्वयं नहर के राष्ट्रीयकरण की उधमगा से फ़ाय सिन में तहलका मच गया। सिन का सरकार ने मिस्र के इस काम का वैश्ववाणिज्यापूण वतनाया और 27 जनवरी का मिस्र के पास एक विराय नव नज़ा। नासिर ने उस विराय पत्र का नामज़ूर कर दिया। उसका कहना था कि मिस्र ने स्वयं नहर का राष्ट्रीयकरण अपना सम्पूणता के आधार पर किया है और साथ ही स्वयं नहर में उदाओ के आवागमन में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं सम्पित की गया है। उस पर सिन काफी रज़ मज़ा और उसने मिस्र के सभी सन्निग का जन्म कर लिया। मिस्र पर और भी अधिक प्रतिक्रिया उगाय गया। फ़ाय ने भी सिन का हाँ अन्तर्गण किया। अमरिका सहित अन्य साम्राज्यवादी देश ने भी सिन और फ़ाय का समर्थन किया। महान शक्ति यों में सम्पित सधन मिस्र का साथ दिया।

भारत की प्रतिक्रिया—भारत के लिए स्वयं नहर का बड़ा महत्व था क्योंकि पारवर्षा गंगा में उबक मार निपात और आयात इस पर निर्भर करता था। भारत में इस समय जिनके पक्षपातीय यात्रना चल रही थी और उस यात्रना का सचनता बहुत ही तक स्वयं नहर में नौचानन की स्वतन्त्रता पर निर्भर था। अतएव भारत के ना यह नहीं चाहता था कि नहर का सामान्य स्थिति में किसी तरह का गड़बड़ा हो। जिस नाटकाय गगन राष्ट्रीय नासिर ने राष्ट्रीयकरण का घोषणा का भी वह भारत का अवश्य हाँ मसल नहीं आया। तबन भारत उस पहलू पर विचार नहीं कर सकता है उसका एक ही उद्देश्य था कि नहर के द्वारा नौचानन में को कठिनाई नही हो और इसका आशयन राष्ट्रीय नासिर ने राष्ट्रीयकरण घोषणा के समर्थन ही दे दिया था। अतएव भारत ने राष्ट्रीयकरण का घोषणा का समर्थन किया। 1 अगस्त 1956 का एक सावजनिक संग्राम मापन तत्वे उदाहरणाने कहा कि मिस्र के जन सामान्य में किसी व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करने का पूरा अधिकार। नासिर का यह वाय पूर्व के राष्ट्रवादी के अन्तर्गत है और यदि वही राष्ट्रा का इसका गति का दृष्टि से नहीं देखना चाहें। पश्चिमा एगपस में उन्हें तब की प्राप्ति में का कठिनाई नही होगा। नहलन पश्चिमा देश का चलावना दत्त एव कहा कि वह का ऐसा काम नहीं उगावे जिसके फलस्वरूप काइ सधन प्रारम्भ हो जाय।

संयुक्त-सम्पन्न—सिन और फ़ाय के जिन स्वयं नहर का राष्ट्रीयकरण एक पारवर्षागत था। उसीलिए उस घटना पर विचार करने के लिए 2 अगस्त का

प्रिये फ्रांस और अमेरिका के विभिन्न मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ। यहाँ यह निर्णय किया गया कि स्वयं सङ्घ पर विचार करने के लिए स. म. मे चौबीस राष्ट्रों का एक सम्मेलन बुलाया जाय जहाँ स्वयं सङ्घ के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था का व्यवस्था पर विचार करने तथा मिस्र की तो के साथ साथ नहर का उद्घाटन करने का अर्थ राष्ट्रों के हितों पर भी विचार हो।

16 जगस्त के तदनु सम्मेलन शुरू हुआ। उनमें बार्डिन राष्ट्रों में ही भाग लेना स्वाकार किया। सम्मेलन में तीन योजनाएँ रखा गया। डेलस योजना गोलाब योजना तथा मनन योजना। डेलस योजना में 1888 के समझौते का प्रस्तावना का हा भाँत यहाँ कहा गया था कि इस नहर को सब देशों के लिए मुक्त और गतिकान में समान रूप से खुला रहना चाहिए। साथ ही इस योजना में नहर पर मिस्र का सर्वोच्च सत्ता को मान्यता दी गयी तथा नहर का चयन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सङ्घ की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। इस बाढ़ को जल काया की रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्रमण को देना था और उस के लिए अधिकार एवं सुविधाएँ मिस्र को सरकार से प्राप्त करनी थी।

दूसरी विभाग मंत्री शालाब ने अपनी योजना में मिस्र के सम्प्रभु अधिकारों को मान्यता देना तथा सब देशों के लिए नहर को हमारा स्वतंत्र और खुला रखना तथा मिस्र द्वारा नहर की सुरक्षा परम्परा आदि की व्यवस्था का माग था कि तु भारतीय प्रतिनिधि दृष्टि मनन के प्रयत्न से गोलाब न अना योजना वापस लेना।

मनन योजना — डेलस योजना से सर्वदा भिन्न एक योजना (मनन योजना) भारत ने प्रस्तुत की। भारतीय प्रतिनिधि ने पहले डेलस योजना की आलोचना की और कहा कि स्वयं सङ्घ मिस्र का सम्पत्ति है। उस अंतर्राष्ट्रीय सत्ता का स्थापना का अर्थ एक नये मानवाङ्क के साथ स्वयं सङ्घ के मन्त्रियों का फिर से जावित करना है। उन्होंने कहा कि यहाँ सम्मेलन अमेरिका योजना का स्वाकार कर लेता है तो मिस्र से वापस के सार द्वार ब. हो जायेंगे और नताजा युद्ध भी नही निकलेगा।

इस उद्घाटन उद्घाटन अन्ती योजना पक्ष की विमर्श छ. गता पर जारी रखा गया था। इस योजना में नहर पर मिस्र की सर्वोच्च सत्ता का और इस से व गुना रखन का सिद्धांत स्वाकार करते हुए भोगा न प्रतिनिधित्व के आधार पर नहर का उद्घाटन करनेवाले को का एक परामर्श मंत्री मर्या बान का बात था।

परंतु न सम्मेलन ने मनन योजना का स्वाकार नहीं किया। सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रभाव सर्वोच्च था। जहाँ 22 जगस्त का सत्र दोषों ने डेलस-योजना का सनघन कर उसे स्वीकार कर लिया। सम्मेलन द्वारा यह भी निर्णय किया गया कि अरब निया के प्रधान मंत्री राबर्ट मनीज डेलस योजना का लेकर जाहि जायें। मनन न इस निर्णय का विरोध किया। उनका कहना था कि

सम्मनन सम्भव का मुख्य पक्ष—मित्रता मित्र नहीं था है। इसका अपुष्टि में तो निषेध था है उसे किसी भाँति भारत में उपको मानन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। मनन का मुन्नाब या हिंसा न सम्मनन का पूरा कार्यवाही राष्ट्रपति नामिर के पास भेज दा आप लेकिन सम्मनन इस बात को भा नहीं माना।

मुरक्षा परिषद की कारव ३—3 मितम्बर से 9 मितम्बर तक मैजोर काहिरा में राष्ट्रपति नामिर से सम्मनोता-वाना करत रहें। तकिन यह सम्मनोता वार्ता असकन रही। मैजोर गरा प्रस्तुतप्रस्तावा का राष्ट्रपति नामिर न मित्र की प्रमुनता पर हस्तगत करनेवाला काम बजा कर ठकरा दिया।

इस मित्र के वसकन होन पर 12 मितम्बर 1956 को ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की कि सिन फ्रांसिसा प्रमरिका स्वतंत्र नहर में से गुजरनवाने यातायात का उन्नरणाधिक लेन के लिए उसके उपयोग करनेवालों का सघ (Suez Canal Users Association) गठित कर रहे हैं। इस सघ का एक कार्यालय भी खान लिया गया। सोविषत सघ ने इसकी कट आलोचना की। भारत में भी इसका विरोध तीव्र प्रतिष्ठित था। जवाहरनाथ नेहरू ने इस पर जाना मत प्रकट करत हुए कहा कि इस सघ की स्थापना में सघ का सब पक्ष के बजाय बग़ा।

नेहरू का इस घोषणा ने सिन जोर फ्रांस को आक्रामक कार्यवाही बत करन के लिए प्रेरित किया जोर 13 अक्टूबर 1956 को सारा विश्व सुरक्षा परिषद के समनन रखा गया। मुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पेश हुआ जो इनेस यात्रना में मित्रता जुनता या जात्र ब्रिगस पुन उन्नरणाधिक नियंत्रण का बात आयी गया थी। अन्तः सोविषत सघ ने बात का प्रयोग कर इस रुत कर दिया।

मित्र पर आक्रमण—जब सिन जोर फ्रांस मित्र में हस्तगत करने का मोहा ने इने तो ताकि व स्वतंत्र र पर इन स्वतंत्र स्थापित कर सकें। यह मोहा उन्हें मात्र भी मिन गया। 29 अक्टूबर 1956 का इजरायल ने अरबों प्राचान गुत्र मित्र पर सम्मनवत उनकी सनाह अथवा प्ररणा से जवानक आक्रमण कर दिया। यह आक्रमण जना आक्रामिक या कि इजरायल सनाए मित्र प्ररणा में सहसा हा पकास मान अन्तर तक इस गयीं और इस प्रकार उन्होंने स्वतंत्र नहर तक का आगो नुरा रुत कर ली। इस पर तुरा यह या कि इजरायल द्वारा यह जागेर उन्नरणा या कि इसका सनाह उन्नरणाधिक मित्र पर है जिसकी उन्नरणाधिक कार्यवाही ने इजरायल को उन्ना बटोर काम उन्नरणा का बाप किया है।

इजरायली आक्रमण का ठाक दूसर ही दिन 30 अक्टूबर को सिन के तका जान प्ररणा मन्त्री श्री एयानी ईन्त ने ब्रिटिश नाकसना में यो घोषणा की कि फ्रांस और सिन की सुरक्षा में मित्र एक इजरायल से यह मांग की है कि वे परमाणु युद्ध करना बन्द करके स्वतंत्र नहर में इस मान पर तक अपना सनाह हटा दें और इस बात के लिए सम्मति प्राप्त करें कि सिन तथा फ्रांस में सनाह पाट सनाह दाना-रिया एक स्वतंत्र के सहत्वपूर्ण स्थानों पर अन्त्याया और पर अन्त्याया नियंत्रण स्थापित कर न

ताकि युद्धगत शानों पक्षा को परस्पर लड़ने से रोका जा सके और स्वेच्छ गहर म जहाजों के स्वतंत्र आवागमन की गारंटी दी जा सक। इस माँग का उत्तर देने का निये मिस्र को केवल बारह घण्टे का समय दिया गया और यह चतावना दी गयी कि यदि इन अवधि में दोनों पक्षों ने प्रस्तावित बातों पर अमन नहीं किया तो ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी फौज स्थिति को सुधारने के लिए हस्तक्षर करेंगी।

स्वल्प काल से स्वेच्छ पर ब्रजा जमान का यह एक ब्रिटिश फ्रांसीसी बाल थी। मिस्र का राष्ट्रपति नासिर ने क्रिने और फ्रांस के इस संयुक्त अटिम्भम को अन्वाकार कर लिया। इन पर ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी वायु सेना का हवाफ् जालों ने साइमन स्थित हवाफ् अड्ड से उड़ान भर कर मिस्र का महत्त्वपूर्ण कृषि स्थला पर हमला बोन दिया। कभी दिन सुधा परंपद में सब राटोस मिस्र में सना का प्रय। न करन की प्राथना करन वाला प्रस्ताव फ्रांस और ब्रि न क वा। क कारण फ्रांस न हो सका। यह प्रस्ताव अमरिका द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिम्मे यह माँग रखी गयी थी कि इजरायल अविनश्य अपनी सनाएँ मिस्र से वापस बना न और संयुक्त राष्ट्रसंघ के सभी सस्य मिस्र के क्षेत्र में शक्ति का प्रयोग न कर अपवा शक्ति का प्रयोग करने को धमकी न द।

मिस्र पर आक्रमण की भारतीय प्रतिनिधिया—मिस्र पर सान दशा का इस हमले पर भारत में तीव्र और तत्काल प्रतिनिधिया हुई। वही पुरानी बराफ (An old familiar evil) सान उनिवेगवाद की पुनर्जीवित करन का नया प्रयास (New attempt to revive the old style colonialism) नरु की तात्त्विक प्रतिनिधिया था। 31 अक्टूबर को भारत सरकार का आर स इस आक्रमण से उत्पन्न परिस्थिति पर एक वक्तव्य प्रकाशित हुआ। इसमें इजरायल का आक्रमण की निम्न बड़ बड़ बातों में की गयी। ब्रिटेन और फ्रांस के राजाहान आक्रमण की तीव्र मरुता करत हुए कहा गया कि यह पुरान उनिवेगवाद का एगिया और अफ्रिका पर फिर स ना ने का काय है। जबकि सान नरु ने कहा वासवी गता ी क मध्य में भा हम अंतरहवी और उनीसवा गतादियों का युग में जा रहे हैं जब लट पाट करना ही पश्चिमी राष्ट्रों का मुख्य साधन होता था। किन अब जमाना वरुन चुका है। एगिया और अफ्रिका का लोग अब जग चुके हैं और किसी मूय पर इस लूटलूट का सहन नरु करेंगे।

भारत की प्रतिनिधिया कवन भरुना करने तक ही सीमित नहीं रही। कर् नीतिक सूत्रों का जरिये यह इस बात का भी प्रयास करन लगा कि आक्रामकों की सेनाएँ मिस्र का भूमि को छोड़कर वापस खनी जाय और युद्ध बं हा जाय। इस कार्य का लिए भारत संयुक्त राष्ट्रसंघ को मुख्य माध्यम बनाना चाहता था। इसनिए उमने सोवियत संघ के उम सुझाव को जिसमें दूसरे बाहु ग सम्मेलन का बनाने का बात कही गयी थी नामजूर कर दिया। संयुक्त राष्ट्रसंघ में स्वच्छ का मामला से ज्ञान का लिए भारतीय कूटनीति सक्रिय हो गयी।

1 नवम्बर 1956 को मित्रकी समस्या पर विचार करने के लिए साधारण सभा का विद्वान् अधिवेशन प्रारम्भ हुआ जिसमें उस समस्या पर बड़ा बंट तथा उग्र विवाद हुआ। ब्रिटिश-प्रारब्ध निधि के खपत काय का अनुना वागिया में अमेरिका द्वारा का गई कायवादा से का।

2 नवम्बर 1956 को साधारण सभा ने संयुक्त अमेरिका का एक प्रस्ताव प्रवृत्त वामत से स्वीकृत किया। उसमें खपत नहुए के प्रयोग में अतिशय प्राप्ति तथा इजरायली सैनिक कायवादा पर अम्मेर बिता प्रकट का कई या और जविनम्ब मुद्ध बंद कराने पर बल दिया गया था। 4 नवम्बर का साधारण सभा ने कनाडा का यह प्रस्ताव पास किया कि संघ के नामाधिक हाग हेमरपोट मित्र में उदादिद कराने तथा मुद्धविगम की यह मान के लिए संघ का एक जागतकागीन सभा (United National Emergency Force) को शक्ति प्रस्तुत कर। इस पर 25 नवम्बर के सनिष्ठ दलों से बना अंतराष्ट्रीय सभा के छह हजार सनिष्ठ मित्र में स्वीकृत कर संघ की अध्यक्षता में शक्ति स्थापित करने के लिए भेजा गया। इन सभा प्रस्तावों में भारतीय प्रतिनिधि दल ने महत्वपूर्ण भूमिका का निरूह दिया।

5 नवम्बर को साविदित संघ ने फ्रान्स और ब्रिटेन का यह बतावना था कि संयुक्त राष्ट्रसंघ के छह सदस्यों के साथ वह मध्यपूर्व में शक्ति स्थापित करने और आक्रमण रोकने का पूरा प्रयत्न करेगा। इसका फौरन प्रभाव पड़ा। फ्रान्स और ब्रिटेन साविदित संघ तथा अमेरिका के संयुक्त विगम में का-गानगी उठ बतुथ। अतः क्या तिन हमारा उठ न संघ का यह पुनः प्रस्ताव दिया कि 67 नवम्बर को मध्य रात्रि में छह सदस्यों के बीच मुद्ध बंद करेगा। 7 नवम्बर का संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा ने एशिया अफ्रीका व दलों का यह प्रस्ताव पास किया कि ब्रिटिश प्राप्तिसा और इजरायली सभाएं मित्र की भूमि से हट जाएं उद्ध नगर के क्षेत्र में अन्तराष्ट्रीय शक्ति स्थापित का जाय। सत से सत (आजोश बनाता तथा कोनम्विया भारत नावें और पाकिस्तान) की एक सन्निधि अंतराष्ट्रीय नेता के बचाये जन के लिए बनाए गई। 15 नवम्बर का इस सभा (UN E F) का अनुना प्रस्ताव मित्र पर बतुथ।

संयुक्त राष्ट्र आधिकारिकीन सभा के सगुन के सम्बंध में भाग्यवादी प्रतिनिधि वृष्ण मनन ने स्पष्ट कर दिया कि यह मित्र का सरकार का आहवा सहा बतुथ का जा सकृपा और अम्बका काम बचन मुद्ध विगम रक्षा की यह मान कराने का मान कि वह छान प्राप्तिसा सभा के अन्तराधिकारी के रूप में मित्र का भूमि पर आदिम अमान वाली सेना (Occupation force) बना।

24 नवम्बर का साधारण सभा ने न ब्रिटिश फ्लेव और इजरायली दलों के सतकान मित्र से हट जाने का प्रस्ताव पास किया। 22 दिसम्बर तक ब्रिटेन और फ्रान्स ने भारत बतुथ कायिमा के साथ मित्र से बतुथ फ्रीव तथा नी किन्तु इजरायल ने गाजा का पूरा तथा गर्मेन अम्ब क्षेत्र से बतुथ सेनाएं इजरायल से अन्कार

किया। 19 जनवरी तथा 2 फरवरी 1959 का साधारण सभा ने 'जबरायन द्वारा फौज हटाने के तथा महासचिव का इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के दो अर्थ प्रस्ताव पास किये। 'जबरायन ने इसका भा पावन नहीं किया। इसके बाद छा प्रतिष्ठानों ने यह प्रस्ताव पारित किया कि सब राज्य जबरायन को मनिक तथा आर्थिक सहायता देना बन्द कर दें। इस पर पहली माच 1957 का जबरायन ने कुछ गरीबों के साथ सेनाएँ हटाना स्वाकार किया और 7 माच तक सब सेनायें हटाने ली गयीं।

स्वेज सफट के शुरू से अत तक भारत की सरकार और जनता मित्र का पूरा समर्थन करती रही। इसके साथ ही ब्रिटिश राष्ट्रपति नासिर पर भरोषा दवाव डालती रही कि वह योना समय से काम लें और ऐसा कार्य कर लें। अनाये जिसे समझीता करने में विघ्न बाधा पड़े। पश्चिम के लेखकों और प्रेक्षकों ने भी इन बातों का कबूल किया है कि स्वेज सफट को निपटान में भारत की देन अत्यंत महत्वपूर्ण थी।¹

हंगरी में सोवियत हस्तक्षेप और भारत

हंगरी विवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि—हंगरी की धना जिनका भूतगत सोवियत मध्य के हस्तगत से हुआ था स्वेज सफट समसामयिक था। हंगरी विवाद के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का रूप यह है कि सन् 1949 में ही निर्धारित है कि मध्य यूरोप के इस छोटे देश में द्वितीय महायुद्ध के बाद सोवियत देश का सविधान बना और 18 अगस्त 1949 को यहाँ सोवियत संधक जनता का गणराज्य स्थापित हुआ। 23 अक्टूबर 1956 को हंगरी के प्रतिनिधियों की तरफ से सुधार में स्थापित विरोध प्रकटित हो गयी। इन तरवों का संयुक्त राज्य अमेरिका से सहायता मिल रही थी। प्राति अदवा बगावत होने पर हंगरी की तत्कालीन सरकार, सरकार ने सोवियत संधक से सहायता अनुरोध किया कि वह हंगरी में प्राति स्थान रखने के लिए सैनिक सहायता दें। सोवियत संधक सहायता से कुछ ही दिनों में विद्रोह दब गया और हंगरी सरकार की इस छा में सोवियत सेना वापिस बर्ना ली गयी कि कुछ सोवियत फौजों को ली ने हो विरोधियों ने बर्ना धमने पर बर्ना और विद्रोह शुरू कर दिया। उसी माँग थी कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री इमरे नेगा (Imre Nagy) को फिर से प्रधानमन्त्री बनाया जाय। अतएव नेगी को न प्रधानमन्त्री बना दिया गया। बूब इस समय तक विरोधियों को

1 Throughout the period when the Suez crisis lasted the Government of India played a conciliatory and constructive role in furtherance of mutually satisfactory settlement by negotiations. In fact Western observers conceded that to India it was due much of the credit for moderation and restraint in the actions and opinions of the Egyptian Government throughout the acute phase of the Suez crisis. —M. S. Rajan *Indian World Affairs* (1954-56), p. 178

अमेरिका से काफ़ी सहायता और प्रेरणा मिल चुका था। अब वह हंगरी से सावित्र सना हंगरी की मांग करने लगा (1946 में इस और हंगरी के मध्य हुए एक समझौते के अनुसार रूसी फ़ौजें हंगरी में रहती थीं)। इसमें लगा का विदेश हाईर सावित्र रूस से यह मांग करना पड़ा कि वह हंगरी से अपनी फ़ौजें हटा ले। 1 नवम्बर को लगा ने एक नयी संयुक्त सरकार बनायी। वारसा पक्ष का परित्याग कर दिया और संयुक्त राज्य ने अपनी सहायता का रक्षा करने का मांग का। पर नवी के मुख्य सहायक किंतु रूस के प्रबल पक्षाधारी जानोन कादार (Kadar) ने हंगरीवा प्रतिकारा अमेरिका तथा किसानों का सहायता से लगा का सरकार का उन्मूलन किया और अपना सरकार बनायी। तत्पश्चात् उसने नुरत दो विधियों का दवान कर लिए सावित्र सघ से उना नवन का अनुरोध किया। उसके उत्तर में 4 नवम्बर को रूसी सनाया ने हंगरी में प्रवेश किया और 22 नवम्बर को नगर नगी का अन्तर्गण कर लिया गया। रूसी सनाया का सहायता से का सरकार ने अमेरिका द्वारा प्रोत्साहित प्रति का चुरा तरह से कुचन किया। अनुमानतः दो लाख हंगरी जनता का उन्मूलन वारसान के अत्याचारों के कारण अपने देश से बाहर भागना पड़ा।

सुरक्षा परिषद में हंगरी का प्रश्न—जब सावित्र सना का सना हंगरी में प्रतिशक्ति का दवान कर लिए आग वरही था उसी समय अमरीकी ने सुरक्षा परिषद से रूसी हस्तगत के विरुद्ध अपने देश की रक्षा का प्रायना की। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक अच्छा अवसर मिल गया। 4 नवम्बर 1946 को उसने सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें यह आशा व्यक्त की गयी थी कि सावित्र सघ अपना सना को हंगरी से वापस बुलाकर अपने हस्तगत का अन्त करे। प्रस्ताव पर बोलते हुए सावित्र प्रतिनिधि ने कहा कि उसका सना हंगरी में वहाँ का सरकार के बुलाने पर गया और सुरक्षा परिषद का इस बात में हस्तगत करने का काम अविकार नहीं है। उसने सुरक्षा-परिषद के इस प्रस्ताव का नही पास करने का अनुरोध किया लेकिन जब अन्त में प्रस्ताव पर मतदान हुआ तो सावित्र सघ ने वागों का प्रयोग करके उसे रद्द कर दिया।

साधारण सभा में हंगरी का प्रश्न—सुखे वा संयुक्त राज्य अमेरिका ने हंगरी के प्रश्न पर विचार करने के लिए साधा न सना का बटक की मांग का। 9 नवम्बर को साधारण सभा का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ। यहाँ एक प्रस्ताव रखा गया जिसका आशय था कि रूस हंगरी से अपनी सना हटा ले ताकि वहाँ संयुक्त राष्ट्र का ऐक्य-रेख में बुलाव कराया जा सके। सावित्र प्रतिनिधि ने इस प्रस्ताव का धार विरोध किया लेकिन इसका काम प्रस्ताव नहीं पड़ा और सभा ने प्रस्ताव का वाकार कर लिया। इसके बाद सावित्र विरोध प्रस्तावों का तीव्रता गयी। हंगरी से सम्बन्धित दस प्रस्ताव साधारण सभा में प्रस्तुत किये गये। गांधी युद्ध के मारचिया का एक अच्छा मोका मिल गया था और वह उस अवसर की किंसा भा मूल्य पर खाना नहीं आसूते थे।

10 जनवरी 1957 को सभा ने एक प्रस्ताव पास करके पाँच देशों का एक समिति स्थापित की और हंगरी की स्थिति का निरक्षण करने के लिए महासचिव का भ्रमण का निश्चय किया। लेकिन हंगरी की सरकार ने इस प्रस्ताव का मानने से इंकार कर दिया। 3 दिसंबर को अपने स मूचना के विषय महासचिव का दान में किसी तारीख को बहाल में स्वागत करने के लिए तैयार है किंतु वह किसी भी हालत में निरीक्षण का हंगरी आन की अनर्मा। नोट रखा। सत्र पूर्व 12 दिसंबर 1956 को एक संविधान विरोधी प्रस्ताव ग्राह्य कर दिया गया जिसमें कहा गया था कि 'इसने हंगरी की स्वतंत्रता का उपहसन करके हंगरी का जनता के मौलिक अधिकारों के उपयोग में बाधा डालकर बाहर का उपहसन किया।' निष्पक्ष विचार के ताल इस प्रस्ताव की सम्भोरता का सब सम्भले जब साधारण सभा इसी तरह के प्रस्ताव दक्षिण अफ्रिका का पास की सरकार के विरुद्ध पास किया जाती लेकिन इन देशों में अमेरिका के विद्यार्थियों का आगमन या आर इसीलिए वही मानव के मौलिक अधिकारों का दमन नहीं हो रहा था। इस कारण इन प्रस्तावों का मूल में जो बात थी वह समा सम्भले थे। इस ने इन प्रस्तावों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और समुक्त राष्ट्रसंघ (असामंजस) को भी सम्भलता नहीं मिला।

लेकिन समुक्त राष्ट्र अमेरिका हंगरी के प्रश्न का सध में बार बार उठा रहा। 10 जनवरी 1957 के प्रस्ताव के आधार पर जिस समिति का संगठन हुआ था उसको हंगरी में प्रवेश की इजाजत नहीं मिली थी। इसलिए इसने हंगरी से भाग कर आनेवाले कुछ सरणार्थियों से भेंट की और उनकी गवाही के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में सो वयत सध को हंगरी में हस्तक्षेप के लिए दोषों ठहराया गया। 10 दिसंबर 1957 को साधारण सभा का ग्राह्य अविश्वेन प्रारम्भ हुआ। इस अधिवेशन में इस रिपोर्ट पर विचार हुआ और बाद में एक प्रस्ताव पास करके फिर सोवियत हस्तक्षेप का निराकार किया। साथ ही समुक्त राष्ट्रसंघ के अध्यक्ष जिस वाम अधिकांशों को उत्तरदायित्व सौंपा गया कि हंगरी जाकर वही समुक्त राष्ट्रसंघ के सध को पूरा करने का प्रयास कर। लेकिन हंगरी की सरकार समुक्त राष्ट्रसंघ के किसी भी प्रस्ताव पर राजी नहीं हुई।

हंगरी में सोवियत हस्तक्षेप और भारतीय प्रतिक्रिया—हंगरी में सोवियत हस्तक्षेप के प्रति प्रारम्भिक भारतीय दृष्टिकोण को आनाचना देना और विदेश दोनों जगह हुई। हंगरी में जिस समय सो वयत हस्तक्षेप शुरू हुआ उसक प्रति अपनी प्रति क्रिया व्यक्त करने में भारत सरकार ने असाधारण विलम्ब किया। इसका कारण यह था कि इसी समय स्वयं सकट अपना भरम सीमा पर पहुँचा था और भारत सरकार का ध्यान पुनर्स्थापनी पर केंद्रित था। इसके भी कई कारण थे। मिस्र और भारत का सम्बन्ध बहुत दिनों से अस्थिर माना जाता है क्योंकि विदेश-नीति के क्षेत्र में राष्ट्रपति नागिर और प्रधान मंत्री महार एक ही विचार के पोषक थे। असमंजस की नीति में दोनों का अन्त विरुद्ध था। फिर स्वयं संकट में भारत का विराट — 13

का अपना हित बना रहा तक जग हुआ था। यदि किसी कारणवश स्वयं नहर बन गई तो भारत की अर्थ-व्यवस्था पर इसका तत्काल प्रभाव पड़ता। इस हानत में भारतीय दृष्टिकोण से स्वेज नहर की समस्या का समाधान अत्यंत आवश्यक था। हंगरी के साथ ऐसी कोई बात नहीं थी। वह भारत से बहुत दूर था और भारतीय जनता की उसमें कोई विशेष रुचि भी नहीं थी।

द्वितीयतः भारत सरकार को हंगरी में होनेवाली घटनाओं का सम्बन्ध में आधिकारिक तौर पर तुरंत सूचनाएं न मिल रही थीं। यह ठाक है कि हंगरी के साथ भात का कूनातिक सम्बन्ध था लेकिन हंगरी के लिए पृथक् रूप से का भारतीय द्वावास बहापस्ट में स्थापित नहीं था। सोवियत सभ में भारतीय राजत्त ही हंगरी क लिए भा काम करता था। जब हंगरी में घनाए घटन लगीं उस समय द्वावास का काइ दरिष्ठ प्नाधिकारी वहाँ नहीं था। भारत सरकार का अर्थ कई मूत्रा स सबसे अवश्य मिन रही थीं लकिन यादातर वे एफ एसर की विरोधी था और उन पर विवास करक नीति निश्चय करना सहज नला था। इनम स बहुत सबरी र शा यद्ध की छाप स्पष्ट रूप से परितक्षित हो रही था। तसा कि नेहरू न कहा था कि स्वज संकट क सम्बन्ध में सभा बाते विन्तुन साफ हैं लेकिन हंगरी क विषय में कोई स्पष्ट चित्र उसत घ नहीं हा रहा है। उस हानत में भारत सरकार हंगरी क सम्बन्ध म तुरत अपनी प्रतिप्रिया व्यक्त नहीं कर सकती था।

बात में जब कुछ दिवसनीय मूर्तों स भारत सरकार का हंगरी क सम्बन्ध म कुछ जानकारी मिलन लगी तब उस सम्बन्ध म भारतीय दृष्टिकोण स्पष्ट हान उगा। 25 अक्टूबर का जवाहरलाल न कहा कि इसमें कोई सन्देह नहा कि हंगरी क राष्ट्र जागरण म सावियत सभ न सनिद हस्तार किया है। बात में मूर्तों क नवे अधि वशन (नयी निन्ना) म बोन्त हुए उलान पच्चीन का उत्तरत दिया और कहा कि यह वन आन्ध्रकी बात है कि पच्चीन को माननेवाले राष्ट्र इस सिद्धांतों के उत्तरन करने म कोई वसर नहीं उठा रहे हैं। नेहरू का सकेत स्पष्टतया सोवियत सभ । आर था क्योंकि उस समय मिस पर आक्रमण करनवान नशा न पच्चीन की सति को नहीं माना था।

9 नवम्बर का मयक्त राष्ट्रसभ की साधारण सभा में हंगरी के प्रन पर विचार हुआ और सोवियत हस्तक्षन की निन्दा करते ए दस प्रस्ताव पन दिय गय। इन प्रस्तावों पर बाते हुए भारतीय प्रतिनिधि वी० क० कृष्ण मन्न ने कहा कि हंगरी के सवान का गीत युद्ध का प्रश्न बनाना गलत होगा। उनका व ना था कि एम तरह के प्रस्ताव को स्वीकार करके मयक्त राष्ट्र सभ रगी की अनता की मन्गयता नो करेगा बरि वहाँ की सभया और भा उनम पायगी। मन्न के एम दृष्टिकोण को बनी कन आनाचना ए। भारत का वन शानातिक पार्श्या न दू वारस बनान की माग की। यह कहा गया कि मन्न का गतिविधि स ऐना प्रतीत हाता है कि वह भारत का प्रतिनिधि न होकर सावियत सभ का प्रतिनिधि हो। मन्न विरोधी आन्गनन न हतना

बड़ा नून पक्ष निम्ना कि जवाहरलाल नेहरू को उस सम्बन्ध में सलाह देना पड़ा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के हर क्षेत्र में स्वतंत्रता पर आक्रमण किया जाना है। हम नहीं चाहते कि गतिविधियों को राष्‍ट्र अपनी इच्छा मनवान के लिए छुड़ा दिया जा सके। यह बात जाहिर है कि हंगरी की अधिकांश जनता अपनी राष्‍ट्र व्यवस्था में परिवर्तन चाहती है और हमने लिए उन विरोध विद्या जिसकी विन्‍गी नेता द्वारा कृत किया गया है। इनके बाद भी कई अवसरों पर जवाहर लाल नेहरू की जनता के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की।

संयुक्त राष्‍ट्रसंघ की साधारण सभा में जसा कि हम देख चुके हैं हंगरी का प्रश्न था वह बरत रहा और भारत सरकार ने इसके प्रति नीति-मुक्त की राजनानि से ऊपर उठकर अपनी दृष्टिकोण अपनाया। भारतीय प्रतिनिधि हमारा यह विश्‍वासनी देखे रहे कि साधारण सभा की मामला के गुणावगुणों पर ध्यान दत्त हुए कोई निष्‍पत्ति करना चाहिए। लेकिन जत्र सभा ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो भारत ने हंगरी के प्रश्न पर क्या ही छल अपनाया जो एक उदरस्थ दण के अन्‍तरूप हो सके। इस बात की कई क्षत्रों में फट आलाचनाए हुई लेकिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विशेषण करने पर प्रतीत होता है कि हंगरी के सभ्य के सम्बन्ध में भारत सरकार का दृष्टिकोण विन्‍गुन ठीक था। भारत ने हंगरी की जनता के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की सोवियत हस्तक्षेप की निन्‍गा की लेकिन संयुक्त राष्‍ट्रसंघ के उन निष्‍पत्ति में सामन्तर बनने से नकार कर दिया जा पूव और पश्चिम के नीति मुक्त से प्रभावित थे।

हंगरी के सम्बन्ध में भारत के दृष्टिकोण को अत्यन्त नरम कहा गया। मिस्र पर ब्रिटेन और फ्रांस के आक्रमण के विरुद्ध भारत ने जारी में अपनी आवाज बजा दी थी। कुछ लोग चाहते थे कि भारत उसी तरह और उन्‍हा राष्‍ट्र में सोवियत संघ की आवाजना करे। लेकिन वे भूल गये कि इन दोनों घटनाओं के स्‍वरूप में जन्म न आसमान का अंतर था। एक खुला और न्याहीन आक्रमण था तो दूसरा हस्तक्षेप था जो वास्तव में सभ्य की गतों के अन्तगत कानूनी दृष्टि से विन्‍गुन उचित था। एक साम्राज्यवाद को लान्‍ड का प्रयास था तो दूसरा हंगरी की जनता की आजादीय अमरिकी प्रभाव से मुक्त रखने का प्रयास था। एक पुराने उपनिवेगवा का पन्‍थ लान्‍ड का प्रयास था तो दूसरा वैचारिक आक्रमण (Ideological aggression) के सिना कुछ नहीं था।

1 In the Hungarian case there was no immediate aggression as in the case of Egypt. The former was really a case of continuing intervention with Soviet armed forces based in Hungary under the Warsaw Pact. In the Suez case the force of aggression came from outside especially for the purpose and it illustrated an old familiar evil a revival of the old style colonialism. The Hungarian case illustrated the new evil of ideological domination. Nehru quoted in *Daily News* Budapest *The Economist* 1 November 1956 P 582

कांगो की समस्या और भारत

1960 से 1963 तक कांगो के अन्तर्ग्रहण युद्ध ने भाषण-मय सन्धि व शांति पर एक महान सतर्कता उपस्थित कर दिया और इस काल में अंतरराष्ट्रीय राजनीति पूरा तरह इसी समस्या पर केंद्रित रहा। 30 जून 1960 का बल्जियम के अन्तर्ग्रहण पंचदश वर्ष तक चले गानवाने आधिपत्य से मुक्त होन के पश्चात् स्वतंत्र कांगो गणराज्य का स्थापना हुई लेकिन दृढात्मक स्वतंत्रता प्राप्त के साथ ही अन्तर्ग्रहण पर मुसीबतों के बादल घिर आये। देश का शासन जरूर बहा का अर्थ-व्यवस्था बना-गाले द्वारा बल्जियन स्वतंत्र गणराज्य में अपनी स्थिति अक्षुण्णित समझकर स्वतंत्र हो गई। परिणाम यह हुआ कि जनमन्त्र्य कागोवासिया के हाथ में शासन चले तथा अर्थ-व्यवस्था एक ही अर्थ-व्यवस्था हो गयी और कांगो के एक प्रांत स्वतंत्र होन का प्रयत्न करने लगे। प्रधान मंत्री जुमुम्बा देश में शासन और व्यवस्था बनाने पचास हजार सैनिकों की कांगोली सेना द्वारा ही रख सकता था लेकिन सेना स्वयं विद्रोह पर उठाई थी। 6 जुलाई को नियोपोलिटन की सेना में अचानक विद्रोह हो गया। 7 और 8 जुलाई को एक ही मोर्चे दूर दक्षिण में बिजविल नामक स्थान पर भी विद्रोह हो गया। बिजविल की मांग बतन में बंदि और सेना के उच्च पदा पर असन देश वासिया की नियुक्ति की थी। बिजविल का एक बड़ा कारण यह था कि कांगोली सैनिक अपने बल्जियन अधिकांश से उन हथियारों को छान लेना चाहते थे जो उनके कागो के सरकारी गानामा में जमा कराने के म्यान पर तेजी से अपने असैनिक देश वासिया में बंदि जा रहे थे। बल्जियम कांगो में न हस्तक्षेप करने के अवसर का ताक में था ही। अतः उसने कांगो के बल्जियनों की सुरक्षा के बहाने 9 जुलाई 1960 का कांगो में अपनी सेना भेज दी। इसके बाद ही बल्जियम के पंचदश स 11 जुलाई को कांगो के एक प्रांत पर कटाका न गोम्ब के नृत्य में नियोपोलिटन के विद्रोहियों को एक पृथक स्वतंत्र राज्य बनाने की घोषणा कर दी और बल्जियम ने उस सरकार को पूरी तरह सहायता देने का प्रस्ताव कर दी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय एक समझौते के अनुसार कांगो के कुछ निश्चित अंश पर दो हजार बल्जियन सैनिकों का रखन की व्यवस्था हुई थी परन्तु इस व्यवस्था का उल्लंघन करते हुए बल्जियन की फौजों कटाका में पहुँचने लगीं। इस पर जुमुम्बा ने बल्जियम सरकार से मांग की कि बल्जियन फौजों का हथियार अपने अंश तक ही सीमित रहना चाहिए परन्तु बल्जियम पर इस प्रस्ताव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उनकी फौजों ने राजधानी के यूरोपियन भाग पर भी अधिकार कर लिया।

संयुक्त राष्ट्रसंघ में कांगो विवाद का प्रवेश—संयुक्त परिस्थितियाँ में 12 जुलाई को प्रधान मंत्री जुमुम्बा द्वारा बल्जियम पर आक्रमण करने तथा कटाका के पृथक राज्य बनाने के लिए मंडलान का आरोप लगाया गया। जुमुम्बा सरकार ने बल्जियम द्वारा कांगो पर आक्रमण माना और 12 जुलाई को संयुक्त राष्ट्रसंघ से यह प्रार्थना की कि कांगो को बल्जियम के आक्रमण से रक्षा के लिए तुरंत सैनिक सहायता दी जाय।

संयुक्त राष्ट्रसंघ में जाते ही कांगो का मामला शीत युद्ध के क्षत्र में चला गया। सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पर आरोप लगाया कि दस हज़ारों बंजरों को वहाँ ज़ेबन सनाआ को पुनः औपनिवेशिक शासन स्थापित करने के लिए भेज रहा है। 13 जुलाई 1960 को सुरक्षा परिषद की बैठक हुई और महासचिव डाग हैमरगोल्ड ने कांगो सरकार को अविलम्ब सैनिक सहायता भेजने की प्रार्थना की। इस बैठक में रूस और अमेरिका बुरी तरह एक-दूसरे के विरुद्ध उग्र रूप में। सोवियत संघ ने बेजिम्बे के आक्रमण की निंदा की तथा अमेरिका पर कांगो की स्वतंत्रता ध्वंसन का घटपत्र का दोषारोपण किया। अमेरिका ने इस दोषारोपण का खण्डन किया। सुरक्षा परिषद ने ट्यूनिशिया का एक प्रस्ताव पास किया जिसमें बेजिम्बे का कांगो से अपनी सना को हटाने का आग्रह दिया गया था और महासचिव का यह अधिकार दिया गया कि जब तक कांगो की रक्षा करनेवाली सेना अपने कार्यों में समर्थ न हो तब तक उसको आवश्यक सैनिक सहायता दी जाय। इसी समय सोवियत संघ ने यह घोषणा की कि यदि कांगो पर पश्चिमी देशों का आक्रमण जारी रहा तो सोवियत संघ कारवाई करने में संकोच नहीं करेगा।

संघ द्वारा कांगो में हस्तक्षेप—सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के अनुसार 28 जुलाई को संयुक्त राष्ट्रसंघ की सेना कांगो पहुँच गयी। इसमें बेजिम्बे और कांगोली सैनिकों का सम्मेलन कराया गया जहाँ अड्डों पर अधिकार कर लिया ताकि बिम्बे की सेना उनका उपयोग कर कांगो में हस्तक्षेप न करे। संयुक्त राष्ट्रसंघ ने कांगो की सना को प्रशिक्षण देना भी शुरू कर दिया ताकि सरकार स्वयं विद्रोहियों का दमन कर सके। जुलाई के अन्त तक संयुक्त राष्ट्र की सेनाएँ बटांगा का घाड़कर कांगो का सभी प्रांतों में पहुँच गयी। अब कांगो का मामला उलझन में आ गया। जंगल में बिजिम्बे की सेनाओं को हटाना तथा बटांगा की स्वतंत्रता स्थापना करना। बेजिम्बे अपनी सेना का हटाने के लिए तैयार नहीं था और बटांगा के प्रधान मंत्री मोम्बे ने यह घोषणा की कि वह अपना प्रदेश में संयुक्त राष्ट्रसंघ की सेना का प्रवेश नहीं करने देगा। उन्होंने बटांगा को पूर्ण स्वतंत्रता घोषित करते हुए संयुक्त राष्ट्र का कार्य का अनन्तित्व बताया। इस हानिकारक स्थिति में संयुक्त राष्ट्रसंघ ने बटांगा की सेना बटांगा में नहीं प्रवेश कर सकती थी। हैमरगोल्ड इससे बचना चाहता था। उमन घोषणा की कि सना बटांगा में नहीं घुसगी। इसके बाद सुरक्षा परिषद में एक पर विचार होने लगा। वहाँ एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें बिजिम्बे की सेना का बटांगा से तुरंत हट जाना की मांग थी। इस प्रस्ताव ने बटांगा में संयुक्त राष्ट्रसंघ की सेना का प्रवेश भी आवश्यक बताया। सुरक्षा परिषद ने इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए महासचिव हैमरगोल्ड स्वयं दो विचारणीय व्यक्तियों की मंडली सेना लेकर बटांगा के लिए रवाना हुए और 16 अगस्त को यह सेना बटांगा में प्रवेश कर गयी।

संघ द्वारा हस्तक्षेप का नतीजा यह हुआ कि कांगो में तुरंत ही एक गृह-युद्ध ने भीषण रूप धारण कर लिया। संयुक्त राष्ट्र गृह-युद्ध अफ्रीकी राष्ट्रों और यूरोपीय

साम्राज्यवाद का बीच युद्ध था जिसमें एक पक्ष का प्रतिनिधित्व मुमुक्षा और दलितवाद का एक पक्ष का रूप में साम्राज्य का प्रतिनिधित्व गान्धी कर रहा था। समस्या का एक दूसरा पहलू भी था। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और सांप्रदायिक पक्ष मध्य पूर्व युद्ध का एक मुख्य विषय बन गया।

भारतीय राजनीति —कांग्रेस में घटनाएँ जिस नाटकात्मक ढंग से घटीं उनका विस्तारपूर्वक वर्णन करना हमारा उद्देश्य नहीं है। जना हाइकोर्ट द्वारा घोषणा की कि यह महायुद्ध न मजदूरों का कारण बन गया जिससे हजारों हजार लोगों की मृत्यु लम्बेबाँव का या अश्वारोही युद्धों के कारण हुई। महासचिव का भाषा निम्नलिखित है : "नृप घटनाक्रम के दौरान भारत का दृष्टिकोण दिखाने का था। भारत मानता था कि कांग्रेस का सत्य मूल्य रूप से अविरोधवादिता — हस्तक्षेप का परिणाम है। अतएव उनमें से ही बहारा हस्तक्षेप का निरास किया और यह दृष्टिकोण बनाया कि समस्या का समाधान केवल संयुक्त राष्ट्रमंडल के जरिये ही चाहिए। चूंकि कांग्रेस का प्रश्न था दुनिया के मध्य पूर्व-युद्ध का प्रश्न बन चुका था और उस विषय शक्ति का स्तर था इसलिए भारत सरकार का चिन्तित होना दिखाने स्वाभाविक था। अतएव समस्या के समाधान में भारत ने संयुक्त राष्ट्रमंडल का मदद रूप से स्थापना की। अतएव प्रारम्भ में संघ ने निम्न किया था कि कांग्रेस में शांति व्यवस्था की स्थापना के लिए संघ की सलाह भी दी जाए और महान के उद्देश्य धाना गिना किया। आर्य गणराज्य, लाइबेरिया, मारको और अन्योपा के गणराज्य उस हजार सैनिक कांग्रेस पक्ष में। उन्हें हजारों जहाज से पश्चिम में जिन देशों ने संघ की सहायता की उनमें भारत भी था। इस अतिरिक्त विश्विद्यालय और संकेत के लिए भा भारत ने अलग बुद्ध सैनिक भेजे। बाद में संघ के महासचिव डॉ. हेमरिंग्टन ने अंतर्राष्ट्रीय सैनिकों की कांग्रेस पर उन्हें परामर्श देना एक समिति का निर्माण किया और कांग्रेस में भारत के राजदूत दयानंद का अगला निम्न प्रतिनिधि नियुक्त किया। कुछ ही दिनों में राजदूत दयानंद ने कांग्रेस की स्थिति पर अपना एक लम्बा चौथा रिपोर्ट महासचिव को प्रस्तुत की। उसमें कहा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायिकवादी कांग्रेस को संरक्षित करने में सहायता दी है, दलितवाद अति कारियों ने उन घटनाओं का उच्चारण किया है और कुछ दिनों में अंतर्राष्ट्रीय अमान्य वीर काय करने के लिए प्रारम्भ से उत्तरदायी हैं। कुछ दिनों में उनका अन्त एक विश्वव्यापी बनने का रहा है। कांग्रेस में उस समय कोई सरकार नहीं है कांग्रेस का उक्त मुद्दा तथा मुद्दा के स्थान पर अराजकता उत्पन्न कर रहा है।

कांग्रेस का रण हा अभावही बिना था और चूंकि उसमें पूरा सच्चाई या दलीलें लम्बेबाँव विराधा दलों ने अमान्य की बड़ा आनाचना का और अन्त अतिरिक्त दिनों में उन्होंने प्रश्न भारत विराधा अभियान चलाया।

एन आर्थोचकाका के अवकाश कांग्रेस में गान्धी स्थापित कराने के लिए भारतीय कृपाति सभा सक्रिय रहा। 17 अक्टूबर 1960 का उद्घाटन राष्ट्रमंडल की एक

बठक कागो समस्या पर विचार करने के लिए बठी तो भारत ने कुछ अन्य राष्ट्रों के साथ मिलकर कागो से सार्जित एक प्रस्ताव पत्र किया। संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रथमों के पत्रावली 963 के आते आते कागो की समस्या का समाधान हो गया। इन प्रक्रिया में भारत ने संधि का अरना पूरा समर्थन और सहयोग दिया।

वियतनाम की समस्या और भारत

वियतनाम में अमरीका हस्तक्षेप—हिन्दू चीन की समस्या का ध्यान करते समय हमने जेनेवा सम्मेलन का उल्लेख किया है। जनवा समझौता के द्वारा वियतनाम का राष्ट्र दो पृथक् राष्ट्रों में बंट गया। उनमें वियतनाम और दक्षिण वियतनाम और यह निर्णय हुआ कि अंतर्लिय नियंत्रण आयोग की देख रेख में वहाँ चुनाव सम्पन्न होगा और तब एक ही एकीकरण होगा। जेनेवा सम्मेलन के बाद से वियतनाम के एकीकरण का माँग वियतनामियों द्वारा बराबर होती रही और अन्तरिम कम्युनिस्टों ने इस माँग का समर्थन किया। लेकिन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के दबाव में पड़कर दक्षिण वियतनाम की सरकार ने एकीकरण की सारी माँगों को ठकुरा दिया। जब शांतिपूर्ण रास्ते से एकीकरण का सम्भावना एकदम खत्म हो गयी तो दक्षिण वियतनाम के दंगे भक्तों ने एक आन्दोलन शुरू किया। उन्हीं वियतनामियों ने एक संगठन कायम करके सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक कामवाही शुरू कर दी। वियतनाम आन्दोलन को उत्तर वियतनाम का पूरा समर्थन मिला। बाद में वियतनामियों ने युद्ध शुरू किया और अब दक्षिण वियतनाम की सरकार ने इस कुचनना शुरू किया तो इसने एक गृहयुद्ध का रूप धारण कर लिया।

वियतनाम आन्दोलन दस्तों को हवाई से हटाया मित्रों ने सहा। सितम्बर में कांग्रेस कागो पार्टी का हवाई में तीसरा सम्मेलन हुआ और समस्त दक्षिण वियतनाम को मुक्त करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के तीन महीने बाद हवाई में दक्षिण वियतनाम को मुक्त करने के लिए एक मोर्चा संगठित किया गया और इसके बाद सितम्बर 1961 में दक्षिण वियतनाम के लिए वियतनामियों की परिवर्तमानों की पार्टी नामक एक दल भी संगठित कर दिया गया। इस घटना में वियतनाम की स्थिति अत्यन्त गंभीर हो गयी और 1961 में बड़े पैमाने पर वहाँ जन गृहयुद्ध छिड़ गया। इस समय ने एक नियमित युद्ध का रूप धारण कर लिया। स्थिति काय से बाहर हाथ दख दक्षिण वियतनाम के राष्ट्रपति ने अफिरका में सैनिक सहायता माँगी। मई 1961 में अमरीकी उपराष्ट्रपति जेम्स निसन ने सैनिकों का दौरा किया। बाद में सोल्वर उसने अपना सरकार से यह निर्णय किया कि दक्षिण वियतनाम का अमरीकी सहायता में बढ़ि की जाए। इस पर राष्ट्रपति कनेडी ने अक्टूबर 1961 में अमेरिकन टैक्टरों की दक्षिण वियतनाम हमलापत्र भेजा कि वह साम्यवादी घनोती का सामना करने के लिए सैनिकों की सरकार की आवकताओं को आँके। टैक्टर की रिपोर्ट के आधार पर 4 जनवरी 1962 का संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने दक्षिण वियतनाम को आधिक

इनका उद्देश्य उत्तरी वियतनाम की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को अस्त व्यस्त करना था। अमेरिका के अगलबोर नीति निर्धारका का विश्वास था कि उत्तरी वियतनाम इस नक्सबान की पकड़ में अधिक दिनों तक प्रतिरोध नहीं कर सकेगा और हथियार खाल देगा - किन्तु ऐसा नहीं हुआ।

समझौता के प्रयास - वियतनाम में अमेरिका की कार्रवाई की निम्न 1 सचित्र है। इस कार्रवाई में विद्रोह की सम्भावनाएँ या वयाकि चीन उत्तर वियतनाम की ओर या ओर सोवियत संघ को सहानुभूति भी उसे प्राप्त थी। यदि चीन और सोवियत संघ स्वयंकर उत्तरी वियतनाम के पक्ष में आ जाते तो यह संघर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका तथा चीन और सोवियत संघ के बीच का संघर्ष हो जाता। साम्यवादी गुट में पड़ा 1 फ्रंट में सम्भावना टूटती लेकिन यह कठिन था कि इस ओर चीन कबतक उत्तरी वियतनाम की अमेरिका के हाथों इस तरह हत्या होते देखते रह्यो। अतएव चारों ओर से यह मांग होने लगी कि अमेरिका हवाई हमला बन्द कर दे और वार्ता के लिए प्रयास करे। भारत और फ्रांस की सरकारों ने एक दूसरे जेनेवा सम्मेलन की मांग की। संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव और सतार के अन्य राजनेताओं ने भी समझौता बन्द करने की अपील की लेकिन अमेरिका पर किसी का कोई असर नहीं पड़ा। अतः मार्च 1968 में आर्थिक और सैनिक परिस्थितियों से विरक्त होकर अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन ने एक ना कीय घोषणा की कि वियतनाम में शांति-सम्मेलन करने का उद्देश्य अमेरिका समझौता बन्द कर रहा है। शांति-वार्ता के लिए उन्होंने उत्तर वियतनाम की सरकार को आमन्त्रित किया और मई 1968 में पेरिस में सन्धी पंगा के प्रतिनिधि वार्तालाप के लिए एकत्र भी हो गये। यह वार्ता आज भी बिना कोई विचार प्रगति किये चल रही है।

वियतनाम में भारतीय दृष्टिकोण - जैसा कि हम दस चुके हैं हिंदू के मामले में भारत ने शुरू से ही गहरी रुचि का प्रदर्शन किया है। उस 1954 के जेनेवा सम्मेलन का समर्थन किया और उसको कार्यात्मक स्तर पर अनाम उपयोग किया। हिन्दू शांति मानव उद्देश्य में उसने अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग का उद्घोषण करना और करके एक मानव उद्देश्य प्रण किया।

1968 में वियतनाम में अमेरिका का आक्रामक नीति बिल्कुल स्पष्ट हो गया। जब वियतनाम में अमेरिका का प्रवेश रक्तपात हुआ तो भारत अत्यंत चिन्तित और चिन्तित तरीके में स्थिति में पड़ गया। वियतनाम संघर्ष का स्वरूप एक मर्यादित था। यदि इस युद्ध में कम्युनिस्टों की विजय होती है तो वह बहुत बड़ी चीज की विजय होती और भारत चीन का अपना प्रयत्न मात्र मानता है। इस दृष्टिकोण ने ही वह पूर्व एशिया। चीन के प्रभाव में बड़ी भारतायुक्तियों के लिए बड़ा घातक सिद्ध होगा। इस कारण कुछ लोगों का यह विश्वास था कि भारत को अपने हित को

ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की नीति का पूरा समर्थन करना चाहिए। लेकिन बड़े कारणों से प्रेरित होकर भारत ने ऐसा नहीं किया और बड़े अमेरिका को विपत्तनाम नीति का बड़े धनात्मक बना रहा। यदि भारत अमेरिकी नीति का समर्थन करता तो उसका परिणाम यह होता कि सावियन संघ उनमें नाराज हो जाता और इस हाथ में सावियन संघ से जुड़े हुए हमारे राष्ट्रीय हितों को अंगरेजी पहुँचने। भारत-किस्तान सम्बन्ध भारत-चीन विवाद और कश्मीर की समस्या के बारे में सोचियत मन्त्री हमारे लिए कितनी मूल्यवान था यह काइ दिया हुआ तथ्य नहीं था। इस दृष्टिकोण से विचार करने पर भारत द्वारा उत्तरा विपत्तनाम का समर्थन उचित प्रतीत होता है। और यदि दोनों दृष्टिकोण पर संतुलित विचार किया जाय तो राष्ट्रीय हित की दृष्टि से यह उचित प्रतीत होता है कि भारत 19७4 के जनवा सम्मेलन के कार्यालय पर पूरा बन दे। इसलिए भारत ने अमेरिका की दमनपन की आलोचना की और इसे बन्द कराने के लिए पुरा प्रयास किया। भारत का विश्वास था कि बमबर्षा रोकने से युद्ध के विस्तार का भय कम होगा महाद्व की विस्फोटक स्थिति टन जायगी और पारस्परिक वाता के लिए वातावरण में सुधार होगा। इसी कारण भारत ने अमेरिका से निरंतर बमबर्षा बन्द करने का धनराश किया और जब 1 अप्रिल 1968 को अमेरिका ने सीमित बमबर्षा का निश्चय किया तो भारत ने उसका स्वागत किया और यह आगा यकत की कि इस निश्चय से शांति का भाग प्राप्त होगा। 1972 के मध्य में जब अमेरिका ने पुनः बढ़ते बम परमान पर उत्तर विपत्तनाम पर बमबर्षा शुरू कर दी तो भारत ने बड़े शब्दों में इस आक्रमक कारबाई का निन्दा का।

विपत्तनाम के प्रश्न का लेकर शुरू से ही भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच घोर मतभेद रहा। उत्तर विपत्तनाम के विरुद्ध अमेरिका का आक्रामक सैनिक कारवाँ का भारत ने लगातार विरोध किया। भारत सरकार ने हवाई में भारतीय दूतावास के कार्यालय का दर्जा ऊँचा करने का निश्चय किया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को यह बात पसन्द नहीं आयी और उम्मेद सुले तौर पर अपना नागरिकी जाहिर की।

इससे उत्तरात जुलाई 1970 में दक्षिण विपत्तनाम का अन्तर्गत शक्तिशाली सरकार का विदेशमन्त्री श्यामती बिहू ने भारतीय विपत्तनाम मन्त्रालय सिद्ध के निम्न अतिथि के रूप में भारत का भ्रमण किया। इस यात्रा के लेकर भारत के भारत और बाहर एक विवाद उठ खड़ा हुआ। भारत सरकार द्वारा श्यामती बिहू की भारत यात्रा को रद्द करने के विरोध में निम्न स्थित दक्षिण विपत्तनाम के महावाणिज्य दूत सगोन जोन गेव और इस प्रकार उन्होंने अपना बूटनातिक विरोध प्रकट किया। सगोन में सरकारों तथा गैर-सरकारों हस्त मन्त्रालय बिहू की भारत-यात्रा का उकर बाकी सरगमी पदा हुआ गया। दक्षिण विपत्तनाम का सरकार इस बात से काटा नाराज की कि बावजूद इनके भारत तथा दक्षिण विपत्तनाम के साथ सरकारी स्तर पर सम्बन्ध था भारत सरकार ने मन्त्रालय बिहू का निमन्त्रण बन्द और स्वागत करने को उचित समझा। इसके विरोध में दक्षिण विपत्तनामो छात्रों ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका

का द्वारा पाकर भारतीय दूतावास पर हमला किया। छोड़-फोड़ की कारवाही की और भारत का झुका भा जना दिया गया। तब विमननाम में भारतीय दूतावास की स्वायत्ता की बात तथा सरकारों के रक्षक पर ओमती बिहू का निमंत्रण तथा उनका सगल न न दोना बातों से खुश राय अगिरका की सरकार भारत से काफी नाराज हुई।

1971 के मध्य से भारत और अमेरिका न सम्बंध में बगल देग के प्रश्न को लेकर एक नया मां जाया और दोनों का सम्बंध निरंतर बिगड़ने लगा। इस परिस्थिति में भी भारत और सोवियत संघ के बीच अलग 1971 में एक संधि हुई। इस संधि के सम्बंध होने के बाद यह निश्चित हो गया कि भारत अब पहले से भी अधिक उग्र रूप में अमेरिका की विद्यमान नीति का विरोध करेगा। यह भी स्पष्ट होने लगा कि उत्तर विमननाम के साथ उसका सम्बंध और भी घनिष्ठ होगा। दिसम्बर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जब अमेरिका ने सार्वभौमिकता भारत विरोधी दृष्टि अपनाया तो भारत सरकार ने भी विद्यमान के सम्बंध में अपनी नीति का खुले रूप से स्पष्ट कर दिया। 13 दिसम्बर 1971 को भारत सरकार ने हुनो सरकार के साथ अपने राजनयिक सम्बंधों का दर्जा बढ़ाकर राजदूत स्तर का कर दिया। हुनो से सम्बंध बढ़ाने का बात बहुत अस से विचाराधीन थी लेकिन अमेरिकी प्रशासन की भावनाओं का हवाला करते हुए भारत ने अभी तक इन बातों में कोई काम नहीं उठाया था। जब अमेरिका की भारत विरोधी नीति अपनी चरम सीमा पर पहुँच गयी तो भारत ने हुनो सरकार के साथ अपने राजनयिक सम्बंधों का दर्जा बढ़ाने में जरा भी सतक नहीं किया।

1972 के अन्त में विद्यमान में सति स्थापना की सम्भावना बढ़ गयी और लगा कि पेरिस वार्ता के फलस्वरूप युद्ध विराम हो जायगा। दिसम्बर में सम्झौते का समझौता भी तयार हो गया था लेकिन एकाएक अमेरिका की नीति बदल गयी और उसने पुनः बुरा बहाना पर विद्यमान को ठीका तो पर सम्झौता मुक्त कर दिया। इस बहाने के तहत भारतीय दूतावास पर भी हमला हुआ। भारत ने तत्काल अपना घोर विरोध प्रकट किया। आसिर 27 जनवरी को विद्यमान युद्ध पर सम्झौता हो गया और युद्ध विराम हुआ। यही युद्ध का अन्त हुआ और भारत ने इसका स्वागत किया।

कम्बोडिया का सफट और भारत

मार्च 1979 में कम्बोडिया में एक राजपट्टी के फलस्वरूप राजकुमार नरोत्तम सिंहनक को राष्ट्राध्यक्ष के पद से हटा दिया गया और जनरल सोनोनो वहाँ के प्रधान मंत्री बन। इसके उपरान्त राजकुमार सिंहनक ने पोलिपम अपनी निर्वासित सरकार की स्थापना का लो और कम्बोडिया के देशवासियों को जिनके मोक्ष सरकार को अस्तित्व करने में उनका साथ दें। इस प्रकार कम्बोडिया में गुंडगुंड की घृणनीति तयार हो गयी। चीन और उत्तर विमननाम ने राजकुमार सिंहनक को समर्थन देने का आश्वासन दिया। इसके बाद ही कम्बोडिया में गुंडगुंड दिख

1971 में कम्बोडिया के अपत्यस्य राजकुमार सिहानुक ने एक पत्रकार के साथ विशेष भेट में अपनी यह इच्छा व्यक्त की कि वह अपनी गैरनल युनाइटेड फ्रंट सरकार का एक कार्यालय नयी दिल्ली में खोलना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि इस सम्बंध में उन्होंने भारत सरकार से कोई गौरीयन की या नहीं। वास्तव में राजकुमार सिहानुक ने इस दिनांक का पत्र भी नहीं भेजा।

कम्बोडिया की स्थिति इसका भाग बन गई। जोर नगमग सभी गठनिरपेक्ष सम्मेलन में इस समस्या पर विचार हुआ। भारत ने हर मोर्चे पर अन्य गठनिरपेक्ष राज्यों का साथ देकर राजकुमार सिहानुक को समर्थन देता रहा।

भारत और पश्चिम एशिया का संकट

अरब इजरायल सम्बंध — इस समय पश्चिम एशिया का एक प्रमुख समस्या यहूदी राज्य इजरायल तथा अरबों का उग्र संघर्ष है। पश्चिम में यहूदी समस्या का उत्पत्ति प्रथम विश्व-युद्ध के समय हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटन ने पश्चिम एशिया पर अपना सारा सत्ता समान करने का निश्चय किया और 14 मई 1948 को उसे ही ब्रिटन ने यह घोषणा की कि उन्होंने उसका संरक्षण समाप्त कर दिया है। उसी समय तेन अब्राहम में यहूदियों ने इजरायल राज्य की स्थापना की घोषणा कर दी। उस समय से अब तक अरबों के साथ इजरायल के सैन्य युद्ध हो चुके हैं। प्रथम युद्ध 1948 में हुआ जब अरबों ने इजरायल का स्थापना का विरोध किया। दूसरा युद्ध 1956 में स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के बाद हुआ जहाँ ब्रिटन और फ्रांस के सहयोग पर इजरायल ने मित्र पर आक्रमण कर दिया। उस समय संयुक्त राष्ट्रसंघ के हस्तक्षेप से इजरायल को जीते हुए अरब भू-भागों का छोड़ना पड़ा। युद्ध विशम रहता पर संयुक्त राष्ट्रसंघ की एक आपातकालीन सभा रख दी गयी। लेकिन अरब राज्यों ने अपने सहायकों को बिना रुका रुक इजरायल का नाभिलेखन मिटाना है क्योंकि नई छुड़ाया। इस हानत में दोनों पक्षों के बीच पुनः युद्ध का खतरा अब भी बचता है।

तृतीय अरब इजरायल युद्ध (1967) के कारण — 1964 के अरब राज्यों के काहिरा शिखर सम्मेलन के बाद अरब इजरायल में तनाव आने लगा। सीरिया और जोर्डन से घुसपट्टियों के दमते इजरायल में घुस आते थे जोर ताइ-योड करके उपरत मन्त्रालय करते थे। तब आकर इजरायल ने कई बार इन राज्यों पर प्रयासमण भी किया। इनमें 7 अप्रिल 1967 का सीरिया के विरुद्ध इजरायली कार्रवाई सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी।

7 अप्रिल की घटना के बाद इजरायल और सीरिया की सीमा पर स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण हो गयी। सीमाओं पर दोनों पक्षों के सैनिकों का जमाव होने लगा। ऐसा समझा गया कि इजरायल सीरिया पर आक्रमण करने की पूरी तयारी में व्यस्त है। बातें में ऐसा कि राष्ट्रपति नासिर ने बताया — 'हैं साक्ष्यित गुप्तों से यह जानकारी मिली कि इजरायल सीरिया पर आक्रमण करने की पूरी तयारी कर चुका है।

इन विस्फोटक स्थिति में अरब देशों में भी सैनिक तयारी होने लगी। गाजा क्षेत्र में 1956 से ही संयुक्त राष्ट्रसंघ की आपात सभा रखा गया था कि मित्र इजरायल में संधि को रोका जाय। राष्ट्रपति नासिर ने यह भी कहा कि यह सभा इस क्षेत्र से हटा ली जाय। सब के महासचिव ने इस मांग को स्वीकार कर लिया और

जापान सेना हटा दी गयी। उसके तुरंत ही वात सयुक्त अरब गणराज्य की सेना सिनाई प्रायद्वीप से सटे मिस्र इजरायल की सीमा पर आ बटी। सीरिया और जोर्डान में भी युद्ध की तयारी होने लगी।

मिस्र सऊदी अरब तथा इजरायल से सटे अक्काबा का खाड़ी है जो इजरायल का लान सागर में पहुँचने का रास्ता देती है। इजरायल उस खाने को अपनी जायत रेखा मानता है। 23 मई 1967 को सयुक्त अरब गणराज्य की सरकार ने इजरायल को अक्काबा की खाना में प्रवेश का मनाह कर दी। नासिर ने घोषणा की कि खाड़ी कोई अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग नहीं है। यह मिस्र और सऊदी अरब के प्राणैयिक क्षेत्र में पड़ता है और इसलिए इजरायल को इस पर आवागमन करने का कोई अधिकार नहीं।

सयुक्त अरब गणराज्य की इस घोषणा ने स्थिति का अत्यंत गम्भीर बना दिया। इजरायल के लिए स्वयंभूत रूप से ही वात घो अक्काबा की खाना बंद करके उसका गला घाटने का प्रयास किया गया। ऐसी हानत में अब यह प्रयास निश्चित हो गया कि पश्चिम एशिया में भयंकर विस्फोट होकर रहगा। स्थिति की गम्भीरता को देखकर सयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव यू. थॉमस काहिरा पहुँच और समस्या को दूर करने का प्रयास किया लेकिन काहिरा में उन्हें बार्न एमा उसात्त्वक के लक्षण दिखायी नहीं पड़ा जिससे शांति के प्रयास का और मंजूर किया जा सके। अंत निराश होकर महासचिव यू. थॉमस वापस आये।

उपरोक्त पश्चिम एशिया की तनावपूर्ण स्थिति पर सुरक्षा परिषद में विचार शुरू हुआ। परिषद का 24 मई की बैठक में सोवियत संघ ने स्थिति को बिगाड़ने की चेष्टा जारी कर इजरायल पर हमला और ब्रिटेन तथा अमेरिका पर यह आरोप लगाया कि वे इजरायल का बढ़ावा दे रहे हैं। जबकि अमेरिका ने तनाव में बढ़ि के लिए सोवियत कूटनीति को जिम्मेदार बताया। इस गतिरोध की स्थिति में सुरक्षा परिषद की बैठक स्थगित हो गयी।

ब्रिटेन और अमेरिका ने अक्काबा की खाड़ी के घराय को रोकने तथा अंतर्राष्ट्रीय नियम का उत्तपन बताया। 29 मई को इन दोनों ने इजरायल के प्रधान मंत्री एल्होन को इन बातों का आह्वान किया कि वह अक्काबा की खाड़ी की नाकबंदी खत्म करने के लिए कारबाई करे। साथ ही ब्रिटेन ने पश्चिम यूरोप के देशों से अनुरोध किया कि खाड़ी का स्वतंत्र बनने में वे सहयोग दें। पश्चिम यूरोप के देशों ने इन अनुरोधों में पहल से उत्तर दे दिया और राष्ट्रपति दगात्र ने साफ साफ कहा कि वे किसी भी प्रकार के सहयोग करने को तयार नहीं हैं। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि पश्चिम एशिया में खार बंद रास्ते की एव बंद हो लेकिन एशिया में संघ की प्रस्ताव मान्य नहीं था।

ब्रिटेन और अमेरिका का बरतूस्त पाकर इजरायल ने घोषणा की कि अक्काबा की नाकबंदी आवश्यक है और यदि यह खत्म नहीं किया गया तो इजरायल इन प्रस्तावों को अस्वीकार करके नाकबंदी का सीढ़ देगा। स्थिति उत्तरोत्तर गम्भीर हो रही।

सो थकी सध के युद्धोंन दर्रा दानियात पार करके भूमध्य सागर में प्रविष्ट करने लगे। अरब रक्षा और ग्रीस के युद्धोंन भी भूमध्य सागर के चक्कर काटने लगे। अरब देशों की सैनिक तयारी भी शुरू हुई। जोरान के गाँवों तक न जाने कि रा पहुँचें और नासिर की पत्नी वचन दिया कि यदि इजरायल से संधि हो गई तो जोरान अरब राष्ट्रों का साथ देगा। टयूनिशिया मोरक्को जॉर्डन और सूडान ने भी ऐसी ही घोषणाएँ कीं। अजीरिया ने पश्चिम एशिया में तत्काल फौज भेजने का निर्णय किया। इजरायल में भी युद्ध की तयारी होने लगी। जनरल हायन जो 1956 के मध्य इजरायल युद्ध में शक्ति प्राप्त कर चुके थे वो इजरायल का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया और देश में तामक की घोषणा कर दी गयी। सारा पश्चिमी एशिया देखते ही देखते युद्ध के मदान में पारणत हो गया। किसी भी क्षण युद्ध का विस्फोट हो सकता है और इसको विषम युद्ध में परिणत होने की सम्भावना थी। स्थिति ऐसी आ गयी थी कि लगता था कि संयुक्त राज्य अमेरिका और मोरक्को संधि के बीच इजरायल और अरब जगत की आँखों में मोरी टनकर हो जायगी। इस बीच सुरक्षा परिषद का बंटा बंटक हुई लेकिन उसमें कोई नतीजा न निकला।

तृतीय अरब-इजरायल युद्ध (1967)—इस विषय पर स्थिति में विद्यमान बातें यहाँ से जगानार पट पढ़ने के लिए बेचन पश्चिम एशिया की अरब बनाम यूरोपीय राष्ट्रों का अस्तिर कागामुखी 5 जन 1967 को अचानक बिराट के साथ एकाएक पट पड़ा। यूरोपीय राष्ट्र और अरब जगत के बीच एक तरह से यह युद्ध अनिवार्य और अवश्यमान था। विद्यमान पक्षों के अरब देशों ने यह निश्चय कर लिया था कि इजरायल की किराया उह अपनी आँखों से निहानती ही है। अरब देशों की अपनी सेनाएँ इजरायल के भीमि उभुक्त त्रिकानों पर पक्षान के लिए कम से कम दस दिन का समय और चाहिए था। तब इजरायल की स्थिति और नाजुक हो गया होती। इस हानत में इजरायल ने अतिशीघ्र सशस्त्र पर हमला करने का निश्चय किया। 5 जन का इजरायली विमानों ने एकाएक काहिरा और मिस्र के अन्य हवाई अड्डों पर हमला कर दिया। संयुक्त अरब गणराज्य और इजरायल की सीमा पर गाजा पट में सेंटर दक्षिण इजरायल के नगर क्षेत्र तक दोनों ओर की फौजों में मुठभेड़ हो गयी। युद्ध के प्रथम दिन उभय पक्षा ने अपनी अपनी कामयाबी के बारे में उधोषणाएँ कीं। लेकिन दूसरे दिन ही स्पष्ट हो गया कि हमलों की वजहान का पट जानान युद्ध था। संयुक्त अरब गणराज्य की बुरी पराजय हुई। मन्थुर्न सिनाई प्रायद्वीप इजरायली सेना के कब्जे में आ गया और ये क्षेत्र नगर में पूरा जितारे तक पच गये।

संयुक्त अरब गणराज्य पर आक्रमण होने से साथ ही जॉर्डन सीरिया के साथ भी इजरायल का युद्ध शुरू हुआ। युद्ध के प्रारम्भिक दिनों में सीरियाई फौज का युद्ध सफलता अक्षय मिनी लेकिन जॉर्डन आगे घुटे भी इजरायल की मार को नहीं गं सरा। इजरायली सेना ने जॉर्डन के नगर तथा इसके उत्तर-पूर्व के इलाक़ों पर कब्जा कर लिया। जॉर्डन का हथियार डालने पर विवश होना पड़ा। यह ही निष्कर्ष

जोड़ान के लगभग बास हजार सैनिक और छ निम्न नामगिरी मारे गए। अरब शत्रुओं का मदद के लिए अलगाविया मुहान यमन कुत और मुहान अरब का कुमके इजरायल का सीमा की आर अदम्य बढ़ा थीं। लेकिन युद्ध का स्थिति पर इन्का का असर नही पड़ा।

मुरखा परिषद और युद्ध विराम—युद्ध के छिन्न ही युगाव म मुरखा-परिषद का बैठक बुलाया गया। भारतय प्रतिनिधि 7 परिषद में भाग का कि वह अरब इजरायल युद्ध बन्द करने और दोनों पक्षों का अलग सन्तान 4 जून का तिथि में बारस लान का मांग कर। 6 जून का परिषद न युद्ध बन्द करने का एक प्रस्ताव पास किया। इजरायल युद्ध बन्द करने का तयार हो गया लेकिन अरब शत्रुओं का अरब से यह प्रस्ताव ठकरा दिया गया। अतएव युद्ध में आधान का हानत सबसे बुरा हो रहा था। अतएव उसने युद्ध बन्द करने का मांग स्वाकार कर ला। 7 जून का परिषद न एक दूसरा प्रस्ताव स्वाकार किया। इस प्रस्ताव में यह मांग ला गया था कि मुहानत सन्तान रात के आठ बजे से (शेनविच समय) युद्ध बन्द कर दें। मुरखा परिषद का यह आश्रामक प्रस्ताव था। युद्ध में स्थिति का पूरा पनामन हो गया था। अतएव उसने समय युद्ध बन्द करने के सिवा कोई चारा नहीं रहा। 8 जून 1 इजरायल और मित्र के बीच युद्ध बन्द हो गया। सीरिया न आश्राम आर न युद्ध बन्द करने का घोषणा कर दा।

युद्ध में सलान सन्तान रातों द्वारा इस घोषणा के बाद अरब युद्ध-विराम का भाग का कार्यान्वित करेंगे 9 जून स्वज नहर के किनारे और इजरायल-सीरिया सामावर्ती नहरों में युद्ध जारी रहा। सीरिया पर इजरायल न अरब आश्रामक कारवाइ जारी रखा। यह सीरिया के क्षेत्र में स्थित कुत नामगिरी महत्व के स्थानों पर कब्जा कर लेना चाहता था। इस हालत में पश्चिम एशिया के शत्रु पर विचार करने के लिए 9 10 जून का पुन मुरखा-परिषद भी बैठक हुई। भारत और सोवियत संघ के प्रतिनिधि न मांग की कि इजरायल का आश्रामक घोषित किया जाय लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका ने ऐसा नहीं हान लिया। महामन्त्रि का यह कहा गया कि वह वस्तुस्थिति का पता लगायें। महामन्त्रि ने आरिषा दा सलान साष्ट था कि इजरायल सन्तान आश्रामक कारवाइ में सम्मन है और युद्ध चल रहा है। अतएव मुरखा-परिषद ने एक ओर प्रस्ताव पास करके यह आश्राम लिया कि सीरिया और इजरायल दा पक्षों में युद्ध बन्द कर दें। इजरायल का सामरिक स्थिति पूरा हो चुका था। सीरिया का सामरिक समता समान्त हो चुकी थी। अतएव दोनों पक्ष न तन्त्रान युद्ध विराम स्वाकार कर लिया और 10 जून का दोनों पक्षों में पूनपया नहाइ बन्द हो गया।

युद्ध के समान्त हान के बाद आन्ति-समन्ती का किने कई प्रयास हुए हैं लेकिन इजरायल के बिहू के कारण का समन्तीता नही हो सका। सधन अरब इजरायल सीरिया और जाहान के एक बन्द बह नू नाम पर इजरायल न बन्द कर

रिया है, स्वयं नहर बन्द हो गयी है और कूटनीतिक स्तर पर पूणतया गतिरोध बना हुआ है।

अरब इजरायल संधि में भारत का दृष्टिकोण

जून 1967 के मध्य एशियाई संकट में भारत का दृष्टिकोण भारतीय विदेश नीति का एक बड़ा ही विवादास्पद विषय बन गया। भारत का रुख शुरू से ही अरब देशों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रहा है। समुक्त अरब गणराज्य के प्रति भारत की दोस्ती भी बहुत पुरानी और पक्की थी। उसी कारण भारत ने अभी तक इजरायल को राजनयिक मान्यता नहीं प्रदान की है। संघ के मध्य में जब पश्चिम एशिया में युद्ध के बाद में महराने लग उसी समय से भारत जॉर्जिया में दखल घुसकर अरब गणराज्य का समर्थन करता रहा। सरक्षा परिषद में भारतीय प्रतिनिधि हमेशा अरब राज्यों की वकालत करता रहा। उसने सोवियत संघ के इस कथन का कि भटकानवाली कायवाही इजरायल न शुरू का है समर्थन करता रहा। युद्ध छिड़ने पर प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी का आवास में एक बक्तव्य हुआ जिसमें इजरायल पर युद्ध शुरू करने का सारा उत्तरदायित्व थोपा गया। तत्कालीन भारतीय विदेश-मन्त्री एम. सी. जगन्नाथ ने पश्चिम एशिया की विस्फोटक स्थिति के लिए पूरा उत्तर दायित्व इजरायल पर डाला और कहा कि इस प्रदेश में इजरायल राज्य का अस्तित्व ही सारे तनाव और झगड़े का मूल कारण है। इस प्रकार भारत ने युद्ध में अरबों का प्रबल समर्थन किया जिसकी देश के भीतर बनी कड़ी आलोचना हुई। सम्भवतः अक्टूबर-नवम्बर 1967 के बाद भारतीय विदेश नीति की सबसे कड़ी आलोचना अभी अबतक पर हुई। भारतीय संसद के एक सभ्य श्री नाथ पाई ने कहा भारत एकमात्र देश है जिसे पश्चिम एशिया के संघर्ष में एक भी गोली चलाय बिना भीषण पराजय की क्षति उठानी पड़ी है। मिनाई के महस्थल में एक पत्थर पर यह अभिनव अंकित किया जाना चाहिए—जिस स्थान पर भारत की विदेश नीति को दफनाया गया है जिसके मरने पर किसी ने शोक नहीं व्यक्त किया निमन्त्रेण को सैनिक सम्मान प्रदर्शित नहीं किया गया और निराला शोक की गीत नहीं गाय गया। इस नीति के निमाता नेहरू थे मन्त्री हुआ उनरी पुत्री ने की है।¹ स्वयं ने पाई के नेता एम. आर. मल्लानी के वक्तव्यानुसार भारत सरकार ने समुक्त अरब गणराज्य के चपरासी का कार्य करते हुए अपने को बलि बलिदान कर लिया था। 8 जून को आत्मघात में सरकारी नाव की आलोचना करते हुए ए. सभ्य ने कहा कि तत्काल अरब राज्य अपने पक्ष का समर्थन करने के लिए

1 On a stone in Sinai desert sh was a mason here this epitaph Unrept unrhoured and unsung her lies buried India's non-al gment—created by Nehru killed by his daughter

पर्याप्त हैं। भारत सरकार को चौदहवें अरब राय जसा व्यवहार करना बन्द करना चाहिए। आलाचक्का का कहना था कि इजरायल न भारत के हिता के लिये कभी हानि नहीं पहुँचाये। फिर भी हम उसके अस्तित्व को मित्रान के लिए बिय जान वाले जहाद में क्यों अपना जो शामिल कर रहे हैं। संयुक्त अरब गणराज्य द्वारा अलाचक्का का खाड़ा की नाकेबंदी करने तथा इजरायल को समाप्त करने की धमकियाँ देते रहने के कारण ऐसी विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हुई थी। उसी उत्तरदायित्व जरा राष्ट्रों पर था।

भारतीय नीति की आलोचना के आधार—भारतीय नीति का आलोचना के तीन मुख्य आधार थे। यह कहा गया कि संयुक्त अरब गणराज्य न भारत का भारत-चीन युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध के समय कोई महायन्त्र नहीं था और एक तरह से वह शटम्प रहा। भारत पाकिस्तान युद्ध में तो उसका तत्पक्षता का मुकाबल निश्चित रूप से पाकिस्तान के पक्ष में था। अतः जरा ने स्पष्टतया भारत का विरोध किया। भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय जोषान ने खुद भारत का समर्थन किया और मक्का अरब जैसे राय से उसका मह्यता भी मिला। उस विपरीत इजरायल ने उस सब के समय भारत के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की और सरका परिपक्ष में भारत का बाट दिया जहाँ वह अरब देशों में विरोध किया। जरा के नेता अदन बिहारा वाजपेयी ने कहा कि पश्चिम एशिया के सब के भारत द्वारा अरबों के समर्थन करने का मूल कारण यह था कि यदि भारत ने अरबों का समर्थन नहीं किया तो पाकिस्तान का समर्थन करने वाले मुस्लिम राष्ट्रों का एक गुट उसके विरुद्ध हो जायगा और उसमें संयुक्त अरब गणराज्य सम्मिलित हो जायगा। इस विषय पर नासिर के तथा अरबों के विरुद्ध व्यवहार को और ध्यान बाँट दिया हुआ जानपेयी ने पूछा कि क्या नासिर ने 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान का आक्रमक धापित किया था? क्या उसने यह कहा था कि विश्व के हम भाग में पाकिस्तान का निमाण अन्तिमि का कारण बना हुआ है? यदि उसने ऐसा नहीं कहा तो भारत के विदेश मंत्री ने यह क्या कहा कि इजरायल पश्चिम एशिया में तनाव के कारण बना हुआ है।

आलोचना का दूसरा आधार यह था कि भारत का अपने भविष्य पर ख्याल रखते हुए नीति का निवारण करना चाहिए था। आज स्वयं नहीं इजरायल के लिए बन्द है तो क्या वह भारत के लिए भी बन्द हो सकती है। सम्भव है कि कुछ दिनों के बाद संयुक्त अरब गणराज्य में ऐसा गारा का शसन कायम हो जाय जो घमायल हों और घम के आधार पर पाकिस्तान का समर्थन करे। हम हास्य में यदि भारत-पाकिस्तान में युद्ध छिड़ जाय तो ऐसे गारा भारत के लिए भी स्वयं नष्ट का भाग बन कर सकता है। उस अतिरिक्त इजरायल न भारत का कुछ नहीं बिगाड़ता है यह ठाक है कि निश्चिन्त में इजरायल रज के मज्ज नही होना चाहिए था। लेकिन जब तक भारत-इरायल स्थापित हो गया और संयुक्त राष्ट्रसंघ की भाषना उस मित्र गयी तो उसी नेट केस किया जा सकता है? सब के एक सम्पूर्ण देश के अस्तित्व सम्पन्न करने

चात देशों का धर्मकी का भारत का समर्थन मिले यह क्या याद और धर्म की नीति है ? संयुक्त राष्ट्रसंघ के रूप में सदस्य राष्ट्रों की भाँति अंतरराष्ट्रीय का भी जीवन रहने का अधिकार है ।

आलोचना का तीसरा आधार यह था कि भारत ने अरबों का समर्थन करके अपनी असह्यता तथा शांति की नीति का परित्याग कर दिया । नहूँ इस प्रतिपादित असह्यता का नीति का अर्थ था कि हम विभिन्न गुटों से अलग रहते हुए स्वस्थ वृत्ति में शांति बनाये रखने के लिए प्रयत्न करना चाहिए । किंतु इसमें हमने अपने का अरबों का समर्थन और वनपाती बनाकर असह्यता की नीति का परिष्कार कर दिया । भारत की विदेश नीति का एक मुख्य अर्थ शांति को स्थापना करना है किन्तु हमने हमारे न अरबों का समर्थन करके उन्हें युद्ध के लिए प्रोत्साहित किया । अतः संसद में भारत की विदेश नीति अपने सभी मान्य उद्देश्यों के प्रतिरूप शांति का विरोध करनेवाले तथा तटस्थता और असह्यता का परित्याग करनेवाले थी ।

भारतीय नीति का समर्थन—इन आलोचनओं में कुछ तथ्य अर्थ है फिर भी पश्चिम एशिया के सफट में सम्मेलन में भारतीय नीति का एक दूसरा पक्ष भी था । यह बात ठीक है कि अधिकांश अरब देशों ने भारत पर किस्तान संघर्ष में पाकिस्तान का पक्ष लिया था और सावजनिक स्तर पर संयुक्त अरब गणराज्य ने भारत का जोरदार समर्थन नहीं किया था । किन्तु इसी आधार पर यह मान लेना कि नामिर ने भारत का समर्थन नहीं किया अति प्रतीत नहीं होता । सम्भव है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ के माध्यम से नामिर ने भारत का पूरा समर्थन किया हो । हम जानें कि पता तो तभी लगा जब सोवियतों के लिए संप्रदाय (archives) का द्वार खोल दिया जाय । तबसे के लिए हम प्रधान मंत्री के उस वक्तव्य का अधिकारिक और सत्य मानना पड़ा जिसमें कहा था कि भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत को सत्त अरब गणराज्य में पूरी सहायता मिली थी । क्या उक्त सम्मेलन में संयुक्त अरब गणराज्य ने जो रुत अपनाया हमें म तथ्य की पुष्टि भी होती थी । अरब राष्ट्रों के इस सम्मेलन में एक ऐसा प्रस्ताव लाया था जिसमें भारत-पाकिस्तान युद्ध के सम्मेलन में भारत की आक्रामक कहा था । नामिर के विरोध के कारण पाकिस्तान का राजनय स्थान हटा गया और कमालाबाद सम्मेलन में इस तरह का प्रस्ताव पास नहीं हो सका ।

यह बात कि ठीक है कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में पारस्परिकता के सिद्धांत का पालन होना चाहिए । यदि हम थोड़ी देर के लिए यह मानें कि भारत शांति स्तान युद्ध में हम अरबों का समर्थन नहीं किया तो भी केवल इसी आधार पर हम अरब विरोधी नीति नहीं अपना सकते हैं । हम सब अरब राष्ट्रों को एक ही कोटि में रखने की बात नहीं करनी चाहिए । अस्तव्यस्त अरब राष्ट्रों की भारत के प्रति नीति की दृष्टि में हम तीन वर्गों में विभक्त कर सकते हैं । पहले वर्ग में भारत के प्रति पूर्ण मित्रता करने वाले राष्ट्रों का समर्थन संयुक्त अरब गणराज्य समूह और

होता है। पश्चिमी देशों से भारत के व्यापार का यह उच्चतम भाग है। यदि यह नहर किसी कारणवश बंद हो जाय तो भारत आनेवाला माल अफ्रीका महादेश का चक्कर काटकर उत्तमाशा अतरीय के पाँच हजार मील से अधिक लम्बे भाग से आयागा। इससे समय अधिक लागेगा और भाड़ा भी अधिक देना पड़ेगा। उस समय स्वेज नहर बन्द था। इस स्थिति में अमेरिका से जहाज चागीस के स्थान पर सैतालीस दिनों में पहुँचता था और यूरोप के मार्ग में तीन मप्ताह अधिक लागते थे। अमेरिका से आने वाले मार्ग पर लिए जाने वाले भाड़े में पचीस तथा यूरोप से आनेवाले माल पर चौंस प्रतिशत की वृद्धि हो गयी थी। इसके अतिरिक्त पश्चिम एशिया के साथ भारत का घनिष्ठ वापारिक सम्बन्ध था। यह क्षेत्र हमारे तेल और रासायनिक पदार्थों की आवश्यकता को पूरा करता था और भारत में बने मालों की यहाँ बड़ी खपत थी। अतः अपना महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों को तथा वापार की धारा का अविच्छिन्न बनाय रखने के लिए बड़ी मात्रा में पेट्रोल प्राप्त करने के लिए तथा पश्चिम एशिया की मरिया में अपना मार्ग बनाने के लिए पश्चिम एशिया के अरब राज्यों विंगकर समुक्त अरब गणराज्य से मन्त्रीगुण सम्बन्ध बनाय रखना भारत के लिए आवश्यक था। यह उसके राष्ट्रीय हित में था। यन्ति कुछ अरब राज्यों ने 1962 तथा 1965 के संघर्ष में हमारा साथ नहा दिया तो भी अपना हितों को ध्यान में रखत हुए हम अरब राज्यों का ही समर्थन करना चाहिए। तरह अरब राज्यों के समर्थन से भारत का जितना ठोस लाभ प्राप्त हो सकता था उतना अरब इजरायल के समर्थन में नहीं हो सकता।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के व्यापक दृष्टिकोण से भी भारत द्वारा अरबों का समर्थन वांछनीय प्रतीत होता था। इजरायल की स्थापना साम्राज्यवादी ब्रिटेन और समुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से हुआ था। भारत की यह भावना है कि इजरायल के पीछे अमेरिका का हित छिपा हुआ है। 1967 में अमेरिकी महानायिका पर जोई सीमा नहीं थी। सम्पूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया पर छाये रहने के लिए वह विपतनाम में खूनी युद्ध चला रहा था। इसा समय पश्चिम एशिया का सफ्टवेयर आ गया। इससे ऐसा प्रतीत हुआ कि समुक्त राज्य अमेरिका पश्चिम एशिया से लेकर दक्षिण एशिया तक अपना एकछत्र साम्राज्य कायम करना चाहता है। अमेरिका की यह महानायिका भारत के लिए बड़ी खतरनाक थी। भारत सरकार को यह धारणा बन गयी थी कि यदि अमेरिका अरब समर्थन के हितों को कुच दना तो पश्चिम एशिया का भारत शक्ति-मन्तुल्य विगड़ जायगा। दक्षिण पूर्व एशिया में भी यन्ति उसकी सफ्टवेयर मिल गयी तो भारत अकेले बीच में दब जायगा और तब अमेरिकी दबाव को रोकना बड़ा बठिन हो जायगा।

पश्चिम का उपनिवेशवाद अभी मरा नहीं था। किमान किमी रूप से वह समय-समय पर अपना सर उठाता रहता था। और पश्चिम एशिया में इस उपनिवेशवाद में टक्कर लाने की क्षमता बढाए गए ही स्थिति में था। यन्ति राष्ट्रपति नासिर पराजित हो जान से पश्चिमी एशिया में शक्ति रितना हो जाती जो भारत के हित में कभी भी अशुभ नहीं होता।

धुव जार म हजराय विराघो भ ण न्हा द्य ता अरव हम पर नाराज हो जायगे । 1962 म भारत चान मघय क समय राष्ट्रपति नासिर न एमा हो द्य अपनाया था । स्वय प नहम् ने उह तटस्थ र त हुण समस्या का मुझाने म मद करने का परा मश ि या था । यदि भारताय नता बिना उग्र भाषण न्हि हुण समय म काम करते तो सम्भव था कि राजनयिक स्तर पर स्थिति का बिगडन न राक गिया जाता जो भारतीय राजनय की स त वी उपरि इ हासी ।

भारत और रवान सम्मेलन—पाश्चिम एशिया की समस्या को ंहर बिगत पांच उह वशों म कट्टर तमो घ न ा घटों जिनका ंहर भारत को काफी सीम हुआ । 21 जगस्त 1969 का जल्मन्म म्बिन चौ २ मी वष पुराना अ अकमा भम्बिन् म रहम्यमय डग म आग लग गया । ंम अग्निता न अरव देशो और हजरायन क सम्प्रघ को जोर तनावपूर्ण बना लिया । अग्निता पर विचार करन क लिए छ-बोस मुस्लिम ंशा का एक व्स्वामी निखर सम्मेन् रवान म 22 भितम्बर 1969 का शुभ हुआ । ंम सम्मेन् में भाग लेने के लिए भारत ं अमाधारण ध्याकुन्ता का परिचय लिया । पू कि यह मुस्लिम देशों का सम्मन् हातवाला था अनप्य भारत का ंमम आर्मा प्रत न िया ज सफा था । रातन भारत न प्रारम्भ स हो निमन्त्रण प्राप्त करन रा य न किया । भारतीय विेश म प्राप्य न ंम यन् के समर्पन म दो द्गी ं दा एक तो य् कि जिस सम्मेन् ं पाकिस्तान शामिल हा उमम भारत का उप स्थित हाना ंमलिए जम्हा ं कि पाकिस्तान उस सम्मेन् का उपयोग भारत क निगफ प्रचार करन के लिए न्हा कर सब बहा पाकिस्ताना प्रचार का सण उत्तर लिया जा सके और भारत के निगफ का प्रस्ताव पान न्हा होन लिया नाय । दूसरा दस्ता यह दी गयी थी कि मुस्लिम सम्मेन् म भाग लेकर भारत संयुक्त अरब ग राय तथा एम ही प्रतिगान अरब रा ं का पय मज्जय कर सकना है और मुस्लिम देश म धर्मा घता की ंहर का रात सकता है ।

भारत का ंम सम्मन् म भाग लेने के लिए निमन्त्रण ि या जाय या न्ही इस प्रश्न पर ंस्वामी दशा म काफी बात बिबा हुआ । पाकिस्तान न ंम प्रस्ताव का कडा विरा किया । हुम्मायाद क साम्रा यिक मगठा का हुवाला दत हुण पाकिस्तान न इस्नामी सम्मेन् म भारत को ंगामि करने क विचार पर अन्ता गहुरा विरोध प्रकट किया । रवान सम्मेन् म ंम पर कई टिपों म विचार हुआ । स मन्त गन् ज्ञान के एक त्ति वा भारत को आर्मा प्रत करन का निणय हुआ । ज्यों रयो करक जानि भारत न यह निमन्त्रण मगवा हो लिया । ए वय सूचना अम्हा थीन ंउ द्य श्री कम्म्मेन् म्मो म्मम्म क नतय म भारताय प्रतिनिधि द्म रवान क लिए रवाना हा गया ।

सकिम पाकिस्तान अपने विराघ पर हटा रहा । जब भारताय प्रतिनिधि-ल सम्मन् कम म पहुँचा तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति न ंम्बी उपस्थिति पर विराघ प्रकट किया और सम्मेन् स बाध भाउट कर गये । पाकिस्तानी प्रतिनिधि द्म क

निकट सूत्रों न बताया कि इस्लामी गिस्तर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत का निमन्त्रण लिये जान के विरुद्ध पाकिस्तान न सम्मेलन का शेव कायवाही काव हिफ्जार करन का निाय किया है। आखिर राष्ट्रपति बाह्या छा की दात मान गी त्या और दूसरे दिन पूण अधिवान में भारताय प्रतिनिधि-दल का बठन नहीं लिया गया।

रवात सम्मेलन म शामिल होन के लिए निमन्त्रण पान का भारताय प्रयास तथा सम्मेलन स भारत का जिस प्रकार निकाला गया उत्तक विरुद्ध दश में घोर प्रति क्रिया हुई। निश्चय ही यह सम्वे राष्ट्र का धार अपमान या और उस का न स स की प्रतिष्ठा को गहरा बाधान पड़ा। 1962 में चीन के हाथों पराजय स यह चार किस्सा तरह कम नहीं था। वह चोट सामरिक थी और यह राजनयिक।

भारत के भूतपूर्व परराष्ट्र मंत्री छागला न रवात म मुस्लिम गिस्तर सम्मेलन में भारत के सरकारी तौर पर भाग लेन का अत्यन्त खटखटनक और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। अत्यन्त कठोर शर्तों में एक वक्तव्य जारी करत हुए उन्होंने कहा कि सबन बड़ा बुनियादी सवाल यह है कि इस गिस्तर सम्मेलन स भारत का क्या वास्ता? यह विशद रूप स धार्मिक एवं साम्प्रदायिक सम्मेलन था जिसमें भाग लेन के लिए मुस्लिम देशों का निमन्त्रित किया गया। क्या हमारा मूल्यमि दश है? क्या हमारा देश का कोई राजकाय धम है?

छागला न कहा यह अत्यन्त खटखटनक एवं दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत ने सरकारी तौर पर एक इस्लामी सम्मेलन में भाग लिया। हमने निमन्त्रण पान के लिए भाख मांगी छुआमन का और जब बात म निमन्त्रण मिला ता हम दोस्तर रात पहुँचे। कभी वक्त था जब कां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तब तक पूरा एवं प्रतिनिधि त्वपूर्ण नहीं माना जाता था जबतक उसम भारत का प्रतिनिधि शामिल नहा जाता था। सम्मेलन में हमारी सम्मानपूर्ण स्थिति हाता थी। लेकिन अब समय बदल गया है। यह दुःख है कि भारत न इस्लामी सम्मेलन में भाग लेन के लिए शर्तों के द्वार खटखटाया।

आखिर हम सम्मेलन स हमारा क्या वास्ता था? क्या हमारा देश का कोई राजकाय धम है? हम धमनिरपक्ष हान का दावा करत हैं, सभा धर्मों का एक स्तर पर रखत हैं और सावजनिक जीवन में धम के प्रवेश का अनुमति नहा दत। यह सब विरुद्ध है कि राष्ट्रपति नासिर इस प्रकार का सम्मेलन करन के विरुद्ध था। सांगिया जस छा राष्ट्र न उसमें यह कहकर भाग लेन स इन्कार कर लिया कि वह धम निरपक्ष राष्ट्र है। हमारा अपनी नीति भी निरन्तर इस प्रकार के सम्मेलन के विरुद्ध रही क्योंकि उसन स धार्मिक गुटों म बट जायने और धमाधमा तथा अनिच्छुना का बढावा मिलेगा। अब भारत ने स्वयं उस प्रकार के दूषित कृत्य का समर्थन किया है।

बाद में भारतीय प्रतिनिधि-दल के नेता फखरुल्ला अल अहमद न भा स्वीकार किया कि भारत के प्रति सम्मेलन का खयाल बना असाधारण और दुर्भाग्यपूर्ण रहा। अहमद न कहा कि सम्मेलन की अन्तिम घण्टा म भारताय मुस्लिम समुदाय के

शामिल होने की जो बात कही गयी है उसमें कुछेक बड़ा तात्पर्य है। —हम जानते हैं कि किसी प्रतिनिधि न सम्मेलन में भाग नहीं लिया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन न भारत सरकार को निमन्त्रण भेजा था और भारतीय प्रतिनिधि-दल तो भारत की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने एक बात की निन्दा की कि अन्तिम बंदर की जानकारी भारतीय प्रतिनिधि-दल को नहीं दी गयी।

देश के इस गम्भीर अपमान के लिए भारत की पत्र-पत्रिकाओं और सत्ता में बड़े हो-हल्ला मचा। माग की जान लगी कि देश का इज्जत के साथ ऐसी विलक्षण करतबाग की दण्डित किया जाय। इसका जवाब में भारत सरकार ने प्रवक्तव्यों में सम्मेलन में शामिल होने की उचित ठहराया। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से यह बहाना निकाला गया कि भारत स्वातंत्र्य सम्मेलन में इसलिए नहीं गया कि वहाँ अनेक अस्मिता मस्जिदों में आग लगाने के बारे में विचार होना था बल्कि इसलिए कि उसमें हम बड़े मामले पर विचार होना था कि 'स्लाय' के गरजाने की अधिकार में अन्तर्गत सन्ति अथ सभा अथवा इलाका को किस निकाला जाय। एक बड़े अधिकारी ने तो यहाँ तक कहा कि सम्मेलन इस्लामी नहीं था और इसका नाम था—अनेक अस्मिता सम्मेलन जबकि सम्मेलन के चित्रों से स्पष्ट था कि यह इस्लामी अन्तर सम्मेलन था।

भारतीय प्रतिनिधि-दल के नेता फ़ैय्दुल्ला अली अहमद ने लिखी रिपोर्ट पर हम बात का दाहराया कि यह सम्मेलन किमा इस्लामा मामला पर विचार के लिए नहीं बुलाया गया था और उस आधार पर उठाने इसमें भाग लेने की भारत का आवश्यकता का सही सिद्ध करने का असफल यत्न किया। पता नहीं कि अनेक अस्मिता मस्जिदों में आग लगाने का मामला किस प्रकार इस्लामी सवाल नहीं था। हम इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि अहमदनगर तथा अन्य अरबक्षेत्रों को इज्जत रखने की अधिकार से निकालने के लिए समुक्त राष्ट्रसंघ ने जो भी प्रस्ताव पाम किया है उनका भारत ने समर्थन किया है। लेकिन इनका समर्थन तो साविकत संघ जाँच अनवर दान भी किया था।

घूम फिर कर बात फिर वहाँ आ जाती है। सवाल यह है कि भारत में यह करोड़ मुसलमान होने के कारण हम क्यों सभी इस्लामी सम्मेलन में भाग लेने का यत्न करना चाहिए और सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है कि अमनिरपक्ष राज्य के लिए किसी धार्मिक सम्मेलन में भाग लेने का क्या औचित्य हो सकता है? भारतीय नित के लिए जो मे यह खतरनाक भी था। यदि अनेक अस्मिता मस्जिदों के अग्निशोक पर धार्मिक सम्मेलन हो सकता है तो हजारतों का बाढ़ पर भी इसी तरह का सम्मेलन हो सकता है। इन आधारों पर स्वातंत्र्य सम्मेलन में भारत के शामिल होने का सम्पूर्ण देश में बड़ा विरोध हुआ और सारी घटना की बहुत आलोचना की गयी।¹

1 उदाहरणार्थ इस पर हिंदुस्तान टाइम्स (17 सितम्बर 1969) की यह टिप्पणी थी

To say that India had sent a delegation to attend an Al Aqsa Summit and not the World Islamic Summit is

“बत का सम्मेलन पर भारत का जिस तरह अपमानित किया गया उसका स्तर सुनकर यह सवाल उठता स्वभाविक है कि नयी दिल्ली ने अन्तर्गत सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति क्यों दी? उसी तरह का उस तरह नाचा क्यों दिखाया गया? वास्तविक तौर पर एवं विधि के सम्मान दिवसों का उल्लंघन करके जब कि पहले से ही पता था कि पाकिस्ताना विशेष कारण तयारी समिति में भी फटका दिया जा चुका है कि भारत का सम्मेलन में भाग लेने के लिए न बनाया जाय खे सम्मेलन का आयोजनमा मिला है भारतीय प्रतिनिधित्व खाता का तार क्यों चलाया? बत में तत्सम राष्ट्र का तयारी समिति की बैठक में शामिल न चाहते हुए भी ना नहीं — मुकाम । अन्तर्गत की रूप में अनुकूलित तार नाच दाया था । अन्तर्गत विश्व सम्मेलन का तयारी समिति का एक में पश्चिमिान न बना दिया । तार का पा अपमान नक विधि में जानने के बतय भात चारों तार तित भारतोय दूतावास का यह बतय द मता य तितवन मित पर यह भात का प्रतिनिधित्व का हाकि बतय महा य तितवनन सु दू ही रण ताता । तार एता न तार तिला मु एक मत्री व नृत्य में प्रतिनिधित्व भात का अपमान का तयारी और बतय का भूत क्यों लायी ? बतय सम्मेलन में भाग लेने के तार हत तार भा पाकिस्तान न तार पश्चिमिान का भात मन्व तार का अपमानित न तार का तयारी वरता यी किनु ना तिला में तार तयारी के तार तितों का तार क्यों न बना कि तार में भात के तारों पर तार नक न तितव तार पूर तार बतय वरता तार ?

अन्तर्गत विश्व सम्मेलन का तार तयारी 1966 में था बतय 1969 में ना था । तार तयारी की तिला वन ना तार तयारी के तयारी तार मुम्बैननों में तार तयारी न तार तयारी के तयारी न तार तयारी तार तयारी न तार

absurd. If there can be an Islamic summit to discuss the Al Aqsa fire would not there be an equal case had to be considered at that time for a similar conference on the theft of the Holy Relic from the Hazratbal shrine in Srinagar. If Israel is to be held responsible for the Al Aqsa fire would it be equally true to say that the Government and people of India were responsible for theft of the Holy Relic. And if the Pakistan delegation whether at the conference or outside referred to the Ahmedabad riots to keep India out of an Islamic gathering should this be any surprise. The whole episode has been a sorry fiasco and far from upholding any principle or serving any Indian interest. The Rabat affair has hurt the country's secular diplomacy and image. Hindustan Times Sept.

क्याकि कुछ वष पूर्व इंग्लैनीशिया मे हुए इस्लामी सम्मेलन मे चीन सोवियत सघ आदि क मुस्लिम प्रतिनिधि और मध्य एशिया के मुमलमान सोवियत गणराज्यो के प्रतिनिधि गये थे किंतु रबाय सम्मेलन से व दूर हो र । यूगोस्लाविया मे मुसलमानो की काफी सखादी क बावजूद बलप्रद उससे दर रण और अल्बानिया न भी उसमे को सम्मिलित नही किया। दसरी ओर जसा कि स्वयं अरब राष्ट्रों ने गिजायत की सम्मेलन मे उनको आमन्त्रित किया गया जिनका इजरायल के साथ राजनयिक सम्बन्ध है। नया सि नी क नीति निमाताओं और राजनय की गति मति निश्चित करने वाला न नन सब तथ्यों का उपेक्षा करके ऐसी स्थिति क्या प । कर दो जिसमे समूचा राष्ट्र तिरस्कृत और बाधित हुआ ? इन सारे प्रश्ना का उत्तर है— भारत सरकार की कश्मीर सम्मेली मति । कश्मीर क प्र न को भारत सरकार इतना अधिक महत्त्व देती है कि यह उसकी विदेश-नीति का एक मुख्य सब बन गया है और भारतीय राजनय दलत हूँ तक इसी प्रश्न मे प्रभावित होती रहती है । भारत रान्त सम्मेलन मे इस कारण शामिल होने के लिए तैयार उससे था कि कहीं उसकी निपस्थिति मे पाकिस्तान कश्मीर के प्रबल पर अरब राष्ट्रों का समर्थन न प्र त नर १२

1 It is necessary to ask by the Government of India to get representation at the World Islamic Summit. The stark truth is that this is an obvious manifestation of what might appropriately be described as *The Kashmir factor*. Indian diplomacy. Fifty percent of India's foreign policy is permanently dictated and determined by the Kashmir factor. India wanted to be at Rabat in order not to leave the field clear for Pakistan and to talk to the Muslim nations gathered there on Kashmir or Indo-Pakistan relations generally. It is for the same reason that India fought for an invitation to the Islamic conference at Kuala Lumpur earlier this year. It is for the same reason again that India's great triumph at the Belgrade conference of non-aligned nations is somehow managing to keep out Pakistan. The enormous distortions that the Kashmir factor has introduced in India's foreign policy and even in its domestic policy whether consciously or unconsciously has resulted in double talk, double think and unprincipled contortions for many years. The Government of India's entire position on West Asia and towards Israel is powerfully influenced by the Kashmir factor. India's diplomacy towards the United States, the Soviet Union, China and several other countries has from time to time been visibly subjected to the Kashmir factor.

जैसा सम्मेलन और स्थायी इस्लामी मन्चिवालय पर भारतीय प्रतिक्रिया — ऐसा प्रतीत होता है कि अन्तर्जाली भक्ति की घटना के बाद अरब राज्य द्वारा क साथ अपने चण्ड का उत्तरात्तर मन्चिवाली रा दन गने । राजनीतिक और सनक मोर्चों पर पराभव के बाद इजरायल का समस्या को धार्मिक रूप दन का प्रति बढ़ता गया । 6 मार्च 1970 को आयोजित मुस्लिम देशों के धार्मिक नेताओं का एक बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि पश्चिम एशिया का समस्या मूलत इस्लाम का समस्या है और इसलिए मुसलमानों को उनके लिए अपना सम्बन्ध बनाए रखने का प्रस्तुत रहना चाहिए । मुस्लिम देशों में स्वयंसेवक और धन भेजने का कार्य किया गया । एक मुस्लिम समाचार समिति गठित करने का मुद्दा भी रखा गया । इस सम्मेलन में राष्ट्रपति नासिर मौजूद थे और उन्होंने भी मुस्लिम राष्ट्रों में सहायता की योजना का ।

इस प्रकार अरब इजरायल विवाद में प्रतिनिधि मुसलमानों द्वारा गर मुसलमानों का विवाद बनता गया । इसके लिए ग्राह फरन और ग्राह हसन वरत न नव ज़िम्मेदार थे । ऐसा करने में पाकिस्तान उन्हें एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली सहयोग के रूप में मिला । मुसलमान देशों में शान की नाति भी विरोधाभास में भरा हुई थी । मुस्लिम देशों के साथ ठन का मजहब का कारण दन न विवाद भी नहीं करता और मुसलमान इजरायल का शत्रु भी धारित नहीं करता । ऐसा विचार संयुक्त अरब गणराज्य सारिया और कुछ अन्य मुस्लिम राष्ट्रों द्वारा इस समस्या का राष्ट्रों और धर्मनिरपेक्ष समस्या बनाए रखने का प्रयास करने हुए तक सफल नहीं हो सकता ।

अरब इजरायल विवाद के स्थायीकरण के इस प्रयास का पृष्ठभूमि में हा 1970 में आए मुस्लिम देशों के जवाब-सम्मेलन का अध्ययन किया जा सकता है । इस जनसमन्वय सम्मेलन का तयारा उदात्त सम्मेलन के बाद हो गया था । 24 मार्च का सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए सऊदी अरब के ग्राह फरन ने कहा कि इजरायल ने न केवल फिलिस्तीन और पालेस्टीन का जनता के साथ व्यवहार किया है बल्कि इस्लाम का गान और प्रतिष्ठा को कुचलने का भी काम किया है ।

जवाब-सम्मेलन में एक मुस्लिम मन्चिवालय का स्थापना का मुद्दा का गान विवाद हुआ । मगर संयुक्त अरब गणराज्य ने विवाद और मूलान के प्रतिनिधियों के विरोध के बावजूद मन्चिवालय स्थापित करने का फैसला किया गया । मन्चिवालय का मुख्य कार्यालय जेद्दा में रखा गया । संयुक्त राष्ट्रसंघ का भी प्रतिनिधित्व इस मन्चिवालय में भी एक महामन्त्री हुआ जो हर दो वर्ष के बाद बदल जायगा । भारत सरकार ने इस मन्चिवालय की स्थापना का और पश्चिम एशिया का समस्या का मन्चिवालय पर अपना प्रतिक्रिया सावजनिक रूप से तो व्यक्त नहीं किया लेकिन इसका प्रतिकार मन्चिवालय में ही रखा । यदि यह मन्चिवालय कदम मजहब और सामूहिक मान्यता में ही मुस्लिम देशों के बीच ठाने स्थापित करने का काम करता तो यह मनन में नहीं जाता कि मुस्लिम सम्मेलन में पश्चिम एशिया का राजनीतिक समस्या पर बस

हजार सैनिक विगपनी और सलाहकारों को मित्र से हटा देने को बहा है। इसका कारण यह था कि मित्र सोवियत संघ से अधुनिकतम शस्त्रास्त्र मांग रहा था लेकिन सोवियत संघ ने इस अनुरोध को स्वाकार नहीं किया और सलाह दी कि मित्र राजनीतिक वार्ता द्वारा पर्याप्त एजिया का सफट दूर करे। पर मित्रों ने सोवियत संघ से बहुत नाराज हो गये और उसी विगपनी को मित्र छाड़न का आदेश दिया।

इसमें कोई संदेह नहीं कि रूसी विगपनी की वापसी में पश्चिमी एजिया में सोवियत संघ का राजनय को एक बहुत बड़ा घटना मगा। इस घटना के प्रभाव में भारत अरब मध्य में भी अछूता नहीं रहा। भारत सोवियत मंत्री सचिव के उपरान्त ये दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मसलों पर सहयोग कर रहे थे। मित्र की इस कारवाई से निश्चय ही भारत की स्थिति पर बरा असर पड़ा। यद्यपि भारत सरकार ने इस घोषणा पर तत्काल अपना कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की लेकिन वह भीतर भीतर मित्र की कारवाई से बरा नाराज हुआ।

अरब आतंकवाद और भारत—फिलिस्तीनी अरब चरणायियों ने इजरायल से जलवा लन के लिए एक फिलिस्तीनी भुक्ति समूह बना रखा है जो छापामार तरीकों में आतंक फैलाते रहते हैं। ये छापामार लगभग बारह छोट बड़ गुटों में बंटे हुए हैं जिनमें एक का नाम मिताम्बरी (Black September) अपने आतंकवादी कारनामों के लिए काफी कुख्यात हो चुका है। यही लोगो ने 1970 में तीन पश्चिमी देशों का विमान हरण कर जोर्डन में उतारा था एक पान अमेरिकन हवाई जहाज का कबूला हवाई जहाज पर उतारकर ध्वस्त किया था तथा एक बेजिजियन विमान का अपहरण किया था। इन्होंने छापामारों ने 1971 में पश्चिम जर्मनी के एक विमान जूनर के कारनामों को अपना निशान बनाया था जो इजरायली वायुसेना के लिए माल तयार करता था। लेकिन इनकी गतिविधि अपनी चरमसीमा पर पहुँची जब 5 मितम्बरी 1972 को इन्होंने म्युनिक में ओलम्पिक खेलों में भाग लेनेवाले इजरायली टीम के सभी खिलाड़ियों को पकड़कर नाटकीय ढंग से उनकी हत्या कर दी। आतंकवादीयों के इस काम की निंदा हर जगह हुई। लेकिन कुछ प्रमुख अरब राज्यों ने इसका पूरा समर्थन किया। मोरिया ने छापामारों की मौत को गहना का मोत कहकर मातम मनाया। मित्र ने भी आपत्ति के एक शब्द नहीं बोले। इस आतंकवादियों का हौसला और भी बढ़ा और 4 मार्च 1973 को सूनाम की राजधानी खारतम में साऊदी अरब के दूतावास में काले मितम्बरी गुट के फिलिस्तीनी छापामारों ने दो अमेरिकी और एक बेजिजियन के राजनयिक की हत्या कर दी।

सातवें घटना के पूर्व अरब आतंकवादीयों ने अपने इजरायल विरोधी और इजरायल समर्थक विरोधी अभियान का एक अहम भारत को भी बनाया जहाँ नपास। और चिटिठियों के जरिये बम भजते थे। भारत ने ऐसी गति बधिया की तीव्र भ्रमना की। यदि आतंकवादियों का कारनामा इसी तरह बढ़ते रहे तो सम्भव है कि कुछ प्रमुख अरब देशों के साथ भारत का सम्बन्ध भविष्य में अच्छा नहीं रहे।

चतुर्थ अरब इजरायल युद्ध (1973) और भारत

1973 के प्रारम्भ में ही पश्चिमी एजिया का स्थिति विस्फोटक हो गयी। तत्पश्चात् अरब इजरायल युद्ध के बाद नवम्बर 1967 में सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पास करके सम्बन्ध पणों को आदेश दिया था कि उक्त प्रस्ताव का

जाघार पर वे शान्ति समझौता करें। लेकिन इजरायल का हठबूझी के कारण किसी प्रकार का समझौता नहीं हो सका और ज़रबों के एक विमान भी भाग पर इजरायल का क़त्ल बना रहा। इस कारण पश्चिम एशिया की स्थिति हमेशा तनावपूर्ण बनी रही। जब ज़रब राज्यों के समक्ष कोई रास्ता नहीं रह गया तो उन्होंने पुनः युद्ध छेड़कर अपने भूभागों की मुक्त कराने का निश्चय किया। 6 अक्टूबर 1973 को मिस्र और सिरिया ने इजरायल के सिनैय एकाएक सैनिक कारवाही शुरू कर दी और उस प्रकार ज़रब राज्यों और इजरायल के बीच चौथी गड़बड़ शुरू हो गयी।

इस घटना के प्रति भारत उत्तमोत्तम नहीं रह सकता था। युद्ध शुरू होते ही भारत सरकार ने तत्काल अपनी प्रतिनिधियों को भेजा करत हुए इस युद्ध में इजरायल का दावा ठहराया और ज़रबों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। इस युद्ध को शुरू करने की जिम्मेदारी किस पर है इस पर मौन रहते हुए भारत सरकार ने प्रस्ताव न स्पष्ट किया कि वह क्षेत्र में तनाव का कारण इजरायल का अतिरिक्त रख रहा है। उसने अनुसार ज़रबों के क़त्ल काफ़ी दिना में दिखाने तक सोमा तक पहुँच चुका था। भारत ने स्पष्ट में यह ज़रबों के पक्ष में था और अतिरिक्त समुदाय का। इसका तात्पर्य माना चाहिए। भारत सरकार ने नवम्बर 1967 के सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को समर्थन करते हुए कहा कि यह प्रस्ताव को तुरंत कार्यान्वित किया जाना चाहिए। अनन्त मिस्र के साथ पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन भी दिया। लेकिन युद्ध के आख़िर में के लिए भारत ने कोई राजनयिक पहल नहीं की। शुरू में अनन्त सुरक्षा परिषद का यह युद्ध में हस्तक्षेप का विरोध भी किया। भारतीय दित्तमन्त्री सरदार स्वर्ण सिंह ने पश्चिमियों का इस भाग का कि पश्चिम एशिया में युद्ध तुरंत बंद किया जाना चाहिए समर्थन नहीं दिया। उन वाक्य भाषाया राजनयिता के माफ़न पश्चिम एशिया में शांति की सम्भावना पर ख़तरा लगाते विचार विमर्श चलता रहा। उन वाक्यों में भारत ने स्पष्ट कर दिया कि पश्चिम एशिया में याद के आधार पर ही शान्ति स्थापित हो सकती थी और कार्यान्वित नहीं रहती कि उन सभी ज़रबों के अतिरिक्त आदिपत्य हत्याकाण्ड जिनसे 1967 में हमारे देशों में आकाश पर किया था।

22 अक्टूबर 1973 को सुरक्षा परिषद ने पश्चिम एशिया में युद्ध के सम्बन्ध में युद्ध विराम का प्रस्ताव पारित किया। भारतीय प्रतिनिधि ने यह कहकर कि हमको तब भारत सरकार के विचारों के अनुसार है उस प्रस्ताव पर पूर्ण सहमति दी। भारत ने उस भाग पर यह ज़ाह्य भी व्यक्त की कि प्रस्ताव को लागू करने के लिए शीघ्र काम चलाय जायें ताकि फिर गतिरोध पक्ष नहीं हो।

सुरक्षा परिषद का यह प्रस्ताव कार्यान्वित सध तथा स वत समय अमरिका के संयुक्त प्रदानों के द्वारा था। यह शक्तियों ने अणु में विचार विमर्श करके एकरा में उस प्रस्ताव का बुद्धिमान रूप पर धारण किया था। उस प्रस्ताव में मुख्य में भारत का कुछ प्रस्ताव भी था। मुख्य कारण में दोनो देश भारत के प्रतिनिधि समारमन ने उस बात का फैसला कर लिया। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव शुरू हुआ था जो दो देशों ने समझौते कर लिया और युद्ध पक्षों ने प्रस्ताव को लागू कर दिया सभी स्थिति में प्रस्ताव को समर्थन करने के लिए हमारे पास और कोई चारा नहीं है। कि भा भारत के प्रतिनिधि ने पारित हुए प्रस्ताव में कि नवम्बर 1967 के प्रस्ताव के बजाय वदन का यह प्रस्ताव कि इजरायल ज़रबों के साथ ज़रबों के अतिरिक्त समुदाय का समर्थन करने के

रूप में कायम रहने का हक मिले तथा जिन्स्तीनी जनता के अधिकारों का समचित समाधान स्वीकार किया जाय ।

तेल सफट और भारत — इस प्रकार भारत ने सदा की भाँति अरबों का पूरा समर्थन किया । इस बीच तेल उत्पादक अरब राज्यों ने इजरायल के समर्थन का तिलाफ्त कारवाई करने का उद्देश्य सफलतापूर्वक का मूँय बेहिसाब बढ़ा दिया और उसकी आपूर्ति पर कुछ पाव भी लगा दी । अरबों के इस हथियार का प्रयोग में यूरोप की अर्थ व्यवस्था असंतुलित हो गयी । पश्चिम यूरोप में विकास की गति गंभीर रूप से रुक गयी । मिस्रिशशाह देशों के लिए तेल के मूल्य में बढ़ि विध्वंसकारक सिद्ध हुई । इन देशों ने अतन्त्र जो उन्नति की थी उसका घोषट हो जान की सम्भावना स्पष्ट होने लगी । दिसम्बर 1973 में जब ईरान ने कच्चे तेल का छुटे बाजार में बचन का घोषणा का तो भारत सहित सभी विकासशील देशों में खूब बर्बाद भव गयी । तेल का निर्यात का नतीजा यह होता कि कच्चा तेल खरीदने पर ईरानों तेल प्राप्त कर भवना या रिसर्च योगी खर्च कम होती । इस प्रतियोगिता में स्पष्टतः अमेरिका और जापान के मुकाबले में अर्थ गण पाछे रह जाते । तेल के सफट न भारत के समेत एक विश्व समस्या उत्पन्न कर दी । भारत का दुसरा इस बात का था कि तेल जग में ब्रूत हथियार का उपयोग में अरबों ने अपने दोस्तों और शत्रुओं में कोई फर्क नहीं किया । बू वि अमेरिका इजरायल का साथ था इसलिए यह बात समझ में आ सकती है कि अरब देश अमेरिका को तेल बन्द कर दें या तेल का दाम बढ़ा दें । लेकिन साथ में भारत जो अरबों का मित्र रहा था उसका लिए भी तेल का दाम बढ़े यह बात अतन्त्र भारतीयों को समझ में नहीं आया । अरबों के इस व्यवहार से भारतीय लोकमत बहुत दुःख हुआ और भारत सरकार काफ़ी परेशानी में पड़ गयी । लेकिन जहाँ तक अरब इजरायल संघर्ष में अरबों का समर्थन का प्रश्न था भारत अपनी पुरानी नीति का ही अतन्त्र व्यवहार करता रहा ।

साहोर का इस्लामी सम्मेलन और भारत — 22-24 फरवरी 1974 को पाकिस्तानी नगर साहोर में दूसरा इस्लामी सम्मेलन हुआ जिसमें मुख्यतः पश्चिम एशिया की समस्या पर ही विचार विमर्श हुआ । सम्मेलन में कई प्रस्ताव स्वीकार हुए । जम्हूरियत से इजरायली सन्धि का तुरत हटाने की मांग की गयी । पश्चिम एशिया में शांति समन्वित की सम्भावनाओं पर भी विचार हुआ ।

स्वात में प्रथम इस्लामी सम्मेलन में हुए अनुभव का आधार पर यह बार भारत ने सम्मेलन में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने को चूँक नहीं था । लेकिन राजनीति का इस मजहूबाकरण का प्रयास को भारत ने अभी पसन्द नहीं किया । यद्यपि भारत ने इस पर किसी तरह की अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की लेकिन यह सम्भावना थी कि इस तरह के प्रयासों में भारत और पश्चिम एशिया के देशों में गठन पड़ने लगे । सम्भवतः इसी कारण मिस्र के राष्ट्रपति मन्सूर न साहोर में इस्लामी सम्मेलन में भाग लेने के बाद ही जिनो के लिए (24-25 फरवरी 1974) भारत आया । सआदत की भारत यात्रा का उद्देश्य पाकिस्तान तथा अन्य मस्लिम देशों को यह बताना था कि इस्लामी जिनर सम्मेलन में भाग लेने का यह पक्ष मिस्र शर्मिन् पक्ष भारत का छात्रिक नज़र है । भारत में खाना हाथ का पत्र उठाने यह भी प्रयास कि मिस्र की राजनीति तथा आर्थिक प्रस्ताव पर भारत का पक्ष सहमति रखे ।

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका

(India and the U S A)

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि — स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई निगम सम्पर्क नहीं था। इसका कारण यह था कि प्रथम भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका एक-दूसरे से बहुत दूर पर स्थित हैं। तब अमेरिकी सरकार जान-बूझकर ऐसी नीति का अवलम्बन करती थी ताकि भारतीय किसान दूसरे देशों के सम्पर्क में न आ सकें। सामान्य द्वितीय विश्व-युद्ध के पूर्व तक संयुक्त राज्य अमेरिका भी विश्व राजनीति में पाथक्वया नीति (policy of isolation) का अवलम्बन करता रहा। चीन और जापान को लेकर एशिया के मामले में उसने अपना विचार रचने की प्रवृत्ति का प्रदर्शन नहीं किया। सांस्कृतिक स्तर पर भी दाना दाना का सम्पर्क नाममात्र का ही रहा। स्वतंत्रता के पहले कुछ अमेरिकी वैश्विक और पत्रकार भारत अवश्य आये थे लेकिन भारतीय जीवन का गहरी जाँच-निरीक्षण करना वे उम्हारे अपना मकसद नहीं मानते थे। मिस्स मैयो (Miss Mayo) द्वारा मस्टर इंडिया पुस्तक की रचना ऐसा उद्देश्य से हुई थी। ब्रिटिश सरकार में कुछ अमेरिकी कनिष्ठ मिशनरियों का भारत में काम करने की बातें उनके वादकगणों से दाना देने के सम्बन्ध में काफी दृढ़ता नहीं आया। भारतीय विद्यार्थियों का सभी अमेरिकी विश्व विद्यालयों में पढ़ने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था। यदि कोई भारतीय इस तरह का इरादा प्रकट करता तो ब्रिटिश सरकार उसके नागरिकता में तत्काल रद्द का आदेश उद्घोषित करती। संयुक्त राज्य अमेरिका का अधवास नियम (immigration law) प्रत्यक्ष भारत विरोधी था। इस नियम ने नागरिक के रूप में अमेरिकी में बसने से भारतीयों पर प्रतिबन्ध लगा दिया था।

इन सारा बाधाओं के बावजूद प्रथम विश्व युद्ध के उपरान्त भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य धीरे-धीरे सम्पर्क बढ़ने लगा। भारत के राष्ट्रीय जागरण के नेता अमेरिका का स्वतंत्रता और प्रजातन्त्र का पक्ष मानते थे और वे सोचते थे कि भारतीय स्वाधीनता की लड़ाई में उन्हें अमेरिका की सहायता और प्रोत्साहन प्राप्त होगी। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय नेताओं ने राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के आत्मनिर्णय के सिद्धांत का स्वागत किया। 1919 के जिनो कायस अधिवेशन में अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय ने विल्सन को पदों पर वापस वापस करने के लिए कहा था। उन्होंने विल्सन को कहा कि वे भारत को (Free India for India) का बड़े उत्साह से स्वागत किया। इस प्रकार भारतीयों ने राष्ट्रपति विल्सन से बनी-बसी सम्झौते और यह विश्वास किया कि यदि वे जिनो सम्मेलन में उनका मत सार्वभौमिकता का भी स्वाधीनता का अधिकार प्राप्त होगा। परन्तु इस सम्बन्ध में भारतीयों को बड़ी निराशा हुई। विल्सन ने उनके प्रति किसी तरह की रुचि नहीं की।

द्वितीय विश्वयुद्ध के 1917 में अमेरिका में विमान करनेवाले कुछ भारतीयों ने एक 'इंडियन होम रूल लीग' (Indian Home Rule League of America) की स्थापना कर दी थी। युद्ध के बाद जब अमेरिका के स्वतंत्रता के सिद्धांत का भारत पर लागू नहीं किया गया तब इसी लीग की सचि और राष्ट्रमन्त्री के विद्वत् एक आलोचनात्मक कर दिया। अमेरिकी लोगों ने इन लोगों के आग्रह किया कि वे तब तक शांति संधियों को माँगे न जिस समय नहीं हो जबतक भारत के साथ व्यापक शांति होना।¹ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अमेरिकी सीनेट के समर्थन करने के लिए एक ज्ञापन पत्र समार किया जिसको सिनेटर मेलबो ने सीनेट की कमेटी के अध्यक्ष विमल मणि के समक्ष पेश भी किया। लेकिन भारतीय यूटियोन में प्रयागों का कोई प्रतीक नहीं मिलता। अमेरिकी सरकार का जनता में भारत का कोई प्रभाव नहीं प्राप्त नहीं हुआ।

1927 में कुछ भारतीयों ने 'इंडिया लीग' (India League) नामक एक अमेरिकी संस्था संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित की। इस संस्था ने 'इंडिया टुडे' (India Today) नामक एक मासिक पत्र का प्रकाशन भी शुरू किया। इसी तरह की एक दूसरी संस्था भारतीय स्वतंत्रता की राष्ट्रीय समिति (National Committee for India's Freedom) 1913 में वाशिंगटन में स्थापित की गयी। वाशिंगटन में 'विंडो इंडिया' (Vico India) के नाम से एक भी एक पत्र प्रकाशित। इन दोनों संस्थाओं का उद्देश्य भारतीय परिस्थिति में अमेरिकी राजमन्त्री को अवगत कराना था। 1929 में भी एक लॉर्ड (C. J. Andrews) तथा श्रीमती सरोजिनी नायडू ने भारतीय संस्था के प्रति अमेरिकी महासमुक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया। यह यात्रा काफी लाभदायक रही। भारत के मामलों में अमेरिकी लोगों की रुचि स्पष्ट रूप से बढ़ी।²

स्वतंत्रता संग्राम के समय में अमेरिका के बारे में भारतीय नेताओं की जो भावना थी वह बाद में महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति स्वतंत्र भारत के दृष्टिकोण को माँगे गए। प्रभावित किया।

अमेरिकी कांग्रेस का राजनीति में माध्यम में जवाहरलाल नेहरू का प्रभाव निरालाकारी पड़ेगा जो 1927 में हुई। 1927 के पंद्रह साल बाद इस सम्मेलन में अमेरिकी लोगों के एक प्रतिनिधि आये थे। उन्होंने लोगों के लिए अमेरिका में गहन राज्य अमेरिका की मासिकपत्रों नीति में जवाहरलाल नेहरू का परिचित कराया। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विचार आने प्रतियोगिता में यह है कि तब तक हमने जवाहरलाल नेहरू के विचारों को अमेरिका में समुक्त राज्य अमेरिका के मासिकपत्रों के माध्यम से प्रसारित नहीं कराया। लेकिन यह एक ऐतिहासिक तथ्य है और अमेरिकी राजमन्त्री

1 D. N. Verma *India and the League of Nations* p. 27

2 Prafulla Chandra Sen *The Origins of Indian Foreign Policy* p. 39

3 Jawahar Lal Nehru *An Autobiography* p. 162

अप्रत्याशित सफलता ने अमरीकी नेताओं को बहुत चिन्तित कर दिया। वे अनुभव करने लगें कि युद्ध प्रयास में भारत के राष्ट्रवादी तत्त्वा का सहयोग लेना परमावश्यक है और यह तभी संभव है जब ब्रिटिश सरकार कम-से-कम मित्रांतर के रूप में भारतीय स्वतंत्रता की बात मानें। अतएव अमरीकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट (Franklin D. Roosevelt) ने भारत की स्वतंत्रता का पक्षपोषण करते हुए ब्रिटिश प्रधान मंत्री विंसटन चर्चिल (Winston Churchill) से भारतीय समस्या का समाधान करने पर अनेक बार बातचीत की। प्रधानमंत्री के नाम 10 मार्च 1942 को भेजे गये अपने एक संदेश में भारतीय समस्या के प्रति अपनी गम्भीर चिन्ता व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा था 'यद्यपि इस मामले में मेरा कोई प्रत्यक्ष मतदान नहीं है तो भी मैं समस्या के समाधान के लिए उत्सुक हूँ। भारतीय समस्या में रूजवेल्ट की इस रुचि ने भारतीय समस्या के समाधान के लिए ग्रिप्स मिशन (Gripes Mission) भेजे जाने के निणय की प्रभावित किया। 11 मार्च 1952 को यह घोषणा हुई कि सर स्क्वॉ ग्रिप्स भारतीय नेताओं से वार्ता करने और गतिरोध को दूर करने के लिए भारत जायेंगे। ग्रिप्स वार्ता में मन्त्र देने के उद्देश्य में रूजवेल्ट ने लुई जॉनसन (Louis Johnson) को अपने भारत प्रतिनिधि बनाकर भेजा। यद्यपि जॉनसन की परिस्थिति के बावजूद ग्रिप्स मिशन असफल रहा। लेकिन यह इस बात का सबब था कि अमरीकी प्रानेय भारतीय समस्या में अब सक्रिय रुचि लेने लगा है।

ग्रिप्स मिशन जब असफल होना लगा तो रूजवेल्ट ने एक बार और हस्तक्षेप किया। 11 अप्रैल 1942 को चर्चिल ने नाम अपने संदेश में उन्होंने पुनः यह अनुरोध किया कि समझौता व तात्कालिक भग होने से बचाने के लिए एक और प्रयत्न किया जाय और साथ ही यह भी कहा कि अमरीकी जनता यह नहीं समझ पा रहा है। यदि ब्रिटिश सरकार युद्ध के उपरान्त भारत के विभिन्न भागों का ब्रिटिश साम्राज्य का अधीनता से मुक्त करने के लिए तैयार है तो वह युद्ध के समय उम स्वशासन देने का क्यों राजी नहीं होती? चर्चिल पर रूजवेल्ट के विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और ग्रिप्स मिशन पुनः तबला अमफल सिद्ध हुआ। फिर भी रूजवेल्ट भारतीय समस्या के प्रति उत्साहित नहीं हुआ। 25 जुलाई 1942 को रूजवेल्ट का अपने एक सन्देश में चीन के जेनरल चोंगकाई-शान ने यह अन्तर्भाव किया कि यह भारत की स्वतंत्रता लाने के लिए हस्तक्षेप करे। 12 अगस्त को चोंगकाई-शान को उत्तर देते हुए उन्होंने लिखा 'यह उल्लेखनीय समस्या सभी के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है मेरा और आका काय ब्रिटिश सरकार मिस्टर गांधी और अन्य अंतर्वासियों को यह स्पष्ट कर देना है कि हम ब्रिटिश सरकार अथवा कांग्रेस को निणय के लिए बाध्य करने का नतिक अधिकार नहीं है। 'ऐवन इसके साथ ही हमें दोनों पक्षों को स्पष्ट कर देना चाहिए कि हम उन मित्र हैं और यदि हमारी सहायता की अपेक्षा है तो सहाय्य उम्भन के लिए प्रस्तुत है।'¹

1. भारत की स्वतंत्रता के सम्बन्ध में अमरीकी सरकार ने जो रुचि ली उसका विस्तृत विवरण उन कांग्रेस-पत्रों का पढ़ना समझना है जो अमरीकी विदेश विभाग द्वारा 1960 में फोरेन रिलेशंस में सिरीज फोरिग्न रिलेशंस 1942 (Foreign Relations Series for the year 1942) नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया है।

एसा जगता है कि भारतीय समस्या में अमरिका की रुचि एन विंग एन शैड में ही प्रतिबिम्बित है। वह यहाँ चाहता था कि जापान के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों के दृष्टि में प्रयत्न में किसी तरह का बाधा नहीं पड़े। इसलिए 1942 में भारतीय अन्तिम वाक्य में वरिष्ठ जव ब्रिटिश सरकार ने अमरीका जापानों का प्रयास किया कि अमरीकी सरकार ने इसका कोई विरोध नहीं किया। भारतीय नेताओं का इस बात में पूरी निराशा थी। उस समय ब्रिटिश अपने बचाव के लिए संयुक्त राष्ट्र अमरिका पर पूर्णतः निर्भर था। यदि अमरीकी प्रयासों को भारतीय समस्या के प्रति सचेतन सहानुभूति रखती तो वह ब्रिटिश सरकार पर बाधा प्रभाव डाल सकता था तथा ब्रिटिश का बाध्य कर सकता था कि वह भारत को आजाद दे दे। भारतीय नेताओं ने बारम्बार रजिस्ट्रार से अपील की कि वह भारत के सम्बन्ध में कुछ निश्चय निकाले। लेकिन रजिस्ट्रार ने न तो सन्तुष्टि समर्थन का एवम्भान किया कि नहीं किया।¹ भारतीय स्वाधीनता के प्रश्न पर 1945 तक अमरीका का रुझान ही रहा था। 1945 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में सोवियत संघ ने भारत को स्वतंत्रता का समर्थन किया। लेकिन उस प्रश्न पर अमरीकी प्रतिनिधित्व ने मन रखा ही उचित समर्थन। उस कारण संयुक्त राष्ट्र अमरीका भारतीयों का निराश्रय और भ्रम निरूपित गया।²

उस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व संयुक्त राष्ट्र अमरीका के सम्बन्ध में भारतीयों की धारणा काइ जहाँ नहीं थी। ब्रिटिश भारत में मुसलमान साम्राज्यशासकों का मानव था। अतः भारतीय स्वाधीनता के प्रश्न पर वे बहुत दयाभाव रखते तथा सामाजिक तौर पर समर्थन करने से वे भारत के अमरीका से न समर्थ प्राप्त भारतीयों का ध्यान भी मुशकिल कर दिया। स्वतंत्र भारत का निर्माण नहीं हो ही अमरीकी निराशा तथा पाठ है उनका समर्थन के लिए इस दृष्टिकोण पर ध्यान रखना आवश्यक है।

राजनयिक सम्बन्धों की ओर—राजनीति शास्त्र का अर्थ है घट के निम्न में भारत और संयुक्त राष्ट्र अमरीका एक दूसरे के सम्बन्धों का अध्ययन। अतः भारत अमरीका का सल जल और युद्ध के भारत सरकार का एक वाणिज्य आयुक्त (Trade Commissioner) हुआ था। 1941 में भारत सरकार ने एक एजेंट अमरीका की हागीवर्ग की ओर गिरजा गुजर करण की उस पर निर्भर किया। फरवरी 1946 में जापानों की वीच राजनीति सम्बन्धों का अन्तर्गत हुआ। संयुक्त राष्ट्र अमरीका में अन्तर्गत है। भारत का दृष्टि सम्बन्ध है।

संयुक्त राष्ट्र अमरीका के साथ भारत का राजनयिक सम्बन्ध कायम रूप में था दोनों की सम्बन्ध में एक नये युग का प्रारम्भ था। भारत का अन्तर्गत के अन्तिम सन्तान अन्तर्गत वर्षों के अन्तर्गत में अन्तर्गत अन्तर्गत के अन्तर्गत सम्बन्ध अन्तर्गत और मित्रता का एक विविध बहना रहे है। अतः अन्तर्गत महान् पूरा मामलों में भारत ने अमरीका नीति का बहुत आभावना की है और अन्तर्गत

1 B Prasad *The Origins of Indian Foreign Policy* pp 200 and 257

2 Ibid pp 214 and 258

मामला में उसकी अपना समझन भी दिया है। भारत को 'सल्मन्ता' की नीति पर चलने का कारण नहीं एक जोर अमेरिका ने भारत की हिता को कभी-कभी बहुत नज़रान पड़ेबाय है वहां दूसरी ओर प्रचुर आर्थिक सहायता का द्वारा और भारत चीन संबंध का समय अविविध विना दत्त सन्निह सहायता देकर भारत का प्रति अपनी मन्त्री का परिचय भी दिया है।

संदर्भ का वातावरण में सम्बन्ध का प्रारम्भ—कई परिस्थितियों के कारण भारत के स्वतंत्र होने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत का पारस्परिक सम्बन्ध का प्रारम्भ संदेह के वातावरण में शुरू हुआ। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिका ने भारत का प्रति जो रुख अपनाया था उसको प्रबुद्ध भारतीय भन्ने नहीं था। नवीन भारत सरकार के आगत कई उच्च पद पर मदाधिकारी थे जो युद्धोत्तर कालीन अमेरिकी विचार नीति को नज़रान की निगा में न देखते थे। दूसरी तरफ कुछ प्रमुख अमेरिकी नेता न अमेरिका जोर माविमन सघ का शान युद्ध में एक बना हो गलत दृष्टिकोण अपना लिया था। उनका कहना था कि जो दश स्पष्ट रूप में अमेरिका के साथ नहीं है वे उसके विरोधी हैं। अमेरिकी न भारत की अमन्यन्ता की नीति को ठीक का सासना बतलाया। कुछ प्रमुख अमेरिकी नेताओं ने न्याय के वक्तव्य दिये कि जाहज़ाज़ "है" एक अघ साम्यवादी (quas communist) है जिनका उद्देश्य असन्तुष्टता की आग में धीरे धीरे खिसकाकर भारत को सोवियत युग में ले जाना है। जनवरी 1947 में जॉन फास्टर डब्लु ने कहा था कि भारत में सोवियत साम्यवाद अतकालीन हिन्दू सरकार के माध्यम में अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा है।

भारत और अमेरिका के प्रारम्भिक सम्बन्ध में जो मतभेद उत्पन्न हुए उसके मौलिक कारण थे। तत्कालीन अंतराष्ट्रीय स्थिति पर दाना का दृष्टिकोण में भूत-भूत उत्तर था। अंतराष्ट्रीय साम्यवादी जागृता और उपनिवेशवाद का संघर्ष में दाना लेना के दृष्टिकोण में स्पष्ट उत्तर था। अमेरिकी दृष्टिकोण में सोवियत संघ के नेतृत्व में चल रहे अंतराष्ट्रीय साम्यवादी जागृता युद्धोत्तर विश्व को सबसे बड़ी समस्या थी और इनका कुचर्न के लिए अमेरिका किसी भी हद तक जान का तयार था। वह युद्ध करने का भी तयार था। भारत इस हद तक जाने को तयार नहीं था। वह विश्व शांति को सर्वोपरि स्थान देता था। एक बार श्रीमती विजया लक्ष्मी पण्डित ने ठीक ही कहा था कि भारत का गिरा युद्ध साम्यवाद से भी अजिब बड़ा संकट है। हमारे भारत उपनिवेशवाद का प्रबल विरोधी था। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका स्वयं एक साम्राज्यवादी देश था और विश्व का विभिन्न भागों में यूरोपीय साम्राज्यवाद का खला समर्थन करता था।

युद्धोत्तर काल की दो प्रमुख समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण में उत्तर के कारण प्रारम्भ में ही भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका का सम्बन्ध मन्त्रों के माध्यम से शुरू हुआ। तिस मध्य भाग में विभिन्न पराधीनता से मुक्त हुआ उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का सम्बन्ध अत्यन्त बिगड़ गया था और दाना के मध्य भोषण रूप में जोत युद्ध शुरू हो गया था। सोवियत संघ का विराय करने के लिए अमेरिका विश्व ध्वारी पमाने पर तयारी कर रहा था। इस कार्य में वह अधिक से अधिक देशों का समर्थन प्राप्त करना चाहता था और संसार का सभी गर-साम्यवादी

देशों को अपन गृट का सख्य बना सना चाहता था। एशिया व नवोदित राष्ट्रों की ओर उसका विषय भुकाव था और उसका विचार था कि ये राष्ट्र भीत युद्ध में अमेरिका का साथ दें तथा सोवियत संघ का विरोध करें। जो देश अमेरिका का इस नीति से सहमत नहीं होते थे उन्हें शत्रु या विरोधी की कानि में रखा जाता था। भारत उस समय आर्थिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा हुआ देश था और उस विन्नी सहायता का बनी आवश्यकता थी और यह सहायता अमेरिका से ही मिल सकती थी। अतएव अमेरिका को यह आशा थी कि स्वतन्त्र भारत आर्थिक मूल्यवर्धनका साथ देगा। लेकिन उसे निराश होना पड़ा क्योंकि स्वतंत्र भारत का सरकार न गुप्तों में अलग रहनेवाली असह्यता की नीति को अपना लिया। गृटविन्नीयों के मध्य तत्स्य या असह्यता की नीति अमेरिका को पसन्द नहीं थी और इसलिए वह भारत का गका की दृष्टि से देखने लगा। भारत को अपन राजनयिक जाल में फसान के लिए अमेरिका की ओर से कितने प्रयास हुए लेकिन भारत इन सारे प्रयासों को विफल बनाता रहा। उसने अमेरिकी गृट में शामिल होने से साफ-साफ इन्कार कर दिया। ऐसा हाल में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका का सम्बन्ध सन्तोषजनक रूप से प्रारम्भ नहीं हुआ। दोनों देशों के बीच कुछ मौखिक मतभेद थे जिनका उनके सम्बन्धों पर प्रभाव पड़ना आवश्यक था। इनके अतिरिक्त जब जम समय बीतता गया वनन्वस निम्न बातों पर मतभेद बढ़ता गया

कश्मीर के प्रश्न पर मतभेद—कश्मीर के प्रश्न पर भारत का ज मत और भारतीय प्रयासन अमेरिका के पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण का 1948 से लेकर अब तक कठोर आलोचना रहा है। कश्मीर पर पाकिस्ताना हमरा से उत्पन्न स्थिति पर माय पाने के लिए 31 दिसम्बर 1947 का भारत उस प्रश्न का संयुक्त राष्ट्र संघ में ग गया। उस यह आशा थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका माय का पक्ष ग्रहण करगा और पाकिस्तान को आक्रमणकारा घोषित करान में मदद देगा। लेकिन अमेरिका का दृष्टिकोण ठीक उसके विपरीत था। उसने भारत का समयन करने के बजाय पाकिस्तान का गने लाया। आ तब कश्मीर का समस्या का समाधान नहीं हो पाया है और इसका मूल में अमेरिका भारत विराधी रवमा है। अमेरिका के इस दृष्टिकोण से भारतीय तावमत गलत से ही अमेरिका का विरोधी हो गया। भारतीय समाचार-पत्रों ने लिखा कि संयुक्त राज्य अमेरिका कश्मीर में सोवियत संघ के विरुद्ध सैनिक आता कायम करना चाहता है। उनका विनास है कि यदि कश्मीर भारत के साथ रहा तो उसको इस तरह के जहुने बनान की मुविधा नहीं मिलेगी। अतएव वह पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है।

केवल कश्मीर के प्रश्न पर ही नहीं वरन भारत और पाकिस्तान के मध्य अन्य सगहों पर भी संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत विरोधी दृष्ट अपनाया। भारत पाकिस्तान सम्बन्धों पर अमेरिका के इस रुख ने दोनों देशों के सम्बन्धों में गार हालत का भूमिका निवाही है।

दक्षिण अफ्रिका के प्रवासों भारतीय की समस्या और उपनिवेशवाद पर मतभेद—प्रारम्भ में भारत का एक और मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में पेश था। दक्षिण

अफ्रिका में प्रवासी भारतीयों के साथ वहाँ की सरकार रणभेद की नीति के आधार पर जो व्यवहार कर रही थी उसने सम्बंध में भारत ने संयुक्त राष्ट्रसंघ में प्रश्न उठाया। संयुक्त राष्ट्रसंघ की साधारण सभा में जब इस विवाद पर बहस हुई तो अमेरिकी प्रतिनिधि ने हमारा दक्षिण अफ्रिका की सरकार का समर्थन किया और ऐसे किसी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करने दिया जिससे दक्षिण अफ्रिका सरकार की निंदा हो रही थी। इस तरह पराधीन राष्ट्रों के स्वातंत्र्य आंदोलन के सम्बंध में अमेरिका का रुख भारत को बिना कुछ पसन्द नहीं आया। ऐम आंदोलनों के प्रति भारत की पूरी सहानुभूति थी लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण में इण्डोनेशिया मलया और हिंद चीन के राष्ट्रीय आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद के पक्ष में थे सिवा और कुछ नहीं थे। अतएव इन आंदोलनों को बुचकान में उसने मशेष के उपनिवेशवादी राष्ट्रों को अपना नतिक समर्थन प्रदान किया। भारतीय लोकमत को इससे बड़ी निराशा हुई।

कम्युनिस्ट चीन का प्रादुर्भाव और भारत अमेरिका में रणभेद—यद्यपि रणभेद की नीति तथा उपनिवेशवाद पर दोनों के विभिन्न दृष्टिकोणों के कारण उनका सम्बंध में दूरार तो पड़ ही रही थी। इसी समय चीन का राजनीतिक परिवर्तन न उनका मतभेद को और भी गहरा कर दिया। चीन में कम्युनिस्टों की सफलता के पहले तक भारत के प्रति अमेरिकी नीति लगभग उदासीन थी। लेकिन 1949 में कम्युनिस्टों की जीत और जनवादी चीन की स्थापना ने पूर्वी एशिया की स्थिति को एकदम बदल दिया। बदली हुई परिस्थिति में अमेरिका के लिए भारत का महत्त्व बहुत बढ़ गया। इस सम्बंध में प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रकार वाल्टर लिप्मैन (Walter Lippmann) का कर्त्तव्य प्रभावित हुए। एक क्षण में उसने सोचा था कि जबकि एशिया में निदर्शित फास और राष्ट्रवादी चीन असफल हो गये उस हास्य में हम मित्रों की तलाश वहाँ करें? एशिया में अमेरिकी नीति के निर्धारण के लिए इस मौलिक प्रश्न का समाधान आवश्यक है। मैं यही कहूँगा कि अब हमें हमारा नजरों की ओर दबना चाहिए। हमारी समस्याओं के समाधान की कुंजी उहीं के पास है। यद्यपि यह एक सर-सरकारी प्रश्न का व्यक्तिगत विचार था लेकिन अमेरिका के शासकीय क्षेत्र में भी यही तरह के विचार आने लगे। उसका कहना था कि नजरों सुरत ही चीन द्वारा उपस्थित संकट को समझने और उसका अंत के लिए अमेरिका का हाथ मजबूत करेंगे। इसलिए भारत के प्रति अमेरिकी रुख में कुछ नरमी आयी। उस समय भारत पार आर्थिक संकटों में पड़ा था। इन संकट का मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने कुछ आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया। इन बातों पर विचार विमर्श करने के लिए अमेरिकी प्रशासन ने जवाहरलाल नेहरू को अमेरिका भ्रमण के लिए आमंत्रण दिया। जवाहरलाल ने पहुँचे तो इस आमंत्रण को अंगीकार किया लेकिन मई 1949 में उन्होंने अमेरिका जान का निश्चय किया।

सितम्बर-अक्टूबर 1949 में नेहरू ने अमेरिका की यात्रा की। उन्होंने यह आशा व्यक्त की कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के पुनर्निर्माण के लिए वार्षिक आर्थिक सहायता देगा। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि इस आर्थिक सहायता को प्राप्त करने के लिए भारत अपनी विदेश नीति के मौलिक सिद्धांतों का परिपालन नहीं करेगा। पूर्व और पश्चिम के बीच घटने में पड़ने से भी उन्होंने इंकार किया।

बताया। जवाहरलाल ने बानिने तथा रूयू टायुमा पर अमरीकी सरकार का विचार करत हुए इन्हें जापान को वापस करने का प्रस्ताव रखा और जापान में मित्रों की सहायता का विरोध किया। दूसरे ने जब नेहरू का प्रस्ताव नहीं स्वीकार किया तो नयी दिल्ली में 23 अगस्त को वाशिंगटन को यह सूचना दी कि यह सन्ध्यासिस्को सम्मेलन में शामिल नहीं होगा तथा जापान से पृथक् संधि करेगा। भारत का यह खयाल संयुक्त राज्य अमेरिका को एकदम पसंद नहीं आया। जून 9 जन 1952 को भारत ने जापान के साथ पृथक् संधि कर ली तो अमेरिका में इसका विरोध भी तीव्र प्रतिप्रिया हुई।

हिंदू चीन के प्रश्न पर मतभेद — हिंदू चीन की समस्या का समापन में भी भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में मतभेद था। उपर्युक्त बातें प्रकट हुए ब्यापारिक दलों के विरोध में मौखिक अंतर था। इस समस्या की भारत परस्परिक बातों का आधार पर और प्रातिपक्ष तरीकें से सुलझाने का पक्षपाती था जब कि अमरीकी प्रशासन सैनिक शक्ति का सहारा लेता चाहता था। 1954 में हिंदू चीन की समस्या सम्बन्धी हो गयी। भारत की सरकार ने हिंदू चीन में अपने उपनिवेश कायम रखने के लिए अमेरिका से सैनिक सहायता मांगी। अमरीकी विदेश सचिव जॉन फास्टर डलस ने घोषणा की कि वह हिंदू चीन का कम्युनिस्टों के हाथों नहीं पड़ने देगा और फ्रांस का सहायता करेगा। इसका अर्थ अमेरिका द्वारा युद्ध में लड़ने वाला जोर तृतीय विश्व युद्ध का प्रारम्भ था।

भारत ने अमेरिका के इस दृष्टिकोण का विरोध किया और जवाहरलाल नेहरू ने दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने का लिए एक तरह की मूर्ख प्रस्ताव रखा और युद्ध को नष्ट करने का सुझाव दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका में इस विरोध को प्रतिक्रिया हुई। कुछ अमरीकियों ने उनपर साम्यवादियों से सहानुभूति का आरोपण करते हुए यह कहा कि वह इसकी मित्रता की उम्मीदों को भविष्य में होने वाली हार से घबराता चाहता है। बाद में हिंदू चीन में विरोध भी हुआ और समस्या के समाधान के लिए जेनेवा में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। अमरीकी विदेश सचिव जॉन फास्टर डलस ने इस बात का भरपूर मान किया कि यह सम्मेलन किसी तरह असफल हो जाय। उपर भारत के प्रतिनिधि भी एक कृष्णमान ने सम्मेलन को सफल बनाने का जो-तोड़ प्रयास किया और हिंदू-चीन के सम्बन्ध में एक समझौता हो गया। भारत के इस खयाल के कारण अमेरिका को नाराजगी विद्यमान स्वभाविक थी।

तिब्बत के प्रश्न पर मतभेद — 1950 में चीन की जनवादी सरकार ने तिब्बत पर आधिपत्य कर लिया। तिब्बत में भारत सरकार का मित्रादिपक्ष और वह नहीं चाहती थी कि तिब्बत के सम्प्रदाय में चीन को ऐसी कारवाई करे। जब बेकिंग ने तिब्बत पर आधिपत्य कायम कर लिया तो अमरीकी प्रशासन ने मांगा कि भारत सरकार इसका विरोध करेगी और चीनी आधिपत्य के विरोध में अमेरिका से सहायता लेगी। लेकिन भारत ने चीन के साथ तिब्बत के प्रश्न पर समझौता कर लिया। बाद में पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। संयुक्त राज्य अमेरिका को यह बात भी पसंद नहीं आयी। इस घटना ने दोनों देशों के परस्परिक मतभेदों को और भी बढ़ा दिया।

कि पाकिस्तान अमेरिका द्वारा दी गयी सैनिक सामग्री का दुरुपयोग भारत के विरुद्ध करने का एक प्रतीक है लेकिन अमेरिकी प्रशासन ने हर बार भारतीय शिकायतों की उपेक्षा की। भारत के प्रति शत्रु भाव रखने वाला राष्ट्र जब मुश्किलों की अमेरिकी सहायता में प्रबल सैनिक राष्ट्र बनने लगा तो विवश होकर भारत की भी रक्षा पर अधिक खर्च करना पड़ा। अमेरिका भारत की आर्थिक प्रगति पर प्रतिबल प्रभाव पड़ने लगा। पाकिस्तान को सतृप्त रखने की नीति पर चले हुए अमेरिका ने इस तथ्य की मान्यता की कि बंदूक का प्रयोग आक्रमण करने के लिए उनका ही सविज्ञान बन हो सकता है जितना कि प्रतिरक्षा के लिए और एक टका बंदूक से मारपी के निकल जाने के बाद इस प्रश्न का आवश्यक राजनीति में कोई महत्व नहीं रह जाता कि आक्रमण किसने किया था। पाकिस्तान में भारत विरोधी भावों को प्रचार की पृष्ठभूमि में अमेरिका के अम आश्वासनों की निरक्षरता स्वयं अमेरिका की बात थी कि अमेरिका द्वारा पाकिस्तान का हिंस्र गये शास्त्र का प्रयोग भारत के विरुद्ध नहीं किया जाएगा। यह सैनिक सहायता के संबंध में अमेरिका में भारतीय राजदूत को एम. सी. छागल ने स्पष्ट किया था — संयुक्त राज्य अमेरिका अपने हाथ में स्वयं अपने दूसरे अर्थ में किया हुआ काम को नहीं कर रहा है। वह भारत की कराँची और अरबों पाउंड में अमेरिकी सहायता कर रहा है ताकि उसका औद्योगिक विकास हो सके अभी समय था हमारे विरोधी देशों का शास्त्रज्ञ देखें हमें यह बात के लिए बाध्य कर रहा है कि हम अपने प्रतिरक्षा के लिए अधिक व्यय करें और हम प्रकार हमारे से साधन जितना हमारे देश की जनता के उपयोग के लिए उपयोग होना चाहिए था शास्त्रज्ञ के उत्पन्न में व्यय नहीं है।

एशिया-अफ्रीका में राजनीतिक गूढ़ता का अमेरिकी सिद्धांत—युद्धांतर काल में एशिया और अफ्रीका के देश धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे और यूरोपीय राज्यों का प्रभुत्व उन पर से उठने लगा। अमेरिका जो स्थिति पैदा हुई उनके संबंध में अमेरिका ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि हम क्षत्र में राजनीतिक शून्यता (political vacuum) उत्पन्न हो गयी है और हम गूढ़ता का भरन की जिम्मेवारी अमेरिका की है। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ हम उन क्षेत्रों पर अमेरिकी प्रभाव का कायम करना था। इसी उद्देश्य से प्रेरित हुए अमेरिकी प्रशासन ने 'हार्नेट' नामक मिशन तैयार किया जो अफ्रीका के प्रतिष्ठान किया। भारत में उन मिशनियों तथा शक्तिगणना के मिशन का बहुत आलोचना हुई। जवाहरलाल नेहरू ने बड़ा बड़ा शब्दों में इसका भ्रम बताया। इन घटनाओं ने अमेरिका के एक बहुत बड़ा बग का भारत का विरोधी बना दिया। अमेरिका तरफ से अनेक देशों के सम्बन्ध में तब जोर बिगाड़ आया जब भारत ने सवनाम जोर जाति में अमेरिकी हस्तक्षेप का विरोध किया। यह हस्तक्षेप आइसलैंड पर मिशन के अन्तर्गत हुआ था।

गोआ के मामले पर सम्बन्धों में बिगाड़—1961 तक भारत के कुछ भागों पर पुर्तगाल का अधिकार था और भारत शुरू में इस अपने इस भूभाग को भर्त्सित करने का प्रयास कर रहा था। लेकिन पुर्तगाल की सरकार उस प्रश्न पर भारत सरकार के साथ बातचीत करना को तयार नहीं थी। उस प्रश्न पर अमेरिकी सरकार का रुझान भी भारत विरोधी रहा क्योंकि पुर्तगाल नटो संगठन का एक संस्थापक और अमेरिका एक मित्र राष्ट्र को भारत के लिए नाराज नहीं करना चाहता था। अतएव गोआ और पुर्तगाल विवाद के प्रश्न पर उनसे पुर्तगाल का पूरा पूरा समर्थन किया। 7 नवम्बर 1955 को अमेरिकी विदेश मन्त्रिण अलेक्जेंडर हैग ने

उनके प्रयास से भारत और अमेरिका के सम्बन्धों में काफी सुधार हुआ। चस्टर बॉम के पूर्व अमेरिका भारत को आर्थिक सहायता न देता था। लेकिन नये राजदूत के प्रयासों के फलस्वरूप भारत का काफी मात्रा में अमेरिकी सहायता मिलने लगी। चस्टर बॉम ने इस बात की निश्चिन्ता की कि एशिया में सामर्थ्य का प्रसार की राहों में किताबें भरना ही प्रयत्न करना अल्पकालिक आवश्यक है कि भारत को अमेरिका से पूरी सहायता मिलनी चाहिए। अन्य कई कारणों से भी बाध्य होकर अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता देने की निश्चय किया। एशिया में अनेक विभिन्नता के बावजूद अमेरिका ने भारत के आर्थिक विकास में गम्भीर रुचि ली और कई तरह के ऋणों एवं सहायता में भारत का अनुबन्धन किया। उनका ही प्रेरणा में विश्व-वैक प्रियम अन्तर्गत प्राविधिक सहयोग आया। एशियाई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने ऋण और उपकरण के रूप में भारत को विभिन्न आर्थिक और प्राविधिक सहायता प्रदान की। मौखिक क्षेत्र में भी भारत और अमेरिका की मैत्री रही। फुल ब्राइट योजना (Fulbright Scheme) के अन्तर्गत दोनों देशों के बीच बहुत कुछ परस्पर विद्वानों का आदान प्रदान हुआ। 1956 में उच्च स्तरीय नेहरू ने दूसरी बार अमेरिका की यात्रा की। उस समय भारत के विदेश मंत्री ने जिन लोगों में बड़ी काम आयी। दिसम्बर 1959 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन्सन ने भारत की यात्रा की जिसके फलस्वरूप दोनों देशों के सम्बन्धों में और सुधार हुए। भारतीय जनता ने आनन्दवासर का बड़ा सम्मान और स्वागत किया। 13 दिसम्बर 1959 को जनता ने आनन्दवासर के लिए और नेहरू का जो समुचित विनम्र निम्तर्गत सम्मान किया था कि उनका सम्मान आनन्दवासर तथा शांति के लिए उनके सम्मान प्रथम दोनों देशों की मित्रता का और अर्थिक सम्मान तथा स्थायी बनावेंगे। राष्ट्रपति की यात्रा के उपरान्त अमेरिका की भारत के विकास में और भी गहरी रुचि हुई। 22 मार्च 1960 को अमेरिका के उपराष्ट्र सचिव डग्लस डिल्लन (Douglas Dillon) ने सानिटो की विदेश मन्त्रि के सम्मुख स्वीकार किया कि भारत का आर्थिक विकास अमेरिकी विदेश नीति का एक प्रमुख उद्देश्य बन गया है। इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति आनन्दवासर ने भारत को विभिन्न प्रकार के ऋण 4 मई 1960 को वाशिंगटन में भारत के विदेश मन्त्री एम. के. पाण्डे के साथ स्वयं एक सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए। इस सम्मेलन द्वारा एम. के. पाण्डे का सम्मान करने तथा एम. के. पाण्डे के लिए अमेरिका ने भारत को आयातों पर छूटें तथा गहरे से 1500 करोड़ रुपये भुगतान का निश्चय किया। मई 1960 का यह सम्मेलन सांख्यिक कानून—480 (PL-480) सम्मेलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

पी. एन. 480 का उद्देश्य विकासशील देशों को कृषि वस्तुओं के निर्यात पर लाघान प्रदान करने पर दक्षतर भवितव्य से सहायता प्रदान करना था। निर्यात का अर्थ यह था कि अमेरिका से भारत जो भी वस्तुएं लेगा उसका भुगतान एम. के. पाण्डे के द्वारा किया जायेगा और वह भी कम दाम पर। इस तरह जो वस्तुएं लेगा हुआ वह भारत के निर्यात बैंक में जमा होता रहा। उसका खर्च करने का अधिकार अमेरिकी सरकार का रहा लेकिन भारत सरकार से अनुमति लेकर। इस धारा को पी. एन. 480 धारा कहते हैं। इसी धारा से अमेरिका भारत का अनुदान या कर्ज देता रहा। भारत तथा अमेरिका के बीच पी. एन. 480 कानून के अन्तर्गत जो सम्मेलन हुआ उसका अन्तर्गत भारत के निर्माण में अमेरिकी का निम्नलिखित योगदान रहा है—

कृषि के क्षेत्र में चावल से भारताय विशेषता को अमेरिका में प्रशिक्षण दिया गया। अठरावाँ विकास सम्मेलन अमेरिकी एजेंसी न आधुनिक मध्यप्रदेश महाराष्ट्र मसूर उद्यान रायस्थान पंजाब और उत्तरप्रदेश में कृषि वि विविधता का स्थापना में मन्त्र के माध्यम से आवश्यक महान् उपज देनेवाले खाद्यान्न फसों रासायनिक उर्वरक कृषि यंत्रों के विकास सम्बंधी अनुसंधानकार्य में भी उपयोग किया। भारत में हरित क्रांति के इस कार्यक्रम में खासा योगदान किया था। इनके अगवा वाणिज्य नियंत्रण करन सिचाई और जल विद्युत के उत्पादन के लिए बाह्य नदी घाटी परियोजनाओं के निर्माण में भी सहयोग दिया। विशाखापत्तनम टांम्ब मण्डल गाजा और कान्ता में विशाल रामायणिक उर्वरक संयंत्रों की स्थापना तथा पांच ग्रामीण विद्युत सहकारिता समितियों की स्थापना करने के अगवा उत्तर प्रदेश में ग्रिडिंग नदी पर बांध के निर्माण करने में भी अमेरिका ने सहायता दी। इस कार्यक्रम का सफलता के अंगत उच्च शिक्षा सम्मानों का स्थापना हुई। इनमें दानपुर का इन्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पांच इंजिनियरिंग कॉलेज नौ इंजिनियरिंग शिक्षा संस्थान प्राणिक काल्पनिक हैं। मन्त्रियों राय के सफल नियंत्रण पर भी पी एच 480 निर्माण खासा योगदान दिया। 1950 के दशक में हर वर्ष भारत में इन राय में मरने वाले की संख्या जाहज़ात हुआ करता था किन्तु यह संख्या नहीं के बराबर रहे गयी। इस क्षेत्र में मन्त्रियों उमंग अभियान का सफल बनाने का भी भी पी एच 480 निर्माण के अंतर्गत किया गया। इनके अगवा सांख्यिकीय स्थापना के क्षेत्र में मन्त्रियों पाना का पनि और सफाई संचारा योग्य संयंत्रों अध्ययन और राजस्थान तथा शिवा स्वास्थ्य के बारे में भी अमेरिकी तकनीकी अविकारियों ने अपना योगदान अर्पित किया। जहां तक श्रम जागृता का संबंध है दो मास अधिक मजदूर नेताओं प्रशिक्षण और विशेषता को अमेरिका में उच्च प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा कई अमेरिकी विशेषज्ञों ने भी भारत में काम किया।

भारत-चीन युद्ध और संयुक्त राज्य अमेरिका—अक्टूबर 1962 में भारत-चीन युद्ध होने के पश्चात् भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य का एक नया अध्याय शुरू हुआ। चीन हमले में अपनी रक्षा के लिए भारत ने अमेरिका सरकार में अनुरोध किया कि वह भीमप्रतिभाएं मन्त्रों हैं। इसमें वास्तव में नदी किनारे पतित करने में हम अनुरोध पर अविश्व विचार किया और भारत का सैनिक सहायता भी दी। अमेरिका का भविष्यवाणी काय सना न न के घण्टे के अंतर तक हजार टन युद्ध-सामग्री भारत पहुंचाये था। यह नहर्न के गल्लों में सारा लोभ हम सहायता के लिए अमेरिका का आभारी रहेंगे। यह एक सताप का बात है कि अमेरिका ने भारत के पराजय में नाशायत नाम उठाने का प्रयास नहीं किया। उसने सैनिक सहायता देने के लिए कार्य शुरू नही रखा। विदेश सचिव वीन स्ट्रॉस ने भारत की असह्यता का नाति का प्रत्यक्ष भी था। अमेरिकी राजदूत गवर्नर का का पौड़ी सहायता देकर हम भारत का पश्चिमी देश के सैनिकों में शामिल न। करना चाहते और न हम भारत का तटस्थ नीति का वर्णन के। समझते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति कनेडी कई बार कह चुके हैं कि अमेरिका भारत का तटस्थ नाति का वास्तविक करता है।

लेकिन अमेरिका भारत का वास्तविक सहायता करता रहेंगे यह सत्य था एक सन्निध बात है। अमेरिका में कुछ एक विचार यत्न कि सत्य शिवा पता चला कि अमेरिका सहायता का बराबरदान मिलने में कुछ कठिनाई होना रहेंगे।

कम-कम एक बात स्पष्ट हो गयी । अमेरिका पाकिस्तान के लाभ को दृष्टि से कश्मीर समस्या का हल करवा लेना चाहता है । इसके लिए भारत पर कई तरह के दबाव डाले गये । अमेरिका की प्रेरणा में ही कश्मीर के प्रश्न पर भारत पाकिस्तान वार्तालाप शुरू हुआ था और कलकत्ता के भट्टो-स्वर्ण सिंह वार्तालाप के समय अमरीकी राजदूत प्रोक्टर मल्बय ने जिस नाटकीय ढंग से हस्तक्षेप किया था उसने उस तथ्य की ओर संकेत किया कि भारत के प्रति अमरीकी दृष्टिकोण में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ है । मई 1963 में राष्ट्रपति राष्कार्कणन ने अमेरिका की यात्रा की । पर उसका भी कोई विशेष परिणाम नहीं निकला । अमेरिका ने बोकारो प्लांट बसाने में मदद देने में मन्कार कर दिया । 1963-64 में भारत के प्रति अमरीकी राजनय का एक स्पष्ट प्रतीक हो रहा है—चीनी आक्रमण तथा भारत की आर्थिक स्थिति से उत्पन्न संकट ने लाभ उठाकर भारत को अमरीकी प्रभाव में बाँध कर लेना । और इस निशा में अमेरिका ने कुछ सफलता भी मिली । फिर भी उस बात को भानने से इन्कार नहीं किया जा सकता कि राष्ट्रपति कनेडी के प्याराहण के उपरान्त अमेरिका के साथ भारत के सम्बन्धों में उल्लेखनीय सधार हुआ था और कनेडी प्रशासन द्वारा भारत पर चीन का हमला होने पर जो ज्वलन्त सहायता प्रदान की गयी थी उसने भारतीय जनता का बहुत ही अधिक प्रभावित किया । राष्ट्रपति कनेडी ने भारत की तटस्थता नीति का भी जैसा अमरीकी नेताओं की अपेक्षा भली प्रकार समझा और उसके यथोचित सम्मान किया । कनेडी ने पाकिस्तान और भारत विरोधियों के विरोध एवं प्रचार का परधान न करत हुए भारत-चीन युद्ध के समय और उसके बाद निम्न प्रकार सन्निह सहायता दी वह उनकी महानता और दूरदर्शिता का प्रमाण था । उन्होंने सत्कार का यह महान नेता अत्यन्त आकस्मिक ढंग से हमारे मध्य से उठ गया । उसका मरुतु में भारत ने अपना एक बहुत बड़ा शुभचिन्तक खो दिया । कनेडी के बाद जो निम्न चीन-भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति हुए । जेनसन ने अपने प्रथम भाषण में जो संश्लेषण किया उसमें जापान की गई कि शायद अमेरिका का नया शासन भारत के प्रति कनेडी नीति का ही अनुसरण करे । राष्ट्रपति जेनसन के शासन-काल में भारत का सम्बन्ध बना है । 7 दिसम्बर 1963 को भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच नयी दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने अनुसार अमेरिका भारत को अठ करोड़ डॉलर तारापुर में आणविक शक्ति का सयंत्र स्थापित करने के लिए दान का वादा किया । अमेरिका की सहायता में भारत ने अपनी वायुसेना में भी शक्तिशाली बनाया । 1964 में भारत के विभिन्न भागों में भारत ब्रिग्स आस्ट्रिया अमेरिका के बीच सन्धिको न मी सन्धिको न मी सन्धिको अमेरिका के 1964 में भी भारत में विक्ट साक्षात्त सम्मेलन उपस्थित हुए । दो लाख 480 के अन्तर्गत अमेरिका ने नये मात्रा में भारत में खाद्य पदार्थों की पूर्ति का और कई तरह की आर्थिक सहायताएँ देने का आश्वासन दिया । भारत का इस तरह की सहायता पर्याप्त रूप में अमेरिका में मिली है । पाकिस्तान के विरोध के कारण चीन ने मुलावना करने के लिए अमेरिका ने भारत के हाथों मन्त्रि साजोगमानि और कुछ मन्त्रि मन्त्रित्व दी ।

भारतीय प्रधान मंत्री को प्रस्तावित अमरिका यात्रा—भारत और मध्य-पूर्व अमरिका के सम्बन्धों के इतिहास में 1965 का वर्ष अत्यन्त सन्तान्तरक नहाना माना जा सकता है। अधिक और सान्धाना के अभाव की दृष्टि से भारत के लिए यह वर्ष बड़ा ही अगम सिद्ध हुआ। ऐसी दानत में भारत का अमरिका सहायता का सहक जहरत थी। अतएव अमरीका सहायता प्राप्त करने तथा भारत अमरिका सम्बन्धों में सुधार के लिए भारतपि प्रधान मंत्री राज बहादुर शास्त्री ने मध्य अमरिका जान का कार्यक्रम बनाया और राष्ट्रपति जानसन का जार से उन्हें निमन्त्रण भी प्राप्त ना गया। उसी समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के अमरिका भ्रमण की भी बात थी।

यस समय अमरिका विद्यतनाम में अपना खूनी साम्राज्यवादा बूट बना रहा था और उस उम्माना था कि चान के विरोध में मार्क्सिक सङ्गठन सावर तथा डॉ. के सङ्कट से बाध्य हाकर भारत अमरिका का यिननामा नाति का समर्थन करेगा। तनिन भारत ने याय का सा दत हुए अमरिका की विद्यतनामी नाति की बनी आगचना की। भारत सरकार का यह रुख अमरिका के लिए अमहा था। भारत के प्रति अपना विरोध प्रकट करने के उद्देश्य में 16 अप्रिल को अमरीका राष्ट्रपति ने अपने निमन्त्रण का वापस लत हुए कहा कि अमरानी कार्यक्रम अविश्वामन में अम्य जान के कारण राष्ट्रपति को प्रधान मंत्री का स्वागत करने के लिए समय का अभाव रहेगा। अतएव प्रधान मंत्री राज बहादुर शास्त्री अपनी यात्रा का फिन्हाए के लिए स्थगित कर लें। इस निणय के विरुद्ध भारत में बनी प्रतिक्रियाएं हुए और जनता तथा सरकार दानों ने इस दान का अपमान समया। सम्पूर्ण ना में अमेरिका विरोध भावना का एक तूफान फट पना। बू कि पाकिस्तान और चान का दानता हुआ सम्भव भी अमरिका का पसन्द नहीं था। अतएव राष्ट्रपति अयूब की यात्रा का ना न्हा तरह स्थगित बना लिया गया।

भारत पाकिस्तान युद्ध और अमरिका—5 अगस्त 1965 का पाकिस्तानी मुजाहिदा ने कम्भीर में पुसुधर तब उत्पन्न मचाना गुन किया और अमका तबज जब अमका पईनी ता वहाँ समाचारपत्रा ने पाकिस्तानी राय अनापत ना रहा कि भारत के विरुद्ध कश्मीरनाम ने विनाह कर लिया है। तनिन यह उम्मीद का नाती थी कि अमरीका सरकार का घटना का वास्तविक व्योग मिया नाग तार जिसतब ने अमरिका के अवर उम्मान चीन के साथ पाकिस्तान अपना सम्बन्ध बना रना था उम्मान अतएव एकभार के सम्बन्ध में मयुक्त राय अमरिका की दृष्टि का बन्गा। तनिन यह आमा निगधार सिद्ध ना और अमरिका ने पुन वहाँ रवया अपनाया ता ना मार के प्रशन पर अतक लयका रहा है। यह जानने के अनन्त निम्मा का दिया पाकिस्तान के विरुद्ध है अमरिका मुखों ने महामविब यूसुफ पर दवाद नाग कि व तनिन रिपाए का प्रकाशित नहीं करें। भारत के प्रति मयक्त राय अमरिका के दान असायपूण रव था।

१. मितम्बर का पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पार करके छद्म-जरिया क्षेत्र में भारतीय प्रदेश पर बड़े विनाश पैमाने पर आक्रमण कर दिया। यह पहला अवसर था जब पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध अमेरिका में बने और पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए पटन टंक हवाई बम बपक तथा अन्य अमेरिकी शस्त्रास्त्रों को मदद में माँग लिया। पाकिस्तान की इस कारवाई न अमेरिकी प्रशासन को बड़ी दुःखिता में डाल दिया। जिस समय संयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान में पारस्परिक वरक्षा संधि हुई थी और अमेरिका ने पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने का वादा किया था उस समय भारत ने इस कारण ज़ोरों वहाँ विरोध किया था कि पाकिस्तान को मजबूत हथियारों से माध्यवाद के विरुद्ध लड़ने का भारतीय सुरक्षा पर बुरा प्रतिबल प्रभाव पड़ेगा। पंडित नेहरू ने राष्ट्रपति आइज़नहावर को लिखा था कि पाकिस्तान इन शस्त्रास्त्रों का प्रयोग भारत के विरुद्ध करेगा। उस समय राष्ट्रपति आइज़नहावर ने जवाब दिया कि पाकिस्तान को मित्र अमेरिकी हथियारों का प्रयोग बंद करके कम्युनिस्ट राज्यों के विरुद्ध करने दिया जायगा और यदि पाकिस्तान ने इन हथियारों से भारत पर आक्रमण किया तो संयुक्त राज्य अमेरिका उसका विरोध करेगा और भारत की सहायता करेगा। इस अवसर के आधार पर भारत सरकार ने अमेरिकी सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया कि पाकिस्तान से ठीक तथा मित्रादी मित्रों के अंतर्गत मिले शस्त्रास्त्रों का प्रयोग भारत के विरुद्ध कर रहा है और यह अनुरोध किया कि अमेरिका अपने मित्र राज्य का ऐसा करने से रोके। लेकिन अमेरिकी प्रशासन ने इस तथ्य का ओर जग भी ध्यान न दे दिया और पाकिस्तान की अमेरिकी शस्त्रास्त्रों के दुुरुपयोग से रोकने में अपनी अनमयता प्रकट की। मजबूत राज्य अमेरिका को यह नीति राष्ट्रपति आइज़नहावर के उन आश्वासनों का अंग बन गई। लेकिन उस समय के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को हर तरह की सैनिक सहायता बंद कर दी। लेकिन यह प्रतिवचन भारत के विरुद्ध भी लगाया गया। जयरा ने सरकार ने आक्रमण और अज्ञात दोषों का एक ही कोश में रखने में ऐसा मात्र का सकार नहीं किया। इस अतिरिक्त उमन यह भी धमकी दी कि वह दाना लोगों को अधिक सहायता देना भी बंद कर देगा। यह यद्ध न ले बंद किया गया। इस अवधि में पाकिस्तान का अक्षा भारत की ही अधिक नुकसान होने वाला था क्योंकि उस समय भारत में राज्यों के मभाव के कारण भयंकर-संघर्ष उत्पन्न हुआ था और भारत का अमेरिकी सहायता की सैन्य जल्लरत थी। मितम्बर के महान मयद्ध का समाप्त करने के लिए सहस्रा-परिषद् की चार बैठकें हुईं। जहाँ में सहस्रा परिषद् के अन्य सदस्यों की तरह अमेरिकी प्रतिनिधि भी गये थे। यह भी महान सैनिक युद्ध था कि यद्ध बंद करने प्रयास था समझने किया तथा परिषद् द्वारा पारित प्रस्ताव के पक्ष में अपना मत दिया। लेकिन बहम के दौरान अमेरिकी प्रतिनिधि ने हमला कश्मीर प्रान्त के राजनीति-समाधान पर रखा था। इस दृष्टिकोण से अमेरिका का यह निश्चय ही भारत के लिए ही था। इसी कारण यह था कि संयुक्त राज्य अमेरिका अस्माद के प्रान्त की अभी अंतर्राष्ट्रीय समझौता

मानता है—यह प्रश्न जिसका समाधान भारत की दृष्टि में कश्मीर के गोगा ने कई चुनौतियों में भाग लेकर बहुत पहले कर लिया था।

भारत-पाकिस्तान युद्ध में अमरीकी दृष्टिकोण का एक और पहलू था। 1 सितम्बर को पाकिस्तान ने भारत पर हमला इस विश्वास के साथ किया था कि वह कुछ ही दिनों में भारत को पराजित करने में सफल रहेगा। लेकिन भारत ने जब इसका प्रतिरोध किया और पाकिस्तान ने वह जगहा पर हमला शुरू किया तो पाकिस्तान का पूर्ण विनाश अवश्यम्भावी हो गया। ऐसी हालत में राष्ट्रपति अब्दुल ने एकाधिकार अपने पुराने दोस्ती के नाम पर अमरिका में अपील की कि वह भारत के आक्रमण बंद कराने के सम्बन्ध में कोई कारवाई करे। लेकिन राष्ट्रपति जानसन ने इस बार पाकिस्तान को अनुग्रहित नहीं किया। समयगत राय अमरिका की सरकार ने इस बात का कई बार दुहराया और स्पष्ट शब्दों में कहा कि युद्ध बंद करने के सम्बन्ध में जो भी निणय लिया जायगा वह समयगत राष्ट्र सभ के अंतर्गत होगा और व्यक्तिगत रूप से अमरिका इस सम्बन्ध में कोई कार्य नहीं करेगा। यन्म कोई सन्देह नहीं कि अमरिका के इस दृष्टिकोण ने पाकिस्तान को टूटी छोड़ने और सरला-परिपद के युद्ध विराम प्रस्ताव को मानने के लिए बाध्य कर दिया।

भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान में अपने नये साथी पाकिस्तान पर भारतीय सैनिक दबाव को कम करने के उद्देश्य से 17 सितम्बर का चीन ने भारत का धमकी में भरा एक जस्टिमेटम भजा जिसमें भारत से यह मांग की गयी थी वह तीन दिनों के अन्दर गर कानूनी ढंग में चीनी क्षेत्र में वनाय सैनिक जट्टा को तोड़ दें तथा इसके उपरान्त उसने शीघ्र ही सीमात पर भारत के विरुद्ध सैनिक गतिविधि प्रारम्भ कर दी। चीन की इस कार्यवाही में परिस्थिति बहुत कठिन हो गयी। हम हाज़त में अमरीकी विशेष सचिव ने यह घोषणा की कि यदि चान ने भारत के विरुद्ध कोई सैनिक कारवाई की तो अमरिका भारत को किसी तरह की सहायता देने में जरा भी संकोच नहीं करेगा। यन्म कोई सन्देह नहीं कि नाजुक घडियों में अमेरिका की इस घोषणा में भारतीयों के मनोबल को ऊँचा रखने में बड़ी सहायता मिली। अमरिका की इस घोषणा का भारत में सार्वजनिक स्वागत हुआ।

भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध के सन्दर्भ में समयगत राय अमरिका का दृष्टिकोण हमेशा भारत विरोधी रहा है। भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय अमरिका ने दोनों देशों को शस्त्रास्त्रों की आपूर्ति बंद कर दी थी। लेकिन 1966 में उमन पुन पाकिस्तान को विशाल मात्रा में सैनिक सहायता देना आरम्भ किया। यह तब हुआ जब पाकिस्तान ने चीन के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित कर लिया और चान ने उसको सैनिक सहायता मिलने लगी। इस परिवर्तन के फलस्वरूप भी अमरीका प्रशान्त में पाक समर्थक रूप में कोई परिवर्तन नहीं आया। पाकिस्तान का सैनिक सहायता का पुन प्रारम्भ इस बात का चिन्तक है कि अमरिका भारत की मर्चा की उन्नति परवाह नहीं करता जितनी परवाह उस पाकिस्तान का नाराजगी का है।

प्रधान मंत्री की अमेरिकी यात्रा — अप्रिल 1965 में भारत का प्रधान मंत्री की अमेरिकी यात्रा के स्वयंसेवक स भारत में अमेरिका विरोधी भावना का प्रबल स्फूर्ण फट गया था और इस घटना के कारण दोनों देशों का सम्बन्ध काफी गिर गया था। इस कारण एस के पाटिल और जी डी बिन्स जसे अमेरिका के समयक भारत सीय बहुत चिन्तित थे। जन-जुलाई 1956 में इन दोनों व्यक्तियों ने अमेरिका का भ्रमण किया और यह प्रयास किया कि राष्ट्रपति जॉनसन पुन भारतीय प्रधान मंत्री का आमन्त्रित करें। इस तरह का पाल बुना ही जा रहा था कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध छिड़ गया और भारतीय प्रधान मंत्री द्वारा अमेरिका यात्रा की सी सी सम्भावनाएँ अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई। नवम्बर और दिसम्बर के महीने में भारत अमेरिका सम्बन्ध में दो तथ्य स्पष्ट हुए। युद्ध के कारण अमेरिका ने भारत की हर तरह की सहायता देना बन्द कर दिया था लेकिन भारत में नियम खाद्यान्न संकट की देखते हुए अमेरिका ने फैसला किया कि पी० एस 480 के अन्त में गहूँ की आपूर्ति पुन लागू की जाय। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत का भय मरी स वचन में अमेरिका के इस नियम न बड़ी सहायता की है। दूसरा तथ्य तान का सम्बन्ध से सम्बन्धित है। अमेरिका अभी नहीं चाहता होगा कि संविधान सभ भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करे। लेकिन जब संविधान सभ ने शाश्वत सम्बन्ध का प्रस्ताव रखा और भारत तथा पाकिस्तान दोनों ने इस स्वीकार कर लिया तो कम से कम सावधानी रूप से अमेरिका ने इसका विरोध नहीं किया। अमेरिका के दक्षिण में शाश्वत में समझौता करने में बड़ी सक्षमता मिली। प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु पर श्री हस्क ने अमेरिकी जनता और सरकार की ओर से भारत के प्रति अपार सहानुभूति दर्शायी और यह आश्वासन दिया कि भारत अमेरिका में हर तरह की सहायता की अपेक्षा कर सकता है। कुछ दिनों के उपरान्त इन्दिरा गाँधी भारत की प्रधान मंत्री नियुक्त की गयी। राष्ट्रपति जॉनसन ने उन्हें चर्चार्थ दी और एक पत्र लिखकर यह अनुरोध किया कि वे शीघ्र ही अमेरिका यात्रा का कार्यक्रम बनायें।

28 मार्च 1967 को श्रीमती इन्दिरा गाँधी की अमेरिका यात्रा प्रारम्भ हुई। ऐसी तो श्रीमती गाँधी का पहला अमेरिका की यात्रा कर चुकी थी लेकिन प्रधान मंत्री के रूप में यह उनकी प्रथम यात्रा थी। उस समय भारत भीषण आर्थिक संकट में गुजर रहा था और यह उम्मीद की गयी कि प्रधान मंत्री की यात्रा में प्रचुर मात्रा में आर्थिक सहायता मिल सकती है। लेकिन सब मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इस यात्रा का कोई विपक्ष परिणाम नहीं हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत की आर्थिक बाधाओं को हल करने में उत्तम उत्थान का यत्न करता रहा। भारत पर अपना बाह्य मामलों में वाद लादने का उद्देश्य से उभरने वाला एनडी यू एस एक्वेगन फंडिंग का प्रस्ताव रखा लेकिन सबके दम में इसका इतना व्यापक विरोध हुआ कि सारी योजनाएँ स्थगित कर दी गयीं। भारतीय रुपये के अवमूल्यन के बाद अमेरिका ने पुन उन सारी आर्थिक सहायता की पाल करने का निश्चय किया जो भारत पाक युद्ध के समय बन्द

1970 के प्रारम्भ में भारत और अमेरिका के आपसी सम्बन्धों में दो बातों को लेकर सतर्कता उत्पन्न हुई। भारत सरकार ने हनोई में भारतीय दूतावास के कार्यालय के दर्जा ऊँचा करने का निश्चय किया। संयुक्त राज्य अमेरिका को ये बात पसन्द नहीं आयी। इसके कुछ दिनों बाद भारत सरकार ने यह भी फैसला किया कि दिल्ली छोड़कर भारत के अन्य पाँच नगरों में अमेरिकी सूचना केन्द्रों का काम चलाया जाय। मई 1970 में इन पाँच सूचना केन्द्रों का बंद भी कर दिया गया।

संयुक्त राष्ट्र संघ की पचीसवीं बैठक में भाग लेने के लिए प्रमान में भी हल्ले। गाँधी अकटवर 1970 में भी यूएफ का गया। कुछ कुछ दिन पूर्व अमेरिका ने पाकिस्तान के शास्त्र देने का निश्चय किया था। 1965 में भारत-पाक युद्ध के समय अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान की शास्त्र बेचने पर प्रतिवन्ध लगाया था। भारत के सम्बन्ध में यह प्रतिवन्ध तो लागू रहा जिन पाकिस्तान के प्रति स्पष्ट पक्षपात करता गया। स्वाभाविक रूप से इससे भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में गंभीर पक्ष हो गया। श्रीमता गाँधी ने अपना रोप राष्ट्रपति निम्सन द्वारा आयोजित एक भोजन में शामिल हो कर प्रकट किया।

पाकिस्तान का शास्त्र देने के निमित्त में यूएफ में अमेरिकी विद्वानों का नियमित राजनयिक आगमन गाँधी ने निन्दित। अमेरिकी अधिकारियों ने भारतीय नेताओं का आश्वासन दिया कि अमेरिकी शास्त्रों का उपयोग भारत के विरुद्ध नहीं किया जायगा। मगर भारतीय नेताओं को इस आश्वासन में सन्तुष्ट नहीं हुआ।

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के पारस्परिक सम्बन्धों के इस मजिस्त इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इसमें काँफूस यह नहीं कि इस संघर्ष में अनेक चढ़ाव-उतार आये हैं और सहयोग तथा मतभेद के बीच यह झूटना रहा है। दोनों दलों की मन्त्री के विषय में तरह-तरह की बातें की जा रही हैं। यह कहा गया कि दोनों दलों की मन्त्री का बड़ा टांग आधार है। दोनों की आस्था लाजस्तान में है और यदि समय-समय पर मतभेद उत्पन्न भी हो जाते हैं तो वे स्वाभाविक और स्वस्थ मन्त्री का परिचायक है। जैकन वस्तुस्थिति यह है कि संयुक्त राज्य के महत्वपूर्ण भगवत् पर दोनों के दृष्टिकोण मौलिक रूप से अलग-अलग हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच का सहयोग और मन्त्री है उसका मतलब है कि भारत द्वारा आयोजित महायुद्ध पान को रोकना है। संयुक्त राज्य अमेरिका भी अपने विश्व व्यापार हितों का ध्यान में रखकर भारत की उद्योग नहीं कर सकता। अपना कुछ स्वार्थों को रक्षा के लिए वह भारत को आयोजित महायुद्ध पान पर विवश है। इसमें काँफूस यह नहीं कि व्यक्तिगत जीवन की भाँति अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में भी पराजय का स्थान होता है और मानवता का ध्यान में रखकर भी विदेशों को समूह राष्ट्र अधिक सहयोग देते हैं। लेकिन हम यह भी न भूलना चाहिए कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति एवं व्यापार के सम्मान होती है जिसमें काँफूस तर्क उत्तम दुर्गुनी आमदना को आशा में किया जाता है।

बंगलादेश के मदम में भारत अमेरिका संबंध

अमेरिका भारत विरोधी रवैया—पूर्वो पाकिस्तान में सैनिक तानाशाही के विरुद्ध जन विद्रोह तथा बंगला देश की स्थापना से भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के सम्बंधों में पुनः बंटुता आयी। भारत का पूरी सहानुभूति बंगला देश के स्वातंत्र्य संग्राम के सैनिकों के साथ थी। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिक तानाशाही का अपना समय निया। बंगला देश के नर संहार को रोकने के लिए भारत ने यह प्रयास किया कि भारत का कोई देश पश्चिम पाकिस्तान का किसी तरह की सहायता न दे। लेकिन अमेरिका ने भारत के इस अनुरोध को ध्यान में नहीं लिया और पश्चिम पाकिस्तान का आर्थिक और सैनिक मद देता रहा। जब भारत ने इस पर विरोध किया तो उसे कहा गया कि पूर्व बंगाल की घटनाओं के पक्ष में हम सहायता के लिए अमेरिका पाकिस्तान का वचन दे चुका था। लेकिन बाद में भी अमेरिकी सहायता गवसनी पहुँचती रही। इस स्पष्ट हो गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रामाण्य किता भी काम में पर पाहिया लौ का छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तथा सैनिक तानाशाही का काम रखने के लिए वह किता भी स्तर पर उत्तर सकता है। बात यह थी कि ठीक इसी समय अमेरिका को पाकिस्तानी मजदूरी के संकट उत्पन्न था। चान तथा अमेरिका के मध्य सम्बन्ध स्थापित कराने में पाकिस्तान विचारों का काम कर रहा था और इसी स्थिति में पाकिस्तान का नाखुश करना सम्भव नहीं था। इसलिए बंगला देश के जन विद्रोह को नवान के लिए अमेरिका पश्चिम पाकिस्तान का हर सम्भव मद देता था। भारत का अमेरिकी नाति के विरोध तो प्रतिक्रिया हुआ।

राजनीतिक स्तर पर भी पश्चिम पाकिस्तान को अमेरिका का पूरा मद मिला। संयुक्त राष्ट्रमंडल के महासचिव ने अगस्त 1971 में बंगला देश के शरणार्थियों के प्रत्यावर्तन का सम्भव और सुरक्षित बनाने के लिए सामा के दोनों ओर संयुक्त राष्ट्र संधीय प्रक्षेप नियुक्त किये जाने का सुझाव दिया। भारत ने इस प्रस्ताव का मानने से इंकार कर दिया। भारत का ख्याल था कि यदि सामा के दोनों ओर राष्ट्रमंडल प्रक्षेप नियुक्त कर दिये जाते तो भारत दुनिया का ध्यान बंगला देश में हो रहा पाकिस्तानी अत्याचारों से तिरकर उन पर केंद्रित हो जाता है। दूसरा प्रश्न यह था कि मुठ्ठा भर प्रेक्षक शरणार्थियों का सुरक्षित वापसी के सफेद माध्यम बन सकते थे और वे यह विश्वास दिला सकते थे कि वापसी के बाद बंगला देश में संसन्धन न रहे सकते थे। भारत का यह भी ख्याल था कि महासचिव के इस प्रस्ताव में अमेरिकी राजनयिक काम कर रहा था।

6 अगस्त 1971 को नया दिल्ली से यह घोषणा की गयी कि संविधान मंडल के विभिन्न मंत्री 8 अगस्त को निम्ना धार्योग। एक एक दिन भारत सरकार ने अमेरिका से कहा विरोध प्रकट करके उन स्पष्ट शर्तों में यह बताया कि अमेरिका पाकिस्तान का मद के लिए महान को जा बूझ कर रहा है, वह भारत के प्रति

अमेरिकी प्रशासन का रवैया है। यह बताया गया कि अमेरिका द्वारा सारे आवासनों का उल्लंघन करके पाकिस्तान को लगातार हथियार देना चीन के साथ मिलकर याहिया खान को युद्ध के लिए भड़काना तथा अपने नागरिकों को राष्ट्रसंघ के नाम पर पूर्व बंगाल के प्रक्षक के रूप में भजने से भारत और अमेरिका के सम्बन्ध इस समय इतने बिगड़ गये जिनसे कि पहले सभी नहीं बिगड़ थे। भारतीय विप्लव-नीति के एक प्रवक्ता ने यह भी बताया कि अमेरिका ने पाकिस्तान की पीठ पीछेपाने के लिए भारत में राजनीतिक स्तर पर यह भी कहा कि यदि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई तथा चीन उसमें पाकिस्तान की ओर से लूटा तो अमेरिकी सरकार भारत की सहायता नहीं करेगी। इसे सरकारी दस्तावेजों में अमेरिका का धमकी माना गया। भारतीय अधिकारियों ने साफ-साफ कहा कि अमेरिका ने भारत को अपमानित किया है। वाशिंगटन स्थित भारतीय राजदूत एन के. झा ने कहा कि दक्षिण एशिया में निवसन सरकार जिस नीति पर चल रही है उसमें मेरी सरकार कुछ नहीं है। सारे भारत में आज यह भावना व्याप्त है कि अमेरिका ने हम अपमानित किया है।

इसके तुरन्त ही मार्च 9 अगस्त को भारत और संयुक्त संघ की मंत्री सचि सम्पन्न हुई। इस सचि का घोषणा में अमेरिका में हैरानी और घबड़ाहट का उत्पन्न होना स्वभाविक था। अगस्त 1971 को भारत सोवियत सचि के उपरांत अमेरिका का घट और भी भारत विरामी हो गया।

सबसे ही अमेरिकी प्रशासन किसिगर के प्रभाव के कारण भारत विरोधी नीति का अवलम्बन करता रहा। इस बात का प्रमाण तब मिला जब एक अमेरिकी पत्रकार जैक ऐडरसन ने विदेश विभाग के कुछ गोपनीय दस्तावेजों का रहस्योद्घाटन किया। इसी से पता चला कि अमेरिका ने भारत विरोधी रवैया के प्रति अपना सारी प्रतिक्रिया व्यक्त करत हुए भारत स्थित अमेरिकी राजदूत बेनेथ की कीटिंगन अपनी सरकार को दक्षिण एशिया का वास्तविकता की जानने के लिए दो सार भजे जिनमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का समर्थक राज्य के रूप में स्थापना हो चुका है। इस क्षण में वास्तव में भारत एकलक्ष्य शक्ति है। बंगला देश एक सीमित समस्या है जिसका सम्भवतः जल्दी ही एक स्वाधीन देश के रूप में अध्ययन होगा। अतएव कीटिंगन ने अमेरिकी प्रशासन को सलाह दी कि वह भारत विरोधी नीति छोड़कर तत्काल का समय। लेकिन अमेरिकी प्रशासन पर इन चेतावनियों का कोई असर नहीं पड़ा।

प्रधान मंत्री की अमेरिका यात्रा — भारत-पाकिस्तान सीमा पर तनाव को स्थिति उत्पन्न हो जाने बाद प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने नवम्बर 1971 में कुछ पश्चिमी देशों का भ्रमण किया। प्रधान मंत्री का इरादा पश्चिम के राज नतावा से मिलकर भारतीय दृष्टिकोण से उन्हें परिचित करना था। इसी मिलनगत में वे वाशिंगटन पहुँची और राष्ट्रपति निक्सन से मिलकर उन्हें अपना दृष्टिकोण समझाने का प्रयत्न किया। इस बार निक्सन से वार्ता के दौरान में श्रीमती गांधी ने दो दृष्टिकोणों की। उन्होंने भारत की सत्ता असाहाय और पर निर्भर देश के रूप में पता नहीं किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि भारत अपनी नियति के लिए अकेला खड़ेगा। इस

रुड के विस्फोट पर अमरीकी प्रतिक्रिया—3 नवम्बर को भारत तथा पाकिस्तान के मध्य युद्ध शुरू हो गया। 4 नवम्बर को अमरीकी विदेश विभाग में इस विषय पर एक बड़ा बहस शुरू की जा रही थी जिसमें यद्यपि अमेरिका के लिए भारत को दोषी बताया गया। यह घोषित किया गया कि भारत को हथियारों की खरीद में कुछ हद तक सभी देशों की मदद कर दिया गया है। अमेरिका सोचा अब यह था कि अमेरिका ने भारत को सैनिक सहायता-सामान को आपूर्ति रोकने का निर्णय कर लिया है। यह भी घोषित हो गया कि भारत ने युद्ध बंद नहीं किया था अमेरिकी आधिकारिक मंत्रालय ने यह कहने को वादा भी किया है। उम्मीद है कि अमेरिका ने सुरक्षा परिषद में भारत पर प्रतिबंध रखने की प्रस्ताव की और परिषद को बंकर में प्रस्ताव रखा जा सकता है। हालांकि भारत विरोधी था। हालांकि यह प्रयास के कारण यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। परिषद में भारत विरोधी रविवार के लिए भारत सरकार ने अमेरिका का बहाल करने में निष्ठा की और वाशिंगटन का बहाल करने की कि यह भारत पर किसी प्रकार आधिकारिक या राजनीतिक दबाव डालने का प्रयत्न न करेगा। भारत एक किमी दबाव का स्वीकार नहीं करेगा।

भारत के विदेश मन्त्रिण अमरीकी राजदूत कीर्निंग का मुलाकात अमेरिका के राज विभाग में अपने अपमान पर बड़ा विरोध प्रकट किया और उन्हें स्पष्ट शब्दों में बताया कि वाशिंगटन के रूप में दोनो देशों के सम्बन्ध विग्रह जायते। कीर्निंग का बहाल करने की घोषित कि अमेरिका भारत का हमलावर बनना बन्द कर दे। अमेरिका चाहता है कि भारत सरकार तब तक युद्ध बन्द नहीं करेगी जब तक अमेरिका देश का सारा सारा आना-जाना नहीं बन्द किया जाता। साथ ही वाशिंगटन स्थित भारतीय राजदूत को आदेश दिया गया कि वह भारत का गुस्ता अमेरिका के सामने लाने पर तैयार। अमेरिका द्वारा सुरक्षा परिषद में भारत का विरोध और पाकिस्तान का समर्थन करने तथा भारत का सहायता देने के विरोध में भारतीय जनता में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। 6 नवम्बर को अमेरिका में विभिन्न राजनीतिक दलों की एक सभा में अमरीका रविवार की बहस निष्ठा को रखा। अमेरिका में विचारधारा ने अमरीकी दूतावास के समक्ष एक सभा प्रस्तुत किया और अमेरिका विरोधी नारा लगाये। प्रदर्शन कागज सभा ने नूनावास को एक पापन भी दिया। अमेरिका कहा गया था कि अमरीका साम्राज्यवादिता का आक्रमणकारी पाकिस्तान का सहायता देना प्रजातान्त्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन का एक प्रयास है। आपन में यह भी स्पष्ट किया गया कि वह अमेरिका पाकिस्तान को सैनिक तथा अन्य मदद वित्तही ही मात्रा में करेगा न कि और भारत की सहायता करने का प्रयत्न करेगा। पर हम बता देंगे कि भारत अपने परोपकार पर खड़ा है अमरीकी दबाव पर नहीं।

पाकिस्तान के सैनिक सहायता की रक्षा करने में सुरक्षा परिषद के अमेरिका की जान के उपरान्त अमेरिका जानबूझकर भारत पर सैनिक आरोप लगाते रखा। एक बराबर यह था कि इस्लामाबाद में सके अमरीकी विमान पर भारत ने बमबर्षा की तथा

बगान की खाड़ी में दो अमरीकी जलपातों पर हमला किया। भारत सरकार के एक प्रवक्ता ने इस आरोप को सरासर झूठ बताया।

6 दिसम्बर को अमरीका प्रशासन ने घोषणा की कि 876 करोड़ डॉलर का आर्थिक सहायता के सम्बन्ध में भारत के साथ जो एकरार हुआ था वह रद्द किया जाता है। दो दिन बाद अमरीकी राजदूत कीटिंग ने औपचारिक रूप से भारत सरकार को सूचित कर लिया कि अमरीका भारत के सैनिक सामान दानवन्द कर रहा है। सैनिक सामान के आयात के लिए भारत को अब कोई नये अमरीका से सेंस नहीं लिये जायें तथा वर्तमान लाइसेंस जो बीस लाख डॉलर के मूल्य के थे वे भी रद्द किया जा रहे हैं।

तहाँ तक भारत को अमरीकी आर्थिक सहायता का प्रश्न था भारत का विदेशों से जो सहायता प्राप्त होती थी उसका 38 प्रतिशत योगदान अमरीका का होता था। दूसरे शब्दों में भारत को आर्थिक सहायता देने वाले राष्ट्रों में अमरीका अग्रणी रहा था। इससे उस यह और भी बहम हुआ कि उसकी सहायता के बिना भारत का समुच्चा अस्तित्व लम्बड़ा जायगा। लेकिन युद्ध के पहले ही भारत सरकार ने यह नीति-विषयक निर्णय ले लिया था कि विदेशों से खासकर अमरीका से आर्थिक सहायता नहीं हाँव कर दी जाय। 3 दिसम्बर को अपने प्रस सम्मेलन में श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने स्पष्ट कर दिया कि भारत सरकार अमरीका सहायता के लिए माहूतान नहीं है।

उधर युद्ध में हर मोर्चे पर पाकिस्तान का अच्छी पिटाई हो रही थी। अमरीका ने युद्ध में सुरक्षा परिषद द्वारा हस्तक्षेप करने का एक बार प्रयास किया तथा 6 दिसम्बर का सुरक्षा परिषद की बैठक अमरीका प्रतिनिधि के आप्रह्व पर फिर बुलायी गयी। अमरीका ने पुनः एक भारत विरोधी प्रस्ताव पेश किया और भाग्य पर आरोप लगाया कि पाकिस्तान पर उसका हमला जारी है। सावियत संघ के लोगों प्रयास के कारण यह अमरीका साजिश भी बंद हो गया। सुरक्षा-परिषद में अमरीका हान के बाद अमरीका की माँग पर संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा का अधिवेशन लगाया गया जहाँ एक भारत विरोधी प्रस्ताव पास कराने में अमरीका का सफलता मिल गया। लेकिन भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि वह इस माँग प्रस्ताव का स्वाकार नहीं करेगा। उस पर अमरीका ने पुनः सुरक्षा परिषद की बैठक का माँग का नहीं मन्जूर एक तबसरा भारत विरोधी प्रस्ताव रखा। अमरीका का कहना था कि भाग्य ने साधारण सभा के प्रस्ताव को मानने से इंकार कर दिया है और पाकिस्तान पर उसका हमला जारी है। पूर्वी पाकिस्तान में भारत का सैनिक अभियान बालुचन में उस पर लगाकरना है। यह काम संयुक्त राष्ट्रसंघ के एक सार्वभौम राष्ट्र के अस्तित्व पर आघात है। भारत ने साधारण सभा का अधिवेशन यदुक्त बना प्रस्ताव काटकर राकर विश्वशांति के लिए सतारा पेश कर दिया है। इस हालत में अमरीका ने भारत तथा पाकिस्तान के बीच युद्धबंदी और पीड़ितों का वापसी का प्रस्ताव कि रखा। भारत में अमरीका के यह नवीनतम साजिश के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया हुई। एक भारतीय नेता ने कहा कि अमरीका ने अब अपना असली रूप प्रकट कर दिया है परन्तु उस यह समझना चाहिए कि यह करके भी वह अपने इस घमण्ड में मुकद नहीं हो

सक्ता जिसने द्वारा वह भारत को बमजोर बनाये रखना और इस उपमहादीप में अपने राजनीतिक स्वार्थों की रक्षा करना चाहता है। शांति के सम्बन्ध में अमेरिका बिलना पालण्ड्री था इसका पता इससे तो चल ही गया कि उसने उस पाकिस्तान का रोकने के लिए कुछ नहो किया जो बाला दश की साढ़े सात करोड़ जनता की इच्छा आवाजाओं के साथ खुन की होली खरी पी और जिसने इस दश पर अवस्मात ही आक्रमण बाल दिया था। परन्तु जिन परिस्थितियों में उसकी ओर से परिपत्र में पुनः यद्धबन्ती और फौजा का वापसो का प्रस्ताव रखा गया था उ होने इस पालण्ड्री को बिबुल नगा कर दिया। यह बिबुल उसा तरह था जने कोई एक हाथ में शांति का कपान पकड़ा हुआ हो और दूसरे में तलवार। यदि यह बात न होनी तो वह भारत पर आक्रांता होने और संयुक्त राष्ट्रसंघ के किसी सदस्य राष्ट्र के अस्तित्वका खत्म करने का आराप न लगाता और न ही गुपचुप रूप में इस बात की कोशिश में होता कि पाकिस्तान को किसी प्रकार सैनिक मदद मिल सके। सोवियत संघ न तामरी बार बोने का प्रयाग करके इस बार भी अमरीकी साजिन को बिबल बना दिया।

अमरीकी रवय पर भारतीय प्रतिक्रिया — अमेरिका के निरन्तर भारत विरोधी पैतरेवाजी के कारण भारतीय जनमत का क्षय होना बिस्फुल स्वाभाविक था। भारतीय की मन स्थिति को प्रधान मंत्री ने अपना दो सावजनिक मभाओं में व्यक्त किया। 10 न्गिम्बर का दिने विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच तथा 12 न्गिम्बर को फी ली के नागरिकों की रली में बालते हुए उन्होंने अमेरिका की शांति की बटु धातावना की अपने भाषणों के दौरान बिना अमेरिका का नाम बिये ही प्रधान मंत्री ने कहा कि हम बिभी मदद बाल करने की धमकी न जा रही है। सकिन बाल धमकी हम अपन रास्ते में नहीं हटा सकती है। कुछ देश नहीं दखना चाहते कि भारत राजनयतापूर्वक मोच और निणय करे। पर अपने हम अधिकार में हम बाल हस्त उप बर्दा त नहीं करगे। प्रधानमन्त्री ने कहा कि पाकिस्तान के हस्त और बिनाश की मारी जि मबारी उन न्गों पर है जिहान में बढ बढ हथियार न्गिये हैं। जा लाकनत्र के लिए लम्बा कात करत ये व आज गेरनत्र की रक्षा व प्रश्न पर न सिफ मौन हैं बर न गेरनत्र के अत्र ओ का पत्र न रहे हैं। प्रधान मन्त्री ने चतावना दा कि उन न्शा को भाल जाना चाहिए कि यह काल न्गा का दश किमी व दशय के आगे भुन नायगा।

न्सी समय भारत सरकार न हनोई सरकार के साथ अपने राजनयिक संबंधों का दर्जा बढाकर राजनय स्तर का कर दिया। हनोई में सम्बन्ध बढान की बात बलून असे न बिचाराधीन थी न्तिन अमरीकी प्रशासन की भावनाओं का ब्याल करत हुए भारत न अभा तक न्गिना में कोई कर्म नो उन्वा था। जब अमेरिका की भारत विरोधी नीति अपना गरम सीमा पर पहुँच गयी तो भारत न हनोई सरकार के साथ अपने राजनयिक सम्बन्ध का दर्जा बढान में जरा भी मकोच न्हा न्गिया। आन्तिर अमेरिका की भावनाओं का बबतक रूप न किया जाता।

इस न्गि सुरत ही बाल 16 न्गिम्बर को प्रधानमन्त्री दिनेश गौधा न राष्ट्रपति निश्चयन को गर पत्र न्गिया। भारत अमेरिका सम्बन्ध पर यन् पत्र एक ऐतिहासिक

प्रत्यक्ष माना जाया। उस में कहा गया था कि अमरीकी प्रशासन राष्ट्रपति याह्य
 का हूट कर भारतीय उपमहा भूत का स्थिति का विवाहन कर लिए गया है। 25 मार्च
 के बाद महानों वान गे इस सन्धम म प्रधानमन्त्र स्वयं राष्ट्रपति विम्वन म दिनों।
 अन्ति इन सारा अनिविधियों का काइ परिणाम नहीं निकल। अन्ति न भारत
 राष्ट्रपति का समचन से साफ इन्कार कर दिया। जो हाथ में मैं मन्त्रमहिम
 राष्ट्रपति म पूछ ग कि अब हमना दाप क्या है। राष्ट्रपति निम्न न अब यह का
 काइ जवाब नहीं दिया।

अमरिका का युद्धपोत राजनय — वाता २० के प्रश्न पर परिसन्धान के
 प्रतिनिधि जलनिकार जगी भुटो गरा मुखा परिषद के अन्त भारत दिया हू
 वेनन का प्रयास दिया। उसमें अमरिका के प्रतिनिधि जल बु न मुखा परिषद के
 अन्तर जोर निम्न प्रशासन प्रशासना न ह्या हाइस के मच म म प्रकार गह
 योग प्रदान दिया जा अमरिका राजनिक १९४५ में अमृत का भूतून अमरीका
 विना सचिव जान फास्टर २० के कुचात राजनय का मर दिया न। मरया
 परिषद म अब अमरिका का का मचनता नहीं निर ठा उसन सचिक हाउये के
 घौस २५ भारत को डराना समजाना उ दिया। वाता २० में ज पाकिस्तानी
 फान का पतन उन्मममाना ही २० उव सुभुन राय अमरिका न स्थितान के पन
 टाकि का खाना म स्थित निजाना मचका सतवें बडे (seventh fleet) का
 वाता का खाही की ओर बूच करन का आर दिया। उस निनि में पट्ट
 अमरिकाओं को विन्ति सम्भन्त स्वाहा म टका म रहने के अमृत कि या
 निम्न के लिए अमरिका के एकमात्र परमाणु गति कति निम्न २०
 प्रान का उन्म की खाना में पहुँचना भारत जोर सम्भवत सारियत उभ का
 चरानी देन का एक मच और अमच कम २०।

सतवें बडे के टाकि का ख नी २ प्रमदन की मूचन का नय मह अनुमान
 गया कि राष्ट्रपति निम्न का म अन्त भारत का अगनी नि स घनता का एक
 एना मना निम्न दहूत पन कन का विम्वन वह विना मच घट निम्न का पत
 का मचकार का २०। उस बडे का 15 निम्नर का वाता का गहा में पन वन जो
 नि चटाव मनुता का का वन के समचन का मच का का वाता का नि
 निम्न का उन्म पूव वाता में उव पाकिस्तान के नाकि प्रामों का मनिहों
 का वन म हाइस मचित २० म पकिना पकिस्तान पर वाता का। मनि दनि
 २० म पकिस्तानों का उन्म हा का ठा उस लिए अन्ति का मच म अनु
 मति का पन्ना और भारत न मच का दिया या कि एना कु हा मच मच न
 हा मचक घट जाय २०। पाकिस्तान मनि २० नाकि का निम्न २०
 अनी २० मच का भारत मच नि मच २० में मच २० मच २०। नि
 अन्ति अन्ति करन जो करन वाता में मच २० मच २० निम्न।
 को निम्न के का वन कन ० मच का का निम्न मच २०।

अमरिका के म युद्धपात राजनय (gunboat diplomacy) का क्या कारण हो सकता था। सम्भवतः अमरिका की यह चान थी कि यह बंगला देश के तट पर अपनी नौसेना को ले जावे तथा पाकिस्तानी सना के आसमनपण के फल में उन निकालकर कराँची ल जाय। यह भी सम्भव था कि अमरिका युद्ध विराम में पड़ने पर बंगला देश में किसी रूप में अपना दखल कायम करना चाहता था जिससे युद्ध विराम के बाद पाकिस्तानी सनिका गद्दारा तथा पाँचमा पाकिस्तान में आकर बंगला देश में आर्थिक शोषण करनेवाले को भारतीय सना तथा मुक्तिवाहिनी के पजे में घुसाया जा सके। युद्ध में भारतीय नौसेना को बहुत कामयाबी मिल रही थी। बंगाल की खाड़ी में इटरप्राइज को खड़ा कर देने में भारतीय नौसना की गतिविधि सीमित हो सकती थी। अमरीकी पत्रकार जक एन्सोन ने बाद में जो गुप्त दस्तावेजों का प्रकाशन किया उससे पता चलता है कि सातवें मंडे का बंगाल की खाड़ी में भेजना इसलिए जरूरी था ताकि भारत के जहाजों की नावेजरी हो सके और भारतीय विमानों की सक्रियता पर रोक लगायी जा सके। एन्सोन के अनुसार यह समझ भी भना गया कि भारत सोवियत संघ की यह पता चल गया कि परत आने पर अमरिका अपने बल का प्रयोग भी कर सकता है। सोवियत संघ पर प्रभाव पड़ा करने के लिए यह कदम उठाया गया था ताकि संरक्षा परिषद में उसका खय में युद्ध नरमा आवे।

इटरप्राइज के चान की सूचना जब ही मिली वस ही वाशिंगटन स्थित भारतीय राजदूत लडमीकात झा ने अमरीकी विदेश विभाग में सम्पर्क स्थापित किया और इसके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा। लेकिन अमरीकी प्रशासन ने इस पर कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। इनके उपरांत भारतीय राजदूत ने यह संकेत दे दिया कि भारतीय जनता अमरिका के इस हस्तक्षेप को किसी प्रकार सहन नहीं करेगा। लेकिन यह भी पता चला कि दोपहर में युद्ध के समय अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार तामर पत्र तो मुहैया दिया को चीन का कोई अधिकार नहीं है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार युद्धविराम में पहले जो भी सहाई में हस्ता पर कागा उन युद्ध में हूना माना जायगा और उसके विनाशक सनिक कारवायों का जा सका। भारत का यह विरोध कारणर रहा और इटरप्राइज ने बंगला देश के मामलों में किसी तरह का हस्त पर नहीं किया। इस घटना का एक ही नतीजा हुआ कि अमरिका की तरह बदनाम और अपमानित था। सम्पूर्ण भारत में अमरीकी साम्राज्यवाद के विरोध में एक प्रबल जनभावना दखने को मिला। स्वचालित परमाणु हस्तो से सज्जित सातवें मंडे की बंगाल की खाड़ी में भेजकर अमरीकी शासना ने अपने विरुद्ध भारतीय जनता के मन में जिस घणा विराध तथा आशय का जमाया तथा जनता ने जिस प्रकार सज्ज उनका अभिधक्ति की महत्त्व का बोझ वहाँ के निवास की एक अधूनन्य घटना के विरोधी बनने के लिए बल का अनुभव करने का कारण हो सकता है कि लगभग समस्त वर्गों के लोग ने अपना विराध जल्द प्रदर्शनों द्वारा पत्रा और प्रस्तावों का माध्यम से व्यक्त किया। एक मजदूर और चरारा में सज्ज पत्राधनारी तक ने अमरीकी शासना का विराध किया। मजदूरराया ने अमरीकी

साम्राज्यवाद के विरोध में प्रयत्न किए। विचारियों ने जुगुप्स निकाले। सरकारी कर्मचारियों ने अमराको काउन्सिल के समक्ष विरोध प्रदर्शन किये। सभी राजनीतिक दल ने प्रयत्न किये तथा प्रस्ताव पारित किये। संसद के दोनों सदनों ने अमराको नीतियों का तीव्र आलोचना की। देश के मुसलमानों ने अमराको सूचना कार्यालय के सामने प्रदर्शन किये। फ़िल्म जगत के कलाकारों तथा कर्मचारियों ने अमराको दूतावास के सामने अमराको साम्राज्यवाद के विरोध में नारे गायें। गैरकों और बुद्धिवादियों ने अमराको नीतियों के विरोध में लिख लिखे। अखबारों के पाठकों ने अमराको साम्राज्यवाद के विरोध में सम्पादकों के नाम पत्र लिखे। सारा देश अमराको साम्राज्यवाद विरोधी भावना से भर गया। भारत में अमरिका के लिए यह सबसे बड़ा पतन था। अमराको समाचार-पत्रों में अमराको पर यही छवि रही कि भारत का माध्यम बनाकर सावियत संघ एशिया में कम्युनिस्टिक सुपरपावर प्राप्त करता जा रहा है। भारत सविनय संघ का माध्यम बना या नहीं इस पर मतभेद हो सकता है लेकिन अमरिका के जसविष इराफा का भयावह हो गया। इसका मानने से इन्कार नहीं किया जा सकता।

यूरोपरान्त भारत अमरिका सम्बंध

भारत अकिम्पान-युद्ध के पहले बार बार अमरिका के विरोध रूप के कारण भारत तथा अमरिका का सम्बंध एकत्रित हो गया। सम्भवतः अमरिका का सुधारन सम्बंध का सुधारन के लिए कुछ प्रयास करने से प्रेरित सम्बंध। 8 फ़रवरी 1972 को अमराको कायेने के लिये एक वैश्व विज्ञान-नीति सम्मेलन में निम्नलिखित भारत में सम्बंध सुधारन का उद्देश्य उक्त की। उन्होंने कहा अमरिका भारत में अविश्व जगत् राजनीतिक मामलों पर बातचीत करने का उद्देश्य है, परन्तु उसका दिव्यता उक्त बात में है कि एशिया एशिया का गतिशील देश अपने पक्ष लिया के प्रति कक्षा के अवनता है। अकिम्पान के सरकार द्वारा निम्नलिखित के अवनता का जमनापूरा बताया गया। भारत सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि निम्नलिखित अवनता अमराको का दुश्मन दुनिया का यह बनाना चाहते हैं कि भारत एक अकिम्पान देश बनकर एशिया का बनाना चाहता है। उक्त अनुसार निम्नलिखित भारत में बातचीत करने के लिए जलें रख रहे हैं और एशिया के अमरिका के रूप में जिन्हें का स्वाभिमानता का स्वाकार नहीं कर सकता। भारत का कहना है कि निम्नलिखित भारत सावियत सविनय संघ में भारत का अवनता है। यह कि भारत में सभी सम्बंध सुधारन का उद्देश्य भारत सभी की ताकत का उद्देश्य एक जन सम्बंध का उद्देश्य करने का उद्देश्य है। मतभेद यह कि सावियत संघ में विनय नग्न का सम्बंध भारत नहीं रखे। सारा निम्नलिखित के अवनता का भारत पर टाक डाला जा रहा है। सम्बंध सुधारन के उद्देश्य लिख गया। सम्भव है कि ऐसा वक्तव्य अमरिका निम्नलिखित अमराको का उद्देश्य का यह सम्बंध का उद्देश्य कि उन्होंने भारत के बारे में जो खबरें अवनता या यह सही था।

बात यहां तक सीमित नहीं रही। 21 फरवरी 1972 को अमेरिका ने यह घोषणा की कि पाकिस्तान को आर्थिक और सैनिक सहायता फिर से शुरू किया जा रहा है। आर्थिक सहायता पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी। किंतु उप महाद्वीप में तनाव बने रहने की स्थिति में यदि पाकिस्तान को फौजी सहायता आरम्भ की जाती है तो इसका एक ही अर्थ हो सकता था। वाशिंगटन के शासक नहीं चाहते थे कि एशिया के इस भाग में शांति बनी रहे। वे उस आग की जिसकी चिनगारी भली भाँति बुझी नहीं थी फिर भटकाना चाहते थे। पाकिस्तान का फिर हथियार देने का विचार बरके अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया कि वह भारत के साथ सम्बंध सुधारने में ईमानदारी से काम नही लेना चाहता है।

इसके तुरन्त ही बाद राष्ट्रपति निक्सन की पवित्र यात्रा हुई। यात्रा की समाप्ति पर जो संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गयी उसमें पाकिस्तान व प्रति भारतीय स्वयं तथा बंगला देश में भारतीय सेना की उपस्थिति की चर्चा की गयी। भारत ने इसपर कभी विरोध व्यक्त किया। इन बातों को देखकर यह कहा जा सकता है कि निकट भविष्य में भारत और अमेरिका के सम्बंधों में सुधार की सम्भावना बहुत कम हो गयी।

बंगलादेश की आजादी और युद्ध में भारत की विजय के साथ ही भारत और अमेरिका के सम्बंधों में गिरावट का दूसरा दौर प्रारम्भ हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका ने अभी तक युद्ध में पाकिस्तान की पराजय को स्वीकार नहीं किया और इसके लिए वह भारत की सहायता करने को तैयार नहीं। लेकिन भारत के साथ अमेरिका के बिगड़े हुए सम्बंधों की निरपेक्षता को अमेरिकी समाचारपत्रों और अमेरिकी जनमत ने स्वयं पहचाना और अमेरिकी प्रशासन से यह आग्रह किया कि उसे भारत के साथ अपने सम्बंध सुधारने के लिए सीधे से सीधे तथा ठोस कदम उठाने चाहिए क्योंकि दोनों के बीच विवृत सम्बंधों का कोई तत्कालीन आधार नहीं हो सकता। अनेक समाचारपत्रों ने भारत के साथ अमेरिका के सम्बंधों में विकार के लिए स्वयं राष्ट्रपति निक्सन की विदेश नीति को जिम्मेवार ठहराया। भारत और अमेरिका के सम्बंधों में सुधार पर टिप्पणी करते हुए 4 अक्टूबर 1972 को अमेरिका के प्रमुख समाचार-पत्र 'न्यू यॉर्क टाइम्स' ने लिखा 'दुख की बात है कि भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ही नहीं बल्कि उसके बाद भी भारत और अमेरिका के सम्बंधों में गिरावट होती गयी। गलतफहमी दोनों ओर से थी। लेकिन सबसे अधिक जिम्मेवारी उन लोगों पर थी जिन्होंने पूर्वी बंगाल के शासन के दिनों में पाकिस्तान के पक्ष में पसंदा मुकामे का निष्पत्ति किया। बाद में अमेरिका ने बंगलादेश को मान्यता दी और नये राष्ट्र को पर्याप्त अमेरिकी सहायता दी गयी। इनके भारत की अप्रसन्नता कुछ कम हुई। विद्यमान युद्ध की समाप्ति से एशिया में अमेरिकी नीति के प्रति भारतीय दृष्टिकोण में कम आलोचनात्मक स्थान जायेगा। अमेरिका के लिए यह आवश्यक है कि वह भारतीय उपमहाद्वीप के सर्वोच्च शासिकात्मी राष्ट्र के साथ मनीषण और स्थायी सम्बंध करे। भारत और अमेरिका के सम्बंधों में जो गिरावट हुई उसका पापना दिसम्बर 1971

में भारत का समर्थन करत हुए सोवियत मध्य न उठाया। ठीक मनुष्यन कायम करन का एक महत्वपूर्ण अवसर आया है।

इस समय भारत के विदेशमन्त्री सरदार स्वर्ण सिंह ने अमेरिका का यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने अमेरिका राज्य सचिव विलियम राजस में एक लम्बा बातचीत की। राजस और स्वर्ण सिंह की बातचीत सम्बन्ध-संधार का विश्वास में पहला कदम था। इसी समय एक अमेरिकी पत्र पार्सल कायम में गान्धी इन्स्टीट्यूट गांधी का एक लख प्रकाशित हुआ। इस पत्र में आन्ताप प्रान्तमन्त्री ने दोना देशों के सम्बन्धों के बारे में भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट किया था। ज्ञान मन्त्र में श्रीमता गान्धी ने यह बात स्पष्ट कर दायी कि विश्व-शांति में सम्बन्धित कुछ प्रश्नों पर मतभेद है, लेकिन दोनों देशों के बुनियादी सिद्धान्तों का आधार करत एक सम्बन्धों में सुधार किया जा सकता है।

इस बीच दिसम्बर 1972 में वाशिंगटन में यह घोषणा हुई कि शांति निवृत्तन न दैनिक पत्रिक मोडनिहून का भारत में अमेरिका राज्य निवृत्त किया है। इस निवृत्त से यह आशा बधा कि भारत और अमेरिका के सम्बन्धों में कुछ सुधार अवश्य होगा। इसके कुछ ही दिनों बाद नया दिल्ली में एक एग्रीमेंट एसेम्बली (5 जनवरी 1972) में भाषा करत हुए आयोजी गया न विद्युतम में अमेरिकी वमदारा का कटु आलोचना का। अमेरिकी विदेश विभाग ने आम्ना गान्धी के वक्तव्य पर गहरा रोष व्यक्त किया और विदेश विभाग का आर म यह कहा गया कि भारत में अमेरिका के नये राजदूत आ मोर्गन्टौन का विश्वास प्रस्थापित किया जाता है।

पाकिस्तान का पुनः गन्ध आपूर्ति का निषेध — 11 मार्च 1973 को अमेरिका के सहायक विदेश मन्त्री आ मिक्को ने विदेश मामला मन्त्रि के सम्मुख बयान दत हुए कहा कि पाकिस्तान की आजादी के सिद्धांतों को का मुकाबला करन के लिए सुरक्षा समता बगल के लिए अमेरिकी प्रान्तन पुनः अमेरिकी हथियारों का आपूर्ति पर सम्भारतापूर्वक विचार कर रहा है। इन वक्तव्य के निकलत ही भारत में इसका तीव्र प्रतिक्रिया हुआ। भारतीय विदेश मन्त्री स्वर्ण सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को पुनः हथियारों की आपूर्ति — न — अमेरिकी शांति से भारतीय सम्मन्धान की शान्ति खतरे में पड़ जायगा और स्थायी शांति स्थापित करन की सम्भावनाओं पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। अन्तर्-विदेश सम्मन्धों का नविष्य भा प्रभावित हो सकता है। अन्तर्-विदेश अमेरिकी राज्य का स्पष्ट प्रान्तों में कहा गया कि अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को हथियार दन में भारत की सुरक्षा के लिए भारी खतरा पड़ा हो गया है और अमेरिका का इस कारवा को भारत विरोधी कार्य माना जायगा। भारतीय विदेश मन्त्री ने यह भी कहा कि पाकिस्तान का अस्त्र आपूर्ति का निषेध भारत अमेरिका के सम्बन्धों का सामान्य एवं मित्रतापूर्ण बन्धन के माध्यम में निश्चित रूप से वास्तविक बन्धी। अन्तर्-अमेरिकी राजदूत ने भारत सरकार का यह आश्वासन दिया कि अमेरिकी अस्त्र हथियारों के मामले में पाकिस्तान के साथ पुराने सम्बन्धों का ही पुरा कर रहा है और अब

अमरिका की सरकार ने यह फमला दिया है कि भविष्य में इस उपमहादीप में किसी भी देश को घातक हथियार नहीं दिया जायगा फिर भी भारतीय सौकमल्य इसमें संतुष्ट नहीं हुआ। 15 मार्च को वाणिज्यन सं यह घोषित किया गया कि अमरिका ने लगभग 63 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता भारत को देने का निश्चय किया है। यह सहायता 1 सितम्बर 1971 में भारत-पाक युद्ध के समय रोक दी गयी थी। इस घोषणा से भी अमरिका विरोधी भावना में कमी नहीं आयी। इस निमित्त से यह भी स्पष्ट हो गया कि अमरिका भारत के साथ अपने सम्बन्धों की सुधारने के लिए जरा भी चिन्तित नहीं है।

इसके बाद ही मई 1973 में ईरान को एक विशाल दस्त्रागार बनाने की अमरिकी योजना सामने आयी। अमरिका ने घोषणा की कि वह ईरान को तीन सौ विमान और आठ सौ टैंक देगा और भारी मरुया में अमरिकी प्रशिक्षकों को ईरान भेजा जायगा। इसी समय ईरान के साथ अपने सम्बन्धों को और अधिक गहरा करने के लिए पाकिस्तान सेट्ट प्रयास कर रहा था। पाकिस्तानी नेता लगातार ईरान की यात्रा कर रहे थे और भारत के विरुद्ध ईरान ने सुले तब में पाकिस्तान का समर्थन करना शुरू कर दिया था। यह स्पष्ट हो गया कि आगामी भारत-पाकिस्तान संघर्ष के अवसर पर आब पड़ता पड़ने पर ईरान पाकिस्तान के मकरान तट की रक्षा का भार उठा सकता है। पाकिस्तानी विमानों को अना हवाई अड्डों में पारण दे सकता है और चरखे में अमरीकी साथ सामान पाकिस्तान को हस्तान्तरित कर सकता है। इस पृष्ठभूमि में बड़े पैमाने पर ईरान को सशस्त्र आपूर्ति के अमरिकी निषेध का भारत-अमरिका सम्बन्धों पर प्रभाव पड़ना अवश्यभावी था।

चिल की राजपलटी और भारत-अमरिका सम्बन्ध—11 सितम्बर 1973 को दक्षिण अमरिका के गणराज्य चिल में फागिस्ट सैनिक अपमरो ने एक सूना राजपलटी करके प्रत्यक्ष तौर पर निर्वाचित चिल के प्रथम मावसदा के राष्ट्रपति साबादार आर्बेदे को निमग्न हत्या कर दी। हत्या की घटना में अमरीकी सौ आर्बेदे का हाथ बताया गया। भारत के लिए यह घटना बड़ी ही दुःखद थी। भारत की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अमरिका का नाम निमग्न हत्या के लिए परीण रूप से अमरिकी प्रशासन का जिम्मेदार बताया। इस कारण भी भारत और अमरिका का सम्बन्ध बिगड़ा। अमरिकी सरकार ने भी भारतीय प्रतिक्रिया पर आपत्ति की।

यौ एल 480 पर समझौता—1973 में भारत और अमरिका के सम्बन्धों के सुधार की दिशा में भी कुछ कामयाबी मिली। जुलाई 1973 में अमरिकी सरकार ने भारत स्थित अमरिकी सहायता मिशन की इमारत भारत को सौंप दी। मिशन को यहाँ से भारत पर सोवियत संघ का प्रभाव बहुत बढ़ रहा था। 1973 के बाद सोवियत समझौता के बाद भारत सोवियत संघ के बहुत निकट आ गया था। 1 सितम्बर 1973 में सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के सचिवरी ने अनेक नमोना की यात्रा की और दोनों देशों के बीच कई समझौते पर हस्ताक्षर हुए। भारत पर सोवियत संघ के इस बढ़ते हुए प्रभाव को सीमित करने के लिए अमरिकी सरकार

ने कुछ बन्धन उठाने का निश्चय किया और पी एन 480 पर एक समझौता करने को तैयार हो गया। सितम्बर 1973 से ही इस समझौते के लिए दोनों पक्षों में बातचीत होनी शुरू हुई और 13 दिसम्बर 1973 को इस सम्बन्ध में एक समझौता हो गया। पी एन 480 तथा कुछ अन्य स्पष्ट शर्तों का मन्त्र में भारत का चौबीस अरब सन्तानों के बराबर रूप से अमेरिका का दना था। समझौते के अनुसार अमेरिका ने सालाना अरब अठसठ करोड़ रुपये का ऋण भारत को देने का निश्चय किया। शेष बाँट अरब सैंतास करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण भारत को देना था। इसमें से अमेरिका पचास करोड़ रुपये दस वर्ष के भीतर टावर में बदल सकता था। लेकिन जसा कि अमेरिकी राजदूत ने बताया इस रूप में अमेरिका ऐसा भारतीय मान माना जाएगा सराफ़ा तो सामान्यतः अमेरिका भारत से नहीं उठा रहा है। इसके अलावा कुछ राशि नफ़ान का सहायता के लिए निधारित कर दी गयी। समझौते के अनुसार पी० एन 480 का निधि भारत का ह्रा गयी और इसके बाद भारत पर किसी तरह का दबाव नहीं रहेगा। समझौते के महत्त्व पर बोलते हुए अमेरिकी राजदूत ने कहा कि यह भावात्मककारी सम्बन्धों और बातचीतों की शुरुआत का रास्ता खोल देगा।

नियोगा गाँसिया के सम्बन्ध में मतभेद—अमेरिका द्वारा निम्न महासागर में स्थित ब्रिटिश अधिकृत टापू नियोगा गाँसिया में अमेरिका सैनिक अट्टा कायम करने के निश्चय से भी 1974 में भारत अमेरिका सम्बन्ध में तनाव आया। कनाडा के माध्यम से बारह सौ मोनू दूर स्थित इस छोटे से टापू में अमेरिका और ब्रिटेन ने अपनी वायु सेना और नौ सेना का एक अलग बन्दरगाह बनाने का फैसला किया जिसमें तीन करोड़ डॉलर खर्च करने का अनुमान किया गया। अमेरिका का कहना था कि अलग कायम करने के फलस्वरूप पीछे बाइ आश्रमक उद्देश्य नहीं था। उसने दावा किया कि हिंद महासागर में सावियत नौ सेना की बढ़ती शक्ति विधियों से व्याप्तित होकर और सतुनन कायम रहने के लिए उसने इस क्षेत्र में नौ सेना का विस्तार करने की योजना बनायी है। लेकिन भारत और एशिया के कई देशों ने एक स्वर से इस योजना का विरोध किया। यामती अंदर गंधा ने इस अलग अमेरिकी दाना का भरोसा का और प्रति के लिए इस खतरनाक बताया। उन्होंने कहा कि इस एशिया में अशांति दयेगी। दिवागा गाँसिया के विवाद का तब तक जब अमेरिका राजदूत मोनिहू ने कहा कि यह ता सभा का बात है कि भारत तथा नियोगा गाँसिया के आनवास का समुद्र हि महासागर के नाम से जाना जाता है इस उल्लेख से अमेरिका के माध्यम से कहा जायता को हज़ नहीं तब भारत में इसके विरुद्ध तात्र प्रतिक्रिया हुई। नियोगा गाँसिया में नौसैनिक अट्टा कायम करने के अमेरिकी निश्चय का भारत निरन्तर विरोध करता रहा और इस कारण दोनों पक्षों के सम्बन्ध में बढ़ता अयो।

इस प्रकार 1971 से भारत अमेरिका संबंध में जो गिरावट आया उसमें अब तक का मुधार नहीं हुआ है और दोनों पक्ष एक दूसरे से दूर दूर खिंच जा रहे हैं।

भारत और सोवियत संघ

(India and U S S R)

ऐतिहासिक पृष्ठाधार —स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व भारत और सोवियत संघ का सम्पर्क मुख्यतः जवाहरलाल नेहरू के जरिये हुआ। 1917 की बोरेविक क्रांति ने एंग्लो-सोवियत मित्रता के विनियमों के रूप में प्रभावित किया। भारत की राजनीति पर भी निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ा। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता मुख्यतः बोरेविक क्रांति को नकार की निगाह से देखा करते थे। वहीं पर घटनाओं की सामक-पट्टाओं से महात्मा गांधी विनियमों के रूप में धारण थे। सोवियत क्रांति से उनकी विचारधारा की सीमा थी कि 1924 में लेनिन की मृत्यु पर जब कांग्रेस समिति में एक शोक प्रस्ताव आया तो वह स्वीकार नहीं किया जा सका।

सोवियत संघ के प्रति भारतीय नेताओं का दृष्टिकोण में परिवर्तन 1927 के बाद आया। पदस्थित राष्ट्रीय कांग्रेस के 21वें सम्मेलन (1927) में भाग लेने के उपरान्त जवाहरलाल नेहरू तीन चार दिनों की यात्रा पर सोवियत संघ गये और वहाँ की व्यवस्था से अत्यधिक प्रभावित हुए।¹ स्वतंत्रता के बाद आने पर उन्होंने सोवियत संघ की सफलताओं पर कुछ लेख लिखे और भाषण दिये। उन्होंने कहा कि सोवियत संघ में जो महान प्रयोग हो रहा है उसका भारत के लिए बड़ा महत्व है। नेहरू की धारणा थी कि सोवियत संघ और भारत अन्तर्गत पड़ोसी के नाते काफी अच्छा सम्बन्ध बनायम रख सकते हैं। भारत सरकार शुरू से ही सोवियत संघ का विरोध कर रही थी। नेहरू का कहनाय कि यह विरोध ब्रिटेन और सोवियत संघ के विरोध का भाग है और भारत को इससे कोई मतनवा नहीं है। भारत और सोवियत संघ के बीच सम्बन्ध का कोई कारण नहीं हो सकता है। नेहरू का विचार था कि सोवियत संघ में एक नयी सभ्यता और संस्कृति का जन्म हो रहा है और निराशा के युग में यह आशा की एकमात्र किरण है। सोवियत संघ को ध्यान में रखकर ही हम भविष्य पर आशा कर सकते हैं।² सोवियत संघ की विदेश-नीति से नेहरू बहुत प्रभावित थे और इसकी नीति की नीति कहा करते थे। उनके ध्यान में सोवियत संघ

1 Jawaharlal Nehru *Soviet Russia Some Random Sketches*

Iman Impressions p 34

2 That great and fascinating unfolding of a new order and a new civilization is the most promising feature of our dismal age. If the future is full of hope it is largely because of Soviet Russia and that it has done. If some world catastrophe do not intervene this new civilization would spread to other lands and put an end to the wars and conflicts which capitalism fed. —*Report of the Forty-Ninth Session of the Indian National Congress* p 70

ही यूरोप का एक देश था जो प्रजातंत्र और राष्ट्रियता के सिद्धांतों को पूरा समर्थन देता था और फासिस्टवाद के विरुद्ध एक मात्र सहारा था।

1939-40 में सोवियत नाति के कारण नरुह को खबरदार मन्त्रालय और सावियत संघ के प्रति उनका उत्साह कुछ कम पड़ गया। 1939 के सोवियत क्रमन पकट में उनको बड़ी निराशा हुई। स्टालिन और स्टालिन के बीच इस समय की ओर उल्टे शुद्ध अवसरवादिता कहा और हमका बनी क्या आलोचना का।¹ फिर जब मिनबर 1939 में सावियत संघ ने पूर्वी पोलैंड पर तथा दिसम्बर में फिनलैंड पर आक्रमण कर उन पर आधिपत्य कायम किया तो नरुह का और बड़ा धक्का लगा। बाद में उन्होंने स्वीकृत किया कि सावियत प्रति रक्षा के लिए यह कारवां आवश्यक था और इसलिए उस मन्त्रालय का नाम दे दिया।

सोवियत संघ के प्रति काफ़ी समय तक नतीजों और विशेषकर जवाहरलाल के अनुमान का प्रधान कारण यह था कि सोवियत संघ निरंतर भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन का समर्थन करते रहे थे। उनकी पूरा महानुभाविता भारतीयों के पक्ष में थी। यद्यपि 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन के अंतराष्ट्रीय परिस्थिति के कारण सोवियत संघ अपना समर्थन नहीं दे सका लेकिन यह निश्चय था कि युद्ध समाप्त होत ही भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन को पूरा समर्थन प्रदान समर्थन मिलेगा। 1945 के सन फ्रामिस्को सम्मेलन में जब अपने का जनतंत्र का प्रहरा बहने का अमराकी प्रतिनिधि मौन धारण किया गया उस समय भारतीय तथा अन्य पराधीन जातियों का स्वतंत्रता का प्रश्न उठाने वाला सावियत प्रतिनिधि मानाताव ही था। सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमरीका के दक्षिण में यह अंतर जो सामने आया उसका नरुह या एंगिया का कोई राष्ट्रवादी संघ नहीं भूल सकता था। यह स्पष्ट हो गया कि एक उपनिवेशवाद को महाराज ने बाग्य अर दूसरा उपनिवेशवाद का विरोधी है। सोवियत संघ तथा संयुक्त राज्य अमरीका के प्रति स्वतंत्र भारत का नाति के सम्बंध में हमें इस बात को बराबर ध्यान में रखना चाहिए।²

इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के पक्ष ही सावियत संघ के प्रति जवाहरलाल की एक विशेष धारणा बन गया थी। भारत-सावियत सम्बंध पर इस तथ्य का विशेष प्रभाव पड़ा है।

स्टालिन युग में भारत सोवियत सम्बंध — स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सोवियत संघ के साथ भा भारत के सम्बंध में नहीं रहे उसने अनेक चर्चा-उत्तराव देखे। 1946-47 में उपनिवेशवाद प्रणाली विभिन्न निरन्तरकरण आदि

1 Jawaharlal Nehru *An Autobiography* p 601

2 How it affected Nehru is revealed by his comments Nehru drew a sharp contrast between the U S and Soviet attitudes on this subject (colonialism) and clearly stated that India would remember this when formulating her own policy towards the two countries —B Praad *The Origins of Indian Foreign Policy* P 241

अनेक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर भारत और सोवियत संघ का एक-सा दृष्टिकोण रहा और इन प्रश्नों पर भारत ने अमेरिका के विरुद्ध सोवियत संघ का ही समर्थन किया। परन्तु यह स्थिति बहुत दिनों तक नहीं रही और कुछ ही समय बाद कुछ प्रश्नों के लेकर दोनों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया। यूनान और क़ारिया के प्रश्नों पर भारत ने पश्चिमी गुट का समर्थन किया। फिर पश्चिमी गुट से आधिक्य सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत साम्यवाद विरोधी रूप भी अपनाया। अप्रिल 1949 में नेहरू ने क़ानून विधायिका का विस्तारवादो स्वरूप एंगियोर्दे देगो की शांति और स्वाधीनता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। फिर सोवियत समाचार पत्रों ने यह आरोप लगाया कि भारत सरकार ब्रिटिश और अमेरिकी साम्राज्यवाद से सँतुष्ट रह रही है। जून 1949 में मागल जुकोव ने कहा कि नेहरू सरकार का जनविरोधी स्वरूप उनकी नीतियों में झलकती स्पष्ट है।

वास्तुतः बात यह थी कि प्रारम्भिक दिनों में जिन तरह भारत की जनसमता की नीति को समर्थन दिया अमेरिका ने उस दिनों किया उसी तरह सोवियत संघ ने भी इस नीति को पकड़ा था कि टिफिन में देखा। रूस ने पश्चिम के साम्यवादन के कारण उस समय तटस्थ देशों की प्रति विरोध की नीति का अनुसरण किया क्योंकि जो सोवियत संघ के करीब समर्थक नहीं थे उन्हें सहज आना पड़ता समझता था। स्टालिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़े नीति का अवलम्बन करने वाला था। उसने भारतीय असतन्त्रता की नीति को निबल और अवसरवादी नीति का प्रतिरूप तथा टैंगो-अमेरिकन साम्राज्यवादियों के साथ सहयोग को छुड़ाने का आवरण मात्र समझा। तत्कालीन नीति का कारण स्टालिन भारत को अन्तःविरोधी समझता था। 1952 में बिगिस्को ने कृष्ण मनन से कहा था कि अन्तःस्वरूप में तुम (भारतीय) आन्तरिक हो तुमने मे-बुरे रूप में तुम अपनी स्थिति नहीं जानती और भयंकर अमेरिकी नीति का प्रकटन समर्थक हो। इसी कारण उस समय सोवियत विचारों में भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलन तथा महात्मा गांधी की पूजा आदि का समर्थन बतौरा गया था।

सन् 1949 के अन्त में भारत और सोवियत संघ के सम्बन्धों में कुछ गुंथार हुआ। इसके दो कारण थे। प्रथमतः नेहरू ने असतन्त्रता का रचनात्मक और सशिव नीति का निष्पन्न रूप में बड़ा हो जालनापूर में संचालन किया। ब्रिटन और अमेरिका के साथ अपने मंत्री सम्बन्धों का निर्वाह करते हुए भी उन्होंने अपनी स्वतन्त्र विदेश-नीति का परिष्कार नहीं किया और सोवियत संघ के साथ अपने सम्बन्धों को गुंथारने की जिज्ञासा में अग्रसर होते रहे। हमने भारत के सम्बन्ध में कई भ्रान्तियाँ दूर हुईं। इस बात में भारत ने चीन की नयी सरकार (माओ सरकार) का मान्यता दिवाने का प्रयत्न किया और इस विषय में पत्राचार देना की नाराजगी की परवाह नहीं की। इस काल में ही राष्ट्राङ्गण मास्को में भारत के राजदूत नियुक्त हुए और उनके संप्रयासों से दोनों देशों के मत्रीपूर्ण सम्बन्धों का विकास होने लगा। फलस्वरूप भारत और सोवियत संघ ने आधिक्य सहयोग का

प्रारम्भ किया। 1949 में ही दोनों के बीच एक व्यापारिक समझौता हुआ जिसके अनुसार सोवियत संघ ने चाय और कच्चे तेल के बजाए एक लाख बीस हजार टन गेहूँ और मक्का दाना स्वीकार किया। 1949-50 में दोनों देशों के पारस्परिक सम्बन्ध और भी अधिक बढ़ गए।

कारिया युद्ध शुरू होने पर भारत और सोवियत संघ का सम्बन्ध पुनः कुछ खराब हो जाता। शुरू में भारत सरकार ने अमरिका युद्ध का समर्थन किया और कारिया के युद्ध में उनसे कारिया का आश्रय माना। भारत के इस कदम से सोवियत संघ में रोष पैदा हो गया। परन्तु बाद का घटनाक्रम ने भारतीय नाटिक सम्बन्ध में सोवियत संघ के नेताओं की भावितियों को दूर कर दिया। जब कारिया समस्या के बाद के चरणों में भारत द्वारा सुझाए गए समझौते में 38 वीं अंश रखने पर न करके चीन का संघ द्वारा आक्रमणकारी घोषित न करने का आग्रह किया गया तो स्टालिन ने भारत के नाटिक प्रयासों का पुरस्कार किया। यह सत्य ही कहा गया है कि कारियाई युद्ध के समय भारतीय नाटिक से नहीं बरकरा रहने और निलंबी के बीच मतभेद का स्पष्टि पैदा हुआ वहीं सोवियत संघ के साथ उनके सम्बन्धों में एक नयी सीमा तक प्रगाढ़ता आयी। उसी समय जब चीन ने नाटिक से संघ के प्रश्न पर भारत ने सोवियत संघ का साथ दिया और अमरिका द्वारा आश्रित नगरवासियों को मुम्बई में जान बूझकर कर दिया। जापान नाटिक-संघ के प्रारम्भ के भारत ने स्मरण दिग्गह दिया कि वह जापान का साम्राज्यवादी विजय में जोड़ने का एक प्रयास था। अतएव भारत ने सोवियत संघ का साथ देते हुए जापान को नाटिक-संघ पर हस्तक्षेप करने से रोक कर दिया। उसके कुछ ही दिनों के उपरान्त अप्रैल 1952 में स्टालिन ने भारतीय राजदूत डा. राजगोपालन से मिले का। इस बैठक के बाद महसूस किया गया क्योंकि पिछले दो वर्षों में स्टालिन ने किसी राजदूत का ऐसा अवसर नहीं दिया था। अन्तराष्ट्रीय स्तर पर उस बैठक को सोवियत संघ और भारत के सम्बन्धों में सुधार का प्रतीक माना गया। नवम्बर 1952 में कोरिया-युद्ध के युद्धवर्धियों के प्रश्न पर भारत और सोवियत संघ में पुनः कुछ मतभेद पैदा हुआ लेकिन उसके कारण दोनों के सम्बन्ध बहुत अधिक नहीं बिगड़े और दोनों देशों के बीच अग्रसर शक्ति रहे।

सोवियत संघ का नया विश्व नाटिक और भारत — 1953 में स्टालिन का मृत्यु हुआ और उसके तुरंत बाद सोवियत विश्व-नीति में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। तत्कालीन सोवियत नेताओं में एक नया महानुभाव का भावना आयी। गतिशील सहनशक्ति का सिद्धांत मोदीय विश्व-नाटिक का नया धारा हुआ। जोह आचरण को नाटिक में आश्रित बनाया और सोवियत नेताओं के दावाओं के राजनय का आयोजन किया। उस दावाकरण में भारत और सोवियत संघ के सम्बन्धों में और अधिक सुधार हुआ। उस परिस्थिति का ज्ञान में ज्ञान प्राप्त नाटिकों का प्रमुख हाथ रहा। मुमुक्षु राज अन्धकार ने भारत द्वारा कारिया के राजनीतिक मुम्बई में भाग लेने का विराध दिया। अतएव भारत और सोवियत संघ के सम्बन्धों में अधिक प्रगाढ़ता आयी। 1953 के मध्य में कमोरे की स्थिति भी

विपदने लगी। इसी समय गैब अदुला द्वारा स्वतंत्र कश्मीर का नारा बलवत् किया गया। उस समय भारत की जनता में यह आम धारणा थी कि गैब अदुला के इस नारे की समुक्त राय अमरिका से प्रेरणा मिली है। 1954 के प्रारम्भ में समुक्त राय अमरिका ने पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने का निश्चय किया। भारत में इसका प्रबल विरोध हुआ और इस विरोध में सोवियत संघ ने भारत का समर्थन किया। फलतः भारतीय जनता और प्रशासन में सोवियत संघ के प्रति अधिक हार्दिक अनुरोध पैदा हुई।

हिंद-चीन की समस्या पचगोल और संघ संघटनों का निर्माण—1954 में हिंद-चीन की समस्या ने अत्यंत गम्भीर रूप धारण कर लिया। समुक्त राय अमरीका का फ्रांस का पक्ष लेकर इस युद्ध में कूट पडना चाहता था। भारत ने इसका विरोध किया और हिंद-चीन की समस्या के समाधान के लिए छ गूनी प्रस्ताव रखा। ये प्रस्ताव प्रत्यक्षतः अमरिका विरोधी था। अतः सोवियत संघ में इसका स्वागत हुआ। हिंद-चीन से सम्बंधित जेनेवा सम्मेलन में भी भारत की भूमिका अत्यंत निष्पक्ष रही। सोवियत संघ ने इस पर धुनी जाहिर की।

पुनः भारत और चीन के मध्य पचगोल के समझौते पर हस्ताक्षर किये गये। सोवियत संघ ने पचगोल के मिट्टा तो भी अपनी आस्था यवत की और शांति के माग में इस एक सम्मेलन का म बताया।

फिर एशिया की गीत युद्ध के दायरे में सम्मिलित के लिए अमरिका की प्रेरणा से दो संघ संघटना—दक्षिण पूर्व एशिया संधि संघटना तथा दक्षिण पूर्व एशिया संधि की स्थापना की। भारत ने इन संघ संघटना का प्रबल विरोध किया और अमरीकी नीति का तीव्र प्रतीका की। अमरिका द्वारा स्थापित इन संघ संघटना का विषय में भारत और सोवियत संघ का एक ही प्रकार का दृष्टिकोण होने से दोनों दलों के मध्य पचगोल अधिक मधुर हो गया।

यात्राओं का आदान प्रदान—जून 1955 में जवाहरलाल नेहरू ने सोवियत संघ की यात्रा की और व्लादिमीर सोगो को अपने सहअतिथि व से बहुत अधिक प्रभावित किया। 22 जून को नेहरू और सोवियत प्रधानमंत्री बुलगानिन ने इस यात्रा के एक समुक्त बक्तव्य पर हस्ताक्षर किये कि दोनों दलों का पारस्परिक सम्बंध जो पहले से ही मंत्री तथा सहिष्णुता पर आधारित है भविष्य में भी पचगोल द्वारा निर्दिष्ट होने रहेंगे।

नेहरू की रूस यात्रा के पश्चात् 1955-56 में बुलगानिन और निजिता ख्रुश्चेव ने भारत की यात्रा की। 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद यात्रा पहला बार मार्क्सवादी प्रधानमंत्री सदभावना की यात्रा पर इस प्रकार अपने देश से बाहर निकला था। इसी नेताओं का यह भारत यात्रा भारत की असल जनता की नीति के लिए बड़े आदर और सम्मान की बात थी। भारत में रूसी नेताओं का ऐतिहासिक स्वागत किया गया। अपने महान नागरिक सम्मान का उत्तर देते हुए बुलगानिन ने घोषणा की भारत सोवियत मंत्री की रचना पचगोल के विवस्नीय तथा स्थायी आधार स्तम्भों पर की जा रही है भारत तथा सोवियत संघ के मध्य सन्धी

समानता तथा पारस्परिक नाम के आधार पर आधुनिक एवं आर्थिक सहयोग के विकास के लिए सभी आवश्यक स्थितियाँ पैदा कर ली गयी हैं।

भारतीय मुक्त के समय बुलगानिन ने कहा हम अपने आर्थिक तथा वैज्ञानिक अनुभव का आपके साथ बाँटने के लिए तैयार हैं। नगर में खुश्चव ने भाव विभाज्य होकर धारणा का हम अपनी राह का आखिरी टुकड़ा भी आपके साथ बाँटकर दायेंगे। कश्मीर के दार में बालते हुए खुश्चव ने धारणा की कि सोवियत मध्य कश्मीर को भारत का अभिन्न जग मानता है। आपका जब जब भी हमारी सहयोगिता की जरूरत हो खुश्चव ने आश्वासन देते हुए कहा पहाड़ की चोटियों पर हमारा हमें पुकार लीजियेगा। हम आपका मध्य के लिए आ जायेंगे। दस्तुत कश्मीर के प्रश्न पर भारत की प्रतिष्ठा को रखा सोवियत मध्य ने कहा है। जब हम जमराहा गु ने भारत को पराजित करने का प्रयत्न किया तब-तब नुरत्या परिषद में चीने का प्रयोग करके सोवियत मध्य ने ही भारत का राज बचाया।

हमने सभी भारत की यात्रा के दौरान सोवियत नेताओं ने नावर्तनिक रूप से इन बातों का समर्थन दिया कि गांधी भारत का एक अभिन्न जग है और पुत्रगान का बहुत ही बड़ा कोई अधिकार नहीं है। कश्मीर और गांधी के प्रश्नों पर भारत का समर्थन करके सोवियत मध्य ने प्रत्येक भारतवासी के हृदय में अग्न के लिए एक भावना पैदा करने में सफलता प्राप्त की। दोनों देशों के नेताओं द्वारा एक दूसरे के देश को का रखा सम्भावना यात्राएँ मन्त्रा एवं सहयोग का प्रतीक बन गये। 1955 में ही अनिवार्यता और आतीय भेदभाव से संचालित विभिन्न प्रश्नों के सम्बन्ध में दोनों देशों द्वारा अपनाये गये समान दायित्वों ने दोनों देशों का मित्रता का और गहरा रूप प्रदान किया। यद्यपि 1955 में हंगरी का घटना को लेकर भारत और सोवियत मध्य के सम्बन्धों में कुछ तनाव उत्पन्न हुआ तथा यद्यपि भारत द्वारा हंगरी में का गयी सोवियत सैनिक कायदाही का विरोध करना लेकिन यह तनाव अन्तर्गत कादिक हुआ तथा और हमने दोनों देशों के मन्त्रीपूर्ण सम्बन्धों को कायम रखने की प्रक्रिया में का विशेष ध्यान देना नहीं दे।

निरस्त्राकरण और गांधी—निरस्त्राकरण के क्षेत्र में भी सोवियत मध्य और भारत के सहयोगिता में काफी प्रगति हुई है। 1958 में सोवियत मध्य ने अपार जातिम स्त्राकर अपना तरफ से सामाजिक परीक्षण का करने का निषेध दिया। भारत ने सामाजिक मध्य की इस कायदाही का बड़ा प्रयास का। 1959 और 1960 को सम्पूर्ण सभा अधिवक्ताओं में भारत ने सोवियत मध्य द्वारा रखा गया निरस्त्रीकरण के सभा प्रस्तावों का समर्थन किया। 1962 में गांधी का मुक्ति के सम्बन्ध में भारत का सोवियत मध्य का पूरा समर्थन मिला। जब गांधी के विरुद्ध भारत का सैनिक कायदाही के प्रश्न का सुरक्षा परिषद में उठाया गया तो सोवियत मध्य ने बौटा का प्रयास कर किम प्रस्ताव को पारित नहीं होने दिया। अन्तर्गत भारत कीय जनता के दिल में प्रबल मन्त्री का भाव पैदा।

आर्थिक सहयोग—राजनैतिक क्षेत्रों में सहयोग के अतिरिक्त भारत और सोवियत मध्य में आर्थिक सहयोग भी बढ़ने लगा। 1953 में दोनों देशों का व्यापार

कुल अस्सी लाख रुबल था। 1957 में यह राशि पाँच करोड़ रुबल तक पहुँच गया। सोवियत संघ से भारत का प्रचुर मात्रा में आर्थिक और प्राविधिक सहायता मिली। निलाई में सोवियत सहायता से एक इस्पात का कारखाना गुना जो दोनों देशों की मशीन का प्रतीक है। 1958 के अंत तक भारत को सोवियत संघ से तीन करोड़ रुबल का ऋण मिल चुका था। संयुक्त राज्य अमेरिका का ऋण मुख्य रूप से भारत की सामुदायिक विकास योजनाओं और छात्राग्रीों की आवश्यकता पूरी करने के लिए हुआ है। इसमें तारकालिक लाभ को हो ध्यान में रखा जाता रहा है और इसका स्वरूप मुख्यतः प्रचुर मात्रा में रहा है। किन्तु सोवियत संघ का ऋण स्थूल रूप से तथा स्थायी रूप से निवेश देने वाले मिला के कारणने भारी मशीनों के कारखाने तथा दवाइयाँ बनाने के कारखाने के लिए मिला है। इसका उद्देश्य सग सदा के लिए आराम निभर बनाना है ताकि यह दूसरा का मुहनाज न हो सके। अतः सोवियत सहायता संयुक्त राज्य अमेरिका की अपक्षा में पुनः होत हुआ भी अधिक महत्वपूर्ण है।

सोवियत संघ और भारत के इन मधुर सम्बन्धों की ध्यान में रखते हुए 20 फरवरी 1950 को जवाहरलाल नेहरू ने लोक हो कहा था हम इस बात से परिचित हैं कि हमारे द्वारा एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न मार्गों को अपनाया जा रहा है किन्तु मूलमूल बात एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के दृष्टि काण और मित्रता के प्रति विश्वास और सम्मान की भावना है। मुझे विश्वास है कि ऊँची मतभेदों के बावजूद भारत और सोवियत संघ के बीच यह भावना विद्यमान है। मेरे विचार से यह कहना सही है कि भारत और भारतीय जनता सोवियत संघ और सोवियत जनता के साथ मित्रता की भावना क्षणिक आवृत्ति या स्वार्थ भावना पर आधारित नहीं है बल्कि इसकी जड़ इतनी गहरी है कि समय पर उत्पन्न होने वाले विचारों के मतभेद में यह अपने-आपको सुरक्षित रख सकती है। मैं सोचता हूँ कि यह मित्रता निश्चित रूप से मेरे देश के लिए लाभकर है। मैं आशा करता हूँ कि यह मित्रता आपके देश के लिए और दोष सम्पूर्ण विश्व के लिए हितकर है।

भारत-चीन युद्ध और सोवियत संघ

1952 के अक्टूबर नवम्बर में जब भारत चीन के साथ युद्ध शुरू हुआ तो सोवियत संघ के लिए एक बड़ी कठिन परिस्थिति उत्पन्न हो गयी। इस युद्ध में एक तरफ़ ता सोवियत संघ का भाई चान और दूसरी ओर दोस्त भारत था। इस हालत में वह किसका पक्ष ले यह बहुत ही कठिन समस्या थी। युद्ध के प्रारम्भिक दिनों में सोवियत संघ मौन धारण करे रहा। इससे भारत की बड़ी निराशा हुई। लेकिन 45 अक्टूबर 1952 को सोवियत समाचार पत्र प्रावदा ने अपने अपनेस में भारत से यह जाग्रह किया कि यह चीन के रचनात्मक प्रस्तावों की मातिपूर्ण समझौते के लिए स्वीकार करने के। सोमा विवाद में संलग्न चीन का पक्ष लेते हुए उनमें मुख्यतः मजबूत देशों की निष्ठा को तथा होने ब्रिटिश उपनिवेशवाधियों की विरागति बताया। 5 नवम्बर को अपनेस में प्रावदा ने युद्ध बन्द करने पर तथा दोनों पक्षों द्वारा कोई शत में समाते हुए परस्पर संधि बातचीत करने पर बल दिया।

खुशेब न भी प्रधान मन्त्री नेहरू का एक पत्र में इस प्रकार की बात का मुनाब दिया। भारत के लिए यह स्थिति बनी ही चिन्तनीय और गम्भीर था क्योंकि हान सोवियत संघ की अपना मित्र बनान में बाड़ कमर नहीं छोड़ी थी। जना ने नयी सोवियत संघ द्वारा अपना पुनर्निर्माण के अनुसार भारत का मित्र बनवाने का मित्र विमानों का निर्यात भी स्थगित कर दिया गया। इन सब बातों का लेकर भारत में सोवियत संघ के विरुद्ध प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं का ज्वार-भाटा बढ़ गया।

धीरे धीरे भारत पर चीना आक्रमण के सम्बन्ध में सोवियत संघ का रुख कोन बदल गया और 5 नवम्बर तक वह तटस्थ-नीति पर आ गया। बाद का महत्वपूर्ण घटनाओं ने इस बात का निश्चित संकेत दे दिया कि सोवियत संघ ने भारत का साथ नहीं छोड़ा है और उसका प्रभाव राजनीति तथा आर्थिक दुर्दयित्व का धारण करने का एक प्रमुख कारण रहा है। दिसम्बर 1962 में सुपीम सोवियत के सामने खुशेब ने भारत पर चीन के आक्रमण का दुःख जिया की। सोवियत नाति में भारत के प्रति बिाघी रुख नहीं आना चाहने का रुख प्रमुख कारण रहा है कि जिन महान मुकदमान में धार प्रतिक्रियाओं के बावजूद ना भारत ने अपना रुख की नाति का परिहात नहीं किया और अन्तिम के समय संगठना में शामिल होने से इनकार कर दिया। जब 1963 में चीन ने भारत का प्रस्ताव अमान्य ठहरा दिया तो ना सोवियत राजनीतिज्ञों ने चीन का रुख आलाचना की। इससे अतिरिक्त उच्च आन वाद के निनात हुए मित्र शिमान ने जिय और भारत में मित्र विमान का कारखाना भी स्थापित किया। भारत चीन मित्र में सोवियत संघ के इस प्रकार के वास्तविक व्यवहार के कारण चीन के प्रमुख पानुस्य नेना ने लिखा था—पहले सोवियत संघ ने हम बिवाद में तटस्थता का रुख किया और अब यह मुख्यतः राज्य अमरिका के सम्मानार्थ है कि भारत के प्रति क्रियावाधियों का सुन्दर-मुन्ता समर्थन कर रहा है। स्पष्ट है कि भारत नाति में मन्त्री भारत चीन संघर्ष की बड़ी गौरव पर लय लय है। इस संघर्ष में भारत के प्रति सोवियत संघ का दृष्टिकोण इस बात की प्रमाणित करता है कि दोनों देशों का मित्रता एक मुक्त नींव पर खरी है।

रूस का सहायता—जुलाई 1963 में भारत सरकार के एक अधिकारी वरुण लियम के नेतृत्व में सोवियत संघ से भविक सहायता प्राप्त करने के लिए एक मिशन मस्को गया और सोवियत सरकार ने भारत के भविक सहायता-समाधान के लिए आश्वासन दिया। इस प्रकार सोवियत संघ के साथ भारत सम्बन्धों का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। 1963 में भारत को रूस से प्रचुर मात्रा में सामरिक और प्रौद्योगिक सामान मिली। इससे भारत का मित्र वायुयान और और बड़े मित्र वायुयानों के निर्माण के लिए भारत में एक कारखाना स्थापित करने में सक्षम प्रमाणित हुआ है। इसके लिए पश्चिम ज़रूरत रूस का पूरा से एक बम्बना आक्रमण का रुख है। सम्पत्ति निर्माण के लिए दरवाजा में एक स्थान चुना गया। रूस ने जल प्रकाश का सहायता करने का भी वचन दिया। 4 नवम्बर 1963 का रूस और भारत के बीच

एक क्षण पर नयी दिल्ली में हस्ताक्षर हुआ जिसके अनुसार भारत में तेल और गंधक का पता लगाने तथा उन्हें विकसित करने के लिए इस से टेक्नीशियन भेजे जायेंगे। एक सविनयासी रेडियो स्तम्भ बनवाने में सहायता करने का भी सोवियत संघ ने आश्वासन दिया। इस प्रकार भारत को सोवियत संघ से प्रचुर मात्रा में सहायता मिलती रही है।

सोवियत संघ भारत के प्रति प्रगाढ़ सहानुभूति रखता है हमारा प्रमाण हमें प्रधान मंत्री नेहरू की मृत्यु के बाद मिला। नए प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखकर सोवियत प्रधानमंत्री श्री ख्रुश्चेव ने भारत को यह आश्वासन दिया कि सोवियत संघ हमेशा का तब भारत को यथामुभव सहायता देता रहेगा। उस समय सोवियत जनता और नेताओं का जो सहानुभूतिपूर्ण आचरण हुआ वह अविश्वसनीय था। उसी वर्ष मित्र देशों ने सोवियत संघ भारत का परम मित्र है। वाशिंगटन में 1964 में डॉ. राजा कृष्णन ने इस का राजकीय यात्रा की। हमने पन्द्रहवर्ष दार्शनिक दृष्टि की धारितियों परी तरह दूर हो गयीं।

सोवियत संघ का नवीन नेतृत्व और भारत — 16 अक्टूबर 1964 को ख्रुश्चेव की पतन के उपरान्त सोवियत संघ में जिस नवीन नेतृत्व का उदय हुआ उसके कारण भारत में यह आशंका व्यक्त हो जाने लगी कि अब भारत के प्रति सोवियत दृष्टिकोण में परिवर्तन होगा। ख्रुश्चेव भारत के परम मित्र थे और उनका पता था भारत में अपार दय उत्पन्न हुआ। ऐसा समझा गया कि कांग्रीज़ और ब्रिजजोय चीन के साथ सौद्धातिक प्रश्नों पर समझौता कर लेगा और स्टालिनवादी नीति का अनुसरण करते हुए भारत को न विचार में भारत के पक्ष का समर्थन करना छोड़ देगा। लेकिन यह आशंका निमूलक सिद्ध हुई। तत्कालीन सोवियत राष्ट्रपति मिखोयन ने मास्को में भारतीय राजदूत का यह विस्वास जताया कि भारत के सभी समझौते खुद के साथ नहीं बल्कि सोवियत सरकार के साथ हुए थे और सोवियत संघ उसका पक्ष पालन करेगा। मिखोयन सोवियत राजदूत ने भी भारत सरकार का आश्वासन दिया कि भारत के प्रति उनके देश की नीति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नवम्बर 1964 में दोनों देशों ने एक नए व्यापारिक समझौते किये तथा दोनों देशों के व्यापार में विद्यमान बाधाओं को अन्त में प्राप्त प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की गयी। जनवरी में सोवियत संघ ने भारत में मिर्चा जैसा दूधरा दवाव का कारखाना बनाने में सहायता देने का वाचन दिया। 1965 में भारत के प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने सोवियत संघ की आठ मिन की यात्रा करके दोनों देशों में सौहार्द बढ़ाया और चतुष पक्षीय योजना में सोवियत संघ से तृतीय पक्षीय योजना की अपेक्षा दुगुनी सहायता पाने का आश्वासन प्राप्त किया। इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि भारत के प्रति सोवियत संघ की वर्तमान नीति में ख्रुश्चेव का नीति से कोई अन्तर नहीं आया जहाँ दो देशों की मंत्री में अन्तर्गत की कमी नहीं आयी। सोवियत संघ के नए नेतृत्व से भी भारत को अपार सहानुभूति समर्थन और सहायता मिली है और दोनों देशों का सम्बन्ध अत्यन्त मधुर है।

1965 का भारत-पाकिस्तान युद्ध और सोवियत सघ

कश्मीर समस्या पर सोवियत दृष्टिकोण —सुमार की मताधिकारियों में सावियत सघ ही एक ऐसा देश है जिनमें कश्मीर में भारतीय स्थिति का उचित दृष्टि से समझा है। कश्मीर के प्रश्न पर उसने हमेशा से भारतीय पक्ष का समर्थन किया है। स्वतंत्र ने शुरू में ही यह घोषित किया था कि सावियत सघ कश्मीर को भारत का अंग न अंग मानता है। कश्मीर की समस्या की जटिलता का कारण सावियत दृष्टिकोण में साम्राज्यवादी दलों का नीति है जो एशिया के दो पहली दश का आपस में बढ़ाकर अपना उत्पन्न सीधा करने के उद्देश्य रखते हैं। इन विचारों को सावियत नेता कई बार यकत कर चुके हैं और कश्मीर के सम्बन्ध में सोवियत नीति इसी तथ्य से प्रभावित रहो है। सावियत सघ का विचार है कि भारत और पाकिस्तान एक अच्छे पड़ोसी की तरह प्रत्यक्ष रूप से बातचीत करके इस प्रश्न का तय कर लें। कश्मीर के प्रश्न पर सुरक्षा परिषद की नीतिना बैठकें हुई और उनमें जा भी प्रस्ताव स्वाकृत हुए उनके सम्बन्ध में सोवियत सघ ने इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर दृष्टिकोण का निर्धारण किया। श्री सुखचंद पतन के द्वारा जो भारत में सोवियत विदेश नीति में परिवर्तन का आकांक्षित की जान गयी तो सावियत सघ के नये नस्त्व ने पुनः हा स्पष्ट कर दिया कि कश्मीर प्रश्न के सम्बन्ध में उनकी नीति बही रहणी जा अभा तक थी। सोवियत सघ के दृष्टिकोण में परिवर्तन कराने के उद्देश्य से पाकिस्तान की कूटनीति सक्रिय हो गयी। अग्रे 1965 में राष्ट्रपति अबुब खां इसी उद्देश्य से सावियत सघ गये और नेताओं से अनुरोध किया कि वे पाकिस्तान के सम्बन्ध में पुरानी बातों को भन जाय तथा पाकिस्तान के प्रति अपनी नीति का पुनर्निर्धारण करें। सावियत नेताओं ने पाकिस्तानी राष्ट्रपति का हार्दिक स्वागत किया लेकिन नीति के पुनर्निर्धारण के सम्बन्ध में किसी तरह का सकत नहीं किया। बाद में पाकिस्तान के विदेश मंत्री मुहम्मद नवाज सावियत सघ की यात्रा का। लेकिन इन यात्राओं और प्रयासों के फलस्वरूप सावियत सघ की कश्मीर नीति में का परिवर्तन नहीं हुआ। कश्मीर के प्रश्न पर सुरक्षा परिषद में सावियत बीटा को कुम्भित करने में पाकिस्तान के सा प्रयास विफल हो गये।

भारत-पाक युद्ध और सोवियत सघ—5 अगस्त को कश्मीर में पाकिस्तानी मुजाहिदीन के प्रवेश से स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक हो गयी और भारत ने इस नवीन पाकिस्तानी आक्रमण का मुकाबला करने के लिए दृढ़ नीति का अवलम्बन किया। भारतीय सैनिकों ने मुजाहिदीनों का सफाया करना शुरू किया और सोमा के उस पार युद्ध अंगु का जो पाकिस्तान के अधिकार में था खतम करना शुरू किया। भारत का कहना था कि इन्हीं स्थलों से गुजरकर पाकिस्तानी घुसपैठी भारतीय क्षेत्र में घुसते हैं और कश्मीर का सुरक्षा के लिए उनपर भारतीय अधिकार का हाना आवश्यक है। भारत के इस निगमन से स्थिति को और अधिक खराब कर दिया और पाकिस्तान के साथ प्रत्यक्ष युद्ध अवस्थामाओ प्रस्ताव हान गये। स्थिति का खराब हाल देख सोवियत प्रधानमंत्री ली कासीजिन ने 20 अगस्त 1965 के अंत में कश्मीर

की स्थापना पर चिन्ता व्यक्त करते हुए पाकिस्तान और भारत को पत्र लिखा। उन्होंने दोनों पक्षों को समय से काम लेने तथा प्रत्यक्ष वार्ता द्वारा झगड़े का शांतिपूर्ण निबटारा करने का सुझाव दिया। भारतीय उपमहाद्वीप में इस तरह से स्थिति को बिगड़ते देख सोवियत संघ के लिए चिन्तित होना बिल्कुल स्वाभाविक था। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ जाने की पूरी सम्भावना थी और पश्चिमी यूरोप में पाकिस्तान के सम्बन्ध होने से इस संकट में अन्तर्राष्ट्रीय संकट उत्पन्न होने की सम्भावना थी। सोवियत संघ के अत्यन्त निकट पड़ोस में इस तरह की घटना घटे उसकी आर से वह अपना मुक्त नहीं मोड़ सकता था।

1 सितम्बर को पाकिस्तानी सेना द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का उल्लंघन करके भारतीय क्षेत्र में प्रवेश ने स्थिति को अनियंत्रित कर दिया। इसके प्रतिरोध में भारत को भी प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में आना पड़ा और भारतीय सेना ने कई मोर्चों पर पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध जारी कर दिया। कई क्षेत्रों में भारतीय सेना पाकिस्तान के भू-भाग में घुस गयी। भारत की इस कायवाही को जहाँ पश्चिमी राष्ट्रों ने आश्वस्त्य कहकर सम्बोधित किया वहाँ सोवियत संघ ने भारतीय स्थिति को समझने का प्रयास किया और आत्मरक्षा के लिए लिये गये इस भारतीय कायवाही को उचित बतलाया। पाकिस्तानी हमले के खिलाफ भारतीय प्रवेश की अव्यवस्था और प्रमुखता बनाये रखने के लिए भारत को जो कदम उठाना पड़ा उसका सोवियत संघ में समर्थन किया गया।

यद्यपि भारत पाक युद्ध में सोवियत संघ ने भारत का समर्थन किया लेकिन वह नहीं चाहता था कि उसके दो पड़ोसी एशियाई देश साम्राज्यवाजियों के जान में फँसकर इस तरह लड़ते रहें और अपने आप को खर्बा कर लें। वह चाहता था कि दोनों देश अविनाश्वर युद्ध बंद कर दें। इस समय सोवियत नीति का प्रमुख उद्देश्य विवाद के कारणों में न पड़कर शांति की स्थापना थी। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री कोसिज़िन ने 4 सितम्बर 1965 को भारत के प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर उन्हें साम्राज्यवाजियों को समझने की कोशिश करने की तथा अविनाश्वर युद्ध बन्द करके प्रान्तों को प्रत्यक्ष वार्ता द्वारा घाटल और बाहुगं भावना के अनुरूप शांतिपथ ढग से सुलझाने का सुझाव दिया।

यह दुर्भाग्य की बात है प्रधान मंत्री कोसिज़िन ने निम्ना कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव में कोई कभी नहीं आयी है और दोनों देश युद्ध विराम रेखा पार करके एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहे हैं। कश्मीर में सैनिक मरण स सोवियत संघ बहुत चिन्तित है। अब समय नहीं है कि इस समय के सम्झौते का पता लगाया जाय। कितने मनस्थान की जान धमक जा रही है। युद्ध को तत्काल बन्द करना परामर्श आवश्यक है। इसी प्रधान मंत्री ने दोनों देशों को यह आश्वासन दिया कि वे समस्या के समाधान के लिए सोवियत संघ के सहयोग पर निर्भर कर सकते हैं। यदि दोनों पक्ष चाहें तो समस्या के समाधान के लिए सोवियत संघ अपनी सेवा (Good Offices) अर्पित करने को तैयार है।

रूस के इस प्रस्ताव की मध्यस्थता का प्रस्ताव नहीं कहा जा सकता था

वित्तु इसमें सहा सहयोग से भारत पाकिस्तान के विद्वानों का हस्त करण का मुद्राव अवश्य था। कई क्षेत्रों में यह सहा का भारत विरोधी प्रतिक्रिया माना गया। इस आलाचकों का कहना था कि यदि सावित्र सध भारत के पक्ष का समर्थन करता था और उसकी सन्निध कायवाहा का प्रवृत्त मानता था तो उसका मित्र पाकिस्तान का क्या चलावना दोनों चाहिए थी। भारत और पाकिस्तान दोनों का एक ही तरह का पक्ष लिखना क्या दोनों देशों को एक स्तर पर रखना नही था। तबिन सहा ऐसा मतनव लगाना सावित्र राजनय का नही समर्थन हा माना जायगा। वास्तविकताओं और सुरक्षा परिषद के मंच पर सावित्र सध ने भारत का खुला समर्थन किया था। तबिन यह समय वास्तविकता का नही युद्ध का था। यों स्रोतियत सध इस समय खुलकर भारत का समर्थन करता तो अमरीका के लिए पाकिस्तान का खुला समर्थन आवश्यक हा जाता चान का ना समर्थन उल्लाह प्राप्त हा जाता और भारत का स्थिति बड़ा नाजुक हो जा सकता था। इस प्रतिक्रिया से सावित्र सध के पक्षों का भारत विरोधा करना एकलम अनचित है।

सुरक्षा परिषद में सोवियत सध ने भारत के पक्ष का प्रवृत्त समर्थन किया। 4 सितम्बर का सुरक्षा परिषद ने युद्ध विराम का जो प्रस्ताव पास किया उसका सावित्र सध का पूरा समर्थन प्राप्त था। इस प्रस्ताव से युद्ध बन्द नहीं आया और इसी बीच तान तरफ से भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। इस घटना से आगल जमराका माजिग सन्निध हा उठा। इस क्षेत्र में उसका भारत और पाकिस्तान पर आक्रमण माना गया। पक्ष के भातर से आगल अमरीका गुप्त इस बात का प्रयास करन लगा कि भारत को आक्रमणकारा घापित किया जाय व नही तो कम से कम कमाल में समुक्त राष्ट्रसंघ का सना भजा जाय। कमाल में सध का सना भेजने का माजिग बन्द पुराना था और ब्रिगन और जमराका युद्ध का स्थिति से लाभ उठाना चाहत था। तबिन सावित्र विरोध के कारण था अमरीकी गुट का अपन भारत विरोधा माजिग का परिचालन करना पडा। 6 सितम्बर का सुरक्षा परिषद ने युद्ध बन्द करन के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव स्वीकार किया कि वह भारतीय पक्ष का बहुत हद तक समर्थन करता था। भारत चाहता था कि प्रस्ताव से स्वीकार कर कि वनमान सध का समर्थन पाकिस्ताना मुजाहिदों के व मार प्रका न है। भारत का इस माग का सोवियत सध ने समर्थन किया। इस प्रस्ताव से कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान सम्पूर्ण क्षेत्र में तत्काल युद्ध बन्द करें और सभी सन्निधों का समर्थन पर बुला दें जहाँ से 5 अगस्त 1965 का था। 5 अगस्त की तिथि महत्वपूर्ण है। इस दिन पाकिस्तान घुसपैशियों का प्रवृत्त भारत पर हमला हुआ था। इस तरह प्रस्ताव ने परान सध से पाकिस्तान का निराशा का। प्रस्ताव में 5 अगस्त की तिथि सोवियत सध के कहन पर रखा गया। सावित्र प्रतिनिधि ने स्पष्ट कर दिया कि यदि इस तिथि का उल्लंघन नहीं होता है तो वह प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेगा। इस प्रकार परिषद का 6 अक्टूबर का सध का भारत का सोवियत सध का अपूर्व समर्थन प्राप्त हुआ।

इस प्रस्ताव को कार्यावित करान के लिए जब राष्ट्रसंघ के महासचिव

यू.एन. भारत और पाकिस्तान के लिए रवाना हुए तो सोवियत संघ ने महासचिव के प्रतिनिधित्व का जोरदार साथ दिया। उसी समय ईरान और तुर्की की सरकार तथा इंडोनेशिया ने पाकिस्तान का समर्थन किया और पाकिस्तान को सैनिक सहायता भेजने का आश्वासन दिया। 16 सितम्बर को चीन एक कदम और आगे बढ़ गया और भारत को अस्मिता दे दिया। सोवियत सरकार ने इन विदेशी सैनिकों की सहायता दी कि भारत और पाकिस्तान के मामले में हस्तक्षेप करके स्थिति को और बिगाड़ने का प्रयास नही करे। सोवियत संघ के इस कड़े रुख ने इन देशों को बाध्य किया कि वे भारत के विरुद्ध पाकिस्तान की सहायता नहीं करें।

यू.एन. के प्रतिनिधित्व की विफलता के बाद सोवियत संघ बहुत चिन्तित हो उठा। 18 सितम्बर को प्रधान मंत्री कोसिजिन का एक दूसरा पत्र भारत और पाकिस्तान की सरकारों को मिला। पत्र में कहा गया था कि दोनों देश कुछ और अधिक बुद्धिमानों में काम लें और युद्ध बन्द करें। युद्ध से उत्पन्न समस्या की वार्ता द्वारा तय करने के लिए उस बार सोवियत प्रधान मंत्री ने यह स्पष्ट सुझाव रखा कि उनकी सरकार दोनों पक्षों को अपनी सेवा (Good offices) अर्पित करने के लिए तैयार है। सोवियत संघ प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा राष्ट्रपति अयूब खान के बीच समस्या के समाधान के लिए प्रत्यक्ष वार्ता चलाने की व्यवस्था चलाने को तैयार है और इस तरह की बातचीत यदि दोनों पक्ष चाहें तो सोवियत शाश्वत हो सकती है। ताशकन्द सम्मेलन के विचार की उत्पत्ति यहीं से होती है। भारत ने इस प्रस्ताव को तत्काल स्वीकार कर लिया और कुछ आनाकानी करने के उपरान्त पाकिस्तान ने भी इसे मान लिया। बाद में सुरक्षा परिषद ने 20 सितम्बर को प्रस्ताव पारित करके भारत और पाकिस्तान को युद्ध बन्द करने का आदेश दिया। 23 दिसम्बर को युद्ध बन्द हो गया। सोवियत-संघ ने इसका बड़े रूप के साथ स्वागत किया।

ताशकन्द सम्मेलन—23 नवम्बर को प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने रायसभा में कहा कि सोवियत सरकार से उन्हें पुनः एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें प्रधान मंत्री कोसिजिन ने सुझाव रखा है कि ताशकन्द में भारत और पाकिस्तान के नेताओं का सम्मेलन अब गीघ होना चाहिए। 2 दिसम्बर को भारत में सोवियत राजदूत ने प्रधान मंत्री से मुलाकात करके सम्मेलन की योजना पर विचार विमर्श किया। उन्होंने बताया कि जनवरी 1960 के प्रथम सप्ताह में यह सम्मेलन प्रारम्भ हो और युद्ध विराम रेखा को दृढ़ करने युद्ध विराम के उत्पन्न की बात करने तथा भारत और पाकिस्तान के सम्बंधों में सुधार करने की समस्या पर इस सम्मेलन में विचार हो। उन्होंने यह भी कहा कि स्वयं प्रधान मंत्री कोसिजिन दोनों पक्षों को सनाहूँ भाविरा देने के लिए ताशकन्द में मौजूद रहेंगे। 8 दिसम्बर का यह घोषणा की गयी कि ताशकन्द में भारत के प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच 4 जनवरी से सम्मेलन प्रारम्भ होगा।

4 जनवरी 1966 को ताशकन्द दूरस्थ भवन में जिसका अर्थ तटस्थता भवन है भारत के प्रधान मंत्री पाकिस्तान के राष्ट्रपति और सोवियत प्रधान मंत्री का दिनांक—18

मना का शिखर-स मान प्रारम्भ न्या। ससार म शयन हा काइ एसा यक्ति पा जिसने यह जागा था कि ताशकन सम्मेलन सफल होगा। यात्रा प्रारम्भ करने के पूर्व पाकिस्तान के राष्ट्रपति कह चुके थे कि कम्मार के बिना भारत के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। भारत के प्रधान मंत्री ने भी कहा कि व कम्मार के प्रश्न पर किसी तरह का वां नही करेंगे। सावित्रय सच म भी समझौते के प्रश्न पर सही प्रकट किया गया। तब न अपने विशेष समाचार में कहा कि दोनों के विवादों को जो लगभग दस वर्षों से विग्रह का स्थिति में है, मृत्युना दासान वाम नही ह। फिर भी सम्मेलन शुरू होने के पहले प्रधान मंत्री कोसिजिन ने कहा कि हम का जनता का आशा है कि यह बात सफल होगा। सावित्रय विश्व मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि ताशकन का वायुमंडल वातावरण है और उसमें पक्षपातक परिणामों की आशा की जा सकती है।

पाँच दिनों का वातां के बाद यह स्पष्ट होना लगा कि सम्मेलन किसी हालत में सफल नहीं हो सकता। पाकिस्तान कम्मीर का प्रश्न उत्थान की विधि पर डग हुआ था और भारत वाता करने में स्वीकार कर रहा था। भारत का कम्मीर था कि दोनों देशों का युद्ध नहीं करो का घोषणा करना चाहिए। पाकिस्तान इस प्रस्ताव का मानने के लिए तैयार नहीं था। इन आलतम जन जन ताशकन वाता का अंत करीब आता गया वस वस भारत पाकिस्तान में मतभेद का आगा आगु हाता गया। 9 जनवरी को एक पाकिस्तानी प्रवक्ता ने प्रतिनिधियों के सामने यह घोषित कर दिया कि पाकिस्तान का भारत का युद्ध नहीं करो का प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। पाकिस्तानी प्रवक्ता ने कहा कि जबतक कम्मीर के प्रति पाकिस्तानी दाव का निवेदन नहीं हा जाता या उस दाव का निवेदन के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर ला जाती भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध नहीं करने का कोई समझौता संभव होगा। पाकिस्तानी प्रवक्ता के कथन के बाद अपने प्रस-सम्मेलन में भारत के विश्व मंत्रालय के सचिव श्री सी एस या ने पाकिस्तान द्वारा भारतीय प्रस्ताव के ठहराव जान का पुष्टि की और कहा कि दोनों पक्षों का पक्षि ए- दूसरे से काफी दूर है। उन्होंने कहा कि बात में बहुत कम प्राति न्द है।

सावित्रय राजनय का जादू—11 जनवरी 1966 का सबर यह प्राय निश्चय हो गया था कि ताशकन बात असफल है। यहाँ और सम्भव सम्मेलन के अंत पर सशक्त विनष्टि के निकानना भी कम्ति है। लेकिन सावित्रय राजनय अन्त सक्षि था। ताशकन में सावित्रय सच के साथ नता मोहू य और 10 जनवरी का उनक अथक प्रयास के फलस्वरूप गतिरोध टूट गया और चार बजे सुष्पा का यह सफल मिलन लगा कि भारत और पाकिस्तान में किसी तरह का समझौता हा जायगा। नौ बजे रात को तालिनों की गन्नाहा के बीच राष्ट्रपति अयूब खां तथा प्रधान मंत्री श्री जल बहादुर शास्त्री ने प्रधान मंत्री कोसिजिन का उपस्थिति में एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया। जो बात कथन बारह घंटे पूरे अस्मभव प्रतीत होता था उसका सावित्रय राजनय के जादू ने सम्भव बना दिया। ताशकन बातों की सफलता केवल प्रधान मंत्री कोसिजिन का सफलता ही नही बरन रिप्लन

कुछ वर्षों में सोवियत राजनय को सबसे महान सफलता थी।¹

सोवियत राजनयिक सफलता के कारण—मनो भविष्यवाणियों के बावजूद तात्कालिक सम्मेलन सफल हुआ—यका प्रमुख कारण है सोवियत राजनय की स्थिति और निष्पत्ति। यह बात स्पष्ट है जहां कि सोवियत युग तब भी तात्कालिक ने कहा था कि यह बात जहां मंत्री नीति जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान में स्थिति का बीच उपनिवेशवादियों द्वारा बोया गया है जो होना देना का जनता की भावि और मंत्रीवर्ग वातावरण में रहने के एक नहीं हैं। सोवियत राजनय में सत्तरहवां को स्वायत्त रहा। उनमें एक निष्पत्ति वातावरण में दोनों देश के वणवारा का मित्राया और समर्थन का। इन में उनकी सहायता की निम्न स्वायत्त की भावना का मजबूत अभाव था। सोवियत नेताओं के सहानुभूतिपूर्ण आचरण तथा सत्कारना से सम्मेलन को सफल बनाने में सफलता मिली।

सोवियत राजनय की सफलता का एक और कारण था और यह कारण भौगोलिक था। सोवियत संघ यूरोप के साथ साथ एशिया का भी एक देश है और एशिया में तात्कालिक नीति रहे यह उसके हक में भी अच्छा है। अतएव सोवियत नेताओं के साथ एशिया में तात्कालिक नीति के अर्थ में भी। इस प्रकार का काय स्थिति के साथ एशिया काय तो उनमें सफलता का मित्रता और सम्भावना होता है।²

1. The agreement which Prime Minister Shastri and President Ayub Khan signed at Tashkent on January 11 is not a triumph of Indian diplomacy. It is also not a triumph of Pakistani diplomacy. It is an outstanding triumph of Soviet diplomacy. At Tashkent the Soviet Union emerged as a major factor in Asian affairs, it pushed aside China and kept off any eastern intervention. In bringing together India and Pakistan outside the purview of the Security Council the Soviet Union did something which the Security Council could not do and any other Big Power could not have hoped to do. For the first time over Kashmir India and Pakistan have agreed to carry out certain obligations directly between themselves and this is the measure of the Soviet success.

—M. Chalapathi Rao, *The Tashkent Agreement in The Illustrated Weekly of India*, March 6, 1966, p. 15.

2. With Tashkent something altogether new has come into the world. The Tashkent episode will have an eternal impact on the relationship between the three great neighbours—India, Pakistan and Russia.

Kosygin is able to do what neither Harold Wilson nor Lyndon Johnson could have done. This is not because he is cleverer than they but in the last analysis because he is nearer

Great Britain in spite of the tests of the communist alliance.

राष्ट्र-सम्मेलन के बाद पाकिस्तान के प्रति माविपत मुद्दे के दायरे में दक्षिण को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त राजनीतिक शक्तों में बड़े आगवा-पन की बातें कि कम्यार के प्रश्न पर सोवियत संघ ने पाकिस्तान के पक्ष में कुछ प्रस्ताव दिये हैं। परंतु सोवियत संघ के पक्ष में प्रस्ताव के अन्तर्गत का कुछ समझाने योग्य था। सन् 1965 में उसने शान्ति के पक्ष में समझौते पर रक्षा को कुछ बड़े बड़े समझौते करने को कहा। उनसे शान्ति का यह कहना था कि पाकिस्तान की रक्षा माविपत शक्ति में मशीन रख भारत के लिए हिंसा का सिद्ध हथियार और माविपत का भारत के प्रति नकारात्मक व्यवहार के लिए बाधा का मकड़ों के बिना कुछ लोगों का कहना था कि वास्तव में समझौते के बाद में पाकिस्तान और सोवियत संघ का यह दावा किन डी से बना है वह भारत के लिए चिन्ताजनक है। उनका कहना था कि सोवियत संघ का यह नया सिद्धांत भारत के लोगों के विपरीत प्रमाणित हो सकता है। लेकिन हम यह वादावाही सुनते हैं। अन्त में भी का दावा नहीं है कि बिना हम यह बताया जाय कि सोवियत संघ भारत का विरोध करता रहा है। यदि माविपत संघ पाकिस्तान के प्रति अपना अधिकार नहीं करता रहता तो तात्पर्य में वह शान्ति के पक्ष में दावा समझौते के लिए समझौते के पक्ष में था। यदि तात्पर्य समझौते और उसका दावा माविपत का दावा पाकिस्तान में दखल दे रहे हैं तो यह दावा विवादास्पद था कि सोवियत शक्ति का अन्तर्गत पाकिस्तान के प्रति मित्रता का दावा था तो भारत के लिए बड़े मुद्दे थे क्योंकि यह सोवियत संघ का दावा में समझौता हुआ कि वह पाकिस्तान के लोगों के हृदय में भारत के प्रति विलक्षण को बना था। सन् 1963 में माविपत प्रस्तावों की कोमिटि की पाकिस्तान यात्रा से यह बात दिखाने लगी थी। इस यात्रा के दौरान में राष्ट्रपति जवाहर लाल नेहरू ने सोवियत संघ द्वारा भारत का अन्तर्गत का विरोध किया था। लेकिन कोमिटि ने नहीं यह वादावाही किया कि माविपत अन्तर्गतों की आर्म्ड बल के समानान्तर व्यवहार का मुकाबला करने के लिए किया जा रहा है पाकिस्तान के लिए नहीं। पाकिस्तान से माविपत का दावा बहुत बड़ा था वास्तविकता में यह के लिए किसी भी तरह का नहीं। वहाँ उन्होंने प्रधान मंत्री नेहरू का दावा वास्तविकता में कि यदि भारत और चीन में का मध्य होता है तो पाकिस्तान उस शान्ति में नहीं बना। इन दोनों से यह स्पष्ट था कि माविपत संघ को पाकिस्तान की रक्षा में नकारात्मकता का प्रति पर को प्रतिकूल प्रभाव दे रहा था। इस में का भी कोई भूला जाति कि भारत ने का दावा स्थापित करने का दावा कि नहीं हुआ।

has been helped the United States in spite of its wealth and power has been ineffective

The crucial advantage of Soviet Union has not been due to race colour or culture but to geography. The Soviet Union can talk with authority about peace in Asia because it is a power with an Asian frontier of thousands of miles.

--Hindustan Times January 8 1966

पाकिस्तान को सोवियत सैनिक सहायता और भारत—जुलाई 1968 में सावित्र संध ने पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने का निषेध किया। सोवियत संध का इस निषेध की एक मूल्यपूर्ण पृष्ठभूमि थी।

पाकिस्तान के दृष्टिकोण से तात्कालिक सम्मेलन का एक लाभ यह हुआ कि यह हमारे बहुत अधिक गंजीर पहुँच गया जिसके लिए पाकिस्तान का राजनयिकों में सक्रिय थी। हालांकि सम्मेलन से पाकिस्तान को प्रस्तावित मित्रा और उत्तम रूप से सहायता प्राप्त करने के लिए 1966 में अपना सैनिक मिशन जनरल नूर मौ के नेतृत्व में माइको भेजा। यह मिशन खाती हाथ पाकिस्तान ग्रीक आया। यह ठाक है कि उस समय रूस ने पाकिस्तान का शास्त्रात्मक से इस्तेमाल कर दिया लेकिन वार्ता के दौरान रूसी नेताओं के इस से स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान को सावित्र सैनिक सहायता मिल सकती है। डिसेंबर 1967 में यह संकेत मिलने लगा कि निकट भविष्य में पाकिस्तान का सोवियत संध से शास्त्रात्मक मिल सकते हैं। भारतीय नेताओं ने शास्त्रात्मक मित्रता की सम्भावना मात्र का लेकर सोवियत संध से विराध करना उचित नहीं समझा। अप्रिल 1968 में प्रधान मंत्री कासिमिजि पाकिस्तान पहुँचे। उनके बराबरी पहुँचने के पहले ही राष्ट्रपति अयूब ने अमेरिका को पेशावर ब्रह्म का करने को माँटिम दे दी थी। यह इस बात का संकेत था कि पाकिस्तान किसी कीमत पर रूसी शास्त्रात्मक प्राप्त करने के लिए दंडु सक्षम है। कासिमिजि की पाकिस्तान यात्रा समाप्त होने के कुछ ही दिनों बाद यह स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान को सीधे ही रूस में शास्त्रात्मक मिलन लगने।

10 जुलाई 1968 को जब यह घोषणा हुई कि सोवियत संध ने पाकिस्तान को सैनिक सहायता सामान देने का निषेध कर दिया है तो परे भारत के राजनीतिक क्षेत्र में एक सतृप्तता मच गया। लोगो ने कहा कि सावित्र संध का यह फलता भारत की विदेश नीति के मुह पर बरसारा गमाचा है। सावित्र संध का इस निषेध को भारत रुख सम्बंध के इतिहास की सबसे बड़ी घटना मानी गयी। प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी ने बिना ध्वनन करते हुए कहा कि पाकिस्तान इन हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करेगा। पक्ष भी ऐसा हुआ है कि जब पाकिस्तान को अमेरिका में पीजी सहायता मिलने तक उसने उस सहायता का उपयोग भारत के विरुद्ध किया। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर अमरीका हथियारों का वन पर ही आक्रमण किया था। भारत का बल्ल मुद्र के दौरान भी यह स्पष्ट कर दिया था कि अगर पाकिस्तान का अमरीकी सहायता नहीं मिलती तो वह हमसे की क्षमता नहीं करता।

भारत के अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह की शका व्यवस्था की गयी। कहा गया कि यह मोक्ष की क्षमता है कि पाकिस्तान को रूस में जो हथियार प्राप्त होंगे उनका उपयोग वह हमसे विरुद्ध करेगा। क्या ध्यान के विरुद्ध? क्या सोवियत नेता इन भोले हैं कि वे यह नहीं जानते कि पाकिस्तान को एतमान सहायता भारत से है या अमेरिकी भाँ? हथियार का नाम म आया था भारत के विरुद्ध ही काम में आयेंगे। तब—फिर सोवियत संध ने पाकिस्तान का पीजी सहायता देने का निषेध किया।

पाकिस्तान उन सब सन्तियों के सम्बन्ध में जिन्होंने माविदत मुक्त विभाजित कर रहा है। अलाव में का यह है कि माविदत मुक्त वहाँ राजनयिक बना रहा है। बिस्व के लिए अन्तर्गत सिन नीर अन्तरिक्ष की जलविना का जल रहा है। एक बार भारत का सम्बन्ध और दूसरा बार पाकिस्तान का। दोनों का फीदी महात्मा दत्ता दोनों ही लोगों ने दुष्ट की दत्ता दत्ता है। का यह मान लिया जाय कि माविदत मुक्त सभी लोगों के तन्त्र का सम्बन्ध रहा है। यदि वह स्वयं तन्त्र का दत्ता का दत्ता रहा है। राजनयिक दत्ता का सम्बन्ध जगद विभा और निष्पक्ष पर तन्त्रों के दत्ता का दत्ता है। कि माविदत मुक्त तन्त्रों के दत्ता का दत्ता कर उनका गुत्रत का और सम्बन्ध रहा है। यह सम्बन्ध है कि माविदत मुक्त का दत्ता नीति न है। सक्रिय दत्ता दत्ता का दत्ता दत्ता दत्ता है।

सोविंदरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत के कुछ लोगों में यह भाव का
गया कि सर्वोच्च तथ्य के प्रति भारतीय नीति में परिवर्तन आना चाहिए। उदा
कहना था कि भारत का बदलना सिविलिजेशन का एक नया रूप देना है।
अतः वह सिविलिजेशन बनाना आवश्यक था जो जोड़ में खड़ा रहा है। उदा
नये निदेशों एवं स्थापना के सहायक भावों का प्रभाव मुद्रित हो सका। उदा
प्रधान मंत्री ने सचिवालय में वास्तव में एक नया रूप का ज्ञान कि सर्वोच्च रूप न
पाकिस्तान को देना। मध्यम रूप का ज्ञान कि ज्ञान हमारा सिविलिजेशन में
काद फ नये वापस। उदा यह नीति का ज्ञान कि ज्ञान का ज्ञान
दन का अधिकार है और हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ज्ञान नये प्रान
मंत्रा का सिद्धि नये यह ज्ञान कि ज्ञान कि सोविंदरूप - पाकिस्तान का हृदय
जाने रहा है कि नुवह का एक नाम नये करना जिससे भारत के साथ
उसके सम्बन्धों में बिना पड़ा है।

[illegible]

। अथवा त्रिभुज-समस्या का प्रमाण प्रस्तुत—

That India should be concerned over arms deliveries to Pakistan is understandable in the light of the past experience.

पाकिस्तान को नित्य सहायता देने में भारत के प्रति सोवियत दृष्टिकोण में काफी परिवर्तन महा आया और भारत के प्रति उसकी मित्रता का मापना पहलू को तरह सुन, बनी रही। इस बात का एक प्रमाण तब मिला जब भारत के राष्ट्रपति डा. जवाहर लाल नेहरू का म. यु. (3 मई 1969) के समय सोवियत प्रधान मंत्री कोमिजिन द्वारा भारत आया। स्वयं प्रधान मंत्री के आने का अर्थ यह था कि सोवियत सभ्य भारत की भावनाओं का बहुत बढ़ करता है। साथ ही कोमिजिन का उद्देश्य उन शक्तियों को दूर करना था जो पाकिस्तान की नयी नित्य सहायता देने के निमित्त ने पदा हुआ था। अपने अल्पकालीन मित्र प्रवास के समय प्रधान मंत्री कोमिजिन ने बताया कि भारत और सोवियत मध्य के सम्बन्ध बहुत अच्छे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इन सम्बन्धों पर किसी भी प्रकार की छाया पड़े ऐसा कार्य भी बान नहीं होगी। भारत के राष्ट्रीय हित पर किसी का भी आक्रमण हो या हम नहीं चाहेंगे। हम दोनों का मंत्री सम्बन्ध शांति काय का सचर दृढ़ है और आगे भी अधिक दृढ़ रहेगा।

चकोस्लोवाकिया को घटना और भारत सोवियत सम्बन्ध—1969 तक साम्यवादी जगत् में अलग और सुलभ एकता थी। यूगोस्लाविया को छोड़कर सभी साम्यवादी देश सोवियत सभ्य के नेतृत्व को मानते थे। किन्तु 1969 में साम्यवादी जगत् में उग्र मतभेद उत्पन्न होने लगे। इसका प्रारम्भ सोवियत सभ्य और चीन के सद्दान्तिन मतभेद में शुरू हुआ। 1967 के प्रारम्भ में चकोस्लोवाकिया में भी कुछ नया प्रवृत्तियों का समावेश होने लगा और वहाँ उग्रवाद के नाम पर कुछ ऐसे सुधार लागू किये गये जो साम्यवादी व्यवस्था से मेल नहीं खाते थे। सोवियत मध्य ने पक्ष इसका विरोध किया और चक नेताओं पर दबाव डाला कि वे कोई ऐसा कार्य न करें जिससे साम्यवादी व्यवस्था पर खतरा उत्पन्न हो जाय। चक नेताओं ने पहले टालम टाल की नीति अपनायी। फलतः समाजवादी विरोधी देशों तथा विदेशी ताकत अत्यन्त सक्रिय हो उठे। ऐसे तत्वों को कुचलने के लिए चकोस्लोवाकिया की सरकार एग्रेस्सिव रूप से साम्यवादी थी लेकिन उन्हें विदेशी सहायता (विशेषतः पश्चिम जर्मनी की सहायता) मिलने लगी थी। पश्चिम जर्मनी के समाचार पत्रों में चकोस्लोवाकिया के तटस्थीकरण की चर्चा भी की गयी।

But to make this the touchstone of Indo-Soviet relations as appear to be the tendency in certain political quarters would be to reduce all diplomacy to simple bilateral equations which would be thoroughly unrealistic. Any exaggerated dismay over Soviet attitude would be as unwarranted as the earlier exuberance over Moscow's stance. The Soviet Union's relations with Pakistan are governed by its global interests and dictated by its obvious desire to wean away Pakistan from China and the West. This need not mean any real diminution in Soviet interests in India and hasty conclusions might only inhabit the country's diplomacy for no tangible return. —*Hindustan Times*, May 8, 1969

पूर्वो प्ररोप का सुरक्षा व दक्षिण स चकास्लोवाकिया का एक महत्वपूर्ण सामरिक महत्व है और चेकोस्लावाकिया व बिना वारसा पकट का कुछ भा महत्व नही रह जाता है । चेकोस्लावाकिया का जीतन के बाद हिटलर न पासड पर आक्रमण किया था । इस तथ्य का ध्यान न रखकर पश्चिम जर्मनी व पश्चिम में मुह नहीं फगा जा सकता था । यह ठीक है कि तब तब पश्चिम जर्मनी का आर स आक्रमण का कां सतरा न था । तबिन उसक प्राप्ति हन स चेकोस्लावाकिया म समाजवादी विराधा तत्वा व होमरु वन वन गये थ । इस हानत म सावियन मध और वारसा पकट के अय राष्ठा के समस न ही रामने थ । उक्त आई गारवाइ करके इन विराधी तत्वा का सफाया कर दिया जाय अथवा कुछ समय आर ह्ता जाय । वारसा पकट व राष्ठा न प्रथम उपाय का अवलम्बन करना ही उचिन समझा ।

सोवियत हस्तक्षेप — वारसा संधि के पाँच सन्धय श्वा—सावियन सध हगरा पाठक पूर्वी जर्मनी और बुल्गेरिया ने 14 15 जुलाई व वारसा सम्मेलन व बाद एक संयुक्त पत्र चेकोस्लावाकिया का भजा । पत्र म चेकोस्लावाकिया का नयी सरकार पर 'प्रतिष्ठातिकारी' और समाजवादी व्यवस्था का खतरा पदा करने वाली हान का आराप लगाते हुए चक ननाओ को यह चेतावना दी गयी कि यदि उन्होंने अपना रव्या नही बदला तो उनके विरुद्ध कठोर कारवाही की जायगी । पत्र म कहा गया था हम यह कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि साम्राज्यवाद समाजवादी व्यवस्था म मनभेद पदा करे और यूरोप में शक्ति सतुनन अपन पक्ष मकर ने—चाह यह काम गतिपूण अथवा अगतिपूण उपाया स किया जाय फिर चाहे यह मानर स हो या बाहर म ।

वारसा संधि व इस संयुक्त पत्र का चेकोस्लोवाकिया म तीव्र प्रतिक्रिया हु । चेकोस्लोवाकिया कम्युनिस्ट पार्टी न पत्र म लगाय गय आरोप का सफटन किया और यह इन्ठा यक्त का कि समस्या व समाधान के लिए कम्य तथा अन्य कम्युनिस्ट पार्टिया स मोधी निष्पीय वार्ता हानी चाहिए । चेकोस्लावाकिया कम्युनिस्ट पार्टी व अध्यक्ष मश्वन ने संयुक्त पत्र व उत्तर में कम बात पर आ चय प्रकट किया कि चेकोस्लोवाकिया की स्थिति और पार्टी व उर श्वा को च्चना पानत समझा गया ।

इन पत्र व आगान प्रमाण व बाद साम्यवादी जगत म घटनाए तात्र गनि स घटने तथा और 21 अगस्त 1968 का सावियन सध गया वारसा संधि व दगा की सेनाएं चेकोस्लावाकिया म घुस कर समर क नगरा पर व आ कर लिया । इन सेनाओं ने चेकोस्लावाकिया की राष्ट्रीय असम्प्रती व 166 सन्ध्या को धर लिया और चक कम्युनिस्ट पार्टी के नेता दृक्चक का गिरफ्तार कर लिया । अभी बीच सम्पूर्ण चेकोस्लोवाकिया में पश्चिम जर्मनी के पत्र सक्षिप्ट हो गये जिन्होंने दग व भीतर व स्वतंत्र चक रेडियो का स्थापना कर ली । इन रेडियो स्ेशनों न सोवियत और साम्राज्यवादी विरोधी प्रचार बदे घन न ग हान गये । पर कुछ ने पणों में सम्पूर्ण चेकोस्लोवाकिया ह्मन रेडकारिया व वन म आ गया । सावियन आधिपत्य के विरुद्ध म प्राग में ह्मताल हु और चक नागरिकों न श्वा ह्म यारी

नौ जाओ के नारे लगाए। जेकिन क। भी यापक पमान पर रिसात्मक कारवाही नही हुई। सभ्य सैनिक अभियान के दौरान म केवल तम्र पक्ति मारे गये।

चकोस्लोवाकिया म रूसी हस्तान्तरण ने गत युद्ध क म परिधि को एक नया व्यवहार दिया। पश्चिमी यूरोप विज्ञान और अमेरिका ने उन जनता की मुक्ति संग्राम का समर्थन दिया और पीछे ही इस मामले को मधुवन राष्ट्र मध की सुरक्षा परिषद् म उठाया गया। मुन्ना परिषद् ने एक प्रस्ताव पास करके मास्विन मध और उसके साथी दलों क इस काम की निंदा की।

चकोस्लोवाकिया की घटना और भारत — अगस्त 1968 को जब सोवियत संघ और वारसा संधि के देशों की सेनाओं ने चकोस्लोवाकिया म सैनिक हस्तान्तरण किया उन समय भारतीय मस का वपाकालीन अधिवेशन चल रहा था। रक्षा हस्तान्तरण का खबर मिलने ही समय के मन्त्री सर इम्पनिस्ट दला ने सरकार स मंत्रि की रि चले इस मामले पर अपना खल स्पष्ट कर। प्रधान मन्त्री इरि गंधी ने तुरंत ही एक वक्तव्य दिया। उन्होंने रूसी कारवाही को दुभाग्यपूर्ण बताया हुए चकोस्लोवाकिया की जाता के प्रति भारत सरकार की सन्तुष्टि व्यक्त की। किन्तु उनके इस वक्तव्य म सोवियत विरोधी मम सदस्यों का सन्तोष नही हुआ। जनमध के बलराज मधोज ने सरकार स न केवल सास्विन कारवाही की निन्दा करने का आग्रह किया बल्कि यह भी की कि यदि चकोस्लोवाकिया के नेता विस्थापित सरकार बनाव तो भारत सरकार को उसे भा बना प्रदान करना चाहिए स्वतंत्र पार्टी के मोन मसानी ने कहा कि सरकार का कहे गये म रूसी कारवाही की निन्दा करनी चाहिए और मस म इस आग्रह का एक प्रस्ताव भा पारित किया जाना चाहिए। भारत म इस तरह की प्रतिज्ञा का एक विशेष कारण भा था। सास्विन संघ द्वारा पाकिस्तान को गृहस्थास्त्र दिया जाने क निम्न जुलाई 1968 से भारतीय जनमन पहुँचे म ही क्षय था। जेकिन भारत सरकार का युद्ध मर्यादा म व्यवहार अपनी नीति का निर्धारण करना था। उन चकोस्लोवाकिया की भीतर जाता का पता था और भारत सरकार सोवियत हस्तान्तरण का घुटभूमि स अवगत थी। इस कारण भारत सरकार ने यह निश्चय लिया कि मास्विन करवाही का निन्दा करने म कार्व नाम नही होने को है। मम चकोस्लोवाकिया का का हित सधने वाला नही था। इसलिए जब भारतीय मस म सास्विन कारवाई की निन्दा के लिए एक प्रस्ताव प्रेषित हुआ तो सरकारो पक्ष न मका विरोध किया और प्रस्ताव गिर गया।

23 अगस्त का सुरक्षा परिषद् म चकोस्लोवाकिया म मास्विन करवाही का निन्दा करने के लिए एक प्रस्ताव पार हुआ। भा न भा उन समय मुक्त पक्ष का सम्मेलन था। भारतीय प्रतिनिधि ने प्रस्ताव म निन्दा म हस्ताक्षर मगना मस रखने का आग्रह किया जब प्रस्तावकों ने ऐसा काम म प्रकार कर दिया तो भारतीय प्रतिनिधि ने मम मन म हिम्मा नही लिया। ऐसा करने क लिए

1. सुरक्षा परिषद् म अग्र भगना और निन्दा वाली प्रयाग को स्वर भारतीय प्रतिनिधि ने मन्दात करी से स्वर किया जब दार्जिलिंग वाष्टी म अग्र सम्पादकीय म व्यक्त किया कि भा त न रस की निन्दा न कर भगना का। इसकी हम भगना नही निन्दा करत हैं।

विदेश नीति का एक जटिल अंग हो गया। सोवियत संघ ने पाकिस्तान को न केवल हथियारों से बल्कि पाकिस्तान के नेताओं से संबंधित समस्याओं पर कई बार बातचीत की।

भारत सरकार ने सोवियत विप्लवों के तथा पर अपने विरोध प्रकट किया। अक्टूबर 1970 में राष्ट्रपति की वी. वि. गिरिन सोवियत मध्य की यात्रा की और वाता. क. दौरान सोवियत नेताओं का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया। इन छोटे मोटे मतभेदों के बावजूद सोवियत संघ और भारत की मध्मी में एकमात्र भी कमी नहीं आया है।

भारत सोवियत मध्य

भारत और सोवियत मध्य की संधि—अगस्त 1971 में भारत और सोवियत मध्य के सम्बन्धों में नाटकीय घटनाएँ घटी और एक-एक राजनयिक स्तर पर सरगर्मी आ गयी। 3 अगस्त को मास्को स्थित भूतपूर्व भारतीय राजदूत का डी. पी. घ. बड़े ही गोपनीय ढंग से मास्को पहुँच और सोवियत नेताओं से मुलाकात की। इसके बाद ही यह घोषणा की गयी कि सोवियत विदेश मंत्री ए. ए. ग्रामिन्को 8 अगस्त को भारत पहुँचेंगे। ग्रामिन्को की भारत यात्रा का राजनयिक क्षेत्र में बड़ा महत्त्व दिया गया और ऐसी आशा की गयी कि इस यात्रा का कोई बड़ा ही निर्णायक परिणाम निकलगा। इस बीच भारत और सोवियत मध्य के बीच होनेवाली संधि का प्रारूप तयार हो चुका था। ग्रामिन्को के भारत आगमन का मुख्य उद्देश्य इस संधि पर हस्ताक्षर करना था। यह सारा काम इतना गोपनीय ढंग से हुआ कि किसी को पता भी न चला आभास नहीं मिल पाया। केवल अफ़कनवाजियों का बाजार ही गन रहा। यह कहा जाता रहा कि भारत के लिए इस संधि के समय प्रोमिका सोवियत मध्य की ओर से हमारे साथ एकजुटता प्रकट करने आय है।

भारत पहुँचने पर ग्रामिन्को का बड़ा मध्य स्वागत हुआ और वे गीत हा. म. रतीय विद्या मन्त्री से मन्त्रणा करने में सफल हो गये तथा 9 अगस्त को सबेरे भारत और सोवियत मध्य के बीच शांति मित्रता और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर हो गये। संधि की घोषणा अत्यंत नाटकीय ढंग से हुई। सबेरे ही वजे प्रधानमन्त्री ने मन्त्रिमण्डल की विषय वृत्त बुलायी और उसमें इस संधि पर औपचारिक स्वीकृति दी। कि भारत की ओर से सरदार स्वर्ण सिंह ने और सोवियत मध्य की ओर से श्री प्रोमिका ने मध्य पर हस्ताक्षर किये। प्रधानमन्त्री ने सभ में गिरावा दानों के नेताओं की वृत्त बुलाकर संधि के बारे में उन्हें बताया। बाद में सरदार स्वर्ण सिंह ने सभ के दानों रत्नों में तालिया की गडगडाहट के बीच संधि की प्रतियाँ पेश कर दीं।

सोवियत विदेश मन्त्री श्री प्रोमिका की इसी यात्रा का यह नाटकीय परिणाम भारत का विदेश नीति में नूतनपूर्ण मोड़ का सूचक था। यह पहला अवसर था जबकि भारत एक बड़े राष्ट्र के साथ ऐसी संधि मन्त्रीक द्वारा जिनका मन्त्रिक और रक्षा के मामलों में विषय महत्व है।

संधि का सबसे प्रमुख धारा यह है कि दानों में संधि के दान पर हमला

होन या हमले का खतरा हान पर आना देश सीमा ही परस्पर विचार विमर्श करेंगे ताकि एस सतरे का समाप्त किया जाय और दोनों देशों की शांति तथा सुरक्षा का सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रभावकारा कदम उठाया जाय । इसका अर्थ यह है कि यदि पाकिस्तान या चीन न या दोनों ने मिलकर भारत पर हमला किया तो सावियत संघ हमारा सुरक्षा के लिए प्रभावकारा कदम उठाएगा । संधि के अनुसार दोनों देश एक दूसरे पर किसी प्रकार का आक्रमण नहीं करेंगे । एक दूसरे के अतिरिक्त किसी सैनिक गठबन्धन में शामिल नहीं होंगे तथा दोनों देशों में किसी पर हमला करवा बाध नौकरे देश का किसी प्रकार की सहायता नहीं देंगे । संधि के अनुसार भारत और सावियत संघ इस बान के लिए भा राती हुए कि वे अपने क्षेत्र में किसी प्रकार के ऐसे कार्य का नहीं हाने देंगे जिससे दूसरे पक्ष का सैनिक क्षति होन की आशंका हो ।

हमनावर देशों के बराबर पर विजय गिरानवाला इस संधि में सैनिक सहयोग की अवस्था धाराओं है यद्यपि इसे सैनिक संधि या रक्षा संधि नहीं कहा गया है । इनके अनुसार यद्यपि यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक देश पर हमला दूसरे देश पर भी हमला माना जायगा परन्तु समझौते की शर्तों के बजाय उसका भावना बही है । संधि में दोनों देशों के बीच आर्थिक वित्तिक तकनीकी तथा सांस्कृतिक सहयोग लगातार सुदृढ़ करने का दृढ़ निश्चय प्रकट किया गया ।

उह पृष्ठा की इस संधि में पहला पृष्ठ प्रस्तावना का है जिसमें दोनों देशों का शांति और सह अस्तित्व की नीतियों का बखान किया गया है । संधि के तुरन्त बाद धाराएं हैं । एक मन्त्रालय के भीतर संधि की पूर्ण दोनों देशों न करे और दस्तावेजों का आदान प्रदान करके यह लागू कर दी गयी । आरम्भ में संधि बीस साल के लिए है तब बाद में संधि का अवधि समाप्त होने से बारह महान पहल समझौते करने की नीति में दे सकता है । उसी नीति के अन्तर्गत संधि का अवधि स्वतः हर बार पांच साल के लिए बढ़ जायगी । इसका अर्थ यह है कि यह संधि हमारा हमला बन सकती है ।

प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने विराघा दोनों के मन्त्रालयों की बैठक में इस संधि की सूचना देते समय बताया था कि यह सैनिक संधि नहीं बरन एक मत्री संधि है । संधि पर हस्तक्षर करने के बाद पत्रकारों का सावियत विदेश मंत्री श्री ग्रामिन्का ने बताया कि यह संधि अत्यन्त महत्वपूर्ण है और सावियत संघ इस संधि को बहुत अच्छा मानता है । तात्पर्य में संधि की एक प्रति पत्र करते हुए सरदार स्वर्ण सिंह ने कहा कि यह संधि केवल हमारे दोनों देशों के बीच नहीं बरकि हम नमूने क्षेत्र के लिए शांति सुरक्षा और विकास का व्यापक दान के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा । हम इस तरह का संधि हान से यही शांति स्थिर होगा तथा हम क्षेत्र के देशों की अतृप्तता और प्रमुखता का धन मिलेगा । विदेश मंत्री ने कहा कि यह संधि अत्यन्त शान्ति के लिए है और अब हमारी आजादी पर हमला करनेवालों का निम्न नहीं होगी । उन्होंने इस बान पर बार किया कि

इस संधि से गुट निर्देशता की हमारी नीति मजबूत होगी तथा अंतर्राष्ट्रीय तनाव कम करने में सहायता मिलेगी।

सरदार स्वर्ण सिंह ने आश्वासन दिया कि भारत सरकार की शांति नीति आज भी उतनी ही दृढ़ है जितनी कि पहले थी। किसी दूसरे देश के खिलाफ यह संधि नहीं है और न किसी ऊपरी दश की आर हमारी निगाह है। लेकिन इसके साथ हम किसी देश के आक्रमण की घमकी का बरतारत न करेगा।

संधि के उपलक्ष्य में राजि में सरदार स्वर्ण सिंह ने श्री प्रेमिनी की दावत दी जिसमें भारत तथा सोवियत संघ की शांति मंत्री के जाम पीये गये। इस अवसर पर प्रेमिनी ने कहा कि भारत और सोवियत संघ के बीच यह मैत्री संधि हमारे पिछले पंद्रह वर्षों के प्रयास की चरम परिणति है और इससे विश्व शांति का आधार मजबूत होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह संधि किसी देश के विरुद्ध नहीं है।

संधि का स्वरूप

यह कोई सैनिक गुटबन्दी नहीं है—सोवियत संघ और भारत की यह संधि किसी भी दृष्टिकोण से एक सैनिक गुटबन्दी की संधि नहीं बनी जा सकती। भारत के विदेश मंत्री ने यह दावा किया कि भारत अपनी नीति का परिष्कार कर सोवियत सैनिक गुट में शामिल नहीं हुआ है। संधि में यह व्यवस्था नहीं है कि भारत पर स्वयंसेवक सोवियत संघ पर किया गया हमला माना जायगा जसा कि अमेरिका द्वारा की गयी ताटो छिटाटो तथा सटो सैनिक संधियों में या सोवियत संघ के तत्वावधान में की गयी बारसा संधि में लिखा गया है। इस संधि में तो केवल यह व्यवस्था की गयी है कि दोनों में से किसी पर आक्रमण का खतरा उपस्थित होने पर दोनों पक्ष सीधे ही विचार विमर्श करेंगे ताकि खतरे को समाप्त किया जाय और दोनों पक्षों की शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए समुचित और प्रभावकारी कदम उठाये जाय। इन दोनों के जरिये भारत न किसी भी प्रकार अपने को सोवियत संघ के सैनिक गुट में नहीं बांधा है। इसलिए किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यह संधि किसी देश या देश विशेषों के विरुद्ध है। यह तो भारत और सोवियत संघ के मध्य मैत्री सम्बन्ध और शांति की संधि है। इसका एकमात्र उद्देश्य आक्रमण या आक्रमण की आशंका का निवारण है। सोवियत संघ के साथ भारत ने संधि अवस्था की है कि तुम्हारे गुट के विरुद्ध शांति की संधि है। उसका मार्ग प्रवर्तक सैनिक उद्देश्य नहीं है। सैनिक गुटबन्दी की सजा इस बदायि नहीं दी जा सकती है। यह सही है कि दोनों में से किसी देश पर किसी तीसरे देश ने आक्रमण किया तो उसके प्रतिकार के लिए वे एक दूसरे की सहायता को तयार रहेंगे और इस सम्बन्ध में आवश्यक विचार विमर्श करेंगे। किंतु आप से-आप बिना बुलाये ही मित्र देश की मदद के लिए मगान में नहीं उतर पड़ेगी जसा कि सैनिक गुटबन्धनवादी संधि के परिणामस्वरूप होता है।

हमल के खिलाफ भारत—भारत और सोवियत संघ के मध्य की गयी शांति मैत्री और सहयोग की संधि पाकिस्तान के सम्भावित हमलों के खिलाफ एक

तब जो भारत की। मुश्किलता ज्यों न यह निश्चय जिया कि काइ तानरा दग
 जनों में न किता एक पर जगजाग कर ता द उसक नितकार क लिए एक दूसरे स
 पानग करेग। हमका सीना मनुष्य यदु उबर न। है कि जन्में स एक जाह्नम
 वारी पर हमका क लान्तु दग भा नहीं कहा ज मुकता कि व लपगप है।
 जब परामग हागा तो उसम जाकनए क प्रतिकार का उपाय माना जाए। नकला
 न जागा। हमलिए हमका जग मुनिक मुहानता भा हा माना था। यदु भा हा
 मुकता था कि उस उपाय का स्वप्न बूट बी हो हा। मनुष्यता जाह्नम का
 जाह्नम की जागका क नम हन स =। यदि वह खन हा जाता है तो नित क
 लिए और क्या बचाए ह।

मुश्किलता यह भी निष्कप निवृत्त है कि इन जनों ज्यों पान नता वन
 वानों का जनों दगों में स काइ हथियार नहीं जगा। मनुष्य यह है कि चीन क
 प्रोमान स यदि पकिस्तान न भारत पर हमला किया तो सोवियत मुघ उस किता
 प्रकार का हथियार नहीं देगा। इसके अलावा यह भी भय नहीं रहता कि सोवियत
 मुघ भारत पर हमला करन वानों का जग किता राज नितिक स्वाय के काप
 मजग जगा। भारत पान जगजाग - विनाश सोवियत मुघ का कारबाइ का जागजा
 किता भा जाह्नम क विरुद्ध अदराध न काम (work as deferrent) कगा।

जग नितिक स दखन में एसा प्रभाव हाता है जि भारतियों क मनावन
 का क वा रखन क लिए यह मुश्किलता बढाया। इतर पिछन क ज्यों स जग
 राष्ट्रीय राजनिति में भारत जगजाग पान गया था। वनका जग का घन का जग
 यह जगजाग जगजाग ही दु जगजाग हा गया था। वनका जग का भाग न मुहार
 को राजन के लिए भारत न मुहार क नामग सभी ज्यों स जगजाग की जग दग
 मजियों तथा मजियों का विरुद्ध भजा ठाकि मुहार क जाह्नम तथा विभिन्न सर
 कारों का जगजाग जा मुक। जगिन भारतिय प्रयत्नों का का नतीजा नहीं निकता।
 जगके फलस्वरूप पकिस्तानी जगजागह जगजाग जाहा खाँ का जगजाग दग
 जुनग हा गया। मुमुकत राज अमरिका क प्रास्ताहन तथा चान का अनिश्चित नीति
 स उन्माहित होकर क भारत का बार-बार मुद का बमका न रह थ। उनका ह्यान
 था कि भारत जगजाग पड जागा और इसलिए मजनाठ हो जागा। तन न जग
 रिका न भा पकिस्तान का बमका क साथ अपनी बार स यह घमकी न डाना था
 कि यदि भारत और पकिस्तान में सग हूँ और चान न पकिस्तान का पस
 दिया तो अमरिका भारत का मुहायता क लिए नहीं जागा।

अतएव इस मुश्किलता क जग पकिस्तान का हा नहीं वरन अमरिका और
 चान का भा स्पष्ट न स मजान न गया कि भारत पान हमला किया गया ता
 सोवियत मुघ भारत का मुहायता क लिए बढाया। मुनिक जगजागों का हमला
 कन स पल हजार बार मावता हाता।¹ दानों पनों स स किता पर जाह्नम

1 जसा कि एक भारतिया मनाचारदग न जिम्मेदार बन गए जिया था

मुश्किलता का यह बत है वह बग फलामिना है। बाता जग न जग स्वाय का
 मुद करन क लिए पकिस्तान भारत स उदाइ मान एन का पिछ बूट मुन स
 कागिज कर रहा है। वह मावता है कि चान और अमरिका जगजाग पाठ पर है।

होने की स्थिति में दूसरा तो शान्त परामर्श और कार्य करता—संधि की यह व्यवस्था पाकिस्तान को भारत पर अक्रमण करने के पक्ष में तब तक अमरिका से इजाजत देने पर मजबूर करता। "यह तब" भारत का एक ठोस पाप। हुआ कि वह पाकिस्तान से पाकिस्तान की शर्तों पर युद्ध और अनंतर अमरिका का शर्तों पर समझौता करने से बच गया। "यह प्रकार" यह संधि न भारत के अनेकपक्ष का दूर कर तथा सुरक्षा प्रदान कर उससे आत्मविश्वास की भावना का संचार किया। यही कारण है कि देश के अक्रमण सभी शर्तों द्वारा इस संधि का बेहू स्वागत हुआ। यही तक कि जनसमूह और स्वतंत्र पार्टी जसा दक्षिण पक्षी राष्ट्रियों ने भी इसका स्वागत किया। सारा वातावरण युद्ध के आगमन से जितना तरह-बातिल था उससे पाकिस्तान के आक्रमण विभाग का ठंडा करने का यह उपाय हुआ दसकर पहले जन की सोच लाना आवश्यक था।

सोवियत भारत मंत्री का एक नया अध्याय—भारत और सोवियत मध्य पुराने दोस्त थे और उनका दोस्ती का इतिहास भी बड़ा गानदार था किन्तु सोवियत विदेश मंत्री प्रोमिको के भारत आगमन के बारह घण्टे बाद ही दोनों देशों के बीच जिस बीत वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर हुए उनमें इस दास्ती में एक नयी जिदगी का सूत्रपात किया। भारत यह न। भूल जाना कि सोवियत मध्य न मरुट के समय में उसकी सहायता की। "कमीर" का मामला में अंग्रेज-अमरीकी गुट का पानों का अपने वोटों अधिकार का उपयोग करके सोवियत मध्य न सुरक्षा परिषद में अग्रण किया गया की आवश्यकता के लिए हम विमान ही नहीं। ये मिय विमान बनाने का कारखाना दे दिया जबकि अमरिका ने हम विमान देने। इनकर करके पाकिस्तान को समझपक तथा सहाय विमानों का अलावा भारत पर हमला के लिए सभी तरह के हथियारों से लस किया। जब किसी न हमें पनहुटिया नहीं। तो सोवियत मध्य ने पनहुटिया दी। मिलाई और वाकरो के इस्तेमाल कारखाने भाषान और हरिण के बिजली के भारा यंत्रों के कारखाने तथा सेन की सोज और उन साध करने के कारखाने देकर सोवियत मध्य न हम मजिज सेन के विश्व रक्षण पर लक्ष्य कर दिया और इस निष्ठा में आत्म निभरता की ओर अग्रसर हो गये।

यह सही है कि 1962 में चीन का सैनिक कारवाई की सोवियत मध्य ने तुरंत आग्रहना नहीं की लेकिन कुछ देर बाद उसने चीन की नि। हो नहीं की भारत को चीन का मुकाबला करने के लिए भारी पैमाने पर हथियार प्रदान की।

सोवियत मध्य इन झगड़ों में फँसना नहीं चाहेगा और इस प्रकार भारत बिस्कुन अकेला पड़ जायगा। परन्तु इस संधि से उसका यह भारा मधुर स्थान टूट जायगा। युद्ध की आशमनियाँ वह आज दे रहा है वह मधिव्य में भी दसकेगा इनकी सम्भावना इससे कम हो जायगी। जब उस यह पता होगा कि भारत की पाठ पर कम है तो अमरिका और चीन की यह मिलने पर भी वह भारत पर आक्रमण करने से पहले सोच सोचेगा। कहना न होगा कि सोवियत मध्य और भारत का बीच यह संधि एक समय में हो रही है जब इस उपमहादीप में शांति की यात्रा टगकी यह आय यकता था।

ज्ञान सावित सघ क भारवाहक विमानों से ही उद्धार के सीमांत पर तनात भार तीय मं को का सपनाइ मिलती है ।

दोनों देशों के सम्बन्धों में यादा सा तनाव तब आया जब 1968 में सोवियत सघ ने पाकिस्तान को कुछ हथियार बेचने का निश्चय किया था । लेकिन यह तनाव तब ही समाप्त हो गया क्योंकि सावियत सघ ने एक साल से भी ज्यादा समय से पाकिस्तान का काम हथियार नहीं दिया ।

दगला दंग के तवाल पर सोवियत सघ का रवया भारत में लगभग मिलता जुलता रहा । आरम्भ में ही सावियत सघ ने पाकिस्तान को लिखकर स्पष्ट कर दिया कि वह मानव हत्या समाप्त करके राजनतिक हन चाहता है । भारत की आर से भी लगातार राजनतिक हन की बात कही जाती रही थी ।

इस प्रकार 1955-56 से ही भारत और सावियत सघ में सहयोग चल रहा था । लेकिन इस संधि के सम्पन्न होने के बाद अब यह सहयोग नयी गति से चला । इससे दोनों देश न केवल एशिया और विश्व में छांति स्थापना तथा प्रजातीय एवं उपनिवेशवाद का खतम करने में पहुँचने में वहाँ अधिक सहयोग करेंगे अरितु यह सहयोग शिक्षा, संस्कृति तथा व्यापार के क्षेत्र में भी पहले से अधिक विस्तार पा सकगा । संधि की जा धाराएँ हैं उनमें न बातों का स्पष्ट उल्लेख है ।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में नवीनतम प्रवृत्तियों के उभार की स्वाभाविक प्रतिक्रिया—जिम नाटकीय तत्परता से संधि सम्पन्न हुई उससे साफ जाहिर है कि चीन-अमरिका मंत्रा की सम्भावना से न मिलिन और दिल्ली समानत भयभीत हुए थे । एशिया में दोनों के हित अहित समान थे । अतः भारत सोवियत संधि भारत सावियत हितसाम्य की औपचारिक पुष्टि और विराधी हितों के लिए चनावना था । जिस तत्परता से सावियत सघ ने संधि पर हस्ताक्षर किये उससे यह सिद्ध हो गया कि वह एशिया की राजनीति में अपना दखल कायम रखने की इतत सकल्प है और ढील-छान नीति बरत कर अन्तिम अवसर गवाना उसे सह्य नहीं । अमरिका चीन मेंलजोल सोवियत सघ की बहुरदक्षिता और विलम्ब वृत्ति के कारण हा सम्भव हो सका । यदि भूतपूर्व सोवियत प्रधानमन्त्री ख्रुश्चोव ने तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति आइजनहावर से शीपस्तरिय मन्त्रणा करने के बाद वात्ताजाप को सोहसाग आग बनाया होना और यदि सावियत सघ ने अपने चेकास्लोवाकिया अभियान के अन्य राष्ट्रीय परिणामों का मनकतापूण अध्ययन किया होना तो अमरिका सावियत सघ से विमुख होकर चीन की आर उन्मुख न हुआ होता ।

भारत सावियत संधि प्रस्तावित चीन अमरीकी प्रेमालाप का स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी इसमें सन्देह नहीं । लेकिन इसकी पृष्ठभूमि यहाँ तक सीमित नहीं थी । चीन-सोवियत मतभेद हिंद तथा प्रशांत महासागर में ब्रिटेन के हटन की प्रक्रिया और विपत्तनाम-युद्ध के दलान में किसी तरह पुनकारा पाने की अमरीकी शक्ता के सम्बन्ध में हिंद महासागर की राजनीति बड़ी दिलचस्प हो गया थी । पश्चिमी एशिया में कम्युनिस्ट विरोधी उपस-मुपस के बाद सोवियत सघ की एशियाई राज

नीति में दखल बनाए रखने के लिए भारत पर आघात होना पड़ गया। ब्रिटेन और अमेरिका के हटने से हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में जो शक्ति गठना उत्पन्न हो गयी उससे चीन को सबसे बड़ा लाभ होगा। भारत और सोवियत संघ दोनों को ही यह गवारा नहीं था। चूंकि निम्न भविष्य में भारत-चीन सम्बंधों में सुधार की सम्भना नहीं थी अतः सामरिक दृष्टि से कमजोर राष्ट्र भारत को भी सोवियत संघ पर आश्रित होना पड़ा।

एन गैर कम्युनिस्ट देशों के साथ सोवियत संघ का शान्ति मित्रता और सहयोग की यह दूसरी संधि है। भारत से संधि सम्पन्न करने के पूछ सोवियत संघ मई 1971 में इसी तरह की एक पाँच वर्षीय संधि समुक्त अरब गणराज्य से कर चुका है।¹ सुवर्ण अरब गणराज्य के साथ सोवियत संघ की संधि समझ में आ सकती है क्योंकि पश्चिम एशिया के महाद्वीप में अरबों की सहायता के लिए वर्षों से बचनबद्ध था लश्करि भाग्य के साथ उसका गठन हुआ राजनय की एक चमत्कार प्रतीत होता था। भारत सोवियत संधि न समूच विषय और साक्ष्य सौर पर एशिया को उचित कर दिया। पश्चिम एशिया के मध्य में सोवियत सहायता तथा समझौते के बल अरबों की हार के कारण सोवियत सहायता की साम्य का काफी आघात लग चुका था। क्यूबा और पश्चिम एशिया में पराजय के बाद सोवियत संघ के जीवन में परिवर्तन हुआ जिम्मा प्रतिगमन भारत-सोवियत संधि में हुआ। अब सोवियत संघ मात्र सत्ता और समयन तक सीमित नहीं रहना चाहता था क्योंकि भारत एशिया में उनका अंतिम मुड़ ग है जिसे गवाना उम गवारा नहीं था। भारत सोवियत संघ की एशियाई राजनीति का सबसे प्रथम उपकरण था और भारत का भी सोवियत संघ की भारी अर्थरायी। दोनों के हित परस्पर अभिन्न और भारत सोवियत संधि इसकी औपचारिक विस्तार अभिव्यक्ति थी। चीन अमेरिका मित्रता के साथ में पूर्वी यूरोप के कम्युनिस्ट राज्य भी चाहते थे कि सोवियत संघ इस गठननम अंतर्राष्ट्रीय घटना का मुकाबला करने के लिए कोई राजनयिक काम उठाये। भारत सोवियत संधि बारसा संधि के देशों का अभिसारा का भी एक प्रतिफल माना जा सकता है।² एशिया में एशियाईयों को आपस में लड़ाने की ओर एशिया में सोवियत संघ और चीन भी शामिल है तथा अमेरिका पहल का यह सोवियत जवाब था।

एन और इन संधि से भारत का नाम हुआ ता दूसरी ओर सोवियत संघ

1 भारत ने लिए भी शान्ति मित्रता और सहयोग की यह दूसरी संधि है। इससे पूर्व 1951 में नेपाल के साथ भारत की एक संधि हुई थी। पर उसका शर्त सीमित था

2 In the Soviet bloc countries the treaty is a diplomatic riposte to the global strategy against China. Outdone by Wuhan in the month the Soviet bloc countries have been searching for a Soviet Asia initiative to counter the American commitment of the United States President to visit Peking

—The Indian Express August 10 1971

का भी कम लाभ नहीं हुआ। सावियत सघ कुछ समय से चीन से टकराने के दर से चिन्तित था और राष्ट्रपति निकसन की प्रस्तावित विजिट यात्रा से तो सावियत सघ और भी ज्यादा इस बारे में चिन्तित हुआ। इस संधि के अनुसार सावियत सघ और चीन के बीच सघ के समय भारत मास्का के साथ होगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम चीन से उठने को सावियत सघ की ओर से अपनी सुना भेज देंगे। केवल उस संधि से ही चीन का यह भय रहेगा कि यदि वह सोवियत सघ के साथ युद्ध में पड़ा तो भारत भी जिनकी ओर से उसका मुकाबला कर सकता है। इस प्रकार चीन दक्षिण की ओर से अपना सारा मनो हटा कर सोवियत सघ के खिलाफ नहीं लगा पायगा।

चीन अमेरिका के प्रभुत्व में तलना—दोमर्ची गतागत क इस आठवें दशक के साथ अंतराष्ट्रीय सम्बन्धों में एक नया शृंखला शुरू हुई जिसके दूरगामी परिणाम आकर आसान नहीं। केवल एक महीने के भीतर एतिहासिक महत्व का दो घटनाएँ घटी। एक तो अमेरिकी राष्ट्रपति निकसन की विजिट में नियंत्रण और दूसरे भारत तथा सोवियत सघ के बीच शांति मंत्री और मंत्रियों की यह बीस वर्षों की संधि। दोनों युगांतरकारी घटनाएँ थीं जिनके परिणामस्वरूप विश्व राजनीति एक नया रूप ग्रहण करने लगी। लेकिन इन दोनों घटनाओं का उत्पत्ति के स्वरूप तथा सम्भावनाओं में बड़ा अंतर था। पहले मामले (निकसन की प्रस्तावित चीन यात्रा) में बीस वर्ष से लड़त आ रहे दो प्रचंड शत्रु एक एक दूसरे और नये दाय-बैच की तराश में सौंस उठने के लिए परिस्थितिका हाथ मिलाते की मजबूर हुए थे। लेकिन भारत सोवियत संधि में क्रमशः विकसित बीसवर्षीय मंत्रा का स्नेहाभिमान सम्पन्न हुआ।

चीन और अमेरिका के नेता उन उद्देश्यों अथवा सकारणों से प्रेरित नहीं हुए जो भारत-सोवियत मंत्री संधि में निहित थे। चीन और अमेरिका के नेताओं में विचारों की धारणाओं की ओर दोषकांशीन उद्देश्यों की बहुत बड़ी खाँची जिस केवल राजनय से पाट नहीं सकते थे। दोनों सावियत सघ को अपना प्रतिद्वंद्वी मानते थे और उसका नीचा दिखाने का प्रयास करते थे। दूसरी ओर भारत और सावियत सघ के बीच ऐसी गहरी या दमनस्य की पृष्ठभूमि नहीं थी। भारत और सावियत सघ के बीच विकसित राजनीतिक आर्थिक और सांस्कृतिक सम्बन्धों दोनों का लिए लाभदायक सिद्ध हुआ। राजनयिक स्तर से देखने में एक स्वाभाविक लगता है तो दूसरे में कृत्रिमता का अंश बहुत ज्यादा प्रतीत होता है। एक दो दशकों की मित्रता की परम्परा की धरम परिणति थी तो दूसरा उन अमुककर परिस्थितियों का तात्त्विक परिणाम था जिन पर न अमेरिका का बड़ा या और न चीन का। मनु मिलाप करने के लिए चीन और अमेरिका बाध्य हुए लेकिन भारत सोवियत संधि स्वाभाविक रूप से विकसित हुई। यह केवल तात्कालिक उद्देश्यों से निपटने के प्रयास का फल नहीं क्योंकि इसकी उत्पत्ति आज से लगभग दो वर्ष पहले हो चुकी थी।

संघि की उत्पत्ति—संघि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में बोलते हुए सरदार स्वर्ण सिंह ने बताया कि इसके लिए बार्ताएँ दावप पहल से हाथ चल रही थीं। केवल यही तथ्य कि संघि का मसविदा तीन भाषाओं—हिन्दी, रूसी और अंग्रेजी में तैयार था और तीनों प्रतिपों पर हस्ताक्षर किये गये—संघि की ओर संकेत करता है कि संघि पर काफी समय से विचार विमर्श हो रहा था। वस्तुतः संघि प्रस्ताव का मसविदा पिछले दो वर्षों से तैयार पड़ा था लेकिन इस पर हस्ताक्षर करने से भारत कतराता था। सरदार स्वर्ण सिंह का यह दावा भी बिना टोक था कि संघि होने और संघि से पहले हुई बातों को पूरी तरह गोपनीय रखा गया था। इस गुप्त रखने का कारण यह था कि श्रीमती गाँधी ने हम मामलों में टीका वसा ही गतकता करती थी जहाँ कि राष्ट्रपति निरमल ने किसिज़र की विविध यात्रा का एकत्रित गणनायक बनाकर करती थी। यह आवश्यक भी था। यदि संसार को इसका पूर्वामम ज्ञात तो सम्भव था कि सोवियत तथा भारत विरोधी तत्त्व जहाँ न सक्रिय हो जाते और संघि के मार्ग में राड़े अटकाने में बाज नही आते। हमारे अनिश्चित ऐसी नाजुक संघर्षों विचार प्रसार का मर्यादित साधनिक बार्तालाप और पत्राचार की अपेक्षा रहती है।

1969 के आरम्भ में चीन और सोवियत संघ के बीच सीमा विवाद ने योना सम्भार रूप धारण कर लिया जब कि माच में उमूरी नदी के टाप दमिश्क को नहर दोनों में एक मासूली मन्त्रि निहत हो गयी। यह घटना सोवियत संघ के लिए एक चेतावनी थी। सोवियत संघ ने मसूमा किया कि चीन के साथ उसका सगंठा सद्भावितक स्तर तक भी सीमित नही रह गया है इसकी परिणति दोनों के मध्य प्रवेश टकराव में भी हो सकती है। इस सम्भावना के विरुद्ध उपाय करने के लिए सोवियत राजनय सक्रिय हो गया। संघि बाता आज से दो वर्षों में भी अधि-समय में उस समय शुरू हुई थी जब राष्ट्रपति डा. जकिर हुसैन की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए 6 मई 1969 को सोवियत प्रधान मंत्री कामिज़िन स्वयं नयी दिल्ली आये थे। उस समय इस बात पर अत्यधिक आश्चर्य व्यक्त किया गया था कि दाना प्रधान मंत्रियों की उस बार्ता के दौरान बहो को भी भारतीय दुभाविया मौजद नहीं था। अब यह मानकर चना जा सकता है कि उस समय एता शिष्ट इसलिए किया गया था कि उन नाजुक बार्ता के सम्बन्ध में किसी बात का एता बाहर न चला जाय। सम्भवतः इसी बार्ता में प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी सोवियत संघ के साथ एक संघि के लिए तैयार हो गयीं। 5 जून 1969 को सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी लियोनिड ब्रजनेव ने एशियाई देशों से सामूहिक सुरक्षा के लिए एक सम्मेलन आयोजन करने का प्रस्ताव रखा। चीन की आरंभ में आनेवाले सतर्कों की आर सकेत करने हुए उन्होंने कहा कि एशियाई देशों को मिलजुल कर अपनी सुरक्षा को कठिनों को मजबूत करना चाहिए। जन में सप्रिम सोवियत में बोलते हुए सोवियत विशेष मंत्री ने पुनः इस प्रस्ताव को दुहराया। लेकिन सोवियत संघ के इस मन्त्राव पर किसी एशियाई देश ने ध्यान नहीं दिया। भारत ने इस पर अभी भी सम्भारतापूर्वक विचार नहीं किया।

पर भारत के साथ भी चीन का सीमा विवाद था जिसको लेकर भारत और चीन के बीच 1962 में युद्ध हो चुका था। चूंकि इस मामले में भारत और सोवियत संघ के हित समान थे अतः सोवियत संघ ने भारत के साथ एक सुरक्षा संधि का प्रस्ताव रखा। सोवियत मना-पस मानव प्रकोपी सुरक्षा संधि के मसविदा के साथ फौरन भारत भेजा गया। भारत सरकार का सोवियत संघ के प्रति पूरा सहानुभूति थी और एक समय भारत सरकार उस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार भी हो गयी थी। लेकिन अंतिम क्षण में भूतपूर्व विदेश मंत्री दिनेश सिंह ने हस्ताक्षर के काम को स्थगित करने की सलाह दी और प्रधान मंत्री श्रीमता इंदिरा गांधी उनसे सहमत हो गयी।¹

हस्ताक्षर का स्थगित करने के पक्ष में भारतीय विदेश मंत्रालय का पहला तर्क यह था कि सोवियत संघ से प्रस्तावित संधि के तहत से भारत का गुट निरपेक्षता का नीति पर प्रयोग को मजबूत होने लगा। दो महान गुटों के सुरक्षा समन्वय से अलग रहना ही गुट निरपेक्षता की पहचान थी। प्रस्तावित भारत सोवियत संघ का मसविदा चीन तथा सोवियत संघ की तीस वर्षीय संधि से बहुत कुछ मिलती जुलती थी। इस संधि के कारण ही चीन सोवियत गुट का सदस्य माना जाता था। अब भारत को काट भा गुट निरपेक्ष नहीं कह सकता था।

जिनोयत 1969 में यह साबित हुआ कि एक औपचारिक संधि से बंध जान की जगह भारत का हित इसी में है कि वह सोवियत संघ के साथ मधुर सम्बंध कायम रखे और एम सम्बंध का कायम रखने में सहयोग देता रहे। सोवियत संघ में एक संधि में बाधित हो जाने से अमरिका तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों उसका प्रतिकूल प्रतिक्रिया हो सकता थी।

इसके अतिरिक्त ठीक उसी समय कांग्रेस का बगलार अधिवेशन हुआ और मुत्तासिल पार्टी में भेदक फैल पड़ गयी। इस पक्षस्वत्प लाकसभा में श्रीमता इंदिरा गांधी को पार्टी का स्पष्ट बहुमत नहीं रहा। लोकसभा में राजनीतिक दल का ऐसा दलगत स्थिति था उसमें यह सम्भव नहीं था कि सोवियत संघ से एमो किसी संधि को समन्वय पुष्टि मिल जाता। अतः भारत सरकार सोवियत संघ से एक औपचारिक संधि करने में कतरा गया।

म 1971 में बगलार दल की राजनीति ने भारत के समक्ष एक विकट परिस्थिति उत्पन्न कर दी। बगलार दल की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार भारत पाकिस्तान के सम्बंधों में तनाव के बर्तन के कारण अवगत करने के लिए भारतीय विदेश मंत्री नरदार स्वर्ण सिंह जब जन म भास्का पहुँचता सोवियत अधिकारियों ने एक बार फिर से उस संधि पर हस्ताक्षर करने का मुताव दिया। इस पर विचार करने के बादवास्तविक दल स्वर्ण सिंह मस्का संधि दी गयी।

समय को सँदह नहीं कि यदि बगलार दल की समझा पर अमरीकी सरकार

1. संधि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विवेक जानकारी के लिए देखें—(1) 15 अगस्त 1971 का हिंदुस्तान टाइम्स तथा 18 अगस्त के टाइम्स आफ इंडिया में गिरीलाल जैन का लेख—ट्रिगे डन पण्डिटव ।

या रविया कम पाकिस्तान परक या कम डे-वम तटस्थतापूर्ण होता ता भारत-सावित्र संध सम्भव नत्ता हाती । मास्को ने सरदार स्वर्ण सिंह यागिगत्न पहुँके और अमरीकी अधिकारिया ने उन्हें आवासन निया कि पाकिस्तान को सन्धि सहायता न्हा न्गे । लेकिन जब अत आगमन के बाद भी पाकिस्तान को अमरीकी ह्दियारा की आपूर्ति जारी र्नी और बिमिजर ने भी अपनी भारत यात्रा के दौरान प्रतिरक्षा या प्रतिष्ठा के लिए कोई आश्वासन न्हीं दिया ता भारत सरकार का अमरिका से बही निराशा ूँ और श्रीमती गाँधी ने मास्को से संधि करन का फमला कर निया । इसके बाद उस समय भा जब अमरीकी विदेश मन्त्री श्री राजग ने अमरिका स्थित भारतीय राजदूत श्री एल व झा का यह चेतावनी दी कि भारत-पाक युद्ध में चीन के हस्तन के बावजूद अमरिका भारत को सन्धयता न । करगा ता श्रीमती गाँधी का निश्चय और भी दृढ़ हा गया । 1969 का प्रसिद्धि संधि का जीव को गयी । उसमें पारस्परिक सुरक्षा में सम्बंधित जो धाराएँ या वन भारत के अन्विकाएँ से कुछ कड़ी थीं और भारत पर उनका सामर्थ्य में अधिक उत्तर दायि व डान र्नी थीं । हमने चलने गु निरन्तर का नाति भी समाप्त । र्ना था । अतः उन धारायाँ में हेर-फेर किया गया । कहा जाता है कि वर्तमान संधि को अठ्ठा बीस तथा दसवाँ धाराएँ इसी संशोधन के परिणाम हैं । गुप्त निरपणता से सम्बंधित वर्तमान संधि का चौथी धारा के सम्बंध में कहा जाता है कि यह विद्वान नयी धारा है जो 1969 के संशोधन में नयी थी । इस धारा के द्वारा सावित्र संध ने भारत को गुप्त निरपणता की मर्राहना की ।

1969 के प्रारूप को संशोधित करके के 'एय मन्त्रिपरिषद्' की राजनीतिक मामलात समिति का गान्धीय व न् में मनाया गया जिसने प्रधानमन्त्री के फमल का अनुमोदन कर दिया । संशोधित प्रारूप की प्रति के साथ ही पंधरवाँ धारा का सावित्र संध का रजामन्ती प्राप्त करी के लिए तरफान मास्को रवाना कर दिया गया ।

कहा जाता है कि सावित्र संध का यह जानकर बही खुशी हुई कि भारत सरकार ने आविश्कार उसी ध्यान मान ही ली । आगमन पर बड़े राष्ट्रीय प्रतिनिधि एमी स्थिति में छोटे राष्ट्र के पाम नो जाते हैं । लेकिन सावित्र संध इस मोर्चे का हाथ में न्हीं जाने देना चाहता था । संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए वह इतना आतुर था कि प्रेमिका का तन्त्रान्त्रिणी रवाना कर दिया गया और उनके शिली आगमन के पंधरवाँ घण्टा बाद ही संधि पर हस्ताक्षर हो गये । इन गारी घटनाओं का दलकर ऐसा समझा है कि यह संधि अनिवार्य हा गयी थी और इसे टाला न्हीं जा सकता था । उमता दश की स्थिति पर राष्ट्रपति निवृत्तन के रथवे ने फनस्वरूप भारत के पाम मोहित बिचल रह गये थे । इस अनिश्चित नयी स्थिति में मनुष्य राज्य अमरिका पाकिस्तान और चीन के अन्तर्गत सम्बंधों की तेजी के पीछे पड गया था । वर्तमान संधि के द्वारा इस घटिका दूर करने का यत्न किया गया ।

भारतीय विदेश नीति के इतिहास में एक नया अध्याय—जब से भारत

स्वतंत्र हुआ तब से उसकी विदेश-नीति का मूल आधार गुट निरपेक्षता या असंलग्नता का सिद्धांत रहा है। भारत पर कई तरह के दबाव समय समय पर पड़े ताकि वह नीति का परित्याग कर दे। लेकिन अन्तर्मुखीयत की घटा में भा भारत ने उस नीति का परित्याग नहीं किया। दश के अन्तर बहुत ज़िना से यह भाग हो रहा था कि अंतराष्ट्रीय राजनीति में भारत अकेला पड़ता जा रहा है और इस अकेलेपन को दूर करने के लिए असंलग्नता की नीति का परित्याग होना चाहिए। यह भी कहा जाता रहा कि ममसामयिक अंतराष्ट्रीय राजनीति में असंलग्नता की नीति का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इस नीति का निधारण वस समय में हुआ था जब दुनिया स्पष्टतया दो गुटों में बंटी हुई थी लेकिन 1960 के बाद से गुटबन्धियों का विभाजन रेखा मिटती गयी है और संसार के राष्ट्र प्रमुख तय गिरे से गुटबन्दी में संलग्न हैं। ऐसी स्थिति में 1946-47 में निर्धारित का गया नीति का परित्याग होना चाहिए। किन इन भागों के बावजूद भारत सरकार अपने सिद्धांत पर बड़ी रही और उनसे असंलग्नता की नीति का नहीं छोड़ा।

भारत और सोवियत संघ की संधि ने उस नीति का अंत कर उसका ध्यानपूर्ण रूप से दफना दिया है। लेकिन भारत सरकार ने असंलग्नता की नीति से इतना अधिक माह्र है कि वह अब भी कहता जा रहा है कि यह समझना गलत है कि भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति छोड़ दी है। अगस्त 1971 का निर्देश में एक विंगल 'नमसू' का रची में मध्य कर रहे हुए प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा

बाद माधियन संघ के साथ जो संधि हुई है उसका बावजूद भारत अपनी गुट निरपेक्षता की नीति पर कायम रहता। हमने सोवियत संघ के सामने स्पष्ट कर दिया है कि भारत गुटों की नीति से अलग रहना चाहता है और हमारी बातें उसमें मान ली हैं।

लेकिन प्रधानमंत्री की इस दलील और घोषणा में काइ तथ्य नहीं है। 'ममसामयिक' कहना कि भारत की गुट निरपेक्ष नीति का 'मम' संधि ने अंत कर दिया है। गुट निरपेक्षता की नीति का मतलब महाशक्ति के फौज मध्य एवं तनावों से अपने का दूर रखना होता है। लेकिन एक महाशक्ति के साथ संधि करके भारत अब अपने को इन संधियों तथा तनावों से दूर नहीं रख सकता।¹ भारत के लिए यह संधि गुट निरपेक्षता का अर्थहीनता स्वीकारन के तुल्य है। अंतराष्ट्रीय परिस्थितियाँ और वातावरण के घुटन में असंलग्नता की नीति कब का न दम टाड़ चका थी। भारतीय विदेश में शत्रुता चाह अनचाह उसकी जाह टा रहा था।² अगस्त का घमिकों के भारत आगमन ने उसकी शक्याशा का भाग प्रगट कर दिया और 9 अगस्त को सबर हा उस ज्ञान पर दाह संस्कार किया। भारत सरकार के

1 There is absolutely no doubt that in entering a security arrangement with one of the world's two super powers India has abandoned non-alignment and will in the eyes of many third countries be regarded as having aligned itself with the Soviet bloc — *The Hindustan Times* 10 August 1971

प्रवक्ताओं को ईमानदारी के साथ इस तथ्य को स्वीकार कर लेना चाहिए था।
 आखिर गु निरपेक्षता हमारा एक मान्य मूल्य नहीं है। देश के हित में हम अपनी
 विदेश नीति में परिवर्तन कर सकते हैं और करना चाहते हैं।¹

बंगला देश की राजनीति पर प्रभाव—भारत और सोवियत संघ की संधि
 बंगला देश की राजनीति में उत्पन्न परिस्थितियों का तात्कालिक परिणाम था। इससे
 कोई सन्देह नहीं कि शुरू से ही भारत की सहानुभूति बंगला देश के स्वतंत्रता प्रयासों
 के साथ थी। भारत ने इस बात को कभी भी छिपाने का यत्न नहीं किया।
 और भारतीय मसद ने सहानुभूति एवं समर्थन का एक प्रस्ताव भी पारित किया।
 इसके बावजूद भारत चाहते हुए भी कारगर रूप से बंगला देश की मुक्तिवाहिनी की
 सहायता नहीं कर पा रहा था। बंगलादेश की मांगता स्वर इस्लामावाद के खिलाफ
 उसे प्रत्यक्ष रूप से मदद देने में खराब था। इसका ठेकर भारत और पाकिस्तान के
 मध्य लड़ाई हो सकती थी जिसमें सम्भव था कि चीन और अमेरिका का समर्थन
 पश्चिम पाकिस्तान की ओर मिलता। याहिया खान युद्ध की घमकी भी द दो थी और
 चीन तथा अमेरिका से भारत की चेतावनी भी मिल चुकी थी। उसी हालात में भारत
 अकेले कोई जोखिम भरा कदम नहीं उठा सकता था। सोवियत संघ के साथ संधि
 करके तथा सोवियत समर्थन का आश्वासन पाकर भारत बंगला देश के सद्भाव में अब
 कोई निर्णायक कदम उठा सकता था। इस प्रश्न को लेकर पाकिस्तान के लिए भारत
 से युद्ध करना भी अब तसरे से छाती नहीं रू जाता। अब बंगला देश को लेकर
 पाकिस्तान के सैनिक तांगानाहों के तिन वास्तविक संकट का समय आ गया। यही
 कारण है कि भारत सोवियत संधि की घोषणा ने पश्चिमी पाकिस्तान के अधिका-
 रियों को व्यग्र और अंगात बना दिया। इस संधि पर उनका चिंतित होना या
 घबराना बिनाकुल स्वाभाविक था। जसा कि लंदन में डेली टेलीग्राफ ने भारत सोवि-
 यत संधि पर टिप्पणी करते हुए लिखा था—पूर्वी बंगाल में छापामारों का हथि-
 यार देने तथा उनका सहायता करने में संधि से भारत की अधिक स्वतंत्रता
 मिलेगी। इस संधि के बाद कोई भी पाकिस्तानी सैनिक अधिकारी मोमा के पास
 स्थित छापामार अड्डों पर हमला की हिम्मत करने के पक्ष में बार साचगा। न्यूयार्क
 टाइम्स का कथन था कि यह सन् १९७१ में पाकिस्तान द्वारा भारत पर दिये जाने
 वाले किसी भी हथियार को हटोनाहिन किया जाने का उद्देश्य म की गयी है। इसके
 प्रति का इनका समर्थन नहीं होगा जितना कि बंगाली छापामारों को मदद देने
 का भारत का हीमना बढ़ेगा।

पाकिस्तान इस बात का भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था कि भारत और
 सोवियत संघ के बीच गतिशील मंत्री और सहयोग का बीच बर्षों से सन् १९७१ में अंतगम

1 संधि का गु निरपेक्षता की नीति पर प्रभाव के लिए हिन्दुस्तान टाइम्स
 (22 अगस्त 1971) में प्रकाशित विश्वरूप गुप्त के लेख नीचे आउट साइड की
 कटेस्ट देखिये।

वर्तमान मकद की स्थिति को देखते हुए सोवियत संघ ने भारत का अत्याधुनिक हथियार देने का आश्वासन दिया है। ऐसा समझा जाता है कि अपने नयी शस्त्रा प्रवास के समय ही सोवियत विदेश मंत्री ग्रेमिन्को ने यह आश्वासन दिया कि किसी भी बाहरी आक्रमण की स्थिति में सोवियत संघ की आर स हर प्रकार के प्रत्येक्षात्र पनडुबो तथा जय साज सामान भारत का उपनत्र होंगे। इस हालत में उत्तान भारत पर पाकिस्तानी आक्रमण की आशंका टल गया। इस श्रुति का सन्धान से प्रभावित माना है कि भारत सोवियत संघ का ताकत बढ़ाने की पूर्ति में उठाया गया सोवियत कर्म था। 1966 में सोवियत संघ ने ताकत सम्मेलन की जायवस्था का भी उसका उद्देश्य भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 के युद्ध का औपचारिक रूप से समाप्त कराना था। इस बार सोवियत संघ ने ताकत भावना से प्रारत हाकर युद्ध छिड़ने का सम्भावना का समाप्त कराने का यत्न किया था।¹

भारत में सोवियत प्रभाव की बढ़ि का आशंका—संघि पर श्रुतिपर होने के बाद सरकार स्वयं मिह ने ताकतभा में बालत हुए यह घोषणा भी की कि भारत अन्य देशों के साथ भी इस तरह की संधि करने को तयार है। लेकिन ऐसा करना आसान नहीं होगा क्योंकि भारत सोवियत संघ का सम्बन्ध में भारत के अधिकारों का कुछ अंश में सीमित करेगा है। इस प्रकार की संधि केवल देशों के साथ की जा सकती है जो सोवियत संघ के विरुद्ध नहीं हैं। लेकिन यह सीमा सोवियत संघ का भी बाध होता है। वह भी किसी कम दश (उदाहरणार्थ पाकिस्तान) के साथ ऐसा संधि नहीं कर सकता जो भारत का विरोधी है। इस सम्बन्ध में वास्तव का प्रश्न उठता तो दोनों देश आपस में विचार विमर्श करके इसका नय करेंगे।

यह भाग्य का हा सकता है कि इस संधि के माध्यम से सोवियत संघ भारत में अपने पर फलान का वाणिज्य करे। किंतु ऐसा मानना भी बार् मान नहीं रखता। कम्युनिज्म के विस्तार की इ टा सोवियत संघ के दिल में हो सकता है किंतु संघि में साफ कहा गया है कि एक दूसरे के राष्ट्रीय हित के प्रति सम्मान और विभिन्न राजनीति प्रणालियों के बीच शान्तिपूर्ण सहनस्त्र्व में विश्वास का भावना के साथ चल की जा रहा है। फिर संधि में यह भी कहा गया है कि एक दूसरे का प्रनुमना, एक स्वतंत्रता का दोनों का सम्मान करेंगे और आंतरिक मामलों में हस्त प्र नहीं करेंगे। ऐसा मूरत में सोवियत संघ के भारत में पर फला सकन का वाई सवान हा नहीं उठता।

1 The treaty is seen as a continuation of the Tashkent objective of the Russian government—namely to help and maintain peace or rather avoid the outbreak of war in the Indian subcontinent. What happened at Tashkent was the ending of a war which had already broken out. What happened in Delhi on August 9 was an attempt to stop a breaking out.

—V R Bhatt Tashkent in the Treaty The Hindustan Times 18 August 1971

इसके बावजूद यहाँ एक बात विचारणीय है। सोवियत संघ भारत का एशिया में अपना मुँह दुग मानता है जिसको गवाना उसको गवारा नहीं है। भारत में उसकी दिक्कतों हमारे पक्ष में अब यह है। सन्निह्रमों साथ ही यह बात अछी तरह समझ और स्वीकार कर लेनी चाहिए कि सोवियत संघ को एक ऐसी सबन शक्ति की आवश्यकता है जो उसे अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के खेल में सफल योगदान दे सके न कि उस पर आश्रित रहनेवाले पुछने तारे की। दूसरे शब्दों में सोवियत संघ को एक ऐसे भारत की ही जरूरत होगी जो आश्रम निभर और आश्रित एवं भविष्य दृष्टि से सबल हो न कि एक निबल और आश्रित रहने वाला भारत की जिसका सुरक्षा का भार उसे स्वयं ही न करना पड़े। अतएव एशिया की नया शक्ति में तुलना में प्रभावकारी स्थान पाने के लिए भारत का एक सक्तिशाली और आश्रम निभर देश बनना पड़ेगा। पिछले पचीस वर्षों का इतिहास हम बताता है कि जिस तरी गली राजनीति आर्थिक प्रणाली में हम रहे हैं उसमें यह सम्भव नहीं है। अतः अतः राष्ट्रीय राजनीति में उचित स्थान पाने के लिए हम अपना रास्ता बदलना पड़ेगा।

सोवियत संघ के साथ हमारी नयी मंत्री संधि हमें विशा में भारत का भाग प्रदान कर सकती है। सोवियत संघ का साथ भारत को सहयोग करना है और इस सहयोग को उत्तरोत्तर मजबूत बनाना है। सामंतवाद और पूँजीवाद के अन्तर्गत तथा विहित स्थापनों के हितों को काममें रखकर भारत इस समय को प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः हम बात की सम्भावना बढ़ गयी है कि समाजवादी राज्य की ओर जाने में भारत की गति कुछ बढ़ जाय।¹ यही कारण है कि भारत के कुछ "मुख्य पूँजीपतियों के समाचार पत्रों ने संधि का गुले लिख स्वागत नहीं किया है। यह कोई आश्चर्य नहीं कि संधि पर टिप्पणी करने के लिए इंदुमान टाइम्स तथा स्टैंडमैन ने जो सम्पादकीय लिखे उनके शीर्षक भा लगभग एक ही थे।² सम्भव है इसी कारण ब्रिटिश समाचार पत्रों ने भी इस संधि का स्वागत नहीं किया।

1 The Indo-Soviet Treaty could conceivably have certain repercussions on the internal policy of this country quite apart from its obvious diplomatic significance. It is possible that the present model might foster a spirit of radicalism in the pursuit of domestic policies. External reaction to the Treaty could in certain circumstances reinforce such a tendency. These who have counselled caution in socialist advance may now feel less so to relax the brake. —The Hindustan Times, August 12 1971.

2 हिंदुस्तान टाइम्स (10 अगस्त) का शीर्षक Was this Necessary तथा स्टैंडमैन (10 अगस्त) का Was it really Necessary या टाइम्स ऑफ इण्डिया (10 अगस्त) ने भी Too Early to judge शीर्षक का अर्थन सम्पादकीय लिखकर अपनी आंकाए व्यक्त की।

भारत में ब्रिटेन के आर्थिक हिता पर आ खतरा पड़ा हो सकता था उसका ध्यान मर्यादित हुए उद्योगपति ब्रिटिश समाचार पत्र गाजियन न चेतावना न कि नया शिल्पी खार मास्का के बीच सम्पन्न मंत्री मणि म विभाग व बीच निहित हैं।

भारत-मोवियत संधि पर अमराका प्रतिक्रिया—भारत तथा सोवियत संघ व बीच संधि अमरीका की नृत्ति पर एक विनम्र वक्षपात था। संधि की खबर से अमरीका की नृत्ति के क्षेत्र व्यापक चर्चा शुरू हो गई। राजनयिकों की राय थी कि यह संधि अमरीका और चीन की रिगमग नृत्ति का उत्तर था। किन्तु अमरीकी अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पन्न कोई प्रतिक्रिया व्यवस्था नहीं की गई। यद्यपि ब्रिटिश मंत्री ब्रिटिशम रोशम न अपनी संधि प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि विश्व राजनीति पर भारत मोवियत मंत्री संधि का अर्थ प्रसरण था। तथापि अमरीकी सरकार निश्चित रूप से चिन्तित है। अर्थ का होड़ राकन की बातों तथा ब्रिटिश की बातों से आज व युग में गहन युग का मावना नम सीमा तक समाप्त नहीं हुए हैं कि भारत जैसे बड़े आकार तथा मन्त्र के रूप में साथ सोवियत संघ का मंत्री संधि बार्गमिंग में खड़ा हो पाए नहीं कर। अमरीकी रायों में यह बात मन्त्र की लान लगी है कि संधि के फलस्वरूप विश्व के मन्त्र जनसंख्या वान राष्ट्र में अमरीका के मूल पर संधि प्रभाव पड़ेगा। नम कन्सर्व एक स्थानीय युद्ध का खतरा बन गया जिनका फल भारतीय उपमहाद्वीप में मन्त्र वतों का संधि हो सकता है। बार्गमिंग के अधिकारी भारत मोवियत संधि को छद्म रखा संधि नहीं मानते थे। व समझते थे कि भारतीय विश्व नाति इतना गंभीर और खतरा है कि यह संधि नहीं किया जा सकता कि कवन पूर्वी वगान के छापाचारों के सम्बंध में पाकिस्तान की युद्ध के घमकियों के कारण भारत नम संधि के लिए प्रेरित हुआ। इसमें दूरगामी सम्भावनाओं का अर्थ हो मन्त्र किया गया होगा और इना कारण बार्गमिंग में यह समझा जा रहा था कि संधि संधि मन्त्र म अमरीका नाति का खतरा पड़ेगा है।

यस सम्बंध में यह आकाश व्यक्त था आ रहा था कि अमरीका नम पराजय का खतरा सीका नहीं कर लेगा तथा भारत के प्रति नमका खतरा बड़ा हो जायगा। अमरीका का सरकार न अभी तक भारत का अधिक आर्थिक सहायता न था और पाकिस्तान को सैनिक सहायता देकर सैनिक सहायता वान करन का यत्न किया था। अब पूछ कि भारत का सोवियत संघ से सैनिक सहायता मिलेगी संधि अमरीका नम संधि मन्त्र नम नम। का सन्तुलन खिड़ जायगा। इस सन्तुलन का बनाय रखन के लिए यह सम्भव है कि अमरीका भारत की अर्थ सहायता में कमी करे।¹

1 American assistance to India it is argued could now fall even below the present low levels and PL 480 imports of items like raw cotton may not be that easily available

मधुबत राय अमरिका भारत की ओर से पूणतया निराश होकर विमुख न
हा जाए इसके लिए भारत सरकार की ओर से त काल कुछ कर्म उठाये गये ।
भारत सोवियत संधि सम्पन्न होने के तुरंत बाद यह रहस्य पटन पहन खोला गया
कि 1952 से ही भारत अमरिका से सानि मोका नयन तथा वाणि र संधि के लिए
वातचीत करता र है । भारत का म संधि के मसविने का कुछ धाराए स्वीकार
नहा था । फिर भी भारत सरकार क एक प्रवक्ता ने यह प्रभाव रखा कि यदि
अमरिका इस प्रकार की संधि के लिए इच्छुक हा तो इस विषय को पुन उठ या
जा सकता है । इसके तुरंत बाद भारतीय राजदूत एल क झा ने अमरीकी विदेग
म श्री म मुलाकात की ओर उन्हें बताया कि यह संधि अमरिका पाकिस्तान और
चीन किसी भी दश को सध्य बनाकर नही की गयी है । उन्होंने इस बात का भा
आश्वासन दिया कि सोवियत संघ के साथ जा मत्री मी र की गया है उसके लिए
दा वप म वाप चल रही थी और राष्ट्रपति निक्मन के चीन से सम्बध मुशरने को
वाणिग से उनका कोई सम्बध नहीं है ।

अन्तानि का नया क्षत्र—भारत सोवियत संधि वस्तुतः उम क्रिया की प्रति
श्रिया है जिसन संपूची अंतर्राष्ट्रीय राजनानि का एक छटके म अन्त श्रिया । सोवि
यत चीन संघष अब मात्र सद्वातिक न रहकर शक्तिगत हो गया था । चीन ने अब
पूर्वी यूरोप म अपने पांव पसारन शुरू कर दिए म और अमानिया क बाद रुमानिया
तथा यगोस्लाविया उसके नये मित्र बन गये थ । लटिन अमरिका और अमाजा भी इस
प्रभाव से अछूने नही रह सके । सोवियत संघ ने साम्यवाद तत्त्वा की बनि दफर
अरब राष्ट्रों की मत्री खरीदी थी । अब सूडान और मोरक्को की घ नामों से म
गहरा स मा लगा था । भारत से रक्षा स व करने म सोवियत संघ ने जा तररता
दिखाई थी बहु इसी का फल था । कामिसा मे सोवियत परस्त साम्यवादी राज
नताओं का जो शीघ सम्मेलन हुआ था उसम रमानिया और र्गानाविग सामिन
महा हुए थ । लटिन अमरिका म चीनी का मायमवादी प्रगासन धान सोवियत प्रति
द्विद्विना का असाक्षा बन चका था । जातिर है कि एशिया म शीघ्र हा भारी उदय
पुद्यत होनी और सोवियत चीन प्रति श्रिया हिमरु विस्थाप की ओर प्रवृत्त हता ।
इस क्षण स अमरिका क हट जने क दा से न दोना र माजव दा सतिर्दा के दाव
अप्रत्य र दफराव को आगवा बलवनी हा उठी ।

इस अघ र पर बई दृष्टिवालो म संधि की आलोचनाए हुई । म आला
चकों का कहना था कि भारत सोवियत संधि न किन्हाल के लिए भारत का प्ररणा

Disenchantment with foreign aid in the United States is
already high Pakistan's military crackdown in East Bengal and
now the Indo Soviet treaty could greatly prejudice Congress
sional attitudes to the foreign aid programme

—The Statesman July 10 1971

प्रदान कर ले है लेकिन यह तात्कालिक महत्व की बात है। इस सुरक्षा को स्थायी शान्ति पर्याय नहीं माना जाना चाहिए। बहुत कम यह है कि युद्ध आरंभ की शक्ति के साथ दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर भारत प्रायद्वीप में जाने लगा है। पश्चिम एशिया में यथार्थता कायम रहने की सम्भावना है लेकिन उसका न। पर चान सावित्र सीमा और दक्षिण भारत-पाक सीमा पर दापकानान अगाति का आगमन है। भारत का बाह्य आक्रमण से सुरक्षित होने पर भी युद्ध सन्ता पन सकता है। ऐसे युद्ध की प्रकृति विद्यमान युद्ध के समान हो सकता है। बगल में पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर सामाजिक व अलावा कमर भा छानामार युद्ध के कदम बन सकते हैं। यह जरा नहीं कि पाकिस्तान अपना चान से भारत का प्रान्त युद्ध हो। युद्ध पने के पीछे न भी नगना सकता है। ऐसा स्थिति में नाशित न भारत को मात्र युद्ध सामग्री सप्लाई कर सकता है, विविध न निकलता न नहीं कर सकता। ऐसा लगाई विद्यमान-युद्ध का पुनरावृत्ति माना जायगा जिसमें अमेरिका का विद्यमाना मुक्ति सोवियत सघ का करना हागी।

संघि के जाने चको न दावा किया कि भारत सरकार के प्रवक्तारों द्वारा राख दार बहने के दावबन अब यह तथ्य मान्य नहीं हो सकता कि भारत का पुन निरपनता का नीति अभा भी काम है। एक महााक्ति के साथ सुरक्षा समझौता करके उसने निश्चय ही पुन के साथ अपने का बावद कर दिया है। यह भी जाना कि भारत सोवियत संघि किसी दंग के विरुद्ध नहीं है मान्य नहीं हो सकता। जिस परिस्थिति में संघि सम्मान है वह स्पष्ट है कि यह सुरक्षा पाकिस्तान के विरुद्ध है और इस कारण संघि का इतना आपक समर्थन मिला है। चान और अमेरिका दोनों का पाकिस्तान यह सकता है कि आप नागों का सन्ता न काम हो हमारे विरुद्ध भारत और सावित्र सघ का सदासा है। निश्चय न चान और अमेरिका न संघि के विरुद्ध प्रतिक्रिया हागी। पश्चिमी एशिया में अमेरिका प्रभाव को खत्म करने में सोवियत राजनय जिस तरह सक्ति है उसको ध्यान में रखते हुए अमेरिका का दृष्टि में पश्चिम पाकिस्तान का अभा भी बन महत्व है। विद्यमान में अमेरिकी बाइस से के समान राष्ट्रपति निवसन न विरुद्ध शान्ति पर जा गिया पन भी था उसमें यह बात स्पष्ट रूप से चकता है। इस शान्त में अमेरिका के प्रयास कर सकता है कि भारत सावित्र सन्ता न न मिला वह पाकिस्तान का और मजबूत कर। इस प्रकार भारत सावित्र सघ भारतभय महाा व न न एक नय शीत युद्ध का सूत्रपात कर सकता है और इस शान्त युद्ध का मुख्य लडावा भारत बन सकता है।¹

1 In view of this declaration (Nixon's foreign policy report to Congress) the American may wish to strengthen Pakistan to counter the Indo-Soviet entente. Thus the Indo-Soviet Treaty might well mark the beginning of a new cold war in this part of the world with India in the eye of storm and the

इस विचारधारा को माननेवाले संधि के आलोचकों का कना था कि भारत सोवियत संधि भारत के विरुद्ध चीन और पाकिस्तान के बठजो के का पनिक भय का परिणाम था। यह बगना देश के सभ में चीन तथा अमरिका की नीतियों के प्रति भारतीय प्रतिक्रिया का फल था। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ यह चीन द्वारा उसमें हस्तक्षेप तथा अमरिका की पाकिस्तान की दी जाने वाली मद की सभावनाओं को बहुत बढ़ा चढ़ा कर देखा था। यह कमे कहा जा सकता है कि चीन और अमरिका आखिरी मूड़कर पाकिस्तान को हर हात में सहायता करने जायेंगे। चीन की विशेषता कि पाकिस्तान पर ही कि त नही है उनके विरुद्ध व्यापारी हित और कम बात की सम्भावना बहुत कम है कि बगना देश का दरअसल से पश्चिम पकिस्तान की निकटतम वे लिए बहुत बड़े पैमाने पर वृद्धि वाला की सीमाओं पर भारत के विरुद्ध मुठभेड़ है। यदि कुछ समय के लिए मान भी लिया जाय कि चीन ऐसा करता तो उसका मुनाबता करने के लिए भारत की कम डिग्री जा सताए वही तयार थी। यदि यह भी मान लिया जाय कि चीन उन मनाओं को परास्त करने में सफल हो जाय तो क्या यह सम्भव था कि मसारा की महागतिवादी (विरोधकर सावियत संघ) अपने विरुद्ध व्यापारी हितों का ध्यान म रखने हुए चपचाप बठकर य दबती रहेंगे ? दूसरे शब्दों में वास्तविक सत्य का स्थिति में एक संधि के बिना भी भारत को सोवियत संघ का समर्थन अथ सम्भाव्य रूप से मिलता।

जब दा टकोण से देखने से एगा जगता है कि भारत ने संधि के दूरगामी परिणामों का वि सपण किया जिना ही इसका सम्भवन कर लिया। यह संधि चीन का उन्नति कर सकती थी उस पाकिस्तान के और नजदीक ले जा सकती थी तथा भारत अमराका सम्बन्ध का खाई का और गूरा कर सकती था। सावियत संघ ने अपने विरुद्ध व्यापारी हितों का ध्यान म रखकर इस संधि पर हस्ताक्षर किया था। भारतीय उप महाद्वीप में राजनितिक स्थिरता बनी रहे य उसका उद्देश्य नहीं था। चीन के साथ समझौते करन की नयी जमीनी पत्त का यह सावियत जवाब था। इसलिए जब यह प्रश्न उठेगा कि संधि में चीन तथा मेरा और चीन पटे मता यों कहा जायगा कि एक महागतिवादी विरुद्ध व्यापारी हितों की रक्षा के लिए भारत की विदेश नीति न अपना स्वतन्त्र अतिरिक्त को लिया।

संधि के आलोचकों का यह भी कहा था कि इसमें अन्तराष्ट्रीय राजनीति में भारत के बने प्रयत्न का बर्तन है यह गोपित कर लिया। एगिया में मातृभूत संघ की अपनी नीतियों और सब अन्तर्निहित थे। न किताक का लिए सावियत विदेश नीति अवश्य सन्निधर गो। सावियत संघ के साथ संधि में आगुद

triangular global manoeuvres among Peking Washington and Moscow will lead directly to involve the D Dha 11 1971 as for which obviously it is unprepared

—The H ustan Time 10 August 1971

हा ज्ञान के बावजूद भारत को चाहें उनका समर्थन करना ही पड़ेगा। कहा जाता है कि सालो दाना हाथों से बजती है। सावित्री मेघ ने भारत का सामाजिक कार्यक्रम के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की है। इसका अर्थ है भारत का भाग्य ज्ञान होगा। सावित्री मेघ का एंग्लो-इंडीय नीति का समर्थन करते हुए भारत इस प्रकार का दस्ता चला सकता है। ऐसा हानत में यह निश्चित है कि अन्तर्-एशिया नाटिक निष्पत्ति में भारत के समर्थन और बहुत कम विचार के कारणों के कारण दुर्लभ में समीचीन स्वतंत्रता भीमि है जायगी।

जबकि जिनसे 1971 में बंगला देश का समर्थन का उद्देश्य भारत और पाकिस्तान के मध्य तब लड़ाई लड़ना था भारत सावित्री मेघ का आशयों का नारी आकाए निमूल निम्न है। इस प्रकार के समर्थन सावित्री मेघ ने भारत का पुनः समर्थन किया।

भारत-पाकिस्तान युद्ध और सावित्री मेघ

बंगला देश के मुक्ति संग्राम को सावित्री मेघ ने पुनः पुनः नित्य समर्थन किया जो संग्राम तीव्रता के साथ ही राजनीतिक समर्थन में परिवर्तित हो गया। 25 मार्च 1971 में बंगला देश में उच्च मुस्लिम जनता का एक करके पाकिस्तान सेना ने भाषण नरसंहार शुरू किया। पाकिस्तान के इस क्रूर हमले को भारत ने सभा देशों का ध्यान आकृष्ट कराने का मत किया जिन सावित्री मेघ का छोड़कर सबकुछ सब मान रहा। अप्रैल 1971 में सावित्री राष्ट्रपति ने माह्ला सौ का एक पत्र लिखकर जन अनुपेक्ष किया कि जय के नरसंहार से कोइ नाम नहीं हानवाला है और पाकिस्तान सरकार को अवामा साथ के चुन टूट प्रतिनिधियों के का राजनयिक समर्थन कर देना चाहिए। जिन पाकिस्तान के तात्कालिक पर इस नए संग्राम का कोई असर नहीं हुआ। पाकिस्तान ने पूरे बंगाल का स्थिति के लिए भारत का जिम्मेदार बताया और इसके चतुर्धन सौ देशों के साथ संग्राम करने लगा। इस समय अंतराष्ट्रीय राजनीति में भारत बिल्कुल अकेला पड़ा गया था। बंगला देश की घटना का लेकर यह अकलापन और भी दुष्प्रभाव हो गया था। बंगला देश के भाषण नरसंहार का रोकने के लिए भारत ने कई प्रयास किए जिनसे उसका कोई नतीजा नहीं निकला। भारतीय अमकनता का अन्तर्-पाकिस्तान सेना ग्राह माह्ला सौ का होसला बहुत दुर्लभ हो गया। मुक्ति संग्राम अमेरिका के प्राच्य हन तथा चान का अनिश्चित नीति से उत्साहित होकर वे भारत का बार-बार युद्ध की धमकी दे रहे थे। उनका स्थान था कि भारत अकला पड़ जायगा। तब ता अमेरिका ने भी पाकिस्तान का धमकी के साथ अपना धार से यह धमकी दे दिया था कि यदि भारत और पाकिस्तान में सदाइ एक और चान ने पाकिस्तान का पक्ष लिया तो अमेरिका भारत की सहायता के लिए नहीं आयेगा।

भारत-मोविमन सचि—इस हानत में भारत को एक विश्वजनक सचि का आवश्यकता पड़ा। यह सचि सावित्री मेघ ही हो सकेगा था। इसी समय बंगला देश

को स्थिति और उसको लेकर भारत-पाकिस्तान के सम्बन्धों में तनाव के बढ़ने के बारे में अवगत कराने के लिए भारतीय विदेश मंत्री मरदार स्वर्ण सिंह मास्को पहुँचे। सन् अवसर पर सोवियत अधिकारियों ने भारत के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर करने का सुझाव रखा। उसमें कोई सन्देह नहीं कि यह बगनाहक की तम स्था पर अमरीकी सरकार का रवैया कम पाकिस्तान पर कम या कम से कम तत्परता पूर्ण भी होता तो भारत सोवियत संधि सम्पन्न नहीं होती। मास्को में सरदार स्वर्ण सिंह वाणिज्यिक पहुँचे और अमरीकी अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे पाकिस्तान को सैनिक सहायता नहीं देंगे। लेकिन जब इस आश्वासन के बावजूद पाकिस्तान का अमरीकी हथियारों की आपूर्ति जारी रहो और ब्रिटेन ने भी अपनी भारत यात्रा के दौरान प्रतिरक्षा या सविषय के लिए कोई आश्वासन नहीं दिया तो भारत सरकार को अमरीका से पूरी निराशा हुई और श्रीमती गांधी ने मास्को से संधि करने का फैसला कर लिया। इस वाद उत्पन्न समय भी जब अमरीकी विदेश मंत्री री रोजस ने अमरीका स्थित भारतीय राजदूत श्री एन के झा को यह चेतावनी दी कि भारत पाक युद्ध में चीन के हस्तक्षेप के बावजूद अमरीका भारत की सहायता नहीं करेगा तो श्रीमती गांधी का निश्चय और भी दृढ़ हो गया। संधि की बात पक्की हो गयी और दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने 9 अगस्त को इस पर हस्ताक्षर कर दिए।

संधि की सबसे प्रमुख धारा यह थी कि दोनों देशों में सन् त्रिंशती दश पर हमला होने या हमले का संस्तरा होने पर दोनों देश छात्र ही परस्पर विचार विमर्श करेंगे ताकि ऐसे छतरे को समाप्त किया जाय और दोनों देशों की शान्ति तथा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए समन्वित प्रभावकारी काम उठाये जाय। इसका अर्थ यह है कि यदि पाकिस्तान या चीन ने या दोनों ने मित्र पर भारत पर हमला किया तो सोवियत संघ हमारी सुरक्षा के लिए प्रभावकारी काम उठायेगा। मंत्रि के अनुसार दोनों देश एक दूसरे पर किसी प्रकार का आक्रमण नहीं करेंगे। एक दूसरे के खिलाफ किसी सैनिक सम्बंधन में शामिल नहीं होंगे तथा दोनों देशों में किसी पर हमला करने या ने तीसरे देश को किसी प्रकार का सहायता नहीं देंगे। संधि के अनुसार भारत और सोवियत संघ इस बात के लिए भी राजी हुए कि वे अपने क्षेत्र में किसी प्रकार के ऐसे बाध का नहीं होने देंगे जिससे दूसरे पक्ष की मानक शान्ति होने की आशंका हो।

भारत और सोवियत संघ की संधि बगनाहक की राजनीति से उत्पन्न परिस्थितियों का तात्कालिक परिणाम था। इसमें कोई संदेह नहीं कि शुरू से ही भारत की मानवभूति बगनाहक देश के स्वतंत्रता सप्राप्तियों के सम्बन्धों में भारत ने इस बात का अभी भी ध्यान कायम नहीं किया और भारतीय मन्त्रि ने महानुभूति एवं समर्थन का एक अस्ताव भी पारित किया। इसके बावजूद भारत चाहत हुए भी बारम्बार रूप से बगनाहक की सुनिश्चितवादी की सहायता नहीं कर पा रहा था।

श्रीमती गांधी ने इस बात की चेतावनी भी दी थी कि यदि समस्या का हल तत्काल नहीं निकाला गया तो इसमें बलवान तनाव अथवा गम्भीर रूप धारण कर सकता है। सोवियत नेताओं ने प्रधान मंत्री इरिंदा गांधी के साथ जो संयुक्त विज्ञापन जारी की उसमें दोनों पक्षों के दृष्टिकोणों का हवाला देने के अतिरिक्त यह भाग की गयी थी कि बंगला देश से क्षात्राधिकार का भारत आना एक गम्भीर तनाव पैदा करता है और उसे तुरंत रोकना चाहिए। संयुक्त विज्ञापन में कहा गया था कि 'यदि एक ऐसा राजनीतिक समझौता होना चाहिए जिसमें पक्ष बंगाल की जनता के अविभाज्य अधिकार और आत्मशासित को दृष्टि में रखा जाना चाहिए।

प्रधान मंत्री का इस सावधान यात्रा को सरकारी क्षत्र में करना महत्वपूर्ण और सफल यात्रा बताया गया। संयुक्त विज्ञापन में और सावधान चेतावनी के अर्थ बतलाने में यह स्पष्ट हो गया कि सावधान सच भारत के दृष्टिकोण को समझने में काफी आगे बढ़ चुका है। इन प्रस्तावों के अनुसार श्रीमती गांधी की यात्रा की ठोस प्रतीति यह थी कि सावधान सच ने सच्चे रूप से यह घोषित कर दिया कि बंगला देश में जो कोई भी राजनीतिक हल निकाला जाय वह लोगों की इच्छाओं और हितों को मद् नज़र रखकर ही निकाला जाय। साथ ही यह भी बताया गया कि सावधान सच ने यह स्पष्ट कर दिया कि 'सबसे भारत के लिए कोई अन्य रास्ता अपनाए जाने में संशय है।

1 अक्टूबर का सोवियत सच के राष्ट्रपति निकिता ख्रुश्चेव की उत्तर विपत्तियों जाने हुए भारत में एक दिन के लिए रुक गया। इस अवसर पर उन्होंने बंगला देश के साथ भी उन सभी बातों का उद्घाटन जो सावधान नेताओं ने आत्मता इरिंदा गांधी की मांकी यात्रा के दौरान कही थी। सोवियत राष्ट्रपति ने कहा हम मानते हैं कि सविनय अवज्ञा के प्रति स्थिति का और बढ़ने का हल चाहिए और तनाव को इस क्षत्र के लोगों के अधिकारों और हितों का दृष्टि में रखकर एक उचित समझौता द्वारा दूर किया जाना चाहिए। श्री पदार्थों ने स्वीकार किया कि उस क्षत्र में इस प्रकार की जटिल समस्याएँ पैदा हो गयी हैं जिसमें बहुत गम्भीर परिणाम हो सकते हैं। सावधान राष्ट्रपति ने स्वागत का उत्तर देते हुए कहा कि सावधान सच वर्तमान मित्रता के वातावरण में पूर्वी पाकिस्तान में राजनीतिक हल के लिए भारत की दूर प्रस्ताव से सहायता करेगा।

अब कर के मध्य में सीमा पर निर्माण हो रही। दोनों पक्षों के सेनाओं की सीमाओं पर जमाव के कारण तनाव बहुत बढ़ गया और मुद्दों के आगार निर्माण पटन सगे। इस निर्णय में सावधान नेताओं ने पवित्र मंत्री निकालाई किश्किन का तत्काल निर्णय रवाना किया ताकि युद्ध की सम्भावना पर दोनों पक्षों के बीच उचित स्तरीय मन्त्रणा हो सके। किश्किन ने सरदार स्वर्ण सिंह का आवाहन दिया कि यदि युद्ध हुआ तो भारत अकेला नहीं रहेगा और सावधान सच भारत का पूरा पूरा समर्थन करेगा। सोवियत सच ने भारत का यह आश्वासन भारत-सावधान भावि रा —20

संधि की नींवों धारा में निहित शक्त के अनुसार दिया कि युद्ध की स्थिति उत्पन्न हान पर सम्बंधित लोगों का उच्च सत्ताएं एक-दूसरे से परामर्श करेंगी। सावित्र संधि ने यह भी आश्वासन दिया कि हमल का मुकाबला करने के लिए संधि की सभी शक्तों का पूरा किया जायगा।

फिरावन की यात्रा के फलस्वरूप यह निगम हुआ कि सावित्र फाजी अधिकारी भारत आकर युद्ध की स्थिति का अध्ययन करेंगे। मास्का से मावित्र वायुसेना के प्रधान प. म. काताखाव का तत्काल भारत भेजा गया। पाकिस्तान और सोवियत संधि के आपसी सम्बंध में ज़िम्मेदारी से गिरावट हुआ गया था इसका अनुमान केवल इसी से मिल सकता है कि पाकिस्तान ने काताखाव के दिमाग का पाकिस्तान पर उठान की इजाजत नहीं दी और काताखाव का एक दूसरे रास्ते से भारत आना पड़ा।

युद्ध पर सोवियत प्रतिक्रिया—3 दिसम्बर को भारत और पाकिस्तान में युद्ध शुरू हो गया। भारतीय हवाई अड्डों पर पाकिस्तानी हमलों के समाचार पर मास्का में बड़ी चिन्ता प्रकट की गयी। उस समय सावित्र प्रधान मंत्री कोसिज़िन कोलन हैगन में डेमाक के प्रधान मंत्री के साथ बातचीत कर रहे थे। भारत-पाकिस्तान स्थिति के सम्बंध में ताज़ा समाचार प्राप्त करते ही उन्होंने इस बातचीत का कार्यक्रम रद्द कर दिया और स्वयं के लिए खाना हाँस।

सावित्र समाचार-पत्रों ने भारत का खुला सम्पन्न किया। उनमें इन्दिरा गांधी के उस भाषण की प्रमुखता से छापी गया जिसमें उन्होंने पूर्व बंगाल का मुक्त हल करने के लिए वहाँ से पाकिस्तान सेना की वापस का अहंता बताया था।

भारत पाकिस्तान युद्ध के शुरू होने पर अमेरिका के पहल पर युद्ध पर विचार करने के लिए सुरक्षा परिषद का बत्त बुलाया गया। अमेरिका ने युद्ध विराम और सेनाओं की वापस का एक प्रस्ताव रखा। सोवियत संधि ने इस प्रस्ताव पर वोटों का प्रयोग कर इस रद्द करवा दिया और स्वयं एक प्रस्ताव रखा जिसमें पूर्व बंगाल की समस्या के राजनीतिक समाधान की बात कहा गयी थी। सुरक्षा परिषद में अमेरिका के भारत विरोधी प्रस्ताव के खिलाफ निम्न अधिकार प्रयोग करने के लिए भारतीय विश्व मन्त्रालय ने सोवियत संधि का सहजना की और कहा कि सावित्र प्रतिनिधि ने बंगला देश की सहाय्य स्थिति विश्व के सामने रखी है।

सुरक्षा परिषद की 5 दिसम्बर वाली बैठक में वोटों करने के उपरांत सावित्र सरकार ने मास्का से एक बयान जारी करके सना दर्जों से अनुरोध किया कि वे भारत तक संधि से दूर रहें और उसमें स्वयं को शामिल नहीं करें। बयान में कहा गया था कि सावित्र सरकार विश्वास करती है कि सभी देश इस कदम उठान से दूर रहेंगे जिनसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में स्थिति स्थिति

और भी उज्जित हो उठे। संघ को सीमित रखने का यह प्रस्ताव भारत के हित में था। भारत ने इस वक्तव्य का स्वागत किया और कहा कि भारत किसी बाह्य शक्ति के हस्त में नहीं जाएगा। भारत ने सोवियत संघ से इस समयन के लिए अपना आभार व्यक्त किया। उसका कहना था कि सोवियत नीति भारतीय नीति से पूर्णतः मेल पाती है। बंगला देश पर भारतीय दृष्टिकोण को सोवियत संघ ने मनी भाँति समझा है। इस वक्तव्य में बंगाल की घटनाओं की उत्पत्ति तथा भारत के विरुद्ध पाकिस्तान की कारवाइयों का पूर्ण विवरण दिया गया था।

6 दिसम्बर को मुस्लिम लिग का दूसरा बैठक हुई। अमेरिका ने फिर एक भारत विरोधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिससे चीन का पूरा समर्थन मिला। सोवियत संघ ने पुनः वोटों का प्रयोग करके इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया। इस प्रकार अमेरिका और चीन द्वारा पाकिस्तान को भुलीबुल से बचाने के लिए भारत पर दबाव डालने के अमेरिकी प्रयास को सोवियत संघ ने दूसरी बार वोटों का प्रयोग करके एक महत्वपूर्ण कार्य किया। मुस्लिम लिग में तीसरी बार भी वोटों का प्रयोग करके सोवियत संघ ने भारत का पूरा समर्थन किया।

10 दिसम्बर को जब युद्ध भयानक रूप से चल रहा था भारतीय नौनीतिज्ञों की धर राय-मन्थिरा के निम्न मांगी गयी। भारत पाकिस्तान युद्ध में बाह्य हस्तक्षेप को रोकने में सोवियत संघ मदद के अंतर्गत भारत की क्या मदद कर सकता था इसी प्रश्न पर विचार विमर्श करना हम यात्रा का उद्देश्य था। इसी तरह 12 दिसम्बर को एक सोवियत उपविदेग मनी बेराली कुजनेटसोव भारत आये और राय-मन्थिरा के लिए सबसे अधिकतर मुद्दों में जर्मन युद्ध का अन्त नहीं हो गया। सोवियत संघ ने धर राय-मन्थिरा के जरिये भारत सरकार को आश्वासन दिया कि वह हर हानि में भारत की पूरी सहायता करेगा और मन्थिरा के अंतर्गत गये वक्तव्यों को निमायेगा।

इसी समय यह खबर आयी कि शांति में स्थिति यह है अमेरिका की हानि के लिए अमेरिका का मानवीय देश बंगाल की खाड़ी की ओर रवाना हो चका है। यह एक सनसनीखेज घटना थी और कुछ समय तक ऐसा लगा कि अमेरिका पाकिस्तान का पक्ष लेकर युद्ध में प्रवेश करके शामिल होना चाहता है। इसी संकटग्रस्त स्थिति में सोवियत संघ ने भी प्रशासकों से मुक्त रुग्ण युद्धपोतों की भी कोरियाई सागर से हिन्द महासागर का ओर बढ़ने का आदेश दिया ताकि अमेरिका के प्रवेश पर हस्तक्षेप का कारण मुहैया करवाया जा सके। सोवियत युद्धपोतों की रवानगी की खबर से भारत की अदना मनोबल ऊँचा करने में बड़ी मदद मिली।

जब भारत ने एकतरफा युद्ध विराम की घोषणा की तो सोवियत सरकार ने खुले दिल से इसका स्वागत किया और शांति की जिज्ञा में इस एक महत्वपूर्ण कार्य बनाया। उसने महा शक्तियों को फिर से चेतावनी दी कि उपमहादीप में स्थिति

का सामाज्य हाथ ला रहा है। हमें हमेशा बरकत उस बात अधिक नहीं दिखती। सावित्री सरकार ने एक नया व्यवस्थापन किया और नया रास्ता जो भारत का विकास के सामाजिकरण में बंधना था, उसे तात्कालिकता के साथ मिलाने में सफल रहा। उसने भारत का इस घोरता के लिए विश्व सम्बन्ध का दायित्व ले लिया। पाकिस्तान का भूमि हथियाने का काम किया गया।

सबसे उत्तर में 18 नवम्बर को प्रधानमंत्री ने भारत में सावित्री सरकार को मित्रित करने के लिए निवेदन किया। नया भारत सरकार के प्रति उत्तमता का ज्ञापन किया।

अन्त में निष्कर्ष यह है कि हमें यह याद रखनी चाहिए कि भारत के प्रति हमारे देश का रुझान जितना विश्वव्यापी है, उतना ही सावित्री सरकार के विकास में है। वस्तुतः यदि भारत का सावित्री सरकार से सम्बन्ध नहीं होता, तो पाकिस्तान में युद्ध जादू जाता आसान नहीं था। सुरक्षा परिषद ने सावित्री सरकार के एक बीना न दस द्विद्वन्द्व बना के काम किया। इसीलिए पाकिस्तान के एक नेता ने कहा था कि हम युद्ध में भारत से नहीं बरतें, सावित्री सरकार से बरतें। सावित्री सरकार ने बीना कीटन परिस्थिति में भारत का महादत्ता बनें बनें युद्ध के अन्त का साथ ही प्रगति नहीं किया बनें उन सारे आवाजों का साथ दिया जो भारत सावित्री सरकार का आत्मनिर्भरता के साथ है। साथ ही हमें यह याद रखनी चाहिए कि सावित्री सरकार भारत का एक ऐसा विश्वसनीय मित्र है जो हमें इस पर भरोसा किया जा सकता है।

सहयोग का बलाना हुआ दायित्व — भारत के विकास के लिए विश्व सम्बन्ध का बलाना विकास के समर्थन में भारत और सावित्री सरकार के बीच जुड़कर काम करते रहे। भारत के तरह सावित्री सरकार ने भी बाला विकास के पुनर्निर्माण के काम में हाथ बटाया। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धांगत एक समझौते के सम्बन्ध में सावित्री सरकार ने सहानुभूतिपूर्ण रहा। उसने मित्रता सम्बन्धों और समझौते का ज्ञान पूरा समझ लिया। अगस्त 1972 में सुरक्षा परिषद में सदस्यों के सम्बन्ध के सम्बन्ध के लिए ज्ञान बलाना विकास — आत्मनिर्भर विकास के साथ ही भारतीय और सावित्री प्रतिनिधियों ने मिलकर काम किया। लेकिन चीन के बावले के कारण विकास के बलाना विकास के सम्बन्धों में भी मिल सका।

भारत सावित्री सरकार के प्रति विकास के सम्बन्ध का एक बलाना विकास — भारत-सावित्री सम्बन्धों का स्थापित करने का निष्कर्ष किया गया जो कि जातिगत लोगों में तानों दानों — सहयोग के और अधिक समर्थन के साथ। सम्बन्धों के विकास के लिए विकास के अन्तर्गत बालाना विकास और विकास के लोगों में भी सहयोग बलाना विकास का काम होना गया।

2 अक्टूबर 1972 को भारत और सावित्री सरकार के बीच विकास और विकास के सम्बन्धों के बारे में एक और समझौता हुआ। यह समझौता विकास के अन्तर्गत

दानी दण एव दूगर् का वनानिह रिपदा म नानकारा अपरुण और निगपन अप
 वध करायग । महवपण वनानिह समस्यादा क समचित २० और अपरुण काय
 नमा क निर्माण य रिण सममान क अवगत समय समय पर दानी दणा क विगपना
 क बीच विचार निमा २१ सा २२गा । दानी दण मित्रर वनानिह अनुमधान का
 एव यापर कायक्रम नगर करग । मद्रि पर ह ना इर दान क अवसर पर सावि
 यत उपद्राव मना न उतताया रि रिण वप भारत और सावित्र संध क वाच
 गत्याग और मित्रता ना ना मद्रि ना २३गा एव जरा करग है । मद्रिए
 दानी दणा क रिण राफा मद्रक २४ । सावित्र संध और भारत क वाच वनानिह
 मामना म म याग नून ना मद्रि २५गा मरवार का नाति म मद्रुपण परिमन
 का परिचायक ह । जना नर भारत न पश्चिमा दानी म । वनानिह और तवानी
 जाननागे प्रा न नून ना प्रयाग निरा ना । मगर अमरिका क माध राशनातिह
 मनभेद नून न कारण भारत मरवार न तवनीही म याग क मद्रुपण म सावित्र
 संध म अद्रि सत्याना प्रा न क ना २६गा मद्रक कर दिया ।

भारत और सावित्र संध का मद्रा का मद्रुपण परिणाम अन्त र्था म प्रवट
 हुआ है । दानी दणा क गत्याग म भारत ना अन्त साभ प्राप्त हुए २७ । मितम्बर
 १९७३ म भारत क समान एव भाषण राद्य मवट पदा हुआ । समोव पर सावित्र
 संध न भारत का थीम राद्य नून गहू नून का आश्वामन दिया । मद्र सावित्र संध की
 मद्रान उतरना थी । सपर २८ की कहा गया था रि सच मित्र न मवट क
 समय हमारा मद्रायता का ह ।

गत वर्षों म भारत न मून उद्यागा म सावित्र संध क मद्रयोग म अन्त
 उद्याग स्थापित हुए । आधिक और तवनीरा सत्याग का परिणाम मद्र निवना कि
 भारत का नून उद्यागा की स्थापना म करोगा मद्र की बिन्नी मद्रा कावचन हूँ ।
 १९७३ क अन्त तक का मद्रावन जीदागिर याजताए सावित्र सत्याग म सचाहित
 हूँ जितम पचीम पूरो । नुना या और उनम तजी म उद्यान भा आरम्भ हा
 गया था । भारत की आधिक मद्रानता म २९ करन म इन योजनाजा न अन्त
 भूमिरा निभायी है । यन् य मद्रा जाय कि भारत क समस्त उद्याना म वहुत
 दान अश सावित्र स याग का है ता का अतिपावित नभा हागी । रि यन् य
 है कि समस्त उद्याग का जगा प्रतिगत अन् विद्यत् अपरुण का माठ प्रतिगत
 तन् उद्यान का पचाम प्रतिगत । तन् पाधन का ताम प्रतिगत समस्त इत्यान
 उद्यान का ताम प्रतिगत और विवना उद्यान का थीम प्रतिगत भाग सावित्र
 स क सत्याग की मद्रा रि ह । भारताय मद्र उद्यागा म सावित्र स याग
 म निमित भित्ति ह्सात कारगाना मद्रा रि जाता ह । य कागान
 कराड टन ना उद्यान करना था । इसम भारत का करोगा मद्र की
 मद्रा की वचन हूँ । अब इस कागान का उद्यान मद्रा म और द्रि क जा
 री है । मद्र ३० मद्रा टन बाधित क्षमता और बढ जायगी । इसा मद्रा जव
 बाजारो ह्सात कारगाना की स्थापना म कर्तिना हा री की तव सावित्र संध

चांग म उम पूरा किया गया। उनके अगला भाग माना उद्यान जा गया म म्या
 न्ति किया गया हमम पूर का खाना क एकत्र नया किय जान हैं। यम माम
 चिन्ता तथा आमुनियम च्याग क सुवत्र नया नान ह। इरिद्धा का भाग विजनी
 काखाना भा मावियत मद्याग म म्यापिन म्या। क्रपिका और हैरागान म
 म्यापित एवापिक काखान म दवाया तगा का जा रान ह। य राना कार
 नान भा मावियत मद्याग क पणिामम्वम्य द्यापिन म्या। रानम्यान का मूरत
 गम काम म मावियत मद्याग म यात्रिक खना गुम म्या। उम काम क कारण हा
 याद्यान म मामन म कमावाता राजस्यान दचन वाता राय बन गया। म्या का
 म्या दवाया का भा मावियत मद्याग म यम ताम पचा। मिर विमाना क
 काण भागन का मयमना का जमन का काफा दवा म्या मम पूरा म गया है।
 च्यागा म मद्याग क मयावा भागन और मावियत मद्य क वाच द्यापर का आगन
 प्रान भा द्युत व म्या म्या।

अ सनव का भारत यात्रा—मित्रता और मद्याग क म वातावरण म 26
 नवम्बर 1973 का मावियत कम्युनिस् पार्टी क मयमचिव त्रियानि ब्र जनव भारत
 का यात्रा पर म्या पद्या। य यात्रा भागन और एगिया का राजनानि क लिए
 अत्यन्त मत्वपूर्ण था। मावियत मया का नया मिला म अमनपूर्व स्वागत हुआ जा
 म वात का प्रमाण था कि भागन और मावियत म्या का मत्री मतरातर ह हा
 रहा है। म्या जड पर भाव मयामावचनिक अमिनदन में ब्र जनव का प्रधान
 मर ना कि मावियत सब मुख और म्या म भागन क माय रहा। भागन-मावियत
 मया का उन्हान विश्वमामि म काफा दवा यागमान म म ममय वताया और म
 दाना म्या का मित्रता म प्रमान न मानवा म्या का मयावना का। मान किना म
 ममिनन ममाराह म वात म्या उन्नि कया मारा म पारम्यरिक मया एक
 मयनाराण का मर है। म जिन भा मपर चन म्या म मया का नया मया
 बनाए म्यता जाता है। भागन और मावियत म का य मया अब मिला क
 म्यात का मर मुह म गया है। उन्हान म मय भा म्यन किया कि दाना
 दवा का य मया मयिया तव कायम म्या। ब्र जनव न कया कि भारत का
 मयनता पर म म्या म्या है और अब मक मामन का ममया जाता है ता
 म मपर म्या भा मया है। मकिन मय य मर मर म्या है कि भागन प्रगति
 म माग पर है। मारा म्या म्या का य मया किना म्या क किड मरी है। य
 मया विश्व मामि का म्या म एक मय म्या म ह।

वातचात का समाप्ति क वा म मयन विमपि मया का गया उमम
 मया म्या क वाच विचार विमय पर मयाय यन किया म्या और य कया गया
 कि मम मया म्या का मया और भा मुह म है। मया म्या न म दान का
 आवश्यकता पर जा दिया कि एगिया मया म मयाया मामि म म्यायित्व हा
 और मक दवा म परम्यर मम मयागन। विमपि म एगिया म मामि और

स्थिरता कायम करने में आपसी सहयोग के साथ ही सब देशों के समान प्रयास से काम करने पर जोर दिया गया क्योंकि हमें एशिया के देशों में सन्भावित बढ़ती तथा सामाजिक और आर्थिक विकास पर व सुरक्षा की भावना के साथ काम करना चाहिए। दोनों देशों ने मध्य एशिया और सोवियत मध्य के बीच शांति तथा सन्तुलन सहयोग की स्थापना का प्राथमिकता लाभ ममाना तथा छोटे देशों तक पहुँचाने पर जोर दिया। दोनों देशों ने यूरोप में सुरक्षा और सहयोग के लिए प्रस्तावित सम्मेलन का सफलता का कामना की। साथ ही उन्नतिवाद एवं प्रजातीय विभेद की नीति खत्म करने पर बल दिया। घाषणा में भारत और सोवियत मध्य ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी आस्था व्यक्त करने हुए हमें हर दृष्टि में मजबूत बनाने का सन्धान किया। दोनों नेताओं ने हथियारों की हानि रोकने तथा आम एवं पूर्ण निरस्त्रीकरण पर बल दिया। कहा गया कि हमें पारमाण्विक आघ्र भी शामिल किया जाना चाहिए। दोनों देशों ने हिन्द महासागर का शांति का क्षेत्र बनाये रखने की अपनी सन्तुष्टा व्यक्त की। घाषणा पत्र में भारतीय उपमहादीप में आपसी बातचीत के द्वारा विभिन्न समस्याओं के हल तथा शिमला समझौते के कार्यान्वयन पर जोर दिया गया तथा उपमहादीप की स्थिति परीक्षण सामान्य बनाने की जिज्ञा में अगस्त 1973 के भारत पाकिस्तान समझौते का महत्वपूर्ण कर्म बताया गया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर चिन्ता व्यक्त करते हुए सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के तत्ती से नागू करने पर जोर दिया। यह कहा गया कि जबतक अरब देशों का इजरायल खाने नहीं कर देता तबतक वहाँ की स्थिति सामान्य नहीं हो सकती।

आर्थिक समझौता—द्विजनेव के इस तिथि प्रवास के दौरान भारत और सोवियत मध्य के बीच सम्बन्धों को नयी जिज्ञा देने तथा उभय तत्वा में परिपूरित करने की जिज्ञा में 29 नवम्बर 1973 का नयी दिल्ली में तीन एतिहासिक समझौता पर हस्ताक्षर किए गए जिनके अधीन व्यापार तथा आर्थिक सहयोग बढ़ाने दोनों देशों के यात्रा जायागा में निरन्तर सम्बन्ध स्थापित करने तथा एक-दूसरे के सरकारी प्रतिनिधियों का विधि मुविधाएँ प्रदान करने की व्यवस्था की गयी।

आर्थिक और व्यापारिक सहयोग समझौता के अन्तर्गत सोवियत मध्य भारत का उसकी प्रमुख यात्राओं के लिए सहायता की नयी किस्त देगा। इस समझौते में उद्योगों के अनिर्दिष्ट कृषि क्षेत्रों का भी शामिल किया गया। इस समझौते का दृश्य आर्थिक निभरता की जिज्ञा में भारत के प्रयासों का सफल बनाना बनाया गया। सोवियत मध्य ने बाफा में स्थापित विमान यात्रा में एक कराड टन और भिन्न स्थान यात्रा में सत्तर लाख टन उन्नत वस्त्र के लिए ऋण देना स्वीकार किया। समझौते के अन्तर्गत उन्नत मयुरानेनायक तथा कनकना भूगर्भ रत्न और मयोजखड नाम्ना परियोजना का स्थापना के लिए भी ऋण देना स्वीकार किया। समझौते में कहा गया कि ऋण के भुगतान की प्रक्रिया की गयी पर अन्त में समझौता होगा।

ब्रजनव का एशिया-मुराहा का मिटान का नया नया है। पचान म इन्ना मिटाना का निष्पन्न किया गया था। जिन पिछले वर्षों में एशिया का गतनातिक परिस्थिति में अन्तर्गत परिवर्तन हुए हैं जो नमो वन्ता - परिस्थिति में ब्रजनव मिटान का प्रतिपादन नमो और माविषत नमो नमो प्रयास किया कि एशिया नमो नमो मिटाना का स्वाकार कर दें। जिन भारत सरकार का प्रतिश्रिया कमा भी इन मिटाना का अनुमान नमो नमो। नवम्बर 1973 में ब्रजनव का भारत यात्रा के दौरान नमो नमो व्यक्त का गया कि सामूहिक मुराहा पद्धति का स्वाकार कर नमो नमो माविषत मध भारत पर नमो नमो नमो। ब्रजनव नमो भारत नमो नमो नमो और अपन मावजनिक भाषण में नमो यात्रा का काया विस्तारपूर्वक निष्पन्न किया। उन्ना कया कि यूरोपीय मुराहा का नमो नमो मन्त्रालय म भी नमो नमो का सामूहिक मन्त्रालय तथा मुराहा का व्यक्ता का जा सकना नमो। ब्रजनव का विचार था कि एशिया में सामूहिक मुराहा में नमो महानय का शानि नमो मुराहा का समस्याका का सम्बन्ध में नमो एक दृष्टिकोण अपनाया जा नमो नमो नमो मन्त्रालय का माय नमो। नमो कहा कि हम चाहते हैं कि नमो नमो पर नमो नमो और नमो नमो नमो म विचार किया जाय ताकि नमो नमो काय का विषय में समय नमो नमो नमो। नमो महान नमो का निष्पन्न प्रयत्न और सम्प करना नमो नमो।

जिन भारत नमो ब्रजनव का नमो यात्रा का यावहारिक नमो माना कयाकि उनका अपना समस्याए और परिस्थितियाँ था। नमो कारण भारत नमो नमो नमो ब्रजनव यात्रा पर किमा नमो का प्रतिनिधि व्यक्त नमो का और नमो माविषत मध नमो नमो भारत पर किमा नमो का दवाव नमो। सम्भवत नमो वजह स ब्रजनव का यात्रा का समाप्ति पर जा संयुक्त विनिधि जाया का गया उमम एशिया सामूहिक मुराहा पद्धति का का नमो नमो नमो किया गया।

साविषत आर्थिक महायता—ब्रजनव का भारत यात्रा का नमो अवसर पर माविषत मध नमो भारत का का नमो की मन्त्रालय नमो का मायावामन किया। नमो समय भारत भीषण आर्थिक मन्त्रालय म निरा नमो था। ऊजा का मन्त्र विनिधि मध नमो नमो था नमो नमो तत्वाय मन्त्रालय का जन्म था। अन माविषत मध नमो एक वर्ष का भीतर नाम नमो नमो नमो नमो नमो नमो नमो मिटान का तन नमो का नमो नमो नमो। नमो नमो नमो नमो नमो नमो नमो नमो और नमो नमो का निष्पन्न मध भजन का मा यात्रा किया।

नमो नमो भारत जा माविषत मध का मित्रता और उनका आपमा मन्त्रालय सम्बन्ध निनादिन वन्ता जा रहा है।

भारत-चीन सम्बन्ध

(Sino Indian Relations)

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि — चीन के साथ भारत के सम्बन्ध न भारतीय विज्ञान नीति का जितना प्रभावित किया है उनका मापन किसी अन्य देश के साथ हमारे सम्बन्ध न के किया है। भारत और चीन के मध्य जयंत प्राचीन काल से ही अत्यंत भव्य और सम्पन्न रहा है। भूतकाल में चीन के बीच प्रभाव मंत्री सम्बन्ध था। एशिया में पश्चिमी साम्राज्यवाद के आगमन से चीन का यह भव्य सम्बन्ध एकाएक टूट गया। ब्रिटिश काल में चीन के साथ भारत का जो सम्बन्ध कायम रहा उसका एकमात्र उद्देश्य चीन की जनता का साम्राज्यवादी शासन का शिकार बनाना था। चीन की जनता पर अपनी गुलामी का न के लिए ब्रिटिश भारतीय सरकार ने खुदकर भारतीय साम्राज्यवादी प्रयोग किया। चीन को युद्ध में पराजित करने तथा चीनी राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए भारतीय सत्ता का प्रयोग करने में ब्रिटिश सरकार जरा भी मकाच का अनुभव नहीं किया। यद्यपि भारत की जनता ने साम्राज्यवादी नीति में किसी तरह का सहयोग करना नहीं चांखती थी लेकिन यह सरकार का राज भी नहीं सकती थी। चीन के लोग भारतीयों की नम्र विवशता का समझने थे और सम्भवतः इसी कारण चीन की जनता के बीच किसी तरह का मनमुटाव पैदा नहीं हुआ। इसका विपरीत औपनिवेशिक दामना के अनुभव ने उन्हें एक-दूसरे के सनिकट आकर खड़ा कर दिया।

आधुनिक काल में भारत और चीन के बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध 1927 में हुए पदवित्त राष्ट्रवाद के प्रसंग में सम्भूत हुआ। इस सम्भूत में भारतीय तथा चीनी प्रतिनिधियों की संयुक्त विज्ञप्ति निकाली गयी जिसमें कहा गया था कि पश्चिमी साम्राज्यवाद से एशिया को मुक्ति के लिए भारत और चीन का सम्योग परम आवश्यक है। इसी विषय में चीन में ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय सत्ता का प्रयोग की निन्दा की गयी। चीन के प्रति भारत में आदर में अनुभूति थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कई प्रस्तावों को स्वीकार करके चीन के प्रति ब्रिटिश नीति की आलोचना की। 1931 में जब जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण किया गया तो चीन के प्रति सानुभूति प्रदर्शन करने के लिए चीन दिवस (China Day) मनाया गया और भारत में जापानी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान कराया गया। फिर 1937 में जब चीन और जापान के मध्य युद्ध शुरू हुआ तो भारत ने पुनः चीन के प्रति अपनी सानुभूति व्यक्त की। इस पृष्ठभूमि में यह स्वाभाविक था कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद स्वाधीन भारत अपने इस पड़ोसी राष्ट्र के साथ अच्छे सम्बन्ध कायम रखने का प्रयास करे।

प्राचीन काल में सामंती व्यवस्था थी। आम जनता में राजनीतिक चेतना का अभाव था। मनुष्य केवल तथा सुविधाएँ मंगलार्थी और समाज के उच्चतम वर्ग के लोग में केंद्रित थी। देश की अधिकांश भूमि में शताब्दियों से विदेशी मूल तथा उच्चतम वर्ग के अधिकांश में थी। निरवस्था की प्राचीन संस्कृति में यह सर्वप्रथम सुविधाएँ थी।

मानव ज्ञान की मति रत र शक्तिशास्त्रा राय था रति जगत्वा
 ज्ञाना र म छे रत्ता नामा र उगात्रिगम व प्रश्न पर ति रतिरा जीर मगावा
 म शग । हा गया तथा चीन न ति वन की रजधानी नामा पर अधिहार कर
 सातवें रत्ताई नामा की अपन रत्तानुमार नियमित कर दी ।

निम्नत जीर भारत — भारत में अग्रजा नामित याचित नि व वा
त उन में सम्भर स्थापित करन का मयग प ना प्रथाम भारत में अग्रज गवन्त
उनरन वाग्ने हर्षि ग्यम न रिश । उमन नि उन व तामन में मन्त्रीपण सम्भ ध स्था
पित ि या । इग्गी वीष नपाव न ति उन पर हमरा कर दिया । निम्नत व शासना
न य मयम रिश वि हम हमर व पीर अजेजा का शय है । अन उद्दान स्म
न्डिया सम्भती व साय अन मार सम्भ प्र ता रिश । मर गा अग्रजा न ति उन
व साय सम्भ ध कायम करन व व प्रथाम किय लखि उमन वा मनीषा
नी निता ।

जस समय तक कि उत चीन का भाग माना जान गया था। सन् 1890 में भारत के अग्रज शांगका ने भारत कि उत सीमा निर्धारित करने के लिए चीन - माघ एन सी 2 की। "1" में कि उत के शांगका ने जस संधि का मानने में तैयार कर दिया। जस समय कि उत के सामान्य में जागृता। जस संधि ने उता जीर कि उत 1" ता" नामा में संधि का न सी 2 का प्रस्ताव रखा। म पर अग्रज बन्त प्रवर्धन। प्रोड्ड मिश्र का व रूप में चीन कुछ जागृता का निवेदन भजा जिहात नुन छिपकर कि उत का परा नक्शा बना दिया और सामरिक मन्त्र के मार धाना का पता लगा लिया। जस समय भारत का गवर्नर जनरल ता" वन्त था। व घोर माघनायवा 1 था। कि उत में जस के उद्भूत प्रभाव का वन्त नया मक्ता था। अक्टूबर 1904 में उमन यममयन नामक एक मनापति के नतूरत में एक मना भजी जो नामा तक पहुँच गयी। दना" नामा कि उत में भाग खड़ा हुआ और चीन की न शरण ली। यममयन ने कि उत के अतिराग्या का एन सी 2 पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रार्थना किया। जस आगमि संधि का कि उत के मरणा चीन से मायता प्राप्त करने के लक्ष्य से अग्रजा ने 1906 में चीन के माघ एन सी 2 की। इस संधि के द्वारा चीन ने कि उत पर चीन का सर्वोच्च सत्ता का स्वीकार कर लिया। संधि के तहत यन् निश्चित हुआ कि कि उत की राजधानी नामा में भारत सरकार का एक एजेंट होगा तथा ग्याम तक डार तार पर वनचान का अधिकार भी भारत सरकार को रहेगा। व्यापारिक भागों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार का निम्नतम अपनी सत्ता रखने का अधिकार भी प्राप्त हुआ।

हानि का प्रयास किया। फिर भा चीन का जब जब भाका मित्रा उसने नि दन की स्वायत्तता नष्ट करके उसे अपना अभिन जग बनाने का प्रयास किया।

निर्गत व सम्बन्ध में एक और बात थी। य है भारत सरकार के कृष्ण सिंघे। उसमें सर्वाधिक सम्बन्ध बात यह थी कि यह भारत और चीन के बीच एक मध्यवर्ती रा य (buffer state) था। इस कारण मुगल की दृष्टि में यह क्षेत्र का सामरिक में था।

कम्युनिस्ट चीन और तिब्बत—1949 में जय चीन में मार्क्सवादी शासन की स्थापना हुई तो यह अवश्यम्भावी था कि तिब्बत में सम्बन्ध में नयी सरकार का प्रभावकारी काम उठावे। तिब्बत और पश्चिम में भारत। संपर्क था गया। तिब्बत के अधिपति नामा से चीनी मिशन का हटाने का प्रयास करने लग। तिब्बत के उस प्रयास का चीन की नयी सरकार ने शका की दृष्टि में देखा और समझा कि वह अपने का चीन प्रभाव से मुक्त करना चाहता है। अतएव कम्युनिस्ट चीन की सरकार ने तुरंत ही तिब्बत पर अपने अधिकार का दावा किया। जनवरी 1950 का चीन ने साम्राज्यवादी पद्धति में तिब्बत को मुक्ति दिलाने की घोषणा की। अगले 1950 में चीन की सरकार ने घोषणा की कि तिब्बत पर शीघ्र ही आक्रमण किया जायगा। उस पर भारत ने चीन का एक विरोध पत्र भेजा और तिब्बत का समस्या को शांतिपूर्ण ढंग में हल करने का अनुरोध किया। भारत तिब्बत में अपने विशेषाधिकार का छोड़ने के लिए तैयार था। वह तिब्बत में चीन का सर्वोच्च सत्ता का भी मानने के लिए तैयार था परन्तु साथ ही यह चाहता था कि उसकी (तिब्बत) स्वायत्तता बनी रहे। चीन ने उत्तर में लिखा कि वह तिब्बत का चीन का अभिन जग मानता है। फिर भी यह वह प्रयास करना नहीं चाहता है। चीन ने यह भी लिखा कि वह तिब्बत के प्रतिनिधि में सम्मिलित वार्ता करने का तैयार है। इस पर नयी तिब्बती में चीनी राजदूत और तिब्बती प्रतिनिधि में के बीच वार्ता शुरू हुई जो अबतक तक चलती रही।

25 अक्टूबर 1950 का चीन ने तिब्बत पर एकदम आक्रमण कर दिया। तिब्बती सेनाओं ने घातक प्रतिकार किया परन्तु वह चीन की विशाल शक्ति का सामना करने में असमर्थ रही। भारत ने चीन का विरोध पत्र भेजा जिनके उत्तर में कहा गया कि चीन का उद्देश्य तिब्बत का साम्राज्यवादी शासन में मुक्ति दिलाना है। चीन ने यह भी लिखा कि तिब्बत सम्बन्धी उनकी कांक्षा उसका घरेलू मामला है और उसके बारे में भारत का विरोध विनाश प्रभाव के कारण है। चीन ने भारत पर आरोप लगाया कि वह साम्राज्यवादी शक्तियों के बन्धन में आकर चीन के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है 13 मई 1951 के बीच और तिब्बत के मध्य निम्नलिखित संधि हुई

- (i) तिब्बत का स्वायत्त शासन का पण अधिकार होगा और चीन उसका आन्तरिक मामला में हस्तक्षेप नहीं करेगा।
- (ii) परन्तु तिब्बत के विपक्षी सम्बन्धों का शक्तिशाली चीन पर होगा।

जिसमें चीन को भी शामिल किया गया। चीन के साथ अपना व्यवहार की सदाशयता का प्रदर्शन करते हुए भारत ने अफ्रीकी एशियाई देशों के साथ चीन के सम्बंध को घनिष्ठ कराने में उसकी मदद की। यह सारा काम चीनी चीनी मार्ग भाई के युग में था।

लेकिन तिब्बत के प्रति भारतीय दृष्टिकोण की स्थापना आज भी भारत में नहीं है। यह कहा जाता है कि चीन के प्रति भारतीय नीति की यह पन्नी अस्फुटता थी। भारत का किसी भी कीमत पर चीन के आधिपत्य का मान्यता न। इसी चाहिए थी और तिब्बत की स्वायत्तता के ग्वाय उभरने में हस्तक्षेप भी करना चाहिए था। लेकिन यदि हम वस्तुस्थिति का सही से अवलोकन करें तो यह सम्भव नहीं था। भौगोलिक परिस्थिति के कारण सैनिक हस्तक्षेप करना उस समय बुरा ठिठान था। दूसरे भारत ने कभी इस तथ्य का मानने में इन्कार नहीं किया कि तिब्बत पर चीन की सर्वोच्च मता है। उसका विरोध कचन इन प्रयोगों में था और इस बात प्रयोग का रोशन में सैनिक दृष्टि से बुरा अग्रिम था। अतएव भारत सरकार के समस्त वस्तुस्थिति को बखूब कर ध्यान के सिवा कोई अन्य विकल्प नहीं था।

तिब्बत का विद्रोह और भारत—पचशीस सन्धि के पाँच वर्ष बाद तिब्बत में चीन के विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया। इस विद्रोह का मुख्य कारण भूमि-मुधार था। हम कह चुके हैं कि तिब्बत में अभी भी मध्यकालीन सामन्तवादी व्यवस्था कायम थी। देश की अधिकतर कृषि भूमि शक्ति और सुविधाएँ भठाधीशों और समाज के उच्चवर्गीय वर्गों के हाथों में केन्द्रित थी। सामान्य लोग वहाँ के सबसे बड़े भू स्वामी थे। फिर जब तिब्बत पर कम्युनिस्टों का अधिकार कायम हुआ तो निश्चित था कि वह व्यवस्था अधिक दिनो रातों तक नहीं चल सकती थी। वहाँ भूमि-मुधार का होना अनिवार्य था और उनका ही अनिवार्य भूमि के निहित स्वार्थों का विरोध था। नये सुधारों के काय में तिब्बती लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए चीनिया ने हजारों की संख्या में तिब्बती युवकों को विभिन्न विषयों के प्रशिक्षण के लिए चीन भेजा। सैनिकों में विद्रोह और मरण में समाया द्वारा अघविश्वास कायम रखने के लिए तिब्बतियों का शिक्षा दी जाता था। कम्युनिस्ट शासन ने नये-नये स्कूलों का निर्माण किया जहाँ आधुनिक ढंग में विभिन्न कलाओं और धार्मिक ढंगों की शिक्षा दी जान लगी। नये अन्तर्गत नये नये सड़कें अन्तर्गत आधुनिक भवन और हवाई जहाजों का निर्माण हुआ। गुप्तार्थी और बगारों को प्रेषित करने लगे गये। साम्यवादी शिक्षा की शिक्षा दी जान लगी। इन कार्यों के पन्थस्वरूप तिब्बत की आम जनता में राजनैतिक चेतना आयी और उनके शोषण का अन्त ले गया। सुविधापुस्तक के अर्थान सामान्य और उच्चवर्गीय वर्गों के सारी सुविधाओं में वृद्धि हो जाना पड़ा। नये शासन में तिब्बत में विद्रोह का होना अनिवार्य हो गया।

1956 में तिब्बत में घमाखा का जो विद्रोह शुरू हुआ और जो 1958 तक चलता रहा उक्त सम्बंध में चीन कम्युनिस्ट सरकार का कहना था कि उसको शुरू भी दि रा —2।

करनेवाले पुराने चाना समाज के यहाँ सुविधाप्राप्त वगैरे मिलता दिना तबों में पचास सहायता मिली। उस दिना के दवाइयों का समर्थन प्राप्त था। चान के आमका नये विद्रोह का चेला बरहमा के साथ कुचला। मरा का सम्पत्तियाँ जल कर ना गयीं थीं। तामाजा का कल कर दिया गया। जलविद्रोह में उसे निचले का आम जनता ने भी दूत तामाजा का साथ दिया। चाना मन्त्रिका ने विद्रोहियों का सहायता करने के मन्त्र में एक हजार निम्नलिखितों का पकड़कर जल में डाल कर दिया। हजारों का मन्त्र में निचले का छानकर भाग खड़ा हुआ। तामाजा को भी निचले का छानकर भागना पड़ा। वह भागकर भागते आने जाते भारत सरकार ने उन परण न था। चान का सम्कार न दूत तामाजा का वननाया और भारत पर विचारवानों हान का आराप लगाया। तामाजा में आन पुर्ण गुण हजा और आराप तथा प्रत्यागप के कारण तामाजा का सम्बन्ध अन्त विना गया। चान ने निचले में भागनाय व्यापारियों और यात्रियों पर राक लगा था। इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा भी भेज गये विराध-पत्र का रद्द का टाकरा में टान दिया गया।

भारत चीन सीमा विवाद

उस समय तक भारत और चान के बीच सामा का एक भा धार विवाद पुनः हा गया था। 1950-51 में ही कम्युनिस्ट चीन के नक्शे में भारत के एक बन्दे बड़े भू भाग का चान का अणु लिखनाया गया था। जब भारत सरकार ने चान का ध्यान उस आर आर्कपिन किया तो उन यह जवाब मिला कि मैं नक्शे बुझानिना सरकार के पुराने नक्शे और चान का नयी सरकार का नया समय नहीं मिला कि वह हमें उपयुक्त साधन कर सक। चीन ने यह भी आश्वासन दिया कि भारत का दूत बार में लिखित नान का आवश्यकता नहीं है। क्याकि समय मिलने पर उन नक्शे का ठीक कर दिया जायगा। यह हिना चीनी भाषा भाषा का गुण था और इसलिए भारत सरकार ने चीन को नक्शेयोजना पर मन्त्र नहीं दिया। किन वन्त्र निस्त् चीन ने कभी भी अपना नक्शा नहीं बदला और एक प्रयत्न सम्बन्ध में भारतीय भू भाग पर चान का नक्शा बनाया गया।

भारत और चान का सीमा विवाद मुख्यतः दो सामाजिक के ऊपर है। उनका पूर्व में मकमलान रेखा (Mc Mahon Line) और उत्तर-पश्चिम में ताराख।

मकमलान रेखा — भारत मकमलान रेखा का अपन और नान के बीच एक निश्चित सीमा रेखा मानता है। किन चीन उसका साम्राज्यवादी रेखा कल्पना है। उसका कहना है कि उसका भारत के साम्राज्यवादी त्रिणि अधिकारियों ने अकिनीने चान पर जबरन आगपित कर दिया था किमका चान का किमका सरकार ने कभी मान्यता नहीं दी है। मकमलान रेखा की उत्पत्ति 1914 के किमका सम्मेलन में हुई थी। नया भूगोल मिक्कम और निचले के बीच स्पष्ट सामा रेखा नहीं जान के कारण हमारा सामा विवाद पण होता रहता था। इस पर विचार करने

के त्रिप शिमा में भारत चीन और तिब्बत के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ। बाहर नरों सम्मेलन में सम्मेलन में भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुआ था। यह सम्मेलन में तिब्बत के सम्बंध में एक समझौता हुआ। तिब्बत का 1 भाग में विभक्त कर दिया गया—आन्तरिक और बाह्य तिब्बत। बाह्य तिब्बत और भारत के बीच ऊँचा पठार त्रिपिया का सीमा मानकर मध्य में एक नक्शे में ताल पमित त निर्माण कर दिया था। सीमा रेखा मध्य में रेखा चिन्ता थी। उस समय ताना प्रतिनिधियों ने यह नक्शा पर न साक्षर कर दिया। बाद में जब व नक्शा चीन की सरकार के समक्ष आया तो उसने त्रिपिया मध्य मन्त्रि इस सीमा रेखा का अनुमोदन (ratification) करके मंजूर कर दिया। त्रिपिया चीन की सरकार ने इस रेखा के विरुद्ध रक्षा आपत्ति नहीं की और चीन की वर्तमान चुनौती के पक्ष में मध्यमान रेखा का ही व्यावहारिक रूप में मान्यता दी जाती रही।

संदर्भ — जहाँ तक नद्दा के सीमा का प्रश्न है यह त्रिपिया में चान और भारत के बीच में किसी मध्य का उद्भव नहीं मिलता। भारत सरकार का कर्त्तव्य है कि व्यावहारिक दृष्टि से त्रिपिया सीमा तब भारत और तिब्बत अपना कर्त्तव्य गना लिया में करते रहे हैं और जिस भारत मध्य अपने नक्शे में चिन्ता है। वही परम्परागत सीमा रेखा है। समय समय पर भारत में जानकार विभिन्न सम्बन्धपूर्ण यात्रियों ने भी इसी सीमा का उद्भव अपने यात्राओं में किया है। कश्मीर की उत्तरी सीमा का वर्णन करते हुए अधिवारियों ने 1899 में चान का स्पष्ट किया था कि इसकी पूर्वी सीमा 80 अंगुल पूर्व दिशा में है। इस स्पष्ट पत्र में यह स्पष्ट हो जाता है कि अब कश्मीर भारत की सीमा का अंतर्गत रखा गया है और वही एति हमारा तथा परम्परागत सीमा है। कश्मीर राज्य के राजस्व विभाग के वागजाना में भी यह बात की पुष्टि होती है कि कश्मीर की सरकार ही अब कश्मीर के व्यावहारिक मार्गों की रक्षा और सम्भाल करानी रही है।

सीमा विवाद का आरम्भ — 1950 से अगस्त 1 6 तक की घटनाएँ— 17 जुलाई 1954 को पंचवर्षीय सम्मेलन के तुरंत बाद चान ने भारत का एक विराट पत्र भेजा जो यह आराधना करता था कि भारतीय गना ने यह नाम चानों स्थान पर गन्तव्य तरीके से अधिवार कर लिया है। यह नाम चानों स्थान भारत में बहालता के नाम से जाना जाता था और यह उत्तर प्रमाणित था। भारत सरकार ने चीन के आराधना के प्रत्यक्ष में 7 अगस्त 1954 को किया कि यह स्थान भारतीय प्रमाण है जो चानों भारतीय सीमा सुरक्षा गना का एक चोरी है। तिब्बत स्थित चानों अधिवारों अधिवारों के नाम पमन का प्रमाण करने के जो उपाय चीन में चानों स्थान है। अक्टूबर 1954 में तब पंडित ने चानों स्थान का नाम त्रिपिया का चीन नामों के समान रखा। उस समय चानों स्थानों के नाम एक मामूली और सामान्य पत्राचार टांक दिया।

अप्रैल 1955 के बाद भारतीय सामा पर चान की कायदाहा जार गार म प्रारम्भ हुई। चीन न वनाहाता पर अधिकार का दिया और अपना मना का एक टुकड़ी बहा स्थायी रूप म स्थापित कर ता। अप्रैल 1956 म चाना मुनिक् टुकड़िया न दमजान और वातावरण प्रयोग में प्रवेश किया। नमा प्रकार भिपका गरा हुपसा और गुद म भी अतधिकार प्रवेश किया गया। 1957 म नन मुनिक् टुकड़िया न तहिल्टि विचिनन म प्रवेश किया जो जुलाई 1958 म तलाख के सुरुनाक कि पर अपना कजा कर दिया। तलाख म नन भारत न एक वनवत नू भाग पर दावा किया। दावा हा नहा। उसन भारत का प्राशिक सामा म जकरा चान (Akshai Chin) एक का अनाधिकृत रूप म बना दिया। भारत सरकार का इम तय्य का जानकारा पहल न था किन मान्नाय जनता स सत्ता छिराकर ग्या गया था। इमलिए जब भारतीय जनता का यह जान हुआ कि भारत चीन सामा नदग पर चान का मगस्व टुकड़िया न भारत का वन म क्षेत्र तथा दिया है और अधिक भूमि हन्गत करन का तयारा कर रहा है तब वह हतप्रभ हा गया। जायामका का खन्शन का मग जार पकन ग्या। तागज चौकी पर चाना सना क वज तथा लहाख म भारताय गयना दन पर किय गये चानो आक्रमण स ता यह अमताप और भा उग्र हो गया। उसी समय तिब्बत म विद्रोह ग्या और दलाह नामा भागकर भारत आया। भारत म उमका शरण ग गया। नस कारण चीन का सरकार भारत सरकार म और अधिक क्रुद्ध ग गयी। इसक बाद म हा तिब्बत म भारताय व्यापारिया और ताथमाधिया क माग म नाना प्रकार का बाघाएँ उत्पन्न का जान गयो। पूर्वी तथा पश्चिमा तानो सीमाआ पर चीन का हरकतें तना मे गुन हा गयीं तथा उसन भारताय सामा क विभिन्न प्रणाम म अपन मुनिक् दस्त भेजत जार चौकिया स्थापित करन का काय प्रारम्भ कर दिया। 23 जनवरी 1959 के पत्र में चान की सरकार न यह स्पष्ट किया कि भारत और चान के बीच कभा भा मताआ का निर्धारण नहीं ग्या है और तथाकथित सीमाए चीन के विरुद्ध किंग गय माम्नायवाली पटवत्र का परिणाम मात्र है। चान न मकम्तान रेखा का गरवानुना घोषित कर दिया और उम एक परम्परा यन सामा मानन म नकार कर दिया। 20 अक्टूबर 1959 का चान का मनाआ न तलाख के वागम माग त्रिप का क न म धुनकर नो भारताय मिणाटिया का मार टाना जोर नन का वनी बनाकर सामा क नम पाग ग गय।

समझौता बाता — चान का नन माग कायवात्या म भारत का राजमन उत्पन्न गत्र हा गया और ननिगाशात्मक मुनि कायवाता के लिए नानक माग हान ग्या। किन पन्ति नन न एमा करन म नकार कर दिया। ननका नक था कि भारत मभा अन्तराष्ट्रिय समस्याआ का गानिपूण नम ममुत्थान के लिए वचन बद्ध है। चान का नन कायवात्या का भारत पकान का ननधन मानता रग और उनका विरोध करता रहा।

इस बात म सीमा विवाद म उत्पन्न समस्याआ का मुनज्ञान के लिए नाना

सरकार के बीच पत्र का आदान प्रदान जाता रह्य। पहला पत्र पन्ति नेहरू ने 14 दिसम्बर 1953 का चीनी प्रधान मंत्री चाऊ एन लाई का लिखा जिसमें उन्होंने यह बात लिखी कि जब 1954 में वे भारत आयें थे तो उनका ध्यान चीन में प्रकाशित ऐसे मानचित्रों का जोर जाकर्षित किया गया था जिसमें भारत का बहुत सा प्रदेश चीन के अधिकार में दिखाया गया है। नेहरू ने अपने पत्र में लिखा कि चीनी प्रधान मंत्री द्वारा यह अवधान लिया गया था कि वे मानचित्र राष्ट्रपति सरकार के समय के जोर चीन में साम्प्रदायी शासन का नम मशाधन का समय नहीं मिल सकता है। नेहरू ने स्मरण करवाया कि 1956 में आ चाऊ एन लाई का दावा था भारत में आगमन था तब उनसे आ बातचीत हुई उसका सारांश इस प्रकार था प्रधान मंत्री चाऊ ने मकमल होने रखा कि सम्पूर्ण में यह बात कि उनका विचार में ब्रिटिश साम्राज्यवाधियों द्वारा स्थापित यह सीमा त रेखा ठीक नहीं है फिर भी क्योंकि यह एक सिद्ध तथ्य बन चुका है और चीन में जोर भारत तथा बर्मा में मन्त्रीपण सम्बन्ध है जो चीन सरकार की सम्मति है कि मकमल होने रेखा का उस स्वीकृति दे देनी चाहिए। परन्तु इस विषय में चीनिया ने अभी तक निम्नती अधिकारियों से परामर्श नहीं किया है। उनका जमा करन का विचार है।

अपने अभी पत्र में भी नेहरू चाइना पिकेटोरियन में प्रकाशित एक मानचित्र का उल्लेख करते हुए बताया कि हमें भारत और मलय के बीच प्रतीत चीन की सीमा के अलग हो लिखा है। चीनी सरकार ने प्रत्युत्तर में लिखा कि वे नवग पुरान नक्शे का आधार पर छापी और अभी चीनी सरकार ने अपना सीमा का सब तण और सम्बद्ध देशों में परामर्श नहीं किया है और वह स्वयंसेव इन साम्राज्य में परिवर्तन नहीं करना चाहती। नेहरू के लिए चीनी सरकार का इस प्रकार का स्वयंसेव ही अत्यन्त और आवश्यक था। अतः उन्होंने लिखा कि चार वर्ष पूर्व राष्ट्रीय पन्तिमाण के कार्य में मगन होने के कारण चीन का नक्शा मशाधन करन का अवकाश न मिलन की बात तो समय में आ गइती थी परन्तु चीनी गणराज्य का स्थापना के बाद यह बात न भविष्य मानचित्रों का अज्ञान बहुत परमान करन बाका है। न ब्रिगान प्रयोग में भारत का भूभाग हाल में काफी सम्पूर्ण नहीं है और हम पर का विचार नहीं है। मैं नहीं जानता कि इन सुप्रसिद्ध और गतिविधन साम्राज्य का किसी प्रकार के मवक्षण प्रभावित कर सकन है।

श्री नेहरू के साथ वे पत्र का प्रत्युत्तर देने हुए चीनी प्रधान मंत्री आ चाऊ एन लाई ने लिखा कि हमारे देश में अत्यन्त प्रकाशित मानवा मानचित्रों में चीनी सीमाएं बर्मा तथा मलाय में चीनी नक्शा में लिखित का जानवाती सीमाओं के अनुसार छापी गयी है। हमारा यह मत है कि सीमा त रेखा का प्रत्येक भाग अत्यन्त प्रमाणों के आधार पर छोड़ा गया है अतः सम्पूर्ण जमा में परामर्श किए बिना इसमें परिवर्तन करना अनुचित होगा। इसके अतिरिक्त इसमें अनेकों में स्थानीय अथवा धर्म प (1) अथवा भारी सरकार उन्नाम होगी।

भारत चीन युद्ध

अपना पूरा सैनिक तथाकथित करने के बाद 20 अक्टूबर 1962 का रात में भारत की उत्तरी सीमा के दोना अंचल पर चीन का सशस्त्र प्रहार हुआ। युद्ध का प्रारंभ हुआ। जिस पर हमने एक महीने तक चीन भारत के विरुद्ध प्रचार करना रहा कि भारत चीन की भूमि पर आक्रमण करता जा रहा है। बाद में हम प्रचारों में नुकसान के उपद्रवों के बजाय भी चर्चा निरंतर कर गये। 20 अक्टूबर का सारे चार बजे चीनी सैनिकों ने एक घाघणा की विभागीय फौजें चीनी सीमा रास्ता पर हमला कर दी है। चीन की मनाआ ने 20 अक्टूबर का नया क्षेत्र में गौर मय एक हजार मील दूर लद्दाख में मार्च पर तापमान हवा ताप और गन्धारी ताप की मनायता में प्रचल आक्रमण करने युद्ध का आरम्भ कर दिया। नया में चीनी मनाआ ने चौकीय घण्टा में भीतर की छाया तथा खिन्नमान की भारतीय चौकीय पर अपना अधिकार कर लिया। तत्पश्चात् रात में मनाआ का एक कण मनुष्य के वधनात्मक यहाँ चीनिया में अत्यधिक विशाल मनाआ का साथ आक्रमण किया। वह कि सा सैन्य भी भक्ति भारतीय चौकीय पर टट पट जोर चीनी मनुष्यमान उठाकर विजया द्रुत। चीनी मनाएँ अपनी अनुकूल परिस्थितियाँ की तयारियाँ तथा उपकरण शस्त्रों के मनाआ मनुष्यमान रखा पार करके उत्तरी पूर्वी सीमा में बने तजी में आग धरती गयी। छाया की चौकी पर अधिकार करके मनुष्यमान पर भी अधिकार कर दिया। 25 अक्टूबर का चीनी मनाआ ने मनुष्यमान रखा में मनुष्यमान मनुष्यमान पर अधिकार कर लिया। 28 अक्टूबर में 14 नवम्बर तक युद्ध में कुछ क्षति की किन्तु बाद में फिर तजी में गयी। 15 नवम्बर 16 नवम्बर का चीनी मनाआ रात में मनुष्यमान पर हमले किया गये। 13 नवम्बर का चीनी मनाआ का लक्ष्य बना गया। नवान में मनुष्यमान की मनुष्यमान मनुष्यमान का कुछ मनुष्यमान के पास चीनीय मनुष्यमान की चीन चरित्र चरित्र भारतीय शक्ति का पर दिया गया तथा अम्मी मनुष्यमान दूर वामदिना में भा हमला सम्बंध विरुद्ध कर लिया गया। 16 नवम्बर तक चीनी मनाएँ वामदिना में भा जाण आमाय के मनुष्यमान के उत्तर में स्थित तराई मनुष्यमान के चार मील उत्तर में पहुँच गया। नवान में त्रिम क्षत्र का चीन अपना बना रहा था उस पर भी उगत अधिकार कर लिया। विश्व प्राप्त करनी हुई चीनी मनाएँ 20 नवम्बर तक त्रिम क्षत्र पर आ पहुँचा था वहाँ में उनको दशपुत्र की नीचे आमाय के मनुष्यमान पूर्वी वगान तथा वगान की छाया में फिरो द रहे थे।

इतनी लड़ाई होने के बाद भी मनुष्यमान में मनुष्यमान में आ औपचारिक दण्ड में युद्ध की घोषणा नहीं की और दोना के बीच राजनीतिक सम्बंध भी बरकरार रहा।

चीन का त्रिमक्षी प्रस्ताव—भारतीय चौकीय पर आक्रमण करने के पारस्परिक अर्थात् 16 अक्टूबर 1962 का चीन का मनुष्यमान रात में एक त्रिमक्षी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया त्रिमक्ष निम्न बातें बनी गयी थी

यथार्थ है। श्रिजन्मभी इसी प्रतिनित्या है। यद्धुम् हावही त्रिनिश सरकार जोर
तगमय सभी त्रिनिश पत्र पत्रिका न भारत का पत्र नित्या। (केवल जगत् प्रसिद्ध
और वयावद्ध त्रिनिश वत्त रमक न मुद्ध न त्रिनिश भारत को पोषी त्रिनिश।)
महारानी त्रिनिश न त्रिनिश कि भारत पर त्रिनिश जात्रमण म मरी सरकार का
महारा धरणा त्रिनिश है। राष्ट्रमण्डलीय दंगा म कजा न वत्त त्रिनिश त्रिनिश
भूति व माय भारत का त्रिनिश नित्या।

यद्यपि गुप्त हान और लगातार भारतीय मना का पराजय का वातावरण भारतीय जनमन में भारत सरकार पर गंदाव गला बिंदु तथा की रता के लिए पश्चिमी देशों में सतिव मंगलता की याचना करे। नतीजा यह हुआ कि जवाहरलाल नेहरू को पश्चिमी देशों में समी प्रायना करनी पड़ी। भारतीय प्रायना के प्रत्युत्तर में अमेरिका प्रिन्स और उसका तुरत बाद प्राम पश्चिमी जमना जास्त तिया और कनाडा न नन सति म भारत का प्रभावकारी सतिव मंगलता भजी। इन देशों द्वारा भज गये अस्त्रशस्त्र टीन समय पर भारत पहुँच और भारतीय सतिवता से जा अस्तव गुप्त शस्त्रों में ही न न न थ तुरत नय शस्त्रों में सुगठित किया जा गया। अमेरिका अमेरिकी सना के उच्च अधिकारी और प्रिन्स के राष्ट्रमण्डलीय मंत्री भी भारत पहुँच। उन्होंने भारत का भ्रमण करके कानिना तक सतिव, सतिव वस्तु स्थिति की जाँच की और भारतीय सतिव आवश्यकताओं का अध्ययन किया। बाद में अमेरिका और राष्ट्रमण्डलीय देशों ने अपने सतिव राष्ट्रमण्डलीय का भवनर भारत का हवाई और सतिव मंगलता इन के लिए एक विस्तृत प्रतिबन्धन तयार किया जिसके फलस्वरूप भारत का सना म सतिव सामग्री मिलने लगी।

पश्चिम के मध्य न एक ओर बात उठाना पड़े। हम मध्य के समय अमेरिका की ओर सत्ता का प्रयोग नैतिकता तथा कि भारत अपना अन्तर्गतता की नीति छोड़ें। अमेरिकी राजनेताओं ने भारत का भीति का प्रयोग की। एकर न हेरीमेन ने कहा भारत ओर पश्चिम के लिए यह अन्त है कि भारत माध्याम सच से अपना सन्तोषण मध्य धरनाथ रख। इस प्रकार राष्ट्रपति कनेडी ने कहा हम जानते हैं कि तटस्थता की स्वतन्त्रता का रखा है। इस विषय हम तटस्थता की नीति की सहायता करण जितनी सहायता अपने गुट के दशा की करत है।

सोवियत रूस—भारत चीन युद्ध के मामला में सोवियत रूस की प्रतिनिधियां प्रारम्भ में अत्यन्त निराशाजनक रहीं लेकिन बाद की घटनाओं ने मिट्टी भर दिया कि उसका रुख भारत के पक्ष में है। 23 अक्टूबर 1962 के प्रावधान के सम्मानार्थ लेख में खुले रूप में चीन की 24 अक्टूबर वाली शर्तों का समर्थन किया गया। साथ में भारत में आग्रह किया गया था कि वह चीन की रचनात्मक प्रस्तावों का शांतिपथ समझौते के लिए स्वीकार करे। मामला विवाद में चीन का पक्ष लाने हुए उसने कुख्यात मकसमान रक्षा की निन्दा की तथा उसे ब्रिटिश उपनिवेशवादियों की विरासत बताया। 5 नवम्बर के अग्रगण्य में प्रावधान में युद्ध बन्द कर

देन तथा दाना पत्र आग का पत्र गत गगत परस्पर सन्धि-वात्ता करन पर न्या दिया । खूबच न भी प्रधान मन्त्री नहू का एक पत्र मन्त्रा प्रकार का दाना का मुदाव दिया । सावित्र मय न अपन पूव निश्चय क अनुसार भारत का न्या नान वाट वायम माग विमाना का न्यायन भा स्थगित कर दिया । मन चान का अपना भा और भारत का जपना मित्र कया । मम भारत म मम न प्रति प्रति कया । न मा कृपयना न कवत्ता म एक भाषण न न कया मम चान का भा और हमारा मित्र है । भा न ममम मित्र की अपना प्रति नाना न । जत सावित्र मय मम कम मनायना न सकता ह । कृपयना का मत था कि सावित्र मय इन मयप म तत्त्व और न्यायन है क्योंकि व समयना न रि म मयप क निग चान हा न्यायन है । मन चान का आन्नामक नया मममा त्र वि पश्चिमा म म एमा मममकर म पगे मनिक् मनायना ने रह हैं ।

जहा तक वायमन नहू का ममम था सावित्र मय म उनका वा निरागा नया ह । नका न विद्वान या कि कुठ आवश्यक जचना क वाग सावित्र मय क ख म भारत क प्रति अनुसार प्रवृत्ति भा न न न न्या हा पर व अतत भारत क विपम म नहीं जाया । वा म एमा नाना । चान द्वारा युद्ध प्रारम्भ किय जान का कर सावित्र मय और चान क वाच सुद्धानिक प्रान की खा अधिक चीन न गया और वयुवा का समस्या का ममाधान न न सावित्र मय न चीन क प्रति कया म्द अपनाया । सावित्र मय न निश्चित रूप म चान पर नवाव नया कि म भारत क माय मयप म विमुख नाना चाणि और मम का म नया कि चान द्वारा एकपक्षीय युद्ध विगम का घोषणा करन क पाछ म की वना ह नारायण का मय निम्ति था ।¹

पाकिस्तान का हव—भारत चीन यह क समय पाकिस्तान न स्पष्टनया भारत विराधा मय जनाया । यह विन्तु न स्वाभाविक था । मन भारत का न जावा न मनिक् मनायना का पूरी तरह वि पश्चिमा । नका न्या या कि चान न भारत पर किना प्रकार का आक्रमण नहा दिया । द न ममाय मामा मयप का घना ह जिसका भारत न निज का ता न्यायन वना दिया है कि वा

1 म विषय म यद् स्मरण रखना चाि कि एक नवम्बर 1963 का प्रकाशित मासिकादी चाना पत्र पापुज डेना न म पर य आगा नया था कि ख खच न 1962 म भारत पर चाना आक्रमण नान म एक मन्त्रा पूव चाना गत उन का यद् आक्रामक न्या न विन्तु म विषय म पिकिंग का मनायना कया किन्तु न विपगत मन म्मम्बर 1969 म मुग्राम सावित्र म भाषण कत न चान का जायचना का । पापुज नया का य न न नका क 19 म्मम्बर 1963 क उम यद् क म या म्मम भारत पर आक्रमण क विग कान्वा प्रमादा का पूव रूप म आक्रामक न कन क विग पिकिंग न न्या का गया था । पापुज डेना का य नया था कि प न सावित्र मय न न विवा म न्यायना का मय दिया और अब व अमिका क मासिका क पिटर मन्त्राय प्रतिनिगवातिया का न्यायना ममयन कर न्या ह ।

में पाकिस्तान के विरुद्ध ध्वजार करने के लिए पश्चिम में अधिनाधिक नमिक्त मन्त्र
यथा प्राप्त कर सकें। राष्ट्रपति अयूब खान ने अपने पश्चिमी मित्रों का धनाधान
दा कि प्रति मिश्रणों और सैन्य का पाकिस्तान के लिए कार्य मन्त्र सिद्ध नहीं था
ता उन अलग हट जायें। उसने वादे अयूब खान ने यह भा मुद्राया दिया कि पक्ष
समय है जब ब्रिटेन और अमेरिका भारत का कश्मीर प्रश्न पर धुक्कन के लिए वाध्य
कर सकें। पश्चिमी गुट का पाकिस्तानों विरोध पर ध्यान देना पड़ा और भारत
पर उद्घातन प्रभाव था कि कश्मीर के प्रश्न पर वह पाकिस्तान में वार्ता करे।
विश्व मंत्रियों के स्तर पर दाना प्रश्नों के मध्य यह वार्ता के प्रभाव में बनी भी
नहीं सका का नवीजा गयी निवृत्त।

तत्पश्चात् राष्ट्र की प्रतिक्रिया — भारत चीन युद्ध की जा प्रतिक्रिया तत्पश्चात्
राष्ट्र में हुई। अयूब खान की आश्चर्यजनक या। अन्तर्नीति और एक राष्ट्रपति
मुद्रा के लिए भारत ने जितना दिया था उतना शायद ही किसी और देश ने
दिया था। किन्तु भारत के भक्त के समय के चुपचाप हो रहा। मित्र के राष्ट्रपति
नामिर भूगोलाविद्या के टीने तथा घाना के एनजमा भारत के गहरे मित्र मान
जाते थे परन्तु अन्तर्भातिन छोड़कर भारत का साथ नहीं दिया। घाना के
एनजमा ने भारत का शस्त्र सहायता देने के लिए ब्रिटेन में विरोध भी प्रकट किया।
टीने और नामिर भी लगभग चुप रहे।

चीन की दूसरी धमकी — चीन ने भारत की 8 सितम्बर में पक्ष की स्थिति
स्थापित हान की माँग का ज्वरा दिया और यह धमकी दी कि इस बात पर अह
रहने से सीमा संधि मुद्रा नहीं पायगा। उसने भारत का आश्रमक प्रतारया।
इतना ही नहीं कादम्बा सम्मेलन प्रारम्भ हान में पक्ष उसने धमकी में भरा भारत
विरोधी प्रचार किया ताकि सम्मेलन के समस्त राष्ट्रों को धमका कर उन्हें भारत
की आश्रमगत भागा का समयन करने से रोक सकें। अपने इस प्रयास में वह बहुत
हल्के तक सफल भी रहा। सम्मेलन के एक दिन पूर्व चीन ने भारत का एक धमकी
भरा पत्र भेजकर निम्न बातों का कहा था या ना में उत्तर देने का क्या

(1) भारत युद्ध विरोध का प्रस्ताव स्वीकार करता है या नहीं

(2) भारत चीन का यह प्रस्ताव स्वीकार करता है या नहीं कि दाना देश
का मनाए 7 नवम्बर 1959 की नियंत्रण रेखा में सीमा किनामीटर पीछे हट जायें

(3) भारत चीन की यह माँग स्वीकार करता है या नहीं कि दाना या के
अधिकार परस्पर मित्रों और मनाओं की वापसी और विम मुद्रा धमकी के विषय में
विचार विनिमय करें।

सामान्य विचार पर उस समय तक भारत ने पूरी तरह से क्या क्या अपना दिया
था। अतः चीन के प्रस्ताव की नामजूर करत हुए जवाब देना शुरू किया। अन्त
तीय सीमा पर चीन के उस दावे का भारत सरकार या कार्य भारताय कभी भा
स्वीकार नहीं कर सकना एक परिणाम चाहे कुछ भी हो। इन दावों का मानन से
परे हिमालय का भूगोल ही बचता जाता है और इस प्रकार हम सारा हिमालय चीन

कानून्यो प्रस्तावों का मूला मूल उद्देश्य निम्नित था कि भारत और चीन के मध्य स्थित पूर्ण गतिरोध को अन्त्य करने का समाप्त करके तथा मानावरण प्रभुता नष्ट दिया जाय जिसे दाना राशन अपने सीमा विषयों का समाधान करने के लिए वातावरण प्रारम्भ करने की निम्न म अग्रसर ।।

कानूनी सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों ने कानूनी प्रस्तावों को पारित करने के उपरांत श्रीमती भण्णारनायक ने अनुरोध किया कि वे इन प्रस्तावों को दाना राष्ट्रीय की सरकारों के सामने रख उपस्थित करें ताकि आवश्यक स्थिति परण मौके पर ही किया जाकर दाना सरकारों का इस बात के लिए सम्मत किया जा सके कि वे पारस्परिक समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए प्रस्तावों को मानने हेतु उद्यत हैं ।

उपयुक्त निश्चय के अनुसार श्रीमती भण्डारनायक ने पञ्च चीन का जोर फिर भारत का दौरा किया। भारत ने कुछ स्पष्टीकरण के बाद सम्पूर्ण कानगवा प्रस्ताव का स्वीकार कर लिया और उसका स्पष्टीकरण के अनुसार पूर्वी क्षेत्र में भारतीय सेना मैकमहोन रेखा तक जा सकेगी। चीनी सेना भी अपने पक्ष स्थाना तक जा सकेगी लेकिन त्रिवाङ्गप्रस्त स्थाना पर उमका जाना भी बर्जित था। १1 जनवरी 1963 का चीन के विष्णु मन्त्री जो चीन की न कानगवा प्रस्ताव का सिद्धांततः स्वीकार कर दिया लेकिन साथ ही यह भी कहा कि कुछ प्रान्त पर चीन का अपना विचार है जिनपर वार्ता के दौरान में विचार किया जा सकता है। वास्तव में चीन कानगवा प्रस्ताव मानने में आनाकानी कर रहा था। उसमें कोलम्बो प्रस्ताव को बस्तुतः गहरा किया और उस प्रकार भारत चीन सम्बंध में राजनीतिक स्तर पर एक तरह का पूर्ण अनिरोध उत्पन्न हो गया। चीन के इस में तीन बातें स्पष्ट हो गयीं (1) चीन अपने पक्ष के आधार पर भारत से राजनयिक सम्बन्धिता करना चाहता था (2) चीन कानगवा प्रस्ताव का पूरी तरह स्वीकार करने के लिए तयार नहीं था तथा (3) चीन किसी प्रकार की मध्यस्थता का विरोधी था। यह भी कहा जाता है कि यदि भारत चीन का कुछ रियायत न की प्रस्तुत हो जाय तो चीन नफा और लड़ाई में खाली किया गया स्थाना पर भारतीय सेनाओं द्वारा बम्बा किया जाना का विरोध नहीं करेगा।

9 अक्टूबर 1963 को भारत सरकार का प्रधान मंत्री पण्डित लाल बहादुर शास्त्री एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने पत्र में मन्त्रालय से कहा कि दाना पत्र का अर्थ धार्मिक गुप्त कर देनी चाहिए। इसका जवाब में भारत सरकार ने धीरे से कहा कि वह पहले कालम्हा प्रस्तावों का परीक्षण करे तब धार्मिक गुप्त कर देना का मन्त्रालय से। उस हालत में यदि धार्मिक अमलदारों को भी धार्मिक धर्म विचारों का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक समझौता जा सकता है। लेकिन धार्मिक धर्म मन्त्रालय का दायित्व गया। उन्हें यह भारत का व नाम करता है।

3 अक्टूबर 1963 को राष्ट्रपति नागिर ने तब प्रस्ताव रखी त्रिगम कायदा कायदा।

का बाना का पुराना आवाज तो यह मुनाब द्वाारा था कि भारत चान विवाद को जल को लिए एक पुराने काँदा-मसाले का सायाजन है। किन्तु अब प्रस्ताव आ काइ नतान न। निरन्तर।

भारत चान विवाद को सम्बन्ध में 1964 में 1. अन्तराष्ट्रीय घटनाएँ घटी हैं। फरवरी 1964 में जब चान को प्रधान मंत्री बनाया गया तो वेना को प्रधान मंत्री ने उनका गैर आवाज न जा मुमुक्षु विन्ति किन्तु समझना था कि भारत जो चान का काँदा मसालों का गंधा पर ज्वित्त प्रदर्शन बाना गुन का दना चाहिये। अब सम्बन्ध न जा पुराना बात है बल्कि यह कि मार्च 1964 में आका के प्रधान मंत्री श्रानिना भगवानायक के गैर भारत मुक्ता का यह सूचना मिता कि यह चान का नरकार नयाव का सात चौकियों का खाना बन के लिए तयार न बार इसका बात बोता गुन न मुक्ता है। भानायासम में 1964 पर आने पर प्रधान मंत्री ने कहा कि यदि चान स्वयं प्रस्ताव न नरह का प्रस्ताव रखे तो हम पर विचार किया जा सकता है।

मार्च 1964 में पं. जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु पं. श्री वाङ्ग-एन-साय ने एक शाक मन्त्रा मन्त्रा जिनमें उन्होंने यह भी कहा था कि भारत आवाज का विन्ता अन्तराष्ट्रीय है और इसका समाधान शान्तिपूर्ण रूप से होना चाहिए। श्रानिनी भगवानायक ने इन विचारों का आन्तर किया और नतीजतन चान नए अन्तों कहा कि काँदा ज्वित्त इस समस्या का समाधान के लिए चला करता रहेगा।

किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि चान को पं. मारमुनाबन्धिवर्य ने। वस्तुतः चान काँदा प्रस्ताव का सम्बन्ध न करण पर धारण करता रहा है। इन प्रस्तावों के प्रति अन्तः मान्यता का प्रमाण न के लिए अन्तः तत्त्व-तत्त्व के प्रपच रहे आ इसका लिए अन्तः पूरी शक्ति के साथ मुचेर रहा।

भारत पाक युद्ध और चान — 1965 से ही चान पाकिस्तान के साथ जगत सम्बन्धों का मुधार जा था। यह सम्पाद्य है कि जब चान में साम्प्रदायिक आवाज का स्थापना था तो पाकिस्तान ने नमक प्रति का मजानुर्ति प्रदर्शित नहीं की था। जमरिजा के मृत्यु में चान के खिलाफ जा पतिव पूव एन्डि मय सम्मान बना मन्त्रा पाकिस्तान एक सम्मय न गता जार अन्तः मारा नाति चान विश्वास का कश्माक के प्रश्न पर चान न भाव को समर्थन दिया था।

किन्तु सामा विवाद का एक भाग और चान में जब सम्मान नत जा तो पाकिस्तान और चान गता एक हीन के अन्तः कगव जात न। गता नती के सम्बन्ध मुधारण के वक्त प्रदर्शन न और पाकिस्तान में चान का सम्मान मन्त्रा गता। राबर्तिया और पकिा में कननकात नए जा चान पाकिस्तान भा भा के नार जगत न। किन्तु गता गतों के अन्तः अन्तः का का मुदानिक आन्तर नहीं था। ए समाजवादी आवाज का पाद्य और अन्तः मुनिव तानागता सान्त्वना और धमाका का नद था। यदि गता न का सामान्य बात था तो वह ही भारत का विरोध। नर मन्त्रा का आधार बबन भारत का विरोध था।

पाकिस्तान और चीन का नवीन मंत्री का प्रथम व्यावहारिक प्रयोग सितम्बर 1965 में हुआ जब भारत और पाकिस्तान ने बीच तहान् छिड़ गयी। इन लड़ाई में चीन ने पाकिस्तान का पूरा-पूरा समर्थन किया और भारत को आक्रामक बतलाया। चीन ने पाकिस्तान का सैनिक सहायता देने का आवासन दिया। इसी व्यवस्था करने के लिए कुछ चीनी अधिकारी पाकिस्तान भी आये। भारत-चीन सीमा पर चीन ने सैनिक हस्तक्षेप भी शुरू कर दी।

चीन की इस गतिविधि पर भारत सरकार का दृग स्पष्ट था। वह इस सम्भावना का ध्यान में रखे हुई थी कि चीन भी इस अवसर से लाभ उठाकर भारत पर आक्रमण कर सकता है। अतएव चीन के विनाश भी अपना अपनी सयारी जारी रखी। भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दे दी कि यदि चीन भारत पर आक्रमण करता है तो सारा भारत पर मुराबमा किया जायगा। समुक्त राष्ट्र अमेरिका और साविधित मण्डल भी चीन को चेतावनी दे दी कि वह यद्ध में हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं करे।

चीन का अतिमहत्त्व — चीन चीन पर आक्रामकियों का कार्य प्रभाव नहीं पड़ा। 16 सितम्बर 1965 का चीन की सरकार ने भारत सरकार को एक अतिमहत्त्व दिया जिसमें यह मांग की गयी कि चीन चीन के अन्दर भारत विविधमान सीमा पर गर रनिनी ठग से बनाये छुपन सनित प्रवि टाना को हटा ने अथवा इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। पत्र में यह भी मांग की गयी थी कि भारत सीमा पर आने सार अतिक्रमण त वास्तव में कर द अपहृत सीमा निवासियों और पकड़े गये मवेशियों को वापस कर द और सीमा के पार परेशान करनेवाले हमलों से विमुक्त हो जाय। अथवा इससे गम्भीर परिणामों के लिए भारत सरकार पूरी तरह से जिम्मेवार होगी।

चीन की इस चेतावनी ने भारत में जनमनी तथा पाकिस्तान में हथ की सत्तर पन गयी। ऐसा लगता हुआ कि पाकिस्तान और भारत का अन्तर्गत व्यापक रूप धारण कर लेगा। चीन यदि भारत पर आक्रमण कर देता तो परिस्थिति बहुत नाजुक हो जाती और भारत पर यह युद्ध विजय युद्ध का रूप भी धारण कर सकता था। अतएव मन्त्रिमण्डल ने जिन पर विचारण का मुख्य दायित्व है तुरन्त ही चीन को चेतावनी दी कि वह आग में तेल सिमबाह नहीं करे। इस तरह की चेतावनी साविधित मण्डल और समुक्त राष्ट्र संघ पर भी भेजी गयी। जहाँ तक भारत का सम्बन्ध था उसने चीनी अतिमहत्त्व के लक्ष्य को सन्तोष का प्रमाण दिया। चीन को हमकी गम्भीर अवस्था भी लक्ष्य में अग्रगण्य नहीं थी। यह चीन और पाकिस्तान के अन्तर्गत विचारण का स्वाभाविक परिणाम था।

लेकिन भारत ने चीन को चेतावनी का स्वीकार कर लिया। अतिमहत्त्व के जवाब में 13 सितम्बर को लोकसभा में प्रधानमन्त्री ने सिक्किम विवाद मामला पर भारत द्वारा अतिमहत्त्व दिये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रश्न पर चीन का दबाव हम स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि चीन की सैनिक गति हम मा विचार — 22

रूपनी प्रादेशिक अखण्डता का रक्षा से विचलित नहीं कर सकते। भारत ने चीन के आरोपों का खदेन किया और कहा कि यदि चान का सरकार समझती है कि भारत ने उसके प्रदेश में सैनिक प्रतिष्ठान बना लिए हैं तो वह उसे ठाढ़ सबटा है चीन भारत इसका कोई विरोध नहीं करेगा।

चीन की सैनिक हस्त — अल्टिमेटम देने के साथ ही चीन ने सिक्किम तथा सहाय क्षेत्रों में सना का जमाव और सैनिक गतिविधि शुरू कर दी। अल्टिमेटम का अवधि समाप्त होने के पूर्व ही उसने सामा के पार स्थित भारतीय सनाओं पर गाना चलाया भी शुरू कर दिया। कुछ जगह भारतीय क्षेत्र में चानी सैनिक घुस आए। 19 सितम्बर को अल्टिमेटम का अवधि समाप्त होने वाला था लेकिन चीन ने बहुत बड़े पैमाने पर कोई कारबाही शुरू न करके इसका अवधि तान ली कि लिए बार देना दी। बाद में 23 सितम्बर को भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो गया तो पकिंग रेडियो ने एक नाटकाय भाषणा करते हुए कहा कि भारतीय सैनिक प्रतिष्ठानों को ताड़कर अपनी सामा में वापस लौटेंगे। चान के इस मनगढ़त कहाना को भारत सरकार के एक प्रवक्ता ने उपजाऊ चीना मस्तिष्क की उपमा देखाया।

चान और भारत के सम्बन्ध में तनावपूर्ण स्थिति जून 1967 में आयी जब चान ने जामुनी का आरोप लगाकर पकिंग स्थित भारतीय दूतावास के दो राजनयिकों का अवधित व्यक्ति घोषित करके उन्हें चान से निकट जान का आदेश दिया। इनमें से एक को यह कहा गया कि इसके आचरण का अर्थ एक नावजनिक अणु सत में होगी। बाद में जब दोनों राजनयिक चान से निष्काशित होकर मदद के लिए लौटे तो पकिंग और कैटन में चानी गान रणकों ने उनके साथ बड़ा घुरा और नष्ट व्यवहार किया। इन घटनाओं की प्रतिक्रिया भारत में हुई। भारत सरकार ने भी चाना दूतावास के राजनयिकों का अवधनीय व्यक्ति घोषित करके भारत छोड़ने का आदेश दिया।

संघर्ष का नया दौर (1967)—भारत चीन सीमा पर दोनों देशों के सैनिक गतिविधियों ने अब बढ़ा हुआ नयानक रूप धारण कर लिया। 11 सितम्बर 1967 को नायुना घटना इसी का परिणाम था। कहा जाना है कि उस दिन चीना सैनिकों ने पहले भारतीय जवानों को अपने साथ बातचीत में लाना चाहा और तब अवलोकन पर हमला कर दिया। भारतीय सैनिकों ने इसका विरोध 11 सितम्बर को चानी दूतावास का एक नाट भवा जिसमें सम्बन्धित दोनों देशों का और चानी सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया था। इस नाट का कारण इस प्रकार है

अगस्त 1967 के प्रथम सप्ताह में चाना सैनिक टुकड़ों समय-समय पर तिब्बत सिक्किम के बीच का अंतराष्ट्रीय सीमा के पार एक सिक्किम में घुसपठ करता रहा है। इसके अतिरिक्त चाना सुना ने एक अधिकारों तथा भारत में के द्वारा सिक्किम प्रदेश में स्थित भारतीय सना का उत्तखित किया है। नयुना क्षेत्र में चीन के संग्राम सैनिक सामा पर नाग नक्षत्र में एकदिवस हाथ लगा तथा समका अतिक्रमण करने लगे। 17 अगस्त को चाना टुकड़ों ने नायुना क्षेत्र में त्रिका

अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करने वाले सिविकम की तरफ ने जल विभाजक तक जाती थी। जब भारतीय सुरक्षा दल द्वारा उनको चेतावनी दी गयी तो साठ चीनी सैनिक टुकड़ियाँ सीमा पर आ गयी और चीनी देनेवाली वारदातें करने लगीं। बाद में 20 अगस्त 1967 को जब भारतीय सैनिक सिविकम के प्रदेश में तार खींच रहे थे तो हल्की मशीनगन तथा हथगोली के साथ 120 चीनी सैनिक टुकड़ियाँ उनके विरुद्ध हट गयीं।

ये उत्तजनात्मक कायवाहियाँ 6 सितम्बर तक बहुत गम्भीर बन गयीं। इस दिन सुबह के समय जब भारतीय गस्तीदल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सिविकम की तरफ नाथुला के दक्षिण की ओर बढ़ रहा था तो सशस्त्र चीनी सैनिक द्वारा उसे सतकारा गया। इससे बीस तो सीमा के भीतर भी पुग आये। 7 सितम्बर को जब भारतीय सैनिक सचिप्य में होनेवाली पुनर्पैठ की रोकने के लिए तार खींच रहे थे तो पुन साठ चीनी सैनिक टुकड़ियाँ सिविकम के प्रदेश में पुस आयीं और वहाँ बीस मिनट तक रहा। इन सैनिकों ने नाथुला स्थित साउथस्पीकरों से उत्तजनात्मक प्रसारण किये। 10 सितम्बर की तीन अलग-अलग अवसरों पर चीनी सैनिक सिविकम की सीमा में पुग आय।

11 सितम्बर 1967 को चीनी सैनिक ने सीमा के पार के भारतीय रक्षा दला पर गोलाबारी शुरू कर दी। इसी प्रकार की उत्तजनात्मक कायवाही चोला में भी की गयी। चीन सरकार यह अच्छी तरह जानती है कि सिविकम तिब्बत सीमा एक गैरपरिभाषित अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तथा चीन भी इसे मान्यता देता है। आक्रमण करके चीन सरकार उस क्षेत्र में मजबूत छिड़ना चाहती है जो कि अभी भी अगढ़े के कारण नहीं रहा।

भारत सरकार ने स्थिति को अधिक गम्भीर बनने से रोकने के लिए तथा विवाद को दूर करने के लिए यह सझाया कि दोनों ओर से तुरन्त युद्ध विराम हो तथा दोनों ओर के सैनिक कमण्डर नाथुला में मिलें।

नाथुला कांड को स्पष्टि धूमिल भी न हो पायी थी कि 2 अक्टूबर को चोला में दोनों पक्षों के बीच एक भिडत हो गयी जबकि चीनियों ने यहाँ स्थित भारतीय सैनिकों पर गोलाबारी शुरू कर दी। चोला नथुला से साढ़े तीन मील पश्चिमोत्तर में है और नाथुला की भांति ही भारतीय दृष्टि से इगला बड़ा सैनिक महत्व है। चोला में 2 अक्टूबर 1967 को शाम पाँच बजे तक गोलाबारी चलती रही किन्तु बाद में यहाँ शांति हो गयी। गोलाबारी शुरू करना तथा उत्तजनात्मक कार्यवाही करने के लिए चीन ने भारत को विरोध पत्र भेजा। भारत ने भी अपने विरोध-पत्र में चीन से मांग की कि वह सिविकम सीमा पर आक्रमण और उत्तजनात्मक कार्यवाहियों करने से औरन बाज आये नहीं तो उसे भी सम्भार परिणाम होने उठनी जिम्मेवारी चीन पर होगी। विरोध पत्र के अन्त में यह भी हमरन लिखाया गया था कि नथुला सम्झौती पटना के बाद भारत सरकार ने दोनों ओर के सैनिक अधिकारियों को बातचीत का मुताविका पा पर यह रचनात्मक कार्य चीन की सरकार को माया नहीं हुआ।

को जमी भागना और निन्दा को बना बड़ी आवाजना - गरी मे इस व तथा ति इत म चीन के हस्त उप को नहीं की । हमने एशिया और अफ्रिका व नवीन रा यो की स्वत प्रता का समयन किया । डोनोशिया की स्वाधीनता निताने म बड़ा भाग लिया । किन्तु जब चीन न हम पर हमला किया तो निसी मित्र न हमारा साथ नहीं दिया । मिस इडानाशिया अ जि दम हम मामते म मोन रहे । सोवियत सघ बारम्भ म काफा समय तक चप रहा । उस समय सोवियत सघ व प्रमुख पनों न चीन को आक्रान्त घापित करन उसका मित्रा नहीं की तथा भारत से अनुरोध किया कि वह चीन के अमानजाफ प्रस्ताव को स्वीकार करत हु बिना शत के युद्ध बन कर दे । इसके विपरीत पंचिमी देगो - अमरिका इगन बनाडा पंचिमी जमनी ने तुरत ही हमारी सहायता की । ये सारो घटनाएँ इस बात का सिद्ध करती हैं कि भारतीय विदेश नीति मे आवश्यकता का पण एक म नही रहा है ।

इसमें कोई सन्दह नहीं कि उपयुक्त आलोचना मे सत्य का कुछ अंग है । जवाहरलाल नेहरू न कहा था कि हमारी मित्रता के बावजूद चीन ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार म सामान्य नियमों का इतनी भार - पेक्षा की है कि अब उसकी सहायता में हमारा विश्वास गम्भीर रूप से सिमित हो गया है । उपलब्ध साक्ष्यों व आधार पर अब हमें उसकी अपनी स्वत प्रता तथा संस्थाओं का शत्रु समझना चाहिए । यह आलोचना भी सहा है कि शांतिमय विदेश नीति व कारण सैनिक तयारों और रणसामग्री का ओर आवश्यक ध्यान नही दिया गया । नेहरू क शांति म अतीत काल म हम नियन्त्रिता और निरन्तरता की मानवोप समस्याओं में इतने उलझे हुए थे कि हमने प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं की तुलनात्मक दृष्टिकोण से बहुत कम ध्यान दिया । यह स्पष्ट है कि हम इस ओर अधिक ध्यान देग कि हम अपनी सशस्त्र सेनाओं को मजबूत बनायें तथा जहाँ तक सम्भव हो सना के लिये आवश्यक सशस्त्रों तथा अन्य सामानों को अपने देश में ही तयार कर ।

अतएव भारत चीन युद्ध ने भारत की अपनी प्रतिरक्षा का ओर सजग कर दिया । भारतीय सस ने एक प्रस्ताव स्वीकार करके एक एक इंच भूमि पर से आक्रान्तों को खदेहन की प्रतिज्ञा की । प्रतिज्ञा के अन्त म भारत आत्म निभर बनने का प्रयास करने लगा । फलत इस पर अपना व्यय बहुत अधिक बढ़ गया । नतीजा यह हुआ कि भारत की राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का कार्य पूरी तरह बन्द कर देना पड़ा । एम एम राजन ने लिखा था भारत चीन युद्ध से हुई पराजय से एक मात्र महत्वपूर्ण शिक्षा यह मिली कि मरणा शय न करके बलशानकारी राज्य बनाते रहने के कारण ही अपनी क्षत्रीय अखण्डता की रक्षा नहीं कर सके । ¹ राष्ट्रीय पुनर्निर्माण व कार्य को त्याग कर राष्ट्र के समस्त साधन की प्रतिरक्षा पर केन्द्रित करने से साम होग या हानियोग दो मविष्य ही बनता प्रकटता है । सैनिक विज्झात के

लिए यह तो मानना ही पड़ेगा कि भारत न मानता विश्व-मान्यता में इन तन्त्र का सम-
बेग कर लिया है कि मान्यता प्रकृत उपायी है।

चीन का विश्व-मान्यता में नया प्रवृत्ति और मोड़ — 1970 के प्रारम्भ में
ही चीन की विश्व-नीति में परिवर्तन का बृहत्तम चिह्न मिला। जून 1970 में
विश्विय सियत का-कारी भारतवाय सहजत क माय मान्य-ननु न बृहत्तम यों क
लिए हेमकर बाते का और कहा कि भारत तथा चीन का नुन मित्र बन जाना
चाहिए। इस मायला का पन्ना को लेकर राजनयिक यों में क उरु को दान
बाजियाँ लायी गयीं। कई हस्तों तक भारत सरकार पटु बना नानु बठ रहा कि
साम्यवादी चीनका बार से गति का नानु दान्य है। पकि के राजनयिक
ने यहाँ तक कह दिया कि नया विश्व क प्रति पकि की कट्टर यचना का भवना
बद धीरे धार सनाय हा रही है। किन य म्बनायन बने यों।

दिर भा भारत सहित अनक यों क माय सम्बन्ध सुधारन का बात पकि
में सुनी जान गयी। इस समय दान्यविक्रता का पहचनकर बृहत्तम एन का कान को
सन्मुख प्रतीत हुआ किन विश्व में उनके बार में अवत का धरणाओं में क गति
वत न दान। इस नानु से प्रेरित हा-र चीन क प्रधान मन्त्रा न 1970 में बृह
देशों का भ्रम किया। विश्व-मान्यता क अत्रिक स्तर हान का संकेत इस बात से भी
मिला कि एंगोलाबिसा का तरक से चीन ने मान्यता का हा-र बनाया। इस प्रधान
कम्पुनिय जगत के दान यों क प्रति चीन क रवय में अचर-माना परिवर्तन नदर
आया। 1971 क प्रारम्भ में अमरिका क प्रति चीन का मान्यता में परिवर्तन के सन्मुख
दृष्टिकोण होन लगे। अप्रिल 1971 में चीन ने दान्य वय दान अमरिका क
पिन्गोंग टोन को निमन्त्रित किया और समक दय का रिग-मदन के लिए ठान
अनरोका पत्रकारों को भा जान दिया। इसे एक मह-बूना पन्ना दताया गया और
यह दान व्यक्त का नानु चीन और अमरिका क मायों में एक नया अन्वय
गुरु होन जाता है। चीन में विनाहियों बार पत्रकारों का बहा स्वागत था। दानों
देशों के दाव दलीलान का प्रत्यक्ष सम्बन्ध कयन था और अमरिका तथा चीनी
पत्रकारों का एक दूसरे गग में अवधानन का माय सुल गया। इसी समय दान्य
दय दान विश्व और चीन भा परम्पर गीनन सम्बन्ध कयन करने के लिए सहमत
हो गये। राष्ट्र-गति निवदन न चीन क माय मायों को सुधारन के लिए एक नया
वाचमुत्रा योजना को घोषणा की। समे यों यों क बीच मा-र का बात
भा मान्यता थी। इसी समय बृहत्तम संकेत ना निन विश्व क अत्रिक निगला या
सकता था कि भारत क प्रति भी चीन का पहल दिना कहा रवया गयी थी।
चीन की विश्व-मान्यता में इन प्रवृत्तियों के कारण अलसत्तर भारत से एक सम्बन्ध
सुधारने का सम्भावना बढ़ गया। एता लग मानों भारत क प्रति चीन के रवय में
बृहत्तम नयी आयी हा। अप्रिल 1971 में चीन में नानु धान्यिक दान में भाव लन क
लिए चीन की सरकार ने हापकाय रिग मायवाय दान्य दान्य का-रु के निमन्त्रित
किया। इसके उपरांत चीन का विश्व-मान्यता में बृहत्तम मह-बूना परिवर्तन दूर।

इसके तुरत बाद राष्ट्रपति निक्सन के निजी सलाहकार डा. हेनरी किस्सिजर ने गोपनीय ढंग से चिट्ठी की यात्रा की और चीना नेताओं से बातचीत की। 16 जुलाई को यह घोषित किया गया कि चीन के नेताओं ने राष्ट्रपति निक्सन को चीन भ्रमण के लिए आमंत्रण दिया है और राष्ट्रपति ने इस निमन्त्रण को स्वीकार कर लिया है। निक्सन की यह घोषणा अत्यन्त महत्वपूर्ण थी। यह इस बात का सबसे ठोस प्रमाण था कि चीन और अमेरिका के पुराने जग तापूण सम्बन्ध सख्त हो रहे हैं और दोनों देश अपने मतभेदों को हल करने की दिशा में प्रयत्नशील हैं तथा महान राष्ट्रों के सम्बन्धों के इतिहास में एक नया यग आरम्भ होनेवाला है।

राष्ट्रपति निक्सन की घोषणा ने भारत के लिए एक नयी स्थिति पैदा कर दी। भारत के कुम्भराजनीत रुझानों का विचार था कि वाशिंगटन का यह नया कदम अमेरिका चीन और पाकिस्तान का त्रिगुणी गठजोड़ है। इस समय भारत अपना देश की समस्या में उलझा हुआ था। पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन को मिलाने में बिचीनिया का पार्श्व भूमिका निभाया। इसलिए भारतीय नेता कुछ भयभीत अवस्था में थे। उनका अनुमान था कि चीन की स्थिति पर चीन अमेरिका मत मिलाने का तत्कास प्रभाव पड़ेगा। यही चीन की राजनीति पर स्थिति में चीन के साथ संबंधों को सामान्य करने के प्रश्न पर भारत में विचार होने लगा। भारतीय समाचार-पत्र यह भी कहने लगे कि भारत का भी चीन की नवीन स्थिति की मांग्यता देनी चाहिए और अपने विचारों के मध्य में समझौता करने के लिए यार्न प्रारम्भ करनी चाहिए। यह कहा गया कि 1962 के चीन-कम्पनिस्ट पार्टी की नौवीं कांग्रेस के बाद से चीनी सरकार का दृष्टि भारत के प्रति बहुत विपरीत नहीं रहा है। भारत विरोधी प्रचार की भाषा की कृता क्रोध तथा आरोपों की गम्भीरता प्रमाण कम होती गयी है। भारत के प्रति चीन का दृष्टि कुछ नरम अब हो गया है। भारत के आमन्त्रण पर चीनी राजदूत राष्ट्रीय उत्सवों तथा राजनयिक अवसरों में शामिल होने लगे हैं। विदेशों की राजधानियों में भारतीय तथा चीनी राजदूतों का सामाजिक सम्पर्क बढ़ा है। भारत को विपन्न स्थिति में होने के केवल एक सप्ताह पूर्व भारत को मे भारतीय और चीनी राजदूत एक ही में दो बार मिले। निश्चय ही यह एक राजनयिक औपचारिकता थी। फिर भी इनका महत्व कम नहीं है। इसका इतना महत्व भी अवश्य है कि यह कई वर्षों से जो चीनी राजदूत इस राजनयिक औपचारिकता को नहीं धरते थे वे इसको अब आवश्यक मानने लगे हैं। चीन के इस दृष्टिकोण से भारत को लाभ उठाना चाहिए। भारत सरकार भी इस आवश्यकता को महसूस करती थी और इसलिए विदेशों में वर्षों में यह कई बार कहा चुकी थी कि यदि चीन से उचित प्रत्युत्तर मिले तो भारत उससे सामान्य संबंध बनाने के लिए तैयार है। 4 अगस्त 1971 को राज्य सभा में एन. प्रसन्न के उद्घरण में विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह ने कहा था भारत की आम नीति चीन के संबंधों में सुधार का स्वागत करता है लेकिन जब तक चीन में उचित प्रत्युत्तर नहीं मिलता हम अनेकें कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोगों का कहना था कि भारत और चीन के संबंध में सीमा विवाद को जरूरत

[illegible][illegible]

अग्नि पदार्थ को जल एवं अम्ल के मिलन से उत्पन्न होकर पृथ्वी पर फैला हुआ एक पदार्थ माना जाता है। अग्नि पदार्थ को जल एवं अम्ल के मिलन से उत्पन्न होकर पृथ्वी पर फैला हुआ एक पदार्थ माना जाता है। अग्नि पदार्थ को जल एवं अम्ल के मिलन से उत्पन्न होकर पृथ्वी पर फैला हुआ एक पदार्थ माना जाता है।

[illegible]

बाद में दोनों देशों ने अपने राजदूतों को वापस बुला लिया था। यहाँ राजदूतों का फिर से नियुक्त करन की बात उठी। चीन ने प्रधान मंत्री न भारतीय प्रस्ताव का स्वागत किया और सगाव लिया कि चूँकि पहले भारत ने ही अपने राजदूत को वापस बुलाया था इसलिए उनके फिर से नियुक्ति के सम्बन्ध में भारत को ही पहल करनी चाहिए। इसी बीच भारत और पाकिस्तान में बीच लड़ाई छिड़ गयी और यह बात आगे नहीं बढ़ सकी।

वागदोर की समस्या और भारत पाक युद्ध के प्रति चीन का रुख

मार्च 1971 ई. में पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने गण्टा मुजिबुररहमान के नेतृत्व में पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा उनके आप्रिय गोपण के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जनता की चीन आरम्भ से ही पद नित मानवता का मुख्य प्रयत्न रहा है। अतः जब वगानियों ने आप्रियके गोपण के विरुद्ध विद्रोह किया और पाकिस्तान ने उसका क्रूरतापूर्ण दमन शुरू किया तब यही उम्मीद थी कि चीन उन असहाय वगानियों के साथ केवल सहानुभूति ही प्रकट नहीं करेगा बल्कि उनका सश्रिय में भी दगा। लेकिन इस समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक विचित्र करार में रही थी और चीन ने वगानों के इस को समझवाणी सिद्धान्त के दृष्टिकोण से नहीं बरन अपने राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से देखा। पश्चिमी पाकिस्तान के तानाशाहों की निंदा करने के बजाय उसने उनका समर्थन करना शुरू कर दिया। भारत वगला दश की स्वतंत्रता सेनानियों की जा में द कर रहा था चीन ने उसकी आलाचना की और इस पाकिस्तान के आंतरिक मामले में भारताय हस्त प्र बताया। यद्यपि चीन ने वगला देश के सश्रय पर कभी कोई टिप्पणी नहीं की लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान का समर्थन करके उसने वही रकबा अपनाया जो सश्रय राज्य अमेरिका का था।

इतना हीन पर भी जुलाई 1971 में आरम्भ की रा राधी ने वगला देश के बारे में चीन प्रधान मंत्री चाऊ एन साई को एक पत्र लिखा और उन्हें वगला देश की घटनाओं से अवगत कराने का प्रयास किया। मगर चीन से इस पत्र का कोई उत्तर न आया। भारत और चीन के बीच तब तक अधिक तक किसी प्रकार के सवाद के अभाव के कारण पत्र के उत्तर की आशा नहीं करने चाहिए थी। इस बीच निम्न की चीन द्वारा आमंत्रित किये जाने की घोषणा हुई तथा अगस्त में भारत सामर्थ्य सधि हुई। इसी घटनाओं ने वगला देश के प्रति चीनी दृष्टिकोण को बहुत ही पर प्रभावित किया और इस सम्बन्ध में चीन पूर्णतया भारत विरोधी बन गया। यह बराबर भारत पर आरोप लगाता रहा कि वह पाकिस्तान के अ-दलील मामले में हस्त प्र कर रहा है।

सश्रय राष्ट्रमध्य की सदस्यता प्राप्त करने के उपरांत सश्रय के भव्य चीनी प्रतिनिधि का जो पहला भाषण हुआ उनमें पुनः इस आरोप को दोहराया गया। चीनी प्रतिनिधि ने कहा कि भारत पाकिस्तान के मामले में ठीक उसी तरह हस्त प्र कर रहा है जथा उसने तिब्बत में किया था।

नवम्बर में भारत पाकिस्तान सभा पर मुक्तियों के उद्घाटन के तत्पश्चात् बड़े गद्दा और युद्ध के आसार दिखाया पहन सगा। एम नाजुक समय में पाकिस्तान का एक गिफ्टमैनल जुगुनिकार अली मुद्रा के मन्त्रालय में जाता गताओं ने प्रमाण करने के लिए पिकिंग पहुँचा। पाकिस्तानी गिफ्टमैनल के सम्मान में राजकाय भाज के अवसर पर चीन के कायदाहक विश्व मन्त्री का पेंग ने भारत पर आराप लगाया कि वह पाकिस्तान के आंतरिक मामल में दखल दे रहा है। चान ने भारत और पाकिस्तान से अपनी की कि वे अपनी सीमाओं पर तनाव कम करने के लिए आपस में बातचात करें।

आ ची पेंग ने आराप लगाया कि भारत पाकिस्तान को मदद की घमड़ी दे रहा है तथा दमनात्मक गतिविधियों में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि राप्ती के बीच विवाद सम्बद्ध दोनों पक्षा शरा बातचीत में तय करने चाहिए न कि मुक्ति बन स। आ ची पेंग ने यह भी कहा कि पूर्व दगात का सम्मान को हन करने के लिए पाकिस्तानी जनता का स्वयं का मन्त्रिपरिषद् गस्ता दूटना चाहिए। उन्होंने कहा कि टमहूनीय में तनाव का स्थिति में चान की सरकार तथा जनता काफी चिंतित है यदि पाकिस्तान पर किसी गैर का उमना हुआ तो चान का सरकार तथा जनता पूरी तरह पाकिस्तान सरकार तथा जनता सावधानिकता और सन्तुष्टता का रखा के लिए वहाँ की जनता द्वारा किये जा रहे सबय का सगा की नति समयन करेगी।

आ ची पेंग ने कहा हमारा विश्वास है कि पाकिस्तान की अधिकांश जनता देशभक्त है तथा वह राष्ट्रीय एकता तथा गैर का अवलोकन को कायम रखना चाहता है और आंतरिक पूरा तथा बाह्य हस्तगत का विरोध करता है। कायदाहक विश्व मन्त्रालय ने कहा कि हमारा मत है कि किना दग के आंतरिक मामलों का समझौता जनता द्वारा हनकिया जाना चाहिए। आ पेंग ने कहा चीन राजनीति दगाप के इस तकमल प्रस्ताव का समयन करता है कि भारत और पाकिस्तान की सगा सीमाओं से उचित दूरा तक दृष्ट जाय।

इसी बीच सन दिसम्बर में भारत और पाकिस्तान के बीच सहाय दिय गयी। 5 दिसम्बर को अमरिका के अनुरोध पर मुरगा परिषद् का बैठक हुआ। वक्त्र में अमरीकी प्रस्ताव पर बहस के दौरान चाना प्रतिनिधि ने दूरी जाय-बराग के साथ पाकिस्तान का साथ दिया। चीना प्रतिनिधि शवाग हा ने पाकिस्तान के मत को सहा बजात हुए भारत को आक्रमकारी घोषित किया। उससे अनुसार भारत ने दूरी आक्रमण सावित्य सभ के दगाप पर किया था। तद्व का मरोत्र दूरी चीना प्रतिनिधि ने पुष्टा कि गुरगापियों का बहाना लेकर क्या भारत विध्वत पर मा आक्रमण करेगा ?

जब 6 दिसम्बर को मुरगा परिषद् का दूसरी बैठक हो तबमें चान ने मा एर प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तबमें भारत पर आक्रमणकार होना का आराप लगाया गया था। इसी आराप का एक प्रस्ताव चान ने साधारण सभा के अधिवेशन (8 दिसम्बर) में

भी पेश किया। इस प्रस्ताव पर यद्यपि बहुमत नहीं हुआ फिर भी इसने चीन के भारत विरोधी रुख को प्रकट कर दिया। मुख्य प्रस्ताव (जो पारित हो गया) पर बोलते हुए चीनी प्रतिनिधि ने कहा कि उसने युद्धविराम प्रस्ताव के पक्ष में वोट तो द दिया है लेकिन 'चीन प्रस्ताव को सत्तापजनक' नहीं मानता क्योंकि 'समय हमलावर और पोषित में अंतर नहीं किया गया है और हमलावर का नाम भी नहीं लिया गया है। किसी भी राज्य के अदलतों मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। चीनी प्रतिनिधि ने भारतीय कायवाही की तुलना 1931 ई. के जापानी कायवाही से की जब जापान ने चीन के एक प्रांत मंचूरिया पर आक्रमण किया था।

10 दिसम्बर को चीन के समाचार पत्र पिपुल्स डेली ने भारत की चेतावनी खते हुए लिखा— भारत साधारण सभा के प्रस्ताव का भारीतरफ़ा खंडन कर रहा नहीं तो उसे एक घोर नज़ाज़नक़ पराजय का मुहू देवना पड़ेगा। यदि तुम विश्व जनमत की अपेक्षा करना चाहते हो और सोवियत साम्राज्यवादियों की मदद से यह सोचते हो कि तुम दुनिया में जो चाहोगे कर सोगे तो यह तुम्हारी भारी भूल है। इसमें अतः तुम्हारी पराजय निश्चित है। चीन की जनता पाकिस्तान की जनता के साथ है।

चीन का जो इसने से ही नहीं भरा। 16 दिसम्बर को उसने आरोप लगाया कि सिक्किम सीमा की ओर से कुछ भारतीय सैनिक तिब्बत में घुस आये हैं। यह सरासर ग़लत आरोप था। लेकिन इसके कुछ उद्देश्य थे। अमेरिका के साथ बंधन का आगमन हो चुका था। चीन की घमकी का पाकिस्तान के साथ एकता प्रदर्शित करके उसने मनोबल को उठाना और भारत की परेशानी में डालना था।

भारत की प्रतिक्रिया —संयुक्त राष्ट्रसंघ के मंच से अथवा रेडियो प्रसारण में चीन का रुख स्पष्टतया भारत विरोधी था और अमेरिका से किसी तरह कम नहीं था। लेकिन चीन के सद्म में भारत का रुख बराबर नरम बना रहा। अमेरिका की नीति और उसके रवये की तो मूल आलोचना हुई लेकिन चीन के सम्बंध में समय से काम लिया गया। इसका कारण यह था कि चीन बिगुल पक्ष में था और युद्ध के पहले उसके साथ सम्बंध सामान्य करने की बात थी। ऐसा हालत में चीन जबनफ़ को विरोधी कदम नहीं उठाता तबतक उसके साथ भौतिक मध्यम में खूबना एकदम बेकार था। इसलिए 2 जनवरी 1972 को एक प्रेम सम्मेलन में बोलते हुए प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी ने कहा भी कि चीन द्वारा पाकिस्तान के समर्थन के बावजूद भारत के सम्बंध चीन से बेहतर हो सकते हैं। युद्ध के शिरो में चीन के रवये पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि चीनी दलितों के बारे में जो अनुमान लगाया गया था कि वह सही निकला। चीन ने भारत पाकिस्तान-युद्ध पर एक नयी नुस्ती प्रतिक्रिया की जो हमारी कल्पना से परे नहीं थी यानी चीन ने न तो हमारा प्रयास से अधिक पाकिस्तान का समर्थन किया न उचित रूप।

भारत पाकिस्तान युद्ध में चीन के रक्षकों की दलवार एवं प्रश्न उत्पन्न होना स्वाभाविक है। चीन क्या सबूत की घंटा में चपचापा रखा देखता रहा और व्यय का आनाश प्रयत्न कर पाकिस्तान का तसल्ली देता रहा। अनेक बार चीन की ओर से कहा गया था कि हम पूरा तरह पाकिस्तान के साथ हैं और माह्या खां भी पूर्व में फंसी सैन्य की तसल्ली दिनांत है कि अमरिका और चान हमारा मदद में आना चाहते हैं।

चीन के अलग खड़े रहने के कारण कोई हो सकता है। तबता है कि उस सावियत संघ का भय था कि इस लड़ाई में चान के कू. न ही सोवियत संघ सिविलियन का धार से सैनिक दबाव डाल सकता था क्योंकि सावियत संघ युद्ध में बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ आत्म चेतावनी दे चुका था। सके अतिरिक्त किसी भी हारत हुए देश का जितना समय अपने दोस्त का मरान तक जान के लिए देना चाहिए वह पाकिस्तान नहीं दे पाया। यदि पाकिस्तान कुछ दिनों के लिए और युद्ध चलाता तो सम्भव था कि चीन उसके पक्ष में मरान में कू.ता।

भारत के प्रति चीन का नवीन दृष्टिकोण—स्वतंत्र बगना देश का स्थाना के बाद भी भारत के प्रति चीनो रक्षकों में काई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। फरवरी 1972 में पोलैंड में चीन के राजदूत ने भारतीय राजदूत से मुलाकात की। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार उस मुलाकात में दोनों राजदूतों के बीच काई ऐसी बातचीत नहीं हुई जिसका राजनीतिक महत्व हो। इसके बाद 15 अगस्त 1972 को ताल किला के समारोह में चीनी दूतावास के कुछ प्रतिनिधि भी उपस्थित थे लेकिन इस उपस्थिति का भी कोई राजनीतिक लक्ष्य नहीं निकाला जा सकता। कारण अबतक चीन ने कोई ऐसी बात नहीं कहा है या कोई ऐसा काम नहीं उठाया है जिससे कि हम तत्काल पर पटु हो जाय कि वह भारत के साथ अपने सम्बन्ध सुधारना चाहता है। जबकि विपरीत भारत ने सरकार स्तर पर कई बार इस बात का संकेत दिया कि वह चीन के साथ मंत्री बनना चाहता है। 19 अगस्त 1972 को कुछ अमरिकी सैनिकों के साथ बातचीत के दौरान प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी ने कहा था कि भारत चीन के साथ अपने सम्बन्ध बेहतर करना चाहता है। तबकि चीन ने अब तक इस सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया है।

शिमला समझौते के बावजूद भारत के प्रति चीन के रक्षकों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। संयुक्त राष्ट्रसंघ में वगैरह देश के प्रवेश को रोकने के लिए चीन ने वीटा का प्रयोग किया। इससे यह स्पष्ट हुआ गया है कि चीन इस उपमहादीप में हुए परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। भारत के प्रति चान का दृष्टिकोण इस प्रकार क्या जटिल होता जा रहा है? इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि भारतीय उपमहादीप के प्रति चीन का नीति का सबसे बड़ा निगायक तब भारत सोवियत मंत्री संधि हो गया है। इस संधि में बहुत सा घाते जुड़ा हुआ है। सैनिक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मंत्री संधि सामूहिक सुरक्षा के अनेक सिद्धांत

का एक ऐसा प्रतिरूप है जो एशिया की आवेकताओं के अनुसृत मढ़ा गया है। प्रज व का मिट्टात चीन से सम्बन्धित है और जाने अनजाने इस सचि न चीन से हमारा एक विदाय प्रकार का रि ता कायम कर रिया है—एक एगा रि ता जो विनिग की दृष्टि म मन्त्राण नहा है। चान यह मानकर चल रहा है कि सोवियत सघ चान के पारो ओर जा घराबो कर रहा है। भारत उजो से उजका अण बनता जा रहा है। दक्षिण एशिया के हर मान पर रूसी मन्त्रिका का अधिकाधिक विराध चीन की विदेशनीति का स्वाभाविक अण बन चला है। इस तरह चान द्वारा भारत व विरोधका मुख्य कारण सोवियत सघ के प्रति चीन की विता और नीति है। चीन भारत को सोवियत सघ से घनिष्ठ रूप से सम्बन्ध मानता है और इसलिए चीन की भारत का विरोध करना आवेक कर और स्वाभाविक लग रहा है। एसी स्थिति म यह उम्मीद करना व्यथ है किर्बनकट भविष्य म चीन और भारत के सम्बन्ध मर्याद हो जाय। अग्रिन 1974 में भारत सरकार के विदेश मन्त्रानय द्वारा "वागित एक प्रतिवेदन से इस बात की पुष्टि हाती है। प्रतिवे न म कहा गया था कि चीन के साथ सम्बन्धो को सामान्य बनान की भारत की त्र दृष्टि के बावजू चीन की प्रतिक्रिया अनुकूल नही रही है। चीन भारत की ओर से आा बन है क्योंकि यह सोवियत सघ का घनिष्ठतम सूर्योगो बन गया है। चीन के साथ भारत के सम्बन्ध "सो हात म सुधर सकते है जब हम य साबित कर द कि सोवियत सघ से हमारी दोस्ती का मतलब यह नही कि विदेश नीति के मामल म हम अनगनी खतरा खो पात है।

कोटनित गिष्टमडल पो चीन यात्रा—निरट भवि २५ भारत चीन गम २ की सम्भावना बहुत कम है। लेकिन ठउ २ गवर्ण म कुल प जाए तेमो घटी है जो भविष्य मे दोनों के घलओन के लिए आधार साबित हा सकती है। 24 म 1974 को पौब सस्ताह के लिए अग्रिच भारतीय डा. द्वारकानाथ का निग स्मारक समिति के धार से रशो का एक सम्भावना गिष्ट म २ चीन-व्यापार पर गया। 1971 म भारत सोय टेगुन टेनिस टीम के च न अग्रण के बा भारत और चीन की जनता म प्रत्यण सवा का यह पहला अवसर था। गिष्टमडल व नेता दानिएन सकोपी के अनुसार हम जही जही भी गये हमारा असाधारण रनू से स्वागत हुआ। भों देगो के राजनयतिक सम्बन्ध सधारन म गिष्ट मडल न वा पहन नही को यह एसा कर भा नही सकता था। अतः यह दाना देशो का सरकारों पर टी निमर करता है कि वे राजनयतिक सम्बन्ध सधारन की शिा म व म बडावे। आइ बक पर चीन की शानि कारी शता की सवा के लिए भेज गय भारतीय विविमल दल की अलख सदभावना और वक्तव्यपरायणता के प्रतीक डा. कोटनित का स्मति में गठित सह्या के म स्य चीन जाकर मुख्यतः उन सम्बन्धो का स्मति का ही उमार सव जो राजनयतिक पीठ पर सने से नही मिट सकती है। रि तु गिष्ट मडल व भाय चीन सरकार के विरुध व्यपहार से य संकत अण म मिला कि इस सामित मवाद का आग चलकर कभा एक राजनयतिक सवा के रूप म परिवर्तन एमम लगम्भव नही है।

भारत और पाकिस्तान

अगस्त, 1947 में दो दुकहों में भारत का विभाजन करके भारत और पाकिस्तान नाम के राष्ट्रों का निर्माण हुआ। पाकिस्तान का जन्म साम्प्रदायिकता के आधार पर हुआ था। भारतीय मुस्लिम लोग न 'दो राष्ट्रों' के सिद्धांत (Two nations theory) का प्रतिपादन करत हुए भारतीय मुसलमानों के लिए एक पृथक् राष्ट्र की मांग रखी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस मांग का प्रबल विरोध किया और जब को दूसरा विकल्प नहीं रहा तभी उसने देश के विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार किया। इस कारण मुस्लिम लोग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच काफ़ी कटुता बढ़ी। देश के विभाजन के उपरान्त पाकिस्तान में मुस्लिम लोग की और भारत में कांग्रेस की शासन की बागडोर मिली। विभाजन के बाद यह उम्मीद की गयी थी कि भारतीय उपमहाद्वीप के ये दोनों राष्ट्र पुराने बातों को भूलकर शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे। दोनों गरीब मुल्क थे और दोनों के समान लगभग एक-सी ही समस्याएँ थीं। लेकिन इन सामान्य समस्यारों ने उनके पारस्परिक सम्बन्ध का किसी तरह प्रभावित नहीं किया और ब्रिटिश शासनकाल में जो कटुता उत्पन्न हुई थी वह ज्यों-की-त्यों बनी रही। शका और सन्नेह के वातावरण में उनका जन्म हुआ था और दोनों देशों के सम्बन्ध में सार सत्य विद्यमान रहे। ऐसी हालत में दोनों देशों का सम्बन्ध खराब रहे यह बिल्कुल स्वभाविक था।

इस प्रकार के वातावरण का विभाजन की प्रतिक्रिया और उसके उत्पन्न समस्या ने और भी गहरा कर दिया। 1947 के साम्प्रदायिक दंगा तथा अराजकता में जल्ने छुटकारा पाने के लिए देश का विभाजन बहुत ही अल्प समय में कर दिया गया। बहुत सी समस्याओं को देश में निश्चिन्त करने के नाम पर छिपा दिया गया। स्मरणीय है कि ब्रिटिश काल में राजनीतिक दृष्टि से भारत दो भागों में बंटा हुआ था — ब्रिटिश भारत और आज़ाद भारत। भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम में दोनों राष्ट्रों के सम्बन्ध में यह व्यवस्था की गयी थी कि 'नए नए अपने-अपने हितानुसार किमा भा नव निर्मित होमिनियन में शामिल हो सकेंगे'। इस व्यवस्था का दोनों देशों ने निश्चिन्त मन से अग्रसारित और पालन की परम्परा वहीं से शुरू हो गयी।

दोनों राष्ट्रों की समस्या — दोनों रियासतों के सम्बन्ध में भारत और पाकिस्तान का बराबर मुख्य रूप से तीन रियासतों का लेकर हुआ जनागढ़, हैराबाद और कच्छ। जनागढ़ और हैराबाद दोनों के नए मुसलमान थे, लेकिन उनकी

बहु स हदक प्रजा हि दु थी । जनागढ़ के नवाब ने अपनी रियासत का पाकिस्तान में मिलाने का निणय किया । भारत ने इसका विरोध किया और सनिक कारवाई करके नवाब को पाकिस्तान भाग्य व लिए वश कर दिया । रियासत के दीवान और वहाँ की पुलिस ने जिसका हाथ में वहाँ का प्रशासन या भारत सभ में जनागढ़ के मिलने की घोषणा की । 9 नवम्बर 1947 को भारत सरकार ने रियासत का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया । फरवरी 1948 में जनागढ़ में राय के विमर्शन के प्रश्न पर जनमत संग्रह कराया गया जिसमें भारत के विरोध में केवल 91 मत पड़े ।

भारत की इस कारवाई का पाकिस्तान ने बड़ा विरोध किया और जनमत संग्रह को ढोंग कहते हुए इस प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठे पा ।

हैदराबाद राज्य का शासक निजाम अपने को स्वतन्त्र रखना चाहता था लेकिन भौगोलिक स्थिति के कारण भारत सरकार इस बात को नहीं मान सकती थी । हैदराबाद के राजाकारों के साम्प्रदायिक संगठन ने स्थिति को और भी गम्भीर बना दिया । फलतः सितम्बर 1948 में भारत को हैदराबाद के खिलाफ भी सनिक कारवाई करनी पड़ी । इस प्रश्न पर पाकिस्तान ने हैदराबाद के निजाम का समर्थन किया । हैदराबाद का प्रश्न भी सुरक्षा परिषद में आया । लेकिन इस प्रश्न पर भी सुरक्षा परिषद का कोई नियम नहीं हुआ । भारतीय प्रतिनिधि ने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा कर दी कि वह इस प्रश्न पर किसी बात विचार में भाग नहीं लेगा ।

देगी रियासतों के सम्बन्ध में कश्मीर को लेकर भी विवाद उठा उसने भारत पाकिस्तान के सभ्रत पूरा सम्बन्धों को खराबी कर दिया । कश्मीर की समस्या को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य जो विवाद उठ सहा हुआ उसने भारत पाकिस्तान सम्बन्धों के सभी पहलुओं को प्रभावित किया । अतएव इसका वजन हम आगे विस्तार प्रवक करेंगे ।

देगी रियासतों की समस्या के अतिरिक्त भारत पाकिस्तान के सम्बन्धों में और भी कई विवाद के कारण थे । उनका संक्षिप्त वर्णन नीचे दिया जा रहा है —

आधिकारिता — विभाजन के उपरान्त पाकिस्तान और भारत के बीच कई आधिकारिक समस्याएँ थीं । दोनों देशों के बीच आमन्त्री तथा वज्र का बदलावा एक सामान्य घन के सम्बन्ध में सन्तोषजनक विभाजन करना था । मुद्रा के सम्बन्ध में निणय लेना था । भारत को अविभाजित भारत के मुद्रा बकाया का पक्षपन कराह रखा पाकिस्तान को देना था । इसा समय कश्मीर का मुद्रा सम्बन्ध हुआ । भारत सरकार ने इस हकका की अापी को स्वीकृति करने का निश्चय किया । लेकिन महत्वा गांधी से इस निणय का विरोध किया और तब भारत सरकार को अपना निश्चय अस्वीकार करना पड़ा । इस में अस्वीकृति के कारण स्थिति तेज हो गई । इस हकका निश्चय पर पहुँचे हैं कि हमारे इस आदर रखने से जो भारत के उच्च आग्यों और गांधीजी के पुनर्मान का के अनुकूल है विश्व को विश्राम हो जायगा कि हम पूरे तोर से गति और उद्वेगना के हकका हैं । लेकिन पाकिस्तान को भारत के इस उच्च आग्य पर विश्राम नहीं हुआ और कुछ ही दिनों के भीतर व्यापारिक

सम्बंध में भी इन नयी सुर हर्ष क्यों कि पाकिस्तान न तुरंत हा जूट क नियात पर प्रतिबंध लगा दिया। सुर के अदम्य क कारण ना दोनों देशों क मध्य तनाव पदा हुआ। कुछ दिनों क उपरांत जायिक सम्बधों को सुधारने का यत्न किया गया और इसमें कुछ सफलता भी मिली। तबिन इसका कोई स्थायी समाधान नहीं हो सका।

जायिक समस्याओं में सबसे कठिन विस्थापिता की सम्पत्ति की समस्या थी। विभाजन के बाद पाकिस्तान क बहुत से हिंदू भारत और भारत से बहुत से मुसलमान पाकिस्तान अपनी अपनी सम्पत्ति छाटकर भाग छड़े गए। इन सम्पत्तियों के हस्तांतरण का प्रश्न तबिन कठिन बन गया। पाकिस्तान में यह मुसलमानों की सम्पत्ति तीन करोड़ से ऊपर हुआ थी और भारत में मुसलमानों की सम्पत्ति केवल तीन से करोड़ का थी। विस्थापित सम्पत्ति के इस प्रश्न को हल करने के लिए भारत सरकार की ओर से सलाह दिया गया कि दोनों देशों की सरकारें मिलकर सरकारी स्तर पर इस प्रश्न का समाधान करें और पाकिस्तान सरकार भारतीयों की बचाया सम्पत्ति का भारत-सरकार को मुआवजा करे। इस कठिन समस्या का समाधान के लिए भारत और पाकिस्तान के अम्बिवागियों के मध्य बहस बातचीत भी हुई। तबिन कोई समझौता नहीं हो सका। अल्पसंख्यकों की रक्षा क प्रश्न ने इस समस्या को और भी जटिल बना दिया। विभाजन के बाद ही अल्पसंख्यकों की रक्षा का प्रश्न सम्भीर रूप से उपस्थित हुआ। दोनों देशों में साम्प्रदायिक तनाव और लोगों के कारण हुए समस्या को सुलझना बड़ा कठिन सिद्ध हुआ। 2 अप्रिल 1950 का साम्प्रदायिक-हृत्पत्रों का राजनयिक सम्पर्क में रक्षा की भावना उत्पन्न करने तथा विस्थापितों की सम्पत्ति के सम्बंध में भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों के बीच एक समझौता हुआ जिसके नूतनन्यायकत होती समझौता (Nehru Liaquat Ali Pact) कहते हैं। तबिन इस समझौते में इन समस्याओं का पूरा समाधान नहीं हो सका।

नदियों के पाना का झगडा—तबिन इन सभी समस्याओं से सम्भार समस्या भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के पाना का झगडा था। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ सभा नदी 1 भारतीय क्षेत्र में निकलती हैं। विभाजन के बाद पाकिस्तान को यह मय हुआ कि यदि भारत से पाकिस्तान का सम्बंध बहुत दूरा रहा तो भारत इन नदियों के बहाव को रोककर अपने ज भाग में मात्र न सक्ता है जिससे सिंधु के पाना के अभाव में पाकिस्तान को बहुत नुकसान पैदा सक्ता है। भारत का भी अपने जायिक विकास के लिए स सदा बाध बधदाना अवकाश था। ऐसी हानि में दोनों देशों के बीच नदियाँ के पाना के प्रश्न का लेकर स सदा का उत्पन्न होना अवकाश पमावा था।

विभाजन के बाद इन क प्रश्न का समाधान नदियों के पाने पर ही और दोनों देशों के बीच स तनाव बना। 1959 में एक हमरी की विधान सभिन तबिन यत्न ने इस समस्या का राजनयिक स्तर पर हटाकर तबिन स सदा पारित स्तर पर मुआवजा का सलाहना और इसका लिए विश्व बैंक (World Bank)

मन्त्र नेने को मिकारिंग की। सितम्बर 1951 में इस वें के अध्यक्ष मुनीन इनक ने सम्पत्तता करता स्वीकार कर लिया। मुजीब लक और उनके बाद में इस्लाम सहयोग से यों तक बानी चान के उपरांत 19 मिनम्बर 1960 के भा 7 और पाकिस्तान के बीच जल के प्र न पर एक समझौता हो गया। इस समझौता को 1960 का नहरी पानी समझौता कहा है जिस पर प्रधान मन्त्री नेहरू और राष्ट्रपति अयूब खान ने स्वयं रावलपिंडी में हस्ताक्षर किये। इस समझौते के अनुसार आ कि नदिया के विभाजन पर आधारित है यह निश्चय किया गया कि दस वष की आत रिक्त अवधि के बाद जो पाकिस्तान की प्रायना पर त न वष के लिए बढ़ायी जा सकती है सोना पूर्वी नदियों का पानी भारत के अधिकार में रहेगा जबकि सोनों पश्चिमी नदियों का पानी पाकिस्तान के अधिकार में केवल इसका भीमिन पानी उत्तर की ओर जम्मु और कश्मीर प्रांत में प्रयाग किया जायगा। यह तय हुआ कि दस वष तक भारत पूर्वी नदियों (सप्तर्षी रावी और वास) से पाकिस्तान को प्रायेक वष घटता हुई मात्रा में पानी देगा और नयी जोड़ने वाली नहरा के निर्माण के लिए पाकिस्तान को आवश्यक मात्रा में धन न देग। यदि पाकिस्तान भारत से पानी देनेवाली अवधि में तीन वष के लिए प्राप्तता करेगा तो प्रायना स्वीकृत होये पर उसी अनुपात में भारत द्वारा पाकिस्तान को दी जानेवाली धन राशि में कमीती कर दी जायगी।

12 जनवरी 1961 को इस संधि को शर्तें लागू कर दी गया और इस प्रकार दोनो देशों के बीच का एक बहुत बड़ा विवाद शांत हो गया। समझौता पर टिप्पणी करते हुए अशहरवल नहरा ने यह वास्तवमें एक बहुत अवसर और कई रूपों में एक स्मरणीय निम है। स्मरणीय है कि इस रूप में कि इसने द्वारा कई वषों में भारत पाकिस्तान के सम्मुख प्रस्तुत एक अत्यंत कठिन और जटिल समस्या को हल करने सतोपजनक रूप में मुत्तझा दिया गया। स्मरणीय इस रूप में भी कि यह हमारे दोनो देशों और विश्व बक के सामूहिक प्रयत्नों का एक अनुपम उदाहरण है।

कश्मीर का विवाद

समस्या का सूनपात — 15 अगस्त 1947 का विभाजन के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में दो राज्यों—भारत और पाकिस्तान की स्थापना हुई। स्वतंत्रता के पूरे महीने में बहुत से देशी राज्य थे जिनको विभिन्न सरकारों के साथ विशेष गठितों के अंतर्गत पर सम्बंध कायम था। स्वतंत्रता केन के पूरे दिशि नर नर न यह घोषणा कर दी कि भारतीयोदेशी राज्य अस्त ह आनुसार अस्त होया ह। निर्माण करेग। के बाद तो भारत या पाकिस्तान में गांधी मित्र सन्त हैं अबव अस्त ह। है। कश्मीर देश तरह का एक देश राज्य था जिसका शासन एक विदूषा राजा जिसका नाम था बहगुन मुर्तिम था। कश्मीर के राजा ने स्वतंत्र रहने का निर्णय किया। लेकिन पाकिस्तान एक राज्य को अपने साथ मिलाता चाहता था। तब से उसने कश्मीर पर आप्रिया दमक डाला जिससे बाध्य हुआ कि पाकिस्तान के साथ मित्र जाय।

हुमलावर कबालियों को पदोपयोगी सामग्रियां से सहायता कर रही था। इस हासत में भारत सरकार ने सशस्त्र राष्ट्रसंघ चार्टर की धारा 34 और 35 के अन्तर्गत सुरक्षा परिषद से यह शिकायत की कि पाकिस्तान से सहायता पाकर कबाली लोग भारत के एक अंग कश्मीर पर आक्रमण कर रहे हैं जिससे अन्तर्राष्ट्रीय शांति के भंग होने का भय है। अतएव सुरक्षा परिषद में आक्रमण को रोक कराने के लिए कदम उठावे। पाकिस्तान ने भारत के आरोपों का खण्डन किया और उस पर अनेक प्रचारोप लगाते हुए कहा कि भारत में कश्मीर का विनयन अवध है।

भारत की शिकायत पर सुरक्षा परिषद को कोई निश्चित निणय नही चाहिए था। उसको आक्रमण करने वाला के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नही हुआ। बात यह थी कि सुरक्षा परिषद में अमरीकी गुट का दामत था और भारत गीत युद्ध के क्षय में असहमता की नीति का अवलम्बन कर रहा था जो अमरीका को फटा खोलों में नही सहाता था। इससे विपरीत पाकिस्तान इस गुट का एक पिछलगुआ था। अतएव अमरीकी गुट ने टान मटोन की नीति अपना कर वास्तविक प्रश्न को ओझल करने का यत्न किया। 20 जनवरी का सुरक्षा परिषद ने तीन सदस्यों के एक आयोग की स्थापना का फैसला किया जिसका एक सदस्य भारत की सिफारिश पर दूसरा पाकिस्तान की सिफारिश पर तथा तीसरा इन दोनों की सिफारिश पर नियुक्त होता। आयाग को बीच पन्नाल और मध्यस्थता का काम सौंपा गया। भारत ने इस आयोग के लिए चेकॉस्लोवाकिया को और पाकिस्तान ने अर्जेंटीना को चना पर ये दोनों राज्य तीसरे नाम के लिए सहमत नहीं हुए। इस कारण सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष ने सशस्त्र राज्य अमरीका को आयोग का तीसरा सदस्य मनोनीत कर दिया। 21 अप्रिल को सुरक्षा परिषद ने आयोग में दो और सदस्य बढ़ा दिये। ये सदस्य कोलम्बिया और बेल्जियम थे। इन पाँच राज्यों से आयोग बना और उसका नाम भारत और पाकिस्तान के लिए सशस्त्र राष्ट्र का आयोग (United Nation Commission for India and Pakistan) पड़ा। इसी बीच सुरक्षा परिषद ने एक और प्रस्ताव पास किया और यह सिफारिश की कि कश्मीर से विदेशी कबालियों पाकिस्तान के नागरिक और भारतीय मना हटा जाय और भारत माघण लेखन की स्थापना करना करके अनमत समूह के लिए उचित वातावरण तयार करे।

संयुक्त राष्ट्र आयोग (U N C. I P) के रूप में सशस्त्र राष्ट्र आयोग ने अपना काम तुरत शुरू कर दिया। विचार के दोनों पक्षों में मिलने और उनके विचारों से अवगत होने के पश्चात् उसने दोनों पक्षों से युद्ध बन्द करने का कहा और समझौता करने के लिए एक प्रस्ताव रखा जिसके मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित थे (1) पाकिस्तान कश्मीर से अपनी सेना हटा ले तथा बिना कबालियों और कश्मीर में सामान्य रूप से न रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को वहाँ से हटाने का प्रयास करे (2) इस प्रकार के क्षेत्र को जिसको पाकिस्तानी सेना ने छापी कर रखा है उसका वास्तविक प्रबंध आयोग के निरीक्षण में स्थानीय अधिकारी करें (3) जब पाकिस्तान इन दोनों

शर्तों को पूरा कर ल और आयोग इसका सूचना भारत को दे दे तो भारत भा अपना सेना का अधिकांश भाग कश्मीर से हटा ल । 4) अन्तिम समझौता होने तक भारत युद्ध विराम की सुमांजा के भीतर उतनी ही सेनाए रखे जितना उस प्रान्त में कानून और व्यवस्था के लिए आवश्यक है ।

भारत में पाकिस्तान ने इन शर्तों को मानने में टाउमटान की पर वाद में कुछ शर्तों के साथ इस प्रस्ताव का मान लिया । उसके बाद उदा वास्ता के बाद 1 जनवरी 1949 का दोनों पक्ष युद्ध बंद कर देने पर सहमत हो गए । एक युद्ध विराम रेखा निश्चित की गयी और उसका कुछ भाग के लिए आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों के निरीक्षक नियत किए गए । कश्मीर का अन्तिम फैसला जनमत संग्रह द्वारा होना था । अतएव जनमत संग्रह के प्रस्ताव के लिए अमरीका नागरिक श्री चार्टर निमिटज का नियुक्त किया गया । प्रस्ताव बनकर वह कश्मीर पहुँचा और भारत तथा पाकिस्तान की सरकारों में जनमत संग्रह के सिद्धान्त पर बात कराने लगा । पर दोनों पक्ष इस प्रश्न पर राजी नही हो सके । चार्टर निमिटज ने तब पत्रत्याग कर दिया ।

मकनाटन योजना — इसके बाद पाकिस्तान के आक्रमक आदा के कारण कश्मीर का समस्या पुन गम्भीर होना लगा । उस हाउस में 29 दिसम्बर 1949 का सुरक्षा परिषद के कनाडियन अध्यक्ष जनरल मकनाटन ने समस्या को सुलझाने के लिए एक प्रस्ताव रखा जिसकी मकनाटन योजना (Mc Naughton plan) कहते हैं । इस योजना में भी पाकिस्तानी आक्रमण की कोई चर्चा नहीं थी और आक्रात तथा आक्राता को एक ही स्तर पर रखा गया था । इसमें पाकिस्तानी सेना को हटाने के साथ साथ भारतीय सेना को हटाने की बात भी थी । इस प्रकार कश्मीर का अक्षय्यकरण करके जनमत संग्रह का प्रस्ताव किया गया था । अनेक कारणों से भारत का यह प्रस्ताव मान्य नहीं था ।¹ इसलिए उसी उस योजना का अस्वीकृत कर दिया ।

डिक्कान मिशन — मकनाटन योजना के विफल होना पर 24 फरवरी 1950 को सुरक्षा परिषद ने एक और प्रस्ताव स्वीकार किया जिसका वास्तव पाँच मनीन के माध्यम से कश्मीर में दोनों पक्षों की सेनाए हटाने का था । इस काम का वास्तव दिया के उक्त आवादाय के आयोग पर आवत डिक्कान का सौंपा गया । म 1950 में

1 मकनाटन योजना पर बोलते हुए मध्यवर्ती राष्ट्रमंडल में भारतीय प्रतिनिधि श्री वरुण चरित्त रय ने कहा Today the position is that Pakistan which throughout 1948 denied giving any aid either to the invaders or to the Azad Kashmir force is not only an invader but in actual occupation of nearly half the area of the state without any lawful authority from any source. This is naked aggression of which no one can approve but there is no sign of disapproval in the present proposal the Mc Naughton proposal

डिविजन ने अपना काम शुरू किया। उसने कश्मीर से दोनों पक्षों की सेनाएँ हटाने पर जोर दिया। डिविजन की अंतिम योजना सपूर्व कश्मीर में जनमत संग्रह के स्थान पर इसका विभाजन करने की थी। उसका यह प्रस्ताव था कि आक्षेप पाकिस्तानी अधिकार में है यह उसके साथ रहे जो भारतीय सेना द्वारा अधिकृत क्षेत्र है भारत में रहे और कश्मीर घाटी का भाग्य निर्णय जनमत संग्रह द्वारा हो। लेकिन यह योजना दोनों पक्षों में किसी को भी माय न हुई। भारत अपनी सेना हटाने पर भी नहीं राजी हुआ क्योंकि उसके विचार में पाकिस्तान की सेना कश्मीर में आक्रमण करने के लिए लायी थी और भारतीय सेना कश्मीर सरकार के अनुरोध पर उसकी रक्षा के लिए लगी थी। सबसे आखिर की बात तो यह थी कि यद्यपि डिविजन ने यह स्वीकार किया था कि कश्मीर में विरोधी कबालतियों तथा मई 1948 में पाकिस्तान की नियमित सेनाओं का प्रवेश अंतर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन था। फिर भी उसने भारत और पाकिस्तान दोनों को एक ही स्तर पर रखा। इस हालत में डिविजन यह समझ गया कि कश्मीर की समस्या उससे नहीं संलग्न सकती है। अतएव उसने सरक्षा परिषद से अनुरोध किया कि उस उसके पक्ष भारत से मुक्त कर दिया जाय। सरक्षा-परिषद को उसने यह भी परामर्श दिया कि दोनों पक्षों की प्रत्यक्ष वार्ता करके इस प्रश्न को हल करना चाहिये।

प्राहम मिनत —सर ओवेन डिविजन की विफलता के बाद सदन में राष्ट्रमण्डलीय सम्मेलन ने कश्मीर समस्या का समाधान का एक और यत्न किया। इसमें अक्स जोकरग तथा पचापती फसने का प्रस्ताव रखा गया। लेकिन भारत को इन तरह का कोई भी प्रस्ताव माय नहीं हो सकता था। इसी समय कश्मीर की सरकार ने संविधान बनाने के लिए एक संविधान परिषद के निर्वाचन की योजना बनायी। इस पर परवरी 1951 में पाकिस्तान ने कश्मीर के प्रश्न को पुनः सरक्षा-परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किया। परिषद ने ब्रिटेन और अमेरिका के एक संयुक्त प्रस्ताव का पास करके सर आवनडिविजन के एक उत्तराधिकारी को नियत करने का फैसला किया जो कश्मीर में दोनों पक्षों की सेनाओं को हटाने पर जनमत संग्रह का रास्ता तयार कर सके। 20 अप्रैल को फिर एक अमेरिकी नागरिक डा. फ्रैंक पाउम का इस पक्ष पर नियत कर दिया गया।

प्राहम अखिल भी वहीँ तक इस समस्या को सुलझाने का प्रयास करना रहा। इसके लिए उसने खूब प्रयास किये। पर कोई भी प्रस्ताव दोनों पक्षों का माय नहीं था। मार्च 1953 का प्राहम न अपनी अंतिम रिपोर्ट में डिविजन की नीति यह सुझाव दिया कि इस समस्या का सुलझाने के लिए भारत और पाकिस्तान में प्रत्यक्ष वार्ताएँ होनी चाहिए।

प्रधान मंत्रियों की वार्ता —प्राहम के उपयुक्त सुझाव के अनुसार दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों ने सदन करीबी और नयी दिशों में कश्मीर के संबंध में बातचीत किया जिसमें उन्होंने यह तय किया कि जनमत संग्रह 1954 में किया जाय और उसकी देख रेख के लिए प्रासंगिक नियुक्त कर दिया जाय। परंतु जनमत संग्रह के

प्रशमक के नाम पर दोनों के बीच कोई समझौता नहीं हो सका। फिर भी दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों के बीच पत्र व्यवहार होता रहा।

पाकिस्तान अमरीकी सैन्य हस्तक्षेप और कश्मीर समस्या के बहस में परिवर्तन—इसा बीच कुछ ऐसी घटनाएँ घटीं जिसके फलस्वरूप कश्मीर समस्या के स्वरूप में आमूल परिवर्तन आ गया। 1953-54 में पाकिस्तान पाश्चिमी गुट में शामिल हो गया। समस्त राष्ट्र अमरीका से उसका गुप्त सौदा हुआ कि जिम्मे अनुसार पाकिस्तान न सैनिक सहायता देना स्वीकार करेगा। 22 फरवरी, 1954 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सादुल्लाह जहाँ ने स्वयं यह घोषणा की कि संयुक्त राष्ट्र अमरीका पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सैनिक सुरक्षा दानन के अंतर्गत सैनिक सहायता देने का तयार हो गया है। भारत ने पाकिस्तान का अमरीका द्वारा सैन्य सहायता दिये जाने का तीव्र विरोध किया तथा अमरीका के नागरिकों को जो कश्मीर में कार्य कर रहे थे अत्रालास घाटे में निकल आने का आदेश दिया। यद्यपि अमरीका ने अपने स्वयं की नीति में कहा कि पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने का उद्देश्य भारत की शक्ति पहुँचाना नहीं है किन्तु अमरीका के इस सटोकेषण की ओर उस समय तुरंत ही खुल गयी जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की कि सैनिक सहायता से उन्हें कश्मीर की समस्या को सुलझाने में सहायता मिलेगी। अब भारत में अमरीका के प्रति एक अवस्था का भाव आने लगा और इसीलिए उस अमरीका विरोधी मंच समयक हान का खिताब दिया जाना लगा।

अमरीका द्वारा पाकिस्तान का सैन्य सहायता का कश्मीर की समस्या पर अवलंब होना बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। संयुक्त राष्ट्र अमरीका द्वारा समर्पित सैन्य सहायकों में पाकिस्तान के शामिल हो जाने से कश्मीर की समस्या तीव्र युद्ध के क्षेत्र में आ गयी। कश्मीर स्थित गिरगिट में अमरीका हुआइल ब्रह्मा बनाना चाहता था। गिरगिट साविध सच के बन्धन निकल पड़ता है कि इस हानि में यह कस इच्छा बना कर मरता था। यों तो पहले से ही साम्प्रदायी जगत का महानुभूति भाव के प्रति रहा है पर अब तो साविध-सच के कश्मीर के मामले पर खुलना भारत का पूर्ण समर्थन करने लगा। 1956 में साविध मंच के प्रधान मंत्री बुनगानिन तथा पार्टी के सचिवरी था कि कश्मीर भारत आय। कश्मीर प्रमो के समय उन्होंने घोषणा की कि साविध सच कश्मीर का भारत के अनिर्णय मानता है—यदि आवश्यकता पड़े तो आप पहाड़ का आँख। परन्तु हाँ आप आँख दे दो बिना और हम आपका सहायता आ आयेगे।

युद्ध-चक्र का प्रस्ताव—अमरीका ने सैनिक सहायता देने का निर्णय ठहराने के लिए पाकिस्तान को कहना था कि उस सैन्य अपने अधिकारों पर भारत के आक्रमण का डर बना रहता है। इस कारण भारतीय प्रधान मंत्री ने पाकिस्तान के समर्थक प्रस्ताव रखा कि दोनों एक समझौता करें यह मानें कि आपसी विवादों का तय करने के लिए वे युद्ध का सहारा नहीं लेंगे। वस्तुतः यह प्रस्ताव

पहल पहल 1949 में हो रखा गया था। 22 दिसम्बर 1949 को भारत ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त को एक प्रस्तावित सयुक्त प्राप्ता का मसविदा सजाया और इसके कुछ दिना बाद ही श्री नेहरू ने पाक प्रधानमंत्री को अपने पत्र में लिखा 'भौगोलिक और बहुत से अन्य कारणों से यह अत्यंत आवश्यक है कि दोनों देशों के बीच जो अनेक मतभेद उठ खड़े हुए हैं उनका निबटारा हो। इस आशय की एक दल प्राप्ता करने पर हम किसी भी हालत में प्रतिपक्ष तरफ़ों से उत्तर दे रहे हैं अपने दोनों देशों के साथ साथ हम समस्त दुनिया की बहुत बड़ी सेवा कर रहे क्योंकि इसमें हम लोगों के दिमाग में युद्ध का भय जाता रहेगा।

नेहरू बार बार आवाहन रहे लेकिन पाकिस्तान ने कभी तक सहभावना का पाठ सीखा हा नहीं। इस पर 1956 में नेहरू ने पुनः निम्नलिखित शब्दों में पाकिस्तान से युद्ध-वजन समझौते की अपील की मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान और भारत दोनों इस बात के लिए सहमत हो जायें कि किसी भी कारणवश हम लोग परस्पर युद्ध नहीं करेंगे और प्रतिपक्ष अपनी समस्याओं को हल कर लेंगे तो ही सन्तुष्ट है कि वे कुछ समय के लिए हस्त न भी हो लेकिन उनके लिए लड़ाई करने के बजाय उन समस्याओं को विचारोद्योग बनाये रखना अधिक अच्छा होगा। इसलिए युद्ध वजन घोषणा अत्यंत वाछनीय है इससे हमें सहायता मिलेगी।

पाकिस्तान इस तरह के किसी समझौते को करने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसका कहना था कि पहले भारत और पाकिस्तान के विवादों का समझौता होना चाहिए तभी किसी तरह का युद्ध-वजन समझौता कारगर हो सकता है।

कश्मीर सविधान सभा द्वारा राज्य के विलयन का अनुमोदन — सीधी चीज 1954 में कश्मीर सविधान-सभा ने कश्मीर के भारत में विलय का अनुमोदन कर दिया और 1956 में उसने राज्य के लिए एक नये सविधान का स्वीकृत तथा अंगीकृत किया जिसके द्वारा कश्मीर प्रत्येक दृष्टिकोण में भारत का वंश अंग बन गया। इस सविधान को 26 जनवरी 1957 में लागू करने का नियम किया। इस तरह अब कश्मीर समस्या का स्वरूप बिल्कुल बदल गया और जनमत संग्रह का बार्ड में नहीं रहे गया। पाकिस्तान द्वारा अमरीकी मध्यस्थता में शामिल हो जाने का कारण जनमत संग्रह की बात पहले ही निरस्त हो चुकी थी। 15 अप्रैल 1956 को प्रधान मंत्री श्री नेहरू ने अपने एक भाषण में इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि जनमत संग्रह का प्रश्न स्पष्ट रूप से इस बात के साथ सम्बद्ध था कि पाकिस्तान का कश्मीर का अन्तर्गत होगा या नहीं। पिछले नौ वर्षों में पाकिस्तान में उत्तम प्रकार के न अन्तर्गत रहा है। इस बीच में कश्मीर का स्वरूप बिल्कुल बदल गया है और कई नए घटनाएँ हुई हैं। पाकिस्तान को दो जानेवाली समस्याएँ सहायता का स्वरूप बिल्कुल बदल गया है कि अब यदि पाकिस्तानी सेनाएँ कश्मीर की भूमि से निष्काशित कर ली जायें तो सीमा-सीमा सीमा के अन्तर्गत अपनी नई स्थिति की करती हैं तो भी नई सहायता से उनकी सहायक और भारत की शक्ति पहले से बहुत अधिक बढ़ गयी है। पाकिस्तान

ने भारत को दोषी बतसाया। कराची भारत की कठिनाइयों से नाजायज फायदा उठाना चाहता था। इसलिए पकिंग के साथ नये सिरे से उमन मित्रता शुरू की। नवम्बर में जब बहुत बड़े पमाने पर भारत और चीन के बीच युद्ध शुरू हुआ तो भारत ने अमेरिका और ब्रिटेन में सैनिक सहायता की याचना की। तुरंत ही इन देशों से युद्धोपयोगी सामान भारत पहुँचने लगे। पाकिस्तान ने इसका बड़ा विरोध किया। उमन कहा कि चीन की ओर से भारत पर ऐसा कोई हमला नहीं हुआ है कि इतने बड़े पमाने पर उसे सैनिक सहायता दी जाय। पर पाकिस्तान के विरोध का कोई असर नहीं पड़ा और भारत का सैनिक सहायता मिलती रही।

स्वर्ण सिंहा भरी दास्ताँ—भारत की सैनिक आवश्यकताओं से परिचित होने के लिए अमरावती में श्री एवरन हेरामन धोर ब्रिटिश मंत्री डेन सैट नवम्बर 1962 में भारत आया। उस अवसर से लाभ उठाकर उन्होंने पाकिस्तान और भारत में मत मिलाप कराने का यत्न किया। इसके फलस्वरूप प्रधान मंत्री नेहरू और राष्ट्रपति अयूब खान का 29 नवम्बर 1962 को एक संयुक्त बयान निकला जिसमें कहा गया था कि दोनों व्यक्ति उपर्युक्त समय पर भारत-पाकिस्तान मतभेद की सुलझाने के लिए वातावरण करेंगे। साथ ही यह तय हुआ कि उस शीप सम्मेलन का माग प्रशस्त करने के लिए मंत्रियों के स्तर पर पहले कुछ वातावरण हो। 29 दिसम्बर 1962 को मंत्रियों के स्तर पर पला सम्मेलन रावलपिंडी में हुआ। जनवरी और फरवरी 1963 में और सम्मेलन हुए और यह निश्चय हुआ कि मध्य माच में कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के मंत्रियों की वाता हो।

नकिन आयोजित कलकत्ता सम्मेलन के पूर्व ही पाकिस्तान ने चीन के साथ एक समझौता कर लिया। लेकिन म दोनों देशों के बीच ज्ञा समझौता हुआ उसके फलस्वरूप पाकिस्तान द्वारा अधिकृत कश्मीर का एक बड़ा भाग पाकिस्तान ने चीन को दे दिया। भारत ने उस समझौते पर बड़ा कड़ा विरोध प्रकट किया। इसी पृष्ठभूमि में 10 मार्च 1963 को कलकत्ता में भारत-पाक वातावरण पुन प्रारम्भ हुई पर उसमें कोई निष्पत्ति नहीं निकली। उसके बाद ज्ञा दशा के प्रतिनिधियों के दो और सम्मेलन हुए। अंतिम सम्मेलन शिमला में मई 1963 में हुआ। पर वहाँ भी कोई समझौता नहीं हुआ और वातावरण का यह मित्रमित्रा समाप्त कर दिया गया।

पाकिस्तान का जासूसी पडयंत्र—सितम्बर 1964 में भारत में पाकिस्तानी दूतावास द्वारा फताय गरीब जामसी तान का पता भारत सरकार को लगा। नजी दिल्ली स्थित पाकिस्तान का दूतावास इस पत्रिका का बन्धु था जिसने यह भारत की गुप्त सामग्री भेजने का पता लगाया था। इसमें दूतावास के उच्च पदाधिकारी सम्मिलित थे। पडयंत्र का पता लग गया तो भारत सरकार ने जासूसी में सम्बद्ध अधिकारियों को भारत से हटाने का निश्चय किया। लेकिन इसा समय भारत स्थित

पाकिस्तान के उ चायुक्त के व्यवहृतगत अनुरोध पर भारत सरकार न अपन निचय की घोषणा को पाँच दिनों के लिए स्थगित कर लिया । इसी बीच पाकिस्तान सरकार न कराँची स्थित भारतीय दूतावास के कुछ प्रमुख अधिकारियों पर धमूसी करन का शोषारोपण करके उन्हें पाकिस्तान छोड़ देन की आषा दे दी । पाकिस्तान की इस घोषणा के बाद भारत सरकार न भी पाकिस्तानी अधिकारियों का भारत छोड़न की आषा दे दी । इन घटनाओं की लेकर दोनों देशों के बीच तनाव फना ।

24 अक्टूबर 1963 को पाकिस्तान सरकार के आदेश सदाका और राजागो म भारतीय पुस्तकालय व कर दिये गये । 21 नवम्बर को राजागो म भारतीय हाई कमिशन का कार्यालय व कर दिया गया । इसी दिन पाकिस्तानी समाचार पत्रों ने यह समाचार छापा कि कमोर 1949 का युद्ध विराम रेखा को पाकिस्तान मायता नहा देता । 4 दिसम्बर को पाक अधिकृत कश्मीर के राष्ट्रपति श्री के एच तुर्गाद ने कहा कि युद्ध विराम रेखा के समीप बसने वाले नागरिकों के बीच दस हजार राष्कले बाँी गयी हैं तथा और बाँी जायगो ।

हजरतनाल घटना और भारत पाक सम्बन्ध — 28 दिसम्बर 1963 का श्रीनगर की हजरतनाल मस्जिद मे पगुम्बर मादव का पवित्र बाल चोरी घना गया । इस घटना को लेकर पाकिस्तान व समाचार पत्रों ने भारत के विरुद्ध छूब प्रचार किया और साम्प्रदायिक घृणा विप्य फनाया । फलत पूर्वो पाकिस्तान म बड़े पमान पर साम्प्रदायिक दगा भुट हा गया । इस दगा में कई हजार व्यक्ति मर और कई हजार शरणार्थी भारत भाग आये । इससे प्रतिक्रियास्वरूप भारत के कुछ जगहों पर दग हुए । इस कारण भारत और पाकिस्तान का सम्बन्ध और भी बिगड गया । तकिम साम्प्रदायिक दग की आग का बुयाना उस समय सत अधिक आव पक पा । अतएव इस समस्या के समाधान के लिए फरवरी 1964 म भारत और पाकिस्तान के स्वराष्ट्र मंत्रियों (Home Ministers) का एर सम्मेलन िती में हुआ । इस सम्मेलन का कोई विषेय परिणाम नहीं हुआ तकिन अपमन्वकी का उस्ताह तो कुछ लय व बडा । ि ती सम्मेलन मे यह निचय हुआ कि स्वराष्ट्र मंत्रियों का एर दूसरा सम्मेलन सितम्बर 1964 म रायनपिडी म हो जिमम अपमन्वकी की रणा के उपाय निर्धारित किये जाय ।

कश्मीर पुन सरसापरिषद म — पाकिस्तान इस स्थिति म माम उठाने का निचय किया और अगस्त 1964 म कश्मीर की समस्या को पुन सरसा परिषद् म ले गया । हजरतनाल बाँड को लेकर कश्मीर मे जो सरगर्मी लायी उसको पाकिस्तान ने कश्मीरियों का बिरोह बतलाया और गमुक्त राष्मय के हस्ताप की भाग का । तकिन बठन म सुरक्षा-परिषद कुछ न कर सकी और यह निचय किया जा कि 5 मई 1964 के दिन कश्मीर समस्या पर परिषद बिचार करे ।

गुरु मई म कश्मीर की सरकार ने दोस अपसा की जन स भुवत कर लिया । बहुत िनों मे पाकिस्तान यह प्रचार कर रहा था कि कश्मीर के एक्मान नना दोस स नना को जेल म बाँ करके भारत सरकार कश्मीर की जनता को भुवत हुए है ।

इन नये प्रकार का महाफोट करन व लोप से सरकार न गल का हि क
 लिया। ए वन ए लुप्त हा गज न कमीर क लिए जलननिधय व अतिहाय को
 जनमत नष्ट की माग की। इसा वाक्वरणमें 5 म 1964 का कमीर क प्रान पर
 विचार करन क लिए सुरक्षा परिषद क बैठक में पाकिस्तान क प्रतिनिधि या मुद्रा
 तथा भारतय प्रतिनिधि या गान्ता न जपन-अन विचार व्यक्तिये। पाकिस्तान
 प्रतिनिधि न कमीर में जनमत मुद्रह का क ना पुता माग रही। भारत य प्रति
 निधि न पुन इसका विराध लिया। लत्र म जय जवमुरों का तरह एम बार मा
 सुरक्षा परिषद किता निधय प हीं ए व सका। परिषद में एक प्रस्ताव पागित
 ग्रा बिस्व द्वारा दनों एनों क य अनुरा किया गया कि व प्रत्य वाता दग
 सनस्या क गान्तिप समाधान क लिए प्रयस कर रहे।

भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध का सुधारन में गल व्यक्त का के यन — न
 1964 में कमीर क ग्रा व्यक्त का कमीर का सरकार न कमीर एम वनों ए
 दल में रखन क वा मुक्त कर लिया। गल व्यक्त का मुक्ति क वा भारत
 और पाकिस्तान क सम्बन्ध में एक ए व्यक्त क ग्रा।

येन म वाक्वर किता ए लुप्त माहय न भारत सरकार का कमीर सम्बन्ध
 नाति का कमीर जलान्ता का एम कमीर क लिए जलननिधय क की कमीर की माग
 रही। पाकिस्तान का सरकार एम न व्यक्त का कमीर निधय। जन विचारों क
 वाक्वर पर कमीर-जनमत क समानान क लिए लुप्त व्यक्त निधय जय और प
 नहु म वाक्वर की। एम ए शिों का समाधि क दल एम माहय न य दलया
 कि कमीर-जनमत का समाधान मा हा मा है एद भारत द्वारा पाकिस्तान का
 सम्बन्ध व्यक्त हा। एम एद भारत पाकिस्तानमल निता क लिए नाकार प्रत्य
 कर ग। एम नमा म सान्ति प्रयुव वी म निधय क लिए व पाकिस्तान ए
 और इन बात पर रहे ग्रा क वि। एम न पाकिस्तान क सुवर्षों में एम क
 लिए व प्रान म ९० एम म निधय क लिए मात गय। एम दोष 27 म
 196४ का ९ म क म एम हा एम और एम माहय क मा प्रत्य व्यक्त हा एम।
 भारत द्वारा पाकिस्तान क सम्बन्धों में निधि में वा परिणम नहीं हुआ।

कठका माग

कच्छ का कच्छ (Ruha of Kutch) पुगन पुस्तक ग- (इद भारतय
 प्रत्य) द्वारा पुगन निधय (इद पाकिस्तान मय) क बीच में एम क।
 एम कच्छ एम कच्छ क कच्छ — कच्छ में या गर 19 7 में एम कच्छ का
 राय माग क माग निधय एम कच्छ कच्छ माग माग का कच्छ वन यदा।
 एम प्रत्य का कच्छ क राय में एम कच्छ का कच्छ कच्छ कच्छ कच्छ कच्छ
 हए य मदिन 1914 में कच्छमल निधय सरकार न य कच्छ कर लिया कि
 यह मच्छ कच्छ कच्छ के कच्छ में एम। पाकिस्तान सरकार एम कच्छ का

नया मानती। जल्दा कहना है कि 24 अगस्त के उत्तर में पतीस सौ घण्टी का सात पुराने सिंध प्रान्त के अंदर या दस विभाजन के बाद पाकिस्तान को मिलना चाहिए या और भारत ने जबरन स्वीकार पर अपना अधिकार जमा लिया है। भारत सरकार इस मत से सहमत नहीं था। उसका कहना था कि यह सम्पूर्ण इलाका कच्छ के राजा के मातहत था और स्वीकार नहीं था। क्षम भारतवादी है।

1965 की अप्रिल में कच्छ का नाम प्रकाश लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष हो गया। पाकिस्तानी सना की दो दबडी भारतीय क्षम में घुस गयी और कच्छ के कई गांवों पर अधिकार कर लिया। भारत को यह अनुमान नहीं था कि पाकिस्तान एकाएक इस तरह की आक्रमण कारवाई करेगा। 9 अप्रिल को यह सवाई शुभ हुई और अनियमित रूप से जून तक चलती रही। ब्रिटिश प्रधान मंत्री विलसन का मध्यस्थता में 30 जून को युद्ध विराम हो गया और समझौता के तारा यह था हुआ कि दोनों पक्ष 1 जनवरी 1965 की स्थिति से वापस चले जाय तथा तीन व्यक्ति दो मिलाकर एक ट्रिब्यूनल बन जो (यदि दोनों देशों के मंत्रियों के स्तर पर कोई समझौता न हो सके तो) इस विवाद पर अपना फैसला दे। ट्रिब्यूनल का काम होगा कि दोनों पक्षों के दावा की जांच करे एक रिपोर्ट दे तथा इसके निष्पक्ष दोनों पक्षों को मान्य हो। युद्ध विराम के बाद ट्रिब्यूनल का सचल हो जाना था। भारत और पाकिस्तान का ट्रिब्यूनल न एक एक सदस्य को मनोनीत करना था और वे दोनों सत्य एवं तीसरे व्यक्ति का अध्यक्ष बनते। इसमें से कोई व्यक्ति भारत या पाकिस्तान का नहीं हो सकता था। यदि ट्रिब्यूनल के संस्थापन का बनाव करने में काल मरभूत हुआ तो समझौता के अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव को उसको मनोनीत करने का अधिकार दिया गया।

कच्छ के इस समझौते को भारत में बड़ा आलोचना हुई। यद्यपि आक्रामकको उन क्षमों को घाली कर देना पड़ा जिनपर उसने अधिकार कर लिया था लेकिन भारत और पाकिस्तान मतभेद में पचासवीं फेसल का सिद्धांत मानना गलत था। कुछ लोगो का ह्यार्थ था कि पाकिस्तान कच्छ की तरह ही कश्मीर में स्थिति उत्पन्न करके इसी नमूने पर कश्मीर समस्या को पक्ष निष्पक्ष के सिद्धांत के आधार पर निमित्त करने की मांग कर सकता है।

जुलाई 29 को भारत और पाकिस्तान के विशेष मंत्रियों ने यह तय किया कि वे दोनों कच्छ पर अंतिम समझौता करने के बाद जून 20 अगस्त का निर्णय मिलें। तब तक पाकिस्तानी मुजाहिदों ने कश्मीर में गहरा पड़ा कर दो और इस हालत में बिना मंत्रियों का वाता सम्म नहीं रही। अतएव भारत ने सचाव किया कि कच्छ का प्रत्यक्ष सीधे ट्रिब्यूनल में रखा दिया जाय। पाकिस्तान ने इरान के एक व्यापारी तथा भारत ने मंगोलिया के एक नागरिक को ट्रिब्यूनल में अपना प्रतिनिधि मनोनीत किया। इन दोनों ने मिलकर एक स्वेडिश को बना। सितम्बर 1965 ई में ट्रिब्यूनल ने अपना काम शुरू किया। ट्रिब्यूनल द्वारा दोनों

देशों को आग दिया गया कि वे कच्छ के सम्बन्ध में अपने-अपने दावे प्रस्तुत करें ताकि उन पर विचार करके वह अपना नियम दे सके।

19 फरवरी 1968 को ट्रि-यूनल ने अपना नियम दे दिया। इसने अपने नियम में विवादग्रस्त क्षेत्र का नब्बे प्रतिशत भाग भारत को दिया और ग्यारह तान को बास बगमोल का प्लाका पाकिस्तान को दिया गया। इस इनाके में कजरकोट का वह ध्वस्त स्थान भी है जहाँ से 1965 की लड़ाई शुरू हुई थी। इसके अलावा जाहलद की ऊँची भूमि और नगरपरगार के धान भी पाकिस्तान को दिये गये इनाक में शामिल थे।

“गप” दृष्टि से यह नियम भारत के पक्ष में हुआ हुए भी भारत में नसकी प्रतिश्रिया बहुत रोचकपूर्ण हुई। रहीम बाजार से दमिणी इनाक का पाकिस्तान को देने का वाक्य कारण नहीं था। ट्रि-यूनल के अध्यक्ष स्वयं के जन गुप्तार लापरवाही ने अपने फसल में कहा कि इस इनाक में शान्ति और स्थायित्व बनाये रखने के लिए यह जरूरी है कि इस पर पाकिस्तान का दावा स्वीकार किया जाय। इसका मतलब यह था कि इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का कोई कानूनी अधिकार नहीं है लेकिन राजनीतिक विचारों से उसका यह इनाक देना उचित होगा।

प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने इस नियम का राजनयिक कारणों से प्रेरित बताकर नसकी निन्हा की। भारत के कुछ राजनीतिक दल ने यह स्पष्ट कर दिया कि नब्बे ट्रि-यूनल का नियम मान्य नहीं है और वे नसके कायाकाल का विरोध करेंगे। लेकिन युद्ध विराम के दौरान में कच्छ के मामले का ट्रि-यूनल को सौंपित समय भारत ने यह शक्त मान ली थी कि ट्रि-यूनल का फैसला उस मान्य होगा। इस कारण भारत के समक्ष कोई दूसरा विकल्प नहीं रह गया। भारत-सरकार ने नस में प्रबल विरोध के बावजूद फैसले का मान लिया और उस कायाकाल किया। ट्रि-यूनल ने जिन क्षेत्र को पाकिस्तान का माना वह क्षेत्र पाकिस्तान के अधिकार में चला गया।

1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध

कश्मीर में पाकिस्तान की घुमपट —बम्बो कच्छ समझौते का स्माही मूखन भी न पायी थी कि पाकिस्तान ने कश्मीर में अपनी हरकत शुरू कर दी। इस बार का पाकिस्तानी योजना 1947 के आक्रमण से बड़-बड़ कर थी। इसके लिए पाकिस्तान वर्षों से तैयारी कर रहा था। चान की सहायता से हजारों पाकिस्तानी सैनिकों को छापामार युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया था और योजना यह थी कि यह छापा मार दास्ता अगस्त वस में आधुनिक हथियार से लस हाकर कश्मीर में घुसगा और कश्मीर के अरर उपद्रव तथा तोड़ फोड़ करक एसोसियति पन कर दगा जिसमें भारतीय सना का कश्मीर से भागना पड़े। पाकिस्तानी दासकों का विश्वास था कि कश्मीर का मुस्लिम जनता इन छापामारों के साथ सहपाप करगी।

4-5 अगस्त की रात्रि में इस तरह के हजारों पाकिस्तानी छापामार कश्मीर में घुस गये। पाकिस्तानी रेडियो ने दावा किया कि कश्मीर की जनता ने बड़े पमान पर

विद्रोह पर दिया है। मुजाहिदों ने रेडियो स्टेशन हवाई अड्डा आदि स्थानों पर अधिकार कर लिया है और मीनगर का पतन होने ही वाला है। वान यह भी कि भारतीय अधिकारियों को पाकिस्तानी छापामारों की घुमपट्ट की खबर बाद में लगी। तबला इन मुजाहिदों ने कमीर में उपद्रव गारु कर दिया था। भारतीय सेना ने सीमा कारवाई कर दी और सबसे मुजाहिद पकड़ लिया गया था मार डाले गए।

जब भारतीय सेना घुमपट्टियों के पहले ज़ापा का सफाया कर दिया तो पाकिस्तान ने दूसरे ज़ापा को भेजा। दूसरे ज़ापा के प्रयोग ने हम तम्र को सफल कर दिया कि विराम रेखा क आसपास सेमे स्थित पहाड़ी जंगली इलाके हैं जिनमें होकर पाकिस्तानी घुमपट्टी भारतीय कमीर में पहुँचने हैं। अतएव भारत सरकार ने यह निश्चय लिया कि पाकिस्तान की इन हरकतों का मु। के लिए रोकने के लिए इन स्थानों पर अधिकार कर लिया जाय। इस निश्चय के बाद अगस्त के तीसरे सप्ताह में भारतीय सेना ने कारगिल क्षेत्र में तीन पाकिस्तानी प्रतिष्ठानों पर आधिपत्य कर लिया जहाँ से घुमपट्टी भारतीय क्षेत्र में घुसने थे। 25 अगस्त का दिवसान। त्र में भारतीय सेना ने दो पाकिस्तानी प्रतिष्ठानों पर अधिकार कर लिया। इसके बाद उरी-पुच क्षेत्र में मन्त्रि कारवाई की गयी और हाजीपीर के दर्रे पर भी भारतीय सेना का अधिकार हो गया। हाजीपीर पर क़ा हो जाना से घुमपट्टियों का रास्ता एकदम बंद हो गया।

मुकुन्द रायगढ़ के अधिकारी इस समय पुष्ट विराम रेखा का पहरा कर रहे थे। उन्होंने इन सारी घटनाओं को देखा और जनरल निम्नो ने सारी घटनाओं को सूचना महासचिव मू यान को दे दी। स्थितिका विगत देश महासचिव ने भारत और पाकिस्तान दोनों को समयसे कामलने की कहा। सकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला।

पुष्ट का आरम्भ — भारत द्वारा विराम रेखा को पार करने की प्रतिनिधिया पाकिस्तान में स्वाभाविक रूप से हुई। 25 अगस्त के बाद से भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं में कई जगह प्रत्यक्ष मुठभेड़ हो गयी और यह निश्चय गा प्रतीत होने लगा कि भारत और पाकिस्तान में अब युद्ध छिड़ जायगा। अधिक पाकिस्तानी क्षेत्र को भारतीय अधिकार में जाने से रोकने के उद्देश्य से पाकिस्तान ने प्रत्यक्ष रूप से आक्रमण करने का निश्चय किया। सुबह करिया क्षेत्र इसके लिए बहुत उपयुक्त था क्योंकि पाकिस्तान इस क्षेत्र में आसानी से हमला कर सकता था और अखनूर पर क़ा करने ऊपरी कमीर को जम्मु से अलग कर भारतीय क्षेत्र पर अधिकार कर सकता था। हिन्दन के विपक्ष प्रहार के दर्रे पर सितम्बर का नवम्बर ही टका और आधुनिकतम सस्त्रास्त्रों से ससत पाकिस्तानी सेना ने अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पार करके सुबह करिया क्षेत्र में आक्रमण कर दिया। पाकिस्तान के यह आक्रमण भारत के लिए जीवन मरण का प्रश्न हो गया। अतएव प्रतिरोध में भारतीय यादु सेना से मदद ली गयी और कुछ समय के लिए आक्रमण को रोक रिया गया। सकिन युद्ध का दबाव घटा नहीं और ऐसा प्रतीत होने लगा कि इस क्षेत्र पर किसी भी हाल पाकिस्तान का अधिकार हो सकता है।

5 सितम्बर को पाकिस्तानी वायुसेना ने अमृतसर पर हमला किया। इस घटना से यह निष्कर्ष निकालना कठिन नहीं था कि पाकिस्तान सचप के क्षेत्र को विस्तृत करके पंजाब पर आक्रमण करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान की इस योजना की कूचन और छद्म-जूरिया क्षेत्र में पाकिस्तानी सैनिक दबाव का काम करने के उद्देश्य से भारत में 6 सितम्बर को पाकिस्तान के पंजाब प्रान्त पर तीन तरफ से आक्रमण कर दिया और भारतीय सेना लाहौर की ओर बढ़ने लगी। पाकिस्तानी रेडियो से बोलते हुए राष्ट्रपति अयूब खान ने कहा कि हमने गैर युद्ध की स्थिति में हैं। यह सचमुच भारत और पाकिस्तान के बीच एक अपाहिण युद्ध था जो समस्त सीमा पर बड़े पैमाने पर चला जा रहा था। दोनों देश पूरी गति के साथ युद्ध में जुट गए थे।

संयुक्त राष्ट्रमंडल में भारत-पाक युद्ध का मामला

जाना कि हम यह चर्चे हैं कि 5 अगस्त 1965 को तीन हजार के लगभग पाकिस्तानी कश्मीर युद्ध विराम रेखा को पार करके भारतीय क्षेत्र में घुस आये थे। इनमें से अंशिक लाजाद कश्मीर सेना के सैनिक थे किन्तु वे अनधिकृत पोशाक में घुसे थे। ये घुसपट्टियाँ आधुनिकतम अस्त्र-शस्त्रों से लस थे और इनका उद्देश्य भारतीय क्षेत्र में तोड़ फोड़ और आतंक फैलाना था। सम्भवतः पाकिस्तान का इरादा 1947 के इतिहास को दोहराना था। 9 अगस्त को ये अफ़ला के बंद की वष गाँठ के अवसर पर कश्मीर जनमत संग्रह दल ने एक विनाश प्रदर्शन का आयोजन किया था। उसी दिन घुसपट्टियों का अपनी कारवाँ चलावती थी ताकि पाकिस्तान को यह कहने का मौका मिल जाय कि कश्मीर का जनता ने भारत के विरुद्ध विद्रोह कर दिया है। भारत सरकार ने इस घटना का सूचना विराम रेखा पर स्थित संयुक्त राष्ट्रमंडल के पर्यवेक्षक को दे दी। इन पर्यवेक्षकों ने स्थिति की जाँच पता करने की और संयुक्त राष्ट्रमंडल के मुख्य सैनिक पर्यवेक्षक जनरल निम्मी (General Nimmo) ने महासचिव को इस बात की सूचना दी कि असैनिक पोशाक में दहूत से गैर सीमा के उस पार से भारतीय क्षेत्र में घुस रहे हैं। 10 अगस्त को महासचिव यू.थात ने भारतीय और पाकिस्तानी प्रतिनिधियों से बातचीत करत हुए कहा कि वे अपनी सरकारों को समय से काम देने को बता रहे हैं।

इसी बात भारतीय सेना के घुसपट्टियों का पर पकड़ाने की और कश्मीर में शांति-स्थापना का कार्य में सफल हो गया। भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि वह घुसपट्टियों का गमना करने के लिए तैयार है ताकि मानवचित्र को पाकिस्तान के अनुशासन को चाहिए कि वे इन स्थितियों का वापस बना दें। पाकिस्तान के विदेश मंत्री जेट ए. मुजा ने कहा कि उनका देश किसी तरह इन घुसपट्टियों में सम्बद्ध नहीं है। 18 अगस्त को यह सुनने में आया कि महासचिव ने कश्मीर की स्थिति पर एक बक्तव्य तैयार किया है जिसमें वर्तमान स्थिति के लिए पाकिस्तान का जिम्मेदार बताया गया है किन्तु पाकिस्तान तथा अमराको गुट के दबाव में आकर महासचिव ने उस बक्तव्य को प्रकाशित नहीं कराया। यू.थात ने स्पष्ट

भू के को भारतीय उपमहाद्वीप में भेजने का विचार किया लेकिन यह इरादा भी खारिज किया गया।

इसके उपरान्त महासचिव ने जनरल निम्नो को म्यूवाक बुलाया। 26 अगस्त को जनरल निम्नो म्यूवाक पहुँचे और महासचिव को उन्होंने कश्मीर की स्थिति के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट दे दी। कश्मीर के प्रश्न पर अपनी मन्त्रणा का दौरा पूरा करने के बाद महासचिव समस्या के समाधान के लिए नये धिरे से बंदम उठाने पर विचार करने लगे। उन्होंने यह बतलाया कि कश्मीर की लड़ाई के बारे में जनरल निम्नो ने जो रिपोर्ट दी है उसको धमी के प्रकाशित नहीं करेंगे। सुरक्षा परिषद् की बैठक में इसको पेश किया जायगा।

भारत पाक युद्ध—1 सितम्बर को पाकिस्तान की नियमित सेना ने अतः राष्ट्रीय सीमा रेखा को पारकर भारतीय भू भाग पर आक्रमण कर दिया। इसके प्रतिरोध में भारत को बहुत बड़े पमाने पर सैनिक बारबाद करने पड़ी। युद्ध की अग्नि कलने की सम्भावना बहुत बढ़ गयी। महासचिव ने सुरक्षा परिषद् के सदस्यों से मन्त्रणा की और पाकिस्तान और भारत दोनों से युद्ध बन्द करने की अपील की। 4 सितम्बर को भारत ने इसका जवाब दिया। उसका कहना था कि जब तक पाकिस्तान घुमपट्टियों को वापस नहीं बुला लेता और आक्रमण बन्द नहीं कर देता तब तक भारत युद्ध बन्द करने में साधार है।

सुरक्षा परिषद् की बैठक—उसी दिन 4 सितम्बर को सुरक्षा परिषद् की बैठक हुई। कश्मीर की समस्या पर विचार करने के लिए परिषद् की यह 125 वीं बैठक थी। भारत ने परिषद् से यह माँग की कि यह पाकिस्तान को कश्मीर में आक्रमण घोषित कर और पाकिस्तान से यह माँग करे कि यह कश्मीर के सब भागों से अपनी सेना हटा ले। भारतीय प्रतिनिधि पायसारायी ने कहा कि पाकिस्तान ने अपने आक्रमण के द्वारा 1949 में कराँची में हुए युद्ध विराम समझौते को टुट्टे-डुट्टे कर दिया है और युद्ध विराम रेखा को बसाईखान के रूप में परिवर्तित कर दिया है। बहस का प्रारम्भ करते हुए पायसारायी ने कहा कि सुरक्षा-परिषद् पिछले अठारह वर्षों से कश्मीर समस्या को सुलझाने में असफल रही है क्योंकि यह इस समस्या के साथ तथ्य कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया है मानने से हमेशा इनकार करती रही है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में आजकल जो हो रहा है वह पुनः एक भारी आक्रमण है। ग्यापविहीन पाकिस्तानी दावे से सुरक्षा-परिषद् पचपन्न भ्रम और बहुवादे में पड़ गयी है।

पाकिस्तानी प्रतिनिधि सैयद अमज्जद अली ने कहा कि भारतीय प्रतिनिधि द्वारा दिया हुआ एक भी बहस्य ऐसा नहीं है जो कि मनबद्ध न हो और तथ्यों के आधार पर तर्क वित्त नहीं किया जा सकता है। इसके बाद छः निर्वाचित सदस्यों की ओर से प्रलेशिया ने एक प्रस्ताव रखा जिसमें कश्मीर में अविश्लेष्य युद्ध विराम लागू करने के लिए भारत और पाकिस्तान से माँग की गयी थी। इसमें सम्मेलन करने का दि० था —24

और युद्ध विराम रेखा के अपने भागों में सब सनिकों को वापस बुला लेने के लिए वह आग्रह करती है।

मन्त्रेशिवार्थ प्रतिनिधि राधाकृष्ण रमानी ने कहा कि प्रस्ताव उससे अधिक फुल नहीं कर सकता उसमें कबन अधिकतम युद्ध को बंद करने की मांग की गयी है। परिपक्व न इस प्रस्ताव का स्वीकार कर लिया।

परिपक्व का यह प्रस्ताव अनेक श्रद्धा से भरा पड़ा था। इसमें कश्मीर में पाकिस्तान के नए आक्रमण की निम्न न करके पुनः उस ऐतिहासिक भूल को ठहराया गया जो 1947 में पाकिस्तानी आक्रमण के समय की गयी थी। इस बार जब कि समुचित राष्ट्रसंघ के महासचिव स्पष्ट रूप से पाकिस्तान को वर्तमान हमले के लिए दोषी बताया था तो सरला परिपक्व को यह उपमा 'माय का गंगा घोंटने के समान' थी। सरला परिपक्व की उक्त बचक महासचिव यू. यात की रिपोर्ट पर विचार के लिए जब बुलायी गयी थी तब उस पर कोई विचार ही न किया जाना विस्मयकारी था। यह विस्मय उस समय और अधिक हो जाता है जब कि भूल प्रश्न पर विचार न कर आक्रामक पाकिस्तान तथा आक्रान्त भारत को समान कोटि में रखने का प्रयत्न किया गया। सरला परिपक्व ने जो प्रस्ताव सबसम्मति से स्वीकृत बताया जाता है उसमें भारत तथा पाकिस्तान दोनों से तत्काल युद्ध विराम करने की अपील की गयी। लेकिन वास्तविकता की घोर उपमा कर केवल औपचारिक कारवाई से काई नाम नहा हो सकता। सरला परिपक्व के शब्दों ने इसपर तनिक भी विचार नहीं किया। युद्ध विराम का प्रस्ताव स्वीकार कर फल अदायगी तो कर दी गयी किन्तु इस बार तनिक भी ध्यान नहीं लिया गया कि आक्रमणकारी पाकिस्तान का अपनी सेना पीछे हटाने का आदेश दिया जाय। जबतक कश्मीर पर नया हमला करने वाले दंग को न रोका जायगा तबतक बाहिर युद्ध बन्द भी कैसे हो सकता है? इस बात की धोर सरला परिपक्व के अध्येत तथा सन्धियों का ध्यान न जाना 'खेदजनक' था।

यह स्थिति उस समय और भी गम्भीर चिन्ता का कारण बनी जब कि महासचिव यू. यात की कश्मीर सम्बन्धी रिपोर्ट पर कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहा समझा गयी। एन. ओर तो महासचिव श्री यू. यात की पहली रिपोर्ट तथा उनके कश्मीर सम्बन्धी रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं हान दिया गया फिर जब तत्सम्बन्धी गोपनीय रिपोर्ट उपस्थित की गयी तब भी उस पर ध्यान न दिया जाना आश्चर्यजनक ही नहीं घोर अनपकारी भी था। इस रिपोर्ट में महासचिव यू. यात ने जब पाकिस्तान को वर्तमान संघर्ष के लिए दोषी ठहराया तो फिर सरला-परिपक्व के अध्येत और सन्धियों को इस कहने में सहाय क्यों हुआ?

6 सितम्बर को युद्ध की स्थिति पर विचार करने के लिए सरला-परिपक्व की दूसरी बैठक हुई। यू. यात ने परिपक्व को सूचित किया कि भारत और पाकिस्तान दोनों ने युद्ध बंद करने से इंकार कर दिया है। उस रात सरला-परिपक्व ने सबसम्मति से एक संकटकारीन प्रस्ताव पास किया जिसमें भारत और पाकिस्तान को तत्काल युद्ध बंद करने के लिए कहा गया। उनसे यह भी अनुरोध

किया गया कि वे अपने सशस्त्र सैनिकों को उन स्थानों पर लौटा लें जहाँ वे गत 5 अगस्त को थे। प्रस्ताव में महासचिव से प्रार्थना की गयी थी कि वे इस प्रस्ताव को तथा 4 सितम्बर के प्रस्ताव को मनवाने के लिए हर सम्भव प्रयत्न का उपयोग करें।

उसी समय महासचिव ने यह घोषणा की कि वे बहुत शीघ्र युद्ध करना के लिए पाकिस्तान और भारत जायेंगे।

यू. पाँत का शांति अभियान—सुरक्षा परिषद के इस प्रस्ताव के आधार पर 9 सितम्बर को यू. पाँत करीबो पहुँचे। तीन दिनों तक पाकिस्तानी नेताओं से उन्होंने बातचीत की। पाकिस्तान ने युद्ध विराम के प्रस्ताव को मंजूर करने के लिए तीन शर्तें रखीं।

1 युद्ध विराम का बाँट सम्पूर्ण कश्मीर से भारत और पाकिस्तान अपनी सेनाओं को पूरी तरह हटा लें।

2 जनमा संप्रहू होने तक कश्मीर में शांति-व्यवस्था बनाये रखने के लिए अफ़िकी एशियाई देशों की सेना रयी जाय।

3 तीन महीने के भीतर कश्मीर में सुरक्षा परिषद के 5 जनवरी 1949 के प्रस्ताव के अनुसार जनमत संप्रहू के लिए मतदान किया जाय।

इन शर्तों ने स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान युद्ध बन्द करने के लिए तयार नहीं है क्योंकि ये शर्तों में ऐसी भी शर्तों भारत-किसी हालत में नहीं मान सकता था। 12 सितम्बर को महासचिव दि ली पहुँचे। दि ली में भारतीय प्रधान मंत्री से उन्होंने तुरन्त युद्ध बन्द करने का प्रस्ताव रखा। भारत इस प्रस्ताव को मानने के लिए तयार था लेकिन साथ ही उसने यह स्पष्ट कर दिया कि वह अपनी प्राणैतिक अखण्डता बनाये रखने के लिए स्वतन्त्र है। 15 सितम्बर को राष्ट्रपति अयूब खान ने युद्ध विराम के प्रस्ताव को अंतिम रूप में अस्वीकार कर दिया। यू. पाँत अपने शांति अभियान में विफल होकर यू. पाँत लौट गया।

यू. पाँत पहुँच कर 15 सितम्बर को महासचिव ने सुरक्षा-परिषद् में अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट पेश की। इस प्रारम्भिक रिपोर्ट में बताया गया था कि यदि पाकिस्तान राजी हो तो भारत बिना शर्त युद्ध बन्द करने का सुझाव मानने को तयार था। लेकिन पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव के स्वीकार करने की सूचना नहीं दी है और अस्तुतः उसने प्रस्ताव को अप्रत्यक्ष रूप से ठुकरा दिया है।

सुरक्षा परिषद् की तीसरी बैठक—18 सितम्बर को यू. पाँत की भारत-पाकिस्तान यात्रा की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए सुरक्षा परिषद की बैठक हुई। यू. पाँत ने परिषद से माँग की कि चाटर की धारा 40 के अधीन सुरक्षा परिषद् भारत और पाकिस्तान को सट्टाई बन्द करने का आदेश दे और यदि वे युद्ध विराम में न करें तो चाटर की 39 वीं धारा के अधीन उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाय। महासचिव ने कहा कि चाटर की 40 वीं धारा के अनुसार सुरक्षा परिषद भारत-पाकिस्तान को और आगे सशस्त्र कार्रवाई से विरत होने तथा युद्ध विराम के लिए आदेश दे सकती है। 1948 में सुरक्षा-परिषद् ने कलिसोन के प्रश्न पर इसी प्रकार

का आग्रह दिया था। यू. या. त. ने कहा कि दोनों दलों के नेताओं से तुरंत एक ग्रीष्म सम्मेलन करने के लिए परिषद अपन कर सकती है। यह सम्मेलन सभ्य सहयोग से किसी तटस्थ देश में हो सकता है।

भारतीय प्रतिनिधि एम. सी० छागन्ना ने परिषद से कहा कि पहले वह यह निश्चित कर कि भारत पाकिस्तान युद्ध में कौन आक्रामक है। उन्होंने घोषणा की कि मोनिक प्रश्न यह है कि आक्रामक कौन है? यही उपयुक्त समय है जब कि आक्रामकारी को कहा जाय। उन्होंने कहा कि राष्ट्रमधीय परवर्षों के रिपोर्ट में यह बात साफ-साफ कहा गया है कि 5 अस्त का कम्मार में सशस्त्र अतिक्रमकारी सीमा पार करके पाकिस्तान से भारत में घुस। आ छागन्ना ने कहा कि राष्ट्रपति अबूब खा का कट्टर और दुराग्रह रूप रख इसलिए था कि दक्कन की पकिंग का घमकी के बारे में पहले से ही जानते थे। अबूब खा चाहते हैं कि भारत दानों मार्तों पर लड़े। वे चाहते हैं कि चीन भारत पर हमला बाने। उन्होंने कहा कि जान बूझकर राष्ट्रपति अबूब खा का नवीनतम पत्र यू. या. त. का उसी समय दिया गया जब कि चीन ने भारत को चुनौती दी। चीन ने भारत को चुनौती दी थी यदि वह तिरस्त्र-सिक्किम सीमा के अपने सैनिक तिब्बानों का नष्ट नहीं करता तो इसका परिणाम भयानक होगा। छागन्ना ने कहा कि हमारी सरकार कम्मार में किसी भी विदेशी सेना भेजने का विरोध करेगी। कम्मीर में जनमत सभ्य का भा भारत विरोध करेगा।

मन्मथिया के प्रतिनिधि राधाकृष्ण रमानी ने वहुस में भारत का समर्थन किया और कहा कि परिषद को एक अनुसूत्रीय प्रस्ताव पास करना चाहिए जिसमें युद्ध-विराम के लिए महासचिव की अपनी स्वीकार करने की भारताय उत्तरदायी सहायता का जाय घर्तों का स्वीकृति दिना पाकिस्तान द्वारा उस न मानने के हठ पर छे प्रकट किया जाय। कम्मीर में पाकिस्तान के मशस्त्र अतिक्रमण की नमूना की जाय तथा पाकिस्तान से लड़ाई बंद करने का कहा जाय।

रसा प्रतिनिधि ने भारत पाकिस्तान सभ्य से नाम उठानवाले पक्षों का चेतावनी दी और कहा कि ये पक्ष अपने विस्तारवादी इरादों और नापाक नीतियों के कारण यह सब कृत्रिम कर रहे हैं। भारत-पाकिस्तान के सभ्य में कबल उहीं लोगों का नाम पढ़ें सकता है जो विश्व की जनता में नापाक इरादों से फूट डालना चाहते हैं तथा जिनके विस्तारवादी एवं सभ्यवादी इरादे हैं। सुरक्षा परिषद का इस बात पर जार देना है कि जो प्रस्ताव पास हुए हैं उनपर तुरंत अमल किया जाय। विपक्ष नाम में अमेरिकी आक्रमण से सम्भार बनी स्थिति भारत पाकिस्तान के सभ्य से और सम्भार हा उठा है और एशिया में तनाव बढ़ गया है। सभ्य इस की सीमा के और निकट आ गया है। अतः इस और ज्यादा चिन्तित है। अमेरिका और ब्रिटेन ने भी युद्ध विराम का समर्थन किया।

उत्तरा-परिषद के सम्मेलन में कवन जोड़ाने का अकसा वह देश रहा जिसने पाकिस्तान का समर्थन करते हुए कहा कि सुरक्षा परिषद को कम्मार का प्रश्न हल करने के लिए अग्रसर होना चाहिए जो चल रहे सभ्यों की अक है। सुरक्षा परिषद

को कश्मीर का प्रश्न सुलझाने में अंतिम निर्णय के अधिकार पर बल देने की जरूरत है। बिना हमके भारत पाकिस्तान के बीच वार्ता के लिए कोई समान आधार नहीं दिखाई पड़ता।

सुरक्षा परिषद ने अपनी 20 सितम्बर की बैठक में दस मतों से निर्णय द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव पारित किया। जोनों ने मतदान में भाग नहीं लिया। प्रस्ताव में परिषद ने भारत और पाकिस्तान को आदेश दिया कि वे बुधवार को साढ़े चारह बजे से युद्ध बंद करने का आदेश जारी करें और बाद में अपने सारे सैनिक उस स्थानों पर वापस हटा लें जहाँ वे अगस्त 1965 में थे। महासचिव से कहा गया कि वे युद्ध विराम के निरीक्षण और सेनाओं की वापसी के निगरानी के लिए आवश्यक सहायता की व्यवस्था करें। साथ ही सभी देशों से कहा गया कि वे ऐसी कोई कार्रवाई न करें जिसमें स्थिति और बिगड़े। परिषद ने इस बात पर विचार करने का भी निश्चय किया कि वर्तमान झगड़े में निहित राजनीतिक समस्या के हल के लिए युद्ध विराम के बाद क्या कदम उठाये जाय।

प्रस्ताव की समीक्षा—सुरक्षा परिषद का यह प्रस्ताव भारत के साथ एक आधार था। इसके द्वारा भारत और पाकिस्तान को युद्ध बंद करने का आदेश दिया गया था। लेकिन उक्त आदेश केवल पाकिस्तान को दिया जाना चाहिए था कारण पाकिस्तान ने ही सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को अस्वीकार किया था। भारत ने तो उसे पहले ही बिना शर्त मान लिया था। भारत जब युद्धबंदी के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार था तो कोई कारण नहीं कि उसे भी उक्त आदेश दिया जाय। आक्रमणकारी तथा आक्रान्त दोनों के साथ एक प्रकार का यह व्यवहार बहुत ही घटनेवाला था। युद्ध बंद करने का आदेश तो उस देश को दिया जाना चाहिए जिसने युद्ध शुरू किया हो। पाकिस्तान ने ही भारत पर आक्रमण किया था और वह सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को भी मानने के लिए तैयार नहीं था। ऐसी स्थिति में भारतीय प्रतिनिधि श्री छागला का यह कथन सचपा उचित एवं मुक्तिमुक्त रहा कि युद्धबंदी का आदेश केवल पाकिस्तान को ही दिया जाय जिसने भारत पर आक्रमण किया है। प्रस्ताव में भारत को आदेश देने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी। वह तो पहले से ही हमने लिए तैयार था वगैरें पाकिस्तान भी इसे स्वीकार करे।

प्रधान मंत्री वास्ती तथा समुक्त राष्ट्रमण्डल के महासचिव यू. थॉमस ने बीच जो पत्र व्यवहार हुआ था उससे स्पष्ट है कि भारत तो शान्ति के निमित्त युद्ध विराम के लिए प्रस्तुत था किन्तु पाकिस्तान को दुराग्रही घातों के कारण यह सम्भव नहीं हो सका। भारत महासचिव यू. थॉमस के प्रस्ताव को मान लेने के लिए प्रस्तुत था किन्तु जब पाकिस्तान बिना शर्त युद्ध विराम के लिए तैयार हो रहा हुआ तो क्या किया जाता। इस प्रकार महासचिव यू. थॉमस को अमानत बनाने का सारा दोष पाकिस्तान तथा उसे प्रोत्साहन देने वाले देशों पर था। गहरार को इन की सुरक्षा परिषद की बैठक में महासचिव प्रधान ने अपने इस प्रयास के बारे में जो रिपोर्ट दी उससे भी उक्त तथ्य की ही पुष्टि होती है। सुरक्षा परिषद को पहले ही महासचिव की रिपोर्ट

पर विचार कर पाकिस्तान का आक्रमणकारी घोषित करना चाहिए था। यह न कर बहुत बड़ी गलती की गयी। यू.एन. के प्रयास का विफल कर पुनः पाकिस्तान न हिमावत का ओर शांतिप्रिय दलों का दृष्टि एवं आग्रह का दुहराया। यहाँ नहीं पाकिस्तान राष्ट्रसंघ के सम्बन्ध में भी जिस प्रकार का बार्तें करने लगा था वह उसके औद्योगिक का सूचक था।

इस बार भी मुरम्मा परिषद ने मने प्रान्त का उद्घाटन कर पाकिस्तान के आक्रमणकारी स्वरूप पर पगा हालत का कागिरी की। यह पन्ना अवसर नहीं जबकि पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया है। 1947 में भी भारत यहाँ काम किया था। अब जब कि संयुक्त राष्ट्रसंघ के कश्मीर स्थित प्रधान पक्षों के जनरल निम्नो ने स्पष्ट गतों में पाकिस्तान को हमला करनेवाला घोषित किया और उसका पुष्टि महामन्त्रि दू. यन्त्र ने भी अपनी सुरक्षा-परिषद की रिपोर्ट में की। एक बार भी पाकिस्तान का हमलावर घोषित न करना भारत के साथ सरासर अयोग्य करना था। प्रस्ताव में यदि मुद्दबन्दी का हाँ आदेश होता तो बात दूसरी होती। इसमें कश्मीर का राजनीतिक समाधान के समाधानों की भी चर्चा का गया थी। प्रस्ताव में इसका उल्लेख अप्रान्तिक एवं अनावश्यक था। कारण कश्मीर पर भारत का प्रभु सत्ता के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं उठाया जा सकता। 1947 में भी भारत ने ही कश्मीर पर पाकिस्तानी हमला का कटिघात का था उस समय भी भारत को याद नहीं मिला और पाकिस्तान के आक्रमणकारी रूप प्रकट होने पर भी वह किसी प्रकार लाजिब एवं दण्डित नहीं हुआ। इस बार जब कि संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रति निश्चितता सर्वोच्च अधिकारी की यह रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया है उस समय भी पाकिस्तान का आक्रमणकारी न घोषित करना बड़े ही आश्चर्य का बात है। स्पष्ट है कि सुरक्षा परिषद् गुने के आधार पर बड़ी गद्दी है तथा वहाँ राजनीतिक स्वार्थों के अनुसार निर्णय हुआ करते हैं। याद तथा सत्य का परिष्कार के निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह बात सुरक्षा परिषद के नये आदेश से स्पष्ट हो जाती है। सरकारी रिपोर्ट की बैठक में मुद्द विराम के बाद वरमान समय की मूल समस्या के समाधान की जो बात कही गयी वह बड़ा ही अनव्ययमूलक था।

मुद्द विराम — यद्यपि भारत के लिए यह प्रस्ताव का स्वीकार करना पड़ा था लेकिन शांति के नाम पर उसने इस स्वाकार कर दिया। पाकिस्तान ने 22 सितम्बर को इस प्रस्ताव का स्वीकार किया अतएव मुद्द विराम का समय मुरम्मा परिषद द्वारा बना दिया गया। 23 सितम्बर का मुद्द हीन बजकर दस निम्न पक्षों का न मुद्द बन कर दिया।

यद्यपि सुरक्षा-परिषद ने इस प्रस्ताव के द्वारा भारत के साथ याद नहीं किया लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच मुद्द बन कर देना उसकी एक बड़ी बड़ी सकलता मानी जायेगी। इस अवधि में संयुक्त राष्ट्रसंघ के महामन्त्रि दू. यन्त्र के प्रयास भी सराहनीय मान जायेंगे।

युद्ध के परिणाम—पाकिस्तान को यह आगा था कि चीन उसकी सहायता करेगा लेकिन उसे निराश होना पड़ा। उपा मिनाटो और सेटो समूहों ने मंगला की याचना की लेकिन वहाँ से भी उसे निराश होना पड़ा। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एक बहुत बड़े भू भाग पर अधिकार कर लिया। युद्ध के खाम होने पर सात सौ चालीस बगमीन का पाकिस्तानी क्षेत्र भारतीय कब्जे में था और दो सौ चालीस बगमीन के तत्काल भारतीय क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में थे। जन घन और सैनिक साजो सामान में दोनों पक्षों की अपार क्षति हुई।

भारत और पाकिस्तान के कटु सम्बन्धों के इतिहास में सितम्बर 1965 का युद्ध एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह उस मनमुटाव और कटुता की भावना का परम विकास था जिसको घमाघ पाकिस्तानी अधिकारी 1947 से पालतू आ रहे थे। पाकिस्तान के लिए एक घातक सीमा स्थापित करने तथा भारत को नीचा दिखाने का यह एक प्रबल प्रयास था। लेकिन युद्ध में पाकिस्तान की पराजय ने यह सिद्ध कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय झगड़े का निवटारा शक्ति द्वारा करने का प्रयास व्यर्थ होता है और जो लोग पहले तलवार उठाते हैं वे तलवार से ही नष्ट हो जाते हैं। भारत के लिए यह विजय धर्म निरपेक्षता समाजवाद और स्वतंत्रता के सिद्धांतों की विजय थी। हमने सिद्ध कर दिया कि भारत अपनी प्रादेशिक अग्रगण्यता बचाये रखने के लिए कटिबद्ध है और उससे कोई भी शक्ति उसने अभिनव कश्मीर को उससे विलय नही कर सकती। इसके अतिरिक्त इस युद्ध के निम्नलिखित परिणाम हुए —

1 पाकिस्तान हमेशा कहा करता था कि यदि कश्मीर की समस्या का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान नहीं हुआ तो वह दूसरे तरीकों का अपनायनगा। "दूसरे तरीके" का तात्पर्य शक्ति अर्थात् युद्ध का सहारा लेना था। इसलिए पाकिस्तान 1954 से ही अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। सितंबर 1965 में उसने इस दूसरे तरीके का व्यवस्थित प्रयोग किया लेकिन उसकी मनोवामना पूरी नहीं हुई। अतः उम्मीद की जा सकती है कि भविष्य में अब पाकिस्तान इस तरह की घमनी न दे।

2 पाकिस्तान के शासकों का विश्वास था कि भारत के साथ युद्ध छिड़ जाने की स्थिति में कश्मीर की मुस्लिम जनता उसका साथ देगी और भारत के खिलाफ विद्रोह कर देगी। उन्हें यह भी विश्वास था कि घम के नाम पर भारत के मुस्लिम नागरिक पाकिस्तान का समर्थन करेंगे और पाकिस्तान (militia column) का काम करेंगे। लेकिन युद्ध के दिनों में भारत में मुनलमानों ने जिस देशप्रेम का प्रमाण दिया उसने यह सिद्ध कर दिया कि पाकिस्तान की सारी उम्मीद बेकार थी और पाकिस्तान के नागरिकों का अधिकांश अल्पमत में है।

3 इस युद्ध ने भारत में एक अग्रगण्य स्वाभिमान पैदा किया और देश की आत्मनिर्भर बनने की भावना बलवती हुई। पाकिस्तान युद्ध में अमेरिका द्वारा मुफ्त में दिये गये हथियारों और बम-व्यक्तियों का प्रयोग कर रहा था लेकिन भारत के अधिकांश हथियार स्वदेशी थे। भारत में बने विमानों की उपस्थिति ने प्रत्येक भार

चीन का सिर ऊँचा कर दिया और सम्पूर्ण युद्ध की अवधि में नागरिकों तथा सैनिकों का मनोबल ऊँचा रहा।

4 सैनिक विशेषज्ञों का कहना था कि इस युद्ध में टैंक-युद्ध कतरीकों का भी प्रभावित किया। पाकिस्तान ने अमेरिका में बन पटन टैंक का प्रयोग युद्ध में किया था। इस टैंक की साहसिक सार सवार में भी और दुनिया का यह सब विश्वासाली युद्ध सम्पन्न माना जाता था। लेकिन जिस तराफ से भारतीयों ने इसका सफाया किया उसका कारण पटन टैंकों की शक्ति में युद्ध विशेषज्ञों का विश्वास घट गया।

5 भारत-पाकिस्तान युद्ध ने भारत का एक शक्तिशाली राजनीतिक नृत्य प्रदान किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का मरुतु कदम नान बहादुर शास्त्री देश के प्रधान मंत्री अवश्य बन गये थे लेकिन नाताय जेता पर उनके नृत्य का प्रभाव नाममात्र का था। पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय शास्त्री ने जिस दृढ़ नीति का अवलम्बन किया उसने यह सिद्ध कर दिया कि वे न नेहरू के साथ उत्तराधिकारी हैं और सम्पूर्ण देश का विश्वास उनमें जम गया।

6 पाकिस्तान के लिए यह युद्ध बड़ा घातक सिद्ध हुआ। इसने पाकिस्तान के सभी विश्वासाली और मायताओं का चकनाचूर कर दिया। 19७१ में पाकिस्तान न्यू यॉर्क के लिए समा सारा का परित्याग कर अपनी सैनिक शक्ति बचा रहा था, लेकिन युद्ध में पराजय ने सैनिक तानाशाहों के शासनायता का स्पष्ट कर दिया। जनता के मस्तिष्क में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक था। क्या इसलिए सभी स्वतंत्रताओं का दानगन किया गया था? हमने कोई गलती नहीं की युद्ध में पराजय अपूर्व की सैनिक तानाशाहों के लिए बड़ा घातक हुआ। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान का शासक वर्ग भी देश का विश्व-नीति में पुनर्निर्धारण के सुबध में साबन लगा है।

7 भारत पाकिस्तान युद्ध विश्व विविध जकातों द्वारा के दृष्ट रहने का अन्तिम नो था। युद्ध के समय पाकिस्तान ने न और इरानीयों का सहयोग एगिया का गति के लिए बहुत स्तरनाक हो गया था। इन दोनों ने अपूर्व एकता और सम्मान का परिचय दिया और यह सहयोग बनकर सीमा पार हो गया जब पाकिस्तान ने चीन और इथोपिया के युद्धों में मददगारों के साथ अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया। पाकिस्तान का कर्म मूल्य अरिष्ट में मतयगिगई प्रतिनिधि द्वारा ज्ञाना न रहने के विश्व में ज्ञानाया गया था।

8 भारत पाकिस्तान युद्ध ने आधुनिक विश्व राजनीति में सुकुत रासुध का उपयोग का सिद्ध कर दिया। इरानीयों द्वारा सभ से अन्तिम जान में सभ के भविष्य के सम्बन्ध में तरह-तरह की आगवाए उत्पन्न होने लगा दी। लेकिन सुरक्षा संधि ने बड़ा अज्ञातवक हस्तगत करके इस युद्ध का बड़ा बर्णन। इस घटना से यह भी सिद्ध हो गया कि यदि अंतराष्ट्रीय मन्त्रों पर महाशक्तिशाली से योग से काम करें तो सभ का पूरा सन्तुष्टा मिल सकती है। भारत-पाकिस्तान युद्ध ने

बंद कराने में सोवियत संध और समुक्त राज्य अमेरिका ने अपूर्व सहायता का प्रयोग किया और इसी कारण परिषद की शांति-स्थापना के कार्य में सफलता मिली।

भारत-पाकिस्तान युद्ध ने सोवियत राजनय की एक नया मोड़ देने का अवसर प्रदान किया। दो राष्ट्रों के झगड़ों को सुलझाने में सोवियत संध ने आज तक कभी अपनी सेवाएँ अर्पित नहीं की थीं। वस्तुतः सोवियत राजनय का इस मिश्रात में विश्वास नहीं था। लेकिन भारत और पाकिस्तान के झगड़ों को सुलझाने में उसने अपनी सेवाएँ अर्पित कीं और तागवद में सम्मेलन का आयोजन किया। सोवियत राजनय के लिए यह बिल्कुल नवीन चीज थी और विश्व राजनीति पर इसका प्रभाव पड़ना अवश्यम्भावी था।

युद्ध विराम का उल्लंघन—समुक्त राष्ट्रसंघ के हस्तक्षेप से 23 सितम्बर 1965 को युद्ध विराम हो गया तथा भारत और पाकिस्तान में युद्ध बन्द कर दिये लेकिन युद्ध के शर्तों में पूर्ण शांति नहीं आयी। दोनों ओर से युद्ध विराम का उल्लंघन होता रहा। समुक्त राष्ट्रसंघ का पर्यवेक्षक दल इन उल्लंघनों को रोकने का प्रयास करता रहा लेकिन यह सम्भव नहीं था। दोनों देशों की सेनाएँ आमने सामने खड़ी रहती थी और इस हालत में मामूली झड़प पर गोली चल जाना की आशंका की जात नहीं थी। संघ के महासचिव ने इन उल्लंघनों को बन्द करने के कुछ मुझाव दिये पर उनका कोई परिणाम नहीं निकला और दोनों ओर से प्रतिदिन युद्ध विराम के उल्लंघन होते रहे।

तागवद सम्मेलन

इन भयानक स्थिति को समाप्त करने के लिए सोवियत राजनय काफी सक्रिय था। सोवियत प्रधान मंत्री का विचार था कि इन गारे झगड़ों का अंत दोनों देश के नेता प्रत्यक्ष बातों करके कर सकते हैं। अतएव गोवर्धन संध के विशेष दल बस्पी नेकर तागवद सम्मेलन की व्यवस्था की और 4 जनवरी को तागवद में राष्ट्रपति अयूब खाँ तथा प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री का ऐतिहासिक सम्मेलन प्रारम्भ हुआ। लेकिन तागवद सम्मेलन में समझौता होना कोई आसान नहीं था। दोनों देशों की दासता अटठारह वर्ष पुरानी थी और हाल ही में दोनों के बीच जीवन मरण का युद्ध हुआ था। लेकिन सोवियत राजनय का जादू दोनों के बीच समझौता करने में सफल रहो और 19 जनवरी 1966 को हर ओर उन्नास के बीच ऐतिहासिक तागवद समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। इस समझौते की शर्तें निम्न लिखित थीं—

अ. त. के सम्मेलन की शर्तों और प. दिव्यन के 2 युद्धों के अंत का प्रसंग है कि दोनों पक्ष जोरदार प्रयत्न करेंगे कि समुक्त राष्ट्रसंघ के घोषणापत्र के अनुसार भारत और पाकिस्तान में अश्वे पनोसियों का सम्बन्ध निमित्त हो। वे राष्ट्रसंघ के घोषणा पत्र के अंतर्गत पुनः दुहराते हैं कि वस्तु प्रयोग का महारा न लगे और अपने विवादों को शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझावेंगे।

वे समझते हैं कि उनके तब म विधेय-र भारत पाकिस्तान उप महा-ीप में और भारत तथा पाकिस्तान के जनता का हित में यह नहीं है कि दोनों देशों में तनाव बना रह । इसा पृष्ठभूमि म जम्मू और कश्मीर क मसल पर विचार किया गया और दाना दगा न अपना अपना पक्ष उपस्थित किया ।

(2) भारत के प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति इस बात पर सहमत हैं कि दोनों देशों के समा सन्न व्यक्तित्वों पर 1966 के पूर्व इस स्थान पर वापस लिये जायेंगे जहाँ वे 5 अगस्त के पूर्व ये बार दोनों पक्ष युद्ध विराम रक्षा पर युद्ध विराम की शर्तों का पालन करेंगे।

(3) भारत के प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति राजी हुए हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच का संबंध एक दूसरे के आंतरिक मामलों में बहुलता के सिद्धांत पर आधारित होगा ।

(4) भारत के प्रधान मंत्री श्री पण्डित इन्दिरा प्रसाद मुखर्जी ने कहा है कि दोनों पक्ष एक दूसरे के विरुद्ध किसी प्रकार के प्रचार का निरुत्साहित करेंगे और ऐसे प्रचार को प्रोत्साहित नहीं करेंगे जो दोनों दलों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध को बढ़ाता है।

(5) भारत के प्रधान मंत्री द्वारा पाकिस्तान के राष्ट्रपति सहमत हुए हैं कि पाकिस्तान के लिए भारत के उच्चायुक्त और भारत के लिए पाकिस्तान के उच्चायुक्त अपने-अपने पदों पर वापस आये और दोनों देशों में राजनीतिक सम्बन्ध पुनः सामान्य रूप से स्थापित हों। दोनों देशों की सरकारें राजनीतिक सम्बन्ध के मामलों में 1961 के विजना नियमों का पालन करेंगे।

(6) भारत के प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति सहमत हुए हैं कि व आर्थिक और व्यापारिक सम्बन्धों को वातावरण सहज बनाने के लिए भारत पाकिस्तान के बीच सहायक व आदान प्रदान का पुन स्थापित करने के सम्बन्ध में विचार करेगा और भारत-पाकिस्तान के बीच वा. वतमान समझौते हैं उनका कायाचित करने का उपाय करेगा ।

(7) भारत के प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति राजा हुए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्रों को आदेश दें कि वे युद्ध बन्धियों की ज़रूरतों का काम करें।

(8) भारत के प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति सहमत हुए हैं कि दोनों पक्ष गुलामियों की मुनसबाया स तथा अन्धधर्म से युक्त व्यक्तियों का निन्दागी स सम्बन्धित प्रश्नों पर आपस में विचार विमर्श जारी रखेंगे। व इस बात पर भी राजी हुए हैं कि दोनों पक्ष ऐसी स्थिति उत्पन्न करेंगे जिससे जनता का भयानक रहस्यी।

नारत पाकिस्तान मुद्दे के दोष में एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष की सीमा सम्पत्ति क्षति का वापसी के बार में वादा करने के लिए सहमत हुए हैं।

(9) भारत के प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति सहमत हुए हैं कि दोनों देशों से सशस्त्र मुकाबला रखने वाले मामलों पर विचार करने के लिए दोनों पक्ष

सर्वोच्च स्तर पर तथा अन्य स्तरों पर आपस में मिलाना जारी रखेंगे। दोनों पक्षों ने इस आवेदन को महसूस किया है कि भरनाया और पाकिस्तानियों की संयुक्त समिति का बनें जो अपने देशों की सरकारों की मंजूरी के लिए आगे बढ़ें।

(10) भारत के प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति सादर संधि के नेतृत्व के प्रति सादर संधि के प्रति और व्यक्तिगत रूप से हम के प्रधान मंत्री की कोसो जिन के प्रति उनका रचनात्मक मित्रतापूर्ण और सुदृढ़ कार्य प्रति कृतज्ञता और प्रगति का गहरी भावना व्यक्त करते हैं। नए सदस्यता से बतमाने सम्मेलन हासका और जिसका परिणाम दोनों पक्षों के लिए सन्तोषप्रद रहा।

ताशकंद सम्मेलन का महत्व — ताशकंद सम्मेलन का चीन में छद्म सन्ध्या वागत हुआ। यह सत्य है कि ताशकंद सम्मेलन से भारत और पाकिस्तान के मौखिक मतभेदों का अंत हो गया। किन्तु उस समय यह उम्मीद करना कि भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों की तारी समस्याओं का समाधान हो जायगा गलत था। ताशकंद का महत्व इस बात में है कि इसने पहले-पहले भारत और पाकिस्तान के नेताओं को अपने झगड़ों को गतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए प्रत्यक्ष वार्ता का अवसर दिया। इससे हम बात की सम्भावना बढ़ गयी। भारत और पाकिस्तान सम्बन्ध में एक नया युग शुरू होगा और दोनों देश अपनी शान्ति और भूतकर्म मंत्री रास्ता अपनायेंगे। ताशकंद सम्मेलन का स्वागत दुनिया ने धार्मिक विजय के रूप में तथा चीन की उपवादी नीति की पराजय के रूप में किया।¹

ताशकंद सम्मेलन के महत्व पर बोलते हुए सोवियत प्रधान मंत्री ने सत्य ही कहा था ताशकंद घोषणा भारत तथा पाकिस्तान के सम्बन्धों में नया मोड़ है। घोषणा से दोनों देशों के सैनिक तथ्यों का अंत हो गया तथा उन्हे दो मुख्य एशियाई देशों के बीच विद्यमान कठिनाइयों का समाधान करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मरे विचार से एशिया के सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र में शान्ति रखने के लिए उक्त घोषणा ने एक वास्तविक आधारगिरा की नोंक रखा है।²

सम्मेलन पर हस्ताक्षर करने के उपरान्त सात बहादुर नास्त्रीन कहा 19
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में ताशकंद सम्मेलन एक विविष्ट प्रमाण है। उन्होंने प्रकट की थी कि सम्पूर्ण विश्व ताशकंद घोषणा का काफी सराबोर अवधि की का मुल्यमाने का एक उदाहरण मानकर उसका स्वागत करना। वस्तुतः ताशकंद

1 The Tashkent Declaration has been generally welcomed as one paving the way for better relations between India and Pakistan and ushering in new era of friendship between the two countries. The Declaration was held as a triumph for forces of peace and a defeat to China which had been at its utmost to wreck this summit talks. — *Hindustan Times* (Delhi) 11 January 1966

2 आनंद (वाराणसी) 12 जनवरी 1966

समझोता अन्तराष्ट्रीय राजनीति में लेम्बानों जैसा और वियना की वृत्त में एक कड़ी है जिस अन्तराष्ट्रीय सम्भावना के विकास में समय समय पर बाधा सह्यता मिलता है। यही कारण है कि यह मुभाव लिया जाता है कि समकालीन अन्तराष्ट्रीय समस्याओं का समाधान ताश्कन्द का भावना (Spirit of Tashkent) में लिया जाय। इसमें कोई सन्देह नहीं कि आज बाल कइ वर्षों तक ताश्कन्द की भावना अन्तराष्ट्रीय राजनीति का प्रभावित करगी।

ताश्कन्द समझौते के बाद — ताश्कन्द सम्झौता के बाद दोनों देशों में इसका प्रभावित करने के लिए ताश्कन्द ब्रह्म उठाया गया और दोनों देशों के सैनिक अपने स्थान पर लौट आये जहाँ व 5 अगस्त 1965 का है। दोनों देशों ने एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार करना भावना कर लिया। ऐसा प्रताप हुआ की भारत और पाकिस्तान के सम्बन्ध में सचमुच की एक नया अध्याय प्रारम्भ हो गया।

लेकिन अभी ताश्कन्द का स्थायी मूलन भी न पायी था कि सीमांतों पर पाकिस्तानी सैनिकों की हस्तचत पुनः पुनः (जुलाई-अगस्त 1966) हो गया। कुछ समय के लिए ऐसा प्रताप हुआ कि ताश्कन्द समझौता का अन्त होन वाला है लेकिन दोनों ने बुद्धिमत्ता से काम लिया। सितम्बर 1966 में भारत और पाकिस्तान के सैनिक अधिकारियों के बीच एक समझौता हुआ और यह निश्चय किया गया कि वे अपने सीमांतों पर यदि कोई सैनिक गतिविधि करें तो इसका पूर्व सूचना एक दूसरे को दें। इस समझौता से वातावरण अवश्य ही कुछ शान्त हुआ। 1967 के प्रारम्भ में भारतीय क्षेत्र में एक पाकिस्तानी हवाई जहाज को भारत द्वारा मार गिराया जाना से दोनों देशों के बीच फिर कुछ तनाव बढ़ गया। लेकिन इससे भी महत्त्वपूर्ण घटना सन् 1967 में घटी जब अखनूर क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान के सैनिकों के बीच एक मामला खड़ा हुआ गयी जिसके परिणामस्वरूप सत्र भारतीय सैनिक मारे गये।

ताश्कन्द सम्झौते से दिसम्बर 1970 तक भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों में कोई विशेष घटना नहीं घटी। जुलाई, 1968 में मादियत सच न पाकिस्तान की सैनिक नहानता से का निश्चय किया। भारत में इसका बड़ा विरोध हुआ। लेकिन पाकिस्तान में यह विरोध के प्रति कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं हुई। इसका एक कारण पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति में समय गुजर रहा था। नवम्बर 1968 में हाजरत हुआ और अप्रैल 1969 में लगभग समाप्त हुआ। पाकिस्तान में प्रचुर की व विरोध में जनजागरण शुरू हुआ। विरोध और चलने हुए और इन्होंने इतना नफरत से धारण कर लिया कि अग्रुव था की राष्ट्रपति के घर से हटा जाना पड़ा। उनके स्थान जनरल याह्या खान ने ले लिया। भारत के राष्ट्रपति डॉ. डॉकिर हुसैन का मृत्यु पर पाकिस्तान ने भी तिरों के लिए राजकीय शोक मनाया वही राष्ट्रीय शोक मनाया गया और यह देश में शामिल होने के लिए मांगल मूर धीरे धीरे दिनी आया। इस घटना से दोनों देशों में सम्भावना बना थी सम्झौता सम्झौते में इकार नहीं किया जा सकता। बाद में (जुलाई 1969 में) ऐसा आचार पर जनरल याह्या खान ठपाने की गयी लक्ष्मी में कुछ पत्र-व्यवहार भी हुआ। लेकिन उहाँ तक

मौलिक प्रश्नों पर मनभेद का प्रश्न है दोनों दश अपने अपने स्थान पर अभी भी खिग रहे।

विमान अपहरण कांड और भारत-पाक सम्बंध — 30 जनवरी 1971 को इम्तिन एयरलाइंस का एक यात्री विमान श्रीनगर में गिरने के लिए बना। रास्ते में ही दो अपहरणकर्त्ताओं ने जहाज के यात्री को बाध्य किया कि विमान को पाकिस्तान ले चले। विमान को जबरन लाहौर के हवाई अड्डा पर उतारा गया। अपहरणकर्त्ताओं ने अपने को कश्मीरी अलफतह संगठन का सदस्य बताया। कश्मीर मुक्ति मोर्चा के नेता मकबूल अहमद ने दावा किया कि मुक्ति मोर्चे के आदेश पर ही विमान का अपहरण किया गया था। लाहौर में उतरने के बाद मोर्चे की ओर से वायुयान को बिना क्षति छोड़ने के लिए तीन शर्तें रखी गयीं। अपहरणकर्त्ताओं को पाकिस्तान में राजनीतिक शरण दी जाय उनके परिवारों तथा मुक्ति मोर्चे के अन्य सदस्यों के परिवारों के साथ किसी प्रकार का दुष्प्रवहार न किया जाय तथा भारतीय विमान के बदले मुक्ति मोर्चे के बन्नी सदस्यों को मुक्त कर दिया जाय। पाकिस्तान ने राजनीतिक शरण की मांग तुरत स्वीकार करली और अपहरणकर्त्ताओं को शर्तों की सूचना भारत सरकार को दे दी। भारत सरकार ने इन मांगों को स्वीकार करने से इंकार कर दिया। भारत के विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह ने पाकिस्तान से मांग की कि भारतीय विमान को तुरत लौटा दिया जाय। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। एक दिन का विमान के यात्री लौ लौटा दिये गये लेकिन 2 फरवरी को अपहरणकर्त्ताओं ने विमान में आग लगाकर ध्वस्त कर दिया। जिस समय विमान को जलाया जा रहा था उस समय पाकिस्तान सरकार के उच्च अधिकारी और सैनिक हवाई अड्डा पर खड़े होकर तमाशा देन रहे थे। इस घटना को पाकिस्तानी टेलीविजन से प्रसारित भी किया गया।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि समूह अपहरणकांड के पीछे पाकिस्तान सरकार का प्रायश्च हाथ था। कुछ दिन पहले पाकिस्तान में चुनाव हुआ था और पूरा पाकिस्तान में अवाामी लोग की अप्रत्यागित सफलता मिली। अवाामी लोग की यह सफलता पाकिस्तान में उभरते हुए लोकतन्त्र समाजवाद और धर्म निरपेक्षता की सफलता थी। पाकिस्तान के सैनिक तानाशाहों ने यह कल्पना नहीं की थी कि चुनाव का परिणाम इस प्रकार निकलेगा। अतएव उनका सङ्घ अब यह हो गया कि किसी तरह अवाामी लोग को सत्ता प्राप्त करने से रोका जाय। इसके लिए भारत के साथ तनाव और युद्ध जसी स्थिति उत्पन्न करना आवश्यक था। इसी भावना से प्रेरित होकर पाकिस्तानी अधिकारियों ने विमान अपहरण का पञ्चयन रचा और सोमा पर तनावनी पदा करने की पूरी कोशिश की।

लाहौर में भारतीय विमान के ध्वंस से भारत भर में आक्रोश का तूफान उठा हुआ। नयी दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायुक्त के दफ्तर के सामने कई दिनों तक प्रदर्शन होते रहे। इसके प्रत्युत्तर में पाकिस्तान में भी भारतीय उच्चायुक्त के दफ्तर के सामने प्रदर्शन हुए। भारत सरकार ने विमान के अपहरण और उसके ध्वंस

जिने जाने के लिए पाकिस्तान सरकार को उत्तरदायी माना और पाकिस्तान की उस विमान उठाने भारत य आकाश में निषिद्ध कर दी। भारत सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भारतीय वायु प्रदेश के ऊपर से होकर पाकिस्तानी विमानों की सीधी उड़ानों पर तब तक प्रतिबंध लगा रहगा जबतक पाकिस्तान ध्वंस किया गया कि विमान अपहरण अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार एक अन्तर्राष्ट्रीय अपराध घोषित किया जा चुका है। राष्ट्र के टोकिया सम्मेलन में जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था इस बात पर निगम हो चुका है और पाकिस्तान अपहरणकर्ताओं का सौदाग के लिए वचनबद्ध है। तबिन पाकिस्तान सरकार पर इन कारवाइया तथा तबों का कोई प्रभाव नहीं पडा। वह मुआवजा देने तथा अपहरणकर्ताओं को भारतीय अधिकारियों के सुपुर्न करन से इकार करती रही।

जिस दिन भारत सरकार ने पाकिस्तान की असन्निध उड़ानें भारतीय आकाश में निषिद्ध कर दी थीं उनी दिन सीमा के दानों और प्रतिरोध का वातावरण और अधिक गहरा हो गया। लाहौर में नागरिक सुरक्षा के अम्यास हुए जि हैं हजारा लोग न दखा और पजाब के घनर न लोगों से युद्ध का प्रशिक्षण लेने का आग्रह किया। साथ ही रेडियो पाकिस्तान की धमकियों को दखत हुए लगा कि दोनों दशों के बीच यदि कोई छोटी-मोटी चर्चा हो जाय तो ता-तुब नहीं। इसी बीच पूर्वी पाकिस्तान में गृहयुद्ध छि गदा जिससे विमान अपहरण बाढ को लेकर सीमा पर तनाव कम हो गया। पाकिस्तान सरकार का सारा ध्यान पूर्वी बंगाल पर केन्द्रित हो गया। इस बीच भारत सरकार ने कई बार यह स्पष्ट कर लिया कि भारत अपने ऊपर से पाकिस्तानी विमानों को उड़ान की इजाजत तबतक नहीं दगा जबतक ध्वंस विमानों का मुआवजा और अपहरणकर्ताया का भारतीय अधिकारियों के सुपुर्न नहीं किया जाता।

पाकिस्तान का गृहयुद्ध और भारत

पाकिस्तान में निर्वाचन — 31 मार्च 1969 को पाकिस्तान के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ जब राष्ट्रपति अयूब खान ने पदत्याग कर लिया और उनकी जगह पर याह्या खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने। अयूब खान के सैनिक शासन के विरुद्ध पाकिस्तान में विशेषकर पूर्वी पाकिस्तान में भयंकर जन आन्दोलन हुआ था जिसका उद्देश्य पाकिस्तान में प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापित करना था। उस उल्लूकधर्मी में अयूब खान को अपदस्थ कर जब याह्या खान ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति का पद सम्हाला तो उन्होंने बान किया कि वे शीघ्र ही दशमें चुनाव की व्यवस्था करायेंगे और शासन मत्ता जनता परा बन गये प्रतिनिधियों को सुपुर्न कर दने। 7 नवम्बर दि 1970 में यह चुनाव सम्पन्न हुआ। 300 सदस्यीय राष्ट्रीय एसेम्बली में मुजाबुररमान की अगामी नेग को 160 स्थान तथा जुलफिकार अली भुट्टो की पितुन पार्टी का 84 का स्थान मिले। 17 नवम्बर को प्रादेशिक विधान सभाओं के चुनाव हुए। इस चुनाव में भी पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजोबुररमान की अगामी नेग और पश्चिमी पाकि

स्तान में भुट्टो की पिपुस पार्टी को सफलता मिली। चुनाव के परिणामों के बिना नेपथ्य से पता चलता है कि यह द्रष्टव्य के सैनिक शासन से उन्हे मनदाताओं ने परिवर्तन लोकतन्त्र प्रगतिशान नीतियों और जनता के प्रति उत्तरदायी राजनीतिक व्यवस्था के लिए मतदान किया।

राष्ट्रीय एसेम्बली में यद्यपि अक्वामी लीग को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया किन्तु पाकिस्तान का राजनीतिक भविष्य अधकार में ही पड़ा रहा। नव निर्वाचित एनेम्बली को 120 दिनों के अंदर पाकिस्तान के लिए संविधान तैयार करना था। राष्ट्रपति याह्या खान ने यह भी धमकी दी थी कि यह संविधान देश की एकता नष्ट करने वाला हुआ तो वह उसे अस्वीकार कर सकते हैं दूसरे शब्दों में यह चाहें तो अनिश्चित काल तक पाकिस्तान में सैनिक शासन बनाये रख सकते हैं।

अक्वामी लीग के कार्यक्रम —नेथ मुजीबुररहमान की अक्वामी लीग एक छद्म सूत्री कार्यक्रम के आधार पर चुनाव में लड़ी थी। इसमें सबसे प्रमुख बात थी पूर्वोत्तर पाकिस्तान की स्वायत्तता। पूर्वोत्तर पाकिस्तान की जनता यह महसूस करने लगी थी कि पश्चिमी पाकिस्तान के प्रोपोजिट वहाँ की छोड़े साठ करोड़ आबादी का शोषण करते हैं और उनका दृढ़ विश्वास था कि इस शोषण का अंत पानी हो सकता है जब पूर्वोत्तर पाकिस्तान को स्वायत्तता मिल जाए।

यह बिना कुछ स्वाभाविक था कि पश्चिमी पाकिस्तान के निहित स्वार्थ वाला उस तरह की किसी भी प्रवृत्ति का विरोध करें। अतएव पिपुस पार्टी के अध्यक्ष ने यह स्पष्ट कर दिया कि 3 मार्च 1971 में डाका में शुरू होने वाले राष्ट्रीय एसेम्बली के अधिवेशन का चुनाव दल बहिष्कार करेगा। स्थिति स्पष्ट थी। राष्ट्रीय एसेम्बली में अक्वामी लीग का बहुमत था और इस बहुमत के आधार पर वह अपने विचारों को अनुसार संविधान बना लेती। भुट्टो अक्वामी लीग के छद्म सूत्री कार्यक्रम का कट्टर विरोध करते रहे। चुनाव के पहले ही नेथ मुजीबुररहमान कहा करते थे कि यदि वे चुनाव में जीते तो वह अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छा सम्बन्ध कायम करेंगे। सीएटी तथा सेंटो से पाकिस्तान को निकाल देंगे और गुरबननिकामने का हरसमय प्रयास करेंगे। लेख रहमान की पार्टी लोकतन्त्र समाजवाद और धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत पर आधारित थी। लेकिन पिपुस पार्टी का वित्तीय आधार इससे एकदम भिन्न था। भुट्टो सशक्त बैंग और इस्लामी समाजवाद की हामी भरते थे। ऐसी दशा में गति रोक का उत्पन्न हो जाना बिकतुल स्वाभाविक था।

उधर राष्ट्रीय एसेम्बली के लिए चले गये अक्वामी लीग के सदस्यों ने नेथ मुजीबुररहमान की छद्म गति में अपना नेता बन लिया तथा उन्हें देश का भावी संविधान तैयार करने की भी पूरी आजादी दे दी। नेता चले जाने के बाद लोग ने अपने समयों के समय भाषण दते हुए देश की अस्थिरता की बात बनी। उन्होंने देश के पश्चिमी भाग द्वारा पूर्वी भाग के शोषण का जिक्र भी किया और कहा कि अक्वामी लीग अब इसको सहन नहीं करेगी।

इसी बात बखामा गा न मुविधान की स्वरक्षा भी तयार कर ला वो माट तोर प- हह-नूरा वायफन क अनुसार या । दस्तावेज में कद्राय सरकार का प्रनिरमा विदेशा मानल बार वित्त का विम्वगता न गया । विदेशी व्यापार और महायन्त्रा रायों क लिए छाह किया गया । कद्र का कर तन का अधिकाइ रखे रहा । श्रावों को विदेशों न स्थापनतायुक्त व्यापार करने का दूत न गयी । यह मुविधान पाकिस्तान के अलामी गराय का न होकर बल्ल पाकिस्तान मयम गराय का होता ।

3 मार्च 1971 से गका में राष्ट्रीय एम्बेसी का अधिवेशन शुरू होन वाला था । बखामा सींग के हन को दनक विमुक्त पार्टी के अधिन जुलिदकार बला मुद्रो ने दनक बट्टियार का घमका दख्खर तिरोध रतान कर दिया । मुद्रो न माप की कि एम्बेसी का बठक स्थगित कर दा जाय और यह तब तक नू नही हो जब तक प्रमुख राजनीतिक त्यों में काइ समझौता नही हो जाता । उन्होंने यह घमका मा गा कि यदि 3 मार्च से एम्बेसी का अधिवेशन शुरू न जा तो पूरे पश्चिमा पाकिस्तान में हड़तालों का गौर शुरू हो जायगा और एक ऐसा विद्रोहक वातावरण बन सकता है जिसमें आम वगर का जीना मुशाल हो जायगा । जानकारी त्यों में यह बागका धक्का का जा रहा था कि मुद्रो आर माह्ला में एक ऐसी सौ-साठ बार अभियान हाता जा रहा है जिसकी सगा पूर्वी पाकिस्तान के हाथ में सत्ता न जान देना है । राष्ट्रीय एम्बेसी का स्थगित करने का निाय तन से पत्र राष्ट्रपति माह्ला खा न मुद्रो से एक तिन पट्ट एक लम्बी वाता का था । मनवता गी वाता में यह निाय लिया गया । 1 मार्च का राष्ट्रपति न एक वक्तव्य दिया और कहा कि 3 मार्च का गका में शुरू होन वाले राष्ट्रीय एम्बेसी के अधिवेशन का अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित किया जाता है ।

माहिला खा की इस घापगा से अगामी सींग के नया सख मुजीबुररहमान न अनी माहुरी का इज्जत करत ए कहा कि 3 मार्च को सार पूर्वी पाकिस्तान में हड़ताल रहगी और तिराध का स्तर हड़ताल तक ही सीमित नही रहगा । 3 मार्च को हड़ताल हुई और उसक बाद हड़तालों का ताँता लग गया । तन घापक पनान पर गगतार कई त्यों तक हड़ताल होन को यह अन्तिम सख गा । हड़ताल को दबान के लिए सेना अन्त बरकों से निाला और क बार गालियाँ चलाकर सखों व्यक्तियों का मौत के घाट उतार दिया । फिर भी जनता का मनोबल नही गिरा । पूर्वी पाकिस्तान के गगत जनजागरण को सखर माहिला खा का मुकना पडा । 6 मार्च को एक रदियो प्रसारण में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एम्बेसी का अधिवेशन अब 25 मार्च न शुरू होगा बकि अधिवेशन कही होगा दसका बिना उन्होंने नही किया ।

बातियों का मुविन सप्राम—7 मार्च 1971 का गका के रमकेम भगन में लाखों नागरिकों के बीच मापन बल्ल हुए सेख मुजीबुररहमान न कहा कि राष्ट्रपति माहिला खा न 25 मार्च को अधिवेशन बुलादा है । कही 7 पता नही बकि हम तन तनी समित होगे जब हमारी चार मार्ग मान सी जायगी । माहल खा का मुनालि सेना की बरकों में बारसी स्थित बड़ हज्ज में पूव पाकिस्तान में बनौठ, मार जान वाल सोपों की मायिक बाँध गया घासन का बाएबोर को जनता द्वारा से ने पय प्रतिनिधि

का सोपने का यकीन । 8 माच से सरकार को न करो की अदायगी और न राजस्व मिलेगा । सरकारी दफ्तर, मायालय और स्कूल बंद रहेंगे । सिर्फ नौ घण्टे के लिए बक खुलेंगे । यदि हम पर एक गोली बरसायी ज यगी तो हम घर घर को किला बना देंगे । देश न जनता के समक्ष एक असहयोग आन्दोलन का कार्यक्रम रखा । इसके द्वारा गन्ध न यह आदेश दिया कि पूर्वी पाकिस्तान की सभी इमारतों पर काल झण्डे फहराये जायेंगे सभी गाँवों और गहरों में सम्प्राम समितियों का गठन होगा सरकारी तथा अर्द्ध सरकारी स्तर पर एक मायालय बंद रहेंगे रेल सेवाओं तथा बदरगाहा का सामान्य तोर पर संचालन होगा लेकिन सेना के लिए आये साज सामान को नहीं उठाया जायगा । यदि सेना पकित का प्रयोग करेगी तो कमचारी काम करने से इन्कार कर देंगे । बैंकों में काम होगा लेकिन पूव से पश्चिम पाकिस्तान आनवालो निधि का हस्तांतरण नहीं किया जायगा ।

8 माच से पूव पाकिस्तान से अवाभी लोग के आदेशों से काम चलने लगा । पाकिस्तान रेडियो के डाका केन्द्र न अवाभी लोग का समयन किया और दोख मुजीबुररमान के भाषण का प्रसारण करने लगा । रेडियो डाका का नाम बदलकर डाका बतार केंद्र कर दिया गया । पहली बार डाका रेडियो से स्वाधीनता पूव के दशभक्ति का गीत गाये गये । गवर्नर के बगालो रमोइये सरकारी गृह छोडकर चले गये । पूर्वी पाकिस्तान के यायाधीनो ने मनोनीत गवर्नर टिक्का खान को शपथ ग्रहण कराने से इन्कार कर दिया । पूव पाकिस्तान राइफल और बगाल राइफल के सैनिकों ने अपन पश्चिमी पाकिस्तानी हुक्मरानों के आदेशों का उत्सर्जन करना शुरू कर दिया । वस्तुतः पूर्वी पाकिस्तान में सुक्ति के लिए समय शुरू हो चका था ।

राष्ट्रपति याह्या खान पूर्वी पाकिस्तान में घटनवाली घटनाओं की संभावना से पूणतया अवगत थे । 25 माच को अधिवेशनकी नयी तारीख तय करने से पहले याह्या खान ने भुट्टो से एक लम्बी बातचीत की थी । शुरू से ही इस बात की आशंका का जा रही थी कि राष्ट्रपति याह्या खान भुट्टो से सौंठगाँठ करके नयी तारीख का जो एनान किया था वह मात्र दिखावा था । प्रसक्तो का कहना था कि पश्चिमी पाकिस्तान में पूर्वी पाकिस्तान जहाज से जाने के लिए लगभग डेढ़ सप्ताह लगे हैं । याह्या खान चाहते थे कि इन डेढ़ सप्ताह दिनों का बीच पूर्वी पाकिस्तान की पश्चिम पाकिस्तानी सेनाओं से इस प्रकार भर दें कि यहाँ का लोग सिर नहीं उठा सक । पूर्वी पाकिस्तान की सान बरोड की यात्राओं में सनिका की सम्पदा मात्र चालीस हजार थी । दलों की काब में बरते बरते चालीस हजार सनिका कभी भी हिंसक लोगों के गिरफ्त में आ सकते थे । अतएव और अधिक सनिका को ल जाना आवश्यक समझा गया । यह निश्चिन था कि यदि बहुत बनी सामदा में पश्चिमी पाकिस्तान सनिका पूर्वी पाकिस्तान पहुँच गये तो वहाँ काफी खतरापात होगा । इसी डर को ध्यान में रखकर विदेशी नागरिकों न डाका छोडना भा शुरू कर दिया ।

पाकिस्तान द्वारा हमन — 5 मार्च को गेख मुजीबुररमान न स्वाधीन बगला दश की घोषणा कर दी और प्रशासन का कार्यभार सम्हालते हुए पतीस आदेश जारी मा बि रा — 25

किये। यह बंदन उस समय उठाया गया जिस समय सैनिक सप्ताहिकारियों के हथकों को बांधकर लेता था। इन हथकों के अनुसार 15 मार्च से आठ अस्तित्व कमचारा जमाने पर नहीं लौटता उस नीकरा से निकाला नो जाता है साथ ही दस वर्ष का मुजाबो जाता। उधर उस ही मुजाबन सत्ता सहायी बंधे ही राष्ट्रपति माह्या ली नरानो से बाता के लिए आका पंच। गनों नताओं के बीच कद दौर में बाताए दूह। मुद्राधन न स्वायत्तता की मांग इत्यादि आर यह कह कि पाकिस्तान के गनों भागों के लिए उद्दिष्टान सत्ता का दक उत्त-जन्म हो और व पृथ-स्य से अपने उद्दिष्टानों का रचना करे। परिणाम पाकिस्तान के जय मता भा गता दुर्गाय गद। गनि इन बाताओं का काइ नताजा नो निजना। 23 मार्च का पाकिस्तान दिवस पर वहाँ माह्या न जवह पाकिस्तान का मा-दुर्गा का बहादुरादी नो न यह नि प्रतिषेध निवस के तौर पर मनाया। इस नि जवहमा नो का मु-समानों पर बला दण के पद पहराय गद। 25 मार्च का यह-माह्या बाता एकाएक मय ग मदी तौर गमा उत मुद्राधनमान पाकिस्ताना मुक्तियों गमा कर निव गद। 26 मार्च का जवामी नो की मुक्ति सोड तथा पाकिस्तानी मना में बाजाप्टा मुद्रा गमा। यह मुद्राधनमान का चर्गाद र-पुर का निस्सा गकर बाता वी दूह फौजों न पाकिस्तानी नो का टाका न देणल कर दिया। मागद ला प्रमोदक जने मुद्राधन स माग खडे ग और मजीद के मक्ति फौज का पूरी तौर पर गमा पर बला हा गया। मुद्राधन मुद्राधन दौरान पाकिस्तानी छात्र न गका का पूरी तरह बला कर दिया जो वह दण इमारतों की जह खहरों का नर-रह-या। टाका विवविद्यालय की पाकिस्तानी मुक्तियों न दाना मुद्रा निगना दनाय। वि-विद्यालय के मुक्तियों निव और छात्र पाकिस्तानी मागन-नों के निका दन। सम्पूर्ण पूर्वी बाल के समाचार-पत्रों पर कदा प्रतिबन्ध लगा दिया गया। निम्न पत्रकारों का दण्ड हाल में दण्ड कर दिया गया और गमा का तरह उन्हें हवा बहा पर ला-र गमा न बाहर किया गया।

26 मार्च को राष्ट्रपति माह्या ली न पाकिस्तान दिवस से राष्ट्र के मान अपने सदाय का प्रसारण दिया। नहोन मुगैद के असहयान जमाने का गहारी का काय धारित दिया और जवामी गमा का ए-गर-जानूना मस्या धारित कर दिया। इसका साथ ही मागद गमा के निवस और कटार कर निव गमा और मागद ला प्रमोदक को बाता गमिला कि वह ननी साधनों का दण्डाकरक पूर्वी बाल का बाताधन मुद्राधन ने। मुद्राधन पाकिस्तानी मुक्तियों का निहृयी बाला जवामी गमा और दूह इमारत मुद्राधन किया। हवारों-हवार की मस्या में माग मा-जान गमा। पूर्वी बाल में एका नरमहार मुद्राधन विवविद्यालय मिलल गमा हो मस्या मुक्तियों के इतिहास में कहीं निव सक। इतने बडे पमाने पर नरमध हान गमा भी नशार के विविध गमा चला मुद्राधन। दरद गमा न इस गमा पर जमाना को प्रतिनिधिय व्यक्त नहा की। निम्न पाकिस्तानी में दिनेय सचिव का पूर्वी पाकिस्तान के मुद्राधन में जमाना दूहा बह जयन निवविद्यालय रहा। जवामी सरकार ने मा-का-का-का गमा में जमाना

प्रतिनिधियां जाहिर नहीं करने का ही निश्चय किया। केवल सोवियत संघ ने पाकिस्तान सरकार को पत्र लिखकर पूर्वी बंगाल में उसके द्वारा किये जानेवाली कारवाइ पर अपना खेम व्यक्त किया और यह आशा व्यक्त की कि पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह समय में काम लेंगे तथा जनता की जनतांत्रिक भावना का आदर करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के तानाशाहों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और वे बंगाल की जनता को कीड़े मकौड़ की तरह मारते रहे।

12 अप्रिल 1971 को स्वाधीन बंगला देश की सरकार का गठन कर लिया गया। लेकिन किसी देश ने इस सरकार को राजनयिक मान्यता प्रदान नहीं की। बंगला देश का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न नष्ट होने पाये इस प्रयास में पाकिस्तान सरकार को पूरी सफलता मिली। सैनिक दृष्टिकोण से पाकिस्तान ने ठीक काल के लिए बंगाल के विद्रोह को कुचन दिया। इस हासत में लाखों लाख की संख्या में बंगाली लोग भागकर भारत आये और भारत के समस्त विस्थापितों ने एक भयंकर समस्या पैदा कर दी। चूंकि भारत में गुरु से ही पूर्वी बंगाल के लोगों की आकांक्षा के प्रति अपनी सहानुभूति दी थी इस कारण पाकिस्तान तथा भारत का संबंध बहुत ही बिगड़ गया।

भारत का दृष्टिकोण—पूर्वी पाकिस्तान में एक अस्थिर हो विधान पमाने पर नरमदया हुआ तथा लोकतंत्र का गला पाटा गया। लेकिन सोवियत संघ छोड़कर किसी देश की सरकार ने इनका आलोचना नहीं की। अरब देशों ने पाकिस्तान का आतंरिक मामला मानते हुए मोन रहे तथा अमेरिका और ब्रिटेन ने इस घटना के प्रति सदस्यता का दृष्टिकोण ही अपनाया। लेकिन पड़ोसी देश होने के नाते भारत में घटनाओं की उपेक्षा नहीं कर सकता था। पूर्वी पाकिस्तान के घनाव में जब नेहरू मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व में अवामी लीग की सफलता मिली थी तो भारत ने इसका खुले दिल से स्वागत किया था। वेत लोकतंत्र घम निरपेक्षता समाजवाद तथा पड़ोसी देशों के साथ पत्रों के प्रवक्ता ये और भारत का यह आशा थी कि उनके हाथ में सत्ता जाने पर भारत पाकिस्तान सम्बंध में मंत्री का एक नया अध्याय शुरू होगा। इसीलिए प्रारम्भ से ही भारत सरकार और प्रगतिशील भारतीय लोकमत की सहानुभूति अवामी लीग के साथ थी। लेकिन जब पाकिस्तान के सैनिक शातकों ने लोकतंत्र का गला पाटना शुरू किया। खुले के साथ ही गाँठ करके इस्लामाबाद में पूर्वी पाकिस्तान की जनता की आकांक्षा का कुचलना शुरू किया तो भारत में घोर निराशा और चिंता हुई। इसीलिए जब पाकिस्तान में गृह उद का सूत्रपात हुआ तो भारत ने पूर्वी बंगाल को अपना पूरा नैतिक समर्थन दिया। भारतीय समाचार-पत्र राजनीतिक पार्टियों और सरकार सब ने एक स्वर से इस्लामाबाद की कारवाइ की निन्दा की और पूर्वी बंगाल के लोगों के प्रति सहानुभूति प्रकट की। बुद्ध लोगों ने अवामी लीग की अस्थाओं सरकार को सुरत मायता देकर सैनिक सहायता देने की याग की। भारतीय संसद में इस विषय पर सधसम्मति से एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस प्रस्ताव में यह दृढ़ विश्वास व्यक्त किया गया था कि बंगला देश की साढ़े सात करोड़ जनता का ऐतिहासिक मुक्ति संघर्ष अंततः सफल होगा। प्रस्ताव में पूर्व में पाकिस्तान पर यह आरोप लगाया गया था कि उसने दिसम्बर 1970 में सम्पन्न

आम चुनाव में पूर्वी बंगाल की जनता के अमिनत की सुरास्तर अपना का और राष्ट्रीय एसम्बली को अपने अधिकार और सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न भूमिका से वंचित रखा।

इसके कुछ ही दिन बाद जिल्पी में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में श्रीमती जिल्पी गांधी ने कहा कि यद्यपि भारत के लिए न तो यह उचित है और न सम्भव ही है कि बंगला देश में पाकिस्तान के मुनिक दूकानों के नृपस कारनामों का मूक रहकर देखता रहे किन्तु अन्तर्गत में ऐसा वाइ काम नहीं उठाना चाहिए जिससे मामला और पचादा हो जाय तथा बंगला देश का जनता की समस्याएँ और उनका सन्ताप दूर जाय। भारत ने बंगला देश का जनता पर टाय गये जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज बुलन्द की है और आशा की है कि मुसलमान के अन्तर्गत भी पूर्वी बंगाल के स्वतन्त्रता सनानियों का समर्थन रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा सबसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें बंगला देश पर टाय गये जोरजुल्म का तीव्र भर्त्सना का साथ ही आर विश्व भर का जनता और सरकारों से यह अनुरोध किया गया कि वे बंगला देश का क्रमिक सहार से पाकिस्तान सरकार का राकन के लिए तुरन्त ठोस काम उठावे। यह प्रस्ताव विशेष मंत्री स्वर्ण सिंह ने पेश किया। उन्होंने आवासन दिया कि बंगला देश का अस्थायी सरकार का मायता नि जान का माग पर सरकार सम्भारतापूर्वक गौर कर रही है।

इस तरह कई प्रस्ताव भारत का भा राजनीतिक पार्श्वों ने पारित किए। बंगाल की घटनाओं का आर विश्व का ध्यान आकर्षित करने के लिए आल इंडिया इंडियो (आकाशवाणी) ने प्रमुख भूमिका का निवाह किया। पाकिस्तानी मुनिक पत्रकों ने इस बात का पूरा प्रबल कर दिया था कि पूर्वी बंगाल में जन विद्रोह आर सना द्वारा कुचल जान की भनक टुनिया का न हो मिल। लेकिन रडिया आर समाचार-पत्रों के सवात्पाताओं ने इस प्रयास का नाकामपाद कर दिया। ऐसा हानन में पाकिस्तान की सरकार ने भारत पर आरोप लगाया कि वह पाकिस्तान के अन्दरूनी मामल में हस्तक्षेप कर रहा है और इसके विरुद्ध कड़ा विरोध-पत्र भेजा। पाकिस्तानी रडिया और वहाँ के नियन्त्रित समाचार-पत्र हमला यहाँ राग अनात रह। ऐसा स्थिति में दोनों दलों के सम्बंध में पुनः जारों का तनाव आ गया।

राजनयिक तनाव—यह तनाव तब आर-गि-द-गया जब कुछ पाकिस्तान ने जिला स्थित पाकिस्तानी उच्चायुक्त से अपना सम्बंध विच्छेद करके भारत में राजनीतिक शरण का माग का और भारत सरकार ने उनके अनुरोध को तत्वात् अकार-द-दिया। उनके पता 18 अप्रिल 1971 को उन्होंने भारत पाकिस्तान सम्बन्धों में उत्तर अन्त कमचारियों ने पाकिस्तान से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर दिया तथा अपने का स्वाधीन बंगला देश का दूतावास घोषित कर दिया। पाकिस्तान सरकार भारत सरकार से यह अपना करता थी कि वह उन उच्चायुक्त के भवन को पाकिस्तान सरकार के सुपुर्न करने में उसकी मन्त करनी, लेकिन यह सम्भव नहीं था। इसलिए उन्हा स्थित भारतीय उन उच्चायुक्त के साथ पाकिस्तान सरकार के दुरे बर्ताव की आशंका बढ़ गया। इस सम्भावना से बचन के लिए भारत सरकार ने दावा स्थित अपने उप-उच्चायुक्त से कमचारियों और उनव

परिवार के सदस्यों को निकालने का फैसला किया। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने इसकी सुविधा नहीं दी तथा कलकत्ता स्थित पाकिस्तान उप उच्चायुक्त की इमारत न मिलने पर भारत को गंभीर परिणामा की धमकी दी। जब पाकिस्तान के नव नियुक्त उप उच्चायुक्त महदी मसूँ कलकत्ता आये तो नगर के लोगो ने उनके विरुद्ध घोर प्रदर्शन किया। इस पर पाकिस्तान ने यह प्रस्ताव रखा कि भारत अपने डाक स्थान उप उच्चायुक्त के कार्यालय को बंद कर दे। इससे तुरत हाथ धाँ भारतीय उप उच्चायुक्त के पदाधिकारियों पर तरह-तरह के प्रतिबंध लगा दिये गये। हमके प्रयुक्त में भारत ने भी पाकिस्तानी राजनयिकों को देश से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। पाकिस्तानी की अद गेराजो व कारण डाक स्थित भारतीयों को निकालने में बड़ी कठिनाई हुई। सावित्रत सध और स्विट्जरलैंड की सरकार की मध्य स्वंता के फलस्वरूप भी इसका कोर् सधाधान नहीं हो सका। राजनयिक स्तर पर दोनों देशों का तनाव बढ़ता ही गया। इसी बीच पूर्वो पाकिस्तान से भारत आनेवाले विस्थापितों की संख्या लगातार बढ़ती रही। इससे भारत का चिंतित होना स्वाभाविक था।

मान्यता का प्रश्न—17 अप्रिल 1971 को बंगला गणराज्य को विधिवत स्थापना होते ही भारत में इस नये राज्य को मान्यता देने का प्रश्न और मुखर हो गया। भारत के सभी राजनीतिक दलों ने जोरजोर से माँग यह कर दी कि भारत सरकार को इस नवीन गणराज्य को तुरत राजनीतिक मान्यता प्रदान कर देनी चाहिए। भारतीय लोकमत का यह स्पष्टिकोण था कि प्रभुसत्ता के लिए यह केम को बिबुल मान्यता न देने का अर्थ यही होता है कि आप उसे दण्डोही माना है और अंतर्राष्ट्रीय विधि की भाषा में वह उचित दंड का पात्र बन जाता है। कुछ लोगो ने यह माँग भी रखी कि यदि कानूनी मान्यता (de jure recognition) देने में कठिनाई है तो कम से कम तथ्येन मान्यता (de facto recognition) तो देना ही चाहिए। लेकिन भारत सरकार इस प्रश्न पर सशम स काम लगी रही। सरकारी नीति का निर्धारण लोकमत के निर्धारण की तरह भावावेग से प्ररित होकर नहीं किया जाता। व्यवहार में किसी दल को मान्यता देने न देने का प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय विधि का न होकर राज्य की नीति का प्रश्न होता है। कई सरकारों को अस्तित्व में आने से पहले ही मान्यता दे दी जाती है और कई सरकारों के अस्तित्व में होने पर भी मान्यता नहीं दी जाती। निर्णायक बात किसी सरकार की अपनी नीति होती है। जहाँ तक बंगला देश की मान्यता का सवाल था ऐसा काम गम्भीर और सर्वांगीण शोध विचार के बाद उठाना था क्योंकि इससे चीन और पाकिस्तान के साथ हमारे भावी संबंध तथा युद्ध की सम्भावना सीधे जुड़े थे।

भारत न संसद में अपने एक प्रस्ताव का माध्यम से यह घोषित कर दिया था कि वह बंगला देश के साथ है परंतु यह मान्यता देने से इसलिए बचता रहा है कि कहीं उसी का आश्रय लेकर पाकिस्तान का भारत को बदनाम करने और उस पर हमला करने का अवसर न मिल जाय। बदनाम तो वह यह कहकर पहले भी कर रहा था

कि बंगला देश की पहचान में भारत का हाथ है परन्तु मायदा देने से वह उस उसके प्रमाण के रूप में पाना नहीं सकता था । भारत से चला था कि यदि बिना मायदा दिये ही काम चल सकता है और बंगला देश में लाञ्छित एवं मान्यता का जा हत्या हो रही है वह बल हो सकती है ता मायदा देकर इस महापीप में ऐसा स्थिति का खतरा भास जन का बय फायदा जा शक्ति का गल्ट कर द और उस दा राष्ट्रों के बीच दू का बंधा बना द । इसलिए उसके प्रयत्न का दिशा निरन्तर यही रही कि पाक को भारत को न्यून बदनाम करने तथा उस पर हमला करने का वहाना न मिल और मामला आसानी से मुलच जाय ।

इसके लिए उसने विश्व भर के बड़े देशों से सम्पर्क स्थापित किया उनमें बीच एक ऐसा बाधावरण बनाने का कागिज का कि बंगलादेश का वास्तविकता से परिचित हो सकें और उसके बाव वहाँ जा नर-संहार हो रहा है उस राक्षस में अपने प्रभाव का प्रयोग करें । उसने उनसे आग्रह किया कि वे उस सैनिक और वार्षिक मन्त्र एकत्र बन कर लें । उसका यह ख्याल ठाक है कि वार्षिक दृष्टि से पानु हो रही पाकिस्तान-सरकार का बसा स्थिति में बंगला देश में नर-संहार बल करने और किसी राशनानिब समयात पर पहुँचने के लिए बाध्य होना पड सकता है। उसमें उस बहुत अधिकसंभवता नहीं मिला । सान्द्रित रूप का छाड़कर न बचने किता बल बड़े देश ने माह्य-सरकार के मन कागजातों का निष्पत्ती नहीं का अपितु अमरिका ने यह कहकर उन सन्निव महायता नना जारा रखा कि वह पन्त ह म्हावृत्त हो चुका है । उसका जवाबा कुछ जराब नों से भी उस मन्त्र का क्रमजानी रहा। विभिन्न देशों के प्रत्यन्तर्णी सुदृष्ट सन्स्थों तथा अन्य लोगों के बक्तों और नखों का भी पाकिस्तान तथा ननपर कोद धसर नहीं पडा । उससे मायदा देने के प्रश्न पर भारत का लाञ्छ-मत भारत सरकार पर निरन्तर बलाव टाटना रहा । सर्वोच्च नेता जयप्रकाश नारायण ने बिब लोकमत की मायदा के पक्ष में करने तथा बंगला देश में हो रहे नापण नर संहार का बाब मुसार दा ध्यान अकृष्ण कराने के लिए कई देशों की भ्रमण गुप्त किया तथा बंगला देश के समयन में राणीय एकता को प्रश्रित करने के लिए दिल्ली में दस लाख लोगों की एक विगाउन रली ल । उद्दिष्ट विश्वजनमत का प्रतिबल प्रति क्रिया की समायदा के दर में माह्य सरकार मायदा नन से कतराता रहा । जो लोग मायदा देने के पक्ष में आन्तानन कर रहे थे वे भारत सरकार की तुल्यता नाति से बडे नाराज थे । उनका कहना था कि यदि बंगला देश पर पाकिस्तानी आक्रमण के तुरत बाव ही शरणापियों को भारत में आन में रोकने के तक सवर भारत न अपना फौजें पूर्वी बंगाल भजदी हानी ता समस्या इतना विकरान होघारा नहीं कर पाती । अगर विश्व जनमत के नाम पर निष्पत्ती को बराबर स्थगित करने में अग्र्यन्त भारतसरकार ने भारतीय जनमत की पूरा तरह उन्मा करत हुए इस अवसर का हाथ से निकल जाने दिया । उनका आरोप था कि राष्ट्रीय हित के प्रश्न पर विश्वजनमत की तुल्य जनमत का अपमान है । उनका यह भी कहना था कि माह्य सरकार ने अपने स्व और कार्यवाई से भारत के सामने बंगला देश की मायदा देने के सिवा और कोई रास्ता

गहोँ छाड़ा है। वह वहाँ लोकतंत्र और मानवता की निरंतर हत्या कर रहा है। भारत की आर शरणार्थियों का बधाह प्रवाह जारी है। यह भारत पर आकांक्षा होने का आरोप लगाकर हमला करने का बहाना ढ ढरही है। १९ सौ सौ की अमरिका और चीन उसकी पीठ पर हैं। वह यह भी अनुमान करता है कि अगर युद्ध होता है तो अनेक बड़ दगा के राजनीतिक स्वाध फसे हान के कारण वह उसके विपरीत नहीं पड़ेगा। यही कारण है कि सन् याह्या की ओर से न केवल ध्वन किया गया कि युद्ध बहुत नजदीक है अपितु पश्चिमी और पूर्वी सीमा पर उसने उसके लिए आवश्यक तैयारियाँ भी शुरू कर दी। मतलब यह है कि उसका छह मामला मुसलमानों का नहीं अपितु किसी बहाने भारत से लड़ाई मोस लेने का था। जब ऐसी हालत थी तो मायना का अधिक दूर तक रोकने का कोई अर्थ नहीं रह जाता।

2 अगस्त 1971 को मास्को स्थित भारत व भूतपूर्व राजदूत श्री बी सर एकाएक रहस्यमय ढंग से मास्को गये। समाचार पत्रों में अटकलवाजियाँ हूँ कि वे बंगला देश की मायता के प्रश्न पर विचार विमर्श करने के लिए भारत-सरकार द्वारा भेज गये हैं। इसी बीच राष्ट्रपति याह्या साँ भारत को युद्ध की घमकी बर्ष वार दे चके थे। कम से कम तीन बार उन्होंने यह वक्त ब द दिया था कि यदि भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के विद्रोहियों का हौसला दाने का यत्न किया तो भारत के साथ पाकिस्तान को परी लड़ाई छि मकनी है और इस युद्ध में हम अकेल नहीं रहेगे इसका मतलब था कि पाकिस्तान को चीन का समर्थन प्राप्त होगा। इसी समय अमरिका ने भी कह दिया कि यदि भारत पाकिस्तान में युद्ध छिड़ेगा और चीन न पाकिस्तान का साथ दिया तो बसी स्थिति में भारत को अमरिकी सहायता की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। याह्या साँ की घमकी तथा चीन और अमरिका के भारत विरोधी दृष्टिकोण से भारत उप महादीप की स्थिति अत्यन्त नाशुक हो गयी और युद्ध का आगका बहद बढ़ गयी।

इस वक्त का प्रकाशन—इसी बीच पश्चिमी पाकिस्तान का सरकार ने पूर्वी बंगाल की घटनाओं पर एक न्वेनपत्र का प्रकाशन किया। यह न्वेनपत्र एक झूठ का पुति दा था। इसमें पूरे एक अध्याय में बंगला देश की समस्या का जनक भारत को बताने का भौंदा प्रयत्न किया गया था। न्वेनपत्र में विमान आहुरण कांड के समय से ही भारत पाकिस्तान सम्बंधों का बितरण करके यह बताया गया कि भारत ने पाकिस्तानी विमानों की भारतीय क्षेत्र पर स हाकर उड़ाना पर प्रतिबध लगाने और याह्या साँ तथा शेख मुजीबुररहमान के बीच हो रही राजनतिक और सवधानिक समझौता बार्ता में गतिरोध पैदा करने के उद् य पर किया। पूर्वी बंगाल की घटनाओं के लिए भारत का ज़रूरदासी ज़रूरते हुए यह कहा गया कि यह भारत मुजाब साँठ बँठ का परिणाम है जो 1968 के अथरतता पत्रयत्र के समय से ही चल रहा था।

भारत-सोवियत सन्धि — बंगला देश में नर-सहार शरणार्थियों की बाढ़ बंगला देश की मायता का प्रश्न तथा पाकिस्तान की घमकियों के कारण भारत और

पाकिस्तान का सबंध बहुत बिगड़ गया। भारत ने विश्वलाकमत्त को जगृउत करने के लिए बड़ा प्रयास किया। लेकिन उसका काइ परिणाम नहीं निकला। पाकिस्तान का घमकियों के सारा में भारत अपने को एकजम बलसा महसूस करने लगा और इस बल-तपन का समाप्त करने के लिए साविदत मुक्ति के साथ एक मंचि करने के लिये उसका समस्त वादविबल नही रहा। अतएव 9 अगस्त 1971 को भारत और सोवियत मुक्ति के बीच एक संधि हुआ गयी। इस संधि से उत्तलाल लाल महदूआ कि भारत पर पाकिस्तानी अक्रमण का भी कुछ समय के लिए रोक लगा गया।

राजनयिकों का प्रत्यावतन—इसी बीच 11 अगस्त 1971 को भारतीय राजनयिकों और उनके परिवारों का वापस भारत के सम्बन्ध में पाकिस्तान से चले रहे विवाद का समाधान हुआ गया। पाकिस्तान के कलकत्ता स्थित उप-उच्च-मुक्त के बगाली सम्मेलन बड़ी सुरक्षा में बगाला में के प्रति निष्ठा की रूप में चुक था। इस कारण पाकिस्तान ने आकाशियत भाँटाव में उच्च-मुक्त के कमचारियों का राक रखा था। जिस लया सोवियत सरकारों के मध्यस्थता से इस प्रश्न पर समझौता हो गया। जिस लया सोवियत विमानों से टाका में रहनवान भारतीय राजनयिक एवं उनके परिवार तथा बनकत्ता में रहनवान पाकिस्तानी राजनयिक का प्रया वतन हो गया।

पुनः मान्यता का प्रश्न—भारत सोवियत मुक्ति के बाद पाकिस्तान के समन्वित अक्रमण का खतरा ल गया और यह उम्मीद का गया कि बगाला देश का तुरन्त ही भारत सरकार की मायता मिल जायगा। लेकिन मुक्ति के बाद जो भारत सोवियत मुक्ति विज्ञप्ति निकली उसने इस आशा पर पानी फेर दिया। इसमें बगाला देश का प्रयोग नहीं किया गया। पूर्वो पाकिस्तान के प्रमाण से यह आशा उठाना हुआ गयी कि मायता के प्रश्न पर निगद बना उठना हुआ कर्त्तव्य का विवना कर्त्तव्य वह भारत सोवियत मुक्ति के पूर्व था।

मुक्ति सेना की गतिविधि में तजा —इसी बीच पाकिस्तानी सेना के विरुद्ध मुक्तिवाहिनी का अनियान उत्तलाल नात्र हाता रहा और उसका चौतरफा हमलों से सुत्रन्त पाकिस्तानी मुक्ति फिर छावनों में सिमलन लग। सिलहट नौजाखानी कमिस्ला मुक्तिवाहिनी राजघाटों चौतरफा आतिशत मुक्तिवाहिनी का कारवाइयों के प्रमुख केंद्र था। इन इलाकों में उसने न केवल मुखार साधनों को सतिप्रस्त करके पाकिस्तानी सेना का मुख्य छावनों में बल-अनप कर दिया बल्कि छपामार सगइयों में मुक्तों पाक सनिकों का मात के घात भी उठार दिया। इस सिनसिल में पाकिस्तानी प्रसाइकों न अपना पूरा ताकत से यह प्रचार करना आरम्भ कर दिया कि मुक्तिवाहिनी का भारत केवल सारात्रों में ही सारात्रा नहीं करता बल्कि उत्तर-पूरबी सनानियों का प्रगिभल भी ले रहा है।

घाटपा की घोषणा—12 अक्टूबर 1971 का गठित पाटपा की महदूब पूरा वरतव्य हुआ जिसमें उन्होंने 27 दिसम्बर का राणाव अनुमदसी का उद्घोषण बुलाने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने एक नये सविधान का घोषणा का सिधत उन्हें निवाचित प्रतिनिधियों की अधिकार हस्तांतरित करने में मुक्तिवाहिनी का।

याह्या खाँ ने जहाँ इस बात का दावा किया कि उन्होंने प्रस्तावित संविधान और भावी सरकार की रचना के बारे में राजनीतिक नेताओं से परामर्श किया है और वे प्रजातांत्रिक पद्धति में विवास करते हैं वहीं उन्होंने इस बात की भी धमकी दी कि पाकिस्तान की एकता का विरोध करने या उनके उद्देश्यों की आलोचना करने वाले व्यक्तियों को सहन नहीं किया जायगा।

इस भाषण के दौरान पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने दावा किया कि वह राष्ट्रीय जनमत उनके पक्ष में है। विशेषकर उन्होंने मुस्लिम दलों की सहायता और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जनवादी चीन के समर्थन के बारे में प्रशंसा व्यक्त की। उन्होंने भारत के विरुद्ध यह आरोप लगाया कि भारत लगातार पाकिस्तान के साथ दुश्मनी का वर्ताव करता रहा है और पूर्व बंगाल में विद्रोह की जितनी भी घटनाएँ घटी हैं उनके पीछे भारत का ही हाथ है। याह्या खाँ के अनुसार भारत पाकिस्तान के बहुत से लाभों में तनाव पैदा करने की कोशिश करता रहा है और इस बात का योजना बनायी गयी है कि पूर्वी बंगाल को पाकिस्तान से अलग कर दिया जाय। उन्होंने पाकिस्तान की जनता को यह बताया कि पाकिस्तान का वह मान सकेट पूरा रूप से भारत की कारवाइयों के कारण हुआ है। इसलिए उन्होंने इस्लाम पगम्बर और इमाम का तबादा कर पाकिस्तान की जनता को किसी भी समय के लिए तयार रहने को कहा। जनरल याह्या खाँ ने धमकी दी कि पूर्व बंगाल में वह अपने योजनानुसार सरकार बनायेगा चाहे उससे लिए उन्हें भारत के साथ युद्ध भी क्यों न करना पड़े। याह्या खाँ के भाषण का एक महत्वपूर्ण अंश बंगला देश से भारत आये हुए शरणार्थियों के बारे में था जिनमें पाकिस्तान के अधिनायक ने यह आरोप लगाया कि भारत शरणार्थियों की सख्या बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है ताकि विश्व का ध्यान दशों से अधिक से अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त कर सके। याह्या के अनुसार भारत में केवल बीस लाख शरणार्थी थे।

सीमान्तों पर सैन्य का जमाव—अक्टूबर 1971 में मुक्तिवाहिनी की प्रतिविधि में अभूतपूर्व तेजी आयी। पाकिस्तानी सैनिक अधिकारियों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या उठ खड़ी हुई। इसमें कोई संदेह नहीं कि मुक्तिवाहिनी के छापामार भारत की भूमि को अपना अड्डा बनाये हुए थे और वही उन्हें प्रतिशत तय प्रशिक्षण मिलत थे। सीमांत पर ही छापामारों को रोकने के उद्देश्य से पाकिस्तानी सैन्य का भारत-पूर्व बंगाल सीमा पर जमाव होने लगा। पश्चिमी सरहद्द पर भी बहुत बड़ी सख्या में पाकिस्तानी फौज तनात कर दी गयी। युद्ध की सम्भावना को देखते हुए भारत सरकार को भी कई रक्षात्मक कदम उठान पड़े और उसने भी सामान्यों पर अपनी सेनाओं का जमाव गुरु कर दिया। इस हालत में स्थिति अत्यंत नाजुक हो गयी। सैनिकों के जमाव के फलस्वरूप भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति इस हद तक पहुँच गयी कि कभी भी दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ सकता था।

इन्दिरा गांधी द्वारा पश्चिमी देशों की यात्रा — "म नाजुक स्थिति में युद्ध का रोकने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री श्रीमता इन्दिरा गांधी ने कुछ पश्चिमी देशों की यात्रा की। इस विदेश यात्रा का स्पष्ट उद्देश्य बगला दंग की समस्याओं से उत्पन्न राजनीतिक, आर्थिक और प्रतिरक्षा सम्बन्धी कठिनाइयों के बारे में भारत का दृष्टिकोण ऐसे देशों के सामने रखना था जो किसी-न किसी नाते भारत उपमहाद्वीप के देशों में दिलचस्पी रखते थे। इसका कारण यह था कि पाकिस्तान बगला दंग के मुक्ति संग्राम का भारत और पाकिस्तान के बीच परम्परागत दुश्मनी के सम्बन्ध में प्रस्तुत करने की काशिश कर रहा था। शरणाग्रियों को भारत भेजकर पाकिस्तान में जा आक्रामक कदम उठाया था उसे हल करने और भारतीय हिता का रक्षा करने के लिए कोई दृढ़ कदम उठाने के पड़े थे प्रधानमंत्री दूसरे देशों का आग्रह कर देना चाहती थी जिसमें कि बाद में यह नहीं कहा जाय कि इस समस्या को दूरी तरह से सुलझाया जा सकता था। श्रीमती गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि भारत को अपनी आजादी के लिए लड़नेवाले पक्ष बगलियों के साथ महानुभूति है और अबतक बगला दंग को भारत ने माफ नहीं दा है तो उसका बस एक ही कारण है कि हम पाकिस्तान को भारत पर युद्ध छेड़ने का अवसर प्रदान करना नहीं चाहते। मगर यदि मुरा का कारण हल नहीं किया तो अब यकता पक्ष पर भारत बगला दंग को मरवा सबप्रमुखता सम्पन्न राज्य के रूप में मान्यता प्रदान कर सकता है। श्रीमती गांधी ने पश्चिमी राजन्याओं को बताया कि सीमा पर अत्यन्त तनावपूर्ण स्थिति है और अबतक बगला दंग की समस्या का समाधान नहीं हो जाता अबतक सरहद्द से भारत अपनी सन्ना नहीं हुआ सकता। भारतीय प्रधान मंत्री ने उन देशों के नेताओं को बताया कि पाकिस्तान जिस तरह की उत्तजना मक कारवाई कर रहा है उसका पृष्ठभूमि में युद्ध दिग्ग गया रहना ठीक नहीं अभीतक ऐसा इसलिए नहीं हुआ है कि भारत अपना दक्षिण सीमा को बचा देना चाहता था ताकि पाकमी नेताओं को यह बहाना का माफा न हो मिल कि भारत ने उतावठपन से काम लिया है। प्रधान मंत्री ने मुक्तिवाहिनी का गतिविधियां में भी पश्चिमी नेताओं को अवगत कराया और यह बताया कि मुक्तिवाहिनी का दमन कर सकने में असमर्थ पाकिस्तान में समझ प्र न को भारत-पाक प्रश्न के रूप में परिणत करना चाहता है।

श्रीमता गांधी की विदेश यात्रा का उद्देश्य पश्चिम के प्रमुख देशों के नेताओं से दृष्टिकोणों से अन्तर्गत करने था कि वे बगला दंग की समस्या के राजनीतिक समाधान के लिए आग्रह करें पर दबाव डालकर युद्ध को भड़कने में राक सकें। लेकिन इस उद्देश्य में उनका कामयाबी नहीं मिली। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर अन्य देशों ने भारतीय दृष्टिकोण पर सन्तुष्टिपूर्ण विचार व्यक्त किया लेकिन माहूला पर कोई दबाव डालने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। कुन मिलाकर श्रीमती गांधी की निराश होकर ही इस दौर पर लौटना पड़ा।

पाकिस्तान में युद्ध समाप्त—प्रधान मंत्री की विदेश यात्रा से कुछ दिनों तक टल गया लेकिन सीमा पर तनाव बढ़ता गया। पाकिस्तान में युद्ध का उमा

बढ़ाया जान लगा। समूचे पाँचवीं पाकिस्तान में भारत का दमन करो की माँग की जाने लगी और जगह जगह इसी आगम के पोस्टर लगाये गये। पाकिस्तानी नेताओं ने स्थिति का भद्का न म कोई कसर नहीं छोड़ी। पाकिस्तानी पञ्जाब के गवर्नर ने लाहौर में एक रस्ती को सम्बोधित करत हुए कहा कि इस बार का मुद्दा अंतिम होगा। याह या ख़ाँ ने भारत का नामोनिगान मिटा देने की धमकी दी। जस-जमे मुक्तिवालों के छापामारों की गतिविधि बढ़ता गयी वैसे वैसे गुस्ते में पाक नेताओं का उमाद बढ़ता गया। इस तथ्य के बावजूद कि मुक्तिवाहिनी के पास पर्याप्त गस्त्रास्त्र तथा अन्य सामरिक साधन नहीं थे वह उत्तरोत्तर अपनी स्थिति सुधर करती जा रही थी। जो अब उसके अधिकार में थे वहाँ तो वह निश्चय बड़ी हुई थी ही। पाकिस्तान सेना द्वारा अधिकृत क्षेत्रों में भी उसका हौसला बुलंद था और उसने अपनी छापामार कारवाइयों से पाकिस्तानी सेना की नाक में दम कर रखा था। मुक्तिवाहिनी के संघर्ष के शुरू के चार पाँच महीने भारी और भारी बारिश करने में बीत चुके थे जिससे सवका बदन गर्म हो और वह एक पथस्थित सेना की तरह लगाने लगे थे। उसका उद्देश्य पाकिस्तानी सेना पर आक्रामक हमला करके उसे परागित करना ही नहीं था बल्कि उस सन्तुष्ट कर अधिकाधिक क्षेत्र पर अधिकार करना अब उसका सन्ध बन गया था। वह बगलाश के किसी एक भाग में नहीं रह रही थी। सारे बगलाश में उसकी गतिविधियों की अनुप्राप्त सुनायी पड़ती थी। यहाँ तक कि इस में भी वह पाकिस्तानी सेना की नाक के नीचे सकल कारवाइयों कर रही थी। अब सबका परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तानी सेना न केवल अपने कमजोर ठिकानों का छाड़ कर भागने लगी बल्कि अब छावनियों से बाहर निकलकर कारवाई करने में भी उसे डर लगने लगा था।

मुक्तिवाहिनी के संगठन में भारत का योगदान — जिस समय मुक्तिवाहिनी का गठन हुआ था उस समय उसमें पचास तीस हजार सैनिक होने का अनुमान लगाया गया था। इन सैनिकों में अधिसंख्यक पूब बगान रेजीमेन्ट पूब पाकिस्तान रायफल और पूब पाकिस्तान पुलिस के जवान थे जो किसी तरह पाकिस्तानी सेना का गिकार होने से बच निकल थे। अब न केवल मुक्तिवाहिनी के सैनिकों की संख्या एक लाख से ऊपर पहुँच गयी थी बल्कि उसमें सभी वर्गों के लोग भी शामिल हो गये थे। अब उसमें सैनिकों में किसान भी थे और छात्र भी बुद्धिजीवी भी थे और महान मजदूरी करके पट भरनवाल मजदूर भी और ये बगलाश की मुक्ति के बिना किसी भेदभाव के कंधे-सं-वधा मिलाकर पाकिस्तानी सेना से लोहा ल रहे थे। पाकिस्तान का आरोप था कि इतने दिनाल पक्षों पर मुक्तिवाहिनी का संगठन स्वयं भारत ने किया है। मुक्तिवाहिनी के सैनिक बगाली नहीं बरन् भारतीय सेना के लोग हैं जो योग्य बदलकर मुक्तिवाहिनी के नाम पर पाकिस्तान के खिलाफ मुद्दा लड़ रहे हैं। पाकिस्तान का आरोप कुछ अर्थों में ठीक था इसमें कोई सन्देह नहीं कि मुक्तिवाहिनी को गठित करने और छात्राश्रमों से उसे लड़ करने में भारत ने अपना पूरा योगदान दिया। छापामारों को भारतीय भूमि पर प्रक्षिण किया गया और उन्हें

वास्तुनिक अस्त भी न हो गया। राजकाय स्तर पर यह काम गरत था। लेकिन भारत के समर्थ को न विकल्प नहीं था। वह गुरु से हा कह रहा था कि समस्या का गान्धि पूरा कर राजनैतिक समाधान है। लेकिन पाकिस्तान उस किसी समाधान को मानने के लिए तैयार नहीं था। उधर एक करार का मुद्दा में अगस्त में भारत की स्थिति का चौकाने में आई कसर न हो रही थी। एसा हानन में भारत का नामन एक है। रास्ता था कि वह मुक्तिप्राप्ति का प्रचार का मन्त्र को बनाये की मुक्ति के लिए एक साथ संगठन कर।

1971 का भारत-पाकिस्तान युद्ध

युद्ध का विस्फोट—21 अक्टूबर को भारत-पाकिस्तान की पूर्वी सीमा पर स्थिति एकाएक विस्फोटक बन गया। दोनों देशों का मुनाए खामन-मानन न था। मुक्तिवाहिनी से जयत हुए कुछ पाकिस्तानी टैंक भारतीय सीमा में प्रवेश कर गए। भारतीय सेना ने जवाब में भारतीय सीमा की ओर पाकिस्तानी सेना के साथ एक मामूली लड़ाई में उसके तरह टैंक नष्ट कर दिए। इसके बाद 22 नवम्बर को पाकिस्तान के चार सुपर विमान कलकत्ता के पूर्वोत्तर क्षेत्र में लक्ष्य ठास माल का दूरा पर भारतीय सीमा में पांच मील भीतर तक घुस गए। भारत के चार नए विमान उसका पाला करने उड़ चले। बड़े दूर तक दानों तरह से हवाई लड़ाई चल रही थी। जिसमें भारतीय सैनिकों ने तीन सुपर विमानों का भार गिराया और उनके साथ हवाई जहाजों को गिरफ्तार कर लिया। 18 नवम्बर को एक अन्य मामूली लड़ाई में पाकिस्तान का जहाज टैंक नष्ट कर दिया गया। उस दिन प्रधान मंत्री शशि सेन का दौरा कर गया था। युद्ध छिड़ने के बादार अब पूरी तरह नजर बान लगे थे।

इस युद्ध का प्रभाव का एक निश्चय कहना है। 20 नवम्बर को पाकिस्तान के राष्ट्रपति याह्या खान ने घोषणा की थी कि वह उस दिनों के भारत भारत के साथ निपट लगे। तीन दिसम्बर को गान या यानी राष्ट्रपति याह्या खान ने घमकी का नवा किया। मुन्ना मुनय भारत-भारत न सूचना कि भारत के पश्चिमी सीमा पर हमला करके पाकिस्तान ने युद्ध प्रारम्भ कर दिया है। एक मर कारी प्रवक्ता ने बताया कि ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति याह्या खान ने अपना पूरा कर लिया है। आगार से आगार तक पश्चिमी भारत के उस हवाई जहाजों पर पाकिस्तान का मुना बमबाग। जम्मू काश्मीर के युद्ध क्षेत्र में युद्ध विमान गिरा पाए करके बड़ा मुद्दा में पाकिस्तानियों के घुस बान तथा पश्चिमी सीमा की बन्दर बोनियों पर पातादारी गुरु करने के साथ दोनों देशों के बीच युद्ध गुरु हो गया। पश्चिमी भारत के उस हवाई जहाजों पर एक है। साथ बखानक हमला करने का एक नया नया—भारतीय वायुसेना को पट्टा बना गया। जिस तरह 1967 में इजरायल ने अरब देशों के हवाई जहाजों पर एकाएक आक्रमण करके उनका हवाई सेना का दूतता नष्ट कर दिया था उसी तरह पाकिस्तान या भारतीय वायुसेना का नष्ट करने का इरादा रखा था। लेकिन इसमें उसका सफलता नहीं मिली। भारत सरकार ने

एकाएक हमले (pre-emptive attack) की सम्भावना के प्रति पूर्ण रूप से सतर्क थी और अपने वायुमार्गों को सुरक्षित स्थानों में रख छोड़ा था। इसलिए पाकिस्तान की आरम्भिक मनोकामना पूरा नहीं हो सकी।

भारतीय प्रतिक्रिया—जिस समय पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया उस समय दंग का कोई वरिष्ठ नेता राजधानी में नहीं था। प्रधान मंत्री कलकत्ता में थी और रक्षा मंत्री तथा वित्त मंत्री भी दिल्ली से बाहर थे। यद्यपि इन वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली से बाहर रहना ही हमला का प्रमाण था कि यद्म की पहल भारत न नहीं की थी। मयावार मिलते ही प्रधान मंत्री शीघ्र ही दिल्ली वापस आ गयी। इसी बीच रा ट्रपति न आपातकारीन स्थिति की घोषणा कर दी थी। पर्याप्त विचार विमर्श के उपरान्त यह निष्पत्ति लिया गया कि न केवल पाकिस्तान के हमले का डटकर मुकाबला किया जाय बल्कि उसकी यद्म मशीनरी को तबाह कर दिया जाय ताकि हमला के लिए बसेडा ही दूर हो जाय। अगस्त-ला में इकट्ठी भारतीय सेनाओं की आदेश दिया गया कि वह बगला दंग में प्रवेश कर दशमन का परास्त करे। पश्चिमी क्षत्र में भी सेना को इसी तरह के आदेश दिये गये। मध्यरात्रि के करीब भारतीय बमबारी ने पाकिस्तान की ओर उड़ानें शुरू की और पाकिस्तान के महत्वपूर्ण हवाई जहाजों और सैनिक ठिकानों पर बमबारी की। दो देशों के बीच बड़े पमाने पर यद्म छिड़ चका था।

समय साते बारह बजे रात का प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी ने राष्ट्र के नाम एक सन्देश प्रसारित किया। उन्होंने अपने प्रसारण में कहा कि पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया है और अब हम निगया-मक मढाई सङ्गे। उन्होंने कहा कि भारत के पास यद्म के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं रह गया है। पाकिस्तान ने भारत पर बड़े पमाने पर हमला किया है और दंग को कठिन संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए।

पाकिस्तान का दावा—उपर पाकिस्तान का कहना था कि भारत ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ पमाने पर हमला कर दिया है। 4 दिसम्बर के पाकिस्तान गजट द्वारा यह घोषणा की गयी कि पाकिस्तान भारत व साथ यद्म का निपति म है। रेडियो पाकिस्तान स बोले हुए याह्या खाँ ने कहा कि यह पाकिस्तान का भारत से अंतिम मुद्म है। उन्होंने कहा हम अपने दंग की स्वतन्त्रता और असदता के लिए ल रहे हैं। भारत ने हमला पाकिस्तान के नामोनिगान मिगान का धन किया है। पाकिस्तान अब तक इन हरकतों को बर्दाश्त करना रहा है, लेकिन अब स्थिति असह्य हो गयी है। अस्साह की मर्जी से हम इसका मुकाबला करेंगे और पाकिस्तान के मुकाबिल अपने दंग का रणा के लिए अपनी जान का बाजा लगा देंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना को पूरा अधिकार द दिया गया है कि भारतीय हमले का वह उचित जवाब द।

क्या भारत आक्रामक था ?—यद्म के छिड़ते ही कुछ दंगों द्वारा यह आरोप लगाया गया कि भारत ने पाकिस्तान पर आक्रमण किया है। इन राग्यों में प्रमुख थे

पाकिस्तान पर बगला दण्ड में राजनीतिक समझौते के लिए उसी का दबाव कारगर हो सकता था। लेकिन हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। वैसे वह भारत का ही समय से काम लेने की सलाह देता रहा। 30 नवम्बर 1971 को राष्ट्रपति निवमन ने प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी को जो पत्र लिखा उसका आगम्य यही था। समय से काम लेने की यह सलाह कारगर नहीं थी। इसके पहलू में भारत का अमेरिका से इस विषय पर उपदेग मिल सका था। समय से उनका अभिप्राय था कि सामा पर से भारत अपनी सेना हटा ले और एक कराह छरणाधिकी का भार वहन करता रहे। उन्होंने तो यह भी कि अमेरिका का बवल एक ही उद्देश्य था। वह अपने साथी पाकिस्तान का सम्पूर्ण स्थिति से बचाना चाहता था। उसका उद्देश्य बगला दण्ड की समस्या का एक वास्तविक एवं उचित हल निकालना उसका नहीं ब्रिडन। इस संकट में पाकिस्तान को मदद करना था। वह जानना था कि यदि सीमा से भारतीय सेना हटा दी जाय तो पाकिस्तान की एकता कायम रहे जाय। और बगला दण्ड का उद्यम अनर्थक ही निकल सकेगा। भारत को इस बात से कोरा मनलव नहीं था कि वह एकता कायम रहनी है या नहीं। पर वह कम हो सकता था कि बगला दण्ड से छरणाधिकी का प्रवाह बना रहे—कोई ऐसा राजनीतिक समझौता न हो सके जिससे सब छरणाधिकी वापस जा सके और वह सीमा में अपना सेना का हटा ले। यह तो उसके लिए आत्महत्या के समान होता। भारत युद्ध का हामा नहीं था परन्तु आत्म रक्षा का अधिकार तो उसे था ही।

युद्ध रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयास—भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से कुछ प्रयास अवश्य हुए लेकिन वे सबकुछ एकपक्षीय थे और इस कारण वे असफल रहे। एक ओर जहाँ इस बात पर जोर दिया गया कि बगला दण्ड की समस्या का कोई राजनीतिक हल निकाला जाय तो दूसरी ओर कुछ देशों ने यह भी कहा कि सामाया पर से सेनाएं वापस हटा ली जाय। सीमाओं पर संयुक्त राष्ट्रीय आवास भेज जाने की बात भी कही गयी। याह्या खां ने इसके लिए उर्बा की लिंगा भी ओर अमेरिका ने इसका समय भी दिया। लेकिन प्रयत्न की तनाती का प्रस्ताव भारत को मान्य नहीं हुआ। इस सम्बन्ध में भारतीय प्रतिनिधियों को धक्का करते हुए श्रीमती गांधी ने कहा कि माह या तब उपमहादीप पर छाये संकट का गतिपूरा हल बाह्य है तो बगला दण्ड से पाकिस्तानी फौजों को हटा लिया जाय। शांति भंग का जो संकट पैदा हुआ है उसका मूल कारण यह था कि याह्या की फौजों ने बगला दण्ड की आकांक्षाओं को कुचल कर बल नर संहार का जो तात्कालिक किया उसके तानों छरणाधिकी का प्रवाह भारत का ओर हा गया। यह प्रवाह न केवल उनकी सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा था अपितु उसकी सामाजिक और आर्थिक कमरे भी डोड़ रहा था। गत आठ महाने से भारत शांति की रक्षा की खातिर उसे बलित करता रहा है पर आखिर कब तक? जब उगने यह दशा कि पाकिस्तान इसका बाज नहीं

था रहा है और बगला देश में अपने शासन को कायम रखने और उसके युद्ध को नारत पाक युद्ध में बल देने का आमादा है तो उसके सिवा क्या रास्ता रह गया था कि वह भी सीमा पर अपनी सत्ता बनाए रखे । अब यदि पाकिस्तान और उसके साथी देश इस फौजी जमाव और उत्तम युद्ध की आशका को खत्म करना चाहते हैं तो उनका एक ही कर्तव्य है कि जिस कारण से यह जमाव हुआ है उसे खत्म कर दें । यदि बगला देश में पाकिस्तानी फौजों ने तूफान बपा कर भारत के लिए शरणार्थियों की मुसीबत न खड़ी की होती तो उपमहाद्वीप में शांति बग होने का खतरा पदा न होता । इसलिए अब इस खतरे से बचने का एक ही रास्ता है कि पाक फौजें बगला देश से चली जायें ।

बगला देश की मायता—भारत द्वारा बगला देश की मायता देने के लिए पिछले तीन चार महिनो में ज़रदार मार्ग हो रहा था । सभी राजनीतिक पार्टियाँ एक स्वर से लगातार इस मांग को गूँहरा रही थीं । लेकिन प्रधान मंत्री यह कहकर कि उपयुक्त समय में ही मायता के प्रश्न पर विचार होगा इस सवाल को टालती रहीं । भारत सावियत संघ के साथ पुनः यह आशा जगी कि अब भारत बगला देश की मायता दे सकेगा । लेकिन उस समय भी ऐसा नहीं हुआ । इस प्रश्न पर भारतीय लोकमत बड़ा अजीब हो रहा था । लेकिन प्रधानमंत्री ने इस सम्बन्ध में बड़ा ही दूर-दर्शिता का परिचय दिया । उन्हें छिड़ जाने पर अब मायता के सवाल को अग्रिम दिना तक टाला नहीं जा सकता था । युद्ध की अपनी शर्तें होती हैं । बगला देश के युद्ध का और भी विविध शर्तें थी । यदि बगलादेश को लेकर कबन युद्ध चलता रहता और बगलादेश का मायता न दी जाता तो शायद इस युद्ध के नतीजे बहुत सगन्ति न होत । अतएव अब मायता के प्रश्न का एक क्षण के लिए भी नहीं टाला जा सकता था । मायता के साथ युद्ध का प्रश्न था और इसके बाद रास्ता ये—या तो भारत सरकार मायता देकर बगला देश को खुली मान्य करे परिणामस्वरूप पाकिस्तान हमला करे या पाकिस्तान पहले हमला करे और फलतः भारत मायता प्रदान करे । दूसरा विकल्प ही ठाक था और यह द्वितीय ज्ञान के उपरांत इस रास्ता को अपनाना आसान था । उपर बगला देश के नेता आमतो पाषी से निरंतर अनुरोध कर रहे थे कि भारत सरकार बगला देश का मायता देने के बारे में पहल करे । इस अनुरोध पर विदेश मंत्रालय में अध्ययन हो चका था । तब दिसम्बर की आमतो गंधी की वक्तव्य यात्रा के साथ ही लगभग तय हो गया था कि भारत बगला देश का मायता देने का रास्ता है । तब दिसम्बर का एक सम्बन्धी प्रवक्ता ने सवादात्मकताओं का जवाब कुछ संक्षेप में दिया । उसने कहा था कि बगला देश के अस्तित्व का भारतीय जनता पहले ही मायता दे चुकी है । अब तो केवल राजनीतिक मायता देना ही उपर है ।

य दिसम्बर की मधेरे भारतीय लोकसभा की बैठक शुरू हुई । उपर अमरिका ज्ञान तथा कुछ और बड़े राष्ट्र युद्ध विराम के नाम पर बगला देश में पाकिस्तान के आधिपत्य को बनाए रखने का तथा अतसर के परिचय में गह्रा था का फौजों को चिटने से बचाने का प्रयत्न कर ही रहे थे कि श्रीमती गंधी ने बगला देश

को मायता देने की घोषणा कर दी। लोकसभा में हृदय और उत्साह का ऐसा दृश्य था कि वही दृश्य को भिन्न हो जाता कि इस घोषणा के तुरंत बाद दिखायी पड़ा। सभी पार्टियों के सदस्यों ने प्रधानमंत्री की घोषणा का अपूर्व स्वागत किया।

पाकिस्तान द्वारा भारत से सम्बंध विच्छेद—भारत द्वारा वगला दृश्य को मायता गिने जाने की प्रतिक्रिया पाकिस्तान में अत्यंत उग्र रही। उसी दिन पाकिस्तान सरकार ने घोषणा कर दी कि वह भारत के साथ अपना दौलत सम्बंध तोड़ रहा है। स्वामाजिक ने जारी की गयी एक सरकार घोषणा में कहा गया कि तथाकथित वगला दृश्य को मायता कर भारत ने पाकिस्तान के प्रति अपनी घृणा और पाकिस्तान का नष्ट करने की इच्छा का प्रगट किया है। राजनयिक सम्बंध टूटने के उपरान्त दोनों देशों ने स्विट्जरलैंड को एक दूसरे देश में अपने-अपने हितों की दृष्टिमान के लिए नियुक्त किया। स्विट्जरलैंड की दृष्टिमान में ही दोनों देशों के दूतावासों के अधिकारियों को स्वयं भेंट दिया गया।

संयुक्त राष्ट्रसंघ में भारत-पाक युद्ध का प्रश्न

युद्ध की स्थिति—4 दिसम्बर में ही दोनों पक्षों में दोनों मोर्चों पर घमासान युद्ध शुरू हो गया था। भारतीय सेना को आदेश था कि वह मुश्किलों की संयोग से वगला दृश्य पर चौराहा हमला कर दे। उधर पश्चिमी मोर्चे पर भी विंगल पक्षों पर युद्ध शुरू हो गया। कुछ ही घण्टा में निश्चित हो गया कि पाकिस्तान को सभी मोर्चों पर हार खानी पड़ेगी। इस कारण उसके मित्रराष्ट्रों का विचित्र अमेरिका का चिंतित होना स्वाभाविक था। पहले ही उसने भारत को बताया घमकाया पर जब इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उसने युद्ध के मामले को संयुक्त राष्ट्रसंघ में पेश करने का निश्चय किया। वैसे भी युद्ध की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्रसंघ की विचार करना ही था।

सरकार परिषद की पहली बैठक—पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्रसंघ की बर्बादी से बचाने के उद्देश्य से भारत पाक युद्ध के मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ले जाने की पहल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने की। युद्ध शुरू होते ही अमेरिकी प्रशासन ने भारत की आक्रमणकारी घोषित कर दिया। विशेष सर्व्व विविध रोजस ने कहा कि स्थिति जिस तरह बिगड़ती जा रही है उस पर काबू पाने के लिए सुरक्षा परिषद की एक आपातकालीन बैठक सीधे बुलानी चाहिए। अमेरिका के इस स्वयं पर भारत में आश्चर्य फैल गया। भारत का कहना था कि इस समय सुरक्षा परिषद की बैठक से कोई लाभ नहीं होनेवाला है। भारतीय प्रतिनिधि समर सेन ने अमेरिकी प्रतिनिधियों से वार्ता की और उन्हें अपना पक्ष समझाने का दृष्टि किया। भारत का कहना था कि यदि सुरक्षा परिषद यद्विराम की मांग करती है या सेनाओं को वापसी की बात करती है तो उसे यह मांग पाकिस्तान से करनी चाहिए। आक्रमण पाकिस्तान ने किया है उसे वगला देश में सेना हटाने का कहा जाय साथ ही भारत को पश्चिमी मोर्चा से भी। लड़ने भारतीय विराघ का को गती नही निश्चिता।

पाँच दिसम्बर को अमरिका अर्जेंटिना बेल्जियम ब्रिटेन इटली जापान निकारागुआ और सोमालिया की मांग पर सुरक्षा परिषद की बैठक बुला दी गया।

बंगला देश के प्रतिनिधित्व का प्रश्न—बैठक के प्रारम्भ में भारतीय प्रतिनिधि ने मांग की कि पहले बंगला देश के प्रतिनिधि की बात परिषद को सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत इस बात के बहुत खिलाफ है कि उपमहाद्वीप की स्थिति को भारत-पाकिस्तान विवाद के रूप में प्रस्तुत किया जाय। यदि इस मामला पर विचार ही करता है तो उसपर पूरा बंगाल की स्थिति और उसके परिणाम शोधक के अंतर्गत विचार किया जाय। भारत न यह भी मांग का कि परिषद की चुनौती बैठक हा जिससे दुनिया जान सके कि संयुक्त राष्ट्र क्या कर रहा है। इसका पूरा बैठक जब आयोजित की जा रही थी तो बंगला देश के प्रतिनिधि ने सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष से अनुरोध किया कि परिषद में उन्हें भी अपना पक्ष रखने की अनुमति दी जाय। सोवियत संघ और पोलैंड ने उसका समर्थन किया लेकिन चीन ने तत्त्व विरोध करत हुए कहा कि इस तरह एक ऐसी परम्परा स्थापित होगी जिसमें वर्तमान अंतराष्ट्रीय मंच का दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल देने का अधिकार मिल जायगा। अन्त्य में यह कहकर इस प्रश्न को आगे के लिए टाल दिया कि सुरक्षा परिषद का यह बैठक प्रारम्भिक है।¹

सुरक्षा परिषद में चार प्रस्ताव—बैठक के आरम्भ हात ही अमराकी प्रतिनिधि जॉर्ज बुच ने प्रस्ताव रखा जिसमें यह मांग की गया थी कि भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम करें तथा तुरत अपनी अपनी सनाए पीछे हटायें। बेल्जियम इटली और जापान ने एक दूसरा प्रस्ताव रखा जिसमें युद्ध विराम की बात तो कही गयी थी मगर सनाए वापस हटाने का कोई उल्लेख नहीं था। इसके बन्ने इसमें भारत में सराए लाने का एक करोड़ सराए धियों को वापस घर भेजने के लिए अंतराष्ट्रीय समाज के पूरा सहयोग का संभाव दिया गया था। तीसरा प्रस्ताव अर्जेंटिना ब्राजिल निकारागुआ सिअरा लिओन और सोमालिया द्वारा प्रेषित था। इसमें तुरत युद्ध विराम कर सनाए वापस हटाने की बात कही गयी थी। इसके अतिरिक्त भारत उपमहाद्वीप में सनाए की स्थितियों के सम्बन्ध में महासचिव उपायों को लगातार सूचना देने की कहा गया था। चौथा प्रस्ताव सोवियत संघ ने प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया था कि पूर्वी पाकिस्तान में राजनीतिक हल निकाला जाय जो स्वाभाविक रूप से अंत में भूषण समाप्त करेगा। सोवियत प्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि पाकिस्तान से यह भी मांग करे कि वह पूरा बंगाल में हिंसा के समाप्त कायों को बंद करे जिसके कारण स्थिति इतनी बिगड़ी है।

1 यह प्रश्न पुनः 14 दिसम्बर को सुरक्षा परिषद की सभा में उठाया गया। सोवियत प्रतिनिधि ने पुनः यह मांग रखी कि बंगला देश के प्रतिनिधि को बैठक में भाग लेने का अधिकार मिलना चाहिए लेकिन परिषद के अध्यक्ष ने इस अंगीकार कर लिया।

सोवियत प्रतिनिधि जब मलिक ने अमरीकी प्रस्ताव को एकपक्षीय और अस्थायी माना बताया और कहा कि इस प्रस्ताव का उद्देश्य जिम्मेवारी सहाय्य में गलत पक्ष की ओर डालना है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और उसका महान रक्षक तथा पाकिस्तान के कतिपय मित्र देश (जो उसके सैनिक गुट में हैं) भारत और पाकिस्तान को एक ही स्तर पर रख रहे हैं। यह बहुत बड़ी गलती है। ऐसी भयंकर स्थिति की सृष्टि हो न आनी यदि पाकिस्तान यह दिमश्वर के समन्वय चलावा मचने लगे पाकिस्तान के कानूनी प्रतिनिधियों से बातचीत करने से इंकार न करता। श्री मलिक ने कहा कि भारत को दण्डित किया जा रहा है और उसको अपने प्रदेश में एक करोड़ शरणार्थियों का बोझ सँभाल पड़ा है।

पाकिस्तान के प्रतिनिधि आगाज ही ने धमकी देते हुए कहा कि यदि सोवियत संधि का प्रस्ताव स्वीकार किया गया और यदि बंगला देश के प्रतिनिधि को परिपद में बोला दिया गया तो पाकिस्तान को सम्पूर्ण रूप से अपनी समुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मति पर पुनर्बिचार करना होगा। उन्होंने पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति पर विचार करने के सुरक्षा परिपद के अधिकार को चनौती दी। उन्होंने कहा कि भारत हमलावर है।

भारत के प्रतिनिधि समर सेन ने आगाजही के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि 21 नवम्बर की बाद की घटनाओं का हवाला देते हैं जब कि समस्या का जन्म इसके बहुत पहले पड़ा था जब पाकिस्तान ने न केवल बंगला देश की जनता का घर संहार किया वरन् भारत पर एक करोड़ शरणार्थी का बोझ डाल दिया। क्या यह अप्रमत्त आक्रमण नहीं था?

बस के बाद अमरीका के प्रस्ताव पर मतदान हुआ। प्रस्ताव के पक्ष में ग्यारह मत आये थे। ब्रिटेन और फ्रांस ने मतदान में भाग नहीं लिया तथा सोवियत संधि एवं पोलंड ने प्रस्ताव के विरोध में वोट दिया। यह सोवियत संधि द्वारा निषेधाधिकार का प्रयोग था।

सोवियत संधि के बीटो प्रयोग ने भारत के समस्त उपस्थित एक मन्त्रि मण्डल को डाल दिया। भारत-सोवियत संधि के सम्मेलन में बीटो का प्रयोग वांछनीय था। इसके अतिरिक्त सुरक्षा परिपद के माध्यम से अमरीका इस्लामाबाद की सलाहों की बचाने की कोशिश कर रहा था। सोवियत संधि ने उसे सही समय पर विफल कर दिया। याह्या खाँ ने भारत के श्रीनगर से लेकर जामनगर तक के एक दखत हवाई जहाज पर हमला करके जिस बेगमों के साथ पड़वा एसान किया था अमरीका की कोरिंग बेगमों का उससे अलग कर दिया था जिसका उद्देश्य हमलावर का हमला करने और समुक्त राष्ट्रसंघ के हाथ में दिए गए आश्वासन से बचने का मौका देना था।

सुरक्षा परिपद की दूसरी बैठक 6 दिसम्बर को हुई। भारत पाकिस्तान युद्ध को रोकने के लिए आठ दशा न फिर के प्रस्ताव रखा जिसमें पद विराम के अतिरिक्त फौजों की वापसी की बात बड़ी गयी थी। सोवियत संधि ने पुनः बीटो का प्रयोग

करके इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया। दूसरा प्रस्ताव मान्यित नहीं हुआ। तब तब
जिसमें पूर्व बंगाल में सामाजिक समता के द्वारा सभ्य समाज बनाने की बात बनी
गयी थी। यह प्रस्ताव भी पारित नहीं हो सका। अतः न तो एक प्रस्ताव प्रस्तुत
किया था जिसमें भारत पर आक्रमण करने का आग्रह किया गया था।

साधारण सभा में मामला—अमेरिका में स्थित दो प्रभावशाली पत्रकारिता
संस्थाओं द्वारा भारत के बारे में एक लेख लिखा गया जिसमें बहुत सारे सच और झूठ
मिश्रित था। साधारण सभा में यह जान का अर्थ साधन था। 8 दिसम्बर को
भारत विदेश साधारण सभा के समक्ष रख दिया गया। सभी भारत प्रेमियों ने यह
प्रस्ताव पास हुआ कि भारत के लिए पाकिस्तान अस्तित्व में आने के लिए
दोनों ही का अर्थ समझने में आस कर दें। भारत ने प्रस्ताव का निराकार किया।
भारतीय प्रतिनिधि समूह ने यह कहा कि भारत सरकारें इस समय मुख्य रूप से
स्वतंत्रता के लिए लड़ रही हैं जिसे पूर्व बंगाल में पाकिस्तानी सभा ने अस्वीकार
किया। अतः न तो भारत को यह कि कुछ देश यह सिद्धांत प्रचारित करना चाहते हैं
कि वह धर्म मानता है अतः मानकों में बदल नहीं देना चाहिए और तब
असह्यता का ना दाव ब्रह्मा ना रहा। यह सिद्धांत महत्वपूर्ण है लेकिन इसका
अर्थ है कि पाकिस्तानी सभा ने बताया कि उनकी अंतर्गत का बदलाव
करना है।

स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए अंतर्गत में बदल गया। पाकिस्तानी
सभा ने यह दावा किया कि इस देश में एक ही धर्म का पता चलता है कि वह
हिन्दू का कानून पर बल देना चाहता है। इस देश में हिन्दू
सभ्य बड़े पैमाने पर लुप्त हो रहा है। पाकिस्तानी सभा ने अंतर्गत
स्वतंत्रता मताना पता हाव था। अतः यह दे कि अभी भी हिन्दू धर्म
का अस्तित्व ना होगा। अब पूरा समझ लिया गया कि इसका अर्थ है
न दिया गया।

श्री सुन्दर ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत की वही भाव है जो मुस्लिम
पक्ष में था। अतः न तो यह विचार संभव था न ही कि या सभा जब तक कि
बंगाल देश में अंतर्गत के लिए बल देना देश में पश्चिमी पाकिस्तान का सभा
का दावों का दाव का माना नहीं जाता। सुन्दर विचार के साथ ही बंगाल देश के
नवा का रित्त किया जाय और बंगाल देश में नवाओं को पूर्व पाकिस्तान के दक्षिण-
कारी के रूप में मानता हो जाय। अब तक साधारण सभा इस प्रस्ताव पास नहीं
करता जो बंगाल देश का स्वाधीन हो तब तक कुछ नहीं किया जा सकता।

लेकिन भारतीय प्रतिनिधि के विरोध का कोई नतीजा नहीं निकला। सभा
में एक ही बार सभाओं ने प्रस्ताव का समर्थन किया और भारत ने विचार दिया।
अतः सभा ने अंतर्गत में बदल दिया।

इसके बाद यह नहीं कि साधारण सभा इस देश में सभ्य समाज के प्रस्ताव
का पारित होना एक तरह से भारतीय प्रतिनिधि का निराकार था। लेकिन साथ ही यह ब्रह्मा

जा सकता है कि अधिकांश देशों ने साथ के प्रति डॉब्स म द ली थीं और वे ऐसा कुछ नहीं करता चाहते थे जो अमरिका को नास्तिकों और नाराजों का कारण बन सकता था। इस प्रस्ताव पर जो मतदान हुआ था उससे यह नतीजा निकालना कि प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करनेवाले सभी राष्ट्र भारत विरोधी थे गलत होगा। मन्त्रिमंडलों के दबाव से प्रभावित होकर उन्होंने मनमाना किया। उन राष्ट्रों की बात यदि अलग गिरी जाये तो इन देशों में बिराटरी के कारण प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि भारत को बगला दान से अपनी सेनाएँ निकालने के पक्ष में मतदान करनेवाले राष्ट्रों को दो स्पष्ट वर्गों में बाँटा जा सकता है—वे जिन्होंने अमरिका के आग्रह से ऐसा किया और वे जिन्होंने चीन के आग्रह से प्रभावित होकर ऐसा कर्म उठाया। अनेक राष्ट्र ऐसा भी जो ईमानदारी के साथ यह मानते थे कि किसी प्रकार सुलह हो जाये। अमरिका ने पाकिस्तान को मदद देने के उद्देश्य से अपनी बान मन्वान के लिए साधारण सभा के रूप में राष्ट्राधीन पचावन तो जरूर जाना और जो चाँता था वह स्वीकार करा लिया। किंतु सबाल यह था कि यह पचावन सब कौनों जो जरूर याह्या की फौज बगला दान में सीधे नहर सहार कर रही थी—वहाँ लोकतंत्र और मानव अधिकारों की पुनर्जागृति की जा रही थी? तब दशों नारा ध्यान रखे जान पर भी महासचिव उहाँ क्यों मौन बने रह और उन्होंने साधारण सभा की बैठक क्यों न। दुनिया? तब समुपार्न राष्ट्र सभ ने अपना कृत्य कवच धारणाधिया को कुछ मन्त्र दन तर सोमिन रखा और मानवता की रक्षा की चिन्ता क्या नहीं की? सब तो यह है कि इस प्रस्ताव ने यह सिद्ध कर दिया कि साधारण सभा का अर्थ भी यही रखा था अर्थात् यह भारी बहुमत से इस प्रस्ताव को स्वीकार करती और किसी एक प्रस्ताव पर ध्यान नहीं देती जो सम्मेलन के मूल कारणाँ पर जा कर दूर करवा जिससे मुद्दों की वल मान स्थिति स्वयं गति हो जाता। भी आधार पर भारत ने कहा कि वह इस

The resolution adopted by the UN General Assembly on Tuesday with as many as 104 affirmative votes is an act of international pety that makes no contribution whatsoever and resolving or even understanding the problems to which it is supposed to be addressed. It is totally unrealistic completely outdated incomplete and biased. It ignores these absolutely vital and fundamental points: Firstly there is but a crumbling Pakistani military presence left in East Bengal and no political presence whatsoever. Secondly Bangladesh is a reality that no one and nothing can now undo. Thirdly the genesis of the problems has to be seen in Pakistan's brutal genocide. What did the UN or any of its organs say or do in face of this extraordinary tragedy and the mass migration to India of a number larger than the population of more than two third of the

प्रस्ताव को नहीं मानेगा और बगला दण्ड का आदेश करने का मसला जारी रखेगा क्योंकि प्रस्ताव न समर्थक मूल कारण का नहीं समर्थक है। भारत की दृष्टि में यह प्रस्ताव व्यावहारिक या क्याकि स्वयं वास्तविकता की उभार गया थी।

सुरक्षा परिषद की तात्कालिक बैठक — साधारण सभा के प्रस्ताव का भारत ने मानने से इंकार कर दिया। प्रस्ताव के पारित होने के उपरान्त श्रीमती गांधी ने उद्योगों को एकत्रित लिखा और उन्हें बताया कि भारत का इरादा पाकिस्तान के साथ युद्ध में फंसे रहने या उस बचाव करने का नहीं है और न उसका भविष्य पर उस अतिक्रम करना है। पर उस आश्वासन का पाकिस्तान के दातों पर का बल नहीं पड़ा और अमरीकी साक्षि पुन सक्रिय हो गया। 14 दिसम्बर को अमरीका के अनुरोध पर सुरक्षा परिषद की तात्कालिक बैठक हुई। अमरीका ने पुन युद्धविरोध और सन्तानों का दावों का प्रस्ताव पाम करने का चाहा। अमरीका के प्रतिनिधि जार्ज बुग ने मांग की कि भारत पर दबाव डाला जाय कि वह साधारण सभा के प्रस्ताव का तुरत स्वीकार करे।

प्रस्ताव पर वास्तव में पाकिस्तान के प्रतिनिधि तुर्कमनारखाने ने स्वीकार किया कि पाकिस्तान ने कुछ गलतियाँ की हैं मगर उनके बावजूद पाकिस्तान तब तक नहीं हट सकता। तुर्क ने भारत का विचारवादी पक्षित करते हुए कहा कि आज पाकिस्तान का बोली है—कन दूमर दगों का बारा हाणी। एशिया के अन्य देशों का उत्तजित करने का उद्देश्य से तुर्क ने यह चित्र आरेख बताया कि अन्तर्निष्ठता लका नगर दमा और इराक पर भारत का बल करने का चाहा है।

अमरीका के प्रस्ताव पर वास्तव में सावित्र प्रतिनिधि ने कहा कि यह प्रस्ताव बहुत बड़ा नहीं किया जा सकता। उसने अमरीका के मन्त्रों और यथापहान्ताति का आदेश करके उनका प्रस्ताव का खो कर दिया। उस पर अमरीका के दृष्टिकोणों का बोधित हुए न आया। बार बार का प्रयास करके उस विफल कर दिया।

सला और जामान के प्रस्ताव — सुरक्षा परिषद ने अमरीकी प्रस्ताव पर तीन बार सावित्र बोली के प्रयास से सुखत राष्ट्रों में बहिराव पैदा हो गया। उसके तुरत बाद सला और जामान ने भारत पाकिस्तान-मुक्त का नमानि के लिए पैदा फान्ना नगर किया। यह एक नौमूत्री प्रस्ताव था जिसमें सुरक्षा परिषद के तीन सदस्यों का एक समिति बनाया जानवाला था जिसका काम भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराके समझौता कराना था। उस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए परिषद के बड़ा काम हुआ जानवाला है कि भारत ने एकतरफा युद्ध करने की धापना कर दी।

members of the General Assembly who voted on Tuesday. In the face of that fearful silence and indifference to human suffering, with what conscience, moral or political, can the UN now presume to speak. —Hindustan Times December 8 1971

संयुक्त राष्ट्रसंघ की अंतर्भूतता — संयुक्त राष्ट्रसंघ के संविधान से भारत-पाक युद्ध के सन्ध्या में संधि की भविष्य का विचार करने के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि इस संधि की पूर्ण विफलता ही हाथ लगी। युद्ध से पहले जब बंगला देश में पाकिस्तान के अत्याचार का सिलसिला शुरू हुआ और लाखों की संख्या में शरणार्थी भारत आ गये तो संधि से यह आशा थी कि वह दोनों देशों के बीच युद्ध की नींव देने के पहले ही समस्या का कोई समाधान ढूँढ़ निकालेगा। यह आशा तो पूरी हुई नहीं लेकिन जब भारतीय उपमहाद्वीप में युद्ध का आग पूरी तरह भटका तो संधि भी संयुक्त राष्ट्रसंघ युद्ध रोकने और शांति स्थापित करने के कार्य में सक्षम अक्षम ही रहा। यह हस्तक्षेप कर कोई समाधान निकालने में सहायक नहीं हुआ। अतः दोनों देशों की आपसी परिस्थितियों के कारण ही युद्ध बँट हुआ। भारत का उद्देश्य बंगला देश को पाकिस्तानी चंगुल से मुक्त कर देना था। यह उद्देश्य पूर्ण हो गया तो उसने युद्ध बँट करने का आग्रह किया। पाकिस्तान जो युद्ध में हार रहा था उसके समक्ष भी युद्ध बँट करने के विचार दूसरा कोई विकल्प नहीं था।

इस विफलता के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ स्वयं दोषी था। सुरक्षा परिषद के स्थायी सन्ध्या दस देश अक्सर पर अपने हितों और स्वार्थों में ऊपर न। उठ खड़े। सोवियत संघ ने भारत का समर्थन करने के लिए युद्ध बँट करने का प्रयास पर वीटो का प्रयोग किया और अफ़ग़ानिस्तान तथा अमेरिका पाकिस्तान का समर्थन में उभरे। कुल मिलाकर यह प्रमाणित हो गया कि युद्ध रास्ता अथवा युद्ध न होना इन सुरक्षा परिषद की क्षमता बहुत सीमित है। भारत को उम्मीद थी दावा बतलाना पड़ता होगा। 26 मार्च से ही बंगला देश में नरसंहार शुरू हुआ था लेकिन संधि न उसमें कोई रुकावट नहीं किया। अपना निष्पक्षता से उसने एक समीचीन स्थिति स्थापित करने की जिसमें भारत के लिए सन्धि कारवाही के विचार को पारा नहीं रह गया था। संयुक्त राष्ट्रसंघ का बंगला देश का विचार तब शुरू जब पाकिस्तान के तब होने में कोई कसर नहीं रह गयी।

युद्ध का निवरण

पाकिस्तान बड़े हथियारों और पैदावारों के साथ युद्ध में जुटा था। उसकी सेना और तयारी की सीधुरत सम्पूर्ण उपमहाद्वीप में फैली हुई थी। लेकिन जब वास्तविक परीक्षा का अवसर आया तब पता चलता कि पाकिस्तान किसी भी मोर्चे पर भारत का प्रतिरोध नहीं कर सकता है। पश्चिमी मोर्चे पर सबसे जबरदस्त प्रहार पाकिस्तान ने छत्र के इलाके में किया। बंगला देश और राजस्थान तथा पंजाब सीमा पर काफी हज़ारों सैनिकों का पाकिस्तान का छत्र में कारवाही करना स्वाभाविक था। उसे पाकिस्तान ने अपनी सामरिक संपन्नता का आवश्यक सन्ध्या बना। छत्र में उसकी सफलता का अर्थ यह होता था कि राजपूरी और पुष्पही और जनेवाजी भारतीय संचार व बसों पर उसका अधिकार हो जाता और इस प्रकार के मोर्चे

जानेवाली सहक खनरे में पक जाती। छत्र पर उसका आक्रमण बड़ा ही प्रबल था और उससे जानेवाली घन जन की हानि की भी उसने कोई परवाह नहीं की। नकिन इतने प्रयास के बाद पाकिस्तान को कोई महत्वपूर्ण सफलता नहीं मिली। पश्चिमी क्षेत्र में अब सभी मोर्चों पर भी इसका करारी हार होती गयी।

वगना देश में भारतीय सेना न था न जन और वायुसेना से सम्मिलित कार बाह की। वायुसेना ने निश्चित ठिकाना पर प्रहार करके वगना देश में पाकिस्तान वायुसेना के अस्तित्व का ही मिटा दिया। भारतीय नौसेना ने भी साहसिक काम उठाकर बंगलादेश के पाकिस्तानी सेना के भागन के सभी अवसरों का उपयोग कर लिया। जन सेना का अनेक कमिनाइयों का सामना करना पड़ा। सामित सत्ता और उस पर नदीनाता का पार करने की कठिनायियों से सेना का दबाव कुछ मन्द अवस्थित रहा। भारतीय सेना को लगभग चार तिजिन पाकिस्तानी सेना का मुकाबला करना था। उक्तिन सहा अर्थ में यह मुकाबला बर्भा नहीं हुआ। पाकिस्तानी सेना में भागनोह मच गयी और वह अब जानी जान बचाने के उपाय में लग गयी।

पाकिस्तानी सेना का आत्मसमर्पण—इस हालत में पाकिस्तानी सेना का मनोबल टूटना स्वाभाविक था। इसका पता तब लगा जब पूर्व वगना के गवर्नर के सैनिक मलाहवार मजूर फौजान जनी ने तार भेजकर संयुक्त राष्ट्रसंघ के महा सचिव से प्रार्थना की कि उनका फौज को पश्चिम पाकिस्तान पहुँचाने में सहायता दी जाय। राष्ट्रपति याह्या खा ने तुरत उस प्रस्ताव का विरोध किया। उधर भारतीय सेना के उच्च अधिकारी वगना चलावनी दे रहे थे कि पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण करना चाहिए अन्यथा अर्थ का नुकसान हो जायगा। लेकिन पाकिस्तानी सेनापति जनरल जिन्नाजी अना इह पर बड़ा दृढ़ था। उसने कहा कि वह आखिरी दम तक बद्ध बड़ेगा और किसी कामने पर आत्मसमर्पण नहीं करेगा। बात यह था कि अमरिका का सातवा बड़ा वगना का खानी का आर बने चुका था। पाकिस्तानी अधिकारियों को विश्वास था कि चीन और अमरिका सक्रिय हस्तक्षेप करके पाकिस्तानी सेना का बगल आत्मसमर्पण से बचा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारतीय सेनाध्यक्ष ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि वगना देश में सारा पाकिस्तानी सेनाएं घिर गयी हैं। चारों ओर से रास्ता बन्द हो गया है। ब भाग नहीं सकती हैं। मना वसाय है कि वह आत्मसमर्पण कर दे। पर जनरल जिन्नाजी हथियार डालना नहीं चाहता था। उसने प्रस्ताव किया कि उस अपना पौत्रे लहा में हटाकर बुद्ध खान क्षेत्र में सीमित करने का अनुमति दी जाय जहाँ से उन्हें पश्चिमी पाकिस्तान भेजा जा सके। जनरल मानिक शा ने इस प्रस्ताव को नामनूर कर लिया। नियाजी हताश था और यकन में आनाकानी कर रहा था। इस पर निका स्थित विश्वी राजनयिकों ने उस वास्तविकता का समझन की सलाह दी। नियाजी के समक्ष कोई विकल्प नहीं था। 15 दिसम्बर को अपराह्न में जनरल नियाजी ने अमरावी दूतावास के माध्यम से बुद्ध विराम करने की प्रार्थना की। भारतीय अधिकारियों ने उत्तर देते हुए कहा कि बगना देश में सभी पाकिस्तानी सेनाओं को तुरत बुद्ध बन्द करने

और भारतीय सेनाओं के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए आगे बढ़ा दिया जाय। भारतीय जनरल ने यह चेतावनी भी दी कि यदि 16 दिसम्बर को 9 बजे सुबह तक पाकिस्तानी सैनिकों ने युद्ध बंद करके आत्मसमर्पण नहीं किया तो हमारे जवान पूरे ताकत से अंतिम अभियान शुरू कर देंगे। अब तक तो गोलाबारी और बमबारी बंद करने की एकतरफी घोषणा भी कर दी गयी। ताकि आत्मसमर्पण की तयारियों को पूरा किया जा सके। पाकिस्तानी सैनिक अधिकारियों का यह आवास भी दिया गया कि जो पाकिस्तानी सैनिक और अफसर आत्मसमर्पण करेंगे उनके साथ जेनेवा समझौता के अनुसार अच्छा व्यवहार किया जायगा।

बमबारी बिराम अवधि की समाप्ति की घोषणा पर पड़ते तुरंत पाकिस्तानी सेनापति का कोई सन्देश प्राप्त नहीं हुआ। तब जब भारतीय सेना पूरे जोर से आक्रमण करने की तैयारी कर रही थी तो जनरल नियाजी ने छूटने का समय मांगा। इसी बीच किसी भारतीय दृष्टि अधिकारी को डाका भजन का अनुरोध किया ताकि वह उसके आत्मसमर्पण पत्र पर हस्ताक्षर कर सके।

16 दिसम्बर को उसी भयानक जनरल नियाजी ने भारतीय सेनापति का सामने आत्मसमर्पण पत्र पर हस्ताक्षर किये जिसमें मौ मीने पूर्व छात्रों की सेवा में नेता शेख मुजीबुर्रहमान ने बगालत का झण्डा बुन्द किया था। नियाजी ने आत्मसमर्पण के नियमों के अनुसार भारतीय जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने अपनी पिस्तौल रोपकर उसकी गोलीयाँ भारतीय सेनापति के हाथ में समा दी और हथियार डालने के प्रतीकस्वरूप अपने माथ की छुआ। उसी समय जनरल नियाजी गणवेश में सज हुए पद मूचक चिह्नों को उतार दिया गया। आत्मसमर्पण पत्र पर हस्ताक्षर करते समय नियाजी की आँखा में आँसू आ गये। दमनैतिक अंतिम व्यक्ति तब तक मरने का दावा करने के बाद जूद उ अपमानजनक स्थिति में हथियार डालने पड़े। बाद में इसलिये भी कि जगजीत सिंह अरोड़ा और नियाजी किसी जमान में 'दकठ सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। दा दावों बाद जब वह विजिता और विजित के रूप में आमने सामने सटे थे।

कुल 93 हजार पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। उन्हें बगला दंग में रसना खतरे से खाली नहीं था क्योंकि बगाली जनता बदला की भावना से प्रेरित होकर उनका सफाया ही कर सकती थी। अतः इन सारे पद्धतियों की बगला दंग से हटाकर भारत लाया गया।

एकतरफा युद्धविराम—भारत का उद्देश्य पाकिस्तानी जमीन पर अधिकार करना नहीं था और इसलिये जैसे ही बगला दंग स्वाधीन हुआ भारत ने पश्चिमी मोर्चे पर युद्धविराम की एकतरफा घोषणा करने का निश्चय किया। 16 दिसम्बर को रात पीने आठ बजे यह घोषणा कर दी गयी और तुरंत ही सयबुल राष्ट्रमण्डल की इसकी जूझना दे दी गयी। यह घोषणा उस समय हुई जब कि पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय

पश्चिमी मोर्चे पर भारत को युद्ध बंद करना ही था चाहे कोई दण्ड इसके लिए सजाहूँ देता था नहीं।

लेकिन अमेरिकी अधिकारी बराबर इस बात को दुहराते रहे कि उ होने सोवियन सघ म दबाव डनवाकर भारत को राका है कि वो समूचे पश्चिमी पाकिस्तान को छाम न करे। इस बात का निरंतर प्रसारित करने के दो उद्देश्य हो सकते थे—राष्ट्रपति निवस पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं और जनता को यह समझाने की कोशिश कर रहे होये कि भारत पाक युद्ध म अमरिका ने पाकिस्तान की भरपूर सहायता की। ऐसा कहकर भविष्य के लिए पाकिस्तान समुक्त राय अमरिका के बीच अधिक शत्रु सम्बन्ध स्थापित करने की समिका तयार की जा रही थी। इसीलिए इस बात पर जोर दिया जा रहा था कि पश्चिमी पाकिस्तान म प्रचारित हो कि भारत का उद्देश्य पाकिस्तान के अस्तित्व को ही मिटाना था। दूसरा उद्देश्य इसमें समयवत राय अमरिका के बौद्धिक और विचारघोस लोगों का निवसन की नीतियों के प्रति राय प्रकट करने से उत्पन्न प्रभाव को कम करना हो सकता है।

एकतरफा युद्ध विराम की घोषणा की कुछ क्षणों म की आलोचना हुई। आलोचना का कहना था कि भारत ने बिना अपने युद्ध उद्देश्यों का पूरा विषय ही युद्ध बंद करके सन्तुष्टी की है। उनके अनुसार पाकिस्तान को पूरी तरह बर्बाद कर देना तात्त्विक भविष्य म बड़े फिर कभी अपना सर नहीं उठा सके भारत का युद्ध उद्देश्य था। ऐसे स्थानी पुत्राय पत्रान वाला की निदधय हा और निराशा हुई। लेकिन एम सांगी की आलोचनाओं म कोई दम नहीं है। जा लोग यह चाहते थे कि भारत पाकिस्तान को समाप्त कर दे वे यह भल रहे थे कि आज के जमाने मे ये सम्भव नहीं है। युद्ध बंद कर देना सबपा उचित था क्योंकि इसका एकमात्र उद्देश्य—यगना देना। स्वायत्तता—पूरा हो उका था। फिर अंतर्राष्ट्रीय गतिविधि पर भी ध्यान रखना था। समयवत राष्ट्रमण म भारत की स्थिति बिगड़ रही थी। साधारण सभा ने 104 मतों से युद्ध विराम का प्रस्ताव पास कर दिया था जिसकी अवलोकन अधिक रिना तक नहीं की जा सकती था। मुरगा परिपद म भी भारत की स्थिति अत्यंत नाजुक थी। यदि सोवियन सघ ने वोटो का इस्तेमाल नहीं किया होता तो भारत कभी का नहीं रहता। यह वोटो चौबी या पांचवी बार भी इस्तेमाल होता इसकी कोई गारंटी नहीं थी क्योंकि शक्ति सन्तुलन की दृष्टि से सोवियन सघ भी पश्चिमी पाकिस्तान को पूर्ण सवादी की इजाजत नहीं देता। उधर अमरिका और चीन का रक्त भी कना होना जा रहा था। अमरिका का सातवी बेसा बंगाल की खाड़ी म पहुँच चका था। कुछ मिलाफर परिस्थिति गम्भीर होती जा रही थी। एसी जालत में युद्ध के मुख्य उद्देश्य की पूर्ति के बाद युद्ध विराम की घोषणा सभी दृष्टिवा से वादनीय थी। भारत सरकार ने ऐसा निणय करने अपूव इरादगिना का परिचय दिया।

युद्ध में पाकिस्तान की हार के कारण

भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध केवल चौदह दिनों तक चला। इन चौदह दिनों म केवल इतिहासही नहीं मगोन भाव लगया। 25 मार्च के पहले तक जो

पूर्वी पाकिस्तान या बङ्गलादेश में 16 दिसम्बर को पाकिस्ताना सना व आत्मसमर्पण के साथ ही दुनिया के नक्शे में एक स्वतंत्र राष्ट्र और एक अनन्य रूप के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। पाकिस्तान के लिए युद्ध बना ही महंगा सिद्ध हुआ। उस अनन्य देश के एक विशाल अणु—पूर्वी भू भाग से हाथ धोना पड़ा। उसके 93 हजार व लक्ष्मण सैनिक मुद्दबंदी बना दिये गए। पश्चिमी मार्च पर भी उसका एक बन्त बड़े भू भाग से हाथ धोना पड़ा जो भारतीय सना व कर्म में आ गया। इसके विपरीत भारत को क्षति नाम मात्र की रही।

युद्ध के पहले पाकिस्तान तयारी की पूर्णतः सकारात्मक भी कुछ प्रारंभ यह नहीं कह सकता था कि पाकिस्तान का ऐसा करारी हार होगी। लेकिन युद्ध के नतीजे ने इन गारा कथनाओं का विस्मरण किया। जब प्रश्न उठता है कि पाकिस्तान के पराभव के क्या कारण थे। सबसे प्रथम इसका एक कारण सैनिक या अथवा सैनिक दृष्टिकोण से पाकिस्तान भारत का मुकाबला नहीं कर सका और उसका भारी सामरिक नाति विफल हो गया। लेकिन उसके पराभव के कुछ मौखिक कारण भी थे।

कमजोर सैनिक पक्ष—पाकिस्तान की सामरिक स्थिति तो कमजोर सिद्ध ही हुई उसका सैनिक पक्ष भी बड़ा कमजोर था। बंगलादेश का बंगलादेशों ने मित्र नर दिया कि एक सच्चे जन आन्दोलन का कारण ना तानाशाही नहीं बल्कि सच्चा है। बंगला देश में भारतीय पाज का मुक्तिवाहिनी और जनता का पूरा समर्थन मिला। मार्च 1971 में ही पूर्वी बंगाल में जा जनजागरण हुआ उससे यह सिद्ध हो गया कि बंगला जनता जब पाकिस्तानी शोषण का बंगला नहीं कर सकता है। अतएव व अपनी स्वतंत्रता के लिए युद्ध कर रहा था और ऐसा भावना से प्रेरित होकर उन्होंने भारतीय सना की सहायता का था। जब पूर्व में पाकिस्तानी सना हार गयी और भारतीय सना ने प्रवेश किया तो बंगला जनता ने इसका स्वागत एक विजय के रूप में नहीं बरन सक्तिवाता के रूप में किया। भारतीय सना का उन्होंने मित्र वाहिनी का गना था।

दुर्गुण पाकिस्तान अपना ही गलतिया का जिम्मेदार था दिसम्बर 1970 में जब पाकिस्तान में प्रजातन्त्रीकरण का प्रक्रिया शुरू का गयी तो उसका गृह निष्पक्ष पर पक्षना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान का सैनिक तानाशाह ने निहित स्वार्थों के दबाव में पहलूर इस प्रक्रिया के बीच में ही राक किया। मुन्नीपुरमान का जिह्वा पाकिस्तान का प्रधान मंत्री बनाया जाना चाहिए था उन्हें जन में बन्त कर दिया गया। उस पर भी जब बंगला देश की जनता विद्रोह करती रही तो उन्हें बुरी तरह बुचला गया और व्यापक पैमाने पर नरसंहार किया गया। ऐसा स्थिति में अपने पूर्वी भाग पर पाकिस्तानी सरकार का शासन करने का कोई सन्धि अधिकार नहीं रह गया। जब इस प्रश्न को लेकर भारत के साथ उसका गठान हुआ तो उसमें उसका हारना अवश्यमावी था।

इससे प्रतिरिक्त पाकिस्तान की राजनीति पिछले पचास वर्षों में चल रही अस्थायी राजनीति रहा है जिस बिना समय पाकिस्तान के राजनीतिक पतन

को समझना कठिन है। यदि केवल एक वाक्य में पाकिस्तान के परामर्श की परिभाषा करनी हो तो कहना होगा कि पाकिस्तान के पास किसी भी युद्ध में विजयी होने के लिए सबसे जरूरी हथियार नहीं था। यह हथियार था अलोकतन्त्र। लोक समर्थन के अभाव में पाकिस्तान के फौजी शासकों के पास जो अमरीकी या चीनी हथियार थे उसमें पाकिस्तान अपनी सहाय्य बहुत दिनों तक नष्ट सकता था।

भौगोलिक स्थिति — पूर्वी मोर्चे के युद्ध में भगोश पाकिस्तान का सघन नहीं किया। पूर्वी ओर पश्चिमी पाकिस्तान में सक्का जिन्नीमीटर की दूरी थी। भारत का रणरत बंद हो जाने से पाकिस्तान बड़ा कुछक नहीं पहुँचा सकता था। पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी बंगाल पहुँचने का जलमय दो रास्ता बच गया था—ममन का रास्ता। लेकिन युद्ध शुरू होने पर भारतीय नौमना ने इस रास्ते की चेतावनी दे दी कर ली जिससे किसी तरह की आपूर्ति का होना बन्द हो गया। यही कारण है कि बंगला देश में पाकिस्तान को अत्यंत ही असमानजनक स्थिति में आत्मसमर्पण करना पड़ा।

भारत को हस्तक्षेप का मौका—बंगलादेश में घोर नरसंहार करके तथा जन आंदोलन को दबाकर पाकिस्तान तत्काल के लिए किसी तरह इस समावर्त में एक बरत पा सकता था यदि उसने भारत को हस्तक्षेप का मौका नहीं दिया होता। पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती यह हुई कि उसने लाता की सहाय्य में परणाधिया को भारा जाने का मौका दिया। इसके कारण भारत का पाकिस्तान के मामले में हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया। पाकिस्तान को शुरू में ही यह समझना चाहिए था कि भारत उसका घोर दुश्मन है और पाकिस्तान की किसी भी कमजोर स्थिति से अधिक में अधिक लाभ उठाने का प्रयास करेगा ठीक उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान भी भारत की किसी कमजोर स्थिति से लाभ उठाने से धाज नहीं आता। परणाधिया को भेजकर पाकिस्तान ने भारत को बंगला देश में हस्तक्षेप करने का अवसर दिया। पाकिस्तान की यह महान भूल थी जिसका बड़ा ही बड़ा फल उस चवाना पड़ा।

युद्ध का परिणाम

भारतीय विदेश नीति पर प्रभाव—भारत-पाक युद्ध ने भारतीय इतिहास और भगाल को ही परिवर्तित नहीं किया बरन भारत की विदेश नीति में भी एक परिवर्तन किया जिसका आमतौर पर स्वागत किया गया। अमरीका को लेकर भारतीय राजनीति में कुछ भ्रम था। युद्ध के पक्ष तक अमरीकी विदेश नीति बड़ा भ्रांति उत्पन्न करती रही कि जहाँ तक भारत का प्रश्न है वह उसकी लोकतांत्रिक परम्पराओं का आदर करता है। लेकिन बंगाल की छाड़ी की ओर अमरीका के सातवें बेटे के बीच करने के साथ ही भारत में अमरीकी हितों का दुग पुरी तरह ढह गया। भारत के सभी लोगों ने एक स्वर से अमरीकी विदेश नीति की निंदा की और उस लोकतन्त्र का शत्रु तथा फौजी शासन का मित्र बरार दिया।

एक ओर जहाँ भारत में अमरीका का विराध की नहर लगी वहीं दूसरी ओर सावियत संघ की हार्जन बनी। यह समूचे युद्ध के दौरान सावियत संघ ने जिस तरह

भारत और बंगला देश का साथ दिया उसका मराहना सर्वो न का। सुमुख राष्ट्रपति और सुरमा परिषद में युद्ध विराम तथा भारत-पाक युद्ध को लेकर जिन तरह का मतदान हुआ उससे उस बात का अंजा होता है कि भारत की विदेश-नीति एक नयी दिशा लगी। अब भारतीय विदेश नीति कागजात कायबाहियों पर आधारित न होकर भारतीय हितों पर आधारित होगी। भारत के हित जिन राष्ट्रों से जुड़े हैं भारतीय विदेश-नीति उन्हें राष्ट्रों से सम्बंध और मजबूत करेगी। अब भारतीय विदेश-नीति का निर्धारण इस आधार पर होगा—सावियत संघ पर वि. काय किया जा सकता है अमेरिका पर बिस्तृत विश्वास नहीं किया जा सकता है और चान से डरने की आवश्यकता नहीं है।

दक्षिण एशिया के सन्ततन पर प्रभाव — इस युद्ध में कबल पाकिस्तान ही पराजित नहीं हुआ बल्कि अमेरिका और चान के हौसलों और महत्वाकांक्षों की भी पराजय हुई। इन दोनों देशों के राजनीतिक हितों को यह सब प्रति पट्टा। अमेरिका के लिए एशिया में अब दूसरे पाकिस्तान के अलावे कोई ठौर नहीं रहा।¹ चान और अमेरिका को एशिया में एक ऐसा देश की जरूरत थी जो भारत के साथ युद्ध या युद्ध की स्थिति बनाये रखेगा। ऐसा देश केवल पाकिस्तान ही था। लेकिन उसका हट जाने से उस मनमूब पर पानी फिर गया। विशेषतया चीन के लिए यह एक बड़ा हार था। एशिया में सावियत संघ और चान दोनों अविभाजित पाकिस्तान पर अपना अपना प्रभाव बढाने का चपटा कर रहे थे। अब पुराने पाकिस्तान के इन दोनों हिस्से पर ठीक उसी तरह इन दोनों देशों की प्रतिद्वंद्विता नहीं चल सकती उस पहल चलती थी। बंगला देश पर सावियत संघ का ही प्रभाव रहेगा। चीन ने अपने राजनयिक गका से बुलाकर फिनहाल उस हादसे में नष्ट की घोषणा कर दी। दक्षिण एशिया में काबुल मुझा तक स्थितियों का राजनयिक सफलता में आशा तोत बढ़ि हुई जो चान के लिए पराजय थी।

अमेरिका और चीन म बूत बातों पर मतभेद हो सकता था। लेकिन एक बात पर वे एकमत थे। दोनों ही भारत का एक कमजोर राष्ट्र के रूप में दखना चाहते थे। दोनों ही यह चाहते थे कि भारत एक गतिशाली राष्ट्र के रूप में उभर कर नहीं आये क्योंकि ऐसा हान का मतलब एशिया के सन्ततन में परिवर्तन था। लेकिन हुआ यह जो कि नहीं चाहते थे। युद्ध के बाद अफगानिस्तान से लेकर मलयेशिया तक

1 The Pakistan military debacle in East Bengal is at the same time a diplomatic debacle for the United States. Futile last minute White House warnings to Moscow to restrain the Indians in their hour of victory and the provocative dispatch of carrier task force to the Bay of Bengal can neither conceal nor alleviate this disaster to American prestige and posture throughout the democratic world.

—The New York Times December 14 1971

कैल हुए भू भाग में भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर कर आया। अब तक भारत एक उल्लेख्य राष्ट्र रहा था। नेहरू के जीवनकाल में भारत एक नतिक सत्ता रही। 1960 तक उसने सत्तार में एक घाति ब्रिगेड की भूमिका अदा की। लेकिन 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध के बाद भारत की राजनीतिक सत्ता का पराभव हुआ। विश्व की स्थिति बदली और भारत की नतिक भूमिका लगभग समाप्त हो गयी। 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद यह स्पष्ट हो गया कि यदि भारत को सत्तार में महज नतिक भूमिका भी अंग करनी है तो इसके लिए अपनी सैनिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा वापस करनी होगी। 1971 के अंत में भारत को यह प्रतिष्ठा प्राप्त हुई और अब भारत सत्तार में एक बड़े राष्ट्र की भूमिका अच्छी तरह अंग कर सकता है। लेकिन महाशक्ति बन जाना भी कम खतरनाक नहीं है। एक बार महाशक्ति की भूमिका स्वीकार कर देने के बाद सम्बंधित राष्ट्र का भीत युद्ध में शामिल हो जाना स्वाभाविक हो जाता है। एक बार भीत युद्ध में शामिल होने के बाद सम्बंधित राष्ट्र एक ऐसी नियति चक्र में फंस जाता है जिसमें निबल पाना उसके लिए कठिन हो जाता है।

एक महाशक्ति के रूप में भारत के उभरने से पास पड़ोस के देश कुछ भयभीत अवश्य हुए। अतएव जरूरी था कि भारत छोटे राष्ट्रों के मन में भय की बजाय विश्वास पैदा करे। चीन की भूमिका के सम्बंध में बोलत हुए चाऊ-एन लाई ने कहा था कि उनका देश एक महाशक्ति की भूमिका अदा करना नहीं चाहता। वह छोटे राष्ट्रों का विश्वास प्राप्त करना चाहता है। चीन से भी अधिक्त भारत के लिए यह जरूरी था कि वह एंग्लो-देशों का विश्वास प्राप्त करे।

भारत की आंतरिक राजनीति पर प्रभाव—भारत पाकिस्तान युद्ध के समय यह पहला मौका था जब देश की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने अपने सभी मतभेदों को भुला दिया था तथा बंगला देश की आजादी का सवाल एक राष्ट्रीय सवाल बन गया था जिसने कि सभी पार्टियों के तारों का एक दूसरे से जोड़ दिया था। माच के बाद से ही लगभग सभी पार्टियाँ बंगला देश के प्रश्न को लेकर उन्मिक्त थीं। बंगला देश की आजादी का प्रश्न भारतीय जनता और भारतीय परम्परा के सर्वश्रेष्ठ अंगों का प्रतीक बन गया था। बंगला देश भारतीय सत्तार के लिए भी एक अंगि परीक्षा था। यदि भारतीय सत्तार और भारत सरकार ने बंगला देश के मुक्ति आंदोलन का समर्थन न किया होता तो वह भारत के उदात्त परम्पराओं के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात होता।

युद्ध ने भारत को एक सज्जितशाली राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदान किया। प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने युद्ध प्रयत्नों को जिस तरह सज्जित किया उसमें एक मयूख राजनतिक मया का पना चलता है। राष्ट्रपति ने उक्त भारत रत्न की उपाधि देकर उसको उचित मां दता दी। 1967 में चीनी युद्ध के दौरान लगभग सभी पार्टियाँ श्री नेहरू की आलोचना कर रही थी। इस युद्ध के ठाक नी वष के का सत्तार के सेट्टन होत में सभी पार्टियाँ श्रीमती गांधी का अभिनन्दन कर रही थीं। इस

युद्ध के पहले तक श्रीमती गांधी एक पार्टी की नेता थी लेकिन युद्धोपरांत उन्होंने स्वयं को समूचे राष्ट्र के नेता के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। 14 दिसम्बर की शाम को समाराह को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सत्ताधियों का भारत का एक ऐसा नेता मिला जा कि उस एक महान् देश के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए कृत सफल था।

युद्ध के कुछ ही दिनों का बाद भारत के राज्या की विधान मन्त्रालय के लिए चुनाव हुआ। केन्द्र में सत्तापक्ष कांग्रेस पार्टी को इसमें अप्रत्याशित सफलता मिली। यह चुनाव ऐसी परिस्थिति में हुआ जिसमें सत्तापक्ष दल ने अनधिक नाम के पुराने प्रयास किया और फायदा भी उठाया। उसने पाकिस्तान का पराजय से पुराना नाम उठाया और उसका सारा धन स्वयं के लिया। यद्यपि सम्पूर्ण देश में सगन्धि होकर पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध जीता था। सत्तापक्ष दल ने इन चुनावों में मुजीबुर्रहमन के व्यक्तित्व से नाम उठाया जो सर्वथा अनुचित था।

पाकिस्तान में संकट—भारत के साथ चौटह दिनों के युद्ध में बुरी तरह हारने के बाद पाकिस्तान में सैनिक शासकों के विरुद्ध रोष की लहर फैल गई और देश एक घोर संकट में फँस गया। जनता ने माहिया से इस्तीफा की मांग का जुलूस निकाला और उपद्रव किए। याह्या पर मुकदमा चलाने की बात की गई। उन पर सबसे बड़ा आरोप यह था कि उन्होंने भारत के साथ उस तरह युद्ध किया कि पाकिस्तान का हार का सामना करना पड़ा। ऐसा हालत से याह्या का पदत्याग करने पर हुआ। उनको जगह पर विपक्षी पार्टियों के नेता जुलफिकार अली भुट्टो राष्ट्रपति और माजिद ज़ाकिर प्रजासङ्घ नियुक्त किए गए।

भुट्टो को विरासत के रूप में एक खाखाना अर्थव्यवस्था मिली। राष्ट्र और होमलैप के काम मिली। देश में घोर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। बलुचिस्तान और सिन्ध का जनता पिछले दशकों में गिरावट कर रहा थी। युद्ध में पराजय के बाद उनके विरोध और मुखर तथा व्यक्त हो गया। पाकिस्तानी सैनिक 93 हजार जवान और अफसरों का युद्ध जीतने के बाद भारत में बंटा बना लिया था। नये शासन का जल्द से जल्द मुक्त बंगाल की विच्छिन्न समस्या थी। उस प्रकार सत्ता मुहम्मद हान भुट्टो के सामने कई विचित्र समस्याएँ थी जिनके समाधान के लिए पाकिस्तान में उदयन-मुखल शुरू हो गई और पाकिस्तान का संकट बड़ा गहरा हो गया। पाकिस्तान की विदेश-नीति पूरी तरह हतभ्रम हो गई। विभक्त जनमत विभक्त मन स्थिति और विभक्त नेतृत्व का पाकिस्तान नियति के चक्र में बुरी तरह फँस गया। युद्ध के जो कि स्वयं पाकिस्तान की सृष्टि था पाकिस्तान को और विभक्त कर दिया। पराजय ने पाकिस्तान के लिए सभी दरवाजों को बंद कर दिया।

युद्धोपरान्त पाकिस्तान

पाकिस्तान में संकट—भारत के साथ चौटह दिनों के युद्ध में बुरी तरह हार का खाने में सत्तापक्ष दल को लहर ने पाकिस्तान के सैनिक शासकों को अपने सत्ता में लाने दिया तथा देश का संकट में ला घेरना। देश में जनता और शासकों ने अपना भ्रम दूर हो जाने के बाद याह्या के इस्तीफा की मांग की और राजा

कानून तथा मानवता की पाबंदियों का खुलमधुन उल्लंघन करते हुए जुलूस निकाले और उपद्रव किये। प्रशासनकारियों ने ताड़ फोड़ की आग लगायी तथा दण्डम बाणिक संकट भी उत्पन्न हो गया। जनता ने याह्या खान विरोधी नारे लगाये और उन पर मुकदमा चलाने की बातें की जाने लगी। भूतपूर्व एयर मार्शल असगर खान ने यह सब की बिना याह्या और उनके बुद्ध जनरलों पर खुरी अमानत मुकद्दमा चलाया जाय क्योंकि उन्होंने विधान की भंग कर भारत के साथ इस तरह युद्ध किया कि पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा।

इस प्रकार याह्या की सत्ता के पराभव के आधार पर युद्ध विराम की घोषणा के तुरंत बाद ही मजूर आने लग। 19 दिसम्बर को रस्नामाबाद सचिव घोषणा की गयी कि राष्ट्रपति याह्या खान जनता के प्रतिनिधियों को सत्ता सौंपने के बाद अपना इस्तीफा दे देंगे। पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी के नेता जुनफिकार अली मुन्गी जो यूनाइटेड फ्रंट का नेता स्वयं बुलाया गया और 20 दिसम्बर 1971 को राष्ट्रपति तथा सैनिक कानून प्रशासक बना दिया गया। कहा गया कि मुन्गी पाकिस्तान की मौजूदा पार्टियों में सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं। इसलिए उन्हें सत्ता सौंपना लोकतंत्र का मान्यता देना है। पर यह गलत तक था। मुन्गी को पश्चिमी पाकिस्तान में उस समय बहुमत मिला था जबकि बंगला देश नहीं बना था और युद्ध में पाकिस्तान की पराजय नहीं हुई थी। यदि बंगला हुई स्थिति में नये सिरे में चुनाव होता तो उन्हें बहुमत नहीं मिलता।

जा भी हो मुन्गी को एक टूटा हुआ पाकिस्तान मिला और दूटे हुए राष्ट्र की अपनी समस्याएँ होती हैं। युद्ध में पराजित होने ही पाकिस्तान के भीतर परिवर्तन की प्रक्रिया आरम्भ हो गयी। बंगला देश की घटनाएँ तो एक सचमुच थी। इसका प्रभाव पाकिस्तान के अर्थ हिस्से पर भी पड़ा। पाकिस्तान के पञ्जाबी नेतृत्व के विरुद्ध बलुचिस्तान और सिन्ध की जनता पिछले बीस वर्षों से लगातार अपना विरोध और असंतोष व्यक्त कर रही थी। युद्ध में पराजय के बाद यह विरोध और मुखर तथा व्यापक हो गया। मानव त्रुटि होने के लिए संविधान बनाने तथा प्रांतों में लोकप्रिय सरकारों के गठन के लिए समये पाकिस्तान में आन्दोलन ने भयंकर रूप धारण कर लिया।

राष्ट्रपति के रूप में मुन्गी ने बहुत सारे काम किये। बंगलादेश की पुनः पाकिस्तान का अंग बनाने से नकार कर तब तक आन्धी की सुसहान बनाने उसे नागरिक अधिकार दन और दण्ड को गिराकर स्वायत्तम्बी तथा प्रतिपालों बनाने तक की बहुत सी बातें कहीं। उन्होंने सैनिक कमाइनों की मरम्मत की उद्योगपतियों के निष्ठा की ओर पुलिस पर इल्जाम लगाया। बाद में पराजय के त्रिजे निम्नवार कमण्डला को सेवामुक्त किया और उद्योगपतियों के पारपत्र जप्त करने का आदेश दिया। सैनिक गवर्नरों को हटाकर चार प्रांतों में सैनिक गवर्नरों की नियुक्ति की। पाकिस्तान की पराजय और उससे निष्पन्न विम्वेदार सेनाधिकारियों के लिखाप जाँच आरोप का गन्त किया गया। एक अन्य आदेश के द्वारा सभी जमानतवादी के विदेशगमन को रोक दिया गया। इनके अतिरिक्त मुन्गी ने उन बार्ड परिवारों के पारपत्र भी रद्द कर दिये जिन्हें पास कून मिलाकर पाँच अरब रुपये की पजी थी। मुन्गी ने कहे हैं कि मैं एताद किया कि उन परिवारों के धिन्नाप काम उठाये जायेंगे जो देश से पैसा बाहर ला वि रा — 27

भेजेगे। उन्होंने मांग की कि जिस घनराशि को व विशेषों में रखे हुए हैं उन्हें व उन निश्चित अवधि तक वापस ल आवें। मुझे ने यह भी घमकी दी कि अगर ओद्योगिक और कृषि उत्पादन में मुद्धार नहीं हुआ तो व उनका राष्ट्रीयकरण कर देंगे। पाकिस्तान में पिछले कई वर्षों से अनियमित के अधिभार पर प्रतिबंध था। मुझे ने सत्ता में आते ही इस तरह के प्रतिबंध का काफ़ी हट कर हटा दिया। पाकिस्तान का भ्रष्टाचार से मुक्त करने के उद्देश्य से 1200 सरकारी अधिकारियों का अनिवार्य अवकाश प्राप्त कराया गया।

संविधानमय राष्ट्रपति का एक ही साथ अनेक समस्याओं में धर दिया। जनतावादी पार्टी मुस्लिम जाग आदि पार्टियों ने एक स्वर में यह मांग शुरू कर दी कि पाकिस्तान से मांगें हटाया जाय राष्ट्रीय अनुसूचितों का अधिभार कम किया जाय अन्तिम संविधान तैयार किया जाय तथा पम्पनों और बलूच का स्वतंत्रता दत्त हुए स्वातंत्र्य का बहाना किया जाय। इन पार्टियों ने राष्ट्रपति का खुली चुनौती दी कि दलुचिस्तान और सीमांत प्रदेय में तुरंत नाकप्रिय शासन प्रथम किया जाय। जनतावादी पार्टी के नेता खान अबुल कलाम खान ने ता मुनकर कह दिया कि यदि मुझे अस्मिताओं का अधिवेशन नहीं बुलाते तो वह कुछ दलुचिस्तान और पम्पनिलान की अस्मिताओं का अधिवेशन बुलाने सम्मति आदेश जारी करें। वही खान ने वना देश का मा पता देने की भी सलाह दी। इस तरह अन्तर्गत तौर पर परेमाना काफी बनी हुई थी।

सत्ता में आते ही मुझे का औद्योगिक दलों तथा विद्यार्थी आन्दोलनों का भी सामना करना पड़ा। पश्चिमी सीमांत की प्रिंसिपल में भी अड्डाल कर दी।

उसके अनिर्वरित सबसे प्रमुख समस्या—पट्टापरत भारत से जाति संघर्ष की बात थी। भारत ने परिचामी पाकिस्तान के बहुत बड़े इलाक़ों का जीनकर हम पर आधिपत्य कायम कर लिया था। इन इलाक़ों के नागरिक भाग चले थे। इन शरणार्थियों के पुनर्वास की व्यवस्था करनी थी तथा भारतीय आधिपत्य पर पाकिस्तानी इलाक़ों का पुनर्वास था। लगभग 93 हजार पट्टापरत भारत में बंद थे। उनकी वापसी एक ऐसी बिकट समस्या थी जिस यथाशीघ्र मुनत्राय बिना राष्ट्रपति मुने न तो पाकिस्तानी जनता के आन्दोलन छूट कर सकतथ और न अपना साथ ही जमा सकतथ। संविधानमय दलों का मामला बड़ा हा उनका हला था। बंगला देश की सरकार ने कहा था कि नगर हत्याओं के लिए जिम्मेवार पाकिस्तानी मुनियों के विरुद्ध कानूनी कारवाय की जायगी। इस सम्मति में बंगला देश के साथ सम्पादन करने के लिए भारत सरकार बचनबद्ध थी।

एक अन्य समस्या बंगला देश के तथाकथित बिहारी मुसलमानों सम्मरद्ध थी। पूर्व पाकिस्तान के गर बंगला नागरिकों ने पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ सहयोग किया था। बंगला देश का स्थापना के बाद बंगाली नागरिकों ने उनसे बंगला उना शुरू किया और कुछ नये पम्पन हुए। ऐसे भी बंगला देश में उनका टिका रहता बढित था। पाकिस्तान के समस्त समस्या यह थी कि नाखों की मध्या में इन पाकिस्तानी नागरिकों का क्या किया जाय। एक मुद्दा यह भी था कि उन्हें पाकिस्तान बुलाकर वहाँ बसा दिया जाय क्योंकि पाकिस्तान में रह रहे बंगाली आबादी के साथ उनका अन्तर्गत करनी जाय। संविधान यह समाधान भी उन्निहारा स मरा पड़ा था।

बंगला देश के प्रति दृष्टिकोण—राष्ट्रपति मुझे के लिए बंगला देश की

वास्तविकता का स्वीकार करना भी एक कठिन काम था। राष्ट्रपति का पत्र सम्हालते ही श्री मुट्टो ने कहा था 'पूर्व बंगाल पाकिस्तान का एक अंग है हम उसे हर तरह की सहायता देंगे। हम यहाँ के नेताओं से बातचीत करने को तयार हैं वगैरह कि भारतीय सेना वहाँ से हट जाय। उसी रात उन्होंने यह भी बताया कि गद्य मुजीबुरं हमान को जेल में हटाकर एक मकान में लाया गया है। भट्टो मुजीब से इस बीच दो बार मिले और इस बात का जो ठोस प्रयास किया कि किसी भी गत पर सब पूर्व बंगाल को पाकिस्तान में ही बनाये रखे।

8 जनवरी को नैसमुजीब को रिहा कर दिया गया। भट्टो ने कहा कि गद्य को इसलिए छोड़ा जा रहा है कि वह भारतीय सैनिकों को पूर्व बंगाल से हटावे और सारी स्थिति को अपने हाथ में ले। लेकिन 10 जनवरी को दिल्ली में गद्य ने घोषित कर दिया कि पाकिस्तान के साथ बंगला दश का सम्बंध हमारा हमारा क लिए समाप्त हो गया है। इस बात का उन्होंने अपने बाद के कई अर्थ भाषणों में दुहराया। लेकिन इसका बावजूद भट्टो को यह आशा थी कि गद्य मुजीब से उनके बहतर सम्बंध हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि चाहे तो सब पूरे पाकिस्तान के राष्ट्रपति या प्रधान मंत्री बन सकते हैं। पाकिस्तान की एकता के लिए रास्ता में नही आयेगा। उन्होंने पुरानी बातों को बलवान भी अपील की। लेकिन इसका कोई असर नही हुआ।

भट्टो को सब के आचरण से निश्चय हो गया कि दुख हुआ होगा। उन्होंने ससार के राष्ट्रों को चेतावनी दी कि वे बंगला देश को राजनयिक मायता देने में ज़रूरता न करें। लेकिन उनकी इस अशील का भी कोई परिणाम नही निकला। प्रारम्भ में पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों ने बंगला दश को मायता दी। इस पर भट्टो ने उनके साथ अपना कटनीतिक सम्बंध विच्छेद कर दिया। जब राष्ट्रमण्डल के कुछ राष्ट्रों ने बंगला दश का मायता प्रस्ताव की तो पाकिस्तान राष्ट्रमण्डल से भी अलग हो गया। लेकिन मायता देनेवाले सभी राष्ट्रों के साथ राजनयिक सम्बंध तोड़ने का अभियान राष्ट्रपति भट्टो बरकरार नही रख सके क्योंकि मायता उन्नी जल्दी मिलने लगी और पाकिस्तान सभी देशों के साथ अपना सम्बंध विच्छेद नही कर सकता था।

बिदेन नीति—मुद्द के बाद बिदेन नीति के सम्बंध में राष्ट्रपति भट्टो की ओर घोषणाएँ हुईं उनमें सबप्रथम उन्होंने समुक्त राज्य अमेरिका जनवादी चीन तथा कुछ अरब राष्ट्रों के प्रति पाकिस्तान की कृतज्ञता का ज्ञापन किया जिनसे मुद्द के समय थोड़ी बहुत मौलिक या वास्तविक सहायता मिली थी। अमेरिका के सम्बंध में उन्होंने कहा कि उसके साथ पाकिस्तान का पड़नेजसा हो मधुर सम्बंध बना रहेगा। फरवरी 1972 के प्रारम्भ में राष्ट्रपति ने चीन की यात्रा की और चीनी नेताओं से आधिकारिक एवं सैनिक सहायता का आश्वासन प्राप्त किया। सभी बीच सोवियत संघ से भी उन्होंने सम्बंध सुधारने का यत्न किया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति इस समय को भली भाँति जानते थे कि सोवियत संघ के अनादे कीर्ति ऐसी ताबत नही है जो भारत और बंगला देश से कोई बात मतवा सके। इसीलिए उन्होंने बंगला देश को मायता देने पर भी सोवियत संघ से सम्बंध विच्छेद नही किया। 17 मार्च को राष्ट्रपति भट्टो सोवियत संघ गये और सोवियत नेताओं से उपमहादीप की स्थिति पर विचार विमर्श किया। इस वार्ता के दौरान सोवियत प्रधान मंत्री श्री बोसिजिन ने भारतीय उपमहादीप का समस्या का परस्पर बातचीत द्वारा सीधा समाधान ढूँढ़ने पर बल दिया। बोसिजिन ने यह भी सलाह दी कि वे उपमहादीप की समस्याओं को समझाने में

यथाय दृष्टिकोण अपनावें। सोवियत प्रधान मन्त्री ने यह भी कहा कि—समय के बदले शांति एवं सहयोगकी नीति पर चलने के सिवा त्विनि सुधारने का कोई दूसरा यावसगत रास्ता नहीं है। श्री मुट्टो ने अपने उत्तर में कहा कि वह यहाँ बात सम्झौते लेकर आये हैं और समझते हैं कि वे समस्याएँ हल हो सकती जा उपमहाद्वीप के लोगों को विरासत में मिली हैं तथा जिससे आगे शांति का माग प्रशस्त हो सकेगा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोग उनिन के देश के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाये रखना चाहते हैं। उन्होंने सोवियत नेताओं का यह भी आश्वासन दिया कि पाकिस्तान भारत के मित्राफ गत्र तापूण प्रचोर बंद कर दगा।

भारत के साथ सम्बन्ध—युद्ध के पहले और युद्ध के समय मुट्टो ने कई बार कहा था कि पाकिस्तान भारत के साथ हजार वर्ष तक युद्ध करता रहगा। लेकिन युद्ध में अपमानजनक पराजय के बाद जब मुट्टो ने राष्ट्रपति का पद सम्हाला तो उन्होंने एक समझौतावाणी दृष्टिकोण अपनाया। भारत के सम्बन्ध में बोलते हुए कई अवसरों पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक गरीब देश है। उस अपने पडासियों के साथ सह्यस्तित्व के आधार पर रहने की सबकु सोचनी चाहिए। उन्होंने वाद में फिर कहा कि भारत के विरुद्ध पुन युद्ध की तयारी में जुटकर पाकिस्तान सिवा पराजय के और कुछ हासिल नहीं कर सकता। भारत के साथ सहयोग करके ही पाकिस्तान अपनी विकट समस्याओं से छुटकारा पा सकता है।

इसके बाद भारतीय पत्रकारों से श्री मुट्टो ने मुलाकात की। भारत के कुछ चुने हुए पत्रकारों को पाकिस्तान जाना वह भी ऐसे समय में जबकि दोनों देशों के बीच सम्बन्ध टूट चके थे सुखद आश्चर्य था। 15 मार्च 1972 को टाइम्स आफ इंडिया और स्टेट्समैन के प्रतिनिधियों से बातें करते हुए राष्ट्रपति मुट्टो ने कहा कि वे भारतीय प्रधान मन्त्री से यथासम्भव गीघ्र मिलने के लिए उत्सुक हैं। वह भारत और पाकिस्तान की समस्याओं को बातचीत से हल करना चाहते हैं। कश्मीर पर भारत के साथ पाकिस्तान के मौलिक झगड़े के बारे में उन्होंने कुछ नये विचार रखे। उनका कहना था कि कश्मीरियों का आत्मनिर्णय का अधिकार दिलाना पाकिस्तान का काम नहीं है। इस अधिकार के लिए उठना कश्मीरियों का अपना काम है। श्री मुट्टो का विचार यह था कि उसे फातिन का निर्णय नहीं किया जा सकता वैसे ही आत्मनिर्णय के दुनियादी समय की प्रेरणा बाहर से नहीं दी जा सकती। भारत और पाकिस्तान 1947 से अब तक चार युद्ध कर चुके हैं लेकिन सन्निवत पर पाकिस्तान इस समस्या का समाधान करने में विफल रहा है और भारत भी कभी सतोपजनक राजनीतिक हल नहीं निकाल सका।

राष्ट्रपति मुट्टो के इन विचारों से ऐसा प्रतीत हुआ कि वह कश्मीर से पाकिस्तान की दृष्टि हटाने की तयारी कर रहे हैं और वह यह भी मानते हैं कि उपमहाद्वीप के स्थिति मजतून में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है।

भारतीय पत्रकारों से बातचीत करते हुए राष्ट्रपति मुट्टो ने पाकिस्तानी मुद्दों पर भी सवाल का मा उठाया। उस प्रश्न पर बोलते हुए अधार्य। उन्होंने कहा कि मानवा सदन में पाकिस्तान के लिए सबसे महत्वपूर्ण समस्या प्यदासियों की बावली है। मुद्दों का समाधान के मानना रूप में के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत का यह क्या कि मुद्दों का रिहाई में गगना में विचार विमर्श करना अन्याय है मान है। गगना देन में जा कुछ हुआ यह कवन सुनिवाहिनी द्वारा नहीं हुआ। भारत स्वयं इस पर काम फमला से सकता है। लेकिन यदि

अपने पाकिस्तान को बनाने के लिए बंदियों का इस्तेमाल किया तो मेरे पास केवल दो विकल्प होंगे या तो मैं मान जाऊँ और कश्मीर में अथवा अथवा जो भी रक्षा आप खींचना चाहें भय ही वह बाह्य से अथवा इससे भी पश्चिम से गुजरती हो उसे स्वीकार कर लूँ अथवा मैं अपनी जनता को बता दूँ कि समय के अभाव में कोई विकल्प नहीं।

इसके तुरंत बाद श्री भट्टो सोवियत सभ गये। तीन दिनों की सोवियत सभ की यात्रा के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में शांतिपूर्ण वातावरण बनाये रखने विनम्र प्रश्न पर नियंत्रण करने और बिना शर्त भारत और बगला देण से सभ शीते की पक्ष की प्रबल इच्छा प्रकट करने के बाद स्वदेश लौटते ही राष्ट्रपति भट्टो ने एक सावजनिक सभा में पुनः भारत के विरुद्ध कश्मीर को न भुलाने के अलावा और भी कुछ कहना बात कहा। वस्तुतः पाकिस्तान से यह उम्मीद करना कि वह कश्मीर में जनमत संग्रह की बात छोड़ देगा "यादती होगी। कारण कश्मीर का मामला द्विपक्षीय सिद्धांत का विस्तार है और इस सिद्धांत का सहारा छूट जाय तो पाकिस्तान का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जायगा।

पाकिस्तान के हक में यही बात अच्छी थी कि राष्ट्रपति भट्टो जनरल याह्या को सैनिक नीति की छोड़कर शांति बनाये रखने की नीति का अनुसरण कर अपने देश की जनता की सुझावों पर सबसे अधिक ध्यान देंगे। पाकिस्तान के नये राष्ट्रपति के समक्ष अब दो ही विकल्प थे—एक तो यह कि वे भारत के प्रति अपने विस्फोटक रवये को कायम रखें जोड़ तोड़ द्वारा विरुद्ध से हथियार प्राप्त करें और लोगों के जीवन-मृत्यु की विषय विषय सारा पसा हथियारों के खरीद भुगतान के और भारत से भिड़ जाय। लेकिन इस तरह का रवया पातक हुआ। पाकिस्तान की आह्वान कि वह वास्तविकता से सम्मोहित करें और भारत तथा बगला देण से पत्री सम्बंध स्थापित करके उपमहाद्वीप में व्याप्त गुरुत्व और बेरोजगारी जैसे सामाजिक खतरों पर विजय प्राप्त करें।

सजिन प्र न यह था कि क्या राष्ट्रपति भट्टो ऐसा कर में समर्थ हो सकेंगे? भट्टो सत्ता के उन दिने राजनयियों में से हैं जो सत्ता प्राप्त करने या उसे बनाये रखने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। कटोरता सखीयता और कठोरपन के मामले में वे पाकिस्तान के किसी भी जनरल से एक कदम आगे हैं। उनका भारत विरुद्ध पाकिस्तान के किसी भी राजनयिता से अधिक है। पाकिस्तान की जनता एकबार यह स्वीकार कर सकती है कि भारत सबकुछ ही उसका दुश्मन नहीं है। सजिन हजार वर्ष तक भारत। लड़ाई लड़ने की घमभी दनवान नेता भट्टो के मन में कभी यह बात नहीं उतर सकती। दरअसल भारत के विरुद्ध जहाद के अलावा उनका पास कोई नारा है भी नहीं। उन भट्टो को पाकिस्तान का प्रशासन बनाना पाकिस्तान का दूरी हुई सखीय के लिए और भी बड़ा अवशकन है। ऐसे मुजोब के पास आर्थिक और सामाजिक कायम नहीं। पर भी वे पास ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। पाकिस्तान की जनता को भारत विरुद्ध की अनीम दिलाकर ही अपनी सत्ता को बनाये रख सकता है।

यद्यपि भारत पाकिस्तान सम्बंध

बगला देण के उद्यम के बाद भारत पाकिस्तान सम्बंध खराब बेहत मात्र निपटीय नहीं रह सक्ता था जबतक कि ताना मजुहे मादक निपट न आते। भारत साथ प्रमुख समस्या मुद्द के बाद शांति समझौता की थी। इसमें मुद्दबन्दियों का

प्रश्न सबसे जटिल था। 92 हजार पाकिस्तानी युद्धबंदियों की रिहाई के लिए राष्ट्रपति मुट्टो ने मानवता के नाम पर भारत से कई बार अपील की। उन्होंने कहा कि इस प्रश्न पर भारत को उदारता का प्रदर्शन करना चाहिए। लेकिन भारत में ऐसा लोगों की कमी नहीं थी जो सख्त रुढ़ि के समर्थक थे। उनका कहना था कि ऐसा करना गलत होगा। आज थी भट्टो का युद्धबंदियों तथा खाई हुई भूमि को वापस लाना है तो वे झुककर बातें कर रहे हैं। चार छ वष बाद वे फिर सलवारने लगे।

युद्धबंदियों की रिहाई का मामला उतना आसान नहीं था जितना भट्टो समझते थे। पश्चिमी क्षत्र के दक्षिण की रिहाई में तो विघ्न कठिनाई नहीं थी लेकिन पूर्वी क्षत्र के युद्धबंदियों का मामला उन्ना हुआ था। प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी के वगला दश की यात्रा के दौरान जा संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गयी थी उसमें स्पष्टतया यह उल्लेख किया गया था कि नृसम हत्याओं के लिए जिम्मेदार पाकिस्तानी सैनिकों के विरुद्ध वगला दश का सरकार जा कानून कारवां करेगी उसमें भारत पूरा सहयोग देगा। इस दृष्टिकोण से युद्धबंदियों की वापसी वगला दश की सहमति के बिना नहीं की जा सकती थी।

राष्ट्रपति मुट्टो बार-बार यह कहते थे कि युद्धबंदियों के प्रश्न का मानव अधिकार से दृष्टि आये तथा एक वापस शांति समझौते के साथ इसको नहीं जोना जाय। उनका अनुरोध था कि युद्धबंदियों का घोषातिघाघ्न वापस कर दिया जाय। लेकिन भारत सरकार का कहना था कि अन्तिम शांति-समझौता से अलग करके इस प्रश्न को देखा जा सकता है। युद्धबंदियों का वापसी पूरे शांति समझौते का एक भाग होगा।

शांति समझौता से सम्बन्धित एक दूसरी कठिनाई कश्मीर में युद्धविराम रेखा थी। युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने कश्मीर में युद्ध विराम रेखा की पीर करके उसके एक बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया था। भारतीय नेताओं ने कह दिया था कि इस बार ताशकंद समझौते जसी काइ चीज नहीं होगी। कश्मीर में युद्ध विराम रेखा समाप्त हो गयी है। अंतराष्ट्रीय सीमा रेखा और युद्धविराम रेखा में अंतर होता है। युद्धविराम रेखा हर युद्ध के बाद बदल जाती है। कश्मीर में सीमा रेखा विद्वन्वी युद्धविराम रेखा ताशकंद समझौते का परिणाम था। जब जब कि पाकिस्तान ने उस समझौते का उल्लंघन करके भारत पर आक्रमण कर लिया तो वह युद्धविराम रेखा भी समाप्त हो गयी।

मरी बार्ता—इन सारी कठिनाइयों के बावजूद युद्धोपरांत शांति-समझौते की प्रक्रिया शुरू करने का बात दोनों देशों में चलन लगी। यह निश्चित हुआ कि भारत और पाकिस्तान के नासनाथों का एक शिखर सम्मेलन आयोजित हो। मिद्वान के रूप में यह बात मान ली गयी और शिखर सम्मेलन का तयारी के लिए भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच अगस्त 1972 में एक उच्चस्तरीय बार्ता मरी में हुई जिसमें निश्चय किया गया कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति और भारत की प्रधान मंत्री दोनों के पारस्परिक सम्बन्धों की बातों पर विचार विमर्श करने के लिए अगस्त 1972 में मिलेंगे।

शिखर सम्मेलन—इस निश्चय के अनुसार 28 जून 1972 का भारत का प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति का शिखर सम्मेलन शिमला में आरम्भ हुआ और 3 जुलाई को नाटकीय ढंग से दोनों देशों के बीच एक समझौता हो गया। इस समझौते के महत्वपूर्ण अंश ये हैं—

1 भारत व पाकिस्तान की सरकारों का सब व है कि वे दोनों दलों के बीच अब तक चल आ रहे मनमुटाव और विवादों को सम्भलकरके पारस्परिक मनी पूरा सम्बन्ध व उपमहाद्वीप में स्थायी शांति का स्थापना के निम्न काम करेंगी ताकि दोनों देश अपने-आपमें एवं गाँवों का उपयोग अपना जनता के हित में कर सकें।

इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत व पाकिस्तान की सरकारें इन बातों पर सहमत हैं कि

(क) दोनों देशों का सब व है कि वे अपने मतभेदों को द्वितीय धारा द्वारा शांतिपूर्ण उपायों से या ऐसे शांतिपूर्ण उपायों से जिनसे बार में दोनों देशों के बीच सहमति हो गयी हो हल करेंगे। जबकि दोनों देशों की समस्या का अंतिम हल न निकल आये तो भी एक पक्ष यदि को नहीं बलगा और दोनों देश इस बात का प्रयास करेंगे कि ऐसा कोई काम न हो जिससे शांतिपूर्ण सम्बन्धों का क्षति पहुँचे।

(ख) समुक्त राष्ट्र मध्य घेराव के अनुसार दोनों देश एक दूसरे के विरुद्ध बल प्रयोग नहीं करेंगे तथा एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण तथा राजनयिक स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

2 दोनों ही सरकारें अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक दूसरे के प्रति घृणित प्रचार नही करेंगी। दोनों राष्ट्र उन सभी समचारों को प्रोत्साहन देंगे जिनके माध्यम से आपसी सम्बन्धों में सुधार की आशा हो।

3 आपसी सम्बन्धों में सामान्यता तान की दृष्टि से (क) दोनों देशों के बीच डाक मार्ग रोका गया जल, रेल, वायुमार्गों द्वारा पुनः संचार व्यवस्था स्थापित की जायगी। (ख) एक दूसरे देश के नागरिकों और निवृत्त आये इतिहास नागरिकों को आने जाने की सुविधा दी जायगी। (ग) जहाँ तक सम्भव हो सके व्यापारिक एवं आर्थिक मन्तव्यों में सहयोग का मिलजुल जल्द से शुरू हो। (घ) विज्ञान एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में आपसी प्रज्ञान बढ़ाया जायगा।

4 स्थायी शांति कायम करने की प्रक्रिया का मिलजुल आरम्भ करने के लिए दोनों सरकारें सहमत हैं कि (क) भारतीय और पाकिस्तानी सेनाएँ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में रीट जायगी। (ख) दोनों देश बिना एक दूसरे की स्थिति को क्षति पहुँचाये जम्मू के मोर में 7 दिसम्बर 1971 का हुए युद्ध विराम के पत्रस्वरूप नियंत्रण रेखा को मान्य रखेंगे। (ग) सेनाओं की आपसी संपर्कों के माध्यम से दो सप्ताह के भीतर पूरी हो जायगी।

5 दोनों देशों की सरकारें इस बात पर सहमत हैं कि उनके राष्ट्राध्यक्षों की मध्यस्थता के बिना ही दोनों देशों के बीच पर होगी जो दोनों देशों के लिए सुविधाजनक हो। इस बीच दोनों देशों के प्रतिनिधि स्थायी शांति की स्थापना और सम्बन्धों का सामान्य करने के लिए आवश्यक प्रयत्नों के बारे में विचार विमर्श करें। इनमें युद्ध रोकना एवं नागरिकों की वापसी जम्मू-काश्मीर के अंतिम हल के राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने के प्रश्न शामिल हैं।

भारत पाकिस्तान युद्ध के लगभग सात महीने बाद शिपला में श्रीमता इन्दिरा गाँधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति भुट्टो ने यह समझौता करके इस उपमहाद्वीप में एक नया युग का सूत्रपात कराया। यदि दोनों देश सही अवसर में इस समझौता की लागू करेंगे तो उनके सम्बन्धों का इतिहास ही बल्लू आ सकता है और वे बीच-बीच में

से चला आ रहा प्यड़ा सचमुच ही सम्पन्न हो जा सकता है। समझात की भाँति और उनके पाँदों की भाँति की देखकर यह नहीं माना जा सकता कि किसी एक न नव वृद्ध हो गया और किसी ने सब कुछ पा लिया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति भट्टो ने इस समझात का दोनों देशों का विजय कहा था और मुल्ताना का स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं माना चाहिए।

इस समझात की सबसे प्रमुख बात यह थी कि पाकिस्तान ने पानी के भारत के साथ एक बनावटपूर्ण संधि की। समझात में कहा गया है कि दोनों देश एक दूसरे की क्षत्रीय अस्मिता या राशनल स्वतंत्रता के हितों के लिए प्रयोग की शक्ति के लिए और न हथियारों का प्रयोग करें। संधि पर हस्ताक्षर के तुरंत बाद पाकिस्तानी विदेश विभाग ने प्रवक्तों ने समझात को माना कि संधि का यह भाग बनावटपूर्ण संधि ही है।

समझात का दूसरा महत्वपूर्ण अंग यह है कि दोनों देशों ने यह निश्चय किया कि वे अब तक पण्डों का संधि के लिए बन्त करके अपने समान मनुष्यों के लिए निष्पक्षीय बान्धन या अन्य भाव गतिपूर्ण तरीकों में हल करने और बिना समझात का अन्तिम फैसला होने तक अन्तराष्ट्रीय दारवाज में स्थिति को नहीं बदलेंगे।

यह भारत की एक बड़ी सफलता है। भारत सरकार संधि में यह कहती रही है कि वह पाकिस्तान के साथ सभी विवादों का शांतिपूर्ण तरीकों से हल करना चाहती है और किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करती। संधि में दोनों देशों के बीच विवादों में ही ना सामग्री गति को हल का बात नहीं कही गयी।

यह नहीं मूल जाना चाहिए कि भारत सरकार से ही पाकिस्तान के समझात यह प्रभाव रखता रहा है कि दोनों देश बनावटपूर्ण संधि करके सभी देशों के शान्तिपूर्ण तरीकों से हल करने का निश्चय करें। लेकिन श्री नियावत अला से लेकर अन्तराष्ट्रीय याहू खाँ तक पाकिस्तान के कपटकार बनावटपूर्ण संधि का अस्वाभाविक करके यह कहते रहे कि जब तक कश्मीर का हल नहीं हो जाता तब तक वे नियावतों के प्रयोग के अपने अधिकार का नहीं छोड़ सकते। लेकिन अब श्री भट्टो ने पाकिस्तानी नेताओं की इस परम्परा को तोड़ा दिया।

हिमालय समझात का तीसरा पहलू है दोनों देशों में सामान्य भावना कायम करना। इसके लिए समझात में चार कदम प्रदान किए गए हैं। पहला कदम यह है कि दोनों देशों में शांति और स्थिरता के लिए समझात कायम किया जाएगा। सीमा की चौकियाँ शांति जायगी और हथियार बान्धन कायम रहे। दूसरा कदम यह है कि दोनों देशों की जायगी। तीसरा कदम नागरिकों का यात्रा की सुविधाएँ देना है। चारथा कदम है कि दोनों देशों के व्यापारिक संबंध कायम करना तथा चौथा कदम हीना वैज्ञानिक और सांस्कृतिक अन्तर्गत प्रदान। इन कदमों के लिए आवश्यक विवरण दोनों देशों के प्रतिनिधि तय करेंगे।

दोनों देशों के सम्बंध सामान्य बनाने के लिए भारत सरकार संधि में ही ध्यान दे रही है। ताकि सामान्य भावना में भाव सम्बंध सामान्य करने का ध्यान भी लेकिन भारत ने ही एकतरफा कदम उठाया है और पाकिस्तान ने इस संधि में बाद भी कदम प्रदान सरकार न किया था।

हिमालय समझात का चौथा और महत्वपूर्ण भाग यह है कि दोनों देशों के बीच सीमा के पार से अपनी बनाए समझात के पृष्ठभूमि के अन्तर्गत प्रदान के बाद

तीस दिन में वापस कर देंगे। इसका अर्थ यह है कि भारत को पाकिस्तानी पनाब और सिंध के उस क्षेत्र से अपनी सेनाएं हटानी होंगी जिस पर 1971 दिसम्बर के युद्ध में भारतीय सेना ने अधिकार किया था जब कि पाकिस्तान को केवल 69 बगमील के भारतीय क्षेत्र से ही अपनी सेनाएं हटानी होंगी।

समझौते के इस भाग की कुछ शर्तों में आजाचना की गयी और कहा गया कि भारत ने पाकिस्तानी क्षेत्र से अपनी सेनाएं हटाने का समझौता करके बम्बोर पर पाकिस्तान से सौदगाना बनाने का मौका छोड़ रहा है। ऐसा कहनेवाले यह भी कहते हैं कि ऐसी ही गन्ती भारत ने तागकदम की थी।

ग्रेविटि गम्पों को समझने से ऐसा आरोप गन्त सिद्ध हो जात है। पहले तो तागकदम और गिमला समझौते का समय बड़ा एक यह है कि तागकदम समझौते में भारत ने जम्मू के मोर के उन भागों में भी सेनाएं हटाने की बात मान ली थी जिन पर हमारे जवानों ने 1965 के युद्ध में कब्जा किया था। गिमला समझौते में स्पष्ट लिखा गया है कि जम्मू बम्बोर में दाना पत्र 17 दिसम्बर 1971 को युद्ध प्रारम्भ के समय की नियमन रेखा का परो तरह पानन करेंगे और कोई पक्ष गन्तफा बारवाई से बदलन का यत्न नहीं करेगा। इसका अर्थ यह है कि जम्मू के मोर में भारतीय सेनाएं एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगी और तथाकथित आजा बम्बोर के 479 बगमील उस क्षेत्र पर अभी रहना जिस पर 1971 के युद्ध में कब्जा किया गया था।

गिमला समझौते में जिस बात पर समझौता नहीं हो सका वह भी महत्वपूर्ण था। यह युद्धबर्तियों का वापस ले वापस ले सम्बंधित था। सभी रिपोर्टों से यह साफ हो गया था कि एक ओर भारत बम्बोर समस्या के स्थायी हल पर जोर दे रहा था तो दूसरी ओर पाकिस्तान का जोर इस बात पर था कि भारत उसके 96 हजार युद्धबर्तियों मुक्त करे। यही सट्टा तो पाकिस्तान से यह कहकर भले वे कि वे युद्धबर्तियों को रिहा करने के काम को तर्कों व प्राथमिकता देंगे और ऐसा उन्होंने किया भी होगा लेकिन गिमला समझौते में इस प्रश्न पर बचक एक पक्षि यो जिसमें कहा गया था कि इन सवालियों पर दोनों के प्रतिनिधि आगे बातचीत करेंगे।

युद्धबर्तियों के बारे में भारत का दृष्ट स्पष्ट था। चूंकि युद्धबर्तियों ने भारत और बगलादेश के समुद्रत कमान के सामन आ प्रसमपण किया था इसीलिए बगला देश की राय के बिना उनके बारे में कोई फसला नहीं हो सकता। इसके लिए यह जरूरी है कि पाकिस्तान बगलादेश को मायता द। पाकिस्तान के विदेश विभाग के प्रवक्ता ने गिमला समझौते पर हुस्तालर के बाद विदेशी सवालाताओं के समन कहा है कि पाकिस्तान अगस्त में बगला देश का मायता दगा। फिर उसने वाप ही युद्धबर्तियों पर तीनों देशों के बीच चर्चा हो सकती।

बम्बोर सिनारर प्रथम भारत पाकिस्तान गिस्तरवाता के परिणाम कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं मान जा सकते। यह बात अलग है कि अभी समस्याएं हल नहीं हो पायी। समझौते के पूरे किसी प्रभाव का यह गन्तफट्टी नहीं थी कि गिमला में भारत तथा पाकिस्तान के बीच की सभी समस्याओं का समाधान हो जाय। केवल यही आशा की गयी थी कि गिस्तर समझौते में दोनों देशों के सम्बन्धों में एक नये युग का सूत्रपान होगा और बहो हुआ। समझौते पर उम्मीद करत हुए एक समीक्षा ने ठीक ही निष्कर्ष निकाला। यह समझौता न भारत की विजय था और न पाकिस्तान की। यह दोनों देशों की समझौतारी की विजय थी। इस समझौते से सबसे अधिक

चाह विश्व पटल पर कार्यरत तथा साम्राज्यवादी शक्तियों का इस महापक्ष के दलों का आपस में जुड़ाकर स्थापन कर रहे थे पहुँची है।

भारत में शिमला समझौते की वक्तव्य आलोचनाएँ हुई। काइ इस समझौते का दाय क साथ जारी करना तो काइ हम सैनिकों के सम्मान के साथ जाहक देवना चाहता था। एक आलोचक ने कहा कि पाकिस्तान की जमान उस वापस करके भारत सरकार ने मुद्र के मजान में जा जीना था वह वानचोत की मेज पर खा दिया। मगर मानिक प्रश्न यह था कि इस उपमहाद्वीप में कस स्थायी तौर पर शांति स्थापित हो बार इन दोनों शराब मुद्र का वापसी तनाव की निम्नो से अलग जमान चन का हूँ मित। तब के साथ यह काइ नहीं कह सकता कि भारत का अधिभूत भूवा का वापस करने का फसता भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी शांति स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कर्म सिद्ध हो सकता है। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण शरण मानो जा सकता है। शिमला शिखर-वाता में भारत ने भावी शांति के लिए जर्मि पूजी गायी थी। वापक दक्षिण से देखा जाय तो यह वान स्पष्ट हो जायगी कि उपमहाद्वीप पर शांति बनाये रखने के लिए वह उत्तरा है कि भारत और पाकिस्तान आपसी मामलों का तय करने के लिए शर्तों का रास्ता ठाठ दें।

शिमला समझौते के बाद—शिमला सौरीत हो राष्ट्रपति भवन ने पाकिस्तान की राष्ट्रीय एसेम्बली का वक्तव्य बुलायी बार समझौते की पुष्टि का प्रस्ताव रखा। एसेम्बली में बहुसंख्यक शरण मजानों ने समझौते के विभिन्न शर्तों पर अपना अपनी आशंकएँ प्रकट कीं। अधिसूचना के साथ इस बात के प्रश्न नहीं थे कि समझौते में पाकिस्तान की मुद्रवर्तियों की रिहा के सम्बन्ध में काइ फसता नहीं किया गया था। वल्ल सत्यो ने समझौते का स्वागत तो जवय किया मगर हमक साथ ही यह भा व्यक्त की कि यदि पाकिस्तान सचन नहीं रहा तो भारत धामा हो सकता है।

धन में भाग लत हण राष्ट्रपति भवन ने प्रस्ताव का पूरा समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जिम्मा भी सिद्धांत का परिचाय नहीं किया है। धन में एसेम्बली ने समझौते की पुष्टि कर दी। 7 अगस्त को पाकिस्तान ने 6770 भारतीय नागरिकों की रिहा करने की घोषणा भी कर ली।

शिमला-समझौते के बाधा धन के लिए अगस्त 1972 के अन्तिम सप्ताह में भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों की बैठक शुरू हुई। लेकिन प्रारम्भ से ही बातों में कठिनाई पैदा हो गयी। प्रमुख कठिनाई जम्मू-कश्मीर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के स्थापन के सम्बन्ध में पैदा हुई। भारतीय प्रतिनिधि ने इस बात पर दृढ़ था कि शिमला समझौते के अन्तर्गत पाक शर्तों से भारतीय सैनिकों को पाले हटने के साथ साथ ही कश्मीर में वास्तविक नियंत्रण रेखा निर्धारित की जाना चाहिए वक्तव्य ठाठ चौक गाँव का कर भा एक विवाद हुआ। बहुत असे तब बातों चर्चा के बाद 7 दिसम्बर 1972 के शरतर्षिक के बार में समझौता हो गया तथा 11 दिसम्बर के अन्त कश्मीर में पुनरेखांकन सम्बन्धी मानचित्रों पर भी हस्ताक्षर हो गये। सब कुछ वक्तव्य ठाठ चौक का भारतीय अधिकारियों के हवाले कर दिया गया। भारतीय मजान पश्चिम क्षेत्र में शिखर और पश्चिम में शिखर-वाता क्षेत्रों में पाले हुए थे। जम्मू-कश्मीर में वास्तविक नियंत्रण रेखा का अन्तिम रूप से अंकित करने के बाद भारतीय नया पाकिस्तानी बनाए रखा पर धन नवन स्थानों पर बना आयीं।

मानवीय समस्याओं पर समझौता — भारत पाकिस्तान और बंगलादेश के मध्य अभी तक मानवीय प्रश्नों का कोई हल नहीं हो सका था जिसके कारण उप-महाद्वीप की स्थिति सामान्य नहीं हो रही थी। 18 अप्रिल 1973 को भारत तथा बंगलादेश की ओर से समस्त मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए एक त्रिपक्षीय प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि सम्बद्ध देश सभी मानवीय समस्याओं का हल एक साथ करें अर्थात् पाकिस्तानी मुद्दबंदियों की रिहाई पाकिस्तान में जातिस्थों एवं बंगलादेश में विहारों, मुगलमानों की वापसी एवं साथ ही। लेकिन पाकिस्तान को यह त्रिपक्षीय वायव्य पक्ष नहीं आया। यह केवल मुद्दबंदियों का हल में बातचीत करना चाहता था। अतः दुर्घटियों के मामले को लेकर उल्लेख होगा कि वह विश्व मीडिया में फेरिया की ओर बढ़ा कि 15 मार्च 1948 के सैनिकी समझौते के अधीन नरसंहार के अपराधियों को सजा देने का अधिकार पाकिस्तान को है अतः तब से उसने प्राप्ति बिना कि वह भारत को प्रार्थना कि इस सम्बन्ध में कुछ बर्बर कारवायें नहीं करे।

ही बीच रात्रिदिन स्तर पर भी भारत और पाकिस्तान के बीच कोई बहुत बार्ताएँ चलती रहीं। 4 जुलाई 1973 को भी एक दूसरे के नरसंहार में एक भारतीय प्रतिनिधि दल बातचीत प्रारम्भ करने के लिए एकाएक रावलपिंडी पहुँचा। इसमें बंगलादेश का कोई प्रतिनिधि नहीं था क्योंकि अभी तक पाकिस्तान ने बंगलादेश को भी यता नहीं दी थी। इस स्थिति में भारतीय प्रतिनिधि को वास्तव में दो दलों के हितों का प्रतिनिधित्व करना था। अब भारतीय प्रतिनिधि दल पहले से ही एक मानकर चला था कि पाकिस्तान के साथ जो भी बार्ता हो वह 18 अप्रिल के भारत बंगलादेश के संयुक्त प्रस्ताव को ही आधार मानकर हो। लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में कोई विशेष उत्साह का प्रदान नहीं किया। अतः रावलपिंडी जाता ही कोई बिगड़ प्रगति नहीं हुई। बार्ता में एक प्रकार से अवगली मुसलमानों की वापसी के प्रश्न पर अनिरोध उत्पन्न हो गया। पाकिस्तान का कहना था कि वे लोग बंगलादेश के ही नागरिक हैं और उन्हें वहाँ रहना चाहिए। अतः यह निष्कर्ष करके कि 18 अप्रिल 1973 को इस सम्बन्ध में दोनों पक्षों के बीच दिशानिर्देशों में पुनः बार्ता हो रावलपिंडी बार्ता को स्थगित कर दिया गया।

18 अगस्त 1973 को यह बार्ता नयी दिल्ली में शुरू हुई। नयी दिल्ली में स्थानीय तत्कालीन अन्तर-राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत करने के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ महत्वपूर्ण और नाटकीय समस्याओं पर समझौता हो गया। इसका अनुसार पाकिस्तान से सभी बंगालिया बंगलादेश से वापस बंदी सदस्य में पाकिस्तानी नागरिकों तथा भारत से 195 को छोड़कर सभी मुद्दबंदियों की जल्दी ही एक साथ बदला-बदली करने की बात पर दोनों पक्ष सहमत हुए। समझौते में इस बात का संकेत था कि पाकिस्तान भी इस ही बंगलादेश की मांगों तथा साथ साथ मुंबई, बुरहमान और राष्ट्रपति मुंबई के बीच प्रत्यक्ष बातचीत होगी। समझौते की धाराओं में कहा गया था कि बंगलादेश में बंधन पाकिस्तानी नागरिकों के अधिकारों के बाधे में फैला करने के लिए बंगलादेश और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों या उनके प्रतिनिधियों की बातचीत होगी। बंगलादेश ने स्पष्ट कर दिया कि वे अभी बंदी में बराबरी के आधार पर ही भाग लेंगे। समझौते के अंतर्गत बंगलादेश ने यह मान लिया कि प्रस्तावित के समय 195 पाकिस्तानी मुद्दबंदियों पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और इस अवधि में वे भारत में ही रहेंगे। था

सन् 195 पाकिस्तानी युद्धबन्धियों के बारे में कृपता करने के लिए बग़लागा भारत और पाकिस्तान का प्रियता बातचीत होगी।

इस समझौते के अनुसार तीनों देश प्रत्यावर्तन के काम में एक अंतराष्ट्रीय संगठनों से सहायता ले सकने से जो मानवीय न्याय का काम करते थे। स्वयंजरीह की सरकार के प्रतिनिधियों और अंतराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों को पाकिस्तान स्थित बग़ालिया और बग़लादग़ स्थित पाकिस्तानियों के निम्न की पूरी छुटी गयी। यह भी तय हुआ कि पाकिस्तान और बग़लादग़ का सरकारें इन प्रतिनिधियों का उनका काम में पूरा सहायता करेंगे। समझौते में इस बात की भी व्यवस्था की गयी कि अदला-बदली के तानाशाह लोगों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाय। प्रत्यावर्तन का प्रथम तय की जाने पर भारत और पाकिस्तान अन्तः राष्ट्रीय गुरु करने का निर्णय निश्चित करेंगे और फिर जल्दी काम शुरू कर दिया जायगा। समझौते में यह भी कहा गया कि प्रत्यावर्तन का काम पूरा होने तक दोनों देशों की बातचीत के लिए अच्छा वातावरण बनाया जिससे महाद्वीप में समझौते की भावना को प्रोत्साहन मिलेगा।

समझौते पर हस्ताक्षर करने के पहले भारत और पाकिस्तान प्रतिनिधि दोनों के बीच बहस होना शुरू हुई। कई दिनों से इस समझौते का पूरा नहीं माना जा सकता फिर भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि गतिराष्ट्र के एक दौर का इसमें समाप्त कर दिया। भारत ने सामान्यतया पाकिस्तानी युद्धबन्धियों का मुक्त करने का जो फैसला किया उसमें सफल बनने का सामना हुआ। समझौते के द्वारा भारत ने ऐसी समस्या का हल निकालने में सफलता प्राप्त की जो उसके लिए महीनों से पर जानी का कारण बन चुका था। पाकिस्तान युद्धबन्धियों के मामले का भारत का कारणों से अन्याय चाहता था इससे भारत पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ रहा था तथा युद्धबन्धियों को लेकर पाकिस्तान में एक विद्रोही गतिराष्ट्र प्रचार कर रहा था। पर इस समझौते से भारत ने अपने को एक ऐसे मामले से मुक्त कर लिया जो भारत पाकिस्तान और बग़लादग़ तीनों के बीच जटिल हुआ था।

युद्धबन्धियों का मुक्ति के दायित्व बग़लादग़ का पाकिस्तान में पड़े हुए बग़ालियों को वापस प्राप्त करने का मोका मिला। पूरे विश्वमहाद्वीप में पाकिस्तान ने सभी बग़ालियों को वापस करने का दावा माना। इसलिए स्पष्ट था कि पाकिस्तान ने जो भी बग़ालियों पर मुक़दमा चलाया का त्याग छोड़ दिया। बाउता देश के लिए यह एक महान विजय था। मुजाबुरहमान की सरकार के लिए राजनीतिक रूप से बग़ालियों का वापस एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया था।

इस समझौते ने जिसका पलटा नारी रहा वह मोचना हुआ भारत है। जब माच में भारत-बग़लादग़ में संयुक्त वापस पत्र जा। नतीजा था कि बग़लादग़ का मान्यता न मिले तक पाकिस्तानी युद्धबन्धियों का न होने के दावा का छोड़ दिया गया था। इसमें का पाकिस्तान का पलटा नारी हो सकता था जिनमें हमें यह नहीं भूना चाहिए कि वह मानवाधिकार के आधार पर किया गया था। अगस्त 1973 के समझौते में पाकिस्तान का हिस्सा उभाना मलत हुआ। यह एक ऐसा समझौता था जो राजनीति के आधार पर हुआ था। हमें एक दूसरे न समझौते और दूरदर्शिता से काम लिया और इस बात का कोटि का कि एक दूसरे का दावे इन सामान्य मान लें जिससे किसी को को विद्रोह मुक़दमा नहीं हो। इस सम्बन्ध में दावा नहीं हो सकती कि इस समझौते पर मई 1973 में सब

पक्षों ने त्याग और सहिष्णुता से काम लिया। पाकिस्तान चाहता था कि यद्वापराधियों समेत सभी मुद्राकारी छोड़ दिये जायें। बगलाद श इससे निरा राजी नहीं था। वह चाहता था कि जिन बगानियों का यद्वापराधियों का बन्धन सम्बन्ध बना रहे वे लिए रोक लिया गया था उनसे सहित सबको पाकिस्तान से वापस भेज दिया जाय पर इधर से यद्वापराधियों को न छोड़ा जाय। पाकिस्तान इससे सहमत नहीं था। यह बगानियों को बन्धन बनाये रखना चाहता था। इसी प्रकार जो ठाई सात बगाली बगनादश में थे उन सबको पाकिस्तान वापस भेजना चाहता था और बगला श का आप्रहृष्ट था कि वे सब वापस जाय। किन्तु दोनों ने अपने अपने आप्रहृष्ट छोड़ दिये और समझौते में सम्मेलन दिया। पाकिस्तान यह मान गया कि पाकिस्तान स्थित सब बगानियों का वापस भेज दिया जायगा और यह किसी को बन्धन नहीं रखेगा। उसने यह स्वीकार कर लिया कि यद्वापराधियों के प्रश्न पर बाद में फैसला होगा। उधर बगला श ने अपने यहाँ के सब पाकिस्तानियों को तुरन्त वापस लिये जाने की बात छड़ा दी। उसने लिए समझौता का आधार स्वीकार किया गया और दोष का फैसला भावी वार्ता पर छोड़ दिया गया। कुछ लोगो को यह सौदा अच्छा नहीं लगा किन्तु जो हालत थी उसमें इससे अच्छा सौदा नहीं हो सकता था। इसका सबसे बड़ा लाभ यह था कि पाकिस्तान का यदि यद्वापराधियों के प्रश्न को सुलझाने में लिए बगला श का मापता दानी पड़ेगी। यह प्रश्न दोनों के बीच प्रत्यक्ष वार्ता से ही सुलझ सकता था और बातों सबतक नहीं हो सकती थी जयन्त बगला श को भाव्य न मिल जाती। बगला श के बने पाकिस्तानियों के प्रश्न को भी समझौते के अनुसार किसी अगरी द्वीय मानवीय संस्था की सहायता में पाकिस्तान को सुलझाना था। यदि यह न हो सुलझाता तो उसकी गरदन पक्का के लिए यद्वापराधी को टाँप में पड़ी।

फरवरी 1974 में पाकिस्तानी गहर साहोर में इसमें राज्यों का दूसरा सम्मेलन आयोजित हुआ। बगला श का इसमें शामिल करने के लिए यह भाव्य पक्का हो गया कि पाकिस्तान बगला श का राजनयिक मापता प्रश्न कर दे। कुछ अन्य मुस्लिम राज्यों ने पाकिस्तान को उनके लिए राजी करा लिया और 22 फरवरी 1974 को पाकिस्तान ने बगला श का एक पूर्ण स्वतन्त्र राज्य के रूप में मान्यता दे दी। 23 फरवरी को राख मुजीबुररहमान अपने अन्य सहयोगियों के साथ इस्लामा सम्मेलन में भाग लेने के लिए लाहौर पहुँचे जहाँ पाकिस्तानी अधिकारियों ने उनका स्वागत सादर सादर किया। भारतीय उपमहादीप में शांति और सहयोग तथा बगला श तथा पाकिस्तान के बीच सामान्य सम्बन्ध स्थापित करने की दृष्टि में यह बड़ा ही महत्वपूर्ण काम था। इस मापता के फलस्वरूप निम्नलिखित और निम्नी समझौते को पूरी तरह लागू करने का मांग प्राप्त हो गया। इन समझौतों के बाव भी तीन देसों के बीच अभी बर्तमान सम्बन्धों की दिव्यता समाधान होता भाव्य पक्का था। पाकिस्तान द्वारा बगला श का मापना दिये जाने का पक्का स्वतन्त्र इस समस्याओं के समाधान का मांग भी प्राप्त हो गया।

अप्रैल 1974 का समझौता—भारत बगला श और पाकिस्तान के बीच नवी लिप्ति में 5 अप्रैल 1974 को एक दिनाय वाता प्रारंभ हुई और 9 अप्रैल को एक समझौता हो गया। समझौते के अनुसार बगला श ने उन 195 पाकिस्तानी यद्वापराधियों का मुकाबला कर दिया बगला श को जिनपर बर्तमान के आधार पर मुकद्दमा चलाया जा रहा था। पाकिस्तान ने स्वीकार किया कि बगला श में

को पुनः अस्वीकार कर लिया। भारत के परमाणु परीक्षण पर पाकिस्तान की चौंखी हट को अप्रत्याशित नहीं माना जा सकता। दोनों देशों के सम्बन्धों को ऐतिहासिक पष्ठभूमि में पाकिस्तान का संश्लिष्ट होना स्वाभाविक था।

सितम्बर 1974 का समझौता :—भारत के परमाणु परीक्षण से भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों में जो तनाव आया उसका प्रभाव कुछ और राजनीतिक क्षेत्रों पर भी पड़ा। 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में दोनों देशों के बीच चिन्तित पत्रों का आगमन आदि में व्यवधान पड़ गया। यह व्यवधान समाप्त भी नहीं हुआ था कि घण्टाघण्टा का संकट या पहुँचा और 1970 के घटनाक्रम ने शहीदों की भी तोड़ दी। निम्न समझौते के बाद भी इन सम्बन्धों के सुधार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका। लेकिन दोनों देश इन मुद्दों पर समझौता करने के लिए पान कर रहे हैं। अतः इन प्रश्नों पर एक समझौता करने के उद्देश्य से सितम्बर 1974 में दोनों देशों के प्रतिनिधि इस्लामाबाद में मिले। नतीजतन के मध्यस्थान समझौते पर हस्ताक्षर हो गये। न समझौता के अनुसार दोनों देशों के बीच शांति और संचार और यात्रा सुविधाएँ तत्काल जारी करने का निर्णय लिया गया। दमार्ति उद्घाटन के सम्बन्ध में भी वास्तविक हृदय के बिना इन पर कोई निर्णय नहीं हो सका।

इस्लामाबाद में हुए ये समझौते काफी महत्वपूर्ण हैं और इनमें निम्न समझौते के उद्घाटन भावनाओं का प्रतिबिम्ब देखने को मिलता है। यह विचारित किया जा सकता है कि इन समझौतों से दोनों देशों में पारस्परिक प्रवृत्तियों को बढ़ा मिलेगा।

भारत और बंगला देश

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि — 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम भारत — पड़ोस में बंगलादेश का अस्तित्व था। जब पूर्व बंगाल में पाकिस्तानी शासन के विरुद्ध विद्रोह हुआ तब भारत ने स्वतंत्रता मतानिधि का अपनी पूरा सहानुभूति दी। पाकिस्तान के सैनिक तानाशाही ने जब इस विद्रोह का क्रूर दमन शुरू किया तो भारत ने इसका बड़ा तगड़ा विरोध किया। भारत का कहना था कि पाकिस्तान का अवामी नीति के चर्च हुए प्रतिनिधियों के साथ राजनीतिक समझौता कर लेना चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी शासकों पर नरसैय सुझाव का कोई अहम नहीं पड़ा और वे भारत पर ज़राफ़ उगाते रहे कि वह पाकिस्तान के आंतरिक मामले में दखल दे रहा है। बाद में पाकिस्तान ने पूर्व बंगाल में जा नर सहार किया। सवे प्रस्त होकर शासकों का सहायक पूर्वी बंगाल में जा भारत भाग लेने। भारत ने उन के वरन नगराणियों का गुरण दो और उनके मजिन तथा भावसु की व्यवस्था की वरन बंगला देश की मुजिनाहिनी के जवानों की प्रशिक्षण और इशियारभी न्यि एव जागदी प्राप्त करने के लिए उनका उत्साह भी बढ़ाया। मार्च 1971 में हा बंगला देश की एक अस्थायी सरकार बन गया था और भारत सरकार पर दबाव डाला जा रहा था कि वह इस सरकार को मान्यता प्रदान करे। लेकिन भारत की भय था कि यदि उसने बंगला देश को मान्यता दे दी तो पाकिस्तान से युद्ध छिड़ जायगा। अतः अंतराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण भी भारत सरकार मान्यता के प्रश्न को टालती रही।

लेकिन उस बीच भारत सरकार ने बंगला देश में हा रहे भाषण नर सहार का राबन के लिए कई प्रयास किए। भारत के विरुद्ध नताला का विद्रोह भेजा गया ताकि वे उन देशों के नताला का बंगला देश में परे। घटन या स अवगत करा शकें। असा बाव विस्थापितों के निरंतर प्रवाह से भारत के समग्र एक कठिन परिस्थिति पदा हा गयी। काई भी गुरणायी पूर्वी उगात नौटा का तयार नहीं था। अतएव भारत ने यह कहा कि पूर्वी बंगाल की स्थिति में गुशार का एक ही उपाय है पाकिस्तान के शासक अवामी नीति के नतालों से राजनीतिक समझौता कर लें। भारत हमारा स बाव पर दटा रहा।

बंगला देश की समस्या के समाधान के लिए स्वयं भारत की प्रधान मंत्री था इंदिरा गांधी ने कई पत्रिका लगा ता यात्रा की। लेकिन उनकी यात्रा का कोई परिणाम नहीं निम्नता और बंगला देश के प्रश्न का सबर भारत तथा पाकिस्तान के बीच युद्ध अवश्यम्भायी हा गया। 3 दिसम्बर 1971 का यह युद्ध आरम्भ भी हो गया।

बंगलादेश की मान्यता — युद्ध छिड़ने के कुछ दिना पहले भारत सरकार का बंगला देश के विदेश मंत्री का एक पत्र मित्रा जिनम उहने अनुरोध किया था कि भारत तत्काल बंगला देश को मान्यता दे। उस अनुरोध पर विचार हुआ और 6 दिसम्बर का भारत ने बंगला देश को मान्यता दे दी। मान्यता प्राप्ति के उपरान्त

बंगला देश की सरकार ने हुसैन अली का भारत में अपना पहला राजदूत नियुक्त किया। 8 दिसम्बर का अपना परिचयपत्र पेश करत हुए हुसैन अली ने भारत के प्रति अपना जाभार व्यक्त किया और यह आगा व्यक्त की कि दोनों देशों की मन्त्री निरन्तर दृढ़ होगी।

भारत बंगला दश की पहली संधि — 10 दिसम्बर को भारत सरकार और बंगलादेश का सरकार के बीच एक संधि हुई । भातक प्रधान मंत्री तथा बंगलादेश के वायवाहक राष्ट्रपति नजहरु इस्लाम ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया यह एक आयतन मूर्त्वपूर्ण समझौता था । इसके अनुसार बंगला दश को पूरी तरह पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिक तबाहो क कब्जे से आजा कराने के लिए भारतोय सेना तथा बंगला दश की मुक्तिवाहिनी का सम्बन्ध बनना गया और इस समुबन्ध कमान का प्रधान एक भारतीय सेनापति नियुक्त किया गया । समझौते मे यह तय हुना कि दोनों सरकार मिलकर बंगला दश मे सामान्य स्थिति लामेंगी तथा सारे बंगला दश मे आवेक नागरिक सवाए स्थापित करेंगी । इस समझौते से बंगला दश मे भारतीय सेना के उत्तरदायित्व को भी निश्चित किया गया । यह कहा गया कि जमे हो बंगलादश मे स्थिति सामान्य होगी भारतीय सत्रिक लोट आयगे । गरणायियों के वापस लोटने के सम्बन्ध मे इस समझौते में व्यवस्था कर दी गयी थी । दोनों दशा को विद्वान नीति के सम्बन्ध में कहा गया कि उनका आधार मुटनिरपेक्षता की नीति तथा पचशीन के सिद्धांत होंगे । भारत ने बंगला दश की प्रादक्षिक अलक्षता की जिम्मेवारी भी ली । पुनर्निर्माण काम के लिए भारत ने एक सौ करोड रुपये मन्त्र क रूप में देने का वादा किया ।

मुजोर की रिहाई में भारत का योगदान—बंगलादेश की आजागी के लिए भारत और पाकिस्तान में आ प्रथम युद्ध छिड़ा और उसमें पाकिस्तान की जो अपमानजनक पराजय हुई वह भारतीय सना और मुक्तिवाहिनी के सशक्त प्रयासों का वार नाम था। युद्ध में पाकिस्तान के हारते ही बंगलादेश की सरकार ढाका में प्रतिष्ठित हो गयी।

अवामी लीग के नेता दोष मुजीबुररहमान को 25 मार्च 1971 को ही पाकिस्तानी शासकों ने बंद कर दिया था और उन्हें यहीं बंगाल से हटाकर पश्चिमी पाकिस्तान के एक जेल में रख छोड़ा था। स्वतंत्र बंगला देश की स्थापना के बाद भारत के समान सबसे महत्वपूर्ण समस्या दोष मुजीब को कद से मुक्त करना था। इसके लिए भारत का ही प्रयत्न करना था। भारत सरकार ने अल्प विदेशी मर कारो में अद्वाराणि निवह पाकिस्तानी सरकार पर दबाव डाल जिससे दोष मुजीब को रिहा किया जाय। पाकिस्तान सरकार का अंतर्राष्ट्रीय जनमन के समान मुक्त पड़ा और 8 मं वरी को दोष को से रिया कर लिये गये।

राष्ट्र मुजीब का भारत आगमन—10 जनवरी को गैर मुजीब रहमान लगभग ना मीन तर पाकिस्तान जेन की यातनाओं को मुक्तने के बाद मुक्त होकर दिहनी आर । जिहनी में उनका भारतीय जनता और सरकार द्वारा मान्यता स्वागत हुआ । इस अवसर पर बोले हुए गैर मुजीब ने कहा कि बंगला देश की जनता भारत के साथ जफ़ा-जामाद के जना नर नर जगती है । भारत में जाजगल की जनता की स्वाधीनता और मुजीब की रक्षा के लिए अग्रता लू बनाया है । गैर मुजीब ने फिर कहा कि भारत ने बंगला देश के लिए जो कुछ किया है उसने प्रति वे तज्ज-मुस्तफ है ।

भारत-बंगला देश के बीच दूसरी संधि—शेख मुजावरहमान के शाका पत्रचन पर बंगला देश का सरकार का पुनर्गठन किया गया और उन्हें प्रधान मंत्री का पद दिया गया। बंगला देश की इस नयी सरकार के समय जनजातक समस्याएँ और कठिनाइयाँ थीं। भारत में तबतक एक कराह विस्थापितों का वापस आकर बसाना था। सरकार का माठन बिखून छिन्न भिन्न हो चुका था। उसका चरम दुस्मन करना था। युद्ध के कारण बांग्ला देश की संचालन व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गया था। इसका ठीक करना था। बेरोजगारी का समस्या भी बिकराल हो गयी थी। अतएव आर्थिक पुनर्निर्माण का कार्यक्रम चलाया था। इसके अतिरिक्त कानून बारीक्युद्ध का समस्या भी था। मुक्तिवाहिनी के लोगों के पास जन्म शत्रुता और वर्णता की भावना से प्रेरित होकर वे पर बंगाली पाकिस्तानी मुसलमानों के प्रति विघातमय रवैया जनतावे हुए थे। देश में आतंक का भाव फैला हुआ था। नयी सरकार को इन नारी समस्याओं का सामना एक ही साथ करना था।

इन समस्याओं के समाधान में तबसे अत्यन्तपूर्ण पहलवा देने के बाद भारत ने भी अपना अधिकतम पूरा काम का बहन दिया। बांग्लादेश के विपक्ष में समस्त आजात और आन्तरीय प्रतिनिधियों के साथ नया रिश्ता में बाधा हुई और दोनों के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। इसके अनुसार भारत ने बंगला देश का पचास कराह रुपये के मूल्य का मात्र और सहायता के रूप में प्रदान करने का बहन दिया। यह भारत का आर से बंगला देश के पुनर्निर्माण के प्रति हार्दिकता योगदान था।

इसके अतिरिक्त भारत ने पचास लाख पौंड का विदेशी मुद्रा का ऋण भी बंगलादेश को देने का फैसला किया जो पन्द्रह किस्तों में वापस किया जायगा मगर पहले पाँच वर्ष में मात्र किस्त नहीं हो जायगा।

बंगलादेश की मांग्यता—जब तक बंगलादेश का बचत भारत और जटान से ही राजनयिक मायता मिल पाया था। शेख मुजावर का रिहाई के बाद यह निश्चित हो गया कि बंगला देश का आग्रह हो मुसलमानों के अधिकतर लोगों से मायता मिल जायगा। पाकिस्तान और अमेरिका का यह धर्म अवश्य रहा कि बंगलादेश का कार्य मायता न हो लेकिन वे सफल नहीं हो सके। डाका में मुजावरक शान्त हो मायता बचत गया और विभिन्न देशों द्वारा मायता का रास्ता खुल गया। पूर्वी जयता ने पहले बंगला देश का मायता था उससे बाद पूर्वोक्त यूरान के देशों ने। फिर नेपाल को आजात पड़ोसियों का भारी बोझ था वह भी पश्चिमा यूरान के देशों ने ही बंगला देश को मायता देना। मलयेशिया और इंडोनेशिया का मायता भी बंगला देश का इसी समय मिल गया। इस तरह अन्तराष्ट्रीय स्तर में बंगला देश का प्रभाव हो गया। इस बात में भी बंगला देश को भारत का पूरा सहायता मिली।

जनवरी 1972 में काबुल में अन्तराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। बंगला देश का एक प्रतिनिधि सम्मेलन भी इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए काबुल पहुँचा। लेकिन पाकिस्तान ने उसके भाग लेने का विरोध किया। उसने यह भी कहा कि यदि सम्मेलन में बंगला देश के प्रतिनिधि का भाग लेने के लिए बुलाया गया तो पाकिस्तान सम्मेलन का बहिष्कार करेगा। पश्चिम एशिया के कुछ इस्लामा देशों ने पाकिस्तान का समर्थन भी किया। किन्तु इस दौरान भारत सरकार ने भी बराबर का रुख रखा था। उसने अपना रुख जाहिर करते हुए साफ-साफ कहा कि बंगला देश को बुलाव बिना भारत काबुल सम्मेलन में

वर्तई भाग तहों लगा । सम्मेलन के राजनीतिक सत्र में बोलत हुए भारतीय प्रति निधि दल के नेता केशव दश भासकीय २५५ विभुक्त साफ कह दिया कि भारत किसी भी एक अस्तित्व को मजूर नहीं करेगा जो भारतीय उपमहाद्वीप में की गयी वास्तविकता से अलिप्त हो कर लिखा गया होगा । भारतीय प्रतिनिधि दल अपने प्रयास में सफल रहा और वाशिंगटन सम्मेलन ने इस आशय का एक प्रस्ताव स्वीकार कर दिया कि बंगला देश के साथ सारा लोगो को इस बात का पूरा हक है कि वे अपनी मजो के अनुसार अपन अधिकारो और भाग्य का फैसला करें । बाद में बंगला देश को सम्मेलन का स्थायी सम्मेल्य बना दिया गया ।

मजोत्र का पलकता आगमन — 6 फरवरी 1971 को बंगलादेश के प्रधान मंत्री के रूप में भारत सरकार के नियंत्रण पर गछ मुजीबुर्रहमान कलकत्ता आय और दो नित तत् भारतीय नेताओं से उनकी वार्ताए हूँ । दोनों देशों के इस मिलन के अवसर पर भारत और बंगला देश के बीच स्थायी मित्रता की आधार शिला रखी गयी । इस बार जो शिखर सम्मेलन हुआ उसमें दोनों देशों के भावी सम्बन्धों की स्पष्टता तयार की गयी । इस अवसर पर यह आशय व्यक्त की गयी कि भारत और बंगला देश के सम्बन्ध स्थायी रूप से एक दूसरे के सहयोग और मित्रता के आधार पर स्थापित होंगे ताकि पूरे एशिया और विश्वभर भारत उपमहाद्वीप में स्थायी शांति के द्वारा आर्थिक और राजनीतिक प्रगति का अवसर प्राप्त हो ।

कलकत्ता में श्रीमती इन्दिरा गांधी और गछ मुजीबुर्रहमान के बीच अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं पर वार्ताए हुई जिसमें बंगला देश के शरणार्थी और पाकिस्तानी विनाशखोला से पोटित लाखों परिवारों के पुनर्वास की समस्या तथा भविष्य में भारत और बंगलादेश के अतिरिक्त अंतराष्ट्रीय स्थिति पर विचार विमर्श हुआ । पूर्व घोषित नीति के अनुसार भारत ने वचन दिया कि वह बंगला देश के आतंरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा । भारत ने बंगला देश को एक पूर्ण स्वतंत्र राज्य माना । इस नीति के अनुसार भारत ने यह घोषित किया कि 25 मार्च से पहले भारत बंगला देश से अपनी सारी सेनाएं वापस बना लेगा । भारतीय नेताओं ने पहले ही घोषणा की थी कि सेनाएं तभी तब बंगला देश में रहेंगी जबतक वहाँ की सरकार इसकी आवश्यकता महसूस करेगी । यह निश्चय स्थापना क्योंकि दूसरे की पौत्र परवर्तता की प्रतीक मानी जाती है । इससे अतिरिक्त सेनाएं वापस निरस्तन के मिलनित में बिना किसी विचित्राहट के समझौता होने से उन देशों में जो पाकिस्तान के समर्थक थे उन्हें यह कहने का मोका नहीं रहा कि भारत साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों से प्रेरित है ।

दोनों देशों के बीच व्यापार के सम्बन्ध में निश्चय प्रकट किया गया कि जो है वह ही सबे भारत और बंगलादेश के बीच सरकारी माध्यम से ही व्यापार हो ताकि दोनों देशों के असाधारण तत्त्वों को उनकी मित्रता से नाजायब लाभ उठाने का अवसर नहीं मिले । इन सारे फैसलों को एक समुक्त घोषणा में रखा गया । समुक्त सङ्गठन को समुक्त घोषणा का नाम दिया गया और भारत के विदेश मन्त्रालय के एक प्रवक्ता ने स्पष्टीकरण करते हुए बताया कि वचन में एक औपचारिक सङ्ग है जबकि घोषणा दोनों देशों के नेताओं के निश्चय को प्रकट करती है ।

इन्दिरा गांधी की दारु-यात्रा :— 16 मार्च 1971 को भारत की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी सच मुजीब के नियंत्रण पर शरण पट्टेवा जनी अपार

आन्दोलन का वचन दिया गया। संधि के आमुख में कहा गया था कि दोनों देशों की सभी स्थान तथा रक्षणान पर जोड़ी गयी है इसी के परिणामस्वरूप स्वतंत्र वगला का उदय हुआ है।

दोनों देशों ने संधि के जरिये विश्व शांति तथा सुरक्षा को मजबूत बनाने तथा उपनिवेशवादी रणभेद तथा साम्राज्यवाद के अंतिम रूप में उभरने के कार्य करने का संकल्प लिया। उनका मत था कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का हल सहयोग न कि संघर्ष के आधार पर ही दिया जाना चाहिए। संधि की धाराओं में व्यवस्था की गयी है कि जोना में संधि किसी देश पर भी हमला हुआ तथा हमले की घण्टी हुई तो तत्काल आपस में सलाह मशविरा करेंगे जिससे छतरी दूर किया जा सके और उनकी सुरक्षा हो सके। एक दूसरे के विरुद्ध किसी अन्य देश को भी मदद नहीं देंगे न एक दूसरे पर हमला करेंगे। इसके अलावा धारा दस के अधीन वे किसी भी एक अथवा अधिक देशों से खुला अथवा गोपनीय ऐसा कोई समझौता नहीं करेंगे अथवा न कोई जिम्मेवारी लगे जो इस संधि के विरुद्ध हो।

इस संधि के बारे में उत्पन्न मतभेद आपसी बातचीत के जरिये हल किये जायेंगे। हस्ताक्षरकारियों ने एक दूसरे के विरुद्ध किसी भी सैनिक संधि में हिंसा न करने की भी घोषणा की। वे अपनी भूमि का उपयोग एक दूसरे के विरुद्ध हमले के लिए नहीं करने देंगे।

उन्होंने सटस्पना तथा शांतिपण सह-अस्तित्व के सिद्धांत पर अपनी व्याख्या प्रकट की तथा आन्तराष्ट्रीय शांति और राष्ट्रीय सार्वभौमता व स्वतंत्रता को मजबूत बनाने पर जोर दिया है साथ ही दोनों देशों ने उपनिवेशवाद तथा रणभेद के विरुद्ध संघर्ष की मदद देने की भी घोषणा की। यह तय हुआ कि सभी अन्तर्राष्ट्रीय सम्स्याओं पर जिनका उनके हितों पर असर पड़ता है आपस में नियमित तौर पर सम्पर्क रखेंगे हर स्तर पर इसके लिए बातचीत की जाती रहेगी।

संधि की धारा पाँच में आर्थिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्रों में सर्वांगीण सहयोग तथा आपसी व्यापार परिवहन व संचार के काम में सहयोग बढ़ाने की व्यवस्था की गयी है पनविजली व सिंचाई के विचारों में समुदाय तौर पर काम किया जायगा। अपने ऐतिहासिक सम्बन्धों को दृढ़ करके वे साहित्य, विज्ञान, संस्कृति, खेल-कूद तथा स्वास्थ्य के काम में सम्बंध बढ़ाया जायगा।

संधि का विश्लेषण—एक दूसरे द्वारा आक्रमण का शिक्का हाने का छतरी भी इस संधि का भाग ही रहा गया है। दोनों देशों ने संधि की धारणा के अनुसार प्रतिज्ञा की है कि वे एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे और अपनी जमीन पर सशस्त्र ऐसा काम नहीं करेंगे जो दोनो देशों के किसी का सैनिक हानि पहुँचाये अथवा उसकी सुरक्षा के लिए सतारा गया करे। इसके अलावा वे इस बात के लिए भी बचनबद्ध हुए हैं कि वे किसी भी सैनिक गठबंधन में प्रविष्ट या भागीदार नहीं बनेंगे जो दोनों में से किसी एक के विरुद्ध हो। किसी एक के खिलाफ मात्र संघर्ष में जाने किसी तीसरे देश को जोनों में से किसी के भी द्वारा कोई सहायता न देने का निर्णय भी लिया गया है। इन सब के बाद एक दूसरे की सुरक्षा अथवा असाहता का एक दूसरे से हानि पहुँचाने का कोई सतारा नहीं रहता। जहाँ तक किसी तीसरे से सुरक्षा का संबंध है उसके संघर्ष में संधि की धारा 10 में व्यवस्था कर दी गयी है। उसमें साफ लिखा है कि जब भी तीसरे देश से कोई आक्रमण या

उसका मतवा हाता तो ब उस समाप्त करन क विषय म विचार कर ।

भारत न बाग्य रज का आगना में आक्रम यो लिया है । उनक पुनर्निर्माण क लिए वह मत्र एकार का सहयोग लेन का तयार था । वह जानता था कि दुका निर्माण चिन सिद्धान्तों और आगनों क आधार पर न था उहें स्थित हुए उसका रखा और विकास में सहयोग न करत एक दूसरे क लिए अपितु एक म समझ दख म जानि क लिए हितकर होगा । यहा बाग्यर के कि न प्रधान मंत्रा म विज्ञा न यह ज्ञान किया कि क्या मंत्रि क अनुसार बाग्यर पर हमरा मान पा हमरा माना जायगा तो उहने उस जवाब म कहा कहा कि हम स्वमन्त्र दान्यर का भुरपा और वन्यता म बहल निचर है । बगला का जो पृष्ठभूमि है और उसका मुरला म जो भविष्य निहित है उनका प्रति म दृष्टि म क्यों न था ।

सवि म यह भा प्रकट है कि पारस्परिक सम्बन्ध क लिए कोई क्षेत्र उत्तम नहीं छोड़ा गया है । न काल ऐसा कि व समस्याओं पर समय समय पर पारस्परिक विचार विमर्श का व्यवस्था की गया है आ दोनों देशों क हितों पर प्रभाव डाल सकते हैं अन्ति यह निश्चय भा प्रकट किया गया है कि सहनिर्वाह तथा गति वात क परस्पर के मूलभूमि के लिय ब काम करेंगे । इससे अन्तर्गत आपिक, वन्यता तथा तकनीकी क्षेत्रों म भा निवृत्त सहयोग का निश्चय किया गया । समानता पारस्परिक सम्बन्ध क आधार पर बाग्य संचार और यातायात क क्षेत्र में भा पूरा सहयोग का विचार सवि का जग है । बाग्य निर्माण इन विद्युत तथा सिंचन के क्षेत्रों म भी उता पारस्परिक व्यवस्था करन का निश्चय किया गया है जिससे पानी स होन वात विद्युत स दक्षिण म निवृत्त वना का मत्र और उसका अधिकतम उपयोग भी हो सके । उस सवि म दान्यर का जो ज्ञान है कि वह एशिया में गति और विकास क लिए मुक्त आधार बन सकेगा ।

उस सवि में भारत और बाग्य जन दान्यर धारा म निम्न है कि नया यात्राओं क विकास जिन्दाई तथा प्रिक्ता क लिए उ का उपयोग तथा वात गहन के लिए दोनों देश सद्वन रूप म का वाद करेंगे । श्रीम । गांधी का दावा यात्रा का नमार्ति पर प्रकाशित मयुक्त धारणा म स्पष्ट किया गया कि दोनों देशों का संयुक्त नया आयोजन निवृत्त किया जाएगा ।

उस स्लामावात नारा कमन्सव ठाया गया परस्पर-बांध का बगला समाप्त हो गया और दान्यर बाग्य दान और भारत पूर्व का मन्त्रा नितियों का दोनों देशों का समता क नाम म सहा उपयोग कर सकेंगे । बगला का न होकर कमम की नितियों क माग सल जान म हमारा देश का आन्तरिक परिवर्तन उन्ना को भारा साम होगा तथा नारा अन्त बगला का मा ब्रह्मभूत गया तथा दान्यर नितियों क पानी का उपयोग हमारा सहा ता न कर पायगा । व कि नितियों हमारा त्र म गेकर बगला दान्यर उता है । नितिन वात का सूच । उस दृष्टि केर नारा जनता का भारा नाम कर सकेंगे ।

पाकिस्तान सरकार न दोनों देशों क बीच उस सवि का सुरता-मममौता और सम्मग ए-म कि गठबंधन का नाम नि । । किंतु नाम न कृष्ट भा निगा जाय व सवि दोनों देश का बाग्यी मृच्छा और दय क्षेत्र म गति का रखा क उह म म का गया था । व न हो निगा ए-म बाग्य म नों क कि उ या और न की मका को जात्रामक दृश्य था । व कृष्ट दोनों म सम्म दमा न है षणो भारत-मोक्कन उचित है । उनक विषय म कृष्ट न कृष्ट भा वन्त नि

परंतु वह जिस तरह न पिछे न जिनें अमल में आया उनमें स्पष्ट है कि वह किसी के खिलाफ सैनिक गठबंधन के रूप में नहीं है और अधिकबद्ध नशा में न किसी एक की सुरक्षा का खारा हान पर न किया जाता होता है। इसलिए भारत बंगला देश की संधि के सम्बन्ध में भी किसी का शक का गुजा न नही जाना चाहिए। यदि यह बात न जाती तो हम संधि की तीसरी धारा में विश्व में तनाव कम करने तथा अंतराष्ट्रीय शांति के लिए गर-गुर्वदा और शांतिपण सह अस्तित्व की भांति में आस्था ध्येयन न का जाती।

भारत बंगला देश व्यापार समझौता — प्रधान मंत्री रामनाथ गोपाल काका यात्रा तथा उनका गेष्ट मुनाबुर हमान में आपना हितो तथा दोनों देशों की जनता का प्रति तथा सहयोग के विभिन्न पक्षों पर बातचीत के बाद अब भारत और बंगला देश के बीच आम यात्रा तथा भुगतान समझौते का मार्ग प्रशस्त हो गया। 5 मार्च 1972 का दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया। इस समझौते के सम्बन्ध में कुछ विवरण हो गया क्योंकि सीमा पर हानवारी नागरिक वस्तुओं के व्यापार का परामर्श करने में काफी समय लग गया। बंगला देश के अधिकारियों ने सामान्य के समान अधिकारियों में समझौते की मंजूरी पर काफी ध्यान देने करने के बाद ही सीमा व्यापार सम्बन्धों निगम किया। यह समझौता पचास कराट रूपया का लिया गया और उसकी अवधि एक साल रखा गयी। इस समझौते का समझौते की विभिन्न मंजूर पर विचार करने और जटिल अनुभव होने पर सद्विचारों में समाधान करने का व्यवस्था है।

यह व्यापार-संधि तीन सालों में बढ़ी हुई है। पहले सड़ में सीमाओं के दाना और साठ साठ किलोमीटर तक उ मुक्त व्यापार की बात कही गयी है। उसमें आयात निर्यात और विनिमय सम्बन्धी कोई नियंत्रण नहीं रखा गया है। इस व्यापार में कबल वहां चीनें शामिल की गयी है जो राखरा के काम में आती है। इसमें एक बहुत बड़ा लाभ यह होगा कि जहाँ एक दूसरे का अपन यहाँ तयार पाए के लिए बाजार में सक्रिय के। एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति हो पायेगी। इसके अलावा यह उम्मीद होगी सुधारन में सहायक होगा और दूसरों का जो इस समय बकार है उन्हें काम में सक्रिय। जिन में कबल एक बार सीमा पार करने और दो रुपये में कि न न जाने की तत्पर से अवसर है परंतु चारवा जारी एवं अनुचित मुनाफाखारी का रोकन तथा अधिक-अधिक गति का लाभ पट्टी चान की दृष्टि में शायद यह आवश्यक था।

दूसरे सड़ में यह व्यवस्था का गयी है कि दाना देश रुपये — आचार पर एक दूसरे का पचास कराट रुपये में य तब का मात्र भंडार रहे। न ता कोई अधिक नमद हान के कारण अपन स्वाधो न लिए इस अधिक का मात्र स संगी और न कहीं गौरी या त्रिशता में समान कि मात्र न के बाध्य होगा मत जब यह कि इस व्यापार का लाभ का समान रूप में प्राप्त में गता। फिर तब दूसरे का क्षेत्र जान बाल मात्र न ही व्यवस्था हम प्रकार की गया है कि बंगला देश का राखरा जानबाल समान में लिये के चोट लागू द्वारा कायम भांति के लिए। इस प्रकार में तब और भारत का सम्बन्धों का ट घात निज दृष्टि तथा मंगलरी भांति के कि यहाँ जा काही मात्रा में है और जिनकी मात्रा बंगला देश का बहुत है इस आशय में कि दाना मात्रा में व्यापार शक्ति का गति में सक्रिय। विन्मा पुस्तक परिवारों के विनिमय की न व्यवस्था इस संधि में की

गया है उनमें दाना दाना म सांस्कृतिक सम्बन्ध जार मुट्ठा हो सकेंगे।

यहाँ तक तामरे खड का प्रश्न है वह उस व्यापार में सम्बद्ध है जो विश्व म होता है। नरिध में यह व्यवस्था है कि दोनों देश एक दूसरे के यहाँ म काड भा जान उन मुद्रा म चुकता करन के साधार पर भगा सकेंगे। भारत के पास विश्व म मुद्रा कम है किन्तु उस व्यवस्था में न बगल देश का बहुत मद्र मि सगा जिसके पास विश्व मद्र का बहुत अभाव है और जिस मद्र चीजों का आवश्यकता है जो भारत म बाहर म जाता है।

प्रधान मन्त्री श्रीमती गांधी की तीन दिन का टाका यात्रा के बाद जो सुबुद्ध घोषणापत्र काजित म्मा समे कहा गया था कि दोनों देशों के प्रधानमन्त्रियों ने परम्परागत व्यापार के पुनर्जीवन के सिद्धांत जो सामा व्यापार समझौते का दात को स्वाकार कर लिया है। साथ ही उसमें यह भी कहा गया था कि इस मान के अंत तक सम्बद्ध समझौता पर न नौ म्मा के अस्तित्व हो जायग। उस मान पर जो पंचम वर्षीय मधि का गया म्मा घाग पांच म भी कहा गया था कि व्यापार के क्षेत्र म दानों देश अपने पारस्परिक सम्बन्ध का निमित्त करग। अब भारत बगल देश व्यापार मधि जो सामन आया वह उन सब का हा परिणाम था।

भारत बगल देश के मवितताता के रूप में सामन आया था। इस प्रश्न में पाकिस्तान के साथ उसका जो मुद्दा हुआ उसमें यह एक विश्व के रूप में खट हुआ। बगल देश के एक कराड शर्णाधिकियों के लिए समन जो कुछ किया वह एक कहाना है और उसके लिए बगल देश अपने का भारत के प्रति अनुमृतात समझता है। नना ही नहा उन शर्णाधिकियों के अपने हा म में पुनर्वास तथा बगल देश के जाधिक एक औद्योगिक पुनर्निमाण में भारत जो योग दे गया था वह भी किता म छिपा नहीं था। एना मूरत म भारत चाहता ना अपना उस विनिष् स्थिति का बगल देश के साथ व्यापार समझौते के मित्रित्व म पायला उठा सकता था। उस अपने मान म गल सकता था जोर उसके यहा न एना मान प्रति माया में के सकता था जिसका सम आवश्यकता है और जिसके निदान न यह विश्व मुद्रा अतिन कर सकता था पर उस व्यापार समझौते म एसा कुछ नहीं किया गया।

दानों देशों — बाव जो म म्मा सति हूँ उनमें कहा गया था कि वे अपना मित्रता जो प। आपन की समानता और पारस्परिक लाभ — सिद्धांतों के आधार पर आरेंगे। कन्ना न म्मा कि व्यापार-मधि करन पर उन दोनों सिद्धांतों का पूरा-पूरा पालन किया गया। उसमें क्या का एसी गल नना थी जिना किता भा पत्र का और उ स्वाय म्मता आरणा का पालन करकना हा। कीमि का गया था कि उस सति का म्मा न समान रूप म म्मा नठा मक। म्मा म्मा पत्र का और म एक म्मे और मान्याराण नहया का प्रताक था। यह कारण है कि सम का म्मा न। एना जो यह आण कन्ना म्मा नती होगा कि समति न ननों ननों के बाव म श्री और म्मयो का और अधिक म्मा आधार म्मा न म्मा। म्मपि यह सति एम म्मा की है किन्तु यह निश्चय ही एम म्मा आधार को नकार करती है जिससे न म्मा दानों देशों के बाव समान रूप म पारस्परिक म्मा दात व्यापार की बढि हागी अर्थात् उम्का म्मा म्मा अधिक बावक म्मा।

बगल देश के व्यापार-मन्त्रियों सिद्धांतों ने हम बात पर मित्रास म किया कि दोनों देश समन्वय की च म्मा जाति की रकावत का टोहन के लिए म्मसकृप है। उस अनुसार आवश्यकताओं के बहुत म व्यापार में कालगी होगी और व्यापार में

बड़ोत्तरी के साथ दोनों देशों की निकटता भी बढ़ेगी। भारतीय विदेश व्यापार मंत्री अलिमनारायण मिश्र ने समझौते पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस समझौते को केवल व्यापार समझौते की दृष्टि में ही नहीं देखा चाहिए। दोनों देशों की सीमा पर होने वाले घातकों को रोकने के लिए यह समझौता बहुत महत्वपूर्ण है। इस सामान्य आर्थिक सम्बंध पुनर्स्थापित होगा।

इस प्रकार ८२वें पर भारत-बंगलादेश के सम्बंध घनिष्ठ बन रहे हैं।

शिमला समझौता और बंगला देश—बंगला देश के अख्युक्त ने भारत और पाकिस्तान के सम्बंधों में एक नये तत्त्व का समावेश कराया। अतः जब शिमला में भारत और पाकिस्तान के शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ तो उसके पहले भारत सरकार ने बंगलादेश की सरकार से पूरा विचार विमर्श कर लिया। शख मुजीबुररहमान को शिखर वाता में भारतीय स्थिति के संवेदक में अवगत कराने के लिए विदेश मंत्रालय की नीति निर्माण समिति के अध्यक्ष डी. पी. धर की टोका भेजा गया। वाता शरम्भ होने से पूर्व भारत सरकार और बंगला देश की सरकारों के बीच सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तारपूर्वक विचार विनिमय हुआ। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न युद्धादिपक्षों का था। शख मुजीब ने भारतीय नेताओं को स्पष्ट बता दिया कि बंगालियों के विरुद्ध अपराधों के दोषी सैनिकों पर अभियोग चलाने के लिए वे दृढ़ प्रतिष्ठ हैं। अतएव भारत ने उन्हें आश्वासन दिया कि बंगला देश के नेताओं से परामर्श के बिना वह बंगला देश में पकड़े गए युद्धादिपक्षों को छोड़ने का सिलसिला में पाकिस्तान से कोई समझौता नहीं करेगा। यह तय कर लिया गया कि इस प्रश्न को हल करने के लिए पाकिस्तान द्वारा बंगला देश को मांगी दवा और भट्ठा तथा मुजीब के बीच प्रत्यक्ष बातचीत आवश्यक होगी। यह कारण है कि शिमला सम्मेलन में युद्धादिपक्षों की वापसी के सम्बंध में कोई समझौता नहीं हो सका। राष्ट्रपति भट्टो पाकिस्तान में यह कहकर शिमला से चले कि युद्धादिपक्षों की रिहाई के प्रश्न को वे सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे और ऐसा उन्होंने किया भी। लेकिन भारत ने उन्हें स्पष्ट बताया कि बंगला देश की राय बिना उनके बारे में कोई फैसला नहीं हो सकता और इसके लिए यह जरूरी है कि पाकिस्तान बंगला देश को मांगता है।

प्रधान मंत्री शख मुजीबुररहमान ने एक-दूसरे के लिए यह संकल्प दोहराया कि दोषी युद्धादिपक्षों पर बालाश्रम में हल होना चाहेगा। शिमला शिखर वाता पर यह उनका तात्कालिक प्रतिक्रिया थी। शिमला में अख्युक्त ने मुझे न केवल समझौते पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करत हुए आशा व्यक्त की कि मुझे सहयोग और सम्भावना के साथ पुराना वाता को भूतकर बंगालियों के विरुद्ध घृणा और मर्त्यता के दानाकरण का समाप्त करण और समय रहत बंगला देश का मांगता प्रश्न करण। शिमला में हमारी आर्थिक व्यवस्था नहीं हो सकती जबतक वाता में बंगलादेश भी शामिल नहीं हो सकेगा। यह लिए पाकिस्तान का पहले बंगला देश का मांगता दनी हागी। शिमला समझौते पर बंगला देश के नेताओं को इन प्रतिक्रियाओं को भारत का पूरा समर्थन प्राप्त था।

शिमला समझौते पर बंगला देश की साम प्रतिक्रिया का अनुक्रम रहा। बंगलादेश के प्रमुख जनमानस यूज ने टिप्पणी करत हुए किता शिमला समझौते

न भारत के इस विचार को सहा मिल दिया है कि लोगों के आपसी सगठन व प्रयास और किसी बाहरी हस्तक्षेप के बिना नियमित न कर सकत है। समझौते की महान् उपलब्धि माना जायगा।

बंगलादेश और सुदुर्घत संघटन—9 अगस्त 1972 को बांग्लादेश ने सुदुर्घत संघटन का सम्मेलन बनाने के लिए प्रार्थना पत्र राष्ट्रिय किया। 11 अगस्त को सुरक्षा परिषद का वह केंद्र में चान के प्रतिनिधित्व बांग्लादेश के प्रस्ताव का विरोध करत हुए यह आगेय आया कि जब भी बंगलादेश में भारतीय सहायता माँगा है और बंगलादेश ने सुझा परिषद के गत रूप के प्रस्तावों को कार्यान्वित नहीं किया। चीन के प्रतिनिधित्व प्रार्थना पत्र को कार्यमूला में शामिल करने का विरोध किया। पाकिस्तान ने स्मरण किया कि बंगलादेश के प्रस्ताव की प्रार्थना पर तबतक विचार स्थिति आया जाय तबतक निम्न 1971 में सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव का वह पालन नहीं करना। उक्त प्रस्ताव में पाकिस्तानी मुद्रास्थितियों की आपसी का सुधार दिया गया था। तबतक सावित्य और भारतीय प्रतिनिधियों ने बांग्लादेश के प्रार्थना पत्र का अवलोकन समायन किया। भारतीय प्रतिनिधित्व ने इस बात पर सख्त ध्वज किया कि कुछ शक्तियाँ अनन्यस्य रूप से मानवात में शान्ति का प्रस्ताव कर रहा है। भारत के प्रतिनिधित्व समायन ने कहा कि पाकिस्तान और बंगलादेश के बीच नमस्कार को द्विपक्षीय बातों में ही किया जा सकता है। इस प्रकार की इच्छा स्पष्ट बंगलादेश के नेताओं ने व्यक्त की है इसलिए इस अद्य पर बंगलादेश के प्रस्ताव का नहीं राजा जा सकता। तबतक चान ने बांग्लादेश के प्रयोग करके भारतीय प्रयास का एकत्र नालाभ्यव कर दिया।

भारत बंगलादेश मासृति समझौता—चान का इस कारवाह के दृष्टिकोण भारत और बंगलादेश का सहयोग देता रहा। 30 अगस्त 1972 का भारत बंगलादेश मासृति समझौता हुआ करत हुए संयोजन का परिणाम था। इस समझौते के द्वारा दोनों देशों के बीच मासृति स्थिति स्थिति और सन्तुष्टि क्षेत्रों में सहयोग और सन्तुष्टिपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने का व्यवस्था का गयी। समझौते के अंतर्गत दोनों देशों के शिष्ट संस्थाओं के बीच संयोजन बनाने का प्रयास करेगा और मासृति स्थिति स्थिति एवं करके करके न प्रतिनिधिमण्डल के आदान प्रदान को प्राप्ताह करेगा। समझौते में यह भी प्रावधान है कि दोनों देश मासृति वैधानिक और शिष्ट नामों पुस्तकों परिवर्तनों प्रकाशनों आदि का आदान प्रदान करेगा। दोनों देश ने बात पर भी सहमत हुए कि समझौते के कार्यान्वयन का समय समय पर तीव्र के लिए एक सुदुर्घत आयोग गठित किया जाय।

भारत विरोध बानावरण—बंगलादेश के निवासियों में मतभेद और अतन्त अनन्त घृणक हो जाने का एक कारण यह था कि पाकिस्तान पश्चिम में विशालकाय अफगानिस्तान सामाजिक स्थितियों के लिए दया रहा। उन्नी सन्तुष्टि क्षेत्रों और पश्चिम अफगानिस्तान के राजा उ था। पूर-मुस्लिम क्षेत्रों का और अफगानिस्तान के राजा उ था। पूर पाकिस्तान का अन्तर्गत निम्न तन्त पक्षों के लिए पूर्वोक्तियों के राजों में गेम्ता करता चाहत था। पर पश्चिम पाकिस्तान द्वारा संचालित स्थिति न करत यह न भव नहीं हो सता। बंगलादेश का सुझा जो स्वाधान्ता के बावत सन्तुष्टि था कि न केवल उपर इन पक्ष पूर्वोक्तियों में सम्बन्ध बनाने का प्रयास करेगा। इस तरह के अन्तर्गत अन्तर्गत 1972 में बंगलादेश के विदेश मंत्री अन्तर्गत अन्तर्गत न नपाय प्रती पाकिस्तान के राजा उ था। पूर अन्तर्गत अन्तर्गत न नपाय प्रती पाकिस्तान के राजा उ था। पूर अन्तर्गत अन्तर्गत न नपाय प्रती पाकिस्तान के राजा उ था।

हि बगुना दश दक्षिण पश्चिमा वा एक भाग है। वो भोगाग्रि और रावनातिक वातावरण मे उस अपन आपसो डालने की कोशिश करना होगी। पाकिस्तान की तरफ बगुना दश पश्चिम एशिया की ओर प्रवाह क लिए नो रुक सक्ता।

विश्व मन्त्री का नवाग्राजो ने तब बड़ी तरफ से अग्रले गगनो जग
गग। यह वग मया कि वगग गग मिया ने सोज म पव शिमिमु है पचिम
अमिमुग तनी। तारम यह कि मात (ने वागग गग व पचिम मे ह) म उमुग
विचा होने गग है। वगग यग भी मगगग वा विचू कि पवगिमया व गग अमरीकी
प्रमा म है सगिग वागग गग कगग अमरीकी प्रमा म जा रहा है।

1972 के अंत में वल्लभ भट्ट ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति जो प्रयास किए थे, इससे पता चलता है—पश्चिमी पट्टा में और वल्लभ भट्ट की अंतर्निहित नीति। अतः 1972 में ब्रिटिश विदेश सचिव सर एल्गन ह्यूंस होम तथा राष्ट्रपति निवृत्त—जिंदग दावान कोमोती के साथ उनके साथ भी पश्चिमी पट्टा में सन्धि हो गई। ब्रिटेन और पश्चिमी रा. के साथ भी जमीनी भी प्रभावशाली शक्ति सलुत्तन की रातों में बना हुआ है। वे वल्लभ भट्ट का भारत और मोविपत मध्य में प्रभावशाली मानते हैं और चाहते हैं कि वल्लभ भट्ट और पश्चिमी रा. में मध्य हो जाय। अतः वे वल्लभ भट्ट के साथों पर अपना प्रभाव बढ़ाने में मग्न हैं। वे भारत तथा वल्लभ भट्ट का मंत्री की जागेचना खुद आमनी करने लकिन वल्लभ भट्ट के नेता के साथ उनका है कि भारत ही तो सारी दुनिया लगे है और इस आधार पर मध्य मल्लभ भट्टी फार्म का प्रयास करते हैं।

इस बातों का भी मर्मट वगैरहों जातिरिक्त राजनीति ने भी एक भविष्य का निर्माण किया है। मध्य 1973 में बंगला देश में आम चुनाव हुए। नए अठ्ठासी पार्टी के विरोधी दलों के साथ में संघटना गठित करने का प्रयास कुछ भाजन विरोधी दलिकेणों ने अपनाया और भारत विरुद्ध प्रचार का प्रचार किया। नेहरू जवाहीर लाल नेहरू और मोरारजी देसाई ने इसी प्रयास का विरोध किया। 17 जुलाई को भारतीय सरकार ने बहिष्कार का फैसला किया। उन्होंने मांग की कि बंगलादेश को भारत की सहायता से सशस्त्र सैन्य बल भेजने चाहिए। इन सारी बातों के बावजूद भारत और बंगला देश के सम्बन्ध पर स्थिति स्थिर रह गई। क्योंकि बंगला देश ने अपने वैदेशिक सम्बन्धों में तत्पूरा सह सहित्व गुट निरपेक्षता और उन अन्य मित्रताओं के ताल पर बनाने का निश्चय किया है जिनमें पश्चात् आधारित था। बंगला देश और भारत की निकटता का एक कारण दोनों देशों की दृष्टि में सिद्धांतसम्यक् भी है। दोनों देशों का यथा का जस का आधार यह है कि भारत बंगला देश की मुक्ति या आर्थिक पुनर्निर्माण का प्रयास कर रहा है। इस धर्म का आधार विचार साम्य और ऐतिहासिक एवं भौगोलिक कारण है। मध्य का आधार यथा है सम्बन्धों में।

नोएल्ले शास्त्रिणः समझते और मानते हैं— हमें ईसाई ही जिस
कारण इतर पर भारत और बांग्लादेश के बारे में निरंतर घनिष्ठ सम्बन्ध बना रहा है।
पाकिस्तान के प्रति अपना सम्बन्ध के निर्धारण में भारत ने बांग्लादेश की भाषा बर्क
वभा बाइ एक्टर का हार नहीं दी। मुद्रा या तब से मानवीय प्रमा पर
मिलार लाने के बाद भारत और बांग्लादेश ने 18 जून 1973 को मित्रता
का एक निसुखी वाचकम तैयार किया और निम्नलिखित प्रावधानों के

मुख्यतः एक मुस्लिम बहुसंख्या का देश है जहाँ मुसलमानों की आबादी सात करोड़ है। तमिलुनाडु में सम्मेलन के आयोजकों ने बंगला देश का भी स सम्मेलन में शामिल करने का विचार प्रस्तुत किया। लेकिन बंगला देश के प्रधानमंत्री जल्ल मजीबुद्दीन ने साफ-साफ़ कह दिया कि जल्ल मजीबुद्दीन जिसे अब बंगला देश का मान्यता दी जाती है वह पाकिस्तान की भूमि पर है। यह सम्मेलन में उनके भाग लेने का वादा प्रश्न नहीं उठता। इस पर कुछ अन्य मुस्लिम राज्यों ने बाध पड़ा कि पाकिस्तान को मान्यता देने पर राजी कर दिया। पाकिस्तान द्वारा मान्यता मिलने का पक्ष मजीबुद्दीन ने स्वामी सम्मेलन में भाग लेने के लिए गहोर पहुँचे।

मुस्लिम राज्यों के स्वामी सम्मेलन को भारत ने कभी खी निगाना नहीं दिया। राजनीति के मजबूतीकरण की प्रक्रिया को उसने सदैव विरोध दिया है। लेकिन इसका भी सम्मेलन में जल्ल मजीबुद्दीन का भाग लेने में भारत का बमना-बम यह विश्वास है गया कि अब अनिच्छित राज्य के प्रतिनिधि हान के नाते कटकर पाकिस्तान राजनीति का विरोध करेगा।

पाकिस्तान द्वारा बंगलादेश को मान्यता प्रदान करने का निषेध कई दृष्टियों में महत्वपूर्ण था। इसके पक्षरूप पाकिस्तान और बंगलादेश के पारस्परिक सम्बन्धों के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। दोनों देशों के मध्य प्रथम सम्बन्ध सम्पन्न पायम होने में उनकी सामान्य समस्याओं के समाधान में काफी सहाय्यता दी गयी। यह दृष्टिकोण में भारत ने इसका हार्दिक स्वागत किया।

अप्रिल 19 4 की त्रिपलीय वार्ता—बंगलादेश को मान्यता में इस बात का भी आसार नजर आने लगा कि बंगलादेश 3 जून 195 युद्धांतियों के सिंगापूर अधिष्ठापक न्यायसंहार तथा अन्य अधिनियमों के लिए मरुमा चलाने का निषेध किया था उसको सम्भवतः टाट दिया जाय। शायद मजीब ने कहा भी था कि हम बात का निर्णय दिल्ली सम्मेलन के मद्देन में पाकिस्तान भारत और बंगला देश के नेताओं के त्रिपलीय वार्ता में किया जायगा। 5 अप्रिल 1974 को इस त्रिपलीय वार्ता के लिए भारत पाकिस्तान और बंगलादेश के त्रिपलीय वार्ता का सम्मेलन नयी दिल्ली में शुरू हुआ। सम्मेलन शुरू होने के पहले भारत और बंगलादेश के अधिकाधिक में विचार विमर्श करने अपनी रणनीति का निर्धारण कर लिया था। चार दिनों की वार्ता के बाद 9 अप्रिल को तीनों देशों के प्रतिनिधियों ने एक समझौता पर हस्ताक्षर कर दिए। समझौते के अनुसार बंगलादेश 195 पाकिस्तानी गद्दापरा जयों का मुक्त करने पर राजी हो गया और पाकिस्तान भी बंगलादेश में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों का वापस लेने के लिए राजी हो गया। यह त्रिपलीय समझौता भारतीय उपमहादीप की स्थिति उद्घाटन तक सामान्य हो गयी।

भारत बंगलादेश समझौता (मई 1974)— जून 7 म 1971 में त्रिपलीय समझौते को हरा दी उनके के लिए भारत का प्रयास प्रयत्न रहा। भी कम में भारत ने प्रधानमंत्री शरण मजीबुद्दीन को भारत यात्रा के लिए आमंत्रित किया। 12 मई 19 4 का कर लिफाफे राजनयिकों के पर बाध मजीबुद्दीन को आये। यह बंगला पर माना देश के बीच कई समझौते हुए। एक बार मजीबुद्दीन मोमिन को सफल हुआ। भारत और बंगलादेश की सीमाएँ काफी तण्डित हो। 1947 में त्रिपलीय विभाजन हुआ था उसके कई स्थानों पर विवादित था जो कि मजबूत-बंगलादेश में पड़ता था और अंग्रेज भारत में सामान्य का अधिका हिस्सा बंगला देश में और अधिका भारत में। इन तमाम समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह जरूरी हो गया था कि जहाँ

मई 1974 के उस समझौते में दाना देशों का समर्थन और भी धनिष्ठ हुआ है। किन्तु वगनायेज की सरकार और जनता के मन में भारत का लेकर किसी तरह की शंकाएँ नहीं हैं। जिन भारत सरकार की यह जिम्मेवारी है कि वह आगे कोई ऐसा पाय नुहा कर जिसमें कि वगनायेज की जनता या सरकार के मन में भारत के प्रति किसी तरह का संशय पैदा हो। भारत की यह जिम्मेवारी हो जाती है कि वह वगनायेज देश में 1971 में अजित सम्भावना का स्थायी बनाने के लिए परास्त्र प्रयत्नशील रहे और वगनायेज देश की जनता को यह संस्य बराये कि भारत में उस वक्त भी किसी तरह की आशंका न हो सकती।



अफगानिस्तान के बीच तीन झाड़ियाँ हैं। इन झाड़ियों के परिणामस्वरूप अफगानिस्तान परी तरफ अफ जों के प्रभुत्व और नियंत्रण में आ गया।

1921 में अफगानिस्तान को पूर्ण स्वतंत्र और सम्प्रभुता सम्पन्न देश के रूप में मान्यता मिल गयी। 1924 में अफगानिस्तान के युद्ध सामंती ने शाह अमीनुल्ला के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1929 में नाज़िरशाह अफगानिस्तान का नया अमीर घोषित हुआ। वह अधिनायक अफगान प्रजापति को अपने नियंत्रण में आने में सफल हो गया। नाज़िरशाह की हत्या के उपरान्त उसका पुत्र जहीरशाह अफगानिस्तान की गद्दी पर बैठे। 1934 में अफगानिस्तान राष्ट्रमण्डल का संस्थापक बन गया और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण पर उसका स्थापक भूत। द्वितीय विश्व युद्ध में उसने तटस्थता की नीति का अंगक्यन किया। भारत के विभाजन के बाद उसकी तरह पानिस्तान के साथ जुग बंधी।

अफगानिस्तान के साथ भारत का सम्बन्ध

भारत और अफगानिस्तान का सम्बन्ध अत्यन्त प्राचीन है। कल्प के खण्डहर बामिआन से बूढ़ की विष्णु प्रतिमा वनिक तथा अय्य कुपाण राजाओं के सिक्के गजनी के उत्कीर्ण प्रस्तर खण्ड नगराम के तोरण तथा काबुल में बाग के पत्थर और आसामाई की मूर्ति भारत अफगानिस्तान सम्प्रदाय के ऐतिहासिक प्रतीक हैं। अफगानिस्तान के प्रबुद्ध बग का एक हिस्सा स्वयं को जायवनीय बहान में गौरव का अनुभव करता है।

1919 में अमानुशख के गताब्द होने से भारत और अफगानिस्तान का सम्बन्ध में गताब्द आया। यह एक प्रगतिशील विचार का आन्वीषण था और भारत राष्ट्रीय आन्दोलन में उसकी पूरी सहानुभूति थी। उस दिनों काँग्रेस पर गायत्री के नृत्य की स्थापना होने से ब्रिटिश विरोधी आन्दोलन में जड़ पड़ता। मेम समझ में अमानुशख ने ब्रिटिश वायसरॉय को लिखा था कि जयन्त आन भारतीयों को आजादी नह दे देत तथा रोनेट ऐक्ट को खत्म नहीं करत अफगानिस्तान और ब्रिटिश सरकार का बीच सम्बन्ध पूरी तरह ठीक नहीं हो सक्ते। भारतीय नेताओं की भी अफगानिस्तान का प्रति पूरी सहानुभूति रहती थी। पश्चिम नेहरू ने अपनी जायम् तथा में अफगानिस्तान का प्रति अपन सहानुभूति विचार व्यक्त किये हैं।

पश्तूनिस्तान की मांग—भारत की स्वतंत्रता और विभाजन के पश्चात् विदेशी नीति के क्षेत्र में अफगानिस्तान के सम्पन्न अनेक प्रबल विद्वत् हो गये क्योंकि अफजों द्वारा छोड़ी गयी पश्तूनिस्तान की समस्या अब तीव्रतर रूप में दृष्टि हुई। अफगानिस्तान की सरकार ने स्पष्ट रूप से डरण्ड रेखा की मांगता तो वापस कर ली पर तु यह मांग की कि डरण्ड रेखा के आर पार जो बहुनक्षत्र पठान रहते हैं उन्हें स्वशासन का अधिकार दिया जाय और उनके लिए पश्तूनिस्तान के नाम से एक अलग राज्य कायम किया जाय। अफगानों को इस बात का दुःख था कि सारा भारत आजाद हो गया लेकिन वे पश्तान जो भारत के अंग नहीं थे और जिन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में प्रमुख हिस्सा लिया था उन्हें कोई नाम नह दूना। उनका दुःख तब जोड़ बढ़ गया कि पानिस्तान अब इस्लामी राष्ट्र द्वारा भी अफजों के सम्पन्न हो नीति बनाने की घोषणा की गयी। अफगानिस्तान के शासकों ने वापस

न दाय कर रहे हैं। यद्यपि चीन से मध्य सतते हुए अफगान सरकार सारी सहायता वरसता है तथापि चीन अपनी विविध राजनयिक सहायता प्रभाव अपनी स्थिति सहायता की तुलना में कहीं अधिक बड़ा लगता है।

चीन के प्रभाव वृद्धि से अफगानिस्तान में सोवियत संघ का रुचि बढ़ी है। सोवियत नेता इस बात के लिए बलपूर्वक हैं कि अफगानिस्तान में चीन का प्रभाव नहीं बढ़े। इसी कारण से सोवियत प्रधान मंत्री कोसीगिन ने मई 1969 में अफगानिस्तान का दौड़ा की।

नतीजा बताया कि अफगानिस्तान में अफगानिस्तान के प्रति अपना नीति का निष्पत्ति करना है। मास्कुतिक और गलपिक धर्म मसहारा करके भारत अफगानिस्तान पहिली राष्ट्र के साथ अपनी मित्रता बढ़ा सकता है। यह एक अधिक सहायता का प्रश्न है जो भारत के लिए अत्यंत ही कठिन कार्य है क्योंकि अफगानिस्तान का मध्य होने के लिए उसके पास ऐसा कोई साधन नहीं है। अफगानिस्तान सरकार का भारत अफगानिस्तान के रूप में कितना सहायता दे सकता है यह इस पर निर्भर करता है कि भारत अपने एक अच्छे पड़ोसी मित्र के लिए स्वयं कहीं तक अपना पैसा खर्च को तैयार है। एक भारत ने अफगानिस्तान का अधिक धर्म में काफी सहायता दी है लेकिन मास्कुतिक और गलपिक क्षेत्र में सहायता को भी अधिक बढ़ाया जा सकता है।

(2) लका और भारत

लका भारत के दक्षिणी पश्चिम-पूर्व के समीप एक छोट आकाश का देश है। इसका क्षेत्रफल 58,314 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या 1.5 करोड़ है। सांस्कृतिक अंशों पर भारत के साथ यह भी बहुत अधिक समानता है। सामरिक दृष्टि से भारत के लिए इसका अत्यंत महत्व है कि द्वीप के इतिहास पर भारत के घटनाक्रम और विहंगम का बहुत प्रभाव पड़ा है। सामरिक महत्व का जहाँ होने से भारतीय महाद्वीप पर आक्रमण और अधिकार बनवाया किसी भी महाद्वीपवासी अतिरिक्त की गृह दृष्टि से यह द्वीप बच नहीं पाया। सोवियतों ने लका से लगे दोस्रो अंशों के मध्य तक यह यूरोपीय उपनिवेशवादी अतिरिक्तों के चंगुल में फँसता रहा। पुनर्वास तदुपरांत हालैंड और अंत में अर्थशास्त्र ने यहाँ पर अपना अधिकार स्थापित किया। 1947 में ब्रिटन ने इस द्वीप का स्वतंत्र बन देने का निर्णय किया और 4 फरवरी 1948 को यहाँ से ब्रिटिश शासन का अंत हो गया।

भारत विरोधा गुरु — स्वतंत्रता के बाद जब 1953 में जॉन कोटेलाला (John Kotelawala) लका के प्रधान मंत्री थे उस समय भारत और लका के सम्बन्धों को बहुत अच्छा सा संबंध नहीं कहा जा सकता है। (इदम मनामायक सा के प्रथम प्रधान मंत्री थे।) यद्यपि स्वतंत्र होने के बाद भारत ने अनेक बार यह स्पष्ट कर दिया कि वह लका की स्वतंत्रता और संप्रभुता का पूरा सम्मान करता है फिर भी कुछ कारणों से लका की सरकार भारत के प्रति गुवायु बनी रहा। यद्यपि लका की सरकार जिम्मा मनी गुप्त में शामिल नहीं हुई और लका लक्ष्यता की नीति का हा अनुसरण करता रहा लेकिन लका मुख्यतः पूरा तरह पर लका गुप्त का और लका बह नाम्बवादी गुप्त का विरोधी बना रहा। इस नीति के कारण लक्ष्यता भारत का भय कम कर रहा था। इसी कारण लका का मलेशिया (Trincomalee) का नौयुक्तिक लड़ा और कटुनायक (Katu

mayako) का हवाई जहाज ब्रिटिश नियंत्रण में रहने देने का निश्चय किया। सत्र की ससद् में जब सरकार के इस नियम का विरोध हुआ तो जान कोटेलवाला ने इसको उचित ठहराते हुए कहा कि "का क" प्रति भारतीय साम्राज्यवाजियों का महत्वाकांक्षा की ध्यान में रखते हुए ऐसा करना मजबूरी थी है।

उपनिवेशवाद के सम्बन्ध में दोनों देशों के प्रतिनिधियों में महान् अंतर था जोर इस प्रश्न पर 1955 के वांग सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू और कोटेलवाला ने खी टक्कर हो गयी। वांग सम्मेलन की बुलावे में लकाने भारत के साथ सहयोग किया लेकिन जब सम्मेलन शुरू हुआ और उपनिवेशवाद पर वहाँ एक प्रस्ताव रखा गया तो कोटेलवाला ने कहा कि हम पश्चिम के उपनिवेशवाद के साथ साथ सावित्र संध के उपनिवेशवाद का भी निन्दा करनी चाहिए। पूर्वी यूरोप के कम्युनिस्ट देशों का उने सावित्र संध का उपनिवेशवाद और एशिया तथा अफ्रीका में पश्चिम के उपनिवेश के साथ उनकी तुलना की। इस प्रश्न पर सम्मेलन में एक भारी बवंडर खड़ा हो गया और हस्तक्षेप करते हुए नेहरू ने कहा कि सम्मेलन में भाग लेनेवालों को यह नहीं भूना चाहिये कि वे अपने अपने देशों की सरकारों के प्रतिनिधि हैं। इनमें से बहुतों का सम्बन्ध बेकोसतावाजिया पोर्बंड जति देशों से है और वे समुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य भी हैं। संध उ हैं पूण सप्रभताशुक्त राष्ट्र मानता है। इस हान्त में उ हैं उपनिवेश कहना उचित नहीं है।

भारत और लका के बीच मनमुटाव का एक दूसरा कारण पाल्क जलमार्ग (Palk Strait) में स्थित एक छोट सटापू की लेकर था। कच्छाणीव (Kachchaivu) द्वीप के स्वामित्व के लिए भारत और लका के बीच कुछ मतभेद उत्पन्न हो गया। 1956 में भाषा का लेकर लका में कुछ उपद्रव हुए। लका की सरकार ने सिंहली की लका का एकमात्र राजभाषा घोषित करने का नियम किया। पहले तमिल भाषा की भी यह स्थान प्राप्त था। अब तमिल भाषाभाषी लोगों ने इसका विरोध किया और इसके कारण कुछ उपद्रव भी हुए। लका के सरकारी दस्ता में ऐसा विवाद किया जाता था कि इन उपद्रवों के पीछे भारत का भा हाथ है। लेकिन इन सभी समस्याओं से बढ़कर लका में बसने वाले प्रवासी भारतीयों की नागरिकता की समस्या थी जिसके कारण दोनों देशों का सम्बन्ध खराब होता रहा। इस प्रश्न पर हम बाद में विचार करेंगे।

भारत के प्रति लका की नीति में परिवर्तन—जिम ठजी के साथ वाटस वांग लका का पश्चिमी गुट के साथ आवद्ध किये चले जा रहे थे उसकी देखकर प्रपनिवादी विचार के कुछ लकावासी बड़ धन्य थे। अंत जब 1956 में चनाव हुआ तो कोटेलवाला के दल को पीपुल यनाइट फ्रंट ने पराजित कर दिया। इस फ्रंट

1 M S Rajan *Indian World Affairs* p 385

कोटेलवाला का यह आरोप सरकार के एम पणिक्कर के भाषण पर आधारित था जिसमें उसने कहा था कि भारत की सुरक्षा के लिए त्रिकोमाली पर भारतीय प्रभुत्व का कायम होना आवश्यक है या कम से कम वहाँ भारत का नौसैनिक अड्डा होना चाहिए। पणिक्कर एक सरसरकारी व्यक्ति को हैमियन से बोले रहे थे और इसलिए उनके इस भाषण को महत्त्व नहीं दिया जाना चाहिए था। कोटेलवाला के आरोप का खण्डन करते हुए 16 सितम्बर 1954 को नेहरू ने कहा कि लहान कभी किसी भारतीय मुनरी निन्दा का प्रतिपादन नहीं किया। लका के प्रधानमंत्री का विचार प्राप्ति पर आधारित है। इसलिए वही (एम एम राजन की पुस्तक)।

प्रवासियों को वही अधिकार प्राप्त थे जो लका के निवासियों को थे। लेकिन 1948 में जब लका स्वतंत्र हुआ तो यहाँ की सरकार ने यह अनुभव किया कि इतनी बड़ी संख्या में भारतीयों के लका में रहने (इस समय भारतीयों की संख्या 950 000 थी) के कारण वहाँ का मूल निवासियों को पर्याप्त अवसर मुम्भ नहीं हो पायगा। अतः उन्होंने विधान भारतीयों को भारत वापस भर्जन का निर्णय किया। लका की संसद में तुरन्त एक अधिनियम बनाया जिसके आधार पर भारतीय मूल के लोगों को मनाधिकार से वचित कर दिया गया। और उन्हें यह कहा गया कि लका की नागरिकता प्राप्त करने के लिए वे इस बात का समूत दें कि उनका जन्म लका में हुआ है अथवा 1939 से वे लका में निवास कर रहे हैं। लका की सरकार का ध्येय यह था कि वह ऐसी व्यवस्था करे ताकि कम से कम भारतीयों को वही की नागरिकता प्राप्त हो और सभी अनागरिकों को लका में हटाया जा सके। लका सरकार के इस उद्देश्य के मूल में तीन चार बातें थी

(1) आर्थिक कारण से भारत के तमिल मजदूरों और लका के सिधली लोगों के बीच प्रति निता स्वाभाविक रूप से पैदा हो गयी। सिधली लोग यह चाहते थे कि प्रवासी भारतीय वापस लौट जाय क्योंकि उनके कारण सिधली लोगों का रोजगार के अवसर पर वचित रहना पड़ता है। लका की सरकार को अपने देश के निवासियों के अधिकारों के लिए कुछ करना था।

(2) लका में रहनेवाले भारतीयों का दृष्टिकोण अत्यन्त सदनक था। वे वर्षों से लका में रहने के बाद भी स्थानीय नागरिकों के साथ अभी सम्मिल नहीं सके थे। उनकी जड़ अभी तक भारत में ही बना हुई थी। प्रतिवचन वे अपने परिवारों के भारतीय निवास स्थानों को जाते थे और उनके विवाह संबंध भी भारत में ही होते थे। लका के लोगों का यह कहना था कि चूँकि लका के साथ उनका कोई मानसिक अथवा आध्यात्मिक लगाव नहीं है इसलिए उन्हें अपने मूल देश को लौट जाना चाहिए।

(3) लका के अनुसार प्रवासी भारतीय लका की अर्थ व्यवस्था पर भारी बोझ सिद्ध हो रहे थे। भारतीय मजदूर वहाँ कुछ भी कामान थे उन्हे भारत को भेज दते थे अथवा उन भारत में सब करत थे। लका के विदेशी विनियम पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता था।

(4) इस समस्या का एक राजनीतिक पहलू भी था। भारतीयों में साम्प्रदायिक घड़न बढ़ा पड़ था और इस आधार पर वे लका के चुनाव का बहुत हल तक प्रभावित करत थे। इसी कारण 1949 में एक निर्वाचन कानून पास करके भारतीयों का मताधिकार में वचित कर दिया गया।

नहर कोटसवावा समझौता — भारत सरकार ने इस समस्या का हल करने के लिए लका की सरकार से वासता आरम्भ की। जून 1953 में जवाहरलाल नेहरू और नरेंद्र मोहनदास ने समस्या पर लगान में विचार किया। तब वहाँ नाराज निवासियों ने नानायक में भारतीयों के अनिवार्य वापस (Compulsory repatriation) पर जार दिया जिससे पतन नहल न स्वाकार नहीं दिया।

जानवरी 1954 में पंडित नेहरू ने नानायक के उत्तराधिकारी जीवावाटे-वावा के समस्या पर वासता करत के लिए निम्नी आर्माचन किया और बाद में यह प्रश्न पर एक समझौता हुआ जिसको नेहरूवाटवावा समझौता कहते हैं। इस समझौते के द्वारा यह निर्दिष्ट हुआ की भारत में लका की नागरिकता प्राप्त करत

व्यक्तियों के भविष्य का निर्णय एक जग समझौते पर छाँट लिया गया।

(iii) भारत को गेटाये जाने वाले व्यक्ति जगल पंद्रह वर्षों में एक योजना के अनुसार निश्चित संख्या में प्रति वर्ष भारत आते रहने और भी प्रकार-का द्वारा भी नागरिकता प्रदान करने का वाप पंद्रह वर्ष में इस प्रकार की एक अनुपातिक योजना द्वारा पूरा किया जायगा।

(iv) भारत को गेटाये जानेवाले व्यक्तियों को उनके भारत जाने के समय तक सत्ता का सरकार सभी प्रकार की ऐसी सुविधाएँ प्रदान करेगा या जिन विदेशी नागरिकों को प्रदान की जाती हैं परंतु उहें विदेशों का धन भेजने का सुविधा नहीं दी जायगी।

(v) भारत को गेटाये समय ऐसे व्यक्ति अपने साथ उम्र समय के नियंत्रणों के अनुसार अपनी कमाई की पूँजी आदि ले जा सकेंगे जिसका सीमा चार हजार रुपये से कम किमा हाँत में नहान होगी।

इस समझौते के द्वारा भारत और सत्ता के बीच भारतीय प्रवासियों की समस्या का शांतिपूर्ण हल निकाला गया किंतु कतिपय क्षत्रों में तोना दो दशा में यह आलोचना का पात्र बना। भारत में कहा गया कि सुविधाएँ तक सत्ता में निवास करनेवाले सभी व्यक्तियों को सत्ता द्वारा ही नागरिकता प्रदान की जाना चाहिये थी। भारत द्वारा उहें वापस लाना स्वीकार करना अनुचित है। सत्ता में समझौते का आलोचना इस आधार पर हुई कि इसमें अनुषंगों की एक वस्तु के रूप में मान कर उनका बटवारा सम्पत्ति के बटवारे की तरह किया गया है जिसमें व्यक्तियों की इच्छा का कोई स्थान नहीं है। आलोचकों के अनुसार 1 50 000 व्यक्तियों के भाग्य का निपटारा करना और 8 25 000 व्यक्तियों के भाग्य का निपटारा नहान करके भी उनका अंतिम निर्णय पंद्रह वर्षों के उभे समय में करना समझौते का बड़ा भारी दोष है।

कच्छादीव का प्रश्न — मार्च 1968 में कच्छादीव के स्वायत्तता का सत्ता भारत और सत्ता के बीच एक विवाद गह हुआ गया। हिन्द महासागर का एक खाड़ी में स्थित निजन कच्छा दीव पर भारत और सत्ता दोनों देशों की सरकारों ने दावा किया। केवल मार्च महान को छ डकर पूरे वर्ष यहाँ आँमियों के जगन नहीं हाँत। मार्च के महाने में जब यहाँ मसीही सेंट एथनी का एक मनाया जाता है तब यहाँ भारत और सत्ता दोनों हाँ देश से तीक्ष्णप्राप्ती पहुँचन हैं। 1968 के मार्च में इस झेले के अवसर पर सत्ता की सरकार ने द्वीप में अपनी पुलिस भेज दी। भारत में इस पर विरोध प्रकट किया गया और दोनों देशों का सरकारी के दावे प्रतिदावे आये लगे। हिन्द महासागर के विज्ञान परिवेश में अपने आकार की हीनता में हूना हाँ कच्छादीव एकाएक समाचारपत्रों के प्रथम पृष्ठ का विषय बन गया और भारत तथा सत्ता के बीच मनमुटाव का एक कारण निह्न हुआ।

कच्छादीव का क्षेत्रफल मुखिय से एक वर्गमील हाँगा। वह भारत से चारों तरफ से और श्रीलंका से उत्तर में किनारे दूर है। यहाँ में तापीन का पानी उपलब्ध है और नही कोई जानवर देखन का मिता है। इस रेगिस्तानी द्वीप में वन स्फुटि के नाम पर छोटे छोटे पौधे होते हैं। आवास के नाम पर टिन की छत्रवाला सेंट स्पेसनी का एक निजायर है जहाँ लगभग एक सौ व्यक्ति टिक सकते हैं। इस छोटे से द्वीप पर पहले पहल विवाद 1921 में हुआ था। वस्तुमान काय में दो कारणों से इस द्वीप का महान बढ़ गया। यह माना जाता है कि द्वीप के आसपास सत्ता के काफी

भारत है जो इस कारण दीना ही देश द्वारा पर अपना अपना अधिकार जताने का। दूसरे यह द्वीप एक एक महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है कि किना सा विदेशी शक्ति को वहाँ जाने पर भारत का सामरिक स्थिति की खतरा पड़ा हो सकता था। जिस प्रकार आलका में चान का प्रभाव बढ़ता रहा या उससे भारत का संशक्ति होना स्वाभाविक था। भारत नहीं चाहता कि कच्छादीव में किसी भी प्रकार से चीनिया या अन्य किसी विदेशी शक्ति का दख्खाना होने और वह।

दिसम्बर 1968 में सना के प्रधान मंत्री टडले सेनानायक भारत-यात्रा पर आये। इस अवसर पर कच्छादीव और भारतीय प्रवासियों व प्रश्न पर दोनों पक्षों के बीच पुन विचार विमर्श हुआ। कच्छादीव का समस्या पर सेनानायक ने कहा कि यह एक पुराना विवाद है जिसको अंतराष्ट्रीय विधि के नियमों के अनुसार तय किया जा सकता है। वस्तुतः उन्होंने इस बात का संकेत दिया कि कच्छादीव का मतलब कोई मतलब नहीं है बल्कि कुछ भ्रान्तियाँ हैं जिनके कारण विवाद खड़ा हो गया है। अतः मैं भारत और सना दोनों के प्रधान मंत्रियों ने यह राय व्यक्त की कि हम सवाल का सरकारी स्तर पर शांतिपूर्ण ढंग से सुझावन में कोई मुक्ति नहीं होना चाहिए।

अपनी इस भारत यात्रा के अवसर पर सेनानायक ने प्रवासी भारतीयों के लिए एक रियायत की घोषणा की। उन्होंने बताया कि सना का सरकार ने वहाँ के रायहान भारतीयों का कुछ आर्थिक अडचनों से मुक्त करने का फसल किया है। इस फसले के मुताबिक 1964 के भारत-सना समझौते के अंतर्गत जिन भारतीयों का भारत वापस भेजा जाना है उन्हें लगभग 75 000 रुपये (सना के मूल्य के) का सम्पत्ति भारत ले जाने का इजाजत रहेगा। 1964 में जो समझौता हुआ था उसके अनुसार पाँच लाख पच्चास हजार रायहान भारतीयों को भारत वापस भेजने का नियम दिया गया था। उस समझौते के नियमों के मुताबिक उन व्यक्तियों का अपना सम्पत्ति भारत ले जाने के लिए उका विदेशी मुद्रा प्राप्ति प्रमाणपत्र हासिल करना होता। अब सेनानायक का घोषणा के फलस्वरूप व लगभग एक लाख भारतीय रुपये की संपत्ति में सकेंगे। अब तक संपत्ति विनिमय का अडचन के कारण रायहान भारतीयों का विनिमय लगभग रुका हुआ था। अब इसके बाद में इस सिमिति में जान जायगा और यह आगे का जान सनता है कि पाँच वर्षों में यह विनिमय पूरा हो सका होगा।

भारत और उका के सम्बन्धों का सुदृढ़ करने के लिए सेनानायक ने कुछ और भी घोषणाएँ की। उन्होंने कहा कि जगन महाने उका के बुराई का एक प्रतिनिधि मण्डल भारत आयागा और एवज में भारत अपना एक प्रतिनिधिमण्डल उका भेजेगा। भारतीय विद्यार्थियों का नारियल उत्पादन का विविधता का अध्ययन करने के अलावा सना का फसल बारीक बालिता का अध्ययन करेंगे। सेनानायक ने भारत उका के व्यापार का पारस्परिक हितों का दृष्टि से संगठित करना आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि मैं एक प्रेस-कन्फ्रेंस में घोषणा की कि चाय उद्योग के विषय में भारत और सना एक दूसरे के नजरिय सने का निश्चय कर चुके हैं और उनके संगठित होने में अनेक दशकों का समय के विषय में संगठित योग्य होगा। उक्त दशक के बाद ही सना में अनेक संस्थाओं जिन्होंने फलस्वरूप अक्षी-सनामा विदेशी मुद्रा उमाया जा सकती। स्पष्ट है कि इस प्रकार सना और भारत के पारस्परिक सम्बन्धों में पर्याप्त सुधार हो रहा है। भारत-सना समझौते के अंतर्गत सना से नगरिकों विहाय भारतीय भारत

आ चके हैं। तेरह हजार वापस आने के लिए पंजाबत हुए हैं। सत्तर हजार के विषय में फसल हो रहा है। साल पाँच हजार भारतीयों को नागरिकता प्रदान कर दी गयी है।

श्रीलंका का चुनाव और भारत से सम्बन्ध—जनवरी 1970 में भारत के राष्ट्रपति बराह गिरि वक्रेट गिरि ने पाँच दिनांक के लिए लंका का राजकीय यात्रा की। यह यात्रा हर दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण रही। अफगानिस्तान मुद्रा ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। कुछ वय पूव श्री गिरि लंका में भारत के प्रथम उच्चायुक्त बने थे। इन समय उन्होंने भारत और लंका के सम्बन्धों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी।

जून 1970 में लंका में आम चुनाव हुआ और श्रीमती तिरुमावा मन्डारनायक के नेतृत्व में वहाँ एक नयी सरकार गठित हुई। उस समय इस बात की आशंका व्यक्त की गयी कि लंका कुछ भारत विरोधी नीति का अवलम्बन करेगा। श्रीमती मन्डारनायक का दल अधिक उच्चायुक्त के पक्ष में था।

प्रमुख रूप से सिङ्गी जनता का समर्थन प्राप्त करने के कारण तमिलनाडुवासियों का उसे व्यापक समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त वर्तमान प्रधानमंत्री साम्यवादी देशों का साथ धनिष्ठ सम्बन्ध रखती रहा है। श्रीमती मन्डारनायक ने भारत-चीन सम्बन्ध के बाद कोलम्बो प्रस्तावों को प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी यद्यपि इन प्रस्तावों से भारत और चीन के बीच कोई विशेष धनिष्ठता पैदा नहीं हुई। फिर भी इस बात की संभावना है कि लंका की नयी प्रधानमंत्री भारत-चीन के बीच नया संपर्क स्थापित करने की कोशिश करें। मगर इस बात की भी आशंका है कि श्रीमती मन्डारनायक के शासनकाल में लंका चीन के अधिक निकट चला जाय क्योंकि आर्थिक दृष्टि में चीन के आयात निर्यात का बहुत बड़ा बाजार है। इसके अतिरिक्त हिन्द महासागर में कुछ छोटे छोटे टापूओं की लेकर भी मतभेद पैदा हो सकता है। चुनाव में भाग लेने वाले एक अन्य सिङ्गी महाजन प्रकाश ने अपने चुनाव अभियान का भारत के विरुद्ध प्रचार करने में उपयोग किया।

इन आशंकाओं के बावजूद लंका की नयी सरकार ने आवासन दिया कि वह 1964 के सम्झौते को अक्षरशः प्रत्याखित करेगी। सविन्य अवधि दृष्टिकोण से नयी सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाये हैं जिनका भारत विरोधी कदम कहा जा सकता है। सरकार ने पन्द्रह भारतीयों के व्यापारिक आयात लाइसेंस रद्द कर दिया है। व्यापार और उद्योग पर भारतीयों का स्वयंसेवा का समर्थन किया जा रहा है। लंका में भारतीय किन्मा बहुत प्रिय है। उनकी लोकप्रियता कम करने के लिए और अपने देश की किन्मा को अधिक प्रिय बनाने की गरज से मोदरा सरकार ने निर्यात में पचीस प्रतिशत की कटौती कर दी। मनुपूर्व प्रधानमंत्री जिस संनानायक के समय में भा. भारतीय किन्मा का आयात पर पन्द्रह प्रतिशत कटौती की गयी थी। इस प्रकार की कटौती का भारतीय किन्मा उद्योग पर पतङ्क प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। किन्मा फसल के अक्षरशः जंग माध्यम तारिक में लंका के मंत्री में इस बारे में ज्वर भेद कर लंका अपना पक्ष बनाना चाहता था मन्त्र ने उन मित्रों में स्वीकार कर दिया। लंका के मन्त्रियों के इस प्रकार के रविवार में लंका जलाना पड़ा है कि भारत और लंका में जा पुस्तनी सम्बन्ध में उन पर विश्वास बढ़ता है।

1971 में आसता मन्डारनायक पान गयी और वहाँ जनता का अक्षर हुआ। इस अवसर पर चीन ने एक करोड़ साठ लाख चीनर मूल्य का चीनीय ९ टन चीनीय श्रीलंका को उपहार के तौर पर देने का आग्रह किया। साथ ही 10

भरित जाया। अपना भारत यात्रा के दौरान श्रीमती भण्डारनायक प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी से मिलीं। भण्डारनायक से उनकी बातचीत राजा देवा की जाति समस्याओं का उत्तर था। राजा देवा की जाति समस्याओं में वह निरर्थक यात्रा नहीं कर पाई। पर विचार द्वितीय हुआ। 1964 में भारत और श्रीलंका में एक विमान नागरिका के मध्य में एक समझौता हुआ था जिनमें अनुसार राजा देवा से प्रवासा भारत आया के एक नारी सहसा बोले कि मैं अपने देश में 1979 तक भारत जान था। श्रीलंका के अधिकारों में प्रशिक्षण का अधिकार मैं नहीं चाहती थी। उनके अनुसार देश में जिस प्रकार समाने पर बेरोजगारी का समस्या पैदा होता जा रही थी उन पर ध्यान देने का एक मात्र तरीका बन चके हुए राज्य विमान नागरिका की भीषण बापसी था। पर ऐसे वृष अधिकारों में प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी श्रीलंका के लोके पर गयी थीं तब भाष्य प्रस्तुत उठाया गया था। उस वक़्त जहाँ पुनः प्रश्न उठाता श्रीमती गांधी ने भारत जान जाने राजा देवा की समस्या में प्रतिनिधित्व और वृद्धि करने का आश्वासन दिया।

भारत और श्रीलंका — बीच दूसरा मुख्य विमान काटाने का लेख है निम्न सभ्यता में दोनों राज्यों ने निश्चय किया था कि वे प्रतिपक्ष द्वितीय समझौते निश्चय करेंगे। तब श्रीमती भण्डारनायक विमान जाया तो श्रीमती गांधी से उन पर ध्यान देने की उनकी बातचीत हुई। लेकिन इस बात भाष्य विमान पर कार्य अंतिम निष्पत्ति नहीं हो सका।

श्रीमती इन्दिरा गांधी और श्रीमती भण्डारनायक के बीच कुछ राजनयिक मामलों पर भी बातचीत हुई और यह बातचीत सम्पन्न हुई। भण्डारनायक से सम्बन्धित था जहाँ महाशक्ति की गतिविधियों में ब्रह्म वृद्धि हुई है। राजा प्रधानमन्त्री का विचार था कि निम्न समस्याओं का निराकरण करना चाहिये। उद्योग-धन्य नहीं करने चाहिये।

श्रीलंका की सरकार के निम्न भारतीय मूल के नागरिकों के नागरिकों का समझा और राजनीति का समस्याओं का समाधान करने के निवारण निरन्तर आवश्यक होता जा रहा था। देश में समास्थिति की स्थिति उपमाता वस्तुओं में वृद्धि हुए मध्य और तब के भाषा में वृद्धि से आर्थिक कठिनायियों और अर्थान्ति की दौर शुरू हो गया। देश का सुगतान मनुष्य विमान गया उस प्रकार श्रीलंका की भीतर समस्या निम्न वृद्धि गयी जिस तरह आर्थिक कठिनायियों के दौर में श्रीलंका की सरकार गुजर रही थी उसमध्य में असुरक्षा की स्थिति पैदा हो गयी। यदि श्रीमती भण्डारनायक भारतीय मूल के राज्य विहीन नागरिकों तथा ब्रह्मण्य का समस्या का कार्य करने नहीं निवारण देता तो उनकी स्थिति और भी कठिन हो सकती थी।

ब्रह्मण्य पर समझौता—भारत और श्रीलंका के बीच ब्रह्मण्य पर एक अन्ताराष्ट्रीय विमान विषय पैदा गयी। तब राजा देवा ने प्रतिपक्ष तब के देश समस्या का समाधान निश्चय किया। कई वर्षों तक ब्रह्मण्य में सम्पन्न जाता का अध्ययन किया गया। इस अध्ययन में पता चला कि ब्रह्मण्य के निम्न ब्रह्मण्य के निम्न अध्ययन में पता चला है कि ब्रह्मण्य पर भारत का अधिकार रहा है। ब्रह्मण्य के जमान में ब्रह्मण्य देव का साक्षात्कृत समझौता सीमा क्षेत्र में माना जाता था। 1924 में भारत में ब्रिटिश शासन के प्रतिनिधि ने यह निष्कर्ष की कि ब्रह्मण्य को सीमान्त के सीमा क्षेत्र में मान लिया जाय। पुणेवासी दस्तावेज के अनुसार भी ब्रह्मण्य क्षेत्र का भी समुद्री

हुआ। 1937 में अलग होने के बाद बर्मा पर भारत का कुछ कब्जा था। उस पर कुछ विचार-विमर्श हुआ था लेकिन इस समझौते में इसका सम्मेलन नहीं किया गया। जावन का सीमा और बर्मा के सम्बन्ध में समझौता हमें ज्ञात है—सबसे पहले कि भारत बर्मा के आर्थिक पुनर्निर्माण में भी विरामता है और चाहता है कि—यह यह छोटा सा पड़ोसी राष्ट्र में नई अवसर विकसित करने में सफल हो।

17 अक्टूबर 1955 को भारत और बर्मा के बीच एक और समझौता हुआ। इस समझौते के द्वारा भारत ने बर्मा का चार प्रतिशत क्षेत्र पर दावा करने का फैसला किया। भारतीय नेक्सामा में इस समझौते की अवधि भी है। यह कहा गया कि भारत स्वयं एक गैर शक्ति है और इसकी भी रक्षा वह दूसरे को करने के समर्थक है। लेकिन भारत सरकार ने यह कार्रवाई में ईर्ष्या-वितर्क बताया। कोनम्वो योजना के अन्तर्गत भी भारत और बर्मा के बीच एक सन्धि के अन्तर्गत सदागुण होत रहें।

स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद भारत बर्मा का अनेक सम्मेलन आयोजित समस्याओं का समाधान करता रहा। पापु सली, जिनका हाथ में बर्मा का शासन मूल था, में फट पड़ा। एक-दूसरे समझौते करने लगे और दूसरा नया विरोध। बर्मा के माध्यमस्थितों ने जो पापु में गैर शक्ति के अन्तर्गत स्थिति से असन्तुष्ट होकर बर्मा के अन्तर्गत स्थिति का आरम्भ किया। माध्यमस्थितों के सरकार विरोधी अभियान में भारत जनजात के विद्रोही भाग शामिल हो गए। भारत सरकार ने इन उपद्रवों के निपटारे में सहायता की योजना के अन्तर्गत किया।

बर्मा का अवस्था तब और भी गम्भीर हो गया जब लगभग दस हजार कामिलांग सैनिक चीन से आकर बर्मा में आये जो एक और सोमान् क्षेत्र में उपद्रव फैलाने लगे। 1953 में बर्मा में संयुक्त राष्ट्रसंघ का साधारण सभा में यह निर्णयित की कि उसने एक नया कामिलांग की जाँच कराये है और बर्मा में गैर शांतिपूर्ण कार्य कर रही है। अन्तर्गत तुरन्त निर्णयित की कार्रवाई को जारी रखा। एशिया के और देशों के साथ मिलकर भारतीय प्रतिनिधित्व के साथ रक्षा में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें यह मांग की गयी कि इस जाँच को बर्मा के हस्तगत कर दिया जाय और कार्रवाई की जाय। बर्मा में कामिलांग जाँच की कार्यविधि के विरोध में भारत ने बर्मा की सरकार का पूरा पूरा समर्थन दिया।

1964 में जब भारत ने पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया तो बर्मा ने इसका समर्थन किया और पंचशील सन्धि पर हस्ताक्षर किया। 1955 के मातृग सम्मेलन में भारत और बर्मा के प्रतिनिधि ने घनिष्ठ रूप में मिल-जुल कर काम किया।

बर्मा-चीन सीमा विवाद और भारत—चीन के साथ बर्मा का भी एक सीमा विवाद था। अब वर 1956 में बर्मा के प्रधान मंत्री उनल खोन से शांतिपूर्ण वार्ता द्वारा सीमा विवाद का समाधान करने के लिए विधिग बोझा की। परन्तु चीन ने न केवल बर्मा के दृढ़ सीमा सीमा का प्रस्ताव निर्धारण में सहमत नहीं हुआ बल्कि विस्तार द्वारा किया गया था। स्वीकार करने में इन्कार कर दिया बल्कि उसने बर्मा प्रदेशों के कुछ अन्तर्भागों पर भी अपने दावे को दाहताया। फलतः उस समय दोनों देशों के बीच इस प्रश्न पर कोई समझौता नहीं हो सका।

1960 में विधिग ने बर्मा के नए राष्ट्राध्यक्ष जनरल नेविन का सीमा विवाद तय करने के लिए आमंत्रित किया। भारत को भीचा निर्णय के लिए चीन इस

समय अपने सभी पक्षियों के साथ सीमा बिना तय कर नए व लिए गए उत्तरकथ। नविन की पक्षि यात्रा के फलस्वरूप 28 जनवरी 1960 का वमा और चीन - मध्य एशिया मंत्री एवं जनतामण समझौता सम्पन्न हुआ और उस तरह नए समय स चला आ रहा सीमा बिना सुलझा लिया गया।

भारत को यह समझौता विश्व ही समझ नहीं आया। यद्यपि सरकारी तौर पर हम पर का प्रतिनिधता नए नहीं आ गया। लेकिन चीन का कृतार्थता का सफलता से भारत की उचना अने व वनी। 1962 के भारत चीन युद्ध में उमा न वटस्थता का दक्षिण अपनाया। वस्तुतः भारत और चीन के मध्य उमा की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उमक लिए अपने दो गतिगामी पक्षियों के झगड़े में वटस्थता का नीति का अवलम्बन करना ही हितकर है।

वर्मा में प्रवासा भारताया की समस्या—वर्मा में छद्ममान राज व नगमा भारतीय रहत थे। वहा के प्राय सार व्यापार-व्यवसाय पर उहीं लोगों का प्रभुत्व था। वमा की दस लाख एकड़ भूमि पर आ भारताया का ही स्वामित्व था। 1953 में वमा न उमा सभा जमीनों का राष्ट्रीयकरण कर लिया। भारत व दक्षिण में वमा का नरकार न वक्तु लिए धनियुनि का रकम दा वह जपयाप्त था। वत भारत सरकार इस प्रश्न पर वमा सरकार से बातचीत करना चाहता था। लेकिन वह सम्भव नहीं हो सका। 1955 में वमा न भारत जान पर कुछ प्रतिवध नए लिये गए वर्मा से मनिआडर या अथ साधनों द्वारा भारत व्यापार भेजने पर आ रोक लगा लिया। 1962-63 में वमा की सरकार न भारताया व व्यवसाय-व्यापार का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया। फलतः रोजगार व अभाव में वमा न भारतीयों को वमा छोड़ना पड़ा। इसके कारण भारत और वमा के बीच कुछ कटुता आयी लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी।

ऐसी कुछ बातों को छोड़कर जनरल नेविन के नेतृत्व में भारत और वर्मा के सम्बन्ध में काफी सुधार हुए हैं। दिसम्बर 1965 में प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू न रंगन की यात्रा का। 1961 में प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी न भी वमा की यात्रा की। इस तरह समय समय पर जनरल नेविन भी भारत रात रह। यात्राओं के आन प्रदान से दोनों देशों का सम्बन्ध निरंतर बढ़ता रहा है। भारत और वमा के बीच सीमांकन को शांति कर कोई ऐसा बिना नहीं है जिस पर ये दो देश अलग अलग दक्षिण अपनाएँ। मगर यह बिना भी कुछ समय पहले प्राय मुन्नम चुका है। इन दोनों देशों के बीच 90 मील लम्बी सीमा का अकन वास्तु की मज पर सम्पन्न हुआ। वास्तव में इन लम्बी सीमा का थोड़ा सा हिस्सा ही बिना का विषय बन सकता था।

गमोर सीमा बिना व अभाव के वाक्य कटु उस विषय है जो अग्रगण्य रूप से दोनों देशों के सम्बन्धों पर गमोर प्रभाव डाल सकता है। नका और नागालैण्ड व बिना। न प्राय चीन न उहायता प्राप्त करने व लिए उमा सीमा का उपयोग किया है। नागा विद्रोही भारत की प्रतिस्था व लिए जितना धन खर्च कर उमा सभा व वर्मा के लिए मित्र हो सकते हैं। इसीलिए वमा सरकार न भारत व उमा प्रयास में सहयोग दिया है कि भारतीय नागा विद्रोही वर्मा क्षेत्र में होकर चीन न जा पायें। अग्रगण्य प्रभाव डालने वाले विषयों में वर्मा और चीन के सम्बन्ध हैं। पिछले वर्ष जब श्रीमती गांधी रंगन गयी थीं तो जनरल नेविन न यह स्पष्ट कर दिया था कि वमा अपने पक्षियों के साथ मित्रतापूर्वक रचना चाहता है। इसका अर्थ यह

निकाला गया कि भारत और चीन के विवाद में वर्मा तटस्थ रहना पसंद करता है। इस तटस्थता के पीछे चीन के आग्रह की मनोवृत्ति काम कर रही थी। जिन दिनों भारत और चीन के बीच सीमा विवाद जोर पकड़ रहा था उन्हीं दिनों वर्मा ने चीन के साथ अपनी सीमाओं का अवन सफलतापूर्वक किशा क्योंकि वर्मा चीन के कोप का भाजन बनना नहीं चाहता था।

भारत और नेपाल (India and Nepal)

नेपाल की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति—नेपाल हिमालय पर्वत के दक्षिणी ढलान पर बसा है। उसके उत्तर में तिब्बत और दक्षिण में भारत है। भारत उसका निकटतम पड़ोसी है। उसकी भौगोलिक सीमाएँ एक दूसरे से मिली हुई हैं। जब से तिब्बत चीन के प्रत्यक्ष शासन में आया है तब से नेपाल की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण हो गयी है। चीन और भारत के बीच यह मध्यवर्ती राज्य बन गया है। इस कारण चीन और भारत के सम्बन्धों में नेपाल एक अत्यंत प्रभावकारी तत्व बन गया है।

अठारहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक नेपाल कोई संगठित राज्य नहीं था। इसके विभिन्न भागों पर विभिन्न जमींदारों का अधिकार था जो एक प्रकार से स्वतंत्र शासकों के रूप में शासन करते थे। 1769 में महाराज पृथ्वी नारायण शाह ने सम्पूर्ण नेपाल का राजनीतिक एकीकरण कर उसे एक संगठित राष्ट्र का रूप दिया। राजनीतिक दृष्टि से नेपाल के इतिहास में दूसरी महत्वपूर्ण घटना 1846 में पृथी जंग बहादुर ने राष्ट्र की सत्ता का हस्तगत करके राजा की स्थिति को एकदम महत्वहीन बना दिया और स्वयं सर्वोच्च बन गया। जब आधुनिक दृष्टिकोण से राजा ही नेपाल का वास्तविक शासक होने लगा। राजा जयवन्महादुर के पदासीन होने के बाद से लगभग बीस वर्षों तक राजा परिवार के विभिन्न व्यक्तियों ने प्रधान मंत्री के रूप में नेपाल की जनता पर निरंकुश शासन किया।

भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रसार के क्रम में ईस्ट इण्डिया कम्पनी और नेपाल के बीच एक संधि हुआ। अंग्रेजों ने नेपाल को हराकर 1816 में उस पर सुगौली की संधि आरोपित कर दी। इस संधि के अनुसार नेपाल को अपने मूल भाग के कुछ हिस्सों को कम्पनी सरकार को देना पड़ा। बाठमाँडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहने लगा और नेपाल पूरी तरह से अंग्रेजों के प्रभाव में आ गया। नेपाल के आन्तरिक मामलों में ब्रिटिश सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया। वहाँ राजा का निरंकुश शासन चलता रहा।

स्वतंत्र भारत और नेपाल—निकटतम पड़ोसी होने के नाते नेपाल में भारत की रूचि (व्यक्तिगत स्वार्थ) है। भारत के स्वतंत्र होने के समय जो नयी अन्तराष्ट्रीय स्थिति उत्पन्न हुई उसने नेपाल की स्थिति को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। 1947 में भी नेपाल में ब्रिटिश राष्ट्र के लिए गोरखा का भरती किया जाता था। चीन में कम्युनिस्ट चीन के अस्तित्व से यह स्पष्ट प्रतीत होने लगा कि तिब्बत पर यह पूरा तरह अधिकार कर लगे। इस हानि में नेपाल और चीन की सीमा बिगुल भिन्न जायेगी। चीन में कम्युनिस्टों के अस्तित्व से सन्तुष्ट राज्य अमेरिका भी नेपाल की राजनीति में निरक्षर हो लगे। इस तरह नेपाल में कई तरह के हस्तक्षेप के बीच टकराव की संभावना हुई गयी और इस बात की सम्भावना बढ़ गयी

कि नेपाल शीत युद्ध का स्थल बन जायगा। भारत की सुरक्षा की दृष्टि से यह निश्चय ही एक चिंता का विषय था और कोई भी भारतीय सरकार नेपाल की राजनीति की ओर से उदासीन नही रह सकती थी। भारत का विचार था कि विदेशी हस्तक्षेप को सफलतापूर्वक रोकने के लिए नेपाल राजनयिक तथा आर्थिक मुक्तता प्राप्त कर और इस कार्य में भारत उसको सहायता प्रदान करने के लिए प्रस्तुत था। इसलिए 1947 से ही स्वतंत्र भारत नेपाल के भविष्य में रुचि उठा प्रारम्भ किया। 1947 में नेपाल के प्रधान मंत्री ने एक ऐसे पत्रित की माग भारत सरकार से की जो नेपाल के लिए एक संविधान बनाने में नेपाल सरकार का सहायक भूमिका निभा सके। भारत सरकार ने इस कार्य में नेपाल की मदद के लिए एक अरिष्ट भारतीय राजनीतिज्ञ श्री श्रीप्रकाश को नेपाल भेजा। उनकी सहायता से नेपाल के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार हुआ। लेकिन जब कि इस संविधान से राणाशाही की निरंकुशता का अन्त हो रहा था इस लिए राणाओं ने इस कार्यवित नही होने दिया।

राजनयिक दृष्टि से नेपाल में दहता लाने के लिए यह आवश्यक था कि नेपाल में पुरानी सामन्तशाही का अन्त कर 'राजतन्त्रात्मक' व्यवस्था स्थापित हो। इसने लिए नेपाली कांग्रेस के नेता बहुत दिनों में सक्रिय थे और भारत सरकार उनके साथ सहानुभूति रखती थी। ब्रिटिश काल में भारत और नेपाल के बीच जो संधि हुई थी उसको भारत सरकार स्वयं नहीं मान सकती थी क्योंकि उसमें साम्राज्यवाद की बू थी। भारत सरकार नये सिरे से नेपाल के साथ एक संधि करना चाहती थी। 1949 के उत्तरार्ध में भारत सरकार ने नेपाल के राजनयिक अधिकारियों के साथ नयी संधि करने के बारे में वार्ता आरम्भ की लेकिन नेपाल सरकार इसे टालती रही। नवम्बर 1949 में नेपाल के प्रधान मंत्री के पुत्र और नेपाल सरकार के विदेश विभाग के महानिदेशक ने भारत की यात्रा की और प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू से प्रस्तावित संधि के बारे में विचार विनिमय किया। इस वार्ता के आधार पर संधि का एक मसविदा तैयार किया गया और यह नेपाल भेज दिया गया। दोनों सरकारों के बीच विचार विनिमय चलता रहा परन्तु कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला।

इस बीच चीन के यह युद्ध का फलता अंतिम रूप से हो गया। कमिन्तांग की पराजय के बाद वहाँ कम्युनिस्ट शासन स्थापित हुआ। इस हादसे में भारत सरकार ने अपनी उत्तरी सीमा पर स्थित रायो के नये सम्बंध स्थापित करने की ओर विशेष ध्यान दिया। 1949-50 में सिक्किम और भूटान के साथ उसने नयी संधियाँ की लेकिन नेपाल की स्थिति सिक्किम और भूटान से बिल्कुल भिन्न थी क्योंकि नेपाल भारत का संरक्षित राज्य न होकर एक स्वतंत्र देश था। अतएव कुछ समय तक भारत सरकार के इरादों के बारे में नेपाल सरकार अज्ञात सञ्चाल रही।

भारत सरकार ने नेपाल के प्रधान मंत्री को भारत भ्रमण के लिए आमंत्रित किया और 1950 में वे भारत यात्रा पर आये। प्रस्तावित संधि पर पुनः बात चाल हुई। संधि के लिए भारत की एक महत्त्वपूर्ण शर्त यह थी कि नेपाल में लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापित हो। राणा की यह बात बिल्कुल पसन्द नहीं आयी। मोहन धर्मशर जगबहादुर को यह विद्वान्स भी हो गया कि पाकिस्तान और साम्यवादी चीन के विरुद्ध अपनी सुरक्षा की मदद करने के लिए भारत नेपाल की सहायता का प्रबल इच्छुक है। भारत में उनका जो खानदोर स्वागत हुआ उससे उनकी यह धारणा और भी पुष्ट हो गयी। इसका फल हुआ कि उसने भारत के साथ अधिक से अधिक

सोनावा की नीति अपनायी। इस हाथ में प्रस्तावित नेपाल-भारत संधि के बारे में पुनः कोई अंतिम निणय नहीं हुआ था।

भारत-तिब्बत के सम्बन्ध में कम्युनिस्ट चीन की नीति निम्नोक्त उन्नत होती जा रही थी। चीन की नयी सरकार ने साम्राज्यवादी शिकंजे में तिब्बत को मुक्त करने का अपना इरादा व्यक्त कर दिया था और इसके लिए सैन्य तयारी भी शुरू हो गयी थी। इस कारण भारत सरकार अत्यन्त बेचैन थी। नेपाल की सुरक्षा के बारे में भी इसकी लेकर उसकी चिन्ता बढ़ गयी थी। इस सम्बन्ध में भारत-नेपाल सम्बन्धों के बारे में 17 मार्च 1950 का भारतीय संसद में पारित नैतिक नेत्रों ने एक महत्त्वपूर्ण वक्तव्य दिया और कहा 'जहाँ तक कुछ एशियाई गतिविधियों का प्रश्न है भारत और नेपाल के बीच कोई सैनिक सम्बन्ध नहीं है। लेकिन भारत सरकार द्वारा किसी भी आरम्भ में नेपाल पर आक्रमण करने से निवृत्त रहना सम्भव नहीं है। नेपाल पर सम्भावित कोई भी आक्रमण अवश्यम्भावी रूप से भारत की सुरक्षा के लिए खतरा होगा।

अप्रैल 1940 में जनरल विजय शमशेर और एम. एम. दीक्षित ने पुनः भारत की यात्रा की। प्रस्तावित संधि के बारे में इस बार विस्तारपूर्वक चर्चा हुई। दीक्षित तक वातावरण के उपरांत 30 जुलाई 1950 को दोनों देशों के मध्य एक संधि सम्पन्न हुई। लेकिन इस बीच नेपाल में घट रही घटनाओं के कारण भारत सरकार और नेपाल की राजा सरकार के सम्बन्धों में तनाव उत्पन्न हो गया।

नेपाल का यह युद्ध और भारत — राजाशाही से नेपाल को मुक्त करने के लिए नेपाल के राष्ट्रवादी तत्वों ने एक क्रांति करने का निश्चय किया। वे नेपाल के राजा को राजा के प्रभाव में मुक्त कराकर एक संवैधानिक राजतन्त्र की स्थापना का उद्देश्य रखते थे। महाराजाधिराज त्रिभुवन नारायण शाह को नेपाली जनता की आकांक्षाओं में पूरी सहानुभूति थी। इस कारण राजा रामेश्वर जंग बहादुर के साथ उनका तीव्र मतभेद उत्पन्न हो गया। राजमहल में तरह-तरह के षडयन्त्र होने लगे और राजा ने राजा की गतिविधियों पर तरह-तरह के प्रतिबंध लगा दिये। नेपाली राष्ट्रवाद के बढ़ते हुए वेग में राजाशाही अत्यन्त चिन्तित थी और इस बात की सम्भावना व्यक्त जा रही थी कि इसके लिए वह ब्रिटन या अमेरिका में सहायता प्राप्त करे। इस कारण नेपाल के राजनीतिक उन्मुखता से भारत का चित्रित हुना स्वाभाविक था। अतएव नेपाल में गैरतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना में ही यह अपना हित समझता था।

6 नवम्बर 1950 को नेपाल के महाराजाधिराज त्रिभुवन नारायण शाह राजपरिवार के छोड़कर संस्थानों के साथ अपने राजमहल का परिदाग कर भारतीय दूतावास में चले आये और उसकी धारण ग्रहण कर ली। राजा रामेश्वर जंग ने अपने कुछ प्रतिनिधियों को 7 नवम्बर को महाराजाधिराज को वापस लाने के लिए भेजा परन्तु वह इससे लिए तयार नहीं हुए। इस पर खेदित होकर प्रधान मंत्री ने उन्हें मिहाना से बंधुत कर एक बालक (जनेन्द्र) को नेपाल का राजा घोषित कर दिया। इसके चार दिन उपरांत त्रिभुवन शाह अपने समस्त परिवार के साथ वापस आकर भारत चले आये।

ठीक इसी समय नेपाल के राष्ट्रवादियों ने राजाशाही के विनाश अपना सार्वजनिक विद्रोह शुरू कर दिया। वे विद्रोही भारत के भूभाग से विद्रोह का संचालन कर रहे थे। भारत ने इसे रोकने की चेष्टा नहीं की और नेपाल के राष्ट्रवादियों को प्रजातन्त्रवाद के सुधार लाने की सलाह दी। विद्रोहियों ने एक स्वतन्त्र सरकार की स्थापना की

भाषणा कर दा । प्रधान राणा मन्त्री न ब्रिटिश सरकार से सहयता और हस्तक्षेप करन का अनुरोध किया परन्तु ब्रिटिश सरकार इस मामले में भारत के विरुद्ध किसी प्रकार का काम करन के लिए सहमत नहीं हुई । भारत सरकार महाराजा त्रिभुवन का हा नपाल का वध महाराजा मानती रही । इस बात को जवाहरलाल नेहरू ने अपन 6 दिसम्बर 1950 को संसद में दिया गया एक भाषण द्वारा विस्तृत स्पष्ट कर दिया । उन्होंने कहा कि तीन वष पूर्व हमने नेपाल को यह आश्वासन दिया था कि भारत की यह हासिक अनिलापा है कि नेपाल अबदूत स्वतंत्र और प्रगतिशील राष्ट्र बन । हमने उस अधिक-से अधिक मन्त्रीमण्डल पर यह समझान का प्रयास किया कि विश्व में बड़ी तन्त्री से परिवर्तन हो रह हैं और यदि नेपाल इन परिवर्तनों का साथ कम-से कम मिलाकर नहीं चलता तो परिस्थितिया उस एसा करन के लिए विवश कर देंगी । हमारे लिए स्पष्ट कहना कठिन था क्योंकि हम नेपाल में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना नहीं चाहत । लेकिन हमने ईमानदारी के साथ जा भीती पूरा परमर्श दिया उसका नेपाल सरकार ने काफ बिठा नहीं की ।

भारत सरकार के इस रुतबे कारण नेपाल की राजशाही के समान सम-
 सीता करने के अतिरिक्त का-चार नही रह गया । फरवरी 1951 के प्रथम
 सप्ताह में नित्यी में नेपाली कांग्रेस के प्रतिनिधियों राजा के प्रतिनिधियों और
 महाराजा त्रिभुवन के मध्य त्रिपक्षीय बातचीत प्रारम्भ हुई और "मन्त्रो" हो गया ।
 त्रिभुवन पुन महाराजा के पक्ष पर वापस आय लोकतांत्रिक गणतन्त्र-प्रणाली कायम
 करने का इच्छुक हुए । इस आधार पर 18 फरवरी 1951 को बटमाह में नव
 मन्त्रिमण्डल गठन प्रथम की जिसमें प्रधान मन्त्री मोहन शमशेर जबहा और
 एक मन्त्री नेपाली कांग्रेस के नेता भानुका प्रधान कायस्थ बन । इस प्रकार नेपाल
 में सामन्तवाद का अन्त और एक नया युग का प्रारम्भ हुआ । इस समय में भारत की
 नीतिका अन्त नष्ट हो रही ।

नपाली कांग्रेस और भारत विरोधी अनियान :- भारत सरकार ने जिहा के तारान नवासी कांग्रेस का पूरा मनपन किया था और इसमें वह सहा नहीं कि भारत सरकार के इस रव से नेशनल मजदूर मतान व्याख्या करने में बड़ा सहायता मिली। लेकिन यह एक विविध दल है जिने नेशनल कांग्रेस के मतों के सत्ता हान पर भारत और नेशनल के पारलिक सम्बन्धों में का मुद्दा नहीं था। इसका एक कारण यह कि साम्बाणी चानक सम्बन्ध में सम्बन्ध पश्चिमि के सम्बन्ध में भारत सरकार नाल से धनित्त्व सम्बन्ध कायम करना चाहता था। पर भारत इसके लिए तयार नहीं था। जिहा पहाड़ियों के बीच मध्यवर्ती ताल हान कारण वह सम्बन्ध पार रहना चाहता था और जिहा पश्चिमि उसके हित के अनुष था। अतएव भारत सरकार का उमन बनी निराशा हुई। इसर नवासी जिहा के कारण के ऊपर सम्बन्ध की हान के लिए सम्बन्ध नहीं था नाल म जो तारानशाम्ब व्याख्या कायम की गया उस सम्बन्ध का अन्त नहीं हुआ क्योंकि नवासी कांग्रेस के नाल पाल नवासी समाज के सम्बन्ध बर्ध प और तारानों के दा देग में एक का पान था। खान दग जिहा ध्यान में रखकर द एना की शक्ति की काम नहीं था मन्वत प त्रिमस खिन्काम एन्ता का अधिनाधिक का है। अतएव एनी अन्ता का ध्यान दूसरा था यादृष्ट करने के लिए एनी भारत विरोधी रव व्याख्या और यह कहना गर दिया कि भारत नवासी पाल प्रभाव काम करना चाहता है। इन लाल न भारत के विरुद्ध सूत्र प्रचार करना गर दिया। मार्च 1953 में नपाली कांग्रेस के

एक अंग न भारत विरोधी प्रचार में अग्रणी रूप से भाग लेना आरम्भ कर दिया। नेपाली काँग्रेस की कार्यसमिति द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके यह माना कि नपा और भारत के बीच स्वस्थ सम्बन्ध बनाये रखने और इन दोनों देशों के नागरिकों में गलतफहमियाँ बन्ने से रोकने के लिए भारत द्वारा अपने नागरिक विधायकों और सैनिक मिशन को नेपाल से हटा देना चाहिए। 1953-54 में काठमांडू घाटी में भारत विरोधी भावनाएं बढ़ती रहीं। नेपालियों में यह भावना जोर पकड़ने लगी कि नेपाल को भारत और चीन के मध्य एक अवरोधक (buffer) राज्य का भूमिका निभाहू करनी चाहिए क्योंकि तिब्बत पर चीनी आधिपत्य हो जाने के उपरान्त भारत और चीनी एक दूसरे के बिचून आमने सामने खड़े हो गये हैं। मई 1954 में जब भारत का एक मसौदा प्रतिनिधिमण्डल काठमांडू की सद्भावना यात्रा पर आया तो उसे विरोधी जनसमर्थन का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि भारतीय राजदूत की गाड़ी पर पथर फेंके गये। यह घटना नेपाल में स्पष्ट रूप से विद्यमान घायल विरोधी भावना की परिचायक थी जिसमें आगे आनेवाले कुछ समय तक उत्तरोत्तर बढ़ि होती रही।

नेपाल की आन्तरिक राजनीति — फरवरी 1951 में मात्र 1955 तक नेपाल की राजनीति पूर्ण अव्यवस्था की राजनीति थी। दिवंगत समझौता (1951) के बाद नेपाल में संयुक्त सरकार की स्थापना की गयी लेकिन कुछ ही दिनों बाद राजाओं और नेपाली काँग्रेस के प्रतिनिधियों ने उग्र मतभेद पैदा हो गये और एक साथ सरकार में रहना उससे लिए कठिन हो गया। इसी समय डॉ. के. आर्ची सिंह के नेतृत्व में नेपाल में एक सशस्त्र विद्रोह हो गया। इस कारण पश्चिम नेपाल की स्थिति अत्यंत भयानक हो गयी। नेपाल सरकार ने जनरोष पर भारत सरकार ने डॉ. के. आर्ची सिंह के विरुद्ध पुलिस कायदाही में सहायोग करना स्वीकार कर लिया। इस कायदाही के फलस्वरूप डॉ. सिंह अपने अनुयायी सहित गिरफ्तार कर लिये गये। उधर राजाआने अपनी खोयी हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए गोरखा दल नामक एक नये दल का संगठन कर लिया। नेपाली काँग्रेस और राजाओं का मतभेद अब बड़ा उग्र हो गया। 14 नवम्बर 1951 को मातृका प्रसाद कोईराला ने नेतृत्व में नेपाली काँग्रेस की सरकार बनी। लेकिन इससे भी नेपाल की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। शांति और व्यवस्था हर जगह भंग होने लगी। कम्युनिस्टों ने अपना अलग संगठन कायम किया। 22 जनवरी 1952 को डॉ. के. आर्ची सिंह अपने साधियों सहित जेल से निकल भागे और गुना विद्रोह कर लिये। उन्होंने दरबार राजकोष कागजात हवाई जहाज और रेलियों स्टेशन पर कब्जा कर लिया और भारत के साथ स्थापित सैन्य सम्बन्धों का भंग कर दिया। इस मौके पर तत्कालीन मन्त्रालय का माघ किया और विद्रोह कुचल दिया गया। डॉ. के. आर्ची सिंह परार हा गये। 23 जनवरी 1952 को नेपाल नरेश ने संसद कास की पापणा कर दी और राजनीतिक शक्ति बधियों पर पाबंदी लगा दी। इस सम्पूर्ण काल में नेपाल की राजनीति पूरी तरह उलझी रही। इसमें केवल एक ही सशस्त्र स्पष्ट था—नेपाल के सभी राजनीतिक दलों का भारत विरोधी दृष्टिकोण। नेपाल काँग्रेस गोरखा दल कम्युनिस्ट पार्टी के आर्ची सिंह का दल सब के सब भारत विरोधी अभियान में जुट रहे।

1952 में नेपाली काँग्रेस में एक पड़ जाने से नेपाल की राजनीति और जटिल हो गयी। कुछ महीने बाद नेपाल के नरेश बीमार पड़े और इलाज के लिए लंदन जाया पड़ा। देश का शासन बंगाल के लिए बंगाली एक गौहा राज्य परिषद् का गठन कर दिया और इसने अल्पकाल राजकुमार महेन्द्र बनाये गये। लेकिन नेपाल की स्थिति

विपन्न हो जा रही थी। अतः नरग ने 18 फरवरी 1955 को अपनी भाषणात्मक में ही एक अध्यादेश जारी कर गाने राज्य परिषद् को भंग कर सम्पूर्ण अधिकार विधानसभा के उत्तराधिकारी जेदुमार मन्त्र विधिमण्डल को सौंप दी। महेंद्र ने मन्त्रिमण्डल को समाप्त कर गाने का दायित्व स्वयं ग्रहण कर लिया। 13 मार्च 1955 को महागज निधुवन का मरण हो गयी। उनके स्थान पर महेंद्र व - विधिमण्डल अब नरग के विधानसभा का कार्य शुरू हुए। 27 जनवरी 1956 तक नरग स्वयं बालन मंत्र का संचालन कर रहे। इसके पश्चात् उन्होंने तथा प्रसाद आचार्य को मन्त्रिमण्डल बनाने के लिए आमन्त्रित किया। इसी बीच दिसम्बर 1954 में नरग का संयुक्त राष्ट्रसंघ की संस्था में भर्ती गयी। उनके लिए नरग का भारत में मदद सहायता मिली।

डका प्रसाद आचार्य के प्रधानमन्त्रित्वकाल में भारत-नेपाल सम्बन्ध - डका प्रसाद आचार्य के प्रधान मन्त्री बनने से नरग की विदेश-नीति में एक विराट् मान आयी। उनके निवेदन में नरग चीन की ओर झुकने लगे। प्रधान मन्त्री बनने के पूर्व ही आचार्य के पास घोषित कर चुके थे कि उनकी सहनमति साम्यवाद के साथ है और साम्यवादी व्यवस्था कायम करके ही वह नरग में परिवर्तन करने के पक्षपाती थे। प्रधान मन्त्री बनने ही उन्होंने नरग की विदेश नीति पर विस्तर से प्रकाश डाला और कहा कि नरग सभी देशों से मित्र बनकर विश्व शांति बनाये रखने में अपना योगदान देगा तथा सभी देशों से सहायता प्राप्त करेगा वगैरें कि इस नरगता के साथ कोई शत्रु नहीं जुग ले। आचार्य का झुकाव स्पष्टतया मन्त्रों की विपरीत विचारों की ओर था। उनके सहयोग नरग में भारत के प्रभाव का कम कर दिया था।

1956 में अपनी भारत यात्रा के दौरान एक अवसर पर उन्होंने कहा कि नरग भारत और चीन के मध्य एक सुतु रूप से कार्य करना चाहता है और दोनों मन्त्र चाहता है।

आचार्य की इस नीति के परिणामस्वरूप चीन और नरग का सम्बन्ध बनता गया। अक्टूबर 1956 में आचार्य ने चीन का यात्रा का और जनवरी 1957 में चीन के प्रधान मन्त्री चो-एन-लाई नरग आय। अपना यात्रा में उन्होंने नरग का अपना स्वतन्त्रता और स्वाधीनता का अग्रणी रक्तन में यथार्थ नरगता का जो वास्तव एन डग में लिया जिससे यह ध्वनित हुआ कि मानों नरग का स्वतन्त्रता का भारत में छतरा हो। उन्होंने नरगियों का एक समूह में यह भी घोषणा की कि नरगियों और चीनियों में एक ही रक्त प्रवाहित होता है। चीनी प्रधान मन्त्री का यह कथन वास्तव में अत्यन्त राजनयिक था। उनके अर्थ में यह अमिप्राय था कि चीनियों और नरगियों दोनों के पूर्वज नरग का सं सम्बन्धित हैं और दूसरा अमिप्राय यह था कि चीन नरग नरग और सिक्किम का एक मंत्र में आवद्ध हो जाना चाहिए।

डका प्रसाद आचार्य ने उत्तराष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में चीनी प्रधानमन्त्री के द्वारा प्रेषित भाषण का स्वाकार कर दिया और उन्होंने कहा था माना में वास्तव में कहा कि एशिया के अधिकांश अन्धविश्वास हैं। अब यह स्पष्ट है कि अन्धविश्वास में दो कम-अन्धी एशिया एका की संस्था कर बैठे और मान्यता वातों के लिए बैठक आय। हमें इस सम्भावना पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और इस काम उठाने चाहिए कि इस अवसर पर स्थिति नहीं। अन्धविश्वास का लक्ष्य मान्यता अव अवसीक सहायता प्राप्त करने वाले एशिया देशों का ओर ही था। आचार्य ने यह भी कहा कि भारत का अन्धविश्वास में नरग में

राष्ट्रीयता व विकास में सहयोग देना चाहिए क्योंकि राष्ट्रीयता व विकास द्वारा ही एशिया में सामंजस्य व प्रसार का रोका जा सकता है। उनका यह कथन अप्रत्यक्ष रूप में भारत पर यह आरोप लगाना था कि भारत नेपाल को अपना विद्रुह बनाए रखना का प्रयास करता है जो उसे नहीं करना चाहिए।

डॉ. प्रसाद आचार्य के प्रधानमंत्रित्व के काल में ही नेपाल और चीन के मध्य निर्वन के संबंध में एक संधि हुई और सामंजस्य की चीन ने तीन वर्ष की अवधि में नेपाल को छह करोड़ रुपये की सहायता देने का वचन लिया। इस समझौते से यह स्पष्ट हो गया कि नेपाल का चीन के प्रति बहुत अधिक भुक्तान हो रहा है। उस समझौते से भारतीय जनमत नेपाल के इसादी के प्रति स्वाभाविक रूप में संतुष्ट हो गया। 9 अक्टूबर 1956 का इस समझौते पर टिप्पणी करते हुए हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा—नेपाल की वर्तमान सरकार चीन के साथ छह करोड़ रुपये के आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर करके सहो मांग सह रही है। नेपाल उस समय उस सहायता का ही सदुपयोग करने की स्थिति में नहीं है जो भारत से उसे मिल रही है। इन स्थितियों में चीन के साथ आर्थिक सहायता समझौता करना केवल एक राजनीतिक चाल है।

नेपाल और चीन की इस बढ़ती हुई मन्त्री की स्थिति में हम निम्नलिखित स्वाभाविक या कि भारत हिमालय के इस क्षेत्र में अपनी भूराजनीतिक स्थिति सुधारने का प्रयत्न करता है। अतः भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने अक्टूबर 1956 में नेपाल की यात्रा की और दिसम्बर 1956 में श्री डॉ. प्रसाद आचार्य को भारत यात्रा के लिए प्रेरित किया। भारतीय राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा के दौरान नेपाली जनता और शासक वर्ग का स्पष्ट ध्यान में इस बात का आश्वासन दिया कि भारत को नेपाल के संबंध में कोई शत्रुतापूर्ण महत्वाकांक्षा नहीं है और न ही वह नेपाल के आन्तरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप करना चाहता है। राष्ट्रपति ने यह भी घोषणा की कि भारत नेपाल के आर्थिक विकास की तत्परीक्ष करीब की योजना में पूरा पूरा सहयोग देगा। 27 अक्टूबर 1956 को काठमाण्डू में अपने भाषण में डॉ. प्रसाद ने भारत और नेपाल के घनिष्ठ सम्बंध और पारस्परिक हितों का इन शब्दों में व्यक्त किया—नेपाल की भागीदारी और सुरक्षा को कोई भी खतरा भारत की भागीदारी और सुरक्षा के लिए भी उनका ही बड़ा खतरा है। आप के मित्र हमारे मित्र हैं और हम आप के।

डॉ. आई. सिंह का प्रधानमंत्रित्वकाल और भारत—परन्तु दोनों दलों ने नतीजों को न सम्भावना यात्राओं के उपरान्त भी कोई वांछित परिणाम नहीं निकला और डॉ. प्रसाद आचार्य के नवम्बर में नेपाल की विगत नीति पूर्ववत् सामंजस्य की चीन की ओर अभिमुख रही। जुलाई 1957 में आचार्य के स्थान पर डॉ. के. आई. सिंह नेपाल के प्रधान मंत्री बने। यद्यपि उनकी नीति भारत के साथ सम्बंध सहायता से भी परन्तु आचार्य के समय के समाचार-पत्रों ने भारत के विद्रुह तीव्र प्रचार के चलन चलते हुए उन पर तरह तरह के आरोप लगाने शुरू कर दिये। अतः स्वरूप भारत के प्रति नेपाली दृष्टि कोण में कोई विगल परिवर्तन नहीं हो पाया। डॉ. सिंह को यह कार्य में असमर्थता मिली और नवम्बर 1957 में उन्हें स्थान पत्र देना पड़ा। डॉ. सिंह ने नेपाल के ऊपर समुक्त राष्ट्र अमेरिका के दबाव को चर्चा की और यहाँ तक आरोप लगाया कि अमेरिकी मिशन तिब्बत में सामंजस्य की प्रभावों को घटाना करना चाहता है। डॉ. सिंह के प्रधान मंत्रित्वकाल में अमेरिकी

गौर नपान के सम्बन्धों में तनाव बना। भारत स्थित अमरावा राजदूत नडा सिंह इस आरोप का खण्डन किया कि अमेरिका नेपाल को अन्तराष्ट्रीय घण्टों में घनी बना चाहता है।

यौ पी कोइराला और भारत—1959 में आम विधान होने के बाद
 यौ पा का नाम "पञ्च प्रधान मन्त्री बन। जिन् नरु भारत मीन के प्रधान
 मन्त्रित्व के म भारत-भार सम्बन्ध म गति सुधार नग हुए। अरबा न अपन
 शासन के म चान की यात्रा का और चारुण नरु का पुन भारत आन के लिए
 आमन्त्रित किया। कोइराला ने अपना यात्रा के समय साम्प्रदायिक चान के साथ
 एवरस पर्वत शिखर के चार में प्रारम्भिक समझौता बना की और बाद म काश्माह
 म एक समझौता हुआ। भारत म समझौता बना म इस समझौता का बना का जात बना
 हुई। यह कहा गया कि कूटनीतिक मिश्रण द्वारा चान से "सु प्रचार का समझौता
 भारत की तय करने के उद्देश्य से किया गया था।

[illegible]

1962 के उपरान्त भारत नेपाल सम्बन्ध—भारत चीन युद्ध के पश्चात् भारत को मुला के त्रिपक्षीय सम्बन्ध का महत्व और बढ़ गया। भारत सरकार ने सम्पूर्ण क्रिया विचार के माध्यम से भारत-नेपाल सम्बन्ध का विनीत सहयोगिता बना लिया है। आज वह एक सुतन्त्रतापूर्ण गृह मन्त्रालय के माध्यम से भारत की यात्रा का। भारत का अपना कूटनीतिक नीति—भारत-नेपाल के बीच मुक्त वायुमार्ग में पर्याप्त सन्तुष्टि मिली और इस दृष्टिकोण से भारत-नेपाल सम्बन्ध में नया आयाम का जन्म हुआ। यह दृष्टिकोण भारत की जनक यात्राओं के परिणामस्वरूप बढ़ता जा रहा। भारत-नेपाल के बीच एक पर्याप्त आय। एक उपरान्त यह सम्बन्धन न नेपाल की यात्रा का। इससे दोनों देशों के

सम्बन्ध गहरे थे। नेपाली राष्ट्राध्यक्ष बाबु शमशेर बहादुर थापा ने एक अवसर पर कहा था कि जयतक एक भी नेपाली नास्तिक है तब तक नेपाल के रास्ते से किसी भी आतंकवादी के लिए भारत पर आक्रमण करना सम्भव नहीं है।

23 नवम्बर 1964 का भारत के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नेपाल की यात्रा की। यह यात्रा भा. जयंत मन्त्रवर्ण सिद्ध हुई। इस अवसर पर भारत और नेपाल के बीच एक समझौता हुआ जिसके अनुसार भारत द्वारा नेपाल के लिए नौ बरोंहों की यात्रा में सामावर्ती रस्ते सगौली और मध्यापूर्वी नेपाल में आखरा पाणी के बीच 128 मील लम्बी सड़क का निर्माण करने का निश्चय किया गया। वाठमाण्डू में भारतीय सीमा रक्षकों को जानने वाली एक जय मन्त्र यात्रा भारत ने अपना हाथ में ला। जिसके अतिरिक्त भारत ने अपने खर्च में काफी योजना पूरी करने का निश्चय किया। काशी यात्रा के परिणामस्वरूप काशी का उद्घाटन भारत के स्वर्णोत्सव प्रधान मंत्री श्री शास्त्री द्वारा 24 अप्रैल 1965 को किया गया। इस यात्रा का उद्देश्य नेपाल का बाढ़ की क्षति से बचाना तथा विजयी एवं मित्राई से उग लाने पर पहचाना है। भारत नेपाल मंत्री सचिव अध्यक्ष ने भारत द्वारा नेपाल की गयी उदार मतायता के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि भारत नेपाल के सम्बन्ध परातन का सही चक्र आ रहा है। भौगोलिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से जो सम्बन्ध हैं—वे अमर हैं और निरालय के समान पवित्र तथा प्राच्य हैं।

इस प्रकार भारत और नेपाल के बीच मंत्री का उत्तरांतर विराम हुआ गया। नवम्बर 1965 में नेपाल नरेश ने पुनः भारत की यात्रा की। इस यात्रा की समाप्ति पर आठवाँदुर शास्त्री और नेपाल नरेश की द्वार से आसयुक्त निमित्त निकली उगम नेपाल के कमोरे के प्रान्त पर भारत का समर्थन किया। कमोरे के नाम का उल्लेख किये बिना निमित्त में कहा गया कि जम्मू निषेध का मिट्टा न बंधन पराधीन और सरहित राधा पर। आगू किया जा सकता है। प्रमुनता सम्पन्न राधा के विभिन्न अंग पर आगू नष्ट कर भारत। नेपाल नरेश ने इस विनिर्णय द्वारा यह स्वीकार किया कि भारत की सहायता में नेपाल में यह विकसित कार्यो का प्रगति सन्तोषजनक है। भारतप प्रधान मंत्री ने भी आश्वासन दिया कि नेपाल की पंच वर्षीय यात्रा की सफलता में भारत अपना अतिवाधिव यागदान देगा।

1966-1969 के काल में भारत नेपाल सम्बन्ध—जनवरी 1966 में भारत में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने और नेपाल में तुलसी गिरी के प्रधान पर मूय बहादुर थापा ने प्रधान मंत्री का पद ग्रहण किया। प्रधान मंत्री बनने के बाद श्री थापा ने मार्च 1966 में भारत की यात्रा की। इसी वक्त से लोना लगा के सम्बन्ध में सुधार हुआ। लेकिन तुरन्त ही मरुता धन का बकर भारत और नेपाल में हुए विवाद ठहरा हुआ। नेपाल ने इस विवाद पर अपना दावा किया। भारत सरकार इस प्रान्त पर चर्चा करने को राजा हो गयी।

22 अक्टूबर 1967 को भारत के उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने नेपाल की यात्रा की। उन्होंने यह घोषणा की कि भारत नेपाल को एक विशाल कर्चों में सम्मिलित करता है। नेपाल अधिकाधिक संचालन के लोना करने वाली विजयी पत्र योजना पर विशेष ध्यान दिया गया। मोरारजी ने यह भी आश्वासन दिया कि यह नीकी मामलों में भारत नेपाल की विशेष सहायता करेगा।

सैनिक संपर्क दल को भारत सरकार वापस बुला स। ना विष्ट ने कहा कि यदि वे भारतीय कमचारी नहीं गये ना वे अपने पद से त्याग पत्र देंगे। उनका कहना था कि सीमा पर स्थित इन सामरिक सह बंधों के सूचना के जो को अब नया नागरिक अन्तर्गत तरह सम्भाल सकते हैं। प्रधानमन्त्री के अनुसार नेपाल भी भारत की मधो की सदस्य बनने के लिए काठमांडू द्वारा सब कुछ किया जा रहा है जिसके उद्घाटन को भी और मध्य योजना समर्थित है। पर इनमें नेपाल का कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। इससे विपरीत नेपाल को व्यापार और परिवहन मध्य घाट कर्नाटकों का भारत में नामना करना पड़ रहा है। भारतीय समाचार पत्रों में नेपाल के विद्रोह समाचार छापे जा रहे हैं जोर काठमांडू द्वारा भेजे गये सन्नाहों के वाक्य किन्हीं ने अब तक नेपाल का कर्णार्थी योजना में कोई अभिरुचि नहीं ली है।

प्रधानमन्त्री के वक्तव्य को नर चीन समाचार एजेंसी का समर्थन तक मिलता। पत्रिका से एक संवाद में एजेंसी ने कहा कि विपक्ष सम्प्रदाय पर भारत अपने पत्रकारों के प्रति अपनी विस्तारवादी नीति चाना चाहता है। भूतपूर्व प्रधान मंत्री टका प्रसाद आचार्य और पचास प्रशान्त पद्धति की अन्य समस्याओं का जोर मजदूरी संगठनों द्वारा भी प्रधानमन्त्री के वक्तव्य का समर्थन किया गया। त्रिभुवन विश्वविद्यालय के एक संगठन स्वतंत्र छात्र मंच ने अपनी मंभा में भारत अमेरिका और रूस की आलोचना की। उन्होंने मांग की कि सरकार को भारत की विस्तारवादी नीति का जवाब देना चाहिए। नेपाल के एक विश्वविद्यालय के छात्रों ने भारत विरोधी नारे भारतीय साम्राज्यवादी मुर्दावाद लगाये।

नेपाली प्रधानमन्त्री श्री विष्ट ने नेपाली सीमा तट चौकियों से भारतीय सैनिक कमचारियों और सैनिक सम्पर्क दल को वापस बुलाने की बात किम नोयत या स्वाभाविक मान ली यह कहता था जरा कठिन है भारत में भारतीय राजनयिक दल को काफी हद तक और तनाव आ गया। पिछले कुछ दिनों में नेपाल में जिस स्तर पर भारत विरोधी वातावरण फैला हो रहा था उसमें यह अनुमान लगाया जा सकता है कि नेपाल पर चीन का रणनीतिक ताकत से चढ़ रहा था। राजनयिक प्रसक्त इस बात पर आश्चर्य प्रकट करने लगे कि नेपाल के प्रधानमन्त्री का (यदि उन्हें भारत का कोई शिवायन थी) क्या जल्दतर प गयी थी कि वे राजनयिक रास्ता त्यागकर तात्कालिक मंच से ऐम विचार व्यक्त करें जिसका उद्देश्य एक मित्र रा दूत की प्रतिष्ठा को धक्का लगाना हो। भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना कमचारियों और भारतीय सैनिक सम्पर्क दल 1952-53 में काठमांडू के निवेदन पर ही भेज प। नेपाल में भारतीय चौकियों की कुछ सह्या सतरह की जिनपर बेवज्ज अट्ठास निपटो और पाँच अफसर रहते थे। भारतीय अधिकारियों का कहना था कि यदि इन चौकियों पर से भारतीय कमचारियों को हटा लिया गया तो भारत को चीन और तिब्बत की गतिविधि या वहाँ से होनेवाले निम्न भी अन्तर्गण का अभिमुखता प्राप्त नही हो सकती। लेकिन नेपाल की सरकार अपना इस मांग पर नहीं रही। अतएव जुलाई 1970 में भारतीय सैनिक दल व पद सौंप दिया गया। इस कर्म में नेपालियों के मन में शायद वह गवाह दूर हो गयो कि भारत नेपाल को अपना उपनिवेश समझता है।

1969-70 में भारत और नेपाल का सम्बंध बना ही बटल पूरा रहा। काठमांडू में भारतीय दूतावास का आभार मध्य बंध है। लेकिन विद्रोह गुप्त वयो में नेपाल की राजधानी में इसकी प्रतिष्ठा और प्रभाव लगातार कम होता गया।

न नपायों का जार स भारतय दूतावास और उनके सम्चारिका का काफी सहाय म दिया जाता रहा । छान् स्तर क नपाय जविकारा जानपुनर नात विरामी प्रचार करत रह ।

स प्रकार की स्थिति कस अ या ? प्रारम्भ म विन्पा स सम्प्रत क बारे म नपाय न तदस्थता का नाति अनुसरण किया । भारत का स्वाधानत क समय उसका बकाब भारत का जार या ना विन्पा स्वाभाविक था । किन्तु यह स्थिति साना नपावता रही । 1962 म भारत और चान म युद्ध हुआ और स प्रार चीन हिमाय क अचर म ए प्रवर्ग गतिन के रूप म उचित हुआ । नपाय नतावा न स स्थिति की नवरञ्जना नही किया और उहानि अव चान का और भा दास्ता का हाय बनाया । चीन न जा 1956 स गी नपाय म विन्पसी उता रहा था इम नया स्थिति न पूरा पूरा गम उठाया और नपाय क जायिक निमाण म सनायता सन का प्रस्ताव दिया । परिणामस्वरूप 1964 म दोनों देशों क अचर म समझौता हुआ जिसके अनुसार उनम नियमित व्यापार हान ग्या । पहर 1965 म और फिर 1968 म स सधि का नवीनीकरण किया गया । मई 1968 में नपाय और चान न एक वडा निक और सांस्कृतिक समझौते पर भा हस्ताक्षर किये और अव पिछल गिना गनों देशों क बीच एक नया समझौता हुआ है निम अनुसार नपाय जानवान गिना म ना कराह रूप क चीना माय का ब्यापार करेगा ।

1956 स 1969 तक स समझौतों क अन्तगन चान न कुन मियाकर अदतागिस कराह रूप क आर्थिक सहायता सन का वचन नपाय का दिया । स समझौता न चान को नपाय म घसन का अन्तर मि गया । नपाय और चान क मध्य काठमाट्टु-काशी रातपथ क निमाण क सम्प्र म भी एक समझौता हुआ । तपान स तिबत का मियाववाती इस सम्प्र का वडा हा नामरिण महत्व है । उन भारत का उत्तरा सीमा का अत्यन्त जरूजिन बना दिया है । स प्रकार 1962 क वात म नपाय स चीन का प्रभव उत्तरान्तर घडता गया और सके मुख सय तप म भारत विरोधा भवना का प्रासाहित करना था । स घय म चान का वाता मफता मिया ।

1970 का व्यापारिक वार्ता — जकूबर 1960 म भारत और नपाय क बीच ए व्यापारिक समझौता हुआ था । स समझौता का अवधि दस वष का था और स प्रकार जकूबर 1970 म यह अवधि समाप्त हानवाग था । अतएव 1970 क प्रारम्भ म ही एक दूसर व्यापारिक समझौते क गिना नया गिला म जाना गों न प्रतिनिधिया क आक बाता शुरू हुई । सन स वाता का स उपरता नहा मिया क्योंकि दोनों देशों क दृष्टिगतों म मारि अन्तर था । भारत सरकार क अनुसार भारत क जीव उ गुजरनवागी हर विन्पी वस्तु पा कर ग्याना चाहिए । अय दोनों क साथ सी नियम क आन्तर पर समझौते हात हैं किन्तु नपाय सरकार का मत था कि पारो जार म भूमि म फिर स देगा । दूसर दोनों क बीच म स अचना म गुजरन का हर प्रकार की सुविधाए प्राप्त जानी चाहिए । स गिगिन म नपाय क विन्प सचिव पुन्कर नाथ पत न भाति सरकार का आवाचना का कि स नपाय क व्यापार स रात म तप्रा उपस्थित करी है; तकि भारत सरकार का आवा या कि नवम्बर 1968 में स दो देशों — बीच का समझौता हुआ था उनम नपाय न यह गत स्वाकार कर ग था ।

भारत नपाय को व्यापार का मभा जायज सुविधाए देने क लिए तयार था

जिन साथ हा यह भी नहीं चाहता था कि विमान व्यापार समझौते में जा सामिया रह गयी थी उनका अनुचित लाभ उठाया जा सके।

1968 में नेपाल में अनमानतः एक लाख हजार टन जूट पदा हुआ था। घरेलू आवश्यकता के लिए कोई अठारह हजार टन छोड़कर कोई तरह हजार टन जूट निर्यात करने की बात थी। इसके बावजूद नेपाल बाईस हजार टन जूट निर्यात करना चाहता था। नेपाल में पैसा या बच मात को भारत नि शुल्क बाहर जाने देता था। भारत सरकार का कहना था कि जब नेपाल वहाँ औरसे प्राप्त जूट भेजना चाहता है तो इस बात की संकारण गु जाण है कि बाकी जूट बोरी छिपे भारत में नपा पहुँचा है। यदि भारतीय व्यापारी नेपाल की मापत निर्यात करता है तो वह निर्यात शुल्क में बच जाता है जिसका भारत कभी समझन नहीं कर सकता। नेपाल में भारत आनेवाले माल पर तब कोई कर नहीं लगता जबकि वह नेपाल में ही बना हो। मई 1969 में स्टैनलेस स्टील के बतनों और रासायनिक रंग के बच वस्त्रा पर रोक लगा दी गयी क्योंकि नेपाल अपने कारा में अविन मात भेज रहा था। नपा विदेशी मात भारत में न खपा सके (याना भारतीय व्यापारी को उपभोगता आयात कर में मुक्ति न पा सकें) तो उसके लिए जरूरी था कि ऐसी वस्तुओं का आयात भी युक्तिमयत परिमाण में हो। यदि नहा तो उस पर भी कर लगे क्योंकि नपा के व्यापारियों को उस तरह के अवध व्यापार से काफी लाभ होता था।

भारतीय प्रतिनिधियों का कहना था कि जब नेपाल भारत से विदेश व्यापारिक सवि 15 चाहता है तब उसका भी पत्र है कि वह जवध व्यापार रोगन में भारत की सहयना कर। इसकी जगह यदि वह अनुचित रूप में अपनी भौतिक स्थिति का फायदा चाहता और हर मामल को राजनीति के रंग में रंगना चाहता तो दाना पक्षा का दसुविधा होगी।

इस स्थिति में व्यापारिक समझौता वार्ता का कोई परिणाम नहा निकला। नेपाल के वाणिज्य मंत्री नवराज सबेरी ने भारत नेपाल व्यापारिक वार्ता के बार में एक वय न जारा करके कहा है कि बातचीत टट गयी जिससे एक नयी स्थिति पैदा हुई है और जिसका सामना करने के लिए हम तयार रहना होगा। सामान्यतः उस वयान की काफी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि दस वर्षीय व्यापारिक समझौते को नवा करने के सम्बन्ध में यह बढक अन्तिम नहीं थी। समझौते की अवधि अक्टूबर 1970 में समाप्त हो रही थी। सबेरी का ऐसा बयान देने की आवश्यकता शायद इसलिए पनी कि वह भारत से अधिक-अधिक सविधा प्राप्त करना चाहते थे।

वार्ता का दूसरा दौर—सितम्बर 1970 में नेपाल नरग महाराज के आय और प्रधान मंत्री पदिरा गाँधी से उनकी व्यक्तिगत वार्ता हुई जिसमें का सर बारा धनो में काफी सन्तोषजनक बताया गया। इस वृत्त हा जिना शां जव वर 1970 में व्यापारिक समझौता वाता का दूसरा दौर जिना में आरम्भ हुआ। एक वय वार्ता भी असफल हो रही।

नेपाल इस बात पर जार दे रहा था कि उ। राधिकापुर से जाने हुए पाकिस्तान जाने की सुली पूरा दी जाय जो कि पाकिस्तान से उमर व्यापार की माया को देखन हुए बेतुक लगता था। वय ऐसी बीजा के व्यापार का वय में जिनका वनन में विदेशी कच्चे माल की आवश्यकता होती है। नेपाल में सुभाव रता है कि नरग और सरकारी धना में सुने तीर पर बेवन का उो पूरा भविष्यार जिना जाय।

नेपाल भारत से पेट्रोल और नमक जमी बुनियाती चीजें आयात करता है

नेपाल सरकार एक समग्र बन गयी ता बरगान पर जमीन पट्टे पर गेया । नेपाल को रू परिवहन के अन्धा बन्कल तब मात्र जान क लिए मन्त्र का म म भी उपनयन किया गया ।

अ यानि क के मात्र से भी माल तयार करत समय यन्त्र पवान प्रतिगत तब नेपाल का कच्चा मात्र और धर्म ग्या हो तो भारत सरकार उसका ध्यात पर विचार करगी । नेपाल स्टेशनने स्थात तथा नवरी वस्त्रो का भारत मे छुटे तौर पर ध्यात नही करगा । सन्धि म एक समुक्त समिति की नियुक्ति की व्यवस्था का गयी जिसमे दोनो देशो क वरिष्ठ अधिकारी हान । समुक्त समिति की बैठके जनवरी अन्त जुलाई तथा अक्टूबर म एक बार टिनी और एक बार काठमांडू म हुआ कम्मा ।

नेपाल क बड़े उद्योगों तारा तयार मात्र पर पबोस प्रतिगत तब उत्पादन गत्व म छू दी जायगी जिसमे वन् भारत म तयार मात्र का प्रतिपागा बन सक ।

भारत ने इस संधि के द्वारा नेपाल का अनेक रियायतें दी । सन्धि के अनुसार ऐसे उद्योगों क लिए भारतीय नेपाल म पू जो ग्या सकने है जितने लिए क चा मात्र भारत या नेपाल म उपलब्ध है । इससे नेपाल में औद्योगिकरण होगा । संधि का यह व्यवस्था महत्वपूर्ण बतायी गयी । सन् दोनो देशों म जायिक सम्बन्ध मजबूत होंगे । इस संधि के साथ ही भारत-नेपाल सम्बन्ध का यह विद्यमान चरण समाप्त हो गया जो 1971 के जनवरी म शुरू हुआ था ।

संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत क विदेश व्यापार मंत्री जित्ति नारायण मिश्र ने कहा सहयोग क क्षेत्र को बढ़ाना नेपाल क उद्योग तथा व्यापार हमारे पारस्परिक हित में है । नेपाल के मंत्री श्री सुब्बा ने भी प्रमनता प्रकट करने हुए कहा संधि का नेपाल के लिए विपणन महत्व है । यह हमारे व्यापार को बहुपक्षीय बनाने म सहायक होगी । मन्भाव मंत्री तथा पारस्परिक विश्वास के साथ सम्पन्न यह संधि हमारे सम्बन्धों को सुदृढ़ करेगी । समझौते पर हस्ताक्षर होने क बाद प्रकाशित संप्रति विज्ञप्ति मे जा कुछ कहा गया हमारा मार यगी था कि इससे दोनो देशों द्वारा उत्पादित मात्र क पारस्परिक व्यापार का क्षेत्र विस्तृत होगा और नेपाल क औद्योगिक विकास को प्रामाहित करने क लिए नेपाल द्वारा नेपाली तथा भारतीय माल म निमित वस्तुओं के आयात को भारत विपणन मविधा दगर ।

पारगमन परिवहन तथा यातायात के बारे मे जो व्यवस्था निर्धारित की गयी उससे नेपाल की कठिना या अवस्था दूर होगी । अब "हृदयन" था कि भारत की वह शिवायत विस्तार दूर होती है जो पटमन तथा अभ्रव जैसी वस्तुओं का भारत म आयातित कर तपायी व्यापारो विदेशों को निर्यात कर देत थे और अजित विदेशी मुद्रा के एक भाग म विपणन की वस्तुएं सरी कर भारत में बच देते थे । इसम भारत को दोहरी हानि होती थी । इसे रोकने के लिए नयी संधि म कुछ व्यवस्था ता है लेकिन सफलता मुख्यत नेपाल की सक्रियता पर निर्भर रहेगी । भारत को भी तत्पर व्यापार रोकने के लिए गीमा र विशेष चीरती रक्षनी पढनी ।

इस संधि का उद्देश्य दोनो देशों क बीच व्यापार का विस्तार और उमवी विविधरूपता है । इसीलिए उसम यह व्यवस्था की गयी है कि दोनो एक दूसरे के मात्र को अधिकतम प्रथम देगे । भारत कितना अधिक प्रथम दे रहा था इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि नेपाल के कच्चे मात्र को भारत में अदायित और कर मुक्त प्रवेश मिलेगा । इतना ही नहीं नेपाल के औद्योगिक विकास क लिए उसने

यहाँ तक स्वीकार कर लिया है कि आसाम भारतोप और नेपाल। सामग्रा म बना हांग वह परिमाण का बन्धि क बिना नैमित्त भारतोप बाजार में आ मुक्त—उ प का चुग नगी हांग। आन्तारी कर में सुदृष्टित न्न का समन व्यवस्था है।

सोसाभाइक परियोजनासधि—अक्टोबर 1971 में भारत और नेपाल के बीच एक आरसधि हुई। यह भारत और नेपाल के बीच कासा औरगडक परियात्रनाओं से सम्बन्धित था। इन योजनाओं पर दोनों देशों के बीच काफी दरस में पत्रिवाह हा गया था।

पश्चिमा कासा नहर और गन्ध परियोजनाओं पर क्रमशः 1956 और 1959 में समझौता हुआ। 1963 में बाघ और मुख्य कायागा का निर्माण भा हा गया था किन्तु उसका काम रुक गया। 1965 में जब स्वर्गीय गान्धीजी कास्त्रान नेपाल यात्रा का ता उस समय यह सकत मिला था कि परियात्रनाओं का लेकर जा तिरिवाह पना हा गया वह दूर हा जायगा किन्तु ऐसा नपा हा मुका।

बामो और गन्ध परियात्रनाओं पर हुए गम समझौते के अनुसार भारत अपने खच म कायागा का निर्माण करता जिस नेपाल का भा दल्लखनीय गम मिला। द्वापरगाप पश्चिमा कासा नहर परियोजना पर कुछ चागम काइ गय खच होन का अनमान है। उनमें म पांच कराइ स्पय का काम नपा। मत्र म हांग जिसमे 64 000 एकर भूमि का सिचा हागा। बिहार के दक्षिण सि के मात पाख एकड भूमि सिचा। उनके अलावा एक एक एक भूमि का न्न म वचाद भा गी। न्न का मुक्त कायागा ना ना न हांग हा का नम भा न्न भा गी। मत्र म हांग दहा। मत्र का दहा भा 1975 तक तदार हा जाद का अनमान है। कासा यागा म तदार हाद बाग सिन का लानम गधा भा गय वय त त्स मय भूति क हिमाव म नेपाल का मिला। उनमें म कृषि में प्रयुक्त विद्युत शक्ति पर त्स प्रविष्टि दूर भा मियी।

समझौते के अन्तर्गत भारत का मुख्य वस्तु शरा दिया गया जस अनका भारत का नहर का दीनाका और विस्तार का। पश्चिमा कासा न्न म पाना दगान के लिए उन्हें वनायगा जिस नेपाल के म का सिचा हांग का कायागा अन्ति क लिए जलियात्र भूमि का सन्ति पूति कोगा। नेपाल केवज 1972 तक भूमि जुगत के लिए समनत हुआ है जिससे काम करन के चारु मय में सिचा काय काम नपा म।

एक परियात्रना के अन्तर्गत भारत का पूर्वी नेपाल न्न म समुद्र वन घनत्व कम क्षमा वाग चनगे—अन्तिमिक्त निमा—अन्तिमिक्त गी। म चनगे जिस में एक पा त्स वा चनग के समान होंग। नन्न में सिचा के विस्तार का मविवा म अन्तिम हांगना पश्चिमा एक नन्न का सिचा मुक्त निमा (गुगल) निमा का मन्त री।

एक निमा म समझौता भारत-नेपाल सहभा का जिस में कासा का ए और मन्तर्गुण काम था।

अन्य काइ समझौते में पिछले वर्षों में भारत और नेपाल के गान्धीय सम्बन्ध कायागा नगी है। नेपाल भारत का गन्तव्य और मन्तर्गुण का भारत का समझौता नि नेपाल बागे का अन्तिम में मन्तर्गुण है। एका अन्तिम में आगव प्रचाराप और शमकियों म मन्तर्गुण का नन्न का बीच मन्तर्गुण

सुधारना सम्भव नहीं था। भारत अपनी प्रतिरक्षा के सम्बन्ध में नेपाल में अपनी कुछ सैनिक चौकियाँ रखने में जिानगी जानकारी प्राप्त कर सकता था। उगाय नहीं जिन जानकारी में नेपाल सरकार के सहयोग में प्राप्त हो सकता थी। इसलिए जब एक ऐसा समय आ गया था जबकि भारत सरकार को यह महसूस करना चाहिए था कि एक स्वतंत्र देश के प्रति जो व्यवहार होता था वह महसूस करना चाहिए था कि एक स्वतंत्र देश के प्रति जो व्यवहार होता था वह महसूस करना चाहिए था। इसके लिए यह जरूरी था कि नेपाल में वर्तमान परिस्थितियों को समझने के साथ ही वहाँ की आंतरिक घटनाओं के बारे में अपनी प्रतिनिधित्व व्यवस्था की जाय तथा नेपाल को दो जानेवाली आर्थिक सहायता को राजनयिक दबाव के लिए हस्तगत न किया जाय। अभी प्रकार नेपाल सरकार के लिए भी भारत के साथ मित्रता और सहयोग का वातावरण बना करके भी काम था।

नेपाल सरकार का सबसे अधिक भय नेपाली विद्रोहों से रहा है। नेपाल सरकार का कहना है कि ये विद्रोहों आरम्भ से ही भारत में रहते हुए नेपाल के विद्रोह विद्रोहों का संगठन करते रहे हैं। यह सत्य है कि 1963 के बाद से नेपाल के विद्रोह में कोई सशस्त्र विद्रोह नहीं हुआ। तब भी कुछ छिपे छिपे घटनाएँ होती रहीं जिससे नेपाल सरकार को सताएँ गयीं रहीं। भारत सरकार ने भी नेपाल की इन आशंकाओं को दूर करने का प्रयास नहीं किया। 1972 के अगस्त में एक हथियार बन्द गिरौह ने बिहार की सीमा पर नेपाल की एक चौकी हरिपुर पर हमला किया था। फिर जन 1973 में नेपाल एयरलाइन्स के एक विमान को फारबिसगञ्ज में अपहृत कर ले जाया गया और अपहरणकर्ताओं ने तीस लाख रुपये लूट लिए। नेपाल सरकार का सच था कि यह सब नेपाली कांग्रेस के इशारे पर हुआ। इन घटनाओं के पहले गितम्बर 1971 में दिल्ली में बी पी कोइराला ने नेपाल में सशस्त्र क्रांति का आह्वाण किया था। इन घटनाओं का यह अर्थ नहीं कि भारत सरकार नेपाल कायम सत्ता नेपाली विद्रोहियों का समर्थन करती थी। वास्तविक बात यह है कि भारत सरकार इन कार्रवायों के सम्बन्ध में उत्साहित नहीं और इन उत्साहीनता में नेपाल में अन्तर्भावितियों की थी। तथ्य यह है कि नेपाल के सम्बन्ध में भारत सरकार को कोई स्पष्ट नीति नहीं रही है। न तो वह नेपाली विद्रोहियों का समर्थन करती रही है और न ही उसने नेपाली विद्रोहियों का विरोध कर नेपाल की सरकार को आशंका दूर करने का प्रयत्न किया। यदि भारत सरकार के पास कोई स्पष्ट नीति रहती तो या तो वह नेपाली विद्रोहियों की सहायता करती या वह इन विद्रोहियों को भारत में सक्रिय होने की अनुमति नहीं देती।

नेपाल की दूसरी विज्ञाता समुत्पन्न पर पहुँचने के लिए एक निर्दिष्ट योजना का को प्राप्त करने की है। जन्मान्तक व्यापार करने के लिए उगाय तो भारत में मुद्र रत्न पड़ेगा या बगल में ग। नेपाल को तेम किसी माय की तत्त्व है। यह सम्बन्ध में बगल में ग उसकी बातें हुई लेकिन उगाय कोई नतीजा नहीं निकल। भारत भी तेम प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तयार नहीं है। नेपाल का कहना है कि नियमित सम्मान न होने के कारण नेपाल का विदेश व्यापार घट रहा है। यह सम्मानों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना चाहता है।

चीन या पाकिस्तान के साथ एक दोस्त सम्बन्धों में उतार चढ़ाव की बात आम जाना की समझ में आसानी में आ सकती है। मगर नेपाल के इन राजनयिक आर्थिक और सांस्कृतिक पड़ोसी के साथ सम्बन्धों की कटता की जो कभी-कभी वि-

एक सत्ता के रूप में मुखर हो जाता है, समर्थन सामान्य भारतीय जनता के लिए कठिन हो जाता है। बाकि हम न इन्हीं कि भारत और नया के बीच के सम्बन्धों के बारे में हमें के सामनाधिकारियों के पारस्परिक व्यापार का कोई ज्ञान करा सामान्य जनता का नहीं रहती। नीचे बाकि हम न इन्हीं कि सामान्य भारतीय नागरिक नया के साथ न्याय की स्थिति को स्वीकार नहीं करना चाहता। मगर यह एक सच्चाई है कि नया और भारत के बीच गोलम गोलम सम्बन्ध बहुत गैरवास्तविक जगता है। काठमांडू में भारतीय प्रतिनिधियों का नया का दृष्टि में खेदा का जगता है और नयी दिल्ली में बैठ गए पराष्ट्र मन्त्रालय के अधिकारी भी भारतीय नया की अधि कारियों के इस व्यापार को तपाकपित मित्रतापूर्ण कारवायों में रण होकर इस प्रकार के मुकेश में हव हैं जिनका अमाना में राजनयिक घमका माना जा सकता है।

भारत-नया सम्बन्ध के इस सत्ता के बीच को देखते हुए इसमें निम्न में एक भी निष्कर्ष निवारना कठिन नहीं है। एक तो यह है प्रारम्भ में ही नया भारत के इरादों के प्रति शकलु है और उनका यह स्थान है कि भारत चान के निम्न उनका प्रयोग करना चाहता है। लेकिन एक सम्बन्धों जगता हान के नया नया भारत और चान के विचारों में नहीं पना चाहता। वह अनुभव करता है कि जब उसका जनों शक्तिमाना पनाला नया शुरू करें तो उनका सुरक्षा भा खतरे में पड़ जायगा। इसलिए वह दोनों के निम्नों के प्रति अज्ञानता का नाति का अज्ञान करता है और पूरा तपस्य भाव में अपना नाति का निवारण करता है। इस कारण वह भारत और चान दोनों का एक भी निम्न न रखता है। नया के दया नाति भारत के मनानुसार नहीं है जो नया कारण नया में दया चान के प्रभाव के सम्बन्ध में भारत में यह-उरह की बातें जा जगता हैं। लेकिन हमें यह न भूना चाहिए कि नया का सत्कार नया निम्न-नीति के निवारण नया के हित का ध्यान में रखकर हो जागी। भारतीय कानाति न नकारता इस बात में है कि बट नया मानित शायरे में रहकर नया के साथ अपना सम्बन्ध सत्ता के नकि सत्ता चान में पुन का सत्तप हा जगता नया निम्न निम्न में न (नया) भारत विधा सत्ता नहीं अपनावे।

नया और भारत के सम्बन्धों का और निम्न वनज के नदर में हा करवरी 1973 में भारतीय प्रधान मंत्री शानता निम्न नीचा नया का बाया पाने में। नया के नया महाराजा के राजा-राज के पञ्चायत भारतीय प्रधान मन्त्रा को यह पहला पत्र था और नया निम्नों में नया नया सत्ता माना जा सकता है। जगता वक्तव्यों कावर्तनिक भागों और कुछ नयालों के निम्न में शानता नीचा न उन सभी सत्तवर्तनिकों का दूर वनज का नयास निम्न निम्न कारण भारत नया सम्बन्ध में मधुप का केना हुआ जा जा था। जगता का नया में नीचा नीचा ने नया वनज पर वनज निम्न कि भारत का निम्न में नया नया सम्बन्ध में है और जगता निम्न निम्न का नया पाने निम्न करन का भारत के काय इरादा नहीं है।

सिक्किम की घटनाएँ और भारत-नया सम्बन्ध—सिक्किम में सम्बन्धित हान की घटनाओं का जगता भी भारत-नया सम्बन्ध पर पना है। सितम्बर 1974 में सिक्किमी जनता नया नया भारत नया निम्न में सम्बन्धित कर सिक्किम को भारतीय सत्ता का एक सम्बन्ध का जगता दे निम्न। नया नया में भारत के नया नया को नया नया सम्बन्ध का सत्ता नया नीचा जगता नया में नया निम्नों नया

यति उग्र भारत विरोधी प्रवृत्ति प्रदर्शन हुआ। काठमाण्डू स्थित भारतीय दूतावास में प्रदर्शन का पहला निमित्त बना। ऐसे वर्ष अर्थात् भारतीय भी अपमानित किये गये। नेपाली विद्यार्थियों के द्वारा भारत विरोधी प्रदर्शन को कुछ जिम्मेदार तब भी राजनीतिज्ञों की महानुभूति और समर्पण भी प्राप्त था। भारत सरकार ने इस प्रदर्शन के विरुद्ध एक वर्षा विरोध पत्र तैयार कर विश्व सम्प्रदाय को सम्मुख प्रस्तुत किया।

(5) भारत के सरलित राज्य सिक्किम और भूटान

सिक्किम—भारत के पर्वत हिमालय अंचल में सिक्किम स्थित है। भारत नेपाल भूतान और तिब्बत में घिरा हुआ इस रमणीय पर्वतीय देश का कुल क्षेत्रफल 7,137 वर्ग किलोमीटर है। तिब्बत पर चीन के पूर्ण आधिपत्य हो जाने के कारण इस देश का सामरिक महत्व बहुत बढ़ गया है। काठमाण्डू और जेथपा नामक दो द्वारों तिब्बत में सिक्किम आने के मार्ग हैं जिनके द्वारा यतायात संचालित जारी रहा है। अतः सिक्किम चीनियों के लिए उत्तरी भारत में पहुँचने का सबसे छोटा और सरल मार्ग है। इस दृष्टि में सिक्किम भारत का प्रवेश द्वार कहा जा सकता है। यदि भारत और चीन में फिर कोई युद्ध छिड़ जाय और इस युद्ध को अधिकांशतः तक चलने की सम्भावना हो तो चीन का पहला लक्ष्य सिक्किम ही होगा जिसमें वह सभी विश्वासों में आसानी में फँस सके।

अंग्रेजों का प्रवेश—सिक्किम में अंग्रेजों के प्रवेश के पहले तिब्बत नेपाल सिक्किम और भूटान के बीच था। इस समय होत रहने थे। 1861 में बर्मा विद्रोह के बाद ब्रिटिश सेना सिक्किम में घुसी और उस पर अंग्रेजों ने एक सन्धि घोषित दी। इसके अनुसार सिक्किम के राजा ने स्वाधीन रूप से दार्जिलिंग को भारत सरकार को सौंप दिया। भारत और सिक्किम के मध्य आवागमन पर तब से उठाई गयी और ब्रिटिश सरकार को सिक्किम का निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त हुआ। 1890 और 1893 में चीन तथा ब्रिटिश सरकार के बीच जाँच पड़खाई हुई। इनके अनुसार चीन ने सिक्किम पर भारत की सार्वभौमिकता की पूर्ण स्वीकार कर दिया और सिक्किम चीन सीमा भाँड़ो अवसर पर निर्धारित कर दी गयी। ब्रिटिश सरकार ने गैरगोप्यता में अपना एक राजनैतिक अधिकारी नियुक्त किया। इस समय सिक्किम का मन्त्रालय को परामर्श देने के अधिकार प्राप्त करने का अधिकार भी उसे प्राप्त हुआ। 1947 में भारत में अंग्रेजों के हट जाने के बाद भारत पर सिक्किम का यह सारा अधिकार आ पड़ा।

1950 की सन्धि—1949 में चीन में कम्युनिस्ट शासन के अस्तित्व में सिक्किम का महत्त्व बहुत बढ़ गया। अतएव भारत और सिक्किम के बीच 5 अप्रैल 1950 को एक नयी सन्धि हुई। इस सन्धि के अनुसार सिक्किम की सुरक्षा विशेष मामला तथा संचार व्यवस्था का उत्तर भारत सरकार ने संभाल लिया और सिक्किम पूर्ववत् भारत का एक सरलित राज्य स्वीकार किया गया। भारत और सिक्किम के सम्बन्धों का आधार यही समझा गया।

सिक्किम की अभिन्न समस्याओं को प्रस्तुत कर दिया गया। वहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति गिरी हुई है और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा विफलता है। राजनीतिक दलों की दृष्टि भी यही शोचनीय है। इन कठिनायियों के समाधान के लिए भारत ने सिक्किम को पूर्ण आर्थिक सहायता प्रदान की है। सिक्किम की प्रथम योजना में भारत ने सहायित सहायता दी जिसमें अन्न से संचार इन्फ्रस्ट्रक्चर और सामरिक संस्थाओं का विकास किया। सिक्किम की दूसरी योजना के लिए भारत ने एक करोड़ से अधिक रुपये की सहायता दी। भारत की सहायता से वहाँ आर्थिक रूप

का कोई सङ्कोच नहीं है। सिविकम एक दायित्व विकास के लिए भारत सरकार द्वारा प्रयोजित है।

सिविकम का जन आन्दोलन (1973) और भारत—माच अप्रिल 1973 में सिविकम में कुछ राजनीतिज्ञों के चनाए गए लोगों से पठे। सिविकम का मताधिकार उन्नीसवीं राष्ट्रीय परिषद से होता है। इसमें से अठारह सदस्यों का चुनाव होता है और बाकी छह चांग्याल मनोनीत करता है। लेकिन चुनाव के मतानुसार बहाल होता है। 1973 के प्रारम्भ में राज्य परिषद का चुनाव हुआ तथा 26 मार्च 1973 को एक छह सदस्यीय कार्यकारी परिषद नियुक्त की गई।

सिविकम की अधिकांश जनता को यह व्यवस्था पसन्द नहीं आई। सिविकम में राजवश का शासन है और सरकार की कार्यवाही में कानून की सभी का प्रतिनिधित्व प्राप्त करने वाला व्यक्ति यह था कि इस पर कानून द्वारा प्रतिष्ठित लोगों का मानना था। सिविकम के विधान के अनुसार गुप्त अन्तर्गत प्रतिष्ठित का जो प्रतिनिधित्व प्राप्त था वह परिणाम में दो प्रतिष्ठित के प्रतिनिधित्व के बराबर था।

सिविकम के दो राजनैतिक दल—राष्ट्रीय कांग्रेस और जनता कांग्रेस ने इस व्यवस्था का विरोध किया और यह मामला कि शासन व्यवस्था का प्रजातन्त्रीकरण किया जाय। उसपर चांग्याल की सरकार ने जनता कांग्रेस के अध्यक्ष कृष्णचन्द्र प्रधान को गिरफ्तार कर लिया। उसक उपरांत राष्ट्रीय कांग्रेस और जनता कांग्रेस ने एक संयुक्त कार्यवाही समिति का गठन किया जिसके अध्यक्ष राजा जैन्स चयन हुए। सिविकम का अजनैतिक व्यवस्था के लिए एक मध्यम चलान का निश्चय किया गया। लोगों ने पसन्द चांग्याल के प्रतिनिधियों से बातें कीं। लेकिन उसमें कोई नाम नहीं हुआ। तब उन्होंने सचप जारी करने का घोषणा की और कहा कि यह सचप अनकारा चुनाव कानूनों के खिलाफ होगा। 28 मार्च 1973 का गणराज्य में चांग्याल विरोधी प्रदर्शन का गणराज्य हुई और लोगों ने एक एक एक मन के नारे लगाये तथा जनता कांग्रेस के अध्यक्ष कृष्णचन्द्र प्रधान की रिहाई का आग्रह की। लेकिन चांग्याल पर उन प्रदर्शनों का कोई असर नहीं पड़ा।

29 मार्च से प्रदर्शनों में तबीयत लगा और यह सम्पूर्ण सिविकम में फैल गया। उस जन आन्दोलन ने बाद में त्वरित रूप धारण करके चांग्याल के शासन के पाहिरा लिये। चांग्याल ने अपने का रास्ता अपनाया और कुछ व्यक्तियों को कानून कर लिया गया। अखिर के प्रथम सप्ताह में सम्पूर्ण सिविकम में अमृतनूत राजनीतिक तनाव रहा। कानून की कानून-व्यवस्था ठप पड़ गयी। स्थिति गम्भीर हो गयी।

स्थिति का नियंत्रण में बाहर हाथ दख चांग्याल ने भारत सरकार से मदद मांगी। जनता के प्रतिनिधियों ने भी भारत सरकार से यह आग्रह किया कि वह कानून और व्यवस्था का जिम्मेवारा अपने हाथ में ले। सिविकम की जनता के प्रतिनिधियों ने भारत सरकार से यह आग्रह भी किया कि वह चांग्याल का प्रशासनिक ढाँचे में परिवर्तन के लिए बाध्य करे। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि जबतक सिविकम पर दार प्रशासनिक सधारों की दृष्टि नहीं प्रतीत करता तबतक लोगों ने कानून वादचोड नहीं हो सकता।

सिविकम के चांग्याल के अनुरोध पर 6 अप्रिल को भारतीय राजनैतिक अधिकारी एस. के. वाजपेयी ने सम्पूर्ण सिविकम में कानून और व्यवस्था की जिम्मेवारी

अपने हाथ में नहीं और भारत सरकार ने वास्तव में इस देश की निर्विक्रमता का मुख्य प्रयास निरूपित कर दिया। भारत सरकार ने कानून और व्यवस्था की देख रेख के लिए अपनी सत्ता भी निर्विक्रम भेज दी। निर्विक्रम की जनता ने इस बारवाई का स्वागत किया। किन्तु निर्विक्रम में भारतीय सत्ता का प्रवेश न करके प्रदत्तों का पता कर दिया। सबसे बड़ा सबब यह था कि भारतीय सत्ता निर्विक्रम में किसी हितों का रक्षा के लिए चुली? चोग्याल और निर्विक्रम दरबार के पक्ष में था कि निर्विक्रम जनता के पक्ष में? यह स्पष्ट है कि निर्विक्रम की जनता और शासकों के हित आज एक जैसे नहीं हैं एक का हित दूसरे का अहित है। इस हासत में भारत सरकार पर यह जिम्मेवारी है कि वह चोग्याल की जनता के साथ घातचोत करने के लिए बाध्य करे और निर्विक्रम जनता के हितों की रक्षा के लिए हर सम्भव प्रयास करे।

8 मई 1973 भारत सरकार की मध्यस्थता के पदस्वरूप निर्विक्रम में सभी सम्बद्ध पक्षों के बीच एक समझौता हो गया। वयस्क मताधिकार के सिद्धांत की मांगता मिल गयी और यह निश्चय किया गया कि निर्विक्रम में संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की जाय। इस प्रकार निर्विक्रम का शासन के प्रजातंत्रीकरण का रास्ता खुल गया और इसमें भारत सरकार की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रही।

भारत के सहस्राब्दी के रूप में निर्विक्रम—अप्रैल 1973 में जनता की राजनीतिक मांगों का उत्तर निर्विक्रम में हुए जनवादी आन्दोलन ने जब एक रूप धारण कर लिया तथा स्थिति जब चोग्याल के नियंत्रण से बाहर हो गयी तब चोग्याल और जनताओं के आग्रह पर भारत सरकार ने राज्य का सम्पूर्ण प्रशासन अपने हाथ में लेकर स्थिति को नियंत्रित किया। इसके पश्चात् 8 मई 1973 को जनता की मांगों को लेकर भारत सरकार के प्रतिनिधि चोग्याल तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। उपर्युक्त समझौते के अनुसार निर्विक्रम में पहले में अल्प प्रजातान्त्रिक संविधान की स्थापना के साथ एक पूर्णरूपेण जनता के प्रति उत्तरदायी सरकार की स्थापना की व्यवस्था की गयी। इस नये संविधान में जनता के मौखिक अधिकार विधि का शासन स्तम्भ तथा निर्विक्रम राज्यपालिका तथा जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को और अल्प विधायी तथा प्रशासकीय अधिकार प्रदान किये गये। इन समझौते में वयस्क मताधिकार सब वर्गों के लिए मांग समस्त प्रतिनिधित्व तथा एक व्यक्ति एक मत के सिद्धांत का स्वीकार किया गया।

15 अप्रैल 1974 को निर्विक्रम की बत्तीस सदस्यीय विधान सभा के लिए चुनाव हुआ। इस चुनाव में निर्विक्रम-कांग्रेस ने बत्तीस में एकतीस स्थान प्राप्त किये तथा कांग्रेस के प्रतिपक्ष दल नगनर पार्टी को केवल एक स्थान मिला। विधानसभा के अधिवेशन का प्रथम सत्र में ही निर्विक्रम कांग्रेस के नेता बाजी लेंदुपदोरजी ने एक प्रस्ताव पारित करवा कर चोग्याल के अधिकारों में कटौती की मांग करते हुए कहा कि उनकी भूमिका संवैधानिक प्रधान की होनी चाहिए। प्रस्ताव में भारत सरकार से अनुरोध किया गया कि नया संविधान बनाने के लिए वह निर्विक्रम में शीघ्र ही अपना सलाहकार नियुक्त करे।

20 जन 1974 को निर्विक्रम के लिए बनाये गये पहले लिखित संविधान को पारित करने के लिए शावज्जित निर्वाचन द्वारा गठित विधानसभा का अधिवेशन शुरू होनेवाला था तो चोग्याल के राजमहल के पहरेदारों और चोग्याल के कुछ सभ्यकों तथा उनके परिवार के सदस्यों ने विधानसभा के सामने सदस्यों का घेराव कर दिया और उन्हें भयन में डालने में सफल भी हो गये। दो सदस्यों का यह पहरेदार भगा

या। मगर अब परिस्थितियाँ बदल गयीं। भारतीय प्रतिष्ठा का एक सटक निर्माण विभाग न स्थानात् मजदूरों का सहयोग न कई नवा लोग चीन मुक्तों का निर्माण किया। भारतीय सामाजिक नेकर नद्वय भूतान का एक प्रमुख बन्दा तक य सटके जाता है। इस अतिरिक्त हवाई पट्टियाँ भी बनायी गयी हैं। हनीकाप्टर उड़ सकते हैं।

भारत का सहयोग न हा भूतान की नया राजधानी दिपू का निर्माण किया गया। बाँठ हनार फाट का ऊँचा पर स्थित यह नगर धीरे धीरे एक आधुनिक नगर का रूप ले रहा है। नयी नगर में भूतान का प्रशासनिक भवन, सचिवालय और अन्य महत्वपूर्ण भवन स्थित हैं। भारत का सहयोग न हा दूसरे नगर पारा में भी कई महत्वपूर्ण भवनों का निर्माण किया गया। शिक्षा तथा कृषि भवन और अन्य उपयुक्त सामग्री इन का अतिरिक्त भारत सरकार का सहयोग न भूतान में अस्पतालों का भी निर्माण किया गया। भारतीय इजानियरा द्वारा विद्युत् सञ्चालन भूतान में स्थित रात का उद्योग और विभिन्न स्थापना पर छत्रि पत्थरों का खनन का सम्बन्ध में उपयोगी सर्वेक्षण किया। भूतान का शासन पद्धति का आधुनिक बनाने के लिए भी भारतीय विद्युत् सञ्चालन का उपयोग किया गया।

सितम्बर 1971 में भूतान संयुक्त राष्ट्रसंघ का 127वाँ सदस्य चुन लिया गया। यद्यपि अपने आकार और जनसंख्या की दृष्टि से यह देश बड़ा नहीं है फिर भी संयुक्तराष्ट्र में इसका प्रवेश एक महत्वपूर्ण घटना था। यद्यपि भूतान का प्रतिष्ठा और शिक्षा मामलों में भारत का परामर्श सदा मान्य रहा है फिर भी इन पहलुओं पर भी अपने राष्ट्रीय अस्तित्व का अभिव्यक्ति का अभिव्यक्ति बढ़ती गयी रहा था। इसलिए यह स्वाभाविक था कि इस राष्ट्रवाद को विरोध का रूप लेने से रोकने के लिए भूतान का राजा को संयुक्तराष्ट्र उस अंतराष्ट्रीय मंच पर अपनी अंतर्गत की आवाज पहचान के लिए प्रयास किया जाय। 1966 में हा राजा ने एक व्यक्ति का भी कि वह संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनना चाहते हैं मगर भारत का इस प्रस्ताव का समर्थन करने का वादक भूतान ने तुरंत सदस्यता के लिए जा नहीं दिया। अतः कई वर्षों तक संयुक्तराष्ट्र महानभा में अपने पर्यवेक्षक भेजकर यह समर्थन का कारण का कि वह अंतराष्ट्रीय मंच का काम किस प्रकार होता है। कुछ लोगों ने यह गुनाह्यक्त की कि भारत भूतान को भारत पर विश्वास नहीं द्या है इसलिए वह शिक्षा मामलों में अपनी राय अन्य देशों पर अन्य प्रकट करने का प्रयास कर रहा है। मगर वास्तविकता यह है कि भूतान का महाराजा का इस बात का ध्यान था कि यदि उन्होंने भारत और चीन का बीच निश्चित नाति द्या बना करके तत्पश्चात् की नाति अपनायी ता भूतान का लिए खतरा न हो सकत है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने का बात भी भूतान विदेशी और सैनिक मामलों में भारत का परामर्श का मान्यता प्रदान करता रहा। भूतान का विकास कार्य में भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है और यह भूतान के लिए न तो जहाँ तक हा तक भारत का हा अपनी प्रगति के सम्बन्ध में मादन्तक स्वाकार करें क्योंकि जहाँ तक की परिस्थितियाँ समान हैं। भारतीय विद्युत् और कारागर अन्य विद्युत् कारीगरों का अपना काम मध्य में प्राप्त किया जा सक्त है तथा भूतान के छात्रों का शिक्षा भी का लिए भारत से अधिक उपयुक्त स्थान नहीं भी नहीं है।

बगना दान में घट रहा घटनाओं का प्रति भूतान न बगना न को अपना न नति समर्थन दिया और भारत के बाँट वहा ऐसा दान या जिसने लक्ष्य स्वतंत्र

बंगला देश को मायता प्रदान की। 20 अगस्त 1972 का भारत ने यह घोषणा कर दी कि वह केवल भारत और बंगला देश के साथ ही राजनयिक सम्बन्ध रखेगा।

सितम्बर 1972 में भारत के नरेश की मृत्यु के बाद दोरजी जिग्मी सिंग्चे बागचक भारत के नये नरेश बने। इस अवसर पर भारतीय प्रधान मंत्री की बधाई का उत्तर देते हुए नये नरेश ने कहा कि मर हुय में भी भारत के प्रति वही सम्मान की भावना है जो मर पिता के दिन में थी। इससे यह स्पष्ट है कि भूटान के साथ भारत का सम्बन्ध घनिष्ठ बन जाता जा रहा है।

राष्ट्रमण्डल, ब्रिटेन और भारत

(INDIA BRITAIN AND COMMONWEALTH)

राष्ट्रमण्डल का स्वरूप—ब्रिटिश साम्राज्य (British Empire) ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल (British Commonwealth) और राष्ट्रमण्डल (Commonwealth) एक ही संस्था के दो अंग हैं। दोनों एक ही प्रणाली के अंतर्गत हैं और ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत हैं। किंतु आजकल राष्ट्रमण्डल शब्द का ही अधिकारिक प्रयोग किया जाता है।

राष्ट्रमण्डल एक विशिष्ट प्रकार का संगठन है जिसमें न तो प्रादेशिक संगठन कहा जा सकता है और न एक राज्य (State) का संगठन जा सकता है। यह न राष्ट्र है न मंत्री परिषद और न संघ है। इस संस्थापरि संस्था भी नहीं कहा जा सकता है।

इस स्वरूप के वाक्य राष्ट्रमण्डल के मन्त्र का काम नहीं किया जा सकता। आधुनिक युग का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंतराष्ट्रीय मंच है जिसके प्रस्तावों और निर्णयों का विश्व का राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रों के बीच यह स्वतंत्रतापूर्ण सहयोग का एक प्रतीक है और अंतराष्ट्रीय युग का एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली यथावत है। यह एक ऐसा मंच है जिस पर विश्व के कुछ दशक समय समय पर एकत्रित होते हैं। एक मुक्त विचारों की जानने का चेष्टा करते हैं और जिन बातों पर मतभेद होते हैं उनमें पारस्परिक सहयोग के लिए कार्यक्रम बनाते हैं और उसे कार्यान्वित करते हैं। मुख्य राष्ट्रों के बीच अनेक मतभेदों के बावजूद राष्ट्रमण्डल सहयोग का प्रतीक है।

औपनिवेशिक सम्मेलन—1887 में साम्राज्य विचारों का युग की हनु सम्मेलन में स्वतंत्रता के विचारों के प्रधानमंत्री एकत्र हुए। इस अवसर का नाम लगाकर स्वतंत्रता के विचारों तथा साम्राज्य के कुछ बड़े औपनिवेशिक प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन सम्पन्न किया गया। यह प्रथम औपनिवेशिक सम्मेलन (Colonial Conference) कहा गया। साठ वर्ष बाद एक दूसरा औपनिवेशिक औपनिवेशिक सम्मेलन आटावा में हुआ। इसमें ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा एवं आचार व्यवस्था तथा व्यापारिक सम्बन्धों पर विचार हुआ। फिर 1897 में साम्राज्य विचारों द्वारा हारक जयंती के हनु औपनिवेशिक मंत्रियों के आगमन का नाम लगाकर द्वितीय औपनिवेशिक सम्मेलन लंदन में हुआ गया। 1902 में मद्रास अष्टम एडवर्ड के राज्याभिषेक के अवसर पर औपनिवेशिक सम्मेलन का तृतीय सम्मेलन हुआ। चौथा औपनिवेशिक सम्मेलन 1907 में हुआ। उपरोक्त सभी सम्मेलनों में एक महत्वपूर्ण या कर्तव्य इसने सम्मेलन का एक नयी स्थायी स्थापना।

नव विधान के अनुसार प्रथम औपनिवेशिक कांफ्रेंस 1911 में हुआ। इसने 1907 के कार्य का आगे बढ़ाया और सम्मेलन के गठन उपनिवेश कायान्वय के पुनर्गठन और सचिवा के सम्बन्ध में प्रतिनिधित्व में परामर्श के सम्बन्ध में कार्यवाही की विचारनामिका सचिवा के मध्य में मुद्रा प्रारम्भ या बन्द करने के क्षेत्र में प्रतिनिधित्व का

कार्ड शक्ति नहीं दी गयी फिर भी संधियाँ के सम्बन्ध में सम्मेलन ने इन आशय का एक मसौदा प्रस्ताव पस किया कि हेग सम्मेलन (Hague Conference 1911) के ब्रिटिश प्रतिनिधियों को दिये जानवाले अनुदेशकी (instructions) संसार भर के समय डोमिनियनों से भी परामर्श लिया जायगा और उस सम्मेलन में अस्थायी रूप से स्वीकृत किये गये डोमिनियनों को प्रभावित करने वाले कर्बों को उनका विचार के लिए डोमिनियनों की सरकार का भेजा जायगा ।

विशेष नीति के सम्बन्ध में डोमिनियनों को सामित अधिकार का पता इससे चलता है कि 4 अगस्त 1914 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा डोमिनियनों से परामर्श किए बिना ही कर दी गयी । ब्रिटिश सरकार की इस घोषणा के द्वारा डोमिनियनों को भी युद्ध में शामिल कर लिया । डोमिनियनों ने इसका विरोध नहीं किया और बड़े उत्साह से युद्ध प्रयासों में जुट गये । विश्व युद्ध में डोमिनियनों ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की ।

विश्व युद्ध के कारण 1915 में हागे वांग डम्पीरियल का फ़ैम नज़र आ सका लेकिन डोमिनियन मंत्रियों की सदन यात्रा का गंभीर उदात्त उनमें विचार विमर्श किया गया । इस विचार विमर्श के क्रम में डोमिनियन सरकारों के प्रतिनिधियों ने यह मांग की कि ब्रिटिश विशेष नीति के निराकरण में हिस्सा बंटान का अवसर उन्हें भी मिलना चाहिए । डोमिनियनों की यह मांग स्वीकारित थी । ब्रिटिश विदेश नीति का प्रभाव उन पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ रहा था । सो के परिणामस्वरूप 1915 में शामिल होना पड़ा था और युद्ध में उन्हें अपार धन जन का बलिदान करना पड़ रहा था । लेकिन प्रारम्भ में ब्रिटिश सरकार इस मांग का स्वीकार करने का प्रस्तुत नहीं हुई । 1916 में जब लार्ड जॉर्ज प्रधान मंत्री हुए तो उन्होंने इस प्रस्ताव पर विचार किया और सन्धि के लिए डोमिनियनों के प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया । इस सम्मेलन के साथ साथ इम्पीरियल वार कबिनेट (Imperial War Cabinet) की स्थापना की गयी । वार कबिनेट की बैठकों में युद्ध और शान्ति दोनों समस्याओं पर विचार होता रहा । वार कबिनेट की बैठकों में समस्त महत्वपूर्ण विषयों में प्रधान मंत्रियों का सहभागिता करने की प्रथा चली गयी । यदि देखा जाय तो आजकल होनेवाले प्रधान मंत्री सम्मेलन का यह पूर्व रूप था । सम्मेलन में यह भी निणय किया गया कि इम्पीरियल वार कबिनेट का सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाय ।

4 अप्रैल 1917 को इम्पीरियल का कफ़ेड ने एक प्रस्ताव स्वीकार करके भारत को स्थायी रूप से अपना सदस्य बना लिया । यह बात भारत प्रत्यक्ष इम्पीरियल काफ़ेड के सम्मेलनों में नियमित ढंग से सदस्य के रूप में भाग लेता रहा । भारत के इतिहास में यह महत्वपूर्ण घटना थी । यह नण्य इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि भारत की डोमिनियन स्थिति प्राप्त करने की आकांक्षाओं को पहली बार स्वीकृति मिली और स्वशासी अधिकार्य हुए बिना कुछ अंश में उनकी डोमिनियन का दर्जा मिल गया ।

प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रमण्डल का विकास—प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रमण्डल का स्वरूप निखरने लगा । डोमिनियनों को पुष्पक रूप से परिण के शान्ति सम्मेलन में भाग लेने का अधिकार मिला और उनके प्रतिनिधियों ने स्वतंत्र रूप से वसूली संधि एवं अन्य शान्ति संधियों पर हस्ताक्षर किये । वे राष्ट्रमण्डल के सदस्य भी बनावे गये । डोमिनियनों के साथ साथ भारत को भी अपने अन्तर्देशीय स्थितियों का विकसित करने का मौका मिला ।

पेरिस के शांति सम्मेलन के उपरांत होमिनियन को तत्काल अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्वतंत्र देश का दर्जा दिया जाना था। होमिनियन सरकारें अब विदेश में अपने कूटनैतिक तथा वाणिज्य प्रतिनिधि भेजने लगी थीं। 1926 में बनाया गया गठन में अपने दूत नियुक्त किये। होमिनियन सरकारों के साथ सभी प्रकार की पर्यक सुधिया के सम्बन्ध में बातचात करने लगी थीं। इस प्रकार होमिनियन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपना स्थान बनाते रहे। यह प्रक्रिया कभी रुकी से चलता कभी मन्द गति से।

राष्ट्रमण्डल और द्वितीय विश्व युद्ध—होमिनियन का स्वतंत्र और विशिष्ट स्थिति का मान द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने पर हुआ है। यह प्रथा स्पष्ट हो गयी कि राष्ट्रमण्डल के सदस्य राष्ट्रों को स्वतंत्र रूप से यह नियम करने का अधिकार है कि वे युद्ध में भाग लेना चाहते हैं या नहीं। प्रथम विश्व-युद्ध के समय होमिनियनों को यह अधिकार नहीं था।

राष्ट्रमण्डल का वर्तमान स्वरूप—द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक राष्ट्रमण्डल मुख्यतः कुछ श्वेत देशों की समस्या थी लेकिन युद्धोपरांत राष्ट्रमण्डल एक नये युग में प्रवेश किया। युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका के कई ब्रिटिश उपनिवेश स्वतंत्र हो गए और उन्होंने राष्ट्रमण्डल में बन रहने का निश्चय किया। राष्ट्रमण्डल का वर्तमान स्वरूप 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप की स्वायत्तता के बाद सामन आया। स्वायत्तता प्राप्त करने के बाद भारत और पाकिस्तान ने राष्ट्रमण्डल में बन रहने का निश्चय किया। 1950 में गणराज्य बन जाने पर भी भारत ने राष्ट्रमण्डल से अलग न होने का फैसला किया और ब्रिटिश सम्राट को राष्ट्रमण्डल के प्रधान के रूप में स्वीकार किया। इस कारण ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के स्थान पर इस क्षेत्र राष्ट्रमण्डल कहने का निश्चय लिया गया। यह बात सत्य है कि जहाँ भारत पाकिस्तान तथा आदि देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त की बाद भी राष्ट्रमण्डल का सन्ध रह। स्वाकार किया वहाँ बना और दक्षिणी अफ्रीका सहित सदस्यता से अलग हो गये। बाद में जो भी ब्रिटिश उपनिवेश स्वाधीन हुए उन्होंने राष्ट्रमण्डल की सदस्यता स्वीकार कर ली। इस समय राष्ट्रमण्डल के सदस्य देशों की संख्या अठारह है जिनके नाम हैं ब्रिटन ब्रिटेन आस्ट्रेलिया यूजीएण्ड भारत पाकिस्तान तथा धान नाइजीरिया साइप्रस सियरा लियोन, जमका त्रिनिदाद टोबैगो उगान्डा कैमरून मलायिया तंजानिया मंगो माल्टा जाविया गाम्बिया सिंगापुर गुयाना बोत्सवाना लेसोथो वर्वाडास मारिशस और स्वाजीलैंड। इनका बनाया हुआ एकत्रित ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल ब्रिटानी हॉट्टन फिरो गिनबट आदि भी राष्ट्रमण्डल से सम्बद्ध हैं। ये सभी ब्रिटन के सुरक्षित अथवा आश्रित प्रदेश हैं। राष्ट्रमण्डल के स्वायत्त सदस्य देशों को कुछ जनसंख्या अस्वी कराह से भी अधिक है और ये एक कराह वर्गीय से भी अधिक भू भाग पर फैले हुए हैं।¹

राष्ट्रमण्डल का संगठन—जुलाई 1965 तक ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेशों के मामलों में औपनिवेशिक कार्यलय से सम्बद्ध था। 1925 में ब्रिटन तथा राष्ट्रमण्डल के स्वराज्यी सदस्यों के सम्बन्धों के लिए होमिनियन के मामलों के लिए एक अलग मंत्री को नियुक्ति की गयी। जुलाई 1947 में होमिनियन मामलों के मंत्री और

1. 1965 में स्वतंत्रता की एकरूपी घोषणा करके रोरेगिया ने राष्ट्रमण्डल में अपना सम्पन्न नया रखने का निश्चय किया। इसके पूर्व 1961 में अफ्रीकी सभी राष्ट्रमण्डल से अलग हो गया था।

कार्यालय के नाम रख कर कमला राय ट्रस्ट मंत्री (Secretary of State for Commonwealth Affairs) की अध्यक्षता में सम्पन्न की जायगी। अगस्त 1966 से औपनिवेशिक कार्यालय (Colonial Office) का राष्ट्रमण्डल कार्यालय में विलय कर दिया गया और राष्ट्रमण्डल कार्यालय की स्थापना की गयी। 17 अक्टूबर 1968 को विदेश मन्त्रालय (Foreign Office) में राष्ट्रमण्डल कार्यालय को भी मिला दिया गया। इस प्रशासनिक समन्वय का केंद्र बनने की दृष्टि से किया गया।

जुलाई 1964 के राष्ट्रमण्डल व प्रधान मंत्री सम्मेलन के बाद प्रकाशित विज्ञापित में राष्ट्रमण्डल सचिवालय का स्थापना के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये गये थे। जून 1965 के सम्मेलन में प्रस्ताव स्वीकार कर दिये गये। पनस्वरूप राष्ट्रमण्डल सचिवालय का विधिवत गठन हुआ। कनाडा के आर्गो ड हिम्प राष्ट्रमण्डल के पहले मन्त्रिमन्त्रि बनाये गये जिन्होंने 17 अगस्त 1968 को कार्यभार सम्हाला।

ब्रिटिश क्राउन राष्ट्रमण्डल का प्रमुख अंग है जिसे सभी सदस्य राष्ट्र राष्ट्रमण्डल के प्रधान के रूप में स्वीकार करते हैं। यद्यपि सभी सदस्य राष्ट्रों के समक्ष प्रत्येक कोई बंधनक शक्ति प्राप्त नहीं है। क्राउन (Crown) जैसा सम्राट या सम्राज्ञी को केवल प्रतीक के रूप में राष्ट्रमण्डल का अंग माना जाता है।

राष्ट्रमण्डल का दूसरा और सर्वाधिक प्रभावशाली अंग राष्ट्रमण्डलीय प्रधान मंत्री सम्मेलन (Commonwealth Prime Ministers Conference) है। इसका आविर्भाव समय-समय पर क्राउन में ब्रिटिश प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में होता है। 1944 में लेकर अब तक (1969 तक) इस तरह के सात सम्मेलन हुए हैं। इन सम्मेलनों में राजनीतिक और आर्थिक मसल खर्चा के मुख्य विषय रहते हैं। सम्मेलन अपने समय के उभरते हुए अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार करता है। 1965 के सम्मेलन में विश्व में शांति स्थापना की दृष्टि से ब्रिटिश प्रधान मंत्री हारोल्ड विलसन की अध्यक्षता में एक शांति समिति बनायी गयी। इसमें यह काम सौंपा गया कि यह विद्यमान समस्याओं पर अन्तर्राष्ट्रीय विचार विनिमय करने विद्यमान शांति स्थापना के प्रयास करें। इसी सम्मेलन में रोडेसिया के स्वतंत्र पर भी विचार किया गया।

राष्ट्रमण्डल में भारत की स्थिति

राष्ट्रमण्डल की सदस्यता भारत में प्राचीन ही विवादोत्पन्न विषय रहा है। स्मरणीय है कि राष्ट्रमण्डल की पूर्ववर्ती संस्था एम्पिरियल कॉमन्वेल्थ में भारत ने 1917 में प्रवेश किया और तब से लेकर तब तक यह इसका सदस्य बना हुआ है। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तब प्रथम बार उठा कि भारत राष्ट्रमण्डल का सदस्य रह पा नहीं। भारत सरकार ने राष्ट्रमण्डल का सदस्य बन करने का निश्चय किया। 1950 में भारत का गणतन्त्रिक परिवर्तन हुआ। उस समय यह प्रश्न उत्पन्न कि एक गणराज्य किस प्रकार वही सदस्यता का सदस्य बन सकता है जिसका प्रधान एक राजा है। लेकिन इन समस्याओं का समाधान एक सम्मेलन के द्वारा किया गया। भारतीय लोकमत का सन्तुष्ट करने के लिए ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल में ब्रिटिश शासन को हटा दिया गया और इस तरह नए संगठन का नाम ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के स्थान पर केवल राष्ट्रमण्डल हो गया। अब प्रश्न था कि ब्रिटिश सम्राट के प्रति भारत का

रख क्या होगा। वह राष्ट्रमन्त्र का प्रस्ताव पारित करने का जोर एक अलग ही दिशा में लिए इस स्थिति का बखूब काना कूट करती थी। इस कठिनाई का पूरा कानन न लिए बाह्यराष्ट्रों का प्रयोग किया गया। 28 जून 1949 का भारत के हक का पान उस प्रधान मंत्री सरकार के अन्तर्गत पारित प्रस्ताव में प्रतिबिम्बित हो रहा था। भारत का एक सम्पूर्ण प्रभुता सम्पन्न राष्ट्र का निर्माण किया प्रस्ताव था उस सम्प्रदाय से प्रभावित नहीं होती है क्योंकि हमें अन्तर्निहित राजा के प्रति निष्ठा रखने का काम करना नहीं होता। राजा तो केवल हमारे अनुसृत सम्प्रदाय का अंग सम्प्रदायों का एक बखूब प्रतीक होगा क्योंकि हमारे सविधान का सम्प्रदाय है वह सभी का और जोर बाह्य राजों में स्थापित करने में रहता। आप अपने विश्व राष्ट्रमन्त्र का प्रस्तावता करके स्वतंत्र राजों के अनुसृत सम्प्रदाय के प्रतीक हो। तब ही सम्भव होगा।

उस प्रकार भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति और अपने का अन्तर्गत सम्प्रदाय बनने के रूप में राष्ट्रमन्त्र का सम्प्रदाय बनने का निश्चय किया। इसके सम्प्रदाय में बड़े प्रतिक्रियाएँ आईं। कुछ लोगों का कहना था कि भारत का अन्तर्गत सम्प्रदाय के लिए राष्ट्रमन्त्र का सम्प्रदाय बना रहता एक राज्य का राजा है। जिस राजा ने हमें सड़कों वहाँ तक जाने बनकर रखा और भारत का अन्तर्गत सम्प्रदाय बनने रचना और उसके सम्राट का नाममात्र के लिए ही अध्ययन स्वीकार करना हमारा सम्प्रदाय बनने का परिचायक है। राष्ट्रमन्त्र का सम्प्रदाय बनने रचना के भारत सरकार के नियम ने के राज्यों का अन्तर्गत सम्प्रदाय बनने रचना है। राष्ट्रमन्त्र का पदवर्ती सम्प्रदाय इम्पारियल कास्टोस में भारत ने 1917 में प्रदत्त किया था और उसी लिए वे एक आन्तरिक भी बना था। लेकिन उस आन्तरिक का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेताओं (जो किन के प्रति पूरा सम्मति सम्प्रदाय) द्वारा निर्धारित सम्प्रदाय (Liberal Federation of India) के अन्तर्गत बनने रचना था जो वे विस्तृत थे। लेकिन गाँधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 में सम्प्रदाय का मांग कर रखा। अध्ययन पर सम्प्रदाय बना रचना सम्प्रदाय बनने रचना कि भारत पूरा स्वायत्त का स्थापना का मांग करता है और उस पूरा सम्प्रदाय का यह हाथ कि वह ब्रिटिश राष्ट्रमन्त्र में निष्ठा प्रकार का सम्प्रदाय नहीं रहे। प्रतिबन्ध का बखूब था कि ब्रिटिश राष्ट्रमन्त्र के सम्प्रदाय भारत बनने रचना सम्प्रदाय रचना या उसका विपरीत की सम्प्रदाय रचना। नाति का प्रयोग परामर्श में सम्प्रदाय करता। भारत के लिए एक एक सम्प्रदाय स्थिति पाता। 2 सम्प्रदाय सम्प्रदाय का प्रयोग ने राष्ट्रमन्त्र के तर्कों से प्रभावित भारत के अन्तर्गत सम्प्रदाय (1921) में परामर्श रचना

1 Jawaharlal Nehru considered the very idea of a vast and ancient country like India remain a Dominion of England (which implied the membership of the British commonwealth) to be ridiculous and humiliating. He did not believe in reforming imperialism by entering into a partnership with it. The British Commonwealth in spite of its high sounding name he pointed out did not stand for true international co-operation. It was an exclusive system whose membership would deprive India of the freedom to develop contact with the world at large especially with the countries of Asia. One of his great objections to the Dominion status was that would mean the involve

प्रस्ताव किया। इस प्रस्ताव में स्वीकार करने का जय था कि जिस न जवाहरलाल नेहरू के विचारों को मानकर निश्चय कर लिया कि भारत ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल में हर प्रकार के सम्बन्धों को तोड़ दे।¹

स्वतंत्र भारत के प्रधान मंत्री बनने के उपरान्त जवाहरलाल नेहरू की दृष्टिकोण बनने वाले उद्देश्यों ने निश्चय किया कि भारत राष्ट्रमण्डल का सन्तुलन बना रहेगा। अपनी इस परिवर्तित मनोकृति को उचित दृष्टांत दृष्टान्त न केवल स्वतंत्र विश्व में जबकि अनेक विध्वंसकारी शक्तियाँ सज्जित हैं और हम प्रायः युद्ध की जगह पर खड़े हैं मैं सोचता हूँ कि किसी समुदाय में सम्भव विध्वंस करना अभी या नहीं। एक ऐसे सहकारी समुदाय की दृष्टि करने की अपेक्षा जीवित रहता ही जाता है जो वर्तमान विश्व में कुछ हितकारी कार्य कर सकता है। राष्ट्रमण्डल की अस्तित्वता भारत के और सम्पूर्ण विश्व के हित के लिए सहायक है। इससे भारत की उदया की प्रगति में सहयोग मिलेगा।²

इस स्थिति पर इस प्रश्न का उठना कि जवाहरलाल नेहरू के विचारों में इस तरह का परिवर्तन किन किन कारणों से प्रेरित हुआ था। भारतीय संविधान सभा में बोलते हुए नेहरू ने राष्ट्रमण्डल में बन रहने के पक्ष में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये थे

(1) यह समझौता स्वतंत्र इच्छा पर आधारित है और स्वतंत्र इच्छा द्वारा ही रद्द भी किया जा सकता है।

(2) परस्पर मन्त्रीपण व्यवहार तथा सहयोग की इच्छा के अतिरिक्त किसी सदस्य पर किसी तरह का कोई दायित्व या बन्धन नहीं है और उम्र में शक्त है प्रत्येक राष्ट्र अपने इस व्यवहार तथा सहयोग की मात्रा का निश्चय स्वयं अपनी नीति के आधार पर करेगा।

(3) ब्रिटिश सम्राट का राष्ट्रमण्डल का प्रतीक माना गया है परन्तु व्यवहार में वह निराला प्रभावहीन है।

(4) भारत की स्वाधीनता तथा स्वतंत्रता में निषेध न जरा भी मोहित या प्रभावित न हुआ है।

(5) भारत राष्ट्रमण्डल को न तो किसी एसी शक्ति के अन्तर्गत स्थापित करने को ही तयार है कि वह राष्ट्र की संप्रभुता को मोहित करनेवाली बन और न भारत से बातें कि जिसकी मद्दति दगा कि मन्त्रिमण्डल के पारस्परिक संबंधों को राष्ट्रमण्डल के सम्पूर्ण पेश किया जाय। यह एक अलग बात है कि भारत मन्त्रिमण्डल के पारस्परिक विवादों पर मन्त्रीपण बातों में भाग लेने की तयारी हो जाय।

(6) भारत प्रजातिभेद और अनिर्देशिता पर अत्यन्त विचारों को अत्यन्त रक्षक और उन इन प्रश्नों पर स्वतंत्र निषेध न का पण अधिकार प्राप्त है।

ment of India in the reactionary for eign policy of Britain

—S R Mehrotra *India and the Commonwealth* p 130

1 Thus the Congress had accepted Jawaharlal Nehru's view that India sever all connections with the British Commonwealth

—R Coupland *The Indian Problem* p 100

2 Constituent Assembly Debates May 16 1949

(7) राष्ट्रमण्डल में भारत के अधिकारों का प्राप्त करने में सहयोग मिलेगा। अन्य देश भी पारस्परिक लाभ के निम्नता के आधार पर ही भारत को राष्ट्रमण्डल की सदस्यता प्रदान करना चाहते हैं। आज एक दूसरे पर निर्भरता का गुण है। भारत अपने व्यापार वाणिज्य और अपना अनक वस्तुओं के लिए दूसरों पर निर्भर है। ब्रिटन में हमारे प्राचीन सम्बन्ध हैं और हम कुछ वस्तुओं के लिए बहुत कुछ उस पर निर्भर हैं। अब उनके साथ पूर्णतः संबंध विच्छेद कर देने में हमारी अर्थ व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(8) सम्पूर्ण विश्व यह बात देखेगा और समझेगा कि भारत उनके साथ भी सहयोग स्थापित कर सकता है जिसके विशद सबूत हमने सपष्ट किया है।

(9) राष्ट्रमण्डल की सदस्यता अन्य देशों के साथ भारत के मनीषण और सहयोगी सम्बन्धों की स्थापना के माग में बाधक नहीं।

(10) राष्ट्रमण्डल से पृथक्ता का अर्थ होगा भारत को कुछ समय के लिए विश्व से पृथक् हो जाना। यह एक असम्भव स्थिति होगी और वातावरण के प्रभाव में हमारा अकाब किसी न किसी ओर अवलम्ब होगा।

इन तथ्यों के अतिरिक्त नेहरू को एक दो और बातों में राष्ट्रमण्डल में रहने के बने रहने के निश्चय किया और प्रेरित किया। इसका एक आर्थिक कारण था। आर्थिक दृष्टि में भारत का आधिकारिक व्यापार ब्रिटन और राष्ट्रमण्डल के देशों पर निर्भर था। इस हानि में एक-एक राष्ट्रमण्डल से सम्बन्ध विच्छेद कर लेने में कठिनाई थी।

सैनिक दृष्टिकोण से उस समय भारत पूर्णतया ब्रिटन पर आश्रित था। अपने विस्तृत समुद्रतटीय सीमा की रक्षा के लिए भारत ब्रिटन की नौसेना पर आश्रित था। भारत का पूरा सैनिक संगठन ब्रिटिश पद्धति पर आधारित था और सैनिक आयुधों के लिए वह ब्रिटन का मुहताज था।

राष्ट्रमण्डल में बने रहने के निम्न में कुछ लोगों के व्यक्तिगत निर्णायक पाट अलग किया। अतिम ब्रिटिश गवर्नर जेनरल लॉर्ड माउटबेटन ने नेहरू को निश्चित रूप से प्रभावित किया। स्वयं नेहरू की अग्रेसरियत ने अतिम फसला में सहयोग पाट अदा किया।¹ जिस समय जबालूर लॉर्ड नेहरू ने राष्ट्रमण्डल में बने रहने का फैसला किया उस समय उनके सामने अन्य उद्देश्यों के साथ शायद एक उद्देश्य यह भी रहा होगा कि जिस मंच के द्वारा भारत गवर्नमेंट अफ़िकी और एशियाई देशों का मरगना बन सकता है। स्वाधीनता की तरह दूसरे मामलों में भी उनका मागदान कर सकता है। किन्तु नेहरू की नीतिमो की विफलता के कारण ऐसा नहीं हो सका और आज स्थिति यही है कि आज वह भी कि भारत में न केवल विरोधी पक्षों (विशेषकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी) की ओर से राष्ट्रमण्डल छोड़ने का माग की जाती है बल्कि प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी भी परोक्ष रूप से यह स्वीकार करने लगी हैं कि हो सकता है कि ऐसा समय आए जबकि राष्ट्रमण्डल से भारत को अलग होना पड़े।

1. जब जो सभा तथा विचारधारा के प्रति नेहरू की वफा मोन था। अपनी आसक्ति में उन्होंने लिखा है *All my prelection (apart from the political plane) are in favour of England and English people and if I have become what is called an uncompromising opponent of British rule in India it is almost in spite of myself* Jawaharlal Nehru *An Autobiography* P 419

फिर भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि राष्ट्रमण्डल में भारत के बने रहने का जवाहर लाल नेहरू का निर्णय बड़ा महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। गणतन्त्र बनने के बाद नेहरू ने भारत के राष्ट्रमण्डल में बने रहने का जो निर्णय किया उससे प्रभावित होकर ही ब्रिटेन के अर्थ उपनिवेश स्वाधीन होने के बाद राष्ट्रमण्डल में शामिल हुए और उसे विशाल संगठन का रूप दिया। इसी कारण जवाहरलाल को आधुनिक राष्ट्रमण्डल का पिता माना जाता है।

राष्ट्रमण्डल के साथ भारत का सम्बन्ध—इसमें कोई सन्देह नहीं कि राष्ट्रमण्डल में रहने से भारत की स्वतन्त्रता पर कोई आंच नहीं आती और अपनी नीति के निर्धारण में वह पूर्णतया स्वच्छन्द है। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि राष्ट्रमण्डल की सदस्यता भारत के लिए पूरी तरह उपयोगी है। यह तो मानना ही पड़ेगा कि राष्ट्रमण्डल का नतीजा ब्रिटेन है और यह एक मूल्य शिष्टि सस्था है। पर भारत के कुछ अंतर्राष्ट्रीय विवादों में भारत के प्रति ब्रिटेन का दखल अमैत्रीपूर्ण रहा है। भारत और पाकिस्तान के सम्बन्ध में यह बात विशेष रूप से सत्य है। उसने भारत के विरुद्ध पाकिस्तान का हमेशा समर्थन किया है। 1965 के वर्ष के मामले पर उसने पाकिस्तान का पक्ष लिया। कश्मीर के प्रश्न पर उसने सदा पाकिस्तान का समर्थन किया है। 1965 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष में ब्रिटेन ने भारत को आशमय कहा और मुसीबत के क्षणों में भारत को सैनिक सहायता देने से बचकार किया। ब्रिटेन के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश समान थे क्योंकि दोनों राष्ट्रमण्डल के सदस्य थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार पहले सतर्क रही और अपनी आँखें पाकिस्तानी पुसपैठियों की ओर से बंद कर ली। भारत-पाक संघर्ष में ब्रिटेन ने निरपेक्ष ही एक पक्षीय दृष्टिकोण अपनाया।

भारत में ब्रिटेन के इस रवये के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया हुई और 24 सितम्बर 1965 में भारतीय ससद् में हुई बहस के दौरान भी यह मांग की गयी कि भारत राष्ट्रमण्डल का परित्याग कर दे। एक सदस्य ने कहा कि भारत के समस्त खजाने ही रास्ते हैं। वह राष्ट्रमण्डल को छोड़ दे या ब्रिटेन को राष्ट्रमण्डल का नेतृत्व करने से रोक दे।

बेन्गाल के प्रवासी भारतीयों की समस्या को लेकर 1968 के प्रारम्भ में ब्रिटेन और भारत के सम्बन्ध में पुनः सनाय पैदा हुआ और भारत में राष्ट्रमण्डल के परित्याग की बात उठने लगी। 1963 में जब बेन्गाल स्वतन्त्र हुआ उस समय वहाँ पक्षीस हजार के लगभग भारतीय निवास करते थे। बेन्गाल की स्वतन्त्रता के अवसर पर भारतीयों के समक्ष एक विशद समस्या उत्पन्न हो गयी। यह समस्या उनकी नागरिकता से सम्बन्धित थी। उस समय भारत सरकार ने चार भारतीयों को पासपोर्ट दिया और साथ भारतीय ब्रिटेन के पासपोर्ट पर ब्रिटन में रहने लगे।

हाल के वर्षों में अफ्रीकी देशों में सदस्यों की गुप्तगी के बाद अफ्रीकीकरण की जो भावना पैदा हुई उसमें बेन्गाल की सरकार अछूती नहीं रह सकी। बेन्गाल से पहले तंजानिया और उरुग्वे में एशियाई और नागरिकों को निकालित किया जा चुका था। फरवरी 1968 में बेन्गाल की सरकार ने यह निर्णय लिया कि तेरे एशियाई लोगों को जो वहाँ के नागरिक नहीं हैं उनके साथ बेन्गाल में गैर-नागरिक जैसा व्यवहार किया जाय। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि बेन्गाल में बने एशियाईयो

को जीवन यापन में बंचित हो जाना पड़ा।

क्या सरकार के इस निणय में प्रवासी भारतीयों में तहलका मच गया। 1963 में क्या की स्वाधीनता के समय ब्रिटिश पासपोर्ट प्राप्त करके वे ब्रिटिश नागरिक बन गये थे। अतः यह उम्मीद की जा सकती थी कि ब्रिटिश इन लोगों के प्रति अपना ज़िम्मेवारी का निवाह करेगा किन्तु जब केन्या के भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक अपने का वहाँ अरबित अनुभव करके ब्रिटिश भागने लगें तो ब्रिटेन ने एचि याई बाब का रोकने के उद्देश्य में संसद में एक विधेयक पेश किया। उस विधेयक का उद्देश्य 1 मार्च 1968 के बाद क्याई भारतीयों का ब्रिटेन में प्रवेश में रोकना था। ब्रिटिश संसद ने इस विधेयक को पारित कर दिया। ब्रिटिश के इस कानून के मुताबिक उस पासपोर्ट की कोई कीमत नहीं रहे। जा ब्रिटिश न लिये थे तथा केन्या के भारतीय जब ब्रिटिश में जाकर नया बस सकते थे।

इस घटना ने भारत और ब्रिटिश के संबंध में तनाव उत्पन्न कर दिया। केन्या के भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिकों की ज़िम्मेवारी स्पष्टतः ब्रिटिश पर थी। किन्तु ब्रिटिश ने इस ज़िम्मेवारी को निभाने से मुंह मोड़ दिया। इस स्थिति में भारत क्या करता? जहाँ तक कानूनी स्थिति का संबंध था भारत पर उनकी कोई ज़िम्मेवारी नहीं थी। किन्तु समस्या का एक मानवाय पक्ष भी था। उसके अतिरिक्त केन्या और ब्रिटिश के निणय से प्रभावित होने वाले भारतीय ही सबसे अधिक थे।

जिस समय ब्रिटिश संसद में ब्रिटिश में आनवा एशियाई लोगों को रोकने का विधेयक पेश हुआ उस समय भारत में इसके विरुद्ध तार प्रतिक्रिया हुई। अमिल भारतीय कांग्रेस की संसदीय पार्टी में यह सुझाव दिया गया कि ब्रिटिश सरकार से बल्क में के लिए राष्ट्रमण्डल छोड़ दिया जाय और भारत में ब्रिटिश सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण किया जाय। यद्यपि प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू को यह बतला दिया कि एशियाई लोगों को ब्रिटिश प्रवेश में रोकने वाले अधिनियम का भारत और ब्रिटिश के सम्बन्ध पर सांघातिक असर पड़ेगा। ब्रिटिश सरकार पर इस विवाद का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और 29 फरवरी 1968 को उक्त विधेयक स्वीकार करके केन्या के प्रवासी भारतीयों के ब्रिटिश प्रवेश को रोक दिया गया।

राष्ट्रमण्डल का मविष्य—ब्रिटिश की नीति के कारण राष्ट्रमण्डल की बुनियाद निरन्तर ख़ाखनी होती जा रही है। ब्रिटिश में पढ़ते राष्ट्रमण्डलीय देशों के नागरिकों को विशेष सुविधा दी जाती थी। परन्तु 1962 में ब्रिटेन ने राष्ट्रमण्डलीय प्रवास अधिनियम (Commonwealth Immigration Act) द्वारा राष्ट्रमण्डलीय देशों के नागरिकों का विशेष स्थिति का समाप्त कर उन्हें उभय सामान्य विनियमों की स्थिति में ला दिया है। यूरोपीय साक्षा बाजार में शामिल होने का ब्रिटिश आकांक्षा ने राष्ट्रमण्डल की स्थिति का अत्यन्त ख़ाखनी बना दिया है। 26 अक्टूबर 1964 में ही ब्रिटिश सरकार ने वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर उभयमूर्ति आयातित वस्तुओं पर बाह्य के राष्ट्रमण्डलीय देशों में आयातित होने वाला अथवा अथ देशों में उनके मूल्य का पन्ध्र प्रतिशत शुल्क लगा दिया जिससे राष्ट्रमण्डलीय देशों का मिलने वाला व्यापारिक लाभ एक बड़ी मात्रा तक नष्ट हो गया। राष्ट्रमण्डल के प्रति ब्रिटेन की दुर्मुख नीति ने राष्ट्रमण्डल के अकर्मिक देशों के विकास को एक मन्त्रमोह कर दिया। अब ब्रिटिश द्वारा साक्षा बाजार में सम्मिलित हो जाने पर ही राष्ट्रमण्डलीय देशों का और भी अधिक व्यापारिक हानि उगाना पड़ेगा। ब्रिटेन के इस प्रकार के

मूलतः राष्ट्रमण्डल उन देशों का ढींग-सा संगठन है जो कि किसी समय में ब्रिटिश दासता में जकड़े हुए थे। चूंकि ब्रिटेन न समय का रख पहचान कर इन देशों को शांतिपूर्ण ढंग से स्वराज्य दे दिया और आर्थिक विकास में सहायता दी। इस लिए ये देश राष्ट्रमण्डल के रूप में ब्रिटेन से सम्बंध बनाए रखने के लिए राजी हो गये। लेकिन हाल के वर्षों में ब्रिटेन ने अपने स्वार्थों के बशीभूत होकर ऐसे निम्नप विवे हैं जो राष्ट्रमण्डल के अधिकांश देशों के खिलाफ पड़ते हैं। इससे राष्ट्रमण्डल में ब्रिटेन का विरोध बढ़ा है अब यह विरोध चरम सीमा पर पहुँच रहा है।

इसके मुख्य कारण हैं—दक्षिण अफ्रिका के जातिवादी शासकों को यह कहकर हथियार देना कि वे गुड होप अंतरीप में समुद्री मार्ग की सुरक्षा के लिए हैं जबकि सहायता में इन हथियारों का प्रयोग गोरे जातिवादी शासक देश की बहुसंख्यक काली जनता को गुलाम बनाये रखने के लिए करेंगे।

दूसरा कारण यह है कि ब्रिटेन ने मारीशस को आजादी देते समय हिंद महासागर के कुछ टापुआ का मारीशस से अलग करके सीधे अपने शासन में कर लिया था। अब उनमें से एक बड़े टापू डिमागो गाशिया में अमेरिका के सहायक से सैनिक अड्डा बनाया जा रहा है। कहा तो यह जाता है कि यह अड्डा कब संचार साधनों के लिए बनाया जा रहा है लेकिन सभी जानते हैं कि यदि यह अड्डा बन गया तो वहाँ अमेरिका परमाणु अस्त्र रखेगा और उसका मुकाबला करने के लिए इसी जगहों पर हथियारों के साथ हिंद महासागर में गश्त लगाया करेगा। इस प्रकार हिंद महासागर परमाणु अस्त्रों की परिधि में आ जायगा और फिर यदि जडाई शुरू हुई तो हिंद महासागर के चारों ओर के देश उससे प्रभावित हुए बिना न रहेंगे।

तीसरा कारण ब्रिटेन की पुतगाल समयक नीति है। अफ्रिका महादीप में आज पुतगाल ही सबसे बड़ा उपनिवेशवादी राष्ट्र है और अंगोला तथा मोजम्बीक के दो बड़े देश लिस्बन के तोपों के नीचे पिस रहे हैं। ब्रिटिश सरकार एक पुरानी संधि के मातहत लगातार पुतगाल का समयन कर रही है। मोजम्बीक में जम्बेजी नदी पर बड़ा बांध बनाने के लिए पुतगाल की सहायता ब्रिटिश कम्पनियाँ अदन सरकार के इशारे पर कर रही हैं।

चौथा कारण ब्रिटेन की अपनी जातिभेद की नीति है। पूर्वी अफ्रिका में रहने वाले हजारों भारतीयों को ब्रिटेन ने अपने पासपोर्ट दिये थे अब जबकि उन्हें अफ्रिकी देशों में निवासता जा रहा है तब ब्रिटेन उन्हें अपने यहाँ घुसने नहीं देता। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार जिन एशियाइयों के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है वे ब्रिटिश नागरिक हैं और उनके साथ वसा हो व्यवहार किया जाना चाहिए जसा ब्रिटेन के अन्य नागरिकों के साथ किया जाता है।

पाँचवाँ कारण ब्रिटेन की भेदभाव वाली आर्थिक नीति भी है। ब्रिटेन यूरोपाय साक्षात् मही में शामिल होने का यत्न कर रहा है और इससे राष्ट्रमण्डल के देशों को अपना मान ब्रिटेन में बेचने में अनेक कठिनाइयाँ होंगी। उन्हें दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है।

छठा कारण ब्रिटेन की रोडेशिया सम्बन्धी नीति है। रोडेशिया ब्रिटेन का उपनिवेश था लेकिन यहाँ के गोरे अल्पसंख्यकों ने अबरन एकतरफा आजादी तथा गणराज्य की घोषणा करके बहुसंख्यक बासों को अपना गुलाम बना लिया। ब्रिटेन ने रोडेशिया के कालों पर कुछ स्थानीय गोरो के अबरन शासन को सामंजस्य के लिए अपना दायित्व पूरा नहीं किया।

कि राष्ट्रमंडल में गर-नोरी जातिपों का बहुमत है इसलिए यह प्रस्ताव रखा जाने वाला था कि ब्रिटेन को राष्ट्रमंडल से निकाल दिया जाय। लेकिन ऐसा प्रस्ताव पास होना संभव नहीं था क्योंकि यदि ब्रिटेन को निकाल दिया जाता तो अन्य गिरे देश बनावा आसुर लिया और यूजीनैड भी राष्ट्रमंडल छोड़ दे सकते थे।

इस पृष्ठाधार में सिगापुर राष्ट्रमंडल सम्मेलन अत्यंत उनावपूर्ण वातावरण में प्रारम्भ हुआ। सम्मेलन आरम्भ होने से पूर्व यह आशंका व्यक्त की जा रही थी कि यदि ब्रिटिश प्रधान मंत्री एन्व ह्यी ने दक्षिण अफ्रिका को हथियार देने का अपना निणय नहीं बदला तो संजानिया जाबिया और उगांडा सम्मेलन का बहिष्कार करेंगे। यद्यपि भारतीय प्रधान मंत्री इस सम्मेलन में स्वयं सम्मिलित नहीं हो सकी लेकिन भारतीय प्रतिनिधि ने हिंद महासागर ब्रिटेन द्वारा यूरोपीय साक्षा बाजार की सदस्यता और दक्षिण अफ्रिका को हथियार बिये जाने के मतलों पर बड़ा ही कड़ा खल अपनाया। भारतीय प्रतिनिधि ने एक वक्त तो यह भी कहा कि केवल दक्षिण अफ्रिका के साथ ही नहीं बल्कि रोडेसिया और पुतमाल के साथ भी राष्ट्रमंडल को कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार नौ नौनों की परस्पर नोक शोक के बाद 22 जनवरी को एक पांचमूत्री घोषणापत्र प्रकाशित कर राष्ट्रमंडल का यह सम्मेलन समाप्त हो गया। लेकिन इस पूरी समुक्त विवृष्टि में किसी भी समस्या का स्पष्ट निगमन नहीं बताया गया था। इसमें मानवता की समझि जोर सुरक्षा क लिए शांति पूण तरीकों का इस्तेमाल जाति रग या राजनीतिक विचारधारा अलग होने के बाव जन् व्यक्ति और उसके समान अधिकारों की स्वाधीनता इस बात की भायता वि रगभेद एक छतरनाक बीमारी है और जातिभेद की भावना एक बुराई है को बड़ावा नहीं दिया जायगा मानवता के विभिन्न गुटों में घन के असमान वितरण की जो खार् है उसे समाप्त किया जाना चाहिए और युद्ध के सभी कारणों को समाप्त करते हुए पाप और सहिष्णुता की भावना पदा करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए की आगा व्यक्त की गयी थी। इस घोषणापत्र से यह जरूर हुआ कि राष्ट्रमंडल में फट की संभावना कुछ समय के लिए स्थगित हो गयी। लेकिन स्वदेश लोटने पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ह्यी ने घोषणा की कि वह दक्षिण अफ्रिका को साइमस टाउन समझौते के अन्तयत हथियार देने को वधनबद्ध है और उसका वह पाठन करेंगे। फलत सम्मेलन के प्रारम्भ से परस्पर असहमति का जो दायरा बढ़ता और फलता-सा दीख रहा था सम्मेलन के समाप्त होने पर और फट गया। लेकिन यह बात जरूर हुई कि सम्मेलन के दौरान में अमिकी और एशियाई देशों के प्रतिनिधियों ने दिव्य खोलकर बातों की और इन बातों में उन्होंने ब्रिटेन को ही अपना निजाना बनाया। सिगापुर सम्मेलन में ब्रिटेन विरोधी अभियान ने जो इस पकड़ा उसको दखते हुए राष्ट्रमंडल का भविष्य अब अधकारमय ही माना जा सकता है।

राष्ट्रमंडल का मोटावा सम्मसन—2 11 अगस्त 1973 को राष्ट्रमंडल का उन्नीसवा अधिक्शन बनाडा की राजधानी ओटावा में हुआ। इस बीच राष्ट्रमंडल की सन्स्थता में कुछ परिवर्तन हो चुके थे। पाकिस्तान इस संस्था से निकल गया था क्योंकि ब्रिटेन ने 1972 के एक म हो बगला दश की भायता दे दी थी। लेकिन पाकिस्तान की जगह बगला दश ने ले लिया था। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद बहामा राष्ट्रमंडल का एक नया सदस्य हुआ। इसके अलावा इसी समय फरवरी 1974 में स्वतंत्र होनेवाले करेबियाई द्वीप बनाडा ने भी राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण करने की घोषणा कर दी।

आगवा सम्मेलन में वक्तव्यों पर विचार द्वारा त्रिनिकी और न यह स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रमन्त्र में अब एकता कायम नहीं रह सकती। यह तुल्य ही मरुप पर न आ कि ब्रिटन की दृष्टि में राष्ट्रमन्त्र के वक्तव्य दोनों की भिन्नता से कहा अधिक महत्त्व नौ सार्वभौमिक युगपीय आर्थिक समुदाय का है। इन प्रश्न पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री एडवर्ड हॉय ने राष्ट्रमन्त्र के देशों का एक वष और विषय विचारों से न इन्कार कर दिया जिन्हें वे त्रिनिकी से साया बाजार में आदि नान से पूव तक सहज हो प्रस्तुत कर रहे थे। इस अवसर में भारत ने एक प्रस्ताव भी रखा कि त्रिनिकी न उस नहीं माना। राष्ट्रमन्त्र के अधिपत्य सम्मेलनों के प्रवक्ता आग्रह के बावजूद ब्रिटिश प्रधानमंत्री त्रिनिकी प्रभाव महासागर में परमाणु परमाणु करने के लिए शास की निष्ठा करने के लिए भा सहमत नहीं हुए। रोरेशिया के प्रश्न पर भा इस सम्मेलन में कोई निष्पत्ती नहीं हुआ क्योंकि एडवर्ड हॉय ने साफ कह दिया कि 'रोरेशिया का मामला निपटाना राष्ट्रमन्त्र का नया ब्रिटन का उत्तरदायित्व है।

इन बातों को देखकर राष्ट्रमन्त्र के भविष्य के अवसर में अब निश्चित रूप से तरह-तरह की आशंकाएँ व्यक्त की जान उठी हैं। राष्ट्रमन्त्र के कार्यों में न केवल भारत में असन्तोष है, बल्कि कुछ अन्य मुख्य देश जिनमें अधिकतर करिबियन और अफ्रीकी देश हैं भी असन्तोष हैं। यदि यह असन्तोष इसी प्रकार बना रहा तो राष्ट्रमन्त्र का स्थापना का उद्देश्य ही नष्ट हो जायगा। त्रिभु समय राष्ट्रमन्त्र की स्थापना का गया था, उस बात का ध्यान में रखा गया था कि सम्बद्ध देशों के ब्रिटिश सरकार के प्रति सुबहों तथा उनके जापानी विचारों को निपटान की दृष्टि में वह महत्त्वपूर्ण भूमिका बना करता। सन्ध में सम्मेलन देनी के लिए वह एक ऐसा मध्यस्थित होता त्रिभु पर एकत्र होकर व अपना अधिक राजनैतिक और सामाजिक समस्याओं के समाधान साज सुकेंगे किन्तु राष्ट्रमन्त्र की उपस्थितियों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने जिन नए सत्य का प्रस्तुत कर दिया है। प्रजातीय अन्तर्हिंसित नव-भूयुक्तताओं और घनी तथा निधन दोनों के बीच बढ़ती हुई खाई एसी समस्याएँ हैं जो राष्ट्रमन्त्र की बुनियाद का ही खोखला बना रही हैं। त्रिनिकी न अब तक राष्ट्रमन्त्र के प्रति अपने प्रतिबद्धताओं का भली प्रकार नहीं निभाया है और उसके इस रवैया के कारण ही वह देश असन्तोष है। यह ठाढ़ है कि राष्ट्रमन्त्र अब त्रिनिकी की बरीबी समस्या नहीं रह गयी है और न इसका कष्ट रवियों का कष्ट ही माना जा सकता है। परन्तु यह ता सुचनी है कि आज जो त्रिनिकी का ताज राष्ट्रमन्त्र का प्रधान माना जाता है और उन त्रिभु में राष्ट्रमन्त्र की समस्याओं के निपटारण में ब्रिटन का ही त्रिभुकारी मध्य अधिक है। त्रिनिकी इस त्रिभुकारी को कहीं तक और किस प्रकार निभाता है इस पर राष्ट्रमन्त्र का भविष्य निर्भर करता है। लेकिन फिलहाल त्रिनिकी त्रिभु नाति का अवलम्बन कर रहा है उसका देखकर यह निष्कर्ष निकलता है कि राष्ट्रमन्त्र के विपटन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है।